



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5]
No. 5]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 3, 1973/माघ 14, 1894
NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 3, 1973/MAGHA 14, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)
केंद्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities
(other than the Administration of Union Territories)

मंत्रिमण्डल सचिवालय
(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1973

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली-1, 3 जनवरी, 1973

आदेश

का. आ. 255.—कृषि प्रक्रिया संहिता 1898 (1898 का 5) की धारा 492 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, बम्बई के एडवोकेट, श्री क. जे. खण्डेलवाल, और श्री ए. पी. गांधी को एडिशनल चीफ प्रोसेक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एस्पलानेड, बम्बई-1, के न्यायालय में 1972 के केस संख्या 182/सी डब्ल्यू की पेंखी करने के लिए एतद्वारा लोक-अभियोजक नियुक्त करती हैं।

[सं. 37/1/73-एवीडी-4]

कै. एल. रामचन्द्रन, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT
(Department of Personnel)

New Delhi, the 19th January, 1973

S.O. 255.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 492 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898), the Central Government hereby appoints Shri K. I. Khandelwal and Shri A. P. Gandhi, Advocates of Bombay, as Public Prosecutors to conduct before Additional Chief Presidency Magistrate, Esplanade, Bombay-1, case No. 182/CW of 1972.

[No. 37/1/73-AVD-IV]

K. L. RAMACHANDRAN, Under Secy.

का. आ. 256.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 को हुए लोक सभा के निर्वाचन के लिए 35-आसमाम (अज) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री निभर्हि साहा, ग्राम पथारामारा, पो. नूतन बलराम, जिला बांकूरा, पं. बंगाल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री निभर्हि साहा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्थक घोषित करता है।

[सं. प. न. लो. सं./35/71(15)]

ए. एन. सन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-1, the 3rd January, 1973

ORDER

S.O. 256.—WHEREAS the Election Commission is satisfied that Shri Nimai Saha, Village Pathormora, P.O. Nutan Balarampur, District Bankura, West Bengal, a contesting candidate for election to the House of the People from 35-Ausgram (SC) parliamentary constituency, held in March, 1971 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

AND WHEREAS, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure.

NOW, THEREFORE, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nimai Saha to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-HP/35/71(15)]

A. N. SEN, Secy.

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1973

अधिसूचना

क्र० प्र० 258.—लेख्य-प्रमाणक (नोटरीज) अधिनियम 1952 (1952 का 53वां) के खंड 6 के परत्वक के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा वर्ष 1973 के प्रारंभ में व्यवसाय में नियुक्त किये गये लेखा-प्रमाणकों (नोटरीज) की सूची प्रकाशित करती है :-

क्रम	लेखा प्रमाणक का नाम	निवास संबंधी एवं व्यावसायिक पता	अद्वैतांग	किस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत है	विशेष
1	2	3	4	5	6
1	श्री चक्रवर्ती ओरास्वामी	कैथोलिक सेण्टर (दूसरी मंजिल), 6, धारमेनियन गली, मद्रास-1	अधिवक्ता मद्रास उच्च न्यायालय	संपूर्ण भारत	—
2	रुस्तम अद्वैशीर गुजरान	द्वारा मैमर्स गगरात एंड कंपनी वादेशक एवं लेख्य प्रमाणक, अली चैम्बर्स मीडोज स्ट्रीट, बम्बई-1	अधिवक्ता बम्बई उच्च न्यायालय	"	—
3	श्री बाटा कृष्ण बनर्जी	कूज निवास 23-ए, सरदार गंकर रोड, पी० एम० तसीगंज, कलकत्ता	अधिवक्ता कलकत्ता उच्चन्यायालय	"	—
4	श्री भगवती प्रसाद खेतान	1, बी ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता	न्यायावादी कलकत्ता उच्चन्यायालय	"	—
5	श्री तुलसी कुमार बनर्जी	टैम्पल चैम्बर्स, 6 ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता	"	"	—
6	श्री रविन्द्र कृष्ण देव	टैम्पल चैम्बर्स, 6 ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता	"	"	—
7	श्री शिशिर कुमार घोष	द्वारा बसु एंड कंपनी वादेशक, 6 ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता	वादेशक कलकत्ता उच्च-न्यायालय	"	—
8	श्री अनेन्द्र नाथ टैगोर	29, पंडितिया रोड, कलकत्ता और हैस्टिंग्स स्ट्रीट, कलकत्ता	अधिवक्ता कलकत्ता उच्च-न्यायालय	पश्चिमी बंगाल	—
9	श्री हिमांशु प्रकाश गुंगुली	4, ईमर वक्त लैन, हावड़ा (पश्चिमी बंगाल)	"	सम्पूर्ण भारत	—
10	श्री क्रमजी कुरसेतजी हीरजीभार्द	रायल इन्सोरेन्स बिल्डिंग 5 और 7 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता	वादेशक कलकत्ता उच्च-न्यायालय	"	—
11	श्री सुधीर कुमार डे मलिक	द्वारा मार्टिन बर्न लि० 12, मिशन रो एक्सटेन्सन, कलकत्ता-1	न्यायावादी कलकत्ता उच्च-न्यायालय	"	—

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1973

शुद्धि पत्र

क्र० आ. 257.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3(2) में प्रकाशित निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 154/दिल्ली/72 तारीख 27 सितम्बर, 1972 में "23 सितम्बर, 1972 के" शब्दों के स्थान पर "23 सितम्बर, 1972 के अपराह्न" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 154/दिल्ली/72]

बी. एन. भारद्वाज, सचिव

CORRIGENDUM

S.O. 257.—In the Election Commission's notification No. 154/DL/72, dated the 27th September, 1972, published in the Gazette of India, Part II, Section 3(ii), for the words "forenoon of the 23rd September, 1972", the words "afternoon of the 23rd September, 1972" shall be substituted.

[No. 154/DL/72]

B. N. BHARDWAJ, Secy.

1	2	3	4	5	6
12 श्री राधमोहन चटर्जी	द्वारा मैसर्स श्रीर दिगनाम एण्ड कंपनी वादेक्षक, 29 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता	वादेक्षक कलकत्ता उच्च- न्यायालय	प० बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब	--	
13 श्री प्रभुदयाल हिममत्सिगका	6 ग्रील्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता	न्यायवादी कलकत्ता उच्च- न्यायालय	सम्पूर्ण भारत	--	
14 श्री अमर कुमार राय	6 ग्रील्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता	"	"	--	
15 श्री पुण्यव्रत बोस	10 किरण शंकरराय रोड, कलकत्ता	न्यायवादी कलकत्ता उच्च- न्यायालय	"	--	
16 श्री ब्रिक्टर हिलियाम मोसैज	6, ग्रील्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता	"	"	--	
17 मुखरराज बघावन	अधिवक्ता जालंधर सिटी, पंजाब	अधिवक्ता पंजाब उच्च- न्यायालय	पंजाब एवं उत्तर प्रदेश	--	
18 श्री पशुपति नाथ घोष	द्वारा कार मेहता एंड कम्पनी वादेक्षक 11, ग्रील्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता	वादेक्षक कलकत्ता उच्च- न्यायालय	सम्पूर्ण भारत	--	
19 श्री मनोहर लाल कपूर	319, पटेल नगर (पूर्वी) नई दिल्ली	अधिवक्ता	राज्य संघ क्षेत्र दिल्ली	--	
20 श्री रघुनाथ	फ्लैट 8-ए, न्यू सेंट्रल मार्केट (शंकर मार्केट) कनाट सरकस, नई दिल्ली	अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय	सम्पूर्ण भारत	--	
21 श्री हरप्रसाद मेहरा	सं० 3060 चखैवाला, दिल्ली	अधिवक्ता पंजाब उच्च- न्यायालय	राज्य संघ क्षेत्र दिल्ली	--	
22 श्री मिलवाराम कालिया	33/16, राजिन्द्र नगर, नई दिल्ली	अधिवक्ता पंजाब उच्च- न्यायालय	"	--	
23 श्री गंगा विशान कपूर	318, जी०टी०रोड, जलंधर सिटी, पंजाब	अधिवक्ता पंजाब उच्च- न्यायालय	पंजाब एवं उत्तर प्रदेश	--	
24 श्री मेहर चन्द मेहरा	161, माडल टाउन अम्बाला सिटी, पंजाब	अधिवक्ता पंजाब उच्च- न्यायालय	जिला अम्बाला	--	
25 श्री राम दिप्ता मल	7/13, पटेल नगर (पूर्वी), नई दिल्ली	अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश	--	
26 श्री सलिल कुमार चटर्जी	10, ग्रील्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता	वादेक्षक कलकत्ता उच्च- न्यायालय एवं अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय	सम्पूर्ण भारत	--	
27 श्री बृजबहादुर अग्निहोत्री	सीतापुर, उत्तर प्रदेश	वकील	जिला सीतापुर (उत्तर प्रदेश)	--	
28 श्री चमन लाल अरोड़ा	10, न्यू कोर्ट रोड, भूमतसर (पंजाब)	अधिवक्ता	जिला भूमतसर (पंजाब)	--	
29 श्री रामोवर देवजी दामोदर	द्वारा मैसर्स कांगा एंड कंपनी, वादेक्षक, रेडी-मनी मैनेजिअन्स 43, बीर निर्माण रोड, बम्बई	वादेक्षक	महाराष्ट्र	--	
30 श्री देव प्रसाद घोष	12, गोर्धनमेंट प्लेस, पूर्ब, कलकत्ता-1	न्यायवादी	सम्पूर्ण भारत	--	
31 श्री नाथमल हिममत्सिगका	6, ग्रील्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता	"	"	--	
32 श्री नवल एस० फटारफेकर	द्वारा मैसर्स फ्राबफोर्ड वेले एंड कम्पनी, स्टेट बैंक भवन, बैंक स्ट्रीट, बम्बई	अधिवक्ता एवं न्यायवादी बम्बई, उच्चन्यायालय	सम्पूर्ण भारत	--	
33 श्री राम कृष्ण गंग	वकील सं० 6456, रावतपाड़ा आगरा (उत्तर प्रदेश)	वकील, आगरा	जिला आगरा	--	
34 श्री सी० एच० पार्थिवशा	वादेक्षक, द्वारा मैसर्स फ्राबफोर्ड बैंक एण्ड कंपनी स्टेट बैंक भवन, बैंक स्ट्रीट, बम्बई	वादेक्षक	सम्पूर्ण भारत	--	
35 श्री सचिन्द्र सी० सेन	न्यायवादी, टैम्पल चेम्बर्स पहली मंजिल, 6 ग्रील्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता	न्यायवादी	कलकत्ता	--	
36 श्री सुबोध कुमार मालिक	वादेक्षक, द्वारा मैसर्स संदर मन्य एण्ड मॉरगन्स, वादेक्षक रायल इन्सोरेन्स भवन 5 और 7 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता	वादेक्षक	सम्पूर्ण भारत	--	
37 श्री डी०ए० मेहता	अधिवक्ता, 43-बी, हनुमान रोड, नई दिल्ली	बैरिस्टर	राज्य संघ क्षेत्र, दिल्ली	--	
38 श्री दुर्गा प्रसाद तुलस्यान	अधिवक्ता, झुनझुनू राजस्थान	अधिवक्ता	जिला झुनझुनू	--	
39 श्री असबन्त नारायण	अधिवक्ता, उदय मंदिर जोधपुर (राजस्थान)	अधिवक्ता	जोधपुर (राजस्थान)	--	

1	2	3	4	5	6
40	श्री मनहरलाल गिरधरलाल दीशित	वादेशक, द्वारा भाई शंकर कांगा एण्ड गिर- धारी लाल वादेशक, गुजरात समाचार भवन, खानपुर, अहमदाबाद ।	न्यायवादी उच्चन्यायालय	गुजरात एवं महाराष्ट्र	—
41	श्री हैदरमिर्जा	अधिवक्ता, फाटक शेख सलीम, वाराणसी (उ० प्र०)	अधिवक्ता	वाराणसी प्रभाग (उ० प्र०)	—
42	श्री नूर मोहम्मद	अधिवक्ता, उदयपुर राजस्थान	अधिवक्ता	जिला उदयपुर	—
43	श्री सुधीर कुमार सील	द्वारा मैसर्स सुन्दर सन्स एण्ड मोरगन्स, वादेशक रायल इन्सोरेंस भवन, 5 और 7 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	वादेशक	सम्पूर्ण भारत	—
44	श्री जितेन्द्र नाथ सन्याल	द्वारा मैसर्स सुन्दर सन्स एण्ड मोरगन्स, वादेशक रायल इन्सोरेंस भवन, 5 और 7 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	वादेशक	सम्पूर्ण भारत	—
45	श्री इन्दर सेन इसरानी	अधिवक्ता, जे-54, कृष्णा मार्ग जयपुर (राजस्थान)	अधिवक्ता	जयपुर शहर एवं जिला	—
46	श्री पी० सी० कुरियान	333, थाम्बू चट्टी स्ट्रीट मद्रास-1	"	मद्रास एवं केरल	—
47	श्री गुरदयाल सिंह सिन्धु	सं० 1 डोकोहा आलंधर (पंजाब)	"	जिला जालंधर	—
48	श्री सी० एस० बैकटसुब्रमणियन	140, फ्रास कट रोड, कोयमबतोर	"	जिला कोयमबतोर	—
49	श्री पुष्कर लाल जुनेजा	एफ-2, भगतसिंह मार्केट लेडी हाइंग रोड, नई दिल्ली एवं एफ-1, शंकर मार्केट, कनाट सरकस, नई दिल्ली ।	अधिवक्ता	सम्पूर्ण भारत	—
50	श्री जुनीसाल भाटिया	1-डी, 97 लाजपत नगर, नई दिल्ली ।	अधिवक्ता	राज्य संघ क्षेत्र दिल्ली	—
51	श्री जगन नाथ	मोंगा, जिला-फिरोजपुर (पंजाब)	अधिवक्ता	जिला फिरोजपुर	—
52	श्री रामजी दास सिंगल	गुरद्वारा स्ट्रीट भाटिडा (पंजाब)	अधिवक्ता	जिला-भाटिडा	—
53	श्री जी० बी० भट्ट	भट्ट व सलदनहा सेकर भवन, 63, न्यू मराइन लाइनस् बम्बई-20	न्यायवादी एवं अधिवक्ता	सम्पूर्ण भारत	—
54	श्री देवराज सिंह त्यागी	अधिवक्ता, कलक्टोरट कोर्ट कुलुवशहर (उत्तर प्रदेश)	अधिवक्ता	जिला बुलन्धर	—
55	श्री बाल कृष्ण	अधिवक्ता हनुमानगढ़, जिला गंगानगर (राजस्थान)	अधिवक्ता	जिला गंगानगर मुख्य कार्यालय हनुमानगढ़ (राजस्थान) में	—
56	श्री एस० आर० मेहता	अधिवक्ता बलौत्रा (राजस्थान)	अधिवक्ता	बाड़मेर व जालोर मुख्य कार्यालय बलीत्रा (राजस्थान)	—
57	श्री डी० डी० कक्कार	अधिवक्ता, 36/9, पूर्वी पटेल नगर	अधिवक्ता	राज्य संघ क्षेत्र, दिल्ली	—
58	श्री जी० सी० वर्मा	अधिवक्ता तथा श्रीय कमिश्नर ई/12, श्रीन पार्क, नई दिल्ली	अधिवक्ता व श्रीय कमिश्नर	राज्य संघ क्षेत्र, दिल्ली	—
59	श्री डी० डी० कोहली	अधिवक्ता 10, हुसन बिल्डिंग निकोलस सड़क, कश्मीरी रोड, दिल्ली	अधिवक्ता	राज्य संघ क्षेत्र, दिल्ली	—
60	श्री पी० एल० गांधी	अधिवक्ता गांधी बाग के सामने, सूरत	अधिवक्ता	सूरत जिला	—
61	श्री ए० आर० मल्हानी	अधिवक्ता, बी० बी० जैड० एन०/6, गांधी धाम (कच्छ)	अधिवक्ता	जिला कच्छ का अजार ताल्लुक	—
62	श्री एन० सी० शाह	मारफत खैतान एण्ड कंपनी वादेशक, 1 बी, ग्रोल्ड, पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता-1	अधिवक्ता कलकत्ता	कलकत्ता और नई दिल्ली	—
63	श्री टी० दलीप सिंह	मारफत मैसर्स किंग एण्ड परदाइज, 2 फ्लोर, कैथोलिक सेंटर, आरमैनियम स्ट्रीट पोस्ट बाक्स न० 121, मद्रास-1	अधिवक्ता मद्रास	सम्पूर्ण भारत	—
64	श्री जे० आर० गगरात	मारफत मैसर्स गगरात एण्ड को० एल्ली चैम्बर नानिगदास मास्टर रोड फोर्ट, बम्बई-1	अधिवक्ता, बम्बई	सम्पूर्ण भारत	—
65	श्री सावन सिंह	6515, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली	एडवोकेट, दिल्ली	संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली	—

1	2	3	4	5	6
66 श्री आर० सेतलूर	द्वारा आफोर्ड बल एण्ड कं स्टेट बैंक बिल्डिंग बैंक स्ट्रीट, बम्बई-1	ग्रटार्नी एण्ड एडवोकेट, बम्बई	सम्पूर्ण भारत	---	---
67 श्री बजमोहन मेहता	13-ए 12, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली	एडवोकेट, नई दिल्ली	संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली	---	---
68 श्री नैनी गोपाल दत्ता	पी० 21 बी ओल्ड वेलीगंज रोड, कलकत्ता-17	एडवोकेट, कलकत्ता	जिला-24 परगना, झरखी- पुर, कलकत्ता	---	---
69 श्री सुरजीत सिंह सूद	23, नेताजी पार्क, जालंधर सिटी, पंजाब	एडवोकेट जालंधर	जालंधर	---	---
70 श्री जगजीत सिंह बन्स	376-एल मोडल टाउन, जालंधर, सिटी पंजाब	एडवोकेट जालंधर	जालंधर	---	---
71 श्री के० जे० खन्नाना	राजब महल, 144, क्वीन्स रोड, बम्बई-20	एडवोकेट बम्बई	सम्पूर्ण भारत	---	---

[सं० 24/2/72-स्याय]

के० त्यागराजन्, उप सचिव,

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

New Delhi, the 27th January, 1973,

S. O. 258.—In pursuance of the provisions of Section 6 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby publishes a list of Notaries appointed by them and in practice at the beginning of the year 1973 :—

Sl. No.	Name of Notary	Residential & professional address	Qualifications	Area in which he is authorised to practise	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Shri Chakravarthi Doraswamy	Catholic Centre (2nd Floor) 6, Armenian Street, Madras-1.	Advocate Madras High Court.	Whole of India	---
2.	Shri Rustam Ardeshir Gagrati	C/o M/s. Gagrati & Co., Solicitors & Notary Public, Alli Chambers, Meadows Street, Bombay-1.	Advocate Bombay High Court.	Whole of India	---
3.	Shri Bata Krishna Banerji	Koonja Nibas, 23-A, Sardar Shankar Road, P.S. Tollygunge, Calcutta	Advocate Calcutta High Court.	Whole of India	---
4.	Shri Bhagwati Prasad Khaitan	1-B, Old Post Office Street, Calcutta.	Attorney-at-Law, Calcutta High Court.	Whole of India	---
5.	Shri Tulsi Kumar Banerji	Temple Chambers, 6, Old Post Office Street, Calcutta.	Attorney-at-Law, Calcutta High Court.	Whole of India	---
6.	Shri Rabindra Krishna Deb	Temple Chambers, 6, Old Post Office, Street, Calcutta.	Attorney-at-Law, Calcutta High Court.	Whole of India	---
7.	Shri Sisir Kumar Ghosh	C/o Basu & Co., Solicitors, 6, Old Post Office Street, Calcutta.	Solicitor, Calcutta High Court.	Whole of India	---
8.	Shri Arunendra Nath Tagore	29, Panditia Road, Calcutta & 6, Hastings Street, Calcutta.	Advocate, Calcutta High Court.	West Bengal	---
9.	Shri Himansu Prakash Ganguli	4, Issur Dutt Lane, Howrah (West Bengal).	Advocate, Calcutta High Court.	Whole of India	---
10.	Shri Framjee Curset Jee Heerjeebhoy Rustomjee	Royal Insurance Bldg. 5 & 7, Netaji Subhas Road, Calcutta.	Solicitor, Calcutta High Court.	Whole of India	---
11.	Shri Sudhir Kumar Dey Mullick	C/o Martin Burn Ltd., 12, Mission Row Extension, Calcutta-1.	Attorney-at-Law, Calcutta High Court.	Whole of India	---
12.	Shri Rash Mohan Chatterji	C/o M/s. Orr., Dignam & Co., Solicitors, 28, Netaji Subhas Road, Calcutta.	Solicitor, Calcutta High Court.	West Bengal, Assam, Bihar, U.P. and Punjab.	---
13.	Shri Prabhudayal Himatsingka	6, Old Post Office Street, Calcutta.	Attorney-at-Law, Calcutta High Court.	Whole of India	---

1	2	3	4	5	6
14.	Shri Amar Kumar Ray	6, Old Post Office Street, Calcutta.	Attorney-at-Law, Whole of India Calcutta High Court.		—
15.	Shri Punyabrata Bose	10, Kiran Shankar Roy Road, Calcutta-1.	Attorney-at-Law, Whole of India Calcutta High Court.		—
16.	Shri Victor Elias Moses	6, Old Post Office Street, Calcutta.	Attorney-at-Law, Whole of India Calcutta High Court.		—
17.	Shri Mulkh Raj Wadhawan	Advocate, Jullundur City Punjab.	Advocate, Punjab High Court.	Punjab and U.P.	—
18.	Shri Pashupati Nath Ghosh	C/o Kar, Mehta & Co. Solicitors, 11, Old Post Office Street, Calcutta.	Solicitor, Calcutta, High Court.	Whole of India	—
19.	Shri Manoharlal Kapur	3/9, Patel Nagar (East), New Delhi.	Advocate,	Union Territory of Delhi.	—
20.	Shri Raghu Nath	Flat 8-A, New Central Market (Shankar Market) Connaught Circus, New Delhi.	Advocate, Supreme Court.	Whole of India	—
21.	Shri Harpershad Mehra	No. 3060, Charkhewalan, Delhi.	Advocate, Punjab High Court.	Union Territory of Delhi.	—
22.	Shri Milawa Ram Kalia	33/16, Rajindra Nagar, New Delhi.	Advocate Punjab High Court.	Union Territory of Delhi.	—
23.	Shri Ganga Bishan Kapur	318, G.T. Road, Jullundur City, Punjab.	Advocate Punjab High Court.	Punjab and U.P.	—
24.	Shri Mehr Chand Mehra	161, Model Town Ambala City (Haryana).	Advocate, Punjab High Court.	Ambala District	—
25.	Shri Ram Ditta Mall.	7/13, Patel Nagar (East) New Delhi.	Advocate Supreme Court.	Union Territory of Delhi, Rajasthan, Punjab and Uttar Pradesh.	—
26.	Shri Salil Kumar Chatterjee	10, Old Post Office Street, Calcutta.	Solicitor, Calcutta High Court and Advocate Supreme Court.	Whole of India	—
27.	Shri Brij Bahadur Agnihotri	Sitapur, U.P.	Vakil	Sitapur Distt. (U.P.)	—
28.	Shri Chaman Lal Arora	10, New Court Road, Amritsar (Punjab).	Advocate	Amritsar District (Punjab).	—
29.	Shri Damodar Devji Damodar	C/o M/t. Kanga & Co., Solicitors, Ready money Mansions, 43, Veer Nirman Road, Bombay.	Solicitor	Maharashtra	—
30.	Shri Deba Prosad Ghosh	12, Govt. Place East, Calcutta-1.	Attorney	Whole of India	—
31.	Shri Nathmal Himatsingka	6, Old Post Office Street, Calcutta.	Attorney	Whole of India	—
32.	Shri Nawal S. Phatarphekar	C/o M/s. Crawford Bayley & Co. State Bank Bldgs. Bank Street, Bombay.	Advocate & Attorney, Bombay High Court.	Whole of India	—
33.	Shri Ram Kishan Garg	Vakil, No. 6456, Rawatpara, Agra (U.P.)	Vakil, Agra	Agra Distt.	—
34.	Shri C.H. Pardiwala	Solicitor, C/o M/s. Crawford Bayley and Co., State Bank Bldgs., Bank Street, Bombay.	Solicitor	Whole of India	—
35.	Shri Schindra C. Sen.	Attorney-at-Law Temple Chambers, 1st Floor, 6, Old Post Office Street, Calcutta.	Attorney	Calcutta	—
36.	Shri Subodh Kumar Mullick	Solicitor, C/o, M/s. Sandersons & Morgans, Solicitors, Royal Insurance Bldgs., 5 & 7, Netaji Subhas Road, Calcutta	Solicitor	Whole of India	—

1	2	3	4	5	6
37. Shri D.A. Mahta		Advocate 43-B Hanuman Road, New Delhi	Bar-at-law	Union Territory of Delhi.	—
38. Shri Durga Prasad Tulsyan		Advocate, Jhunjhunu, Rajasthan.	Advocate	Jhunjhunu (Rajasthan)	—
39. Shri Jaswant Narain		Advocate, Udai Mandir Jodhpur (Rajasthan).	Advocate	Jodhpur (Rajasthan)	—
40. Shri Manharlal Girdharilal Doshit		Solicitor, C/o Bhai Shanker Kanga & Girdharilal, Solicitors, Gujarat Samachar Bhavan, Kanpur, Ahmedabad.	Attorney High Court, Bombay.	Gujarat and Maharashtra.	—
41. Shri Haider Mirza		Advocate, Phatak Sheikh Saleem, Varanasi (U.P.)	Advocate	Varanasi Division (U.P.)	—
42. Shri Noor Mohammed		Advocate, Udaipur (Rajasthan).	Advocate	Udaipur Distt.	—
43. Shri Sudhir Kumar Seal		C/o M/s. Sandersons & Morgans, Solicitors Royal Insurance Bldgs., 5 & 7, Netaji Subhas Road, Calcutta-1.	Solicitor	Whole of India.	—
44. Shri Jitendra Nath Sanyal		C/o M/s. Sandersons & Morgans, Solicitors Royal Insurance Bldgs., 5 & 7, Netaji Subhas Road, Calcutta-1.	Solicitor	Whole of India.	—
45. Shri Indersen Israni		Advocate, J-54 Krishna Marg, Jaipur (Rajasthan)	Advocate	Jaipur City & Distt.	—
46. Shri P. C. Kurian		333, Thambu Chetty Street, Madras-1.	Advocate	Madras and Kerala	—
47. Shri Gurdyal Singh Sindhoo		No. 1, Dokoha, Jullundur (Punjab).	Advocate	Jullundur District.	—
48. Shri C. S. Venkatasubramanian		140, Cross Cut Road, Coimbatore.	Advocate	Coimbatore District	—
49. Shri Pushkar Lal Juneja		F-2, Bhagat Singh Market, Lady Hardings Road, New Delhi and F-1, Shankar Market, Connaught Circus, New Delhi.	Advocate	Whole of India.	—
50. Shri Chuni Lal Bhatia		1-D, 97, Lajpat Nagar, New Delhi.	Advocate	Union Territory of Delhi.	—
51. Shri Jagan Nath		Moga, Distt. Ferozepur (Punjab).	Advocate	Ferozepur District	—
52. Shri Ramji Dass Singal		Gurdwara Street, Bhatinda (Punjab).	Advocate	Bhatinda District	—
53. Shri G. V. Bhatt		Bhatt & Saldanha Maker Bhavan 63, New Marine Lines, Bombay-20.	Attorney & Advocate	Whole of India.	—
54. Shri Deoraj Singh Tyagi		Advocate, Collectorate's Courts, Bulandshahr (U.P.)	Advocate	District Bulandshahr (U.P.)	—
55. Shri Bal Krishan		Advocate, Hanumangarh Town, Distt., Ganganagar (Rajasthan)	Advocate	District Ganganagar with Headquarters at Hanumangarh (Rajasthan).	—
56. Shri S. R. Mehta		Advocate Balotra (Rajasthan).	Advocate	District of Barmer and Jalore with Headquarters at Balotra (Rajasthan)	—
57. Shri D. D. Kakkar		Advocate, 36/9, East Patel Nagar, New Delhi-8.	Advocate	Union Territory of Delhi.	—
58. Shri G. C. Verma		Advocate, Oath Commissioner E/12, Green Park, New Delhi.	Advocate-Cum-Oath Commissioner	Union Territory of Delhi.	—

1	2	3	4	5	6
59. Shri D. D. Kohli	.	Advocate, 10, Hasson Building, Nicholsons Road, Kashmere Gate, Delhi.	Advocate	Union Territory of Delhi.	—
60. Shri P. I. Gandhi	.	Advocate, Opposite Gandhi Bagh, Surat.	Advocate	Surat District	—
61. Shri A. R. Malkani	.	Advocate, BBZ-N-6, Gandhidham (Kutch)	Advocate	Anjar Taluka of Kutch Distt.	—
62. Shri N. C. Shah	.	C/o Khaitan & Co. Solicitor, 1B, Old Post Office Street, Calcutta-1.	Advocate, Calcutta	Calcutta and New Delhi.	—
63. Shri T. Dulip Singh	.	C/o Messrs King & Partridge, 2nd Floor, Catholic Centre, Armenian Street, Post Box No 121, Madras-1.	Advocate, Madras	Whole of India	—
64. Shri J. R. Gagrati	.	C/o M/s. Gagrati & Company, Allj Chambers, Nagindas Master Road Fort, Bombay-1.	Advocate, Bombay	Whole of India	—
65. Shri Sawan Singh	.	65/5, New Rohtak Road, Karol Bagh, New Delhi.	Advocate, Delhi	Union Territory of Delhi,	—
66. Shri R. Setlur	.	C/o Crawford Bayley & Co., State Bank Buildings, Bank Street, Bombay-1.	Attorney and Advocate, Bombay	Whole of India	—
67. Shri Brij Mohan Mehta	.	13A/2, Rajinder Nagar, New Delhi.	Advocate, New Delhi.	Union Territory of Delhi.	—
68. Shri Nani Gopal Datta	.	P-21 B, Old Ballyganj Road, Calcutta-19.	Advocate, Calcutta.	Distt. 24 Parganas, Alipore, Calcutta.	—
69. Shri Surjit Singh Sood	.	23, Netaji Park, Jullundur City (Punjab)	Advocate, Jullundur.	Jullundur	—
70. Shri Jagjit Singh Bains	.	376-L, Model Town, Jullundur City (Punjab)	Advocate, Jullundur	Jullundur	—
71. Shri K. J. Khambata	.	Rajah Mahal, 144, Queen's Road, Bombay-20.	Advocate, Bombay	Whole of India.	—

[No. 24/2/72-Jus.]

K. THYAGARAJAN,
Deputy Secretary.

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1973

का. आ. 259.—एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1869 का 54) की धारा 28 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा मैसर्स अजय प्रिन्टरी प्राइवेट लि. के अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 143/1970, दिनांक 22 अक्टूबर, 1970) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[संख्या 9 (963)/70-एम. (बी)]

एस. बलरामन, अवर सचिव

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 10th January, 1973

S.O. 259.—In pursuance of sub-section (3) of section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s AJAY PRINTER PVT. LTD. under the said Act (Certificate of Registration No. 143/1970 dated the 22nd October, 1970).

[No. 9/963/70-M(B)]

S. BALARAMAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1972

(आय-कर)

का. आ. 260.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 छ की उप-धारा (2) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उर्गला श्री महावैव पार्वती और कुक्कुली श्री दुर्गा परमेश्वरी मन्दिर, उर्गला गांव, तालुक कसारागांव, डाक-घर कुम्भदाज को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए सम्पूर्ण केल राज्य में प्रसिद्ध लोक-पूजा स्थान के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 233/फा. सं. 176/46/72-आय-कर (ए आई)]

बी. माधवन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

New Delhi, the 28th November, 1972

(INCOME-TAX)

S.O. 260.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80 G of the Income-tax Act, 1961

(43 of 1961), the Central Government hereby notifies Ubrangala Shree Mahadeva Parvathi and Kudkuli Shri Durga Parameshwari Temples, Ubrangala Village, Kasaragod Taluk, P.O. Kumbdaje, to be the places of public worship of renown throughout the State of Kerala for the purposes of the said section

[No. 233/F. No. 176/46/72-IT(AI)]

B. MADHAVAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1972

का. आ. 261.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित संस्था को, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् विहित प्राधिकारी द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (2) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया गया है।

संस्था

औषधीय और औद्योगिक अनुसंधान सोसाइटी, मुंबई।

[सं. 244/फा. सं. 203/42/72-आई टी(ए2)]

New Delhi, the 20th December, 1972

S.O. 261.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961

INSTITUTION

SOCIETY FOR PHARMACEUTICAL AND INDUSTRIAL RESEARCH, BOMBAY

[No. 244/F. No. 203/42/72-IT(A. II)]

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1972

का. आ. 262.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित संस्था को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् विहित प्राधिकारी द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (2) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया गया है।

संस्था

राष्ट्रीय अन्धता निवारण सोसाइटी-भारत।

[सं. 245/फा. सं. 203/5/72-आई टी-(ए2)]

New Delhi, the 21st December, 1972

S.O. 262.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

INSTITUTION

THE NATIONAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF BLINDNESS—INDIA

[No. 245/F. No. 203/51/72-IT(A. II)]

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1972

का. आ. 263.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को, भारत समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् विहित प्राधिकारी द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (3) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया गया है।

संस्था

कौमी एकता ट्रस्ट, नई दिल्ली।

[सं. 247/फा. सं. 203/38/72-आई टी(ए 2)]

टी. पी. भट्टनवाल, उप-सचिव

39 G of India/72—2.

New Delhi, the 23rd December, 1972

S.O. 263.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Social Science Research, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

INSTITUTION

QAUMI EKTA TRUST, NEW DELHI.

[No. 247/F. No. 203/38/72-IT(A. II)]

T. P. JHUNJHUNWALA, Dy Secy.

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1973

सीमा-शुल्क

का. आ. 264.—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार श्री एम. एस. मेहता सीमा-शुल्क कलक्टर (निवारक), मुंबई को साथ ही साथ सीमा-शुल्क कलक्टर, गुंटूर के रूप में भी एतद्वारा नियुक्त करती है।

2. श्री एम. एस. मेहता की नियुक्ति से सम्बन्धित यह औद्योगिक सूचना श्री ए. एस. आई. जाफ़र की, सीमा-शुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, गुंटूर के रूप में, वर्तमान नियुक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

[सं. 9/फा. सं. 582/2/72 एल. सी. 2]

के. शंकररामन, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd February, 1973

CUSTOMS

S.O. 264.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby appoints Shri M. S. Mehta, Collector of Customs (Preventive), Bombay to be concurrently the Collector of Customs, Guntur as well.

2. This notification regarding the appointment of Shri M. S. Mehta shall be without prejudice to the existing appointment of Shri A. S. I. Jaffar as the Collector of Customs and Central Excise, Guntur.

[No. 9/F. No. 582/2/72-LCH]

(केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड)

सीमा-शुल्क

का. आ. 265.—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 5 की उपधारा (1) के अनुसरण में, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड एतद्वारा निर्दिष्ट करता है कि श्री एम. एस. मेहता, सीमा-शुल्क कलक्टर, गुंटूर, ऐसे कलक्टर के रूप में, अध्याय 14 और 16 के सिवाए, उक्त अधिनियम के अधीन किसी सीमा-शुल्क कलक्टर को प्रदत्त या अधिप्राप्त किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या किन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे।

[सं. 10/फा. सं. 582/2/72-एल. सी. 2]

के. शंकररामन, अवर सचिव

(Central Board of Excise and Customs)

CUSTOMS

S.O. 265.—In pursuance of sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby directs that Shri M. S. Mehta, Collector of Customs, Guntur, shall not, as such Collector, exercise any powers or discharge any duties conferred or imposed on a Collector of Customs under the said Act other than those under Chapters XIV and XVI thereof.

[No. 10/F. No. 582/2/72-LCH]

K. SANKARARAMAN, Under Secy.

(वित्त मंत्रालय)

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 विसम्बर, 1972

30 जून, 1970 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काम काज और भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति और प्रगति की वार्षिक रिपोर्ट

का० प्रा० 266—भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट, 1934 की धारा 53 (2) के अनुसार केन्द्रीय निदेशक बोर्ड ने भारत सरकार को 30 जून, 1970 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काम काज और भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति और प्रगति की वार्षिक रिपोर्ट भेजी है जो नीचे उद्धृत की जाती है:—

1. अर्थव्यवस्था की समग्र प्रवृत्तियाँ

जुलाई 1969 से जून 1970 तक के बैंक के लेखा वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के कई पहलुओं में अच्छी प्रगति हुई। सभी महत्वपूर्ण कृषि पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हुई और यह वृद्धि भनाजों और जूट व मेस्ता के उत्पादन में काफी अधिक थी। औद्योगिक उत्पादन में भी काफी अच्छी वृद्धि हुई। यह अनुमान लगाया जाता है कि 1969-70 (राजकोषीय वर्ष) में स्थिर मूल्यों के अनुसार राष्ट्रीय आय में 5 से 5½ प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। यह वृद्धि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए परिकल्पित वार्षिक औसत वृद्धि-दर के लगभग बराबर है। मुख्यतः आयातों में बराबर कमी होने के कारण आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष में पर्याप्त वृद्धि हुई। नियतों में बराबर वृद्धि होती रही यद्यपि यह वृद्धि-दर एक वर्ष के पहले की वृद्धि-दर से बहुत कम थी। मुद्रागत वित्तीय साधनों की वृद्धि-दर भी पिछले वर्ष की तुलना में कम ही थी। सरकार को बैंकों द्वारा दिये गये ऋण के प्रभावस्वरूप मुद्रागत वित्तीय साधनों में पिछले वर्ष की तुलना में कम विस्तार हुआ। इससे इस बात का संकेत मिला कि सरकारी क्षेत्र के बजट संबंधी कार्यक्रमों में पर्याप्त संतुलन आ गया था। इन अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद मूल्य-स्थिति थोड़ी बिगड़ गयी थी। पिछले दो वर्षों में मूल्य में जो सापेक्ष स्थायिता थी उसके स्थान पर इस वर्ष मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी।

2. अर्थव्यवस्था में, विशेषकर कृषि और लघु उद्योग में किये जाने वाले निवेश में बराबर वृद्धि होती रही। मीयादी ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा मंजूर की गयी सहायता और पहले ही मंजूर की गयी सहायता के बितरण में इस वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुई। विशेष रूप से लघु उद्योग क्षेत्र को सहायता की भारी राशि मिली। भारत सरकार के बजट में अल्प बचत प्रयत्न, बैंक जमा, सरकारी प्रतिभूति, स्टॉक और शेयर जैसी वित्तीय वास्तवियों के रूप में बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई उपायों की घोषणा की गयी। आलोच्य वर्ष के अधिकांश भाग में स्टॉक बाजार में मंदी ही रही, किंतु स्टॉकों और शेयरों में निवेश किये जाने के संदर्भ में 1970-71 के बजट में प्रदान की गयी कर संबंधी रियायतों के कारण वह पुनः सक्रिय हो गया।

3. बजट नीति इस प्रकार बनायी गयी कि उत्पादक शक्तियों को और बल मिले और साथ ही गरीबों का कल्याण भी हो। परीक्षा करों की व्यवस्था इस प्रकार की गयी कि निर्यात के विकास और आयात प्रतिस्थापन की विधा में और प्रगति हो और खपत को संयमित किया जाए। निवेश या उत्पादक माल पर लगाये जाने वाले करों और निगम करों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया ताकि उत्पादन में होने वाली प्रगति बनी रहे। बचत जमा राशियों को अधिक मात्रा में जुटाने के उद्देश्य से अल्प बचत की कतिपय वर्तमान श्रेणियों के लिए ब्याज दरों को बढ़ाया गया और अल्प बचत की ऐसी नयी श्रेणियाँ प्रारंभ की गयीं

जिनकी ब्याज दरें ऊँची हैं, किंतु जो कर संबंधी रियायतों की मात्र नहीं हैं। विकास के साथ समाज के अत्यधिक आवश्यकता-ग्रस्त समुदाय के कल्याण के उद्देश्य से 1970-71 के बजट में निम्नलिखित विशेष योजनाओं की व्यवस्था की गयी : (i) सारे देश के चुने हुए 45 जिलों के छोटे किसानों के लिए विशेष योजनाएँ, (ii) विशेष रूप से अकालपीडित क्षेत्रों के लिए चुने हुए ग्रामीण कार्यक्रम, (iii) उन क्षेत्रों के लिए पीने के पानी की सप्लाई की योजनाएँ जहाँ आसानी से इस मौलिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती हो, (iv) औद्योगिक कामगारों और सरकारी कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की सुविधा, (v) बच्चों के लिए पोष्टिक आहार का कार्यक्रम और (vi) गंदी बस्तियों को हटाने, गृह-निर्माण और शहरी भूमि विकास के कार्यों की वित्तीय सहायता के लिए 10 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ एक शहरी विकास निगम की स्थापना।

4. मुद्रा नीति का उद्देश्य हमेशा की तरह आर्थिक विकास को बढ़ाना और साथ ही, अर्थव्यवस्था की मुद्रा-स्थिरकारी प्रवृत्तियों को रोकना रहा। 14 प्रमुख वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण से बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण का पर्याप्त मात्रा में पुनर्वित्तास किया जा सका जिस से कि विकास की प्रक्रिया में, विशेषकर कृषि, लघु उद्योग जैसे अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों में तेजी लायी जा सके जिन पर अब तक वाणिज्य बैंक ध्यान नहीं दिया करते थे। सारे देश में बहुत अधिक मात्रा में जमा राशि जुटाये जाने पर क्रमशः अधिक बल दिया गया।

उत्पादन, मूल्य और नीति संबंधी उपाय

5. 1969-70 में मानसून का प्रारंभ होने में विस्मय होने और प्रारम्भिक महीनों में कतिपय क्षेत्रों में कम वर्षा होने के बावजूद कृषि उत्पादन में पर्याप्त प्रगति हुई। भनाजों के उत्पादन की मात्रा जहाँ 1967-68 और 1968-69 में क्रमशः 950 लाख मी० टन और 940 लाख मी० टन थी वहाँ 1969-70 में बढ़कर 1000 लाख मी० टन हो गयी। यह अनुमान लगाया गया है कि बावल के उत्पादन में 23 लाख मी० टन की वृद्धि हुई अर्थात् वह बढ़कर 420 लाख मी० टन हो गया और गेहूँ का उत्पादन बढ़कर 200 लाख मी० टन हो गया अर्थात् उसमें 13 लाख मी० टन की वृद्धि हुई। अंतिम अनुमान के अनुसार पटसन और मेस्ता के उत्पादन की मात्रा बढ़कर 68 लाख गांठें हो गयी जब कि 1968-69 में वह 38 लाख गांठें थीं। मूंगफली का 51 लाख मी० टन का जो उत्पादन हुआ वह भी पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 11 प्रतिशत अधिक था। व्यापार क्षेत्र में यह अनुमान है कि कई के उत्पादन की मात्रा थोड़ी सी बढ़कर 61 लाख मी० टन हो गयी जब कि वह पिछले वर्ष 60 लाख मी० टन थी। गुड़ के रूप में गन्ने के उत्पादन में बराबर वृद्धि पायी गयी। अनुमान है कि 1966-67 में उसके कुल उत्पादन की मात्रा 125 लाख मी० टन थी जब कि वह पिछले वर्ष 120 लाख मी० टन थी।

6. 1969 के कैलेंडर वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में जो वृद्धि हुई उसकी समग्र दर 1968 की 6.4 प्रतिशत की वृद्धि-दर की तुलना में थोड़ी-सी अधिक अर्थात् 6.9 प्रतिशत थी। आलोच्य वर्ष के पहले की महीनों, अर्थात् जुलाई 1969 से मार्च 1970 तक की अवधि में औद्योगिक उत्पादन में हुई वृद्धि की दर पिछले वर्ष की तबनुकूपी अवधि के 7.4 प्रतिशत की तुलना में कम होकर 5.8 प्रतिशत हो गयी।

7. उपयोग के आधार पर वर्गीकृत उद्योगों के प्रमुख वर्गों में से आलोच्य अवधि में 'मूल उद्योगों' में 7.8 प्रतिशत की कम वृद्धि हुई

जबकि पिछले वर्ष की तदनुसूची भवधि में उनमें 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 'पूँजीगत माल उद्योगों' में 2.0 प्रतिशत की कमी हुई जब कि पिछले वर्ष की तदनुसूची भवधि में उनमें 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 'मध्यवर्ती माल उद्योगों' और 'उपभोक्ता माल उद्योगों' में बराबर वृद्धि होती रही। मध्यवर्ती माल उद्योगों में पिछले वर्ष की 5.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में इस वर्ष 5.5 प्रतिशत की वृद्धि और उपभोक्ता माल उद्योगों में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निविष्ट की गयी वस्तुओं के अनुसार उद्योगों का विश्लेषण करने से पता लगता है कि सामान्य सूचकांक में जिन कृषि आधारित उद्योगों का भार लगभग 44 प्रतिशत है उनके उत्पादन में और सुधार हुआ अर्थात् उनके उत्पादन में पिछले वर्ष के 1.7 प्रतिशत की तुलना में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वृद्धि का प्रमुख कारण यह था कि चीनी और चाय के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि और सूत की कटाई के उत्पादन में थोड़ी सी वृद्धि हुई। धातु आधारित और रासायनिक पदार्थों पर आधारित उद्योगों के उत्पादन की वृद्धि-दरें कम होकर क्रमशः 1.6 प्रतिशत और 8.1 प्रतिशत हो गयी जब कि वे पिछले वर्ष क्रमशः 11.4 प्रतिशत और 20.1 प्रतिशत थीं।

8. 'मूल उद्योगों' में खनन और पत्थर की खानों की खुदाई और उर्वरकों के उत्पादन में कम दर पर वृद्धि हुई। लोहे और धातु के मूल उद्योगों में उत्पादन का स्तर मुख्यतः श्रमिक-प्रभाति, समुचित रखरखाव के अभाव और सरकारी क्षेत्र के एक इस्पात-कारखाने में टेक्नोलाजी संबंधी कतिपय दोषों के कारण पिछले साल के स्तर पर ही रहा। उर्वरकों के उत्पादन की गति में भी भ्रंशतः उनकी कम खरीद और भ्रंशतः निवेश की जाने वाली मूल वस्तुओं की कमी के कारण संदी आ गयी। किंतु भारी भ्रकाबनिक रासायनिक पदार्थों, सीमेंट के उत्पादन और तांबा गलाने वाली और बेसन मिलों के उत्पादन में वृद्धि हुई।

9. 'पूँजीगत माल उद्योगों' में से प्रथम चालकों, बायलरों तथा भाप उत्पादक संयंत्रों, औद्योगिक मशीनों, रेल-सड़क उपकरणों और मोटर यानों से संबंधित उद्योगों के उत्पादन में पर्याप्त कमी पायी गयी। फिर भी बिजली चालित मोटरों और घट्टियों, बिजली के केबलों और बिजली चालित मशीनों, उपकरणों तथा साधनों आदि के निर्माण में पर्याप्त सुधार हुआ। इससे पता चला कि राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किये जाने वाले निवेश में वृद्धि की गयी थी।

सारणी 1—कृषि उत्पादन की प्रवृत्तियाँ

मात्रा	1968-69 (अंतिम अनु- मान)	1969-70 (अनुमानित)
(1) अनाज वस लाख मी० टन	94.1	100.00**
(i) चावल —वही—	39.8	42**
(ii) गेहूँ —वही—	18.7	20**
(2) रुई वस लाख गॉटें@	5.3.	—
	(6.0)†	(6.1)†
(3) पटसन और मेस्ता —वही—	3.8*	6.8@
(4) मूंगफली वस लाख मी० टन	4.6*	5.1@
(5) गन्ना —वही—	12.0	—
(गुड़ के रूप में)		(12.5)††

@ 180 कि० ग्रा० की गॉट ।

* भ्रंशतः परिशोधित अनुमान ।

@ अंतिम अनुमान ।

** अनुमानित ।

† बाणिज्येतर उत्पादन सहित

†† व्यापार-अनुमान ।

व्यापार अनुमान ।

सारणी 2—वृद्धि की दरें—औद्योगिक उत्पादन के सूचक अंक

(आधार : 1960=100)

वर्ग	जुलाई-मार्च का औसत सूचकांक		
	1967-68	1968-69	1969-70
सामान्य सूचकांक	154.1	165.5	175.1
मौसम के अनुसार समायोजित		(+7.4)	(+5.8)
उपयोग पर आधारित			
मूल उद्योग	181.3	201.7	217.4
		(+11.3)	(+7.8)
पूँजीगत माल उद्योग	205.2	219.1	214.8
		(+6.8)	(-2.0)
मध्यवर्ती माल उद्योग	143.2	150.4	158.7
		(+5.0)	(+5.5)
उपभोक्ता माल उद्योग	130.9	138.6	149.3
		(+5.9)	(+7.7)
टिकाऊ उपभोक्ता माल	189.3	223.1	242.1
		(+17.9)	(+8.5)
निविष्ट वस्तुओं पर आधारित			
कृषि आधारित उद्योग	120.1	122.1	128.7
		(+1.7)	(+5.4)
धातु आधारित उद्योग	198.6	221.3	224.9
		(+11.4)	(+1.6)
रासायनिक पदार्थों पर आधारित उद्योग	184.4	221.4	239.3
		(+20.1)	(+8.1)

नोट : कोष्ठकों में दिये हुए आंकड़े पिछले वर्षों की तुलना में हुए प्रतिशत परिवर्तन के सूचक हैं ।

10. 'मध्यवर्ती माल उद्योगों' में से सूत की कटाई में 3.8 प्रतिशत, बैटरियों के निर्माण में 13.3 प्रतिशत और कृत्रिम रेजिन और प्लास्टिक में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पैट्रोलियम परिष्करण शालाओं के उत्पादों की वृद्धि की दर थोड़ी-सी कम थी, अर्थात् जहाँ पिछले वर्ष 10.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहाँ इस वर्ष 8.7 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। उक्त नौ महीने की अवधि में जूट से बनी वस्तुओं के उत्पादन की स्थिति अपरिवर्तित रही जबकि 1968-69 की तदनुसूची भवधि में उसमें 18.3 प्रतिशत की कमी हुई थी।

11. 'उपभोक्ता माल उद्योगों' में से खाद्यान्न उत्पादन (चीनी, चाय और वनस्पति) में इस वर्ष 20.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि पिछले वर्ष की तदनुसूची भवधि में उसमें केवल 0.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। कागज और कागज से बनी चीजों के उत्पादन में भी वृद्धि पायी गयी। संवार उपस्कर, मोटर साइकिल, और साइकिल जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि कम हो गयी। ऊनो/वस्टेड कपड़ों और परिष्कृत तथा औद्योगिक रासायनिक पदार्थों के उत्पादन में क्रमशः 7.8 प्रतिशत और 7.0 प्रतिशत की कमी हुई जब कि पिछले वर्ष की तदनुसूची भवधि में उनके उत्पादन में क्रमशः 46.3 प्रतिशत और 36.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

12. सधु उद्योग क्षेत्र में निवेश किये जाने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण 1969-70 में इस क्षेत्र के उत्पादन के अनुमान में 11.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि 1968-69 में उसमें 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

13. औद्योगिक क्षमता के उपयोग से संबंधित आंकड़े केवल दिसंबर 1969 के अंत तक के लिए उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों के अनुसार स्थापित औद्योगिक क्षमता में औसत मासिक उत्पादन के प्रतिशत अनुपात द्वारा पता लगता है कि 1969 के अंत तक औद्योगिक क्षमता का अच्छा उपयोग हुआ। मूल उद्योगों में से बाहक सोडा, ऐमोनियम सल्फेट, यूरिया सल्फ्यूरिक अम्ल, उर्वरक, सीमेंट, तैयार इस्पात और इस्पात के नल तथा द्यूब के उद्योगों की क्षमता के उपयोग में पर्याप्त सुधार हुआ। किंतु पूंजीगत माल उद्योगों में से मोटर यानों और पावर ट्रांसफार्मरों के उद्योगों की क्षमता का उपयोग 1968 की अपेक्षा इस वर्ष कम हुआ।

14. औद्योगिक उत्पादन में जो कमी हुई उसके प्रमुख कारण इस प्रकार थे : कच्ची कृषि सामग्री की सप्लाई की स्थिति अच्छी नहीं थी और इंजीनियरी और संबद्ध उद्योगों को विशेष श्रेणियों के इस्पात की कमी का सामना करना पड़ा था। सुव्यवस्थित सरकारी और गैर सरकारी औद्योगिक क्षेत्र में निवेश की ओर वृद्धि हुई वह भी इतनी पर्याप्त नहीं थी कि औद्योगिक विकास को सशक्त प्रेरणा प्राप्त हो। 1969 में उद्योग

के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बराबर श्रमिकों की अशान्ति का प्रभाव पड़ा। 1969 में हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण 166.8 लाख श्रमदिन नष्ट हुए जब कि 1961 और 1965 के बीच प्रति वर्ष औसतन 58 लाख श्रमदिन नष्ट हुए थे।

15. आलोच्य वर्ष में, विशेषकर दूसरी छमाही में मूल्यों की स्थिति गंभीर रूप से शोचनीय थी। फसल की कटाई के बाद मूल्यों में जो कमी हुई उसमें अकस्मात् नवंबर महीने के बीच में परिवर्तन आ गया और उसके बाद सामान्य मूल्य-सूचकांक में बराबर वृद्धि होती रही और यह स्थिति वर्ष के अंत तक जारी रही। सामान्य सूचकांक के वार्षिक औसत में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि पिछले वर्ष उसमें 0.2 प्रतिशत की मामूली कमी हुई थी। जून 1969 के अंत और जून 1970 के अंत के बीच सूचकांक में जो वृद्धि हुई वह पिछले वर्ष की तबनुसूची अवधि में हुई 7.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में कम अर्थात् 4.0 प्रतिशत थी। इस वर्ष के दौरान मूल्यों की गतिविधियों में स्थूल रूप से तीन चरणों में जो उतार-चढ़ाव हुए उन्हें निम्नलिखित सारणी में दिखाया गया है।

सारणी 3—बीक मूल्यों में औसती उतार-चढ़ाव

(आधार : 1961-62 = 100)

वर्ग/पंथ	जून 1969 के अंत और जुलाई 1969 के बीच	जुलाई 1969 के अंत और 15 नवंबर 1969 के बीच	15 नवंबर 1969 और जून 1970 के बीच	जून 1969 के अंत और जून 1970 के बीच
सभी पंथ	+ 1.0 (+ 2.0)	-- 4.2 (+ 0.8)	+ 7.5 (+ 4.5)	+ 4.0 (+ 7.4)
खाद्य वस्तुएं	+ 1.3 (+ 2.4)	-- 7.4 (-- 3.7)	+ 7.9 (+ 3.8)	+ 1.2 (+ 2.4)
वासन	+ 1.2 (+ 0.4)	-- 4.3 (-- 7.4)	+ 6.7 (+ 5.2)	+ 3.4 (-- 2.2)
रोहू	+ 3.2 (+ 2.2)	-- 3.8 (+ 5.0)	-- 0.1 (-- 0.3)	-- 0.9 (+ 7.0)
दालें	+ 3.0 (+ 0.9)	+ 6.1 (-- 5.9)	+ 2.7 (+ 7.1)	-- 0.7 (+ 13.5)
खाद्य तेल	+ 2.7 (+ 6.6)	-- 11.9 (+ 25.0)	+ 25.3 (+ 19.7)	+ 13.5 (+ 59.4)
शराब और तमाकू	-- 1.5 (+ 2.9)	-- 6.4 (+ 10.1)	-- 1.0 (+ 3.7)	-- 8.8 (+ 17.5)
ईंधन, पावर, बिजली और धिकनार्थ पदार्थ	+ 0.8 (+ 0.8)	+ 0.5 (+ 0.3)	+ 2.8 (+ 3.0)	+ 4.2 (+ 4.2)
औद्योगिक कच्ची सामग्री	+ 2.5 (+ 4.3)	-- 9.1 (+ 13.3)	+ 16.4 (+ 12.4)	+ 8.4 (+ 32.8)
रुई	+ 1.1 (+ 0.8)	-- 5.8 (+ 3.2)	+ 18.2 (+ 6.5)	+ 12.6 (+ 10.9)
पटसन और मेस्ता	+ 3.5 (+ 9.7)	-- 30.4 (+ 38.1)	+ 23.6 (-- 4.7)	-- 10.9 (44.4)
तिलहन	+ 3.3 (+ 8.5)	-- 10.8 (+ 19.5)	+ 23.2 (+ 22.5)	+ 13.6 (+ 58.7)
मूंगफली	+ 4.1 (11.9)	-- 22.9 (+ 23.8)	+ 37.8 (+ 38.4)	+ 10.7 (+ 91.8)
रासायनिक पदार्थ	-- 1.6 (+ 0.1)	+ 7.8 (+ 5.6)	+ 2.6 (+ 3.8)	+ 3.4 (+ 9.5)
मशीनें और परिवहन उपस्कर	+ 0.3 (--)	+ 2.8 (+ 0.7)	+ 5.7 (+ 0.5)	+ 8.9 (+ 1.2)
निर्मित सामग्री	+ 0.4 (+ 0.7)	+ 2.5 (+ 3.6)	+ 4.6 (+ 3.3)	+ 7.7 (+ 7.8)

नोट : कोष्ठकों में दिये हुए आंकड़े पिछले वर्ष की तबनुसूची अवधि की तुलना में उतार-चढ़ाव के प्रतिशत को दिखाते हैं।

16. फरवरी 1969 से मूल्यों में जो वृद्धि पायी गयी वह पहला चरण थी। इस चरण में 'शराब और तमाखू' तथा 'रासायनिक पदार्थों' को छोड़कर शेष सभी प्रमुख वर्गों में मूल्य वृद्धि हुई। दूसरे चरण अर्थात् जुलाई 1969 के अंत और नवंबर के मध्य के बीच सामान्य सूचकांक में 4.2 प्रतिशत की कमी हुई। इसका प्रमुख कारण यह था कि 'खाद्य पदार्थों' और 'औद्योगिक कच्ची सामग्री' के मूल्यों में क्रमशः 7.4 प्रतिशत और 9.1 प्रतिशत की कमी हो गयी थी। किंतु 'निमित्त पदार्थों', 'मशीनों' और परिवहन उपकरण', 'ईंधन, पावर, बिजली और चिकनाई पदार्थों' और 'निमित्त सामग्री' के मूल्यों में बराबर वृद्धि होती रही। तीसरे चरण में सामान्य सूचकांक में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उक्त वृद्धि प्रायः सभी प्रमुख उपवर्गों में हुई। 'खाद्य पदार्थों', 'औद्योगिक कच्ची सामग्री' और 'निमित्त सामग्री' के मूल्यों में क्रमशः 7.9 प्रतिशत, 16.4 प्रतिशत और 4.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

17. इस वर्ष के दौरान मूल्यों में 4.0 प्रतिशत की जो वृद्धि हुई वह मुख्यतः औद्योगिक कच्ची सामग्री और निमित्त सामग्री के कारण हुई। मूल्य-वृद्धि के लिए खाद्य पदार्थों का योगदान पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम था। खाद्य पदार्थों के मूल्यों में जहां पिछले वर्ष 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहां इस वर्ष कम वृद्धि अर्थात् 1.2 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। चावल के मूल्य सूचकांक में जहां पिछले वर्ष 2.2 प्रतिशत की कमी हुई वहां इस वर्ष 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और गेहूँ के मूल्य सूचकांक में पिछले वर्ष हुई 7.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में इस वर्ष केवल 0.9 प्रतिशत की मामूली कमी हुई। घालों के मूल्यों में भी जहां पिछले वर्ष 13.5 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई वहां इस वर्ष 0.7 प्रतिशत की मामूली कमी हुई। खाद्य पदार्थों के मूल्यों में इस वर्ष के अधिकांश भाग में वृद्धि हुई। इस वर्ष के दौरान हुई यह वृद्धि पिछले वर्ष हुई 59.4 प्रतिशत की वृद्धि से 13.5 प्रतिशत अधिक थी। गुड़ के मूल्यों (मासिक औसत) में 25.8 प्रतिशत की कमी हुई जब कि

उनमें पिछले वर्ष 55.6 प्रतिशत की कमी हुई थी। चीनी के मूल्य लगभग स्थिर रहे।

18. 'औद्योगिक कच्ची सामग्री' के मूल्यों में 8.4 प्रतिशत की जो वृद्धि हुई उसका कारण यह था कि कृषि संबंधी प्रमुख कच्ची वस्तुओं की पूर्ति की स्थिति में उनकी मांग की तुलना में संवी थी। यद्यपि रई, पटसन और तिलहन पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अधिक मात्रा में उपलब्ध हुए फिर भी वे 1967-68 की तुलना में कम ही थे।

19. अगस्त 1969 के अंतिम समय और अक्टूबर 1969 के मध्य समय के बीच में रई के मूल्यों में कमी हुई; किंतु उसके बाद वर्ष के समाप्त होने तक मिलों में रई की आपत में वृद्धि होने के कारण वे बराबर बढ़ते रहे।

20. मूंगफली के मूल्यों में पिछले वर्ष 91.8 प्रतिशत की जो भारी वृद्धि हुई उससे भी 10.7 प्रतिशत की अधिक वृद्धि इस वर्ष हुई। तिलहनों के वर्ग में पिछले वर्ष जहां 58.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहां इस वर्ष 13.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पटसन और मेस्ता के मूल्य सूचकांक में इस वर्ष 10.9 प्रतिशत की कमी हुई। किन्तु इस वर्ष हुई इस कमी से पटसन के मूल्यों पर पड़े उस दबाव का पता नहीं चलता जो अक्टूबर 1969 के बीच में प्रारम्भ हुआ। पटसन और मेस्ता के मूल्यों में 1968-69 में भारी वृद्धि हुई थी; किन्तु 1969-70 में प्रचुर मात्रा में पटसन की फसल की संभावना के कारण उक्त मूल्यों के सूचकांक 8 फरवरी 1969 के 200.6 के उच्च स्तर से बहुत कम होकर 11 अक्टूबर 1969 तक 105.6 तक पड़ चुके। जूट से बनने वाली वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होने और राज्य व्यापार निगम द्वारा न्यूनतम टेकवन्दी मूल्य पर पटसन खरीदने के सरकारी प्रयत्नों के कारण उपर्युक्त कमी की प्रवृत्ति को रोका गया। एक ओर मिलों की जूट संबंधी मांग बढ़ती जा रही थी और दूसरी ओर 1969-70 की पटसन की फसल के संदभ में जहां 76 लाख से 80 लाख तक की

सारणी 4—उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री की उपलब्धि¹

	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70 (अनुमान)
रई (लाख गांठें) सितम्बर-अगस्त				
उत्पादन ²	53.1	65.4	60.2	60.7
आयात	7.8	7.8	4.3	8.2
उपलब्धि ³	82.9	92.4	86.2	88.6
मिलों की आपत (लाख गांठें)	57.6	61.7	62.0	64.0
पटसन और मेस्ता (लाख गांठें) जुलाई-जून				
उत्पादन	65.8	75.9	38.4	67.5
आयात	16.5	—	6.5	—
उपलब्धि	94.0	94.6	64.9	75.5
मिलों की आपत (लाख गांठें)	72.0	71.3	59.5	65.5
प्रमुख तिलहन⁴ (10 लाख मी० टन) जुलाई-जून				
उत्पादन	6.4	8.3	7.1	7.8

¹ उपलब्धि के अन्तर्गत उत्पादन + आयात + प्रारम्भिक स्टॉक आते हैं।

² बाणिज्येतर उत्पादन सहित व्यापार अनुमान।

³ 1969-70 के मौसम (जून तक) में निर्यात की गयी रई (बंगाल देशी) की मात्रा 2.0 लाख गांठें थीं जब कि वह 1968-69 की तदनुकूली अवधि में 1.7 लाख गांठें थीं।

⁴ मूंगफली, तोरिया और सरसों, भलसी, तिख और अण्डी।

गांठों की संभावना का अनुमान किया गया था वहाँ वह कम होकर 67.5 लाख गांठ हो गई और साथ ही 1970-71 की फसल के संबंध में भी प्रारंभ में निराशावादी दृष्टिकोण था; इन कारणों से मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति बनी रही। अक्टूबर 1969 के मध्य समय और जून 1970 के अंतिम समय के बीच में मूल्य सूचकांक में 47.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई अर्थात् वह 105.8 से बढ़कर 156.2 हो गया।

21. अन्य दो महत्वपूर्ण वर्ग 'मशीनो और परिवहन उपस्कर' तथा 'निर्मित सामग्री' हैं जिनके मूल्यों में लगभग 8-9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निर्मित सामग्री के मूल्य वर्ष भर बराबर बढ़ते रहे। निर्मित सामग्री के मूल्यों में जो वृद्धि हुई उसके प्रमुख कारण इस प्रकार थे; दो प्रमुख उद्योगों अर्थात् जूट वस्त्र और सूती वस्त्र के उद्योगों में मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी में क्रमशः अगस्त और अक्तूबर 1969 में काफी वृद्धि हुई और औद्योगिक कच्ची सामग्री के मूल्यों में वृद्धि हुई।

22. अमिक वर्ग के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1960=100) में जून 1969 और जून 1970 के बीच 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में उसमें 1.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

23. कृषि क्षेत्र में उत्पादित की बढ़ाने के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी संबंधी आधार को मजबूत बनाने के उद्देश्य से जो नीति अपनायी गयी थी उसे 1969-70 में जारी रखा गया। अधिक उपज वाली किस्मों के कार्यक्रमों के अधीन आनेवाली जमीन 1968-69 के 92 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1969-70 में 109 लाख हेक्टेयर हो गयी। इसी प्रकार विविध फसल कार्यक्रम के अधीन लायी जाने वाली जमीन को भी 1968-69 के 60.7 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 1969-70 में 78.7 लाख हेक्टेयर बना दिया गया। चूंकि नयी परिस्थितियों में उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति तभी की जा सकेगी जबकि समय पर और पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो, अतः लघु सिंचाई कार्यक्रम पर बराबर जोर दिया गया और उसे व्यापक बनाया गया। इसके परिणामस्वरूप यह प्रत्याशा की जाती है कि लघु सिंचाई के कार्यों में किये जाने वाले सांस्थानिक निवेश की राशि 1968-69 के 106 करोड़ रुपये से बढ़कर 1969-70 में 115 करोड़ रुपये होगी। ग्रामीण बिजली निगम की स्थापना हो जाने से लघु सिंचाई योजनाओं में किये जाने वाले निवेश में और वृद्धि ही सकती है। इस वर्ष किये गये कृषि नीति संबंधी प्रयत्नों में मुख्य खेती के क्षेत्रों में कृषि विकास के लिए प्रारंभ की गयी योजनाओं और चुने हुए जिलों में छोटे किसानों के लिए विकास एजेंसियों की स्थापना किये जाने में हुई प्रगति उल्लेखनीय थी। 1969-70 में उर्वरकों के उपभोग की मात्रा 1968-69 के 18 लाख मी० टन से बढ़कर 21 लाख मी० टन हो गई; फिर भी उक्त वृद्धि लगभग 25 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की पूर्व निर्धारित मात्रा से कम थी। उर्वरकों के उपभोग की दर में जो कमी हुई उसके अनेक कारण थे, जैसे देश के कतिपय भागों में मानसून का विलंब से आना, मुझायी गयी मात्रा से उनका कम उपयोग किया जाना, पर्याप्त वितरण व्यवस्थाओं का अभाव और अनेक राज्य सरकारों के कई ऐसे प्रतिबंधात्मक उपाय जिनसे कारखानों से उपभोग के क्षेत्र तक उर्वरकों की मुक्त आवाजाही में बाधा पड़ी। उर्वरकों के उपभोग की मात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से उर्वरकों के व्यापार के लिए निर्धारित लाइसेंस प्रणाली को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा, वाणिज्य बैंकों को यह सलाह दी गयी कि वे उर्वरकों का स्टॉक करने के लिए अधिक मात्रा में ऋण प्रदान करें और उर्वरक खरीदने के लिए किसानों को ऋण की जो आवश्यकताएं

होती हैं उनकी अधिक उदार शर्तों पर पर्याप्त मात्रा में पूर्ति करें। कृषकों को इस बात का प्रोत्साहन देने कि वे कृषि में अधिक मात्रा में निवेश करें और साथ ही मूल्यों, में उतार-चढ़ाव होने की जोखिम को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने अनाजों की उगाही के लिए आकर्षक मूल्य निर्धारित करने और उगाही के कार्य को और तीव्र करने की अपनी नीति को जारी रखा। प्रमुख कृषि पण्यों के लिए न्यूनतम टेकबंदी मूल्य निर्धारित करने की प्रणाली को भी जारी रखा गया।

24. 1968-69 में 79 लाख मी० टन के लक्ष्य की तुलना में केवल 62 लाख मी० टन अनाजों की उगाही की गयी। उनमें 33 लाख मी० टन चावल, 5 लाख मी० टन खरीफ के मोटे अनाज और 24 लाख मी० टन गेहूं सम्मिलित हैं। लगभग जून 1970 के अंत तक 56 लाख मी० टन अनाजों की जो उगाही की गयी थी वह पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में की गयी 58 लाख मी० टन की तुलना में कम थी। खरीफ अनाजों की उगाही के लिए (1969-70) 55 लाख मी० टन और रबी अनाजों की उगाही के लिए (1970-71) 37 लाख मी० टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक की प्रगति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि 1969-70 में अनाजों की उगाही की मात्रा उतनी ही होगी जितनी पिछले वर्ष थी। देशी उत्पादन में हुए सुधार के कारण अनाजों के आयात को 1969 में कम कर 39 लाख मी० टन कर दिया गया जब कि 1968 में उसकी मात्रा 57 लाख मी० टन थी। 1970 में अनाजों के आयात की मात्रा को और कम कर 30 लाख मी० टन कर देने की संभावना है। खुले बाजार में अधिक मात्रा में अनाजों के उपलब्ध होने से अनाजों के सार्वजनिक वितरण पर पड़ने वाला दबाव कम हुआ। 1969 में स्टॉक से निकाले गये अनाजों की मात्रा 96 लाख मी० टन थी जब कि 1968 में वह 104 लाख मी० टन थी। केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास मई 1970 के अंत में 47 लाख मी० टन अनाजों के स्टॉक थे जब कि उनकी मात्रा मई 1969 के अंत में 50 लाख मी० टन थी। कई शहरों में विधिक राशन व्यवस्था को रद्द कर दिया गया और इस कारण विधिक राशन व्यवस्था के अंतर्गत आने वाली कुल आबादी 1968 के 256 लाख से घटकर 1969 में 226 लाख हो गयी। अतः अनाजों के सरकारी स्टॉकों पर पड़ने वाला दबाव पहले की तरह कम ही होगा। अनाजों की अधिक उपलब्धि के कारण अनीपचारिक राशन व्यवस्था के संदर्भ में भी यह प्रत्याशा की जाती है कि सरकारी स्टॉकों पर पड़ने वाला दबाव पिछले वर्ष से अधिक नहीं होगा।

25. कच्ची कृषि सामग्री की सप्लाई की स्थिति उसकी मांग की तुलना में शोचनीय थी; उस कमी को अधिक आयात कर के पूरा करने का निश्चय किया गया। रूई के आयात की मात्रा को 4.3 लाख गांठों से बढ़ाकर 8 लाख गांठों से अधिक बनाया गया। सोयाबीन तेल और दूसरे खाद्य तैलों तथा चर्बियों का आयात भी बढ़ाया गया। इसके अलावा बैंकों से प्राप्त होने वाली निधियों की सहायता से अधिक मात्रा में स्टॉक बनाये रखने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने 21 जनवरी 1970 से सभी तिलहनों और वनस्पति तैलों, देशी रूई और अनाजों पर बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर मार्जिन दरों को बढ़ाकर और इन पण्यों पर अलग-अलग बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की उच्चतम सीमाओं को कम कर अत्यन्तमक ऋण नियंत्रण लागू किया। इन पण्यों पर दिये जाने वाले ऋणों पर लिये जाने वाले व्याज की न्यूनतम दर 10 प्रतिशत निर्धारित की गयी। 28 अप्रैल को इस दर को तिलहनों और रूई पर दिये जाने वाले ऋणों के संबंध में बढ़ाकर 12 प्रतिशत

कर दिया गया। बैंक ने अनुसूचित बैंकों के प्रथमों के व्याज की 9½ प्रतिशत की उच्चतम दर को भी रद्द कर दिया। उसके साथ ही वस्त्र आयुक्त ने स्टॉक की जाने वाली भारतीय रुई की मात्रा पर बंबई और भद्रमबाबाव शहरों के लिये 2½ महीनों की औसत मासिक खपत, घसम के लिए 4 महीनों की खपत और दूसरे क्षेत्रों के लिए 3½ महीनों की खपत की सीमा का प्रतिबंध लगा दिया। किन्तु अपने उत्पादन के 20 प्रतिशत या उससे अधिक का निर्यात करने वाली या रक्षा-उद्देश्यों के लिए प्राप्त आर्डरों का निष्पादन करने वाली मिलों, उत्पादकों की सहकारी कतारों और अधिकृत निर्यातकों के अधीन रहने वाली मिलों के मामलों में उच्चतर स्टॉक सीमाएं निर्धारित की गयीं। मूल्यों में और वृद्धि हो जाने के कारण सभी मामलों में 17 फरवरी 1970 को स्टॉक सीमाओं में एक महीने की औसत खपत की कमी की गयी। पटसन के मूल्यों में तेजी से कमी हो रही थी और यह स्थिति लगभग सितंबर तक जारी रही और उसकी सफाई की स्थिति में भी सापेक्ष रूप से सुधार हुआ; इस कारण भारत सरकार ने अगस्त 1969 से जूट मिलों पर उत्पादन और खरीद के संबंध में लगाये गये प्रतिबंधों को हटा दिया। इसके अलावा पटसन के मूल्यों की टेकबंदी के उद्देश्य से मिलों के लिए सितंबर 1969 से पटसन की खरीद संबंधी न्यूनतम कोटा निर्धारित किया गया।

26. औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने अपनी उबार आयात नीति को जारी रखा जिससे कि बहुत कम उपलब्ध होने वाली कच्ची सामग्री और पुर्जों के स्टॉक की पूर्ति की जा सके और महत्वपूर्ण आयातित कच्ची सामग्री और पुर्जों के अभाव के कारण उत्पादन में कोई बाधा न पड़े। अपने उत्पादन के 25 प्रतिशत (पहले के 10 प्रतिशत के बदले) या उससे अधिक मात्रा में निर्यात करने वाले औद्योगिक यूनिटों को सफाई में अधिक तरजीह दी गई। इसके अलावा, आयात प्रतिस्थापन के कारण हाल ही के वर्षों में कई उद्योगों को प्रोत्साहन मिला, अतः 159 चीजों के आयात पर रोक लगाकर और दूसरी 56 चीजों के आयात को प्रतिबंधित कर उसमें भी प्रगति की गयी है। 1970-71 के बजट में आयात कर को कम कर या रद्द कर निर्यात के लिए उत्पादन करने वाले उद्योगों को और मशीनों, मोटर-गाड़ियों के पुर्जों, औषधीय रासायनिक पदार्थों, उपकरणों और साधनों पर निर्यात कर बढ़ाकर आयात प्रतिस्थापन के लिए उत्पादन करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। (फिर भी, प्रायोजनाओं की प्रारंभिक स्थापना और वर्तमान प्रायोजनाओं के पर्याप्त विस्तार के लिए आवश्यक आयातित मशीनों के मामले में कतिपय छूटें दी गयीं)।

27. औद्योगिक उत्पादन के मामले में उत्पादन व्यय में हुई वृद्धि की पूर्ति करने के उद्देश्य से मूल्य बढ़ाने की अनुमति दी गयी। इसात के कारखानों में सुधार और नवीकरण का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया और कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन को मांग के बबलते स्वरूप के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से संतुलन-उपकरण लगाया जा रहा है। रांची में भारी इंजीनियरी प्रायोजनाओं और तिरुचि तथा हैदराबाद में जलविद्युत संयंत्रों के पूर्ण हो जाने के कारण इसात बनाने और बिजली के उत्पादन के लिए अपेक्षित उपकरणों के अनुपात में बेशी उत्पादन होने की संभावना बढ़ गयी है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और रिजर्व बैंक ने पूंजीगत माल के उत्पादन और आस्थ-गित अदायगी के आधार पर किये जाने वाले पूंजीगत माल के निर्यात तथा आस्थागित अदायगी के आधार पर बेशी मशीनों की खरीद के लिए मियादी वित्त की सहायता प्रदान करने की जो योजनाएं बनायी थीं आलोच्य वर्ष में जारी रही।

28. औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए एक सशक्त और व्यापक औद्योगिक लाइसेंसिकरण नीति बनायी गयी है। नई औद्योगिक लाइसेंसिकरण नीति के अन्तर्गत महत्वपूर्ण उद्योगों की एक सूची होगी जिसमें अर्थव्यवस्था के मूल, नाजुक और समस्यास्पद उद्योग होंगे। महत्वपूर्ण क्षेत्र के अलावा, 5 करोड़ रुपये से अधिक राशि का निवेश किए जाने के सभी नये प्रस्तावों के संबंध में यह समझा जायेगा कि वे प्रस्ताव भारी निवेश क्षेत्र के लिए हैं। सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों को छोड़कर बड़े औद्योगिक संस्थानों, विदेशी संस्थाओं और विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियों या शाखाओं को महत्वपूर्ण तथा भारी निवेश क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करने में भाग लेने और अपना योग देने की अनुमति दी जायेगी। एक करोड़ रुपये से पांच करोड़ रुपये तक के निवेश वाले मझौले क्षेत्र में बड़े औद्योगिक संस्थानों से भिन्न पाटियों के लाइसेंस संबंधी आवेदनों पर विशेष रूप से विचार किया जाएगा और उन मामलों को छोड़कर जहाँ विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं के कारण सावधानी से छानबीन करनी पड़ती हो अन्य मामलों में उदारतापूर्वक लाइसेंस दिये जायेंगे। जहाँ एक करोड़ रुपये या उससे कम राशि के निवेश के साथ नये यूनिट स्थापित किये जाते हैं या वर्तमान यूनिटों का विस्तार किया जाता है वहाँ अधिनियम के अधीन लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। लघु क्षेत्र के लिए उद्योगों को आरक्षित करने की वर्तमान नीति को जारी रखा जाएगा और आरक्षण के क्षेत्र को उन उद्योगों तक बढ़ाया जायेगा जहाँ बढ़ती हुई मांग की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति करने की प्रत्यक्षा इस लघु क्षेत्र से की जा सकती हो। लाइसेंसिकरण-नीति में किये गये इस परिवर्तन तथा प्रशासन क्षमता में किये गये सुधार के कारण औद्योगिक संस्थाओं और नये उद्योगियों के लिए शीघ्र उद्योगों की स्थापना करना और उत्पादन क्षमता को बढ़ाना संभव होगा। आलोच्य वर्ष की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् गैर-सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक संस्थाओं को कई लाइसेंस दिये गये हैं ताकि वे अपनी औद्योगिक क्षमता को बढ़ा सकें और अपने उत्पादन में, विशेषकर रासायनिक उर्वरकों, एल्यूमीनियम, हिमकारक और शीतकारक मशीनों, वाहक सोडा, संयोजन मशीनों जूट की फस की पट्टी, डबल रोटी और बिस्कुट तैयार करने वाली और डिब्बाबंदी की मशीनों के उद्योग क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि कर सकें।

29. सरकार ने मार्च 1970 में एक अलग औद्योगिक सागत व मूल्य म्युरो की स्थापना की जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह औद्योगिक मूल्यों को निर्धारित करने और बदलने तथा औद्योगिक क्षेत्र की सागत-मूल्य संबंधी प्रवृत्ति पर निगरानी रखने में सरकार की सहायता करे। 1 जून 1970 से अमल में आये एकाधिकार और प्रतिबंधक व्यापार प्रणाली अधिनियम, 1969 से स्वस्थ औद्योगिक प्रणालियों के भी व्यवहार में आने की संभावना है।

बजट संबंधी गतिविधियाँ@

30. 1969-70* के राजकोषीय वर्ष में बजट संबंधी प्रवृत्तियाँ इस प्रकार थीं; केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की राजस्व-प्राप्तियाँ की वृद्धि दर में कमी हुई और उनके राजस्व-वितरणों में सामान्य वृद्धि हुई। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की मिश्रित राजस्व प्राप्तियों में जहाँ 1968-69 में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहाँ 1969-70 में केवल 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी 5)। राजस्व प्राप्तियों

@यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो इस खण्ड में उल्लिखित सारी राशि राजकोषीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) से संबंधित है।

*यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो 1969-70 के संवर्ध में दिये हुए सभी आंकड़े परिशोधित अनुमान हैं।

सारणी 5—केन्द्रीय और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियाँ और विवरण

(करोड़ रुपये)

(1)	1968-69 (लेखा)			1969-70(क) (बजट अनुमान)		
	केन्द्रीय	राज्य	जोड़	केन्द्रीय	राज्य	जोड़
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. कुल प्राप्तियाँ (घ—घा)	4047 (—5.0)	3051 (+23.5)	7098 (+5.5)	4434 (+9.6)	3112 (+2.0)	7546 (+6.3)
अ. राजस्व प्राप्तियाँ	2523 (+6.0)	2322(ख) (+17.3)	4845 (+11.1)	2676 (+6.1)	3380(ख) (+2.5)	5056 (+4.3)
उनमें से कर प्राप्तियाँ	2039 (+4.2)	1708(ख) (+14.9)	3727 (+8.9)	2197 (+8.8)	1798(ख) (+5.3)	3995 (+7.2)
भा. पूंजीगत प्राप्तियाँ	1524(ग) (—18.9)	729 (+48.8)	2253 (—4.9)	1758(ग) (+15.4)	732 (+0.4)	2490 (+10.5)
II. कुल वितरण	3742 (+1.1)	3630 (+10.8)	7372 (+5.7)	4209 (+12.5)	3930 (+8.3)	8139 (+10.4)
उसमें से विकास परियोजना	817 (+9.2)	2110 (+17.5)	2927 (+15.1)	1047 (+28.2)	2300 (+9.0)	3347 (+14.3)
(क) राजस्व	318 (+12.4)	1595 (+16.5)	1913 (+15.8)	373 (+17.3)	1839 (+15.3)	2212 (+15.6)
(ख) पूंजी	499 (+7.3)	515 (+20.9)	1014 (+13.8)	674 (+35.1)	461 (—10.5)	1135 (+11.9)
योजना परियोजना			2461(घ) (+7.1)			2271(घ) (—3.8)
विकासोत्तर परियोजना (क—ख)	1754 (—14.2)	1003 (—4.7)	2757 (—8.2)	2048 (+16.8)	1100 (+9.7)	3148 (+14.2)
(क) राजस्व	1825 (+7.7)	993 (+10.6)	2818 (+8.7)	1953 (+7.0)	1124 (+13.2)	3077 (+9.2)
(ख) पूंजी	—71 (—83.3)	10 (—83.3)	—61 (—83.3)	95 (—83.3)	—24 (—83.3)	71 (—83.3)
III. कुल अधिशेष (+) या घाटा (—) (I-II)	305	—579	—274(ङ)	+225	—818	—593(ङ)

नोट:—(i) आंकड़े अंतर-सरकारी अंतरणों के लिए समायोजित किये गये हैं; अतः बजट वस्तावेजों और सारणी 6 में दिये गये आंकड़ों से वे भिन्न हैं किन्तु समय रूप से संयुक्त स्थिति अपरिवर्तित है।

(ii) कोष्ठकों आंकड़ों से पिछले वर्ष की तुलना में हुई प्रतिशत वृद्धि (+) या कमी (—) का पता चलता है।

(क) बजट प्रस्तावों का प्रभाव शामिल है।

(ख) केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा शामिल है।

सारणी 5—केंद्रीय और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियाँ और विवरण—(जारी)

(करोड़ रुपये)

	1969-70 (परिणोधित अनुमान)			1970-71(क) (बजट अनुमान)		
	केन्द्रीय	राज्य	जोड़	केन्द्रीय	राज्य	जोड़
I. कुल प्राप्तियाँ (घ+भा)	4621 (+ 14.2)	3285 (+ 7.0)	7886 (+ 11.1)	4691 (+ 1.5)	3538 (+ 8.4)	8229 (+ 4.3)
प्र. राजस्व प्राप्तियाँ	2652 (+ 5.1)	2564(ख) (+ 10.4)	5216 (+ 7.6)	2962 (+ 11.7)	8050(ख) (+ 11.2)	5812 (+ 11.4)
उनमें से कर-प्राप्तियाँ]	2110 (+ 4.5)	1927(ख) (+ 12.8)	4037 (+ 8.3)	2390 (+ 13.3)	2168(ख) (+ 12.5)	4558 (+ 12.9)
भा. पूँजीगत प्राप्तियाँ	1969(ग) (+ 29.2)	701 (— 3.8)	2670 (+ 18.5)	1729(ग) (— 12.2)	688 (— 1.7)	2417 (— 9.4)
II. कुल वितरण	4251 (+ 13.6)	4071 (+ 12.1)	8322 (+ 12.9)	4514 (+ 6.2)	4077 (+ 0.1)	8591 (+ 3.2)
उसमें से विकास परिषद	1020 (+ 24.8)	2317 (+ 9.8)	3337 (+ 14.0)	1152 (+ 12.9)	2472 (+ 6.7)	3624 (+ 8.6)
(क) राजस्व	367 (+ 15.4)	1803 (+ 13.0)	2170 (+ 13.4)	425 (+ 15.8)	1912 (+ 6.0)	2337 (+ 7.7)
(ख) पूँजी	653 (+ 30.9)	514 (— 0.2)	1167 (+ 15.1)	727 (+ 11.3)	560 (+ 8.9)	1287 (+ 10.3)
योजना परिषद			2239(घ) (— 5.2)			2637(घ) (+ 17.8)
विकासोत्तर परिषद (क ख)	2095 (+ 19.4)	1184 (+ 18.0)	3279 (+ 18.9)	2158 (+ 3.0)	1115 (— 5.8)	3273 (— 0.2)
(क) राजस्व	1976 (+ 8.3)	1217 (+ 22.6)	3193 (+ 13.3)	2042 (+ 3.3)	1157 (— 4.9)	3199 (+ 0.2)
(ख) पूँजी	119	— 33	86	116 (— 2.5)	— 42	74 (— 14.0)
III. कुल अधिशेष (+) या घाटा (—)	+ 370	— 806	436(ङ)	+ 177	— 537	— 362(ङ)
(I-II)						

(ग) खजाना बिल प्राप्तियाँ (वास्तविक) शामिल नहीं हैं।

(घ) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, और संघनामित क्षेत्रों का योजना परिषद शामिल है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार के बकाया खजाना बिलों में हुई वास्तविक वृद्धि, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के नकदी बकायों का माहुरण, राज्य सरकारों द्वारा अपने नकदी बकाया निवेश लेखों में रखी गयी प्रतिभूतियों की वास्तविक वृद्धि और राज्यों की प्रारम्भित राजस्व निधियों से किये गये वास्तविक अंतरण के आधार पर।

की वृद्धि दर में जो कमी पायी गयी वह मुख्यतः करतार राजस्वों के संवर्धन में हुई। करतार प्राप्तियों में जो वृद्धि हुई उसकी दर 1969-70 में 5.4 प्रतिशत थी जबकि वह 1968-69 में 19.2 प्रतिशत थी। कर-प्राप्तियों की वृद्धि-दर जहाँ 1968-69 में 8.9 प्रतिशत थी वहाँ 1969-70 में थोड़ी-सी कम होकर 8.3 प्रतिशत हो गयी। इसका प्रमुख कारण यह था कि इस वर्ष (क्रमशः तीसरा वर्ष) सीमा-शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व में कमी हुई और साथ ही भू-राजस्व में भी कमी हो गयी। किन्तु पूँजीगत लेख पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्ति में 1969-70 में 18.5 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि 1968-69 में उसमें 4.9 प्रतिशत की कमी हुई थी।

31. 1969-70 में राजस्व वितरणों में जो वृद्धि हुई (12.9 प्रतिशत) वह राजस्व प्राप्ति में हुई वृद्धि की तुलना में अधिक की यद्यपि वितरणों में हुई उक्त वृद्धि 1968-69 में हुई वृद्धि (11.9 प्रतिशत) की तुलना में विशेष अधिक नहीं थी। 1969-70 में राजस्व वितरणों में हुई वृद्धि का कारण विकास व्यय (13.4 प्रतिशत वृद्धि) और विकासेतर व्यय (13.3 प्रतिशत वृद्धि) के अंतर्गत हुई वृद्धि थी।

32. केन्द्रीय सरकार के मामले में 1969-70 में राजस्व लेख में हुए विकास व्यय में हुई वृद्धि (15.4 प्रतिशत) विकासेतर व्यय में हुई वृद्धि (8.3 प्रतिशत) की अपेक्षा अधिक थी। किन्तु राज्य सरकारों के मामले में विकास व्यय में हुई वृद्धि (13.0 प्रतिशत) की अपेक्षा विकासेतर व्यय में तेजी से वृद्धि (22.6 प्रतिशत) हुई। सूखे और बाढ़ से पीड़ित राज्यों में अकाल-राहत व्यय के लिए जो व्यवस्था की थी वह इस वृद्धि का विशेष कारण थी। अकाल राहत-व्यय के लिए जहाँ 1967-68 में 87 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी वहाँ वह 1968-69 में थोड़ी सी बढ़कर 90 करोड़ रुपये हो गयी थी। किन्तु उक्त राशि 1969-70 में में बहुत अधिक बढ़कर 154 करोड़ रुपये तक पहुँच गयी।

33. पूँजीगत लेख पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त वितरणों की राशि में 1969-70 में 12.9 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि 1968-69 में उसमें 4.1 प्रतिशत कमी हुई थी।

34. 1969-70 के बजट अनुमानों की तुलना में केन्द्रीय सरकार के कुल वितरण की राशि में परिशोधित अनुमानों में 221 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई अर्थात् उक्त राशि बढ़कर 5776 करोड़ रुपये हो गयी। उसकी कुल प्राप्ति की राशि में 185 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई अर्थात् वह राशि बढ़कर 5486 करोड़ रुपये हो गयी (सारणी 6)। राज्य सरकारों के मामले में 1969-70 में प्राप्ति की राशि 4790 करोड़ रुपये थी जो बजट अनुमान की तुलना में 332 करोड़ रुपये अधिक थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अधिक मात्रा में वित्तिय साधनों का अंतरण किया (सारणी 7)। किन्तु राज्य सरकारों द्वारा वितरित की गयी कुल राशि 4936 करोड़ रुपये थी जो बजट व्यवस्था से केवल 139 करोड़ रुपये अधिक थी। यह वृद्धि मुख्यतः विकासेतर कार्यों और ऋणों तथा अभिषेक के अंतर्गत हुई।

35. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के 1969-70 के बजट अनुमानों के अनुसार समूचे घाटे की राशि (केन्द्रीय सरकार के बकाया खजाना बिलों में हुई वास्तविक वृद्धि, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के नकदी बकायों से किये गये ग्राहण, राज्य सरकारों द्वारा अपने नकदी बकाया लेखें निबश में रखी गयी प्रति-भूतियों की वास्तविक बिक्री और राज्य सरकारों की प्रारक्षित राजस्व निधियों से किये गये वास्तविक अंतरण के आधार पर (593 करोड़

रुपये थी। 1969-70 के परिशोधित अनुमानों के अनुसार समग्र घाटे की राशि 436 करोड़ रुपये थी जबकि 1968-69 में उक्त राशि 274 करोड़ रुपये थी। 1969-70 में बजट अनुमानों की तुलना में राज्य सरकारों के घाटे की राशि 339 करोड़ रुपये से घटकर 146 करोड़ रुपये हो गयी और केन्द्रीय सरकार के घाटे की राशि 254 करोड़ रुपये से बढ़कर 290 करोड़ रुपये हो गयी।

36. इस प्रकार केन्द्रीय सरकार के घाटे की राशि के बढ़ने और राज्य सरकारों के घाटे की राशि के कम होने का प्राथमिक कारण यह था कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को ऋणों और विभाज्य करों के रूप में अंतरित किये गये वित्तीय साधनों की मात्रा में बजट अनुमानों की अपेक्षा काफी वृद्धि हुई। राज्य सरकारों को दिये गये ऋणों में जो वृद्धि हुई उसका यह कारण था कि सूखे और बाढ़ों से प्रभावित राज्यों को अधिक ऋण दिये गये और राज्यों के वित्तीय साधनों में विद्यमान अंतर को पूरा करने के लिए उन्हें विशेष सहायता दी गयी। विभाज्य करों में जो वृद्धि हुई वह जुलाई 1969 में पेश की गयी पाँचवें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन का प्रमुख परिणाम थी।

सारणी 6—केन्द्रीय सरकार की समग्र बजट स्थिति

	(करोड़ रुपये)		
	1969-70 (बजट अनुमान)	1969-70 (परिशोधित अनुमान)	1970-71* (बजट अनुमान)
I. कुल प्राप्तियाँ (ग्र + ब्रा) .	5301	5486	5450 (5573)
अ. राजस्व प्राप्तियाँ .	2957	2924	3118 (3241)
उनमें से कर प्राप्तियाँ	2196	2110	2267 (2390)
ब्रा. पूँजीगत प्राप्तियाँ .	2344	2562	2332
उनमें से देशी ऋण (कुल)	500	535	455
विदेशी ऋण (कुल)	850	714	719
II. कुल वितरण	5555	5776	5800
उसमें से			
(क) विकास परिष्वय	1047	1020	1152
(ख) विकासेतर परिष्वय	2048	2095	2158
(ग) देशी ऋणों का भुगतान .	394	394	293
(घ) विदेशी ऋणों का भुगतान	208	180	200
III. समग्र घाटा (I-II)	264	290	350 (127)

नोट :—इस सारणी में प्राप्तियों और वितरणों के जो प्रांकड़े दिये गये हैं वे अंतर-सरकारी अंतरणों के लिए समायोजन किये जाने के कारण सारणी 5 के प्रांकड़ों से मेल नहीं खाते।

*फोण्टकों के प्रांकड़े कर संबंधी प्रतिरिक्त उपायों से अनुमानित प्राप्त होने वाली राशि को हिसाब में लेने के बाद निकाले गये हैं।

सारणी 7--राज्य सरकारों की समग्र बजट स्थिति

	(करोड़ रुपये)		
	1969-70 (बजट अनुमान)	1969-70 (परिणोधित अनुमान)	1970-71* (बजट अनुमान)
I. कुल प्राप्तियाँ (अ+आ)	4458	4790	4753 (4824)
अ. राजस्व प्राप्तियाँ (i+ii)	2934	3131	3315 (3384)
उनमें से			
(i) राज्य सरकारों की निजी राजस्व प्राप्तियाँ	1863	1953	2099 (2123)
(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अंतरित की गयी वित्तीय राशि (क+ख)	1071	1178	1216 (1261)
(क) करों में हिस्सा	517	611	682 (727)
(ख) केन्द्रीय सरकार से अनुदान	554	567	534
आ. पूंजीगत प्राप्तियाँ (i+ii)	1524	1659	1440
(i) राज्य सरकारों की पूंजीगत प्राप्तियाँ उनमें से बाजार ऋण (कुल)	732	701	688 143
(ii) केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण (कुल)	792	958	752
II. कुल वितरण	4797	4936	4959
उसमें से			
(क) विकास परियोजना	2300	2317	2472
(ख) विकासोत्तर परियोजना	1381	1456	1394
(ग) केन्द्रीय सरकार की ऋणों की वापसी अदायगी	586	593	603
(घ) अन्य पाठियों की ऋण और अधिम	378	433	381
(ङ) बाजार ऋणों की वापसी अदायगी	89	89	62
III. समग्र घाटा	339	146	204 (135)

नोट:- इस सारणी में प्राप्तियाँ और वितरणों के जो आंकड़े दिये गये हैं वे अन्तर-सरकारी अंतरणों के लिए समायोजन किये जाने के कारण सारणी 5 के आंकड़ों से मेल नहीं खाते।
*कोषों के आंकड़ों पर संबंधी अतिरिक्त उपायों से अनुमानित प्राप्त होने वाली राशि को हिमाब में लेने के बाद निकाले गये हैं।

37. राज्य सरकारों को दिये जाने वाले ऋणों और विभाज्य करों में राज्य सरकारों के हिस्से में वृद्धि कर दिये जाने के कारण केन्द्रीय सरकार के वित्तीय साधनों पर जो तनाव आया उसे एक और करेतर राजस्व में हुई वृद्धि, बेसी बाजार से लिये गये ऋणों और विविध पूंजीगत प्राप्तियों से और दूसरी ओर विकास तथा रक्षा के अधीन किये जाने वाले वितरणों, व्याज की वास्तविक अदायगियों और राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों में बचत कर के काफ़ी हद तक पूर कि गया।

38. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के 1969-70 के वास्तविक घाटे की राशि का परिमाण अभी उपलब्ध नहीं है। फिर भी रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को दिये गये कुल ऋण की राशि से संभावित वास्तविक घाटे की राशि का संकेत मिलता है; ऐसे ऋण की राशि में 1969-70 के राजकोषीय वर्ष में 12.70 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। जब कि 1968-69 में उसमें 241.89 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार को दिये गये वास्तविक ऋण की राशि में 1968-69 के 128.63 करोड़ रुपये की तुलना में 1969-70 में 81.16 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई; राज्य सरकारों को दिये गये वास्तविक ऋण की राशि में पिछले वर्ष की 113.28 करोड़ रुपये की वृद्धि के विपरीत इस वर्ष 68.46 करोड़ रुपये की कमी हुई। इसके अलावा रिजर्व बैंक के पास मार्च 1970 के अंत तक कतिपय राज्य सरकारों के बकाया ओवरड्राफ्ट थे यद्यपि कुल बकाया ओवरड्राफ्टों का परिमाण मार्च 1969 के अंत के स्तर से कम नहीं था।

39. 31 मार्च से जून 1970 के अन्त (अन्तिम शुक्रवार) तक की अवधि में सरकारी क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये वास्तविक ऋण की राशि में 89 करोड़ रुपये की कमी हुई जब कि 1969 की तदनुसूची अवधि में उसमें 7 करोड़ रुपये की कमी हुई थी। 31 मार्च 1970 से जून 1970 के अन्त तक की अवधि में रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार को दिये गये वास्तविक ऋण की राशि में (31 मार्च 1969 से जून 1969 के अन्त तक की अवधि में हुई 185 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में) 10 करोड़ रुपये की कमी हुई और राज्य सरकारों को दिये गये ऋण की राशि में (पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में हुई 192 करोड़ रुपये की कमी की तुलना में) 79 करोड़ रुपये की कमी हुई।

40. केन्द्रीय सरकार का 1970-71 बजट अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों की उस पृष्ठभूमि में बनाया गया जिसमें आर्थिक विकास की वृद्धि के लिए सक्षम प्रयत्न करना सम्भव था। चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् 1969-70 में आय में 5 प्रतिशत और 5.5 प्रतिशत (स्थिर मूल्यों के अनुसार) के बीच वृद्धि होने की जो प्रत्याशा की जाती है वह चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए परिकल्पित वृद्धि दर के बराबर है। आय वृद्धि की गति को बनाये रखने के लिए बजट में विशेषकर पूंजी-निर्माण करनेवाले विकासोत्तर परियोजना के परिमाण में पर्याप्त वृद्धि कर दी गयी है। कुल पूंजी-निर्माण के लिए बजट में जो व्यवस्था की गयी है वह 1969-70 की अपेक्षा 13 प्रतिशत अधिक है। इसके विपरीत, यह अनुमान लगाया गया है कि 1970-71 में उपभोग-व्यय में 1969-70 की अपेक्षा 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी जबकि 1969-70 में 1968-69 की तुलना में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे ऐसी वृद्धियों को उचित सीमा के भीतर बनाये रखने की सरकार की नीति का पता चलता है। इसके परिणामस्वरूप यह आशा की जाती है कि राजस्व प्राप्तियों के रूप में सरकारी प्रशासन की जो बचत होती है उसमें जहाँ 1969-70 में 2.7 प्रतिशत वृद्धि हुई थी वहाँ 1970-71 में 7.6 प्रतिशत वृद्धि होगी। यह प्रत्याशा की जाती

है कि सरकार की वास्तविक बचतों से, जिनमें विभागीय वाणिज्यिक संस्थाओं की बचतें भी शामिल हैं, 1970-71 में सरकारी और विभागीय वाणिज्यिक संस्थाओं के वास्तविक निवेश के 66.4 प्रतिशत की वित्तीय व्यवस्था की जाएगी जब कि 1969-70 में 33.9 प्रतिशत की व्यवस्था हुई थी। बजट में परिकल्पना की जो परिकल्पना की गयी है उससे इस बात का पता चलता है कि सरकार को न केवल स्थायिता सहित विकास करने की चिन्ता है, बल्कि समाज के अभावग्रस्त और गरीब वर्गों के कल्याण की भी चिन्ता रहती है। अभावग्रस्त और गरीब वर्गों के कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए छोटे किसानों और कृषि श्रमिकों के हित के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों, ग्रामीण जल-पूर्ति योजनाओं, बच्चों के लिए पीथिक भ्रातृ सम्बन्धी कार्यक्रमों और औद्योगिक कामगारों तथा विशेषकर सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों की व्यवस्था की गयी है।

41. यह अनुमान लगाया गया है कि 1970-71 के राजस्व और पूंजीगत लेखों से प्राप्त कुल राशि (अतिरिक्त कर-उपायों से प्राप्त भाग को मिलाकर) 5,573 करोड़ रुपये होगी अर्थात् उसमें 1969-70 की तुलना में 87 करोड़ रुपये (1.6 प्रतिशत) की वृद्धि होगी। चूंकि वितरित की जाने वाली 5800 करोड़ रुपये की कुल राशि से 1969-70 की तुलना में केवल 24 करोड़ रुपये (0.4 प्रतिशत) की वृद्धि होने का पता चलता है अतः यह अनुमान है कि समग्र घाटे की राशि 227 करोड़ रुपये होगी जो 1969-70 के 290 करोड़ रुपये के घाटे की तुलना में 63 करोड़ रुपये कम है। यह प्रत्याशा की जाती है कि 1970-71 में समग्र घाटे की राशि कुल वितरणों का 3.9 प्रतिशत होगी जब कि वह 1969-70 में कुल वितरणों का 5.0 प्रतिशत थी।

42. 1970-71 के लिए राज्य सरकारों के बजट में राजस्व (कराधान की 1969-70 की दरों के अनुसार) तथा पूंजीगत लेखों पर 4,755 करोड़ रुपये की प्राप्ति की व्यवस्था की गई है। यह राशि 1969-70 की राशि की तुलना में 35 करोड़ रुपये (0.7 प्रतिशत) कम है। यह कमी केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकारों को अतिरिक्त किये जाने वाले वित्तीय स्रोतों की कुल मात्रा में प्रत्याशित की गयी कमी और राज्य सरकारों के अपने ही वित्तीय स्रोतों में वृद्धि करने का परिणाम है। 4,959 करोड़ रुपये की कुल वितरण राशि 1969-70 की तुलना में 23 करोड़ रुपये अधिक है। विकास व्यय की राशि में जहां 155 करोड़ रुपये (6.7 प्रतिशत) की वृद्धि की गयी है वहां विकासोत्तर व्यय में 62 करोड़ रुपये (4.3 प्रतिशत) और ऋणों और ऋणियों में 52 करोड़ रुपये (12.0 प्रतिशत) की कमी की गयी है। राज्य सरकारों के निजी वित्तीय साधनों से 1970-71 में कुल वितरणों के 56.2 प्रतिशत की व्यवस्था होगी जब कि 1969-70 में 53.8 प्रतिशत की व्यवस्था हुई थी। बजट में 204 करोड़ रुपये के समग्र घाटे की राशि निर्धारित है जो 1969-70 के स्तर से 58 करोड़ रुपये अधिक है। राजस्व लेखों पर 15 करोड़ रुपये के अधिशेष और पूंजीगत लेखों पर 219 करोड़ रुपये के घाटे से यह समग्र घाटा बना है। समग्र घाटे के एक अन्श की पूर्ति करने के लिए राज्य सरकारों ने अतिरिक्त कर लगाने का विचार किया है जिनसे 1970-71 में 24 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है। इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा अमल में लायी गयी अतिरिक्त कर व्यवस्थाओं के कारण राज्य सरकारों को उनके हिस्से के रूप में 45 करोड़ रुपये मिले और राज्य सरकारों को बाजार ऋणों से बजट अनुमानों की अपेक्षा 2 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त हुए। वे भी घाटे की पूर्ति करने में सहायक होंगे। इनसे बजट में परिकल्पित समग्र घाटे की राशि कम होकर 133 करोड़ रुपये हो जाएगी। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार के कर्जों से राज्यों के हिस्से के रूप में प्राप्त राशि, केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान और

ऋणों के संदर्भ में राज्य सरकारों के बजटों में जो व्यवस्था की गयी वह केन्द्रीय सरकार के बजट में की गयी व्यवस्था की तुलना में 171 करोड़ रुपये कम है। इसके लिए व्यवस्था करने पर राज्य सरकारों की बजट-स्थिति से यह संकेत मिलता है कि 1970-71 में 38 करोड़ रुपये का समग्र अधिशेष होगा जब कि 1969-70 में 146 करोड़ रुपये का समग्र घाटा हुआ था।

43. पिछली रिपोर्ट में 1969-70 से 1973-74 तक के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के परिशोधित मसौदे के संसद में पेश किये जाने का उल्लेख किया गया था। योजना का अन्तिम दस्तावेज 18 मई 1970 को संसद में पेश किया गया। उसका अन्तिम रूप सरकार की नयी सामाजिक-आर्थिक नीतियों के अनुरूप बनाया गया है और वह विकास की स्थायिता और सामाजिक न्याय के लक्ष्य की पूर्ति करता है। अन्तिम योजना में कुल परिकल्पना की राशि में 484 करोड़ रुपये की वृद्धि कर दी गयी है अर्थात् प्रासंग्य योजना में जहां 24,398 करोड़ रुपये के परिकल्पना की व्यवस्था थी वहां उसे अन्तिम योजना में बढ़ाकर 24,882 करोड़ रुपये कर दिया गया है। कुल परिकल्पना में सरकारी क्षेत्र के हिस्से की राशि में 1504 करोड़ रुपये की वृद्धि की गयी है अर्थात् उसे प्रासंग्य योजना में परिकल्पित 14,398 करोड़ रुपये (59 प्रतिशत) से बढ़ाकर 15,902 करोड़ रुपये (64 प्रतिशत) बना दिया गया है और गैर सरकारी क्षेत्र के हिस्से की राशि में 1,020 करोड़ रुपये की कमी कर उसे 10,000 करोड़ रुपये (41 प्रतिशत) से 8,980 करोड़ रुपये (36 प्रतिशत) कर दिया गया है।

44. सरकारी क्षेत्र के 15,902 करोड़ रुपये के कुल परिकल्पना की राशि में से केन्द्रीय सरकार (संघ शासित क्षेत्रों और केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित योजनाओं को मिलाकर) और राज्य सरकारों के परिकल्पना की राशि क्रमशः 9,296 करोड़ रुपये और 6,606 करोड़ रुपये हैं जो प्रासंग्य योजना में मंजूर की गयी परिकल्पना राशि (क्रमशः 8,332 करोड़ रुपये और 6,066 करोड़ रुपये) से अधिक है।

45. सरकारी क्षेत्र के परिकल्पना में निवेश के 13,665 करोड़ रुपये और बाह्य व्यय के 2,247 करोड़ रुपये शामिल हैं। यदि धोखाधड़ी देखा जाए तो कृषि और तत्सम्बन्धी क्षेत्रों (सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण को मिलाकर) और बिजली आयोजनाओं पर होने वाले परिकल्पना का हिस्सा थोड़ा-सा बढ़कर क्रमशः 24 प्रतिशत और 16 प्रतिशत हो गया। वह कुल परिकल्पना का क्रमशः 22 प्रतिशत और 14 प्रतिशत था। इसके विपरीत उद्योगों और खनिज पदार्थों, परिवहन और संचार साधनों तथा समाज सेवाओं पर होने वाले परिकल्पना का हिस्सा क्रमशः 21 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 16 प्रतिशत था जब कि उक्त हिस्सा प्रासंग्य योजना में उद्योगों और खनिज पदार्थों तथा परिवहन और संचार साधनों में से प्रत्येक पर 22 प्रतिशत और समाज सेवाओं पर 17 प्रतिशत निर्धारित था। परिकल्पना का शेष तीन प्रतिशत फुटकर मर्चों के अधीन निर्धारित था; प्रासंग्य योजना में भी लगभग उतना ही प्रतिशत निर्धारित था।

46. सरकारी क्षेत्र के परिकल्पना में जो वृद्धि हुई उसके कारण इस प्रकार थे; प्रासंग्य योजना में 10,839 करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की गयी थी वह बढ़कर 11,854 करोड़ रुपये हो गयी; अतः बजट के वित्तीय स्रोतों (कराधान की 1968-69 की दरों के अनुसार) में वृद्धि हुई और अतिरिक्त जमा राशि जुटाने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित था उसे अन्तिम योजना में 2,709 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,198 करोड़ रुपये कर दिया गया; उक्त राशि में 2,100 करोड़ रुपये और 1,098 करोड़ रुपये क्रमशः केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अंश थे। घाटे की वित्तीय व्यवस्था की मात्रा को प्रासंग्य योजना में

सारणी 8—चौथी योजना के वित्तीय साधनों के अनुमान
(1969-74)

(करोड़ रुपयों में)

	प्रारूप योजना		अन्तिम योजना	
	राशि	जोड़ में प्रतिशत	राशि	जोड़ में प्रतिशत
I 1968-69 की काराधान बतों के अनुसार बजट में दिये गए वित्तीय साधन (1+2)	10,839	75.3	11,854	74.5
1. बजट में दिये गये देशी वित्तीय साधन (1 से 10 तक)	8,325	57.8	9,240	58.1
(1) चालू राजस्वों का बकाया	2,455	17.1	1,673	10.5
(2) सरकारी उद्यमों का अंशदान	1,730	12.0	2,029	12.8
(3) रिजर्व बैंक के रख लिये गये लाभ	165	1.1	202	1.3
(4) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बाजार से लिये गये उधार (वास्तविक)	1,166	8.1	1,415	8.9
(5) भारतीय खाद्य निगम और वित्तीय संस्थानों द्वारा लिये गये उधार	—	—	405	2.5
(6) अल्प बचतें	800	5.6	769	4.8
(7) वार्षिकी जमा, अनिवार्य जमा, इनामी बांड और स्वर्ण बांड	—104	—0.7	—104	—0.7
(8) राज्य भविष्य निधियां	640	4.4	660	4.2
(9) विविध पूंजीगत प्राप्तियां (वास्तविक)	1,130	7.8	1,685	10.6
(10) जीवन बीमा निगम आदि से ऋण और राज्य उद्यमों द्वारा बाजार से लिये गये उधार (कुल)	343	2.4	506	3.2
2. विदेशी सहायता (वास्तविक)	2,514	17.5	2,614	16.4
II संचित अतिरिक्त वित्तीय साधन	2,709	18.8	3198	20.1
III घाटों की वित्त व्यवस्था	850	5.9	850	5.4
IV योजना के कुल वित्तीय साधन (I+II+III)	14,398	100.0	15,902	100.0

स्रोत : योजना आयोग, भारत सरकार, चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारूप और अन्तिम

परिकल्पित स्तर अर्थात् 850 करोड़ रुपयों तक ही रखा गया है। सरकारी क्षेत्र के परिव्यय की वित्तीय व्यवस्था का स्वरूप सारणी 8 में दिया गया है।

47. 1969-70 के लिए सरकारी क्षेत्र के योजनागत परिव्यय के लिए 1969-70 के 2,301 करोड़ रुपयों की तुलना में 2,239 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये; यह राशि पिछले वर्ष की अपेक्षा 122 करोड़ रुपये (5.2 प्रतिशत) कम थी। 1970-71 के लिए योजनागत परिव्यय की राशि 2,637 करोड़ रुपये निर्धारित थी जो 1969-70 के योजनागत परिव्यय की राशि की अपेक्षा 398 करोड़ रुपये या 18 प्रतिशत अधिक थी। इस प्रकार पहले दो वर्षों के कुल परिव्यय की राशि चौथी योजना में सरकारी क्षेत्र के परिव्यय के लिए परिकल्पित कुल राशि का 21 प्रतिशत होती है। योजनागत दस्तावेजों में 1968-69 के मूल्यां के अनुसार परिव्ययों की राशि दी गयी है। फिर भी 1969-70 (अप्रैल-मार्च) में थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (आधार 1961-62=100) में 4.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के कारण योजनागत परिव्ययों में वास्तविक कमी होगी।

48. यह अनुमान है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त जमा राशि जुटाने के संदर्भ में किये गये उपायों (डाक शुल्कों, रेल यात्री किरायों और माल भाड़ों में किये गये परिवर्तनों को मिलाकर) से 1970-71 में 202.5 करोड़ रुपयों की राशि प्राप्त होगी। इसमें 1970-71 में किये गये कर सम्बन्धी उपायों के कारण प्राप्त होनेवाले 168.3 करोड़ रुपये (राज्यों का अंश मिलाकर), रेलयात्री-किरायों और माल भाड़ों में वृद्धि करने के कारण प्राप्त होने वाले 26 करोड़ रुपये और डाक और तार शुल्कों में किये गये परिवर्तनों के कारण प्राप्त होने वाले 8.2 करोड़ रुपये शामिल हैं। नूक आय और सम्पत्ति

कर के सम्बन्ध में किये गये कतिपय संशोधन 1971-72 से पूर्णतः प्रमल में आयेगे अतः यह अनुमान लगाया गया है कि इस प्रकार प्राप्त होने वाली राशि बढ़कर अगले वर्ष 223.5 करोड़ रुपये होगी। राज्य सरकारों द्वारा 1970-71 के लिए प्रस्तावित कर सम्बन्धी उपायों से 1970-71 में अनुमानतः 23.7 करोड़ रुपये और पूरे वर्ष में 26.0 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। चौथी योजना के पहले वर्ष, अर्थात् 1969-70 में केन्द्रीय सरकार (रेल विभाग और डाक तथा तार विभाग को मिलाकर) और राज्य सरकारों द्वारा पूरे वर्ष में जुटायी जाने वाली अतिरिक्त जमा राशि अनुमानतः 176.9 करोड़ रुपये होंगी। अतिरिक्त जमा राशि जुटाने के इन सभी उपायों से योजना के पाठ वर्षों के दौरान कुल लगभग 1,850 करोड़ रुपयों (या लक्ष्य का 57.8 प्रतिशत) की राशि प्राप्त होगी; इस राशि में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अंश क्रमशः 1,519 करोड़ रुपये और 331 करोड़ रुपये होंगे।

49. निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए 1970-71 में केन्द्रीय सरकार ने कर सम्बन्धी उपाय किये; आय और सम्पत्ति में अधिक समानता लाना, उपयोग पर नियंत्रण रखना, शहरी-भूमि के मूल्यां के सम्बन्ध में बढ़ती हुई सट्टेबाजी की प्रवृत्ति को रोकना और कर सम्बन्धी विधियों में विद्यमान ऐसी कमियों को दूर करना जिनसे कर से बचने में सुविधा होती है। बचतों और निवेशों के सम्बन्ध में दिये जाने वाले प्रोत्साहनों को उदार बनाने वाले कतिपय उपायों की भी व्यवस्था की गयी है। अतिरिक्त कर सम्बन्धी उपायों से 1970-71 में प्राप्त होने वाले 168.3 करोड़ रुपयों में से केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों से सम्बन्धित प्रस्तावों से प्राप्त होने वाली राशि 133.3 करोड़ रुपये या लगभग 80 प्रतिशत है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों के सम्बन्ध में किये गये प्रस्ताव सामान्यतः अन्तिम उपभोक्ता माणों से सम्बन्धित हैं और वे उपाय इस

बनाये गये हैं कि जहाँ तक हो सके, गमाज के गरीब वर्गों के उपभोग में कोई बाधा न पड़े। पिछले बजट में केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों की विभिन्न दरों को यथामूल्य दरों में परिवर्तित करने की जो नीति अपनायी गयी थी उसे आगे भी जारी रखा गया है। आय कर के सम्बन्ध में 40,000 रुपयों से अधिक आय-वर्गों पर लिये जाने वाले व्याज की सीमांत दरों में वृद्धि की गयी है; आय कर सम्बन्धी छूट की मूल सीमा को बढ़ाकर और नौकरी के उद्देश्य से सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करने वाले करदाताओं की आय में कटौती सम्बन्धी रियायतों देकर कम आय वाले वर्गों को सहायता पहुँचायी गयी है। संपत्ति कर (शहरी भूमि और इमारतों पर लगाये जाने वाले अतिरिक्त संपत्ति कर को मिलाकर) के सम्बन्ध में भी संपत्ति के विभिन्न वर्गों की कर-दरों को बढ़ाया गया है। जहाँ निगम सम्बन्धी कराधान की दरों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है वहाँ कर योग्य आय का हिस्सा लगाते समय मन्तरंजन व्यय और अतिथि-गृह सम्बन्धी व्यय को शामिल न करने की व्यवस्था की गयी है।

50. वचनों और निवेश पर दी जाने वाली रियायतों की और उबार बनाया गया है। कतिपय निवेशों से लाभान्वित और व्याज के रूप में मिलने वाली आय के सम्बन्ध में आय कर के उद्देश्यों के लिए दी जाने वाली छूट की राशि को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है; आस्तियों के चयन की शक्ति को भी व्यापक बना दिया गया है। संपत्ति कर के उद्देश्य के लिए दी जाने वाली छूट की राशि को भी 1.2 लाख रुपयों से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये बना दिया गया है। वित्तीय आस्तियों की जो श्रेणी ऐसी छूट के योग्य हैं उसे व्यापक बनाकर अन्य आस्तियों के साथ उसमें वैकिंग कंपनियों, राज्य वित्तीय निगमों और सहकारी बैंकों में जमा की गयी राशियाँ और सरकारी प्रतिभूतियों और कम्पनी शेयरों को शामिल किया गया है।

51. असम, गुजरात, जम्मू और काश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, नागालैंड, उड़ीसा और तमिलनाडु, इन नौ राज्यों ने अतिरिक्त उपाय करने का प्रस्ताव किया है। राजस्थान और उत्तरप्रदेश ने अतिरिक्त राजस्व तथा रियायतों को बढ़ाने का विचार किया है। इसके विपरीत बिहार और पश्चिम बंगाल ने कर सम्बन्धी रियायतों की घोषणा की है। यह आशा की जाती है कि इन अतिरिक्त उपायों से 1970-71 में 23.7 करोड़ रुपयों और पूरे वर्ष में 26.0 करोड़ रुपयों की आय प्राप्त होगी जबकि 1969-70 में इस प्रकार नये उपायों से (बजट के पश्चात् किये गये उपायों को मिलाकर) प्राप्त हुई आय की अनुमानित राशि 38.3 करोड़ रुपये (पूरे वर्ष में 47.8 करोड़ रुपये) थी।

52. 1969-70 के वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बाजार ऋणों के कार्यक्रमों का परिणाम संतोषजनक था। इस वर्ष मिश्रित वास्तविक प्राप्तियों की राशि 224 करोड़ रुपये थी जो 1968-69 में प्राप्त की गयी वास्तविक राशि (152 करोड़ रुपये) से 72 करोड़ रुपये अधिक है।

53. केन्द्रीय सरकार का ऋण कार्यक्रम 1969-70 में पिछले वर्ष की तरह दो चरणों में समाप्त किया गया। 30 अप्रैल 1969 को जारी किये गये 250 करोड़ रुपयों के 5½ प्रतिशत 1999 ऋण से 275 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, उनमें 107 करोड़ रुपये नकद में और 168 करोड़ रुपये परिवर्तन के रूप में थे। 1 जुलाई 1969 को जारी किये गये 250 करोड़ रुपये के 44 प्रतिशत ऋण 1976 से 260 करोड़ रुपयों की राशि (नकद में 99 करोड़ रुपये और परिवर्तन के रूप में 161 करोड़ रुपये) प्राप्त हुई। जिन ऋणों की अवधि समाप्त हो गयी थी परन्तु जो परिवर्तन के लिए पेश नहीं किये गये थे उन ऋणों की नकदी में वापसी अदायगी (65 करोड़ रुपये) की व्यवस्था करने

पर 1969-70 में केन्द्रीय सरकार को प्राप्त बाजार ऋणों की वास्तविक राशि 141 करोड़ रुपये थी जो 1968-69 की राशि की अपेक्षा 60 करोड़ रुपये अधिक थी।

54. 1 सितम्बर 1969 को पंद्रह राज्य सरकारों ने कुल 155 करोड़ रुपयों के 12 वर्षों की अवधि के 5½ प्रतिशत विकास ऋण जारी किये। जहाँ दो ऋण समूहों पर जारी किये गये वहाँ दूसरे सभी ऋण 50 पैसे के ऋटे पर (अर्थात् 99.50 रु० के निगम मूल्य पर) जारी किये गये। 12 राज्यों के 88 करोड़ रुपयों के दो ऋण, जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी थी, उन राज्यों के सम्बन्धित ऋणों में परिवर्तन के लिए पेश किये गये। सभी ऋणों में अधिक अभिदान किया गया; अधिकांश मामलों में अधिक अभिदान की मात्रा अधिसूचित राशि के 10 प्रतिशत के ऊपर थी। वार्षिक वितरण के बाद स्वीकृत की गयी राशि के 171 करोड़ रुपये थी: उसमें नकदी अभिदान की राशि 125 करोड़ रुपये और परिवर्तन से प्राप्त राशि 46 करोड़ रुपये थी। जिन ऋणों की अवधि समाप्त हुई थी उनके अपरिवर्तित अंश (42 करोड़ रुपये) की नकदी में वापसी अदायगी की व्यवस्था करने के बाद रहने वाली वास्तविक ऋणों की राशि 1968-69 के 70 करोड़ रुपयों की तुलना में इस वर्ष 83 करोड़ रुपये थी।

55. केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने 1969-70 में 224 करोड़ रुपयों के जो कुल वास्तविक बाजार ऋण लिये थे उनमें से जनता (अर्थात् रिजर्व बैंक आफ इण्डिया और राज्य सरकारों को छोड़कर दूसरे निवेशक) द्वारा खरीदी गयी प्रतिभूतियों की राशि 1969-70 में 161 करोड़ रुपये (कुल वास्तविक ऋणों का 72.0 प्रतिशत) थी जबकि 1968-69 में यह राशि 98 करोड़ रुपये (कुल वास्तविक ऋणों का 64.5 प्रतिशत) थी। रिजर्व बैंक द्वारा जनता को छुले बाजार में बेची गयी प्रतिभूतियों की वास्तविक राशि जहाँ 1968-69 में 88 करोड़ रुपये थी वहाँ 1969-70 में कम होकर 18 करोड़ रुपये हो गयी। इस प्रकार जनता द्वारा खरीदी गयी प्रतिभूतियों की राशि 1969-70 में 179 करोड़ रुपये (कुल वास्तविक ऋणों का 80.0 प्रतिशत) थी जबकि उक्त राशि 1968-69 में 186 करोड़ रुपये (कुल ऋणों का 122.3 प्रतिशत) और 1968-69 में 145 करोड़ रुपये (कुल ऋणों का 89.5 प्रतिशत) थी।

56. श्रेष्ठ प्रतिभूतियों के बाजार में सांस्थानिक सहायता के फल-स्वरूप समूचे वर्ष (जुलाई 1969—जून 1970) में स्थायिता बनी रही। सरकारी और अर्ध-सरकारी प्रतिभूतियों का अखिल भारतीय सूचकांक (आधार: 1961-62—100) सामान्य रूप से बढ़कर 99.3 हो गया। केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों का सूचकांक प्रायः 98.9 के आस पास स्थिर रहा परन्तु राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों और अर्ध-सरकारी प्रतिभूतियों के सूचकांकों में क्रमशः लगभग एक अंक और दो अंकों की वृद्धि हुई अर्थात् वे सूचकांक क्रमशः 101.3 और 100.5 हो गये। 1969 के कम कामकाज के समय के शुरू होने के पहले रिजर्व बैंक ने बैंकों के नाम यह निदेश जारी किया कि वे अपने वित्तीय साधनों को बिजली बोर्डों, औद्योगिक वित्त निगम आदि संस्थाओं द्वारा जारी की गयी दीर्घावधि न्यासी प्रतिभूतियों में लगायें ताकि पूंजीगत माल के अनेक उद्योगों के संदर्भ में फिर से मांग बढ़ाई जा सके और कृषि उत्पादन और औद्योगिक विकास को और अधिक प्रोत्साहन दिया जा सके; तदनुसार, बैंकों ने उक्त प्रतिभूतियों में जो निवेश किया उसके कारण इन प्रतिभूतियों में सापेक्षित उपर्युक्त सुधार पाया गया। इसके अलावा, रिजर्व बैंक की खुले बाजार की नीति का लक्ष्य यह था कि बाजार में मुख्यस्थित और सक्रिय व्यापार प्रवृत्तियों को बनाये रखा जाए और व्याज की दरों के सामान्य स्वरूप के अनुरूप उपज के स्वरूप को पुनर्व्यवस्थित किया जाए। इस लेखा वर्ष में खरीदी और बेची गयी

प्रतिभूतियों की राशि क्रमशः 315.3 करोड़ रुपये और 345.3 करोड़ रुपये थी; इसके परिणामस्वरूप वास्तविक बिक्री की राशि 30.0 करोड़ रुपये थी जब कि यह राशि पिछले वर्ष 53.4 करोड़ रुपये थी।

57. 1970-71 के केन्द्रीय सरकार के बजट में देशी बाजार से कुल 455 करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी है जब कि 1969-70 में (कुल) 535 करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त किये गये थे। 1970-71 में जिन ऋणों की अवधि समाप्त हुई उनकी 293 करोड़ रुपये की राशि पिछले वर्ष (394 करोड़ रुपये) की अपेक्षा कम थी। अतः 1970-71 के लिए परिकल्पित 162 करोड़ रुपये की वास्तविक प्राप्तियाँ 1969-70 (141 करोड़ रुपये) की अपेक्षा 20 करोड़ रुपये अधिक होगी। अपने ऋण कार्यक्रम के पहले चरण में केन्द्रीय सरकार ने 11 अप्रैल 1970 को 275 करोड़ रुपये की राशि के लिए सम-मूल्य पर $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत व्याज वाला एक ऋण जारी किया जो सन् 2000 को समाप्त होगा। 1970 को समाप्त होने वाले 4 प्रतिशत व्याज वाले ऋण को परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गयी। उक्त ऋण में अभिदान की गयी राशि 290 करोड़ रुपये थी और वह सारी राशि रख ली गयी; इसमें से 150 करोड़ रुपये नकदी थे और 140 करोड़ रुपये परिवर्तन के द्वारा प्राप्त हुए थे। परिवर्तन के लिए पेश न किये गए उस ऋण के सम्बन्ध में जिसकी अवधि समाप्त हुई वापसी नकदी अदायगी (38 करोड़ रुपये) की व्यवस्था करने के बाद इस बाजार ऋण से प्राप्त होने वाली वास्तविक राशि 122 करोड़ रुपये होगी अथवा बजट में व्यवस्था की गयी राशि का लगभग 70 प्रतिशत होगी और बाकी 50 करोड़ रुपये की राशि वर्तमान राजकोपीय वर्ष के शेष भाग में जुटानी होगी।

58. पन्द्रह राज्य सरकारों ने 1 जुलाई 1970 को कुल 142.50 करोड़ रुपये की राशि के लिए $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत व्याज वाले विकास ऋणों की घोषणा की। उन ऋणों की अवधि 12 वर्षों के बाद समाप्त होगी। राज्य सरकारों के जिन (56.91 करोड़ रुपये की बकाया राशि वाले) ऋणों की अवधि इस वर्ष समाप्त होने वाली थी उनको सम्बन्धित राज्य सरकारों ने नये ऋणों में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गयी। अभिदान की कुल राशि 164 करोड़ रुपये थी—नकदी अभिदान की राशि 131 करोड़ रुपये थी और 33 करोड़ रुपये की राशि परिवर्तन के रूप में प्राप्त हुई थी; सभी ऋणों में अधिक अभिदान किये गये। आंशिक वितरण के बाद प्राप्त अभिदान की कुल राशि 157 करोड़ रुपये थी। जिन ऋणों की अवधि समाप्त होने वाली थी परन्तु जो परिवर्तन के लिए पेश नहीं किये गये थे उनकी वापसी अदायगी (24 करोड़ रुपये) के लिए नकदी की व्यवस्था किये जाने के बाद राज्यों को बाजार ऋणों से प्राप्त वास्तविक राशि 100 करोड़ रुपये होगी जो 1969-70 की राशि की अपेक्षा 17 करोड़ रुपये अधिक है।

59. 1969-70 के राजकोपीय वर्ष में अल्प बचतों की वास्तविक राशि, अनन्तिम आकड़ों के अनुसार, (16 मार्च 1970 से लागू की गयी नयी योजनाओं से प्राप्त 5 करोड़ रुपये को मिलाकर) लगभग 129 करोड़ रुपये है जो पिछले वर्ष की राशि से 16 करोड़ रुपये अधिक है; यह राशि 1969-70 के बजट में अनुमानित राशि से 6 करोड़ रुपये कम है। 1970-71 के लिए केन्द्रीय बजट में अल्प बचतों के अधीन 140 करोड़ रुपये का अनुमान किया गया है। अल्प बचतों को बढ़ाने के लिए बजट में अनेक प्रोत्साहन की व्यवस्था की गयी। इन प्रोत्साहनों में कतिपय वर्तमान बचत माध्यमों पर (आय कर से मुक्त) व्याज की दरों को बढ़ाना और (कर योग्य) व्याज की उच्चतर दरों वाले नये बचत माध्यमों की व्यवस्था करना सम्मिलित है। अल्प बचतों के नये माध्यम इस प्रकार हैं: सावधि डाकघर जमा राशियाँ और (आयकर योग्य व्याज वाली) आबर्ती जमा राशियों की योजनाएं, (आय

कर-मुक्त व्याज वाले) डाक घरों के अवरुद्ध बचत लेखे और 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, II, III (आय कर से मुक्त व्याज वाले) और IV (आय कर योग्य व्याज वाले)। (आय कर से मुक्त व्याज वाले) 10-वर्षीय रक्षा जमा प्रमाणपत्र और 12-वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा प्रमाणपत्र और (आय कर योग्य व्याज वाले) 10-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र बन्द कर दिये गये हैं।

60. 1969-70 के बजट में सार्वजनिक अधिष्ठा विधि योजना से 5 करोड़ रुपये की वास्तविक प्राप्तियों का अनुमान किया गया था; किन्तु वे परिणामित अनुमानों के अनुसार 2 करोड़ रुपये हो गये हैं; परन्तु वास्तव में प्राप्त हुई राशि 1968-69 के लगभग 1 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 1.6 करोड़ रुपये (अनन्तिम) थी। 1970-71 में, इस स्रोत से 5 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने की प्रत्याशा है।

गैर सरकारी निगम क्षेत्र

61. केन्द्रीय सरकार के पिछले तीन बजटों में कर सम्बन्धी जो रियायतें दी गयी थीं उनके कारण यद्यपि निवेश की स्थिति में सुधार हुआ, फिर भी गैर सरकारी निगम क्षेत्र के निवेश कार्य में पिछले वर्ष की अपेक्षा कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। औद्योगिक प्रायोजनाओं पर सरकारी क्षेत्र द्वारा किये जाने वाले निवेश व्यय में अवरोध की स्थिति आ गयी थी और प्रायोजना-सहायता का स्पष्ट चित्र न होने से विदेशी मुद्रा सम्बन्धी वित्तीय सहायता की आवश्यकता व्यवस्था करने में भी कठिनाई उपस्थित हो गयी थी; अतः गैर सरकारी निगम क्षेत्र के निवेश कार्य में उल्लेखनीय वृद्धि न हो सकी। पिछले वर्ष (जुलाई 1968-जून 1969) के अन्त में प्रतिभूतियों के वायदा व्यापार पर लगायी गयी रोक के बाद ईक्विटी शेयरों के मूल्यों में जो कमी हो गयी थी उसमें स्टाकों और शेयरों में किये जाने वाले निवेशों के लिए कर सम्बन्धी काफी रियायतें दिये जाने के फलस्वरूप प्रचुर मात्रा में सुधार हुआ और उन मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति पायी गयी।

62. निगम क्षेत्र के कार्य में 1969-70 में सुधार हुआ। सार्वजनिक सीमित कंपनियों द्वारा की गयी लाभांश सम्बन्धी घोषणाओं के प्रारम्भिक अध्ययन से यह पता चलता है कि अप्रैल-दिसम्बर 1969 के बीच अपने लेखों को बन्द करने वाली 520 सार्वजनिक सीमित कंपनियों में से 164 कंपनियों या 32 प्रतिशत कंपनियों ने अपने लाभांश की दरों में वृद्धि की और दूसरी 156 कंपनियों या 30 प्रतिशत कंपनियों ने पिछले वर्ष की ही दरों पर लाभांश अदा किया। शेष 200 कंपनियों में से, पिछले वर्ष की 98 कंपनियों या 19 प्रतिशत कंपनियों की तुलना में इस वर्ष 63 कंपनियों या 12 प्रतिशत कंपनियों ने अपने लाभांशों में कमी की। लाभांश अदा न करने वाली कंपनियों की संख्या जहाँ पिछले वर्ष 149 थी वहीं यह इस वर्ष 137 हो गयी थी। लाभांश की वास्तविक दरों* के संवेग में, 6 और 10 प्रतिशत के बीच लाभांश अदा करने वाली कंपनियों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई और जहाँ वे 1968-69 में 132 (25 प्रतिशत) थीं वहाँ वे 1969-70 में बढ़कर 157 (30 प्रतिशत) हो गयीं। उच्चतर लाभांश वाली श्रेणी में भी पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कंपनियों की संख्या अधिक थी।

63. (बोनस शेयर को छोड़कर) शेयरों और डिबेंचरों के रूप में पूंजीगत शेयर जारी किए जाने के लिए गैर सरकारी सार्वजनिक सीमित कंपनियों को उनके प्रस्तावों की जो सहमतियाँ/स्वीकृतियाँ दी गयीं उनकी राशि काफी अधिक थी अर्थात् जहाँ वह 1968-69 (जुलाई-जून) में 59.5 करोड़ रुपये थी यहाँ वह 1969-70 (जुलाई-जून) में बढ़कर 89.1* करोड़ रुपये हो गयी। 'प्रारम्भिक' शेयर जारी करने के लिए दी गयी सहमतियों की राशि पिछले वर्ष के 11.3 करोड़

रुपयों से बढ़कर इस वर्ष 19.5 करोड़ रुपये हो गयी और 'आगे' जारी किये जाने वाले शेयरों के लिए जो सहमतियाँ दी गयीं उनकी राशि 48.2 करोड़ रुपयों से बढ़कर 69.6 करोड़ रुपये हो गयी। यदि प्रतिभूतिधार वेखा जाए तो 1969-70 में ईक्विटी शेयर जारी करने के लिए दी गयी सहमतियों की राशि में 17.7 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई अर्थात् वह बढ़कर 13.3 करोड़ रुपये हो गयी; उसी प्रकार डिबेंचर जारी करने के लिए दी गयी सहमतियों की राशि में भी 23.9 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई अर्थात् वह बढ़कर 37.8 करोड़ रुपये हो गयी। अधिमान्य शेयरों के लिए दी गयी सहमतियों की राशि 9.9 करोड़ रुपयों से घटकर 7.8 करोड़ रुपये हो गयी। गैर सरकारी सार्वजनिक सीमित कम्पनियों द्वारा जारी किये जाने वाले बोनस शेयरों के लिए दी गयी सहमतियों की राशि जहाँ 1968-69 में 17.8 करोड़ रुपये थी वहाँ वह 1969-70 में बढ़कर 45.6 करोड़ रुपये हो गयी। सामान्य निवेशकर्ताओं के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से सरकार ने बोनस शेयर जारी करने के सम्बन्ध में नये मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये। उनमें से महत्वपूर्ण सिद्धान्त इस प्रकार हैं: (क) लाभांश के बदले में बोनस शेयर जारी करने की अनुमति न दी जाए, (ख) बोनस शेयर जारी करने की दो घोषणाओं के बीच कम-से-कम 18 महीनों की अवधि हो, और (ग) किसी कम्पनी की बोनस शेयर जारी करने की अनुमति पाँच वर्षों की अवधि में दो से अधिक बार न दी जाए।

64. नये पूंजीगत शेयर जारी करने की प्रवृत्ति जुलाई 1969-जून 1970** में फिर से बढ़ी और विवरणपत्रों द्वारा तथा वर्तमान शेयरधारियों के अधिकार के रूप में जारी किये गये शेयरों की कुल राशि 1968-69 के 57.8 करोड़ रुपयों से बढ़कर 75.8 करोड़ रुपये* हो गयी। यह वृद्धि मुख्यतः ईक्विटी और अधिमान्य शेयरों में पायी गयी; साथ ही, डिबेंचरों में भी थोड़ी-सी वृद्धि हुई। प्रारम्भिक शेयरों की राशि जहाँ 1968-69 में केवल 10.4 करोड़ रुपये थी वहाँ इस वर्ष तेजी से बढ़कर 22.5 करोड़ रुपये हो गयी। पूंजीगत शेयरों में जनता ने जो योग दिया उससे स्थिति में निश्चित रूप से सुधार का संकेत मिला कतिपय शेयरों के लिए बहुत अधिक मात्रा में अभिवान प्राप्त हुआ। सांस्थानिक निवेशकर्ता बराबर हामीदारी की सहायता देने रहे; परन्तु जनता के अधिक योगदान के कारण हामीदारी की रकम का अनुपात पिछले वर्ष के 38 प्रतिशत से घटकर उस वर्ष 27 प्रतिशत हो गया।

65. प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में ईक्विटी शेयरों के मूल्यों में स्थूल रूप से दो चरणों में घट-बढ़ हुई; पहले चरण में जुलाई 1969 से फरवरी 1970 के मध्य तक की अवधि और दूसरे चरण में फरवरी 1970 से मध्य से जून 1970 तक की अवधि आती है। जून 1969 के अन्तिम सप्ताह में शेयरों के बायबा व्यापार पर लगायी गयी रोक के कारण पहले चरण में ईक्विटी शेयरों के मूल्यों में तेजी से कमी हुई। कतिपय क्षेत्रों में 14 प्रमुख वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाव गैर सरकारी क्षेत्र को मिलने वाले ऋण की मात्रा के सीमित होने की आशंकाएं और जूट के कपड़ों के कारखानों तथा कतिपय दूसरे उद्योग के क्षेत्रों में हुई हड़तालें इसके अन्य कारण थे। परिवर्तनीय लाभांश वाली औद्योगिक प्रतिभूतियों के मूल्यों का रिजर्व बैंक का अखिल भारतीय सूचकांक (आधार: 1961-62—100) जहाँ जून 1969 के अन्त में 99.3 था वहाँ वह अगस्त के मध्य तक घटकर 89.2 हो गया। सांस्थानिक निवेशकर्ताओं द्वारा शेयरों के खरीदे जाने के समाचारों, निगमों के सम्बन्ध में अच्छी खबरों और अच्छे पक्ष शेयरों की कमी के कारण अक्तूबर के मध्य तक थोड़ी-सी अवधि के लिए मूल्यों में सुधार हुआ,

परन्तु उसके बाद स्टॉकों के मूल्यों में कमी की प्रवृत्ति फिर से शुरू हो गयी क्योंकि पुनः शेयरों के बायबा व्यापार के शीघ्र प्रारम्भ हो जाने की प्रत्याशा सफल नहीं हो सकी। शेयरों के बायबा व्यापार पर लगायी गयी रोक के विरोध में बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और अहमदाबाद के स्टॉक एक्सचेंजों में 4 दिसम्बर से 18 दिसम्बर तक हड़ताल की गयी। फरवरी 1970 के पहले सप्ताह में सूचकांक घटकर 87.3 हो गया जो इस वर्ष का न्यूनतम स्तर था। दूसरे चरण में, (i) 7 फरवरी 1970 को शेयरों के बायबा व्यापार की सम्भावनाओं की जांच पड़ताल करने के लिए एक विशेष समिति की नियुक्ति के सम्बन्ध में और (ii) 14 फरवरी 1970 को पुनरावृत्ति के श्रेणियों के लिए अधिक क्षतिपूर्ति दिये जाने के सम्बन्ध में की गयी घोषणाओं के कारण स्टॉकों के मूल्यों में वृद्धि होने लगी। निगम क्षेत्र के कर-स्वरूप को बिना किसी पारस्वतन्त्र के बनाये रखने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के बजट में किये गये प्रस्तावों से स्टॉकों के मूल्यों की वृद्धि की प्रवृत्ति और बढ़ी। उक्त बजट-प्रस्तावों का उद्देश्य यह था कि निवेश सम्बन्धी निर्णय लिये जाने के लिए स्थायी बातारवण का निर्माण किया जाए और यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के युनिटों, भारतीय कम्पनियों के शेयरों, सरकारी प्रतिभूतियों तथा ग्रामीण डिबेंचरों और बैंकों के जमा लेखों में किये जाने वाले निवेशों से प्राप्त होने वाली आय के सम्बन्ध में आय कर से छूट दिये जाने की संयुक्त सीमा को 3,000 रुपयों तक बढ़ा दिया जाए। वृद्धि की इस नयी प्रवृत्ति के कारण ईक्विटी शेयरों के मूल्य क्रमशः बढ़कर जून के अन्त तक 100.6 तक पहुँच गये यह स्तर जून 1969 के अन्त में विद्यमान 99.3 के स्तर की तुलना में अधिक था।

66. 1969-70 (अप्रैल-मई) में मीयादी ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा मंजूर की गयी वित्तीय सहायता और उनके द्वारा वितरित की गयी राशि में पिछले वर्ष के सम्बन्धित स्तरों की अपेक्षा वृद्धि हुई; इस वृद्धि का प्रमुख कारण यह था कि राज्य वित्तीय निगमों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि की गयी थी। सभी संस्थाओं द्वारा ऋणों और शेयरों और डिबेंचरों की हामीदारी तथा उनमें प्रत्यक्ष अभिवान के रूप में मंजूर की गयी वित्तीय सहायता की कुल राशि जहाँ 1968-69 में 132.3 करोड़ रुपये थी वहाँ 1969-70 (अप्रैल-मार्च) में बढ़कर 149.9 करोड़ रुपये@ हो गयी। उसी प्रकार वितरित की गयी राशि में भी वृद्धि हुई अर्थात् वह पिछले वर्ष के 85.8 करोड़ रुपयों से बढ़कर इस वर्ष 114.0 करोड़ रुपये हो गयी। औद्योगिक विकास बैंक ने जहाँ 1968-69 में 46.1 करोड़ रुपयों के ऋण† मंजूर किये थे वहाँ 1969-70 में 50.2 करोड़ रुपयों@ के ऋण मंजूर किये और उसके द्वारा वितरित की गयी राशि में भी काफी वृद्धि हुई अर्थात् जहाँ वह पिछले वर्ष में 27.4 करोड़ रुपये थी वहाँ वह 1969-70 में 43.3 करोड़ रुपये@ हो गयी।

67. यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया और जीवन बीमा निगम के हामीदारी और निवेश सम्बन्धी कार्यकलापों से गैर सरकारी निगम क्षेत्र को पर्याप्त सहायता मिली। पिछले वर्ष जीवन बीमा निगम ने शेयरों और डिबेंचरों की हामीदारी और उनमें प्रत्यक्ष अभिवान करने के लिए 14.4 करोड़ रुपयों की राशि मंजूर की थी। यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया ने 1969-70 में शेयरों की हामीदारी और उनमें प्रत्यक्ष अभिवान करने के लिए 10 करोड़ रुपयों** तक की राशि मंजूर की थी जो लगभग पिछले वर्ष

* भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, राज्य वित्तीय निगम और राज्य औद्योगिक विकास निगम।

@ अन्तिम।

† इनमें गारंटियों के सम्बन्ध में वितरित की गयी राशि शामिल है।

‡ इनमें पुनर्भजन और बैंकों को प्रदान किया गया पुनर्वित्त शामिल है।

** प्रारम्भिक आंकड़े।

के बराबर ही थी। लघु उद्योगों के लिए प्रारम्भ की गयी ऋण गारंटी योजना में भी पर्याप्त प्रगति हुई। गारंटियों की बकाया राशि जहाँ 30 जून 1969 को 240.9 करोड़ रुपये थी वहाँ वह मार्च 1970 के अन्त में 535.9 करोड़ रुपये हो गयी थी। इस योजना के अधीन गारंटी के रूप में दी जाने वाली सहायता को व्यापक बनाने की क्रिया-विधि को सरकार ने और अधिक सरल तथा कारगर बनाया ताकि लघु उद्योगों को शीघ्रता से ऋण प्राप्त हो सके।

68. आलोच्य वर्ष के आरम्भ में, मध्य-दिसम्बर 1969 और मध्य-जनवरी 1970 के बीच और पुनः वर्ष के अन्त में चांदी के मूल्य में अस्थायी रूप से हुई कमी को छोड़ दिया जाए तो भारी मात्रा में अनधिकृत निर्यात होने और विदेशों में ऊँची दर होने के समाचारों के कारण बम्बई ब्रिलियन बाजार में चांदी का मूल्य समग्रतः स्थिर हो गया था। चांदी की मूल्य दर जहाँ जून 1969 के अन्त में प्रति किलोग्राम 457 रुपये थी वहाँ वह अस्थायी घट-बढ़ के बाद, 1 अप्रैल 1970 तक बढ़कर 526 रुपयों की उच्च सीमा पर पहुँच गयी। उसके बाद मूल्य दर मई 1970 के अन्त तक 499 रुपयों और 524.50 रुपयों के बीच घटती-बढ़ती रही और वर्ष के अन्त में 504 रुपये हो गयी। इस स्तर पर पूरे वर्ष में चांदी के मूल्य में प्रति किलोग्राम 47 रुपयों की वास्तविक वृद्धि हुई।

69. अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इस वर्ष के अधिकांश भाग में चांदी के मूल्य में स्थिरता बनी रही क्योंकि ऐसनहोवर स्मारक सिक्रे जारी करने के सम्बन्ध में अमेरिकी सेनेट में विधेयक लाये जाने के कारण चांदी की मांग में सुधार होने की सम्भावना थी, परन्तु वर्ष के अन्त में सट्टेबाजी की बिक्री का भारी दबाव पड़ने से पहले हुई मूल्य-वृद्धि का काफी बड़ा अंश लुप्त हो गया। चांदी का मूल्य नवम्बर में 200 सेंट तक बढ़ जाने के बाद वर्ष के अन्त में 161.2 सेंट में आकर रुक गया जबकि पिछले वर्ष 30 जून को 156 सेंट में आकर रुका था।

70. बम्बई ब्रिलियन बाजार में सोने के मूल्यों में पिछले वर्ष के अन्त में जो कमी पायी गयी थी वह अल्प कालिक सिद्ध हुई। 3 जुलाई 1969 को स्वर्ण नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश के जारी होने और उसके स्थान पर बाव में 29 अगस्त 1969 को प्रमल में लाये गये स्वर्ण नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 1969 के जारी होने के फलस्वरूप सोने के मूल्यों में फिर से वृद्धि हुई। मानक सोने का मूल्य जून के अन्त में प्रति दस ग्राम 167.50 रुपये था; उसके बाद उसमें बराबर वृद्धि होती गयी और 25 अगस्त 1969 को वह 184 रुपयों हो गया; और सितम्बर में 177.75 रुपयों और 183 रुपयों के बीच घटते-बढ़ते रहने के बाद वह लगभग निरन्तर बढ़ता ही गया और दणहरे के दिन (18 अक्टूबर 1969) वह प्रति दस ग्राम 186.50 रुपयों की उच्च सीमा पर पहुँच गया। यह वृद्धि नवम्बर के अन्त तक बनी रही और सोने के मूल्य में प्रति दस ग्राम 181 रुपयों और 185 रुपयों के बीच थोड़ी घट-बढ़ होती रही। दिसम्बर के आरम्भ में सोने के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में मंदी आ जाने के समाचारों के फलस्वरूप मूल्य-वृद्धि की प्रवृत्ति में रुकावट आ गयी और 10 दिसम्बर 1969 तक सोने का मूल्य घटकर प्रति दस ग्राम 170 रुपये हो गया और वह फरवरी 1970 के आरम्भ तक इसी स्तर पर बना रहा। एकसाल के प्राधिकारियों ने नये नियम बनाकर यह आवश्यक कर दिया कि परिष्कार के लिए लाये जाने वाले सोने के गहनों के घेचने वालों के नाम आदि बतलाये जाएँ; इसके फलस्वरूप बाजार में मानक सोने की पूर्ति में कमी आ जाने के समाचारों के कारण सोने के मूल्यों में पायी गयी कमी की प्रवृत्ति का अन्त हो गया। मानक सोने का मूल्य 24 फरवरी 1970 को 192 रुपयों की नयी उच्च सीमा पर पहुँच गया। यद्यपि बाव में मूल्य को इस उच्च सीमा पर बनाये नहीं रखा गया फिर भी सोने की मौसमी मांग के कारण

वर्ष के शेष भाग में मूल्य में स्थिरता बराबर बनी रही। 18 मार्च और पुनः 4 अप्रैल 1970 को मूल्य में थोड़ी-सी अवधि के लिए कमी हुई और वह उस अवधि में 183.50 रुपये था; किन्तु उसके बाद मूल्य दर में 184 रुपयों और 191.50 रुपयों के बीच घट-बढ़ होती रही और वर्ष के अन्त में आकर वह 185.50 रुपये हो गया। इस स्तर पर सोने के मूल्य में इस वर्ष प्रति दस ग्राम 18 रुपयों की वास्तविक वृद्धि दिखाई पड़ी।

71. सोने के अन्तर्राष्ट्रीय मुक्त बाजार में जो अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना घटी वह यह थी कि सोने के आधिकारिक मूल्य और मुक्त बाजार के मूल्य में कोई अन्तर न रहा। इस परिणाम के निम्नलिखित अनेक कारण थे: (i) दक्षिण अफ्रीका द्वारा अपने भुगतान शेष के घाटे को पूरा करने के लिए बराबर सोने की बिक्री की गयी, (ii) 8 अगस्त को फ्रांसीसी फ्रांक का अवमूल्यन और 24 अक्टूबर को ड्यूयू मांक का पुनर्मूल्यन किया गया, (iii) ब्रिटेन के भुगतान शेष की स्थिति में सुधार हुआ और (iv) अक्टूबर के आरम्भ में विशेष आह्वान अधिकारों की योजना का अनुसमर्थन किया गया। इन घटनाओं के फलस्वरूप सट्टेबाजी की बिक्री का भारी दबाव पड़ने के कारण मुक्त बाजार मूल्य में भारी कमी आ गई और वह 9 दिसम्बर 1969 को प्रति औंस 35 डावर तक गिर गया और वर्ष के अन्त तक उसी स्तर के आसपास बना रहा।

कृषि निवेश की वित्त व्यवस्था

72. सांस्थानिक एजेंसियों द्वारा कृषि में निवेश करने के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता में पिछले दो वर्षों में पर्याप्त वृद्धि हुई (सारणी 9)। यह वृद्धि मुख्यतः पिछले दो वर्षों में कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा किये गये ऋण सम्बन्धी बायबों और वितरणों और सहकारी भूमि विकास/बंधक बैंकों द्वारा जारी किये गये गामान्य डिवेंचरों में अधिक वृद्धि हो जाने का परिणाम है। 1969-70 में कृषि वित्त निगम लि० द्वारा मंजूर की गयी योजनाओं की संख्या और वितरित की गयी कुल राशि में भी पर्याप्त वृद्धि हुई।

73. इस वर्ष जुलाई 1969 में ग्रामीण बिजली निगम लि० की स्थापना हुई। निगम की स्थापना ग्रामीण बिजली संबंधी कार्य की गति को निम्नलिखित प्रयत्नों द्वारा बढ़ाने के उद्देश्य से की गयी: (i) अग्रता वाले क्षेत्रों में ग्रामीण बिजली संबंधी योजनाओं को वित्तीय सहायता देना, (ii) बिजली बोर्डों द्वारा जारी किये जाने वाले विशेष ग्रामीण बिजली बांडों में अभिदान करना और (iii) विभिन्न राज्यों में संगठित की जाने वाली ग्रामीण बिजली सहकारी संस्थाओं को अवश्य पूंजीगत ऋण देना। निगम ने जनवरी 1970 में कार्य करना आरम्भ कर दिया। उसके द्वारा किये जाने वाले वितरण सामान्य रूप से उपलब्ध वित्तीय साधनों के अतिरिक्त होंगे। यद्यपि उक्त निगम द्वारा दी जाने वाली सहायता फिलहाल कम है फिर भी देश में ग्रामीण बिजली संबंधी कार्य-क्रमों को बढ़ाने में उसके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उसके द्वारा दी जाने वाली सहायता में वृद्धि होने की संभावना है। चौथी योजना में की गयी व्यवस्था के फलस्वरूप निगम के वित्तीय साधनों में भी 150 करोड़ रुपयों तक की वृद्धि होगी।

74. यह संभव है कि चौथी योजना के दौरान भूमि विकास बैंक अपने ऋण संबंधी कार्यकलापों को 700 करोड़ रुपयों तक बढ़ा दें। यह लक्ष्य उपलब्ध वित्तीय साधनों के आधार पर निर्धारित किया गया है। कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा दिये जाने वाले पुनर्वित्त का लक्ष्य 200 करोड़ रुपये है।

मुद्रा की उपलब्धि की प्रवृत्तियाँ

75. 1969-70 (जुलाई-जून) में जनता के पास रहने वाली मुद्रा में 578 करोड़ रुपयों की जो वृद्धि हुई वह पिछले वर्ष की वृद्धि (566

सारणी 9—कृषि के लिए निवेश विवर

(करोड़ रुपये में)

वर्ष (जुलाई-जून)	केन्द्रीय सहकारी/भूमिबंधक/ विकास बैंकों द्वारा जारी किये गये डिबेंचर		कृषि पुनर्वित्त निगम		(कृ० पु० निगम)		कृषि वित्त निगम	
			मंजूर की गई	कुल परिचय्य	कृ० पु० निगम के धायदे	इस वर्ष वितरित की गयी राशि	मंजूर की गई	कुल परिचय्य
	सामान्य डिबेंचर	ग्रामीण डिबेंचर	योजनाओं की संख्या**				योजनाओं की संख्या	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1960-61	9.97	1.55						
1961-62	10.50	2.38*						
1962-63	19.25	1.57						
1963-64	23.34	1.84	3	2.23	2.01			
1964-65	34.81	3.23	8	11.02	9.35	0.45		
1965-66	43.10	4.33	14	13.31	10.31	4.45		
1966-67	52.05	2.93	13	9.18	7.36	2.08		
1967-68	64.51	1.57	87	67.08	58.13	5.67		
1968-69	103.42	5.00	108	79.21	69.32	17.84	6	61.50
1969-70	114.72	1.10	142	92.78	70.92	28.60	23	46.74

वर्ष (जुलाई-जून)	(कृ० वि० निगम)		ग्रामीण बिजली निगम		(ग्रा० वि० निगम)		रिजर्व बैंक आफ इंडिया	
	कृ० वि० निगम के धायदे†	इस वर्ष वितरित की गई राशि†	मंजूर की गई योजनाओं की संख्या	कुल परिचय्य	ग्रा० वि० निगम के धायदे	इस वर्ष वितरित की गयी राशि	मध्यावधि ऋण	
	9	10	11	12	13	14	मंजूर की गई राशि	इस वर्ष ली गई राशि
1960-61							4.68	5.69
1961-62							9.56	7.39
1962-63							9.31	4.18
1963-64							14.01	7.45
1964-65							14.39	7.91
1965-66							14.11	7.45
1966-67							15.49	9.12
1967-68							16.57	9.12
1968-69	4.20@	2.52					19.00	9.02
1969-70	29.31††	15.04	50	31.11	30.28	—	18.30	11.48

नोट : बाणिज्य बैंकों द्वारा भूमिबंधक/विकास बैंकों द्वारा जारी किये गये डिबेंचरों के किये गये भ्रंशदान के रूप में और कृषि वित्त निगम के साथ सहभागिता के द्वारा दिये गये वित्त के आंकड़ों को छोड़कर उनके द्वारा प्रदान किये गये अन्य निवेश वित्त के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उसी प्रकार, सहकारी ऋण एजेंसियों द्वारा अपनी निजी निधियों से प्रदान किये गये निवेश वित्त के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं।

* 13.5 लाख रुपये के विशेष विकास डिबेंचर शामिल हैं।

**मंजूर की गयी परन्तु बाव में रह कर गयी योजनाओं को छोड़कर।

† सदस्य-बैंकों की सहभागिता शामिल है।

@ यह 4.20 करोड़ रुपये के परिचय्य की 4 योजनाओं की सहभागिता से सम्बन्धित है। 57.30 करोड़ रुपये के परिचय्य की दो योजनाओं की सहभागिता को अभी अन्तिम रूप देना बाकी है।

†† यह 29.31 करोड़ रुपये के परिचय्य की 19 योजनाओं की सहभागिता से सम्बन्धित है। 17.43 करोड़ रुपये के परिचय्य की चार योजनाओं की सहभागिता को अभी अन्तिम रूप देना बाकी है।

परिमोचित।

सारणी 10—मुद्रा की उपलब्धि और मुद्रागत साधनों की प्रवृत्तियाँ

(वार्षिक)

(करोड़ रुपये में)

जुलाई-जून में घट-बढ़

	1967-68	1968-69	1969-70
1. जनता के पास चल मुद्रा	+ 235 (+ 7.3)	+ 341 (+ 9.9)	+ 386 (+ 10.2)
2. मांग जमा राशियाँ	+ 276 (+ 15.7)	+ 225 (+ 11.1)	+ 192 (+ 8.5)
3. मुद्रा की उपलब्धि (1+2)	+ 510 (+ 10.3)	+ 566 (+ 10.3)	+ 578 (+ 9.6)
4. मीमादी जमा राशियाँ	+ 258 (+ 13.2)	+ 473 (+ 21.5)	+ 413 (+ 15.4)
5. कुल मुद्रागत साधन (3+4)	+ 768 (+ 11.1)	+ 1039 (+ 13.5)	+ 991 (+ 11.4)
6. बैंकों द्वारा सरकार को दिया गया वास्तविक ऋण	+ 171 (+ 4.1)	+ 433 (+ 9.9)	+ 6 (+ 0.1)
7. बैंकिंग क्षेत्र की वास्तविक विदेशी मुद्रा प्रवृत्तियाँ	+ 81 (+ 81.0)	+ 153@ (+ 84.6)	+ 285 (+ 71.4)
8. जनता के प्रति सरकार की वास्तविक चल मुद्रा देयताएं	—2 (—0.6)	+ 33 (+ 10.4)	+ 11 (+ 3.2)
9. जोड़ (6+7+8)	+ 250 (+ 5.4)	+ 619@ (+ 12.7)	+ 302 (+ 5.4)
10. बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिया गया ऋण	+ 570 (+ 18.6)	+ 641 (+ 17.6)	+ 736 (+ 17.2)
11. रिज़र्व बैंक की वास्तविक मुद्रा देयताएं	—6	—95@	—60
12. अन्य बैंकों की वास्तविक मुद्रा देयताएं	—44	—126	+ 13
13. जोड़ (9+10)	+ 820 (+ 10.6)	+ 1260@ (+ 14.8)	+ 1038 (+ 10.5)

नोट—कोष्ठकों में दिये हुये आंकड़े घट-बढ़ के प्रतिशत हैं।

@रिज़र्व बैंक के षण् विभाग में रखे हुए सारे के पुनर्मूल्यांकन के कारण 1 फरवरी 1969 से उत्पन्न परिवर्तनों को छोड़कर।

करोड़ रुपये) की अपेक्षा अधिक थी। फिर भी वृद्धि की दर 1968-69 में जहाँ 10.3 प्रतिशत थी वहाँ सालू वर्ष में कम होकर 9.6 प्रतिशत हो गयी। कुल मुद्रागत वित्तीय साधनों में जिनमें जनता के पास रहने वाली चल मुद्रा और बैंकों की कुल जमा राशियाँ शामिल हैं, पिछले वर्ष की अपेक्षा कम वृद्धि हुई अर्थात् जहाँ उक्त वृद्धि की राशि 1968-69 में 1,039 करोड़ रुपये या उसकी दर 13.5 प्रतिशत थी वहाँ वह इस वर्ष 991 करोड़ रुपये या 11.4 प्रतिशत थी। यदि घटकवार देखा जाय तो जमा राशि में वृद्धि की अपेक्षा चल मुद्रा में बराबर अधिक वृद्धि

होती रही। इससे यह संकेत मिलता है कि ऋण प्राय में बराबर वृद्धि होती रही। 1969-70 में चल मुद्रा घटक में 386 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष की वृद्धि की अपेक्षा 45 करोड़ रुपये अधिक थी जब कि जमा राशि में हुई 192 करोड़ रुपये की वृद्धि पिछले वर्ष की वृद्धि की अपेक्षा 33 करोड़ रुपये कम थी। इस वर्ष मीमादी जमा राशियों में हुई वृद्धि भी पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी कम थी अर्थात् जहाँ यह वृद्धि 1968-69 में 473 करोड़ रुपये या 21.5 प्रतिशत थी वहाँ वह इस वर्ष 413 करोड़ रुपये या 15.4 प्रतिशत हो गयी थी।

सारणी 11—अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा सरकारी क्षेत्र को दिये गये ऋणों का बकाया

(करोड़ रुपयों में)

	28 जून 1968	27 दिसम्बर 1968	27 जून 1969	26 दिसम्बर 1969—
(i) सरकारी कम्पनियों और निगम	223.38 (+142.2)	299.88 (+34.2)	224.97 (—25.0)	165.37 (—26.5)
(ii) दूसरी सरकारी संस्थाएं	10.08 (+2.9)	14.44 (+43.2)	14.90 (+3.2)	18.97 (+27.3)
(iii) राज्य सरकारें	22.86 (+26.7)	18.46 (—19.2)	87.58 (+374.4)	30.95 (—64.7)
(iv) राज्य बिजली बोर्ड	10.92 (+248.9)	10.74 (—1.6)	23.13 (+115.4)	19.07 (—17.6)
(v) कुल जोड़	267.24 (+116.9)	343.52 (+28.5)	350.58 (+2.1)	234.36 (—33.2)
(vi) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिया गया कुल ऋण	3102.89 (+13.9)	3068.99 (—1.1)	3598.77 (+17.3)	3615.92 (+0.5)
(vii) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋणों में सरकारी क्षेत्र को दिये गये ऋणों का अनुपात	8.6	11.2	9.7	6.5

नोट:—कोष्ठकों में दिये हुए आंकड़े पिछली अवधि की तुलना में हुए परिवर्तनों के प्रतिफल हैं ।

* अनुत्तिम ।

बैंकों द्वारा सरकार को दिये जाने वाले ऋण में 1969-70 में 6 करोड़ रुपयों की साधारण वृद्धि हुई जब कि 1968-69 में उसमें 433 करोड़ रुपयों की भारी वृद्धि हुई थी। इसके विपरीत, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बैंकिंग क्षेत्र की वास्तविक विदेशी मुद्रा आस्तियों की स्थिति से मुद्रा की उपलब्धि में बहुत अधिक वृद्धि हुई। आयातों के लिए की जाने वाली प्रदायगियों में हुई भारी कमी और निर्यातों से प्राप्त होने वाली भाय में हुई थोड़ी वृद्धि के कारण बैंकिंग क्षेत्र की वास्तविक विदेशी मुद्रा आस्तियों में 285 करोड़ रुपयों की भारी वृद्धि हुई जब कि पिछले वर्ष उनमें 153 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी। बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये जानेवाले ऋण से भी पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष मुद्रा की उपलब्धि में बहुत अधिक वृद्धि हुई; अर्थात् इस वर्ष मुद्रा की उपलब्धि में 736 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष में हुई वृद्धि की अपेक्षा 95 करोड़ रुपये अधिक थी। बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण में होनेवाली वृद्धि के परिमाण को निर्धारित करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस ऋण का अधिकांश भाग अनाज की उगाही और उर्वरकों की खरीद और वितरण जैसे वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए भारतीय खाद्य निगम सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सरकारों को दिये गये ऋणों के रूप में था। सारणी 11 से बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये गये कुल ऋण में ऐसे ऋणों के परिमाण और दिसम्बर 1969 को समाप्त हुई अवधि में उनमें हुई घट-बढ़ का कुछ पता चलेगा।

मौसमी प्रवृत्तियाँ

76. 1969 के कम कामकाज के समय (मई-अक्टूबर) में मुद्रा की उपलब्धि में जो कमी हुई (73 करोड़ रुपये) वह 1968 के कम कामकाज के समय की अपेक्षा कम थी। मुद्रा की उपलब्धि में यह कमी मुख्यतः बैंकों द्वारा सरकार और वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये जाने वाले

वास्तविक ऋण में हुई कमी के फलस्वरूप (मौसमी जमा राशियों की घट-बढ़ के लिए समायोजित) हुई थी। उक्त कमी का बैंकिंग क्षेत्र की वास्तविक विदेशी मुद्रा आस्तियों में हुई 45 करोड़ रुपयों की वृद्धि से अंशतः दूर किया गया।

77. 1969-70 के अधिक कामकाज के समय में अर्थात् नवम्बर 1969 से अप्रैल 1970 तक की अवधि में मुद्रा की उपलब्धि में अधिक वृद्धि हुई अर्थात् जहाँ 1968-69 के अधिक कामकाज के समय में उसमें 607 करोड़ रुपयों या 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहाँ उसमें इस वर्ष 695 करोड़ रुपयों या 11.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चल मुद्रा में 512 करोड़ रुपयों की जो वृद्धि हुई वह पिछले अधिक कामकाज के समय की वृद्धि की अपेक्षा लगभग 100 करोड़ रुपये अधिक थी जब कि मांग जमाराशियों में इस वर्ष हुई वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 13 करोड़ रुपये कम थी। मौसमी जमाराशियों में जो वृद्धि हुई वह भी 1968-69 के अधिक कामकाज के समय की वृद्धि की अपेक्षा 38 करोड़ रुपये कम थी।

78. 1969-70 के अधिक कामकाज के समय में बैंकों द्वारा सरकार को दिये गये वास्तविक ऋणों में 130 करोड़ रुपयों की बहुत कम वृद्धि हुई जब कि पिछले वर्ष की तबनीरूपी अवधि में 324 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। फिर भी विदेशी मुद्रा आस्तियों में 181 करोड़ रुपयों की जो वृद्धि हुई वह 1968-69 के अधिक कामकाज के समय में हुई वृद्धि की अपेक्षा 48 करोड़ रुपये अधिक थी। वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण में जहाँ 1969-70 के अधिक कामकाज के समय में 569 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई वहाँ पिछले अधिक कामकाज के समय में 470 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी। इस प्रकार, 1969-70 के अधिक कामकाज के समय में वास्तविक विदेशी मुद्रा आस्तियों और बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये गये ऋण में अधिक वृद्धि होने के कारण मुद्रा की उपलब्धि में भारी वृद्धि हुई।

सारणी 12—मुद्रा की उपलब्धि और मुद्रागत साधनों की प्रवृत्तियाँ

(मौसमी)

(करोड़ रुपये में)

निम्नलिखित समय में घट-बढ़

	कम कामकाज का समय		अधिक कामकाज का समय	
	1968	1969	1968-69	1969-70
1. जनता के पास चल मुद्रा	-126 (-3.6)	-149 (-4.0)	+411 (+12.2)	+512 (+14.1)
2. माँग जमाराशियाँ	-5 (-0.2)	+76 (+3.6)	+196 (+10.0)	+183 (+8.2)
3. मुद्रा की उपलब्धि (1+2)	-131 (-2.4)	-73 (-1.2)	+607 (+11.4)	+695 (+11.9)
4. सीबावी जमाराशियाँ	+230 (+10.6)	+248 (+9.6)	+200 (+8.4)	+162 (+5.7)
5. मुद्रागत साधन (3+4)	+99 (+1.3)	+175 (+2.1)	+807 (+10.5)	+857 (+9.9)
6. बैंकों द्वारा सरकार को दिया गया वास्तविक ऋण	+36 (+0.8)	-14 (-0.3)	+324 (+7.4)	+130 (+2.8)
7. बैंकिंग क्षेत्र की वास्तविक विदेशी मुद्रा प्राप्तियाँ	+9 (+5.0)	+45 (+11.3)	+133@ (+67.7)	+181 (+40.9)
8. जनता के प्रति सरकार की वास्तविक चल मुद्रा देयताएं	-8 (-2.6)	- (-)	+33 (+10.5)	+13 (+3.9)
9. जोड़ (6+7+8)	+37 (+0.8)	+31 (+0.6)	+490@ (+10.0)	+324 (+5.9)
10. बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिया गया ऋण	+56 (+1.6)	+136 (+3.3)	+470 (+12.9)	+569 (+13.4)
11. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वास्तविक मुद्रा देयताएं	+2	-15	-77@	-76
12. अन्य बैंकों की वास्तविक मुद्रा देयताएं	+4	-7	-76	+40
13. जोड़ (9+10)	+93 (+1.1)	+167 (+1.7)	+960@ (+11.2)	+893 (+9.2)

नोट:—कोष्ठकों में दिये हुए आंकड़े घट-बढ़ के प्रति शत हैं ।

@रिजर्व बैंक इणू विभाग में रखे हुए सोने के पुनर्मूल्यांकन के कारण 1 फरवरी 1969 से उत्पन्न परिवर्तनों को छोड़कर ।

79. वर्तमान कम कामकाज के समय में अर्थात् 1970 के कम कामकाज के समय में अब तक मुद्रा की उपलब्धि में उसी प्रकार गैर मौसमी वृद्धि हुई है जिस प्रकार 1969 के कम कामकाज के समय की तदनुसूची अवधि में हुई थी । यद्यपि इस कम कामकाज के समय में अब तक सरकार को दिया गया वास्तविक ऋण कम ही रहा है फिर भी विदेशी मुद्रा प्राप्तियाँ और वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये गये ऋण पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि की तुलना में अधिक ही थे ।

बैंकिंग प्रवृत्तियाँ और ऋण नीति

80. इस वर्ष अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के वित्तीय साधनों पर तनाव बढ़ गया क्योंकि बैंकों द्वारा दिये जाने-वाले ऋण में भारी वृद्धि हुई और जमाराशियों की वृद्धि की दर कम थी । इस वर्ष बैंकों ने रिजर्व बैंक से पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी अधिक मात्रा में ऋण प्राप्त किया । अतः रिजर्व बैंक ने अपनी ऋण नियंत्रण प्रणाली को इस प्रकार और कड़ा कर दिया कि अग्रता वाले क्षेत्रों को अपने द्वारा किये जाने वाले ऋणों के

सारणी 13—सहस्रपूर्ण बैंकिंग प्रक्रियों में वार्षिक घट-बढ़

(करोड़ रुपये में)

	जून 1967	जून 1967 की समाप्त हुए वर्ष में घट-बढ़	जून 1968	जून 1968 की समाप्त हुए वर्ष में घट-बढ़	जून 1969	जून 1969 की समाप्त हुए वर्ष में घट-बढ़	जून 1970*	जून 1970 की समाप्त हुए वर्ष में घट-बढ़
1. कुल बैंक ऋण	2631.1	+359.7	3102.9	+471.8	3598.8	+495.9	4227.6	+628.8
2. कुल निवेश	1069.9	+20.4	1160.7	+90.8	1358.9	+198.2	1505.7	+146.8
(अ) सरकारी प्रतिभूतियों में	922.6	+3.8	975.6	+53.0	1126.3	+150.7	1187.6	+61.3
(आ) अन्य अनुभूत प्रतिभूतियों में	147.3	+16.6	185.1	+37.8	232.6	+47.5	318.1	+85.5
3. नकदी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बकाया	258.8	+63.5	269.5	+10.7	380.3	+110.8	340.8	-39.5
4. माँग पर प्रतिवेश राशि	57.7	-4.5	50.6	-7.1	88.1	+37.5	49.3	-38.8
5. कुल जमाराशियाँ	3517.0	+393.8	3969.0	+452.0	4645.8	+676.8	5239.8	+594.0
(अ) माँग	1664.6	+187.3	1874.8	+210.2	2103.5	+228.7	2307.3	+203.8
(आ) सीमादी	1852.4	+206.5	2094.2	+241.8	2542.3	+448.1	2932.5	+390.2
6. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिये गये उधार	11.5	+9.0	103.5	+92.0	172.2	+68.7	291.5	+119.3

*अनन्तित

स्रोत :—रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 42 (2) के अधीन भेजी गयी साप्ताहिक विवरणियाँ; परन्तु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भिन्न गये उधारों के आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त साप्ताहिक उधार सूचनाओं पर आधारित हैं।

सम्बन्ध में रिजर्व बैंक से उपलब्ध होने वाली पुनर्वित्त सुविधाओं का लाभ उठाने की बैंकों की जो प्रवृत्ति है वह कुछ हद तक कम हो जाए। इन पुनर्वित्त सुविधाओं के सम्बन्ध में दी गयी कतिपय। रियायतें रद्द कर दी गयीं। मूल्यों में होने वाली वृद्धि के संदर्भ में कम मात्रा में उपलब्ध होने वाली कृषि संबन्धी कच्ची सामग्री का अधिक मात्रा में स्टॉक कर रखने की उद्योग क्षेत्र की प्रवृत्ति को रोका गया; इसके लिए माजिन सम्बन्धी आवश्यकताओं को और कड़ा कर दिया गया तथा इन पथ्यों की जमानत पर बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों की उच्चतम सीमाओं को कम कर दिया गया।

81. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल ऋण में 628.8 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जब कि 1968-69 में 495.9 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। जहाँ ऋण में हुई वृद्धि की दर 1968-69 में 16.0 प्रतिशत थी वहाँ 1969-70 में 17.5 प्रतिशत थी। इसके विपरीत, कुल जमाराशियों में थोड़ी-सी वृद्धि हुई अर्थात् जहाँ 1968-69 में उनमें 676.8 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी वहाँ इस वर्ष 594.0 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इस प्रकार, जमाराशियों में जहाँ 1968-69 में 17.0 प्रतिशत वृद्धि हुई थी वहाँ 1969-70 में वह घटकर 12.8 प्रतिशत हो गयी। वर्ष के अन्त में ऋण-जमा अनुपात 80.7 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुँच गया जो जून 1969 के अन्त के स्तर से 3.2 प्रतिशत अधिक था। जमाराशियों में हुई कुल वृद्धि में सीमादी जमाराशियों का अंश 1968-69 की तरह 66 प्रतिशत था। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किये गये निवेशों की राशि में जहाँ 1968-69 में 150.7 करोड़ रुपये की भारी वृद्धि हुई थी वहाँ इस वर्ष केवल 61.3 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इस कारण 22.7 प्रतिशत का जो निवेश-जमा अनुपात था वह एक वर्ष पहले के स्तर से 1.5 प्रतिशत कम था। नकदी और रिजर्व बैंक के पास बकाया में जहाँ

1968-69 में 110.8 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी वहाँ इस वर्ष 39.5 करोड़ रुपये की कमी हुई। इसके फलस्वरूप, नकदी अनुपात जहाँ जून 1969 में 8.2 प्रतिशत था वहाँ वह जून 1970 में घटकर 6.5 प्रतिशत हो गया। बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से लिये गये उधारों की बकाया राशि जहाँ जून 1969 के अन्त में 172.2 करोड़ रुपये थी वहाँ वह जून 1970 के अन्त में 291.5 करोड़ रुपये थी अर्थात् उसका स्तर पिछले वर्ष की अपेक्षा उच्चतर था।

82. 1969 के कम कामकाज के समय शुरू होने के पहले जिस ऋण नीति की घोषणा की गयी थी उसका उल्लेख पिछली रिपोर्ट में किया गया था। जमाराशियों में 1968 के कम कामकाज के समय में 239 करोड़ रुपये की जो वृद्धि हुई थी उसकी तुलना में 1969 के कम कामकाज के समय में 348 करोड़ रुपये की भारी वृद्धि हुई। फिर भी, वह 1968-69 के अधिक कामकाज के समय में हुई 325 करोड़ रुपये की वृद्धि से बहुत अधिक नहीं थी। 1969 के कम कामकाज के समय में जमाराशियों में हुई वृद्धि की दर 7.8 प्रतिशत थी जो उसके पहले के 1968-69 के अधिक कामकाज के समय में हुई 7.9 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में थोड़ी कम थी परन्तु वह 1968 के कम कामकाज के समय में हुई 6.2 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में अधिक थी। जमाराशियों में हुई कुल वृद्धि में सीमादी जमाराशियों में हुई वृद्धि का अंश लगभग 67 प्रतिशत था जब कि 1968 के कम कामकाज के समय में यह अंश 95 प्रतिशत था। इसके विपरीत, बैंक ऋण में 31 करोड़ रुपये की गैर मौसमी वृद्धि हुई जब कि 1968 के कम कामकाज के समय में उस में 43 करोड़ की कमी हुई थी। फिर भी ऋण-जमा अनुपात एक वर्ष पहले के 73.7 प्रतिशत की तुलना में अनुषु 1969 के अन्त में कम अर्थात् 72.9 प्रतिशत था।

सारणी 14—ग्रनुसंचित वाषिष्ठ बैंकों के प्रांकड़ों में मौसमी घट-बढ़

(करोड़ रुपये में)

कम कामकाज का समय 1968		अधिक कामकाज का समय 1968-69		अधिक कामकाज का समय 1969-70		निम्नलिखित तारीख तक का कम कामकाज का समय	
						26 जून 1970*	27 जून 1969
1. बैंक ऋण	-42.9	+426.9	+31.3	+561.6	+173.4	+137.6	
2. सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	+138.7	-2.4	+239.5	-53.9	+34.5	+73.4	
(अ) सरकारी प्रतिभूतियों में	+133.9	-43.0	+208.3	-101.0	+22.5	+68.5	
(आ) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	+4.8	+40.6	+31.2	+47.1	+12.0	+4.9	
3. होथ में नकदी और रिजर्व बैंक के पास बकाया	+30.2	+20.2	+26.7	+6.8	+26.4	+99.4	
4. माग और ब्रह्मसूत्रा पर प्रतिद्वय राशि	+34.6	+6.7	-25.8	-14.2	+4.4	+3.2	
5. कुल जमा राशियाँ	+238.9	+324.9	+348.1	+318.5	+133.2	+205.8	
(अ) मांग	+12.3	+145.1	+115.0	+170.3	42.6	+124.1	
(आ) सीमादी	+226.6	179.8	+233.1	+148.2	90.6	+81.7	
(अ) सीमादी	-81.9	+70.8	-67.5	+203.0	55.0	+71.2	

*अनन्तिम

नोट: (1) ये आकड़े बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आश्रयनम्, 1934 की धारा 42(2) के अन्तर्गत प्राप्त हैं।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त साप्ताहिक उद्यार सूचनाओं पर आधारित है।

(७) ब्रम्ह-बुद्ध के आंकड़े अप्रैल और अक्तूबर के अन्तिम बुधवार के आंकड़ों पर आधारित हैं।

सारणी 15—असंचित वाणिज्य बैंकों के प्रमुख अनुपातों का औसत स्वरूप

(करोड़ रुपयों में)

	अक्तूबर, 1968		मार्च, 1969		अक्तूबर, 1969		मार्च, 1970		जून, 1970		जून, 1969	
	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
1. बैंक ऋण	3034.4	73.7	3461.3	78.0	3492.6	72.9	4054.2	79.4	4227.6	80.7	3538.8	77.5
2. सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	1288.0	31.3	1285.6	28.9	1525.1	31.8	1471.2	28.8	1550.7	28.7	1358.9	29.2
(क) सरकारी प्रतिभूतियों में	1100.8	26.8	1057.8	23.8	1266.1	26.4	1165.1	22.8	1187.6	22.7	1126.3	24.2
(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	187.2	4.5	227.8	5.1	259.0	5.4	306.1	6.0	318.1	6.0	232.6	5.0
3. तकदी और रिजर्व बैंक के पास बकाया	260.7	6.3	280.9	6.3	307.6	6.4	314.4	6.2	340.8	6.5	380.3	8.2
4. बोली और ग्रन्थसूचना पर जमा	78.2	..	84.9	..	59.1	..	44.9	..	49.3	..	88.1	..
5. कुल जमा राशियाँ	4115.1	100.0	4440.0	100.0	4783.1	100.0	5106.6	100.0	5239.8	100.0	4645.8	100.0
(क) माँग	1834.3	44.6	979.4	44.6	2094.4	43.7	2264.7	44.3	2307.3	44.0	2103.5	45.3
(ख) सीमादी	2280.8	55.4	2460.6	55.4	2693.7	56.3	2841.9	55.7	2932.5	56.0	2542.3	54.7
6. रिजर्व बैंक से उधार	30.3	..	101.0	..	33.5	..	236.5	..	291.5	..	172.2	..

नोट : (1) प्रतिशत कुल जमा राशियों के अनुपात में है।

(1) प्रतिशत कुल जमा राशि का अनुपात है।
(2) ये बैंकों के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अन्तर्गत बैंक को द्वारा पेश की गई मासिक विवरणियों पर आधारित हैं। किन्तु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मासिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्राथमिक कार्यालयों से प्राप्त साप्ताहिक सूचनाओं पर आधारित हैं। सभी बैंकों में प्रचलित हैं।

*संज्ञान

83. कम कामकाज के समय के प्रारम्भ होने के पहले ही गर्वनर ने बैंकों से प्रार्थना की थी कि वे अपनी अधिशेष निधियों को सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में लगायें। तदनुसार 1969 के कम कामकाज के समय में बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किये गये निवेशों में क्रमशः 208 करोड़ और 81 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि की जबकि कि 1968 के कम कामकाज के समय में उनमें क्रमशः 134 करोड़ और 5 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। उक्त समय में बैंकों के निवेश-जमा अनुपात में लगभग 3 अंशों की वृद्धि हुई और वह अक्टूबर 1969 के अन्त में 31.8 प्रतिशत हो गया जबकि कि एक वर्ष पहले वह 31.3 प्रतिशत था। नकदी और रिजर्व बैंक के पास बकाया राशि में जो वृद्धि हुई वह 1968 के कम कामकाज के समय की तुलना में कुछ कम थी परन्तु नकदी अनुपात में 0.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई और वह 1969 के कम कामकाज के समय में अन्त में 6.4 प्रतिशत था। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से लिये गये उधारों की राशि जहाँ अप्रैल, 1969 के अन्त में 101.0 करोड़ रुपये थी वहाँ वह अक्टूबर 1969 के अन्त में बढ़कर 33.5 करोड़ रुपये हो गई। यह राशि एक वर्ष के पहले के स्तर से लगभग 3 करोड़ रुपये अधिक थी। बैंक संघटन की सुविधाओं पूर्ण वित्तीय स्थिति और रिजर्व बैंक द्वारा अग्रतावाले अन्तों की दी जानेवाली पुनर्वित्त सुविधाओं की जारी रखने के कारण 1968 के कम कामकाज के समय में मुद्रा बाजार में तंगी की स्थिति न रही। बंबई में बोली दर जहाँ अधिक कामकाज के समय के अन्त में 4 प्रतिशत थी वहाँ अगस्त 1969 के तीसरे सप्ताह में घटकर 3.1 प्रतिशत हो गई परन्तु उसके बाद वह लगातार 4 प्रतिशत तक बढ़ती गई और कम कामकाज के समय के अन्त तक वह उसी स्तर पर रही जब कि 1968 के कम कामकाज के समय के अन्त में वह 3.5 प्रतिशत के स्तर पर थी। कलकत्ता में बोली दर जहाँ अप्रैल, के अन्त में 3.7 प्रतिशत थी वहाँ मई 1969 के दूसरे सप्ताह में बढ़कर 4.6 हो गई, परन्तु अगस्त के अन्त में वह कम होकर 2.9 प्रतिशत हो गई। उसके बाद वह 1969 के कम कामकाज के समय के अन्त तक बढ़कर 3.7 प्रतिशत हो गई। 1968 के कम कामकाज के समय में, कलकत्ता में बोली दर 3.1 प्रतिशत और 1.4.8 प्रतिशत के बीच रही और उस समय के अन्त में 4.1 प्रतिशत थी।

84. 1 सितम्बर, 1969 को रिजर्व बैंक ने एक निदेश जारी कर बैंकों द्वारा चालू लेखों पर और 14 दिनों तक की अवधियों की जमा राशियों पर ब्याज दिये जाने और जमा राशियों पर दलासी की अवयवी किये जाने पर रोक लगा दी। जमा राशियों की अन्य श्रेणियों के लिये निर्धारित की गई ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और उन्हें उन्हीं स्तरों पर रखा गया जो जमा दरों से संबंधित पहले के अखिल भारतीय अन्तर्बैंक समझौते के अधीन लागू थे।

85. 1969 के कम कामकाज के समय में ऋण प्राधिकरण योजना और हुंडी नाजार योजना में क्रियाविधि संबंधी कृतिपय रियायतें भी की गईं। मई 1969 में अधिमों की कुछ श्रेणियों को रिजर्व बैंक से पूर्व प्राधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट दी गई इनमें से महत्वपूर्ण श्रेणियाँ इस प्रकार थीं: अनाज की उगाही सम्बन्धी कार्यकलापों की वित्तीय सहायता के लिये राज्य सरकारों, भारतीय खाद्य निगम और राज्य सहकारी बैंकों को दिये जाने वाले अधिम, सरकारी और दूसरी न्यासी प्रतिभूतियों पर दिये जाने वाले अधिम और राज्य बिजली बोर्डों और सरकारी अन्न के उपक्रमों को दिये जाने वाले अधिम। अगस्त 1969 में अन्तर्वैजीय प्रलेखी जिलों और अर्ध सरकारी संस्थाओं के नाम जारी किये गये सप्ताह जिलों की खरीद और भोजन के सम्बन्ध में भी पूर्व प्राधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट दी गई।

86. भारतीय उर्वरक संघ द्वारा घाट उर्वरक ऋण समिति की सिफारिशों के अनुसार अगस्त 1969 में बैंक ने उर्वरकों के वितरण के लिये दिये जाने वाले अधिम से संबंधित भीमादी बचन पत्रों की न्यूनतम रकम को 50,000 रुपये से घटाकर 25,000 रुपये और किसी बैंक द्वारा किसी एक समय पर जो न्यूनतम राशि उधार ली जा सकती है उसे 5 लाख रुपये से घटाकर एक लाख रुपये कर दिया। रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये जाने वाले अधिमों के पुनर्वित्त के संदर्भ में भी इसी प्रकार की रियायत दी।

1969-70 के अधिक कामकाज के समय की ऋण नीति

87. प्रमुख बैंकों के अध्यक्षों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ 1 नवम्बर, 1969 को हुई बैठक में रिजर्व बैंक के गर्वनर ने 1969 के कम कामकाज के समय की बैंक व्यवसाय की प्रवृत्तियों की समीक्षा की और 1969-70 के अधिक कामकाज के समय की बैंक की नीति के सम्बन्ध में संकेत किया। यह अनुभव किया गया कि यद्यपि कृषि उत्पादन के लक्षण अनुकूल हैं, औद्योगिक उत्पादन में फिर से तेजी आ गई है और नियतों में बराबर वृद्धि की प्रवृत्ति रही है, फिर भी बैंकिंग संघटन के सामने ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की दिशा में निधियों के अप्रयोज्य होने की समस्या नहीं होगी क्योंकि चलमुद्रा की स्थिति में सुधार हुआ है और अधिक कामकाज के समय में तई जमा राशियों से उनके वित्तीय साधनों में वृद्धि होने की संभावना है। इस कारण और अपने कार्यकलापों की योजनाबद्ध बनाने में बैंकों को सहायता पहुंचाने की दृष्टि से बैंकों की ऋण नीति में कुछ सीमा तक स्थिरता बनाय रखने के उद्देश्य से 1969-70 के अधिक कामकाज के समय की ऋण नीति में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किया गया। वास्तविक चलमुद्रा अनुपात पर विचार किये बिना (i) धातुकर्म और इंजीनियरी उत्पादों के निर्यातकों को दिये जाने वाले पैकिंग ऋणों पर, (ii) निर्धारित आधार अवधि (नवम्बर 1968 से अप्रैल, 1969 तक) की अपेक्षा नियत ऋण में हुई वृद्धि के बराबर की रकम तक और (iii) कृषि और लघु उद्योगों को दिये गये (ऋण गारंटी संगठन द्वारा गारंटीकृत) अल्पावधि ऋणों की कुल बकाया राशि के बराबर की रकम तक 4½ प्रतिशत की दर पर पुनर्वित्त उपलब्ध किया गया। इसके अतिरिक्त, वास्तविक चलमुद्रा अनुपात का विचार किये बिना (i) धातुकर्म और इंजीनियरी माल को छोड़कर अन्य माल के निर्यातकों को दिये जाने वाले पैकिंग ऋणों और पोतलदानो-त्तर नियत ऋण पर और (ii) अनाज की उगाही सम्बन्धी कार्यकलापों के लिये राज्य सरकारों, उनकी एजेंसियों और भारतीय खाद्य निगम को दिये जाने वाले अधिमों के सम्बन्ध में बैंक दर पर पुनर्वित्त बराबर प्रदान किया जाता रहा। इसके अलावा निर्धारित आधार अवधि की अपेक्षा नियत अन्न को दिये जाने वाले ऋण में हुई वृद्धि को वास्तविक चलमुद्रा अनुपात का हिसाब लगाने के उद्देश्य के लिये बैंकों की घल आस्तियों के रूप में बराबर माना गया। अन्त में, यदि बैंक विनिष्ट क्षेत्रों से ऋण की आकस्मिक वा विशेष भारी मांगों का अनुभव करें तो रिजर्व बैंक ने योग्य मामलों में उनको पहले की तह बैंक दर पर वित्ताधीन वित्तीय विभाज देने पर विचार करता स्वीकार किया।

88. फिर भी 1968-69 के अधिक कामकाज के समय की स्थिति के प्रतिकूल 1969-70 के अधिक कामकाज के समय के प्रारम्भ से बहुत अधिक वृद्धि हुई। अधिक कामकाज के इस समय के पहले तीन महीनों में ऋण में 277 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि 1968-69 की तदनुकपी अवधि में उसमें 112 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। साथ ही, सूच्यों में गैर-मौसमी वृद्धि हुई और जनवरी 1970 में धोक सूच्यों का मासिक औसत सूचकांक एक वर्ष पहले के स्तर से 6.8 प्रतिशत अधिक था। 5 फरवरी, 1970 को बैंकों के नाम लिखे गये अपने पत्र

में गवर्नर ने बैंकों का ध्यान इस मौसम में बैंक ऋण में और रिजर्व बैंक से बैंकों द्वारा लिये गये उधारों में हुई अत्यधिक वृद्धि की और आकर्षित किया और यह बताया कि ऋण में जो वृद्धि हुई है वह उत्पादन और विपणन की वास्तविक आवश्यकताओं की तुलना में बहुत अधिक है। अतः उन्होंने बैंकों को यह सलाह दी कि वे ऋण पर पर्याप्त रोक लगाये और इस मौसम में जिन क्षेत्रों में ऋण विस्तार हुआ है उनका सावधानी से अध्ययन करें। रिजर्व बैंक से सुनिश्चित सुविधायें प्राप्त करने की बैंकों की जो प्रवृत्ति है उसे संयमित करने और ऋण विस्तार पर रोक लगाने के उद्देश्य से अनाजों की उगाही के लिये दिए जाने वाले अधिमों के सम्बन्ध में, बैंक के वास्तविक चलमुद्रा अनुपात पर विचार किये बिना बैंक दर पर दी जानेवाली पुनर्वित्त विधा को वापस ले लिया गया और कृषि को दिये जाने वाले अल्पकालीन ऋण की कुल राशि तक 4 प्रतिशत की दर दी जाने वाली पुनर्वित्त सुविधा को बन्द कर दिया गया और केवल कृषि के लिये दिये जाने वाले प्रत्यक्ष ऋणों को बैंक दर पर पुनर्वित्त सुविधा पाने के योग्य बनाया गया। बैंकों से यह भी कहा गया कि वे एक महीने के भीतर अपने सांविधिक चलमुद्रा अनुपात में शामिल की गई अपनी आस्तियों को कुल मांग और मावधि देयताओं के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 26 प्रतिशत कर दें।

89. इसके बाद, 18 फरवरी, 1970 को बैंकों के अध्यक्षों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों और रिजर्व बैंक के गवर्नर ने 1969-70 के अधिक कामकाज के समय के पहले तीन महीनों की ऋण और जमा की प्रवृत्तियों का पुनरीक्षण किया। चूंकि 1969-70 के अधिक कामकाज के समय में ऋण में बराबर वृद्धि होती रही, अतः गवर्नर ने बैंकों से कहा कि वे ऋण देने में अत्यन्त सावधानी बरतें और ऋण के अंतिम उपयोग के सम्बन्ध में अधिक सतर्क रहें। गवर्नर ने बैंकों से यह भी आग्रह किया कि वे रिजर्व बैंक से सहायता मांगने के बजाय जमाराशियों के रूप में अपने द्वारा जुटाये जाने वाले वित्तीय साधनों पर अधिक निर्भर रहें। चूंकि बैंक रिजर्व बैंक की पुनर्वित्त सुविधाओं का अधिक मात्रा में लाभ उठाते रहे, अतः बैंकों को दी जाने वाली पुनर्वित्त सुविधाओं की अग्रतावाले क्षेत्रों को दिये गये ऋण में निर्धारित आधार अवधि की अपेक्षा हुई वृद्धि के बराबर की रकम तक और सीमित कर दिया गया। साथ ही, बैंक दर पर पुनर्वित्त प्राप्त करने योग्य न्यूनतम वास्तविक चलमुद्रा अनुपात को भी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया गया और अप्रैल 1970 के अन्तिम शुक्रवार तक उसे और बढ़ाकर 32 प्रतिशत कर देना था। बैंकों से यह भी कहा गया कि वे अप्रैल, 1970 के अन्तिम शुक्रवार तक सांविधिक चलमुद्रा अनुपात से संबंधित अपनी आस्तियों को 26 प्रतिशत कर से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दें।

90. बैंक ने ऋण विस्तार को रोकने और बैंकों द्वारा जमाराशियों के जुटाये जाने की प्रोत्साहित करने के लिये कुछ अतिरिक्त उपाय भी किये। बैंक ने 21 जनवरी 1970 को अधिमों के लिये 2 मार्च 1968 को निश्चित की गई 9½ प्रतिशत की उच्चतम व्याज दर को रद्द कर दिया। यह उच्चतम सीमा बड़े भारतीय अनुसूचित बाणिज्य बैंकों और भारत में कार्यशील विदेशी बैंकों के लिये लागू की गई थी। फिर भी, निर्यात ऋण के खर्च को पर्याप्त मात्रा में कम करने की दृष्टि से बैंकों द्वारा दिये जाने वाले निर्यात ऋण (पोतलदानपूर्व और पोतलनानोत्तर दोनों) के लिये बैंक ने 6 प्रतिशत की उच्चतम व्याज दर को बराबर जारी रखा। अधिमों से संबंधित 9½ प्रतिशत की उच्चतम दर रद्द कर देने और डाक जमाराशियों की कतिपय अधिमों की व्याज दरों में वृद्धि हो जाने के कारण, रिजर्व बैंक ने 28 मार्च 1970 को बैंकों द्वारा दो वर्षों और उससे अधिक अवधियों की जमाराशियों पर देय व्याज की दर में ½ प्रतिशत से ¾ प्रतिशत तक की वृद्धि की, परन्तु बचस

जमाराशियों और दो वर्षों से कम अवधियों की सीमादी जमाराशियों की व्याज दरों को पहले के स्तरों पर ही रखा गया। नई दरें 1 अप्रैल 1970 से लागू हुईं। साथ ही, ऋण को और अधिक उचित ढंग से वितरित करने और उधारकर्ताओं को अपनी ऋण आवश्यकताओं का अनुमान लगाने में अधिक सावधानी बरतने के लिये प्रेरित करने की दृष्टि से, रिजर्व बैंक ने बैंकों के नाम 28 मार्च 1970 को एक निदेश जारी किया जिसके जरिये उनसे कहा गया कि वे 10 लाख और उससे अधिक रूपयों की ऋण सीमाओं के उपयोग न किये गये भंडार पर 1 अप्रैल, 1970 से वार्षिक 1 प्रतिशत का बायबा प्रभार लगायें। वेशी निर्यात और आयात वित्तों, निर्यातों के लिये पैकिंग ऋण, आयातों के लिये खोले गये साखपत्रों, माल के आयात के सम्बन्ध में दी गई ग्यास्त-रसीद सुविधाओं, उगाही सम्बन्धी कार्यकलापों के लिये दी गई ऋण सीमाओं और सोयाबीन तथा सूर्यमुखी तेल के संग्रह और वितरण के लिये राज्य व्यापार निगम को दी गई ऋण सीमाओं के सम्बन्ध में उचित छूट दी गई है।

91. अनाजों की उगाही के लिये दिये गये अधिमों के सम्बन्ध में बैंक दर पर दी जानेवाली पुनर्वित्त सुविधा को 5 फरवरी, 1970 से रद्द कर देने के कारण अनाजों की उगाही से संबंधित कार्यकलापों के लिये बराबर वित्तीय सहायता देते आने वाले बैंकों ने दूसरे अग्रतावाले क्षेत्रों और सीनी उद्योग जैसे जन कतिपय उद्योगों, जिनके सामने अत्यधिक मात्रा में स्टॉकों के जमा हो जाने की समस्या थी, को बढ़ती हुई वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कठिनाई अनुभव की। अतः बैंकों ने अप्रैल 1970 में बैंकों द्वारा अनाजों की उगाही के उद्देश्यों के लिये दिये गये अधिमों में मार्च 1970 को समाप्त हुई तिमाही में दिये गये ऐसे अधिमों के औसत स्तर पर की तुलना में हुई वृद्धि के 80 प्रतिशत के लिये बैंक दर पर पुनर्वित्त प्रदान करना स्वीकार किया। यह सुविधा जुलाई 1970 के तीसरे शुक्रवार तक दी गई और उसके बाद उक्त सुविधा को ऐसे अधिमों के वकाया स्तर के 50 प्रतिशत तक कम किया जाने वाला था।

व्यवसायिक ऋण नियंत्रण

92. व्यवसायिक ऋण नियंत्रण सम्बन्धी उपायों के संवर्धन में पटसन की पूर्ति में पर्याप्त सुधार और उसके मूल्यों में गिरावट हो जाने के बाद बैंक ने सितम्बर 1969 में जूट मिलों को छोड़कर अन्य पाटियों को पटसन पर और जूट के पक्के डिलिबरी आर्डरों पर दिये जाने वाले अधिमों पर प्रकटुबर 1968 में लगाये गये प्रतिबंधों को वापस ले लिया। फिर भी हाल ही के महीनों में तिलहनों वनस्पति तेलों और रुई की पूर्ति की स्थिति में कठिनाई आ जाने और इन वस्तुओं के मूल्यों में तेजी से वृद्धि होने के कारण रिजर्व बैंक प्राक इंडिया ने 21 जनवरी 1970 को एक निदेश जारी कर तिलहनों वनस्पति तेलों और रुई तथा कपास पर दिये जाने वाले ऋणों पर लगाये गये नियंत्रणों को और कड़ा कर दिया। इस निदेश के अनुसार अनाजों पर दिये जाने वाले अधिमों पर लगाये गये नियंत्रण को भी और कड़ा कर दिया गया ताकि बैंक-वित्त की सहायता से बहुत अधिक स्टॉक का संग्रह करने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित किया जाय। तिलहनों और (वनस्पति सहित) वनस्पति तेलों पर दिये जाने वाले अधिमों के न्यूनतम मार्जिन को सभी पाटियों को दिए जाने वाले अधिमों के लिये समान रूप से स्टॉकों के मूल्य के 60 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया। अनाजों पर दिये जाने वाले अधिमों के मार्जिन को भी बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। ऋण के अनुमत स्तरों की तिलहनों और वनस्पति तेलों के मामले में 1967 में किसी बैंक द्वारा बनाये रखे गये अधिमों के कुल औसत स्तर के 70 प्रतिशत और अनाजों के मामलों में 1968 के ऐसे स्तर के 80 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया। मिलों को छोड़कर अन्य पाटियों को रुई और कपास पर दिये जाने वाले

अधिमों के न्यूनतम माजिन को 50 प्रतिशत में बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया और सूची वस्तु गिणो को बिये जाने वाले अधिमों पर 40 प्रतिशत का न्यूनतम माजिन और उच्चतम सीमा निर्धारित कर पुनः नियंत्रण लगा दिया गया। उक्त उच्चतम सीमा नवम्बर 1969-अप्रैल 1970 से प्रारम्भ होने वाली प्रत्येक छमाही अवधि के लिये 1967-68 (नवम्बर-अक्तूबर) की तदनुसूची अवधि के सर्वोच्च स्तर के 85 प्रतिशत के बराबर होगी। इस निदेश से आयात की गई रूई के स्टार्कों पर दिये जाने वाले अधिमों और रूई और कपास के निर्यातकों को दिये जाने वाले अधिमों को बराबर छूट दी जाती रही। इन नियंत्रणों के प्रभाव की ओर बढ़ाने के लिये बैंक ने अनाजों, मिनहनों, (वनस्पति सहित) वनस्पति तेलों और रूई तथा कपास पर दिये जाने वाले अधिमों के लिये 10 प्रतिशत की न्यूनतम दर भी निर्धारित की। बैंकों द्वारा भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकारों और उनके अनुमोदित एजेंटों को अनाज की उगाही और वितरण के लिये दिये गये अधिमों को इस निदेश के उपबन्धों से बराबर छूट दी गई। आयात किये गये पूर्वमुन्नी तेल पर दिये जाने वाले अधिमों को 11 मार्च 1970 को नियंत्रण से पूर्ण रूप से छूट दी गई। रिजर्व बैंक ने 17 मार्च 1970 को बैंकों को यह निदेश दिया कि वे 21 जनवरी 1970 के निदेश से प्रभावित पार्टियों को निर्वन्ध अधिमों या निर्वन्ध बिलों के भोजन के रूप में ऋण सुविधायें प्रदान न करें। 11 अप्रैल 1970 को बैंकों को यह सलाह दी गई कि वे माँग प्रलेखी बिलों पर ऋण देने में अत्यधिक सावधानी बरते ताकि उनके आहूतों को ऐसे ऋणों का दुरुपयोग करने से रोका जा सके। तिलहनों, वनस्पति तेलों और रूई तथा कपास के मूल्यों में लगातार होने वाली वृद्धि को देखते हुए बैंक ने 28 अप्रैल 1970 को बैंकों को यह निदेश दिया कि वे सभी उधारकर्तियों के सम्बन्ध में ऐसे अधिमों पर दिये जाने वाले ध्याज की न्यूनतम दर को वार्षिक 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दें। सूची मिलों को छोड़कर अन्य पार्टियों को देशी रूई और कपास पर दिये जाने वाले अधिमों के न्यूनतम माजिन को भी 60 प्रतिशत बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया। सरकार के स्वाभिन या प्रबन्ध के अधीन रहने वाली मिलों और विनीय दृष्टि से कमजोर मिलों को रूई पर दिये जाने वाले अधिमों के सम्बन्ध में कतिपय छूटें दी गई।

93. गुड़ की पूर्ति की स्थिति में सुधार और उसके मूल्यों में काफी गिरावट होने के कारण बैंक ने गुड़ पर दिये जाने वाले अधिमों पर लगाये गये नियंत्रण को 21 जनवरी 1970 को वापस ले लिया। भारतीय खाद्य निगम से खरीदे गये गेहूँ के सम्बन्ध में अदायगी करने में घाटे की बेलन मिलों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को दूर करने के लिये रिजर्व बैंक ने 10 अप्रैल 1970 को बैंकों को यह सलाह दी कि वे घाटे की बेलन मिलों को दिये जाने वाले अधिमों पर पहले के 50 प्रतिशत के माजिन को घटाकर 25 प्रतिशत का माजिन लागू करें। रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा घाटे की बेलन मिलों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिये गये अधिमों पर लगाये गये उच्चतम सीमा सम्बन्धी प्रतिबन्धों को भी हटा दिया। जो पर दिये जाने वाले बैंक अधिमों को 28 अप्रैल 1970 को नियंत्रण से छूट दी गई।

94. चीनी के उत्पादन में हुई भारी वृद्धि और चीनी के खुले बाजार मूल्यों में गिरावट हो जाने के कारण बैंक ने चीनी पर दिये जाने वाले बैंक अधिमों पर 27 अप्रैल 1963 को लगाये गये अपने नियंत्रण को 4 मई 1970 को हटा दिया। इसके पहले चीनी की मिलों को उन स्टार्कों के सम्बन्ध में जो कारखाने में बाहर जा चुके हैं और जिनपर उत्पादन शुल्क भरा किया जा चुका है और चीनी की मिलों को छोड़कर अन्य पार्टियों को चीनी पर दिये जाने वाले बैंक-अधिमों के लिये 45 प्रतिशत का न्यूनतम माजिन निर्धारित किया गया था। उसके बाद रिजर्व बैंक ने 30 मई 1970 को बैंकों को यह सलाह दी कि वे चीनी की मिलों को

अतिरिक्त वित्तीय सहायता दें ताकि वे अपना पेन्ने का कार्य जारी रख सकें। बैंकों का यह भी सलाह दी गई कि वे चीनी की उगाही और मुक्त चीनी के लिये एक ही माजिन निर्धारित करें। सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क-दर मूल्य या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो वह मुक्त चीनी के माजिन का आधार होगा।

95. वनस्पति के उत्पादन करने वाले यूनिटों से इस आणव्य अभिवेक प्राप्त होने पर कि वे बैंक ऋण पाने में कठिनाई अनुभव करते हैं बैंक ने वनस्पति यूनिटों और रजिस्ट्रीकृत तेल मिलों को दिये जाने वाले अधिमों पर लगाये गये प्रतिबन्धों को 8 जून 1970 को शिथिल कर दिया; इन उत्पादन यूनिटों को बैंक ऋण पर लगाये गये उच्चतम सीमा सम्बन्धी वर्तमान प्रतिबन्धों से छूट दी गई। बैंकों से भी कहा गया कि वे वनस्पति यूनिटों को वनस्पति तेलों पर दिये जाने वाले अधिमों पर 40 प्रतिशत के माजिन को लागू करें। फिर भी यह कम किया हुआ माजिन वनस्पति तेलों के केवल उन स्टार्कों पर लागू होगा जो उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक कारखाने के छः सप्ताहों की खपत और दक्षिणी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक कारखाने के 4 सप्ताहों की खपत के बराबर होंगे और इसका हिसाब निदिष्ट माप्ताहिक खपत के आधार पर लगाया जायेगा। जहाँ कच्चे भात का मूल्य नियति की जाने वाली तेल रहित खली के मूल्य से अधिक है वहाँ बैंक ने विलायक निस्तारण यूनिटों को निस्सारित तेल पर दिये जाने वाले अधिमों को भी इस नियंत्रण से छूट दी। घलसी और अंडी के तेलों को छोड़कर दूसरे अखाद्य वनस्पति तेलों पर दिये जाने वाले अधिमों पर लगाये गये उच्चतम सीमा सम्बन्धी प्रतिबन्ध को भी हटा दिया गया है।

1969-70 के अधिक कामकाज के समय में बैंक व्यवसाय की प्रवृत्तियाँ

96. 1968-69 के अधिक कामकाज के समय की अपेक्षा 1969-70 के अधिक कामकाज के समय में बैंक ऋण में बड़ी भारी वृद्धि हुई। इसके विपरीत पिछले वर्ष के अधिक कामकाज के समय की अपेक्षा इस वर्ष के अधिक कामकाज के समय में जमागणियाँ जुटाने के कार्य की गति में थोड़ी सी मंदी थी। इस समय में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये ऋण में 562 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि 1968-69 और 1967-68 के अधिक कामकाज के समय में यह वृद्धि क्रमशः 427 करोड़ रुपये और 509 करोड़ रुपये थी। अनाज की उगाही सम्बन्धी अधिमों को छोड़कर शेष ऋणों में 1969-70 के अधिक कामकाज के समय में 589 करोड़ रुपयों की जो वृद्धि हुई वह पिछले अधिक कामकाज के समय में हुई 419 करोड़ रुपयों की वृद्धि से अधिक थी। 1969-70 के अधिक कामकाज के समय में बैंकों द्वारा दिये गये ऋण के प्रति-भूति शार विलेपण (अनुमानों पर आधारित से यह पता लगता है कि धनाजों पर दिये गये अधिमों में 1968-69 के अधिक कामकाज के समय की अल्प वृद्धि की अपेक्षा भारी कमी हुई और तिलहनों और रूई तथा कपास पर दिये गये ऋण में हुई वृद्धि 1968-69 के अधिक कामकाज के समय की तुलना में कम थी। (वनस्पति सहित) वनस्पति तेलों और पटगन पर दिये गये अधिमों में 1968-69 की अपेक्षा भारी वृद्धि हुई। चीनी पर दिये गये अधिमों में 102 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि 1968-69 के उन्नी समय में यह वृद्धि 99 करोड़ रुपये थी। हमसे यह संकेत मिलता है कि चीनी उद्योग ने पिछले वर्ष की तुलना में दस वर्ष बैंक वित्त की सहायता की अधिक अपेक्षा नहीं की। निमित्त वस्तुओं में सूची कपड़ों पर दिये गये ऋणों में अधिक वृद्धि हुई जिससे यह पता लगा कि उक्त उद्योग के पाय तैयार माव के स्टार्क इकट्ठा हो गये थे। जूट से बने वस्त्रों पर दिये गये ऋण में 1968-69 के अधिक कामकाज के समय की अपेक्षा केवल मामूली वृद्धि हुई। लोहे तथा इस्पात और इंजीनियरी माल पर दिये गये अधिमों में 58 करोड़ रुपयों की भारी

वृद्धि हुई जबकि 1968-69 के अधिक कामकाज के समय उनमें 13 करोड़ रुपयों की कमी हुई थी इसके विपरीत रासायनिक पदार्थों रंगों दवाइयों और औषधियों पर दिये गये ऋणों में पिछले अधिक कामकाज के समय में हुई 48 करोड़ रुपयों की भारी वृद्धि की तुलना में इस वर्ष 19 करोड़ रुपयों की कमी हुई। गैर-जमानती अधिमों में भी पिछले अधिक कामकाज के समय में हुई 56 करोड़ रुपयों की वृद्धि की तुलना में इस वर्ष 36 करोड़ रुपयों की कम वृद्धि हुई।

97. 1969-70 के अधिक कामकाज के समय में 319 करोड़ रुपयों की जमाराशियां जुटाई गई जो 1968-69 के अधिक कामकाज के समय में जुटाई गई 325 करोड़ रुपयों की जमाराशियों की तुलना में कम थी। इसके फलस्वरूप ऋण-जमा अनुपात अप्रैल 1969 के अन्त

में विद्यमान 78.6 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल 1970 के अन्त में उससे अधिक अर्थात् 79.4 प्रतिशत था। 1969-70 के अधिक कामकाज के समय में सावधि जमाराशियों की अपेक्षा मांग जमाराशियों में अधिक वृद्धि हुई जबकि 1968-69 के अधिक कामकाज के समय में सावधि जमाराशियों में अधिक वृद्धि हुई थी। वस्तुतः सावधि जमाराशियों में 148 करोड़ रुपयों की जो वृद्धि हुई वह 1969 के कम कामकाज के समय में हुई 233 करोड़ रुपयों की वृद्धि की तुलना में बहुत कम थी। 1968-69 के अधिक कामकाज के समय में भी सावधि जमाराशियों में 180 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी। सावधि जमाराशियों में जो कम वृद्धि हुई उसके लिये मूल्यों में हुई वृद्धि और 1969-70 के अधिक कामकाज के समय में निधियों की मांग के कारण उत्पन्न दबाव को कुछ हद तक कारण कहा जा सकता है।

सारणी 16—बैंक ऋण की सामयिक प्रवृत्तियाँ : प्रतिमूतिवार वर्गीकरण

(करोड़ रुपयों में)

	अधिक कामकाज का समय 1967-68	कम कामकाज का समय 1968	अधिक कामकाज का समय 1968-69	कम कामकाज का समय 1969	अधिक कामकाज का समय 1969-70†
सीसमी अधिम	+ 359.7	- 152.5	+ 206.8	+ 192.0	+ 123.0
धान और चावल	+ 63.0	- 36.6	+ 41.1	- 29.0	- 7.7
गेहूं	+ 12.4	+ 69.8	- 33.7	+ 14.4	- 59.4
अन्य अनाज	+ 29.9	- 10.9	+ 9.0	- 3.1	+ 17.2
चीनी	+ 123.0	- 104.6	+ 98.9	- 44.6	+ 102.4
गुड़	+ 4.5	- 5.2	+ 3.7	- 3.6	+ 8.9
मूंगफली	+ 8.2	- 7.1	+ 11.8	- 13.7	+ 5.9
अन्य तिलहन	+ 6.8	- 5.7	+ 13.9	- 17.0	+ 9.0
वनस्पति तेल	+ 11.2	- 2.2	+ 1.6	- 10.2	+ 10.2
रूई और कपास	+ 83.4	- 49.4	+ 68.1	- 86.9	+ 40.4
पटसन	+ 19.2	- 18.1	+ 1.0	- 6.1	+ 10.6
चाय	- 1.9	+ 17.5	- 8.6	+ 7.8	- 14.5
गैर सीसमी अधिम	+ 135.6	+ 89.6	+ 131.4	+ 185.0	+ 365.5
सूती वस्त्र	+ 22.5	+ 14.8	+ 0.5	+ 1.0	+ 27.9
जूट से बने वस्त्र	- 3.7	+ 9.4	+ 6.1	- 0.8	+ 7.1
लोहा, इस्पात और इंजीनियरी माल*	+ 6.0	+ 31.1	- 12.7	+ 44.9	+ 58.3
रासायनिक पदार्थ, रंग, पेंट, दवाइयाँ और औषधियाँ**	+ 23.2	+ 21.5	+ 48.2	+ 7.4	- 19.2
बिजली का सामान	+ 7.5	+ 4.7	- 6.7	+ 18.4	अनुः
औद्योगिक संस्थाओं की आस्तियाँ — चल या अचल	+ 0.3	+ 9.3	+ 4.7	+ 10.3	5.0
मिश्रित पूंजी कंपनियों के शेयर	+ 2.1	- 0.8	+ 3.0	- 1.5	+ 2.6
सरकारी और अन्य न्यासी प्रतिभूतियाँ	- 2.7	- 0.4	- 1.7	+ 0.6	अनुः
सोने और चांदी और बुलियन और गहने	+ 1.2	+ 3.6	+ 1.5	+ 8.4	अनुः
कुल जमानती अधिम	+ 495.3	- 62.9	+ 338.2	- 7.0	+ 488.5
गैर-जमानती अधिम	+ 3.5	+ 33.3	+ 55.8	+ 25.2	+ 35.6
कुल अधिम	+ 498.8	- 29.6	+ 394.0	+ 18.2	+ 254.1

स्त्रोत :—प्रतिभूति के अनुसार वर्गीकृत बैंकों के अधिमों का प्राथिकासासिक सर्वेक्षण। ये आंकड़े केवल रिपोर्ट देनेवाली शाखाओं से संबंधित हैं, अतः वे सारणी 14 में दिये हुये आंकड़ों से मेल नहीं खाते।

*इनमें बाहनों पर दिये गये अधिम शामिल हैं।

**इनमें उर्वरकों पर दिये गये अधिम शामिल हैं।

†बैंकों की चूनी हुई शाखाओं में प्राप्त सध्य-अप्रैल 1970 की विवरणियों पर आधारित अनुमान।

‡इनमें चाय के वागानों को छोड़कर अन्य वागान शामिल नहीं हैं।

§इनमें चाय के वागानों को छोड़कर अन्य वागान शामिल हैं।

अनुः—अनुपात

98. 1968-69 के अधिक कामकाज के समय में जहाँ सरकारी प्रतिभूतियों में किये गये निवेशों में से 43 करोड़ रुपये निकाल लिये गये थे वहाँ इस वर्ष की उसी अवधि में 101 करोड़ रुपये निकाल लिये गये। इसके परिणामस्वरूप निवेश जमा अनुपात जहाँ इस अवधि के प्रारम्भ में 26.4 प्रतिशत था वहाँ अप्रैल 1970 के अन्त में घटकर 22.8 प्रतिशत हो गया जो अप्रैल 1969 के अन्त के 23.8 प्रतिशत के स्तर से कम था। इस समय में नकदी और रिजर्व बैंक के पास बकायों में 7 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि 1968-69 के अधिक कामकाज के समय में उनमें 20 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। इस प्रकार नकदी अनुपात एक वर्ष पहले के 6.3 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल 1970 के अन्त में 6.2 प्रतिशत हो गया। रिजर्व बैंक से लिये गये उधारों के बकायों की राशि अप्रैल 1970 के अन्त में 237 करोड़ रुपये थी जो 1968-69 के अधिक कामकाज के समय के अन्त की राशि (101 करोड़ रुपये) से बहुत अधिक थी। 1968-69 के अधिक कामकाज के समय में जहाँ उनमें 71 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी वहाँ उनमें 1969-70 के अधिक कामकाज के समय में 203 करोड़ रुपयों की भारी वृद्धि हुई। ऋण की मांग के अधिक दबाव और रिजर्व बैंक द्वारा पुनर्वित्त सुविधाओं में की गई कमी के कारण बम्बई और कलकत्ता में अन्तर्बैंक बोली दर पिछले अधिक कामकाज के समय की अपेक्षा 1969-70 के अधिक कामकाज के समय में अधिक ऊँचे स्तर पर पहुँच गई। इस प्रकार बम्बई में 6 फरवरी 1970 तक 4 और 4½ प्रतिशत के बीच रहने वाली उक्त बोली दर में उसके बाद तेजी से वृद्धि हुई और वह 3 अप्रैल 1970 तक 8.9 प्रतिशत हो गई। बाद में वह घटकर 24 अप्रैल 1970 को 6½ प्रतिशत हो गई। कलकत्ता में भी फरवरी 1970 के पहले सप्ताह तक उक्त दर क्रमशः 4.8 प्रतिशत तक बढ़ी और 3 अप्रैल 1970 तक वह बढ़कर 9.00 प्रतिशत तक पहुँच गई। परन्तु उसके बाद वह घटकर 24 अप्रैल 1970 को 6.2 प्रतिशत हो गई। 1968-69 के अधिक कामकाज के समय में बम्बई और कलकत्ता में उस दर के सर्वोच्च स्तर क्रमशः 5 प्रतिशत और 6.1 प्रतिशत थे और अधिक कामकाज के समय के अन्त में वे काफी कम अर्थात् बम्बई में 4 प्रतिशत और कलकत्ता में 3.75 प्रतिशत थे।

99. 1970 के कम कामकाज के समय के पहले दो महीनों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण में बराबर वृद्धि होती रही उक्त समय में ऋण में 173.4 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि 1969 और 1968 की तदनुसूची अवधियों में क्रमशः 137.6 करोड़ और 25.6 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी। अनाजों की उगाही के लिये दिये गये ऋण में 1969 के कम कामकाज के समय में हुई 80 करोड़ रुपयों की वृद्धि की तुलना में इस वर्ष की तदनुसूची अवधि में 77 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई। चीनी चाय रासायनिक पदार्थ और दवाइयों तथा औद्योगिक संस्थाओं की आस्तियों पर दिये गये ऋण में 1969 की अपेक्षा 1970 के कम कामकाज के समय के पहले दो महीनों में काफी अधिक वृद्धि हुई। इसके विपरीत 1970 के कम कामकाज के समय के पहले दो महीनों में कुल जमा राशियों में 133.2 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि 1969 और 1968 की तदनुसूची अवधियों में क्रमशः 205.8 करोड़ और 93 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी। इसके परिणामस्वरूप इस अवधि में ऋण जमा अनुपात बहुत अधिक अर्थात् 80.7 प्रतिशत था जब कि वह 1969 और 1968 की तदनुसूची अवधि में क्रमशः 77.5 प्रतिशत और 78.2 प्रतिशत था। कुछ समय से बैंकों की वित्तीय माधन सम्बन्धी स्थिति पर तनाव बना रहा अतः रिजर्व बैंक से लिये जाने वाले उधारों में वृद्धि होती रही और वे 19 जून 1970 को 307 करोड़ रुपयों के उच्चतम स्तर पर पहुँच गये। इससे बाद वे सप्ताह में वे कम होकर 291.5 करोड़ रुपये हो गए, फिर भी वे एक वर्ष के पहले के स्तर से 119.3 करोड़ अधिक

ही थे। अतः बोली जमा बाजार में तंगी की स्थिति बनी रही और अन्तर्बैंक ऋण दर बम्बई में 6.5 प्रतिशत और कलकत्ता में 7.1 प्रतिशत थी। एक वर्ष पहले दोनों केन्द्रों में यह दर बहुत कम अर्थात् 3.5 प्रतिशत थी।

100. रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह सूचना दी कि हुंडी बाजार योजना के अधीन दी जाने वाली पुनर्वित्त सुविधाओं को जून 1970 के आगे भी जारी रखा जायेगा ताकि बैंक अप्रत्याशित क्षेत्रों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। बैंकों द्वारा चुने हुये राज्यों की प्राथमिक सहकारी समितियों को दिये जाने वाले ऋणों और कृषि को दिये जाने वाले प्रत्यक्ष अत्यावधि ऋणों तथा लघु उद्योगों को दिये जाने वाले ऋण गारन्टी-संगठन द्वारा गारन्टीकृत अत्यावधि ऋणों के सम्बन्ध में ये सुविधायें उपलब्ध होंगी। फिर भी पुनर्वित्त की राशि इन क्षेत्रों को दिये गये बैंक ऋणों के बकायों की कुल राशि से अधिक नहीं होगी। अनाज की उगाही और उर्वरकों के वितरण के लिये दिये गये बैंक अग्रिमों के लिये भी पुनर्वित्त सुविधायें 30 जून 1970 के बाद उपलब्ध होती रहेंगी।

निर्यात बिल

101. निर्यातों के संदर्भ में, बैंकों द्वारा दिये जाने वाले निर्यात ऋण (पैकिंग ऋण और पोतलदानोत्तर ऋण) के लिए बैंक अपनी पोतलदानपूर्व ऋण योजना और निर्यात बिल ऋण योजना के अधीन पुनर्वित्त प्रदान करता रहा। विशेष परिस्थितियों और अलग-अलग पण्यों के निर्यातकों की वाणिज्यिक प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए पोतलदानपूर्व ऋण योजना के अधीन क्रियाविधि संबंधी आवश्यकताओं में आवश्यकतानुसार या तो संशोधन किया गया या उनसे छूट दी गयी। जून 1969 में बैंकों द्वारा भाड़ा संबंधी विभेदक दावों पर दिये जानेवाले ऋणों और अग्रिमों को भी निर्यात ऋण (व्याज उपदान) योजना के अधीन व्याज उपदान के लिए योग्य बनाया गया क्योंकि उन्हें पोतलदानोत्तर ऋण का अंश माना गया। तदनुसार, इन अग्रिमों पर भी निर्यात ऋण के अन्य प्रकारों पर लागू की गयी वार्षिक 6 प्रतिशत की उच्चतम व्याज दर का प्रतिबन्ध लगाया गया।

102. अनुचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये जानेवाले निर्यात ऋण के संदर्भ में उनके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त किये जानेवाले पुनर्वित्त की रकम में लगातार वृद्धि होती रही है। जून 1970 के अंत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्यातों के लिए दिये गये पैकिंग ऋण और पोतलदानोत्तर ऋण के सबध में दिये गये पुनर्वित्त की बकाया रकम क्रमशः 53.9 करोड़ और 52.3 करोड़ रुपये थी। बैंक अपने द्वारा दिये गये निर्यात ऋण के लिए भी व्याज उपदान लेते रहे। आलोच्य अवधि में 40 योग्य वाणिज्य बैंकों से व्याज उपदान के दावे प्राप्त हुए और उन्हें कुल मिलाकर 3.52 करोड़ रुपयों की रकम अदा की गयी। इस रकम में से पोतलदानपूर्ण ऋण और पोतलदानोत्तर ऋण की राशि क्रमशः 1.60 करोड़ रुपये और 1.92 करोड़ रुपये थी।

103. रिजर्व बैंक ने रिजर्व ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17 (3क) के अधीन बनायी गयी अपनी पुनर्वित्त योजना और निर्यात ऋण (व्याज उपदान) योजना को बैंकों द्वारा मशीनों के औजारों के उत्पादकों, निर्माण ठेकेदारों और चमड़ा कमानेवालों को दिये जानेवाले पोतलदानपूर्व अग्रिमों के लिए भी किया। मशीन के औजारों के वास्तविक उत्पादक-निर्यातक पक्के निर्यात आर्डरों/साखपत्रों को बैंकों के पास पहले ही रखे बिना भी कुछ शर्तों के अधीन पैकिंग साख अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं। बैंक वास्तविक ठेकेदारों को भी विदेशों में ठेकों का निष्पादन करने के लिए उनकी प्रारंभिक कार्यकारी पूंजी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के निमित्त निर्यात ऋण पर लागू होने वाले व्याज की दर पर कतिपय सुरक्षा शर्तों के अधिन अग्रिम दे सकते हैं। इसी प्रकार, उन चमड़ा कमानेवालों

सारणी 17—अनुसूचित बाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि, लघु क्षेत्र और निर्यातों के लिए दिये गये अग्रिम

(करोड़ रुपये में)

	स्टेट बैंक आफ इंडिया और उसके 14 राष्ट्रीयकृत बैंक सहयोग बैंक				सरकारी क्षेत्र के कुल बैंक				दूसरे अनुसूचित बाणिज्य बैंक			
	लेखों की संख्या	रकम	लेखों की संख्या	रकम	लेखों की संख्या	रकम	लेखों की संख्या	रकम	लेखों की संख्या	रकम	लेखों की संख्या	रकम
1. कृषि-अग्रिमों का जोड़*												
जून 1969	37740	99.91	126741	62.42	164481	162.33	102545	26.08	267026	188.41		
मार्च 1970	204715	125.34	312403	124.20	517118	249.54	192570	36.54	709688	286.08		
उपरोक्त में कृषकों को दी गई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता*												
जून 1969	37031	11.06	122989	2916	160020	40.22	97378	13.39	257398	53.61		
मार्च 1970	203419	46.53	299679	82.85	503098	129.38	188905	21.05	692003	150.43		
2. लघु क्षेत्र को दिये गये अग्रिमों का जोड़												
(क + ख + ग)												
जून 1969	37688	103.01	36801	153.79	74489	256.86	10791	37.30	85280	294.10		
मार्च 1970	55774	155.22	66309	214.86	119083	370.08	16047	48.51	135130	418.59		
(ख) मछली पकड़ने वालक												
जून 1969	2	..	2322	5.48	2324	5.48	1207	2.74	3531	8.20		
मार्च 1970	1215	2.98	8071	15.88	9286	18.86	1870	5.47	11156	24.33		
(ग) लघु उद्योग												
जून 1969	37686	103.01	34446	148.05	72132	251.06	9574	34.54	81706	285.60		
मार्च 1970	54559	152.24	55217	198.72	109776	250.96	14167	42.94	123943	393.90		
(घ) औद्योगिक आस्थानों की स्थापना के लिए ऋण												
जून 1969	—	—	33	0.26	33	0.26	10	0.02	43	0.28		
मार्च 1970	—	—	21	0.26	21	0.26	10	0.10	31	0.36		
3. निर्यात												
जून 1969	—	70.72	—	123.97	—	194.69	—	68.74	—	263.43		
मार्च 1970*	—	84.00	—	147.77	—	231.67	—	72.31	—	304.80		

स्त्रोत : बैंकों से प्राप्त विशेष विवरणियाँ।

नोट : ये आंकड़े महीने के अंतिम शुक्रवार के हैं।

*आगमनों को दिया गया विकास संबंधी वित्त शामिल है।

**अनुमति

... 50 हजार रुपये से कम।

को भी कुछ शर्तों के अधीन बैंकों द्वारा 6 प्रतिशत की दर पर दिये जाने वाले पैकिंग साख अग्रिमों के योग्य बनाया गया जो राज्य व्यापार निगम के जरिए निर्यात किये जाने के लिए जूतों के निर्माण करनेवालों की मांग पूर्ति करने के निमित्त निर्यात योग्य उत्तम चमड़े की सप्लाई करते हैं। ये अग्रिम रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने और निर्यात ऋण (व्याज उपदान) योजना के अधीन व्याज उपदान प्राप्त करने के लिए भी योग्य होंगे।

104. हीरों के निर्यातकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए और हीरों के निर्यात संबंधी विशेष वाणिज्यिक प्रणालियों के कारण जुलाई 1969 में बैंकों को यह अनुमति दी गई कि वे साख-पत्रों/पक्के निर्यात आर्डरों के दिये जाने का आग्रह किये बिना पोतलदानपूर्व अग्रिम प्रदान करें अन्त में निर्यात किये जाने के लिये हीरों को तराशने और पालिश करने के प्रयोजन से स्थानीय रूप से खरीदे गये या आयात किये गये अपरिष्कृत हीरों पर पोतलदानपूर्व ऋण योजना के अधीन 6 प्रतिशत से अधिक व्याज की रियायती दर पर अग्रिम दिये जायेंगे।

105. बैंकों द्वारा दिये जानेवाले गैर जमानती अग्रिमों और गारन्टीयों से संबंधित 'मानक' से भी उनके द्वारा दिये जाने वाले निर्यात ऋण को छूट दी गई है। बैंक ने जुलाई में यह निश्चय किया कि यदि प्रेषित यह वचन दें कि वे सीधे बैंक को बिना राशि भेजेंगे या माल लौटावेंगे तो इस 'मानक' के उद्देश्यों के लिये पारेषण के आधार पर किये जाने वाले निर्यातों के सम्बन्ध में निर्यातकों को दिये जाने वाले अग्रिमों को शामिल न किया जाये। औद्योगिक विकास बैंक भी योग्य बैंकों को मूलतः पूंजीगत और इंजीनियरी माल के निर्यात के लिये निर्यातकों को दिये जाने वाले मध्यावधि निर्यात ऋण पर पुनर्वित्त सुविधायें प्रदान करता रहा। इस प्रकार की सहायता के विवरण अध्याय 11 में दिये गये हैं।

कृषि, लघु उद्योग और अन्य क्षेत्रों को दिये जाने वाले अग्रिम

106. 19 जुलाई, 1969 को 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीय-कारण किये जाने से कृषि और लघु उद्योग जैसे अग्रतावाले क्षेत्रों को बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के कार्यक्रमों को और अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है और इन क्षेत्रों तथा सामाजिक वृद्धि से वांछनीय अन्य क्षेत्रों में बैंक अब पहले से अधिक विलम्बहीन ले रहे हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये प्रयत्नों का विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय 111 में दिया गया है।

107. कृषि उद्देश्यों के लिये अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिम जहां जून 1969 में 188.4 करोड़ रुपये थे वहां वे मार्च 1970 में बढ़कर 286.1 करोड़ रुपये हो गये; साथ ही साथ उसी अवधि में उन लेखों की संख्या 2.67 लाख से बढ़कर 7.10 लाख हो गई। विशेषकर इस अवधि में कृषकों को दिये गये प्रत्यक्ष ऋण की राशि 53.6 करोड़ रुपये से बढ़कर 150.4 करोड़ रुपये हो गई और इससे सम्बन्धित लेखों की संख्या 2.6 लाख से बढ़कर 6.9 लाख हो गई। 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि के लिये दिये गये अग्रिम जहां जून 1969

(लाख रुपयों में)

	जून 1969	मार्च 1970
लेखों की संख्या	रकम	लेखों की संख्या रकम
फुटकर व्यापार और छोटे कारोबार	28037	1922 71148 4129
स्वयं नियोजित	422	33 22230 656
शिक्षा	594	47 1035 180

नोट :—ये आंकड़े महीने के अन्तिम अवधि के हैं।

स्त्रोत :—बैंकों से प्राप्त विशेष विवरणियाँ।

के अन्त में 62 करोड़ रुपये थे वहां वे मार्च 1970 के अन्त में बढ़कर दुगुने हो गये अर्थात् उनकी राशि 124 करोड़ रुपये थी और उन अग्रिमों के लेखों की संख्या 1.27 लाख से बढ़कर 3.12 लाख हो गई।

108. लघु क्षेत्र (इसमें लघु उद्योग, सड़क परिवहन चालक और औद्योगिक आस्थान शामिल हैं) को दिये गये अग्रिमों के संदर्भ में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिम जून 1969 के 294 करोड़ रुपयों से बढ़कर मार्च 1970 में 419 करोड़ रुपये हो गये और उन लेखों की संख्या 85,000 से बढ़कर 1.35 लाख हो गई। लघु क्षेत्र को दिये गये अग्रिमों में अधिकांश अग्रिम लघु उद्योगों को प्राप्त हुये और वे जून 1969 को 286 करोड़ रुपयों से बढ़कर मार्च 1970 में 394 करोड़ रुपये हो गये। लघु उद्योगों के अग्रिमों के संदर्भ में लेखों की संख्या 82,000 से बढ़कर 1.24 लाख हो गई। लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिमों में हुई वृद्धि का लगभग 50 प्रतिशत अंश 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया, उनके द्वारा इस अवधि में दी गई राशि 147 करोड़ रुपये से बढ़कर 199 करोड़ रुपये हो गई। सड़क परिवहन चालकों को दिये गये ऋण में तेजी से वृद्धि हुई है। बैंकों ने दूसरे अग्रतावाले क्षेत्र अर्थात् निर्यात को दी जाने वाली सहायता में भी वृद्धि की है और निर्यातों के लिये दिये गये ऋण (पैकिंग ऋण और पोतलदानोत्तर ऋण) की राशि जून 1969 के अन्त में जहां 263.4 करोड़ रुपये थी वहां यह मार्च 1970 के अन्त में बढ़कर 336.5 करोड़ रुपये हो गई।

109. प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप ये बैंक उधारकर्ता की ऋण पात्रता के स्थान पर उस प्रायोजना की ऋण पात्रता पर और देने लगे हैं जिसके लिये वित्तीय सहायता दी जानी है। इसका प्रमाण यह है कि इन बैंकों ने फुटकर व्यापार और स्वयं नियोजित व्यक्तियों जैसे अन्य क्षेत्रों को तथा साथ ही उच्च शिक्षा के उद्देश्यों के लिये भारी मात्रा में ऋण दिया है। इस प्रकार, 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों की राशि जून 1969 और मार्च 1970 के बीच फुटकर व्यापार और छोटे कारोबार के मामले में 19 करोड़ रुपयों से बढ़कर 41 करोड़ रुपये, स्वयं नियोजित व्यक्तियों के मामले में 33 लाख रुपयों से बढ़कर 6.56 करोड़ रुपये और शिक्षा के संदर्भ में 4.6 लाख रुपयों से बढ़कर 1.80 करोड़ रुपये हो गई। नौ महीनों की अवधि में छोटे उधारकर्ताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई जिसका प्रमाण यह है कि फुटकर व्यापार और छोटे कारोबार के सम्बन्ध में लेखों की संख्या 28,037 से बढ़कर 71,148 हो गई और स्वयं नियुक्त व्यक्तियों के लेखों की संख्या 422 से बढ़कर 22,233 हो गई।

110. इस प्रकार, कृषि, लघु क्षेत्र और निर्यात के लिये दिये कुल बैंक ऋणों की रकम जहां जून 1969 के अन्त में 745.87 करोड़ रुपये थी वहां वह मार्च 1970 के अन्त में बढ़कर 1,941.19 करोड़ रुपये हो गई, इस कारण कुल बैंक ऋण में उक्त ऋणों का अनुपात 20.7 प्रतिशत से बढ़कर 26.2 प्रतिशत हो गया।

111. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में जमा लेखों की कुल संख्या 31 मार्च 1968 और 31 मार्च 1969 के बीच 22 लाख से बढ़ कर 183 लाख हो गई। व्यक्तिगत लेखों की संख्या में 19 लाख की वृद्धि हुई जिनमें से 16 लाख वचत जमा लेख थे। जमा-लेखों की कुल संख्या में व्यक्तिगत लेखों, जिनमें चालू, वचत और सावधि जमा लेख शामिल हैं, का अधिक हिस्सा बना रहा, अर्थात् व्यक्तिगत लेख कुल लेखों के 88 प्रतिशत थे। 31 मार्च 1969 को समाप्त हुए वर्ष में बैंकों के पास बकाया रहने वाली नया राशियों की रकम में 522 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जिनमें से व्यक्तिगत लेखों में हुई वृद्धि 259 करोड़ रुपये थी। इसके विपरीत, 1968 में जमा राशियों में हुई 451 करोड़ रुपयों की कुल वृद्धि में से व्यक्तिगत लेखों में हुई वृद्धि का अंश 275 करोड़ रुपये था। इसके फलस्वरूप, कुल

जमाराशियों में व्यक्तिगत जमाराशियों का अनुपात मार्च 1968 के 57.3 प्रतिशत से घट कर मार्च 1969 में 56.3 प्रतिशत हो गया। प्रति लेखा आयतन रकम भी 1,612 रुपयों से घट कर 1,586 रुपये हो गई। इसके विपरीत, कारोबारी लेखों की संख्या और जमाराशियों में 1968 की अपेक्षा काफी अधिक वृद्धि हुई। इस प्रकार, कारोबारी लेखों की संख्या में जहां 1967-68 में 56,000 की वृद्धि हुई थी वहां 1968-69 में 94,000 की वृद्धि हुई, जबकि इन लेखों की जमाराशियों में 1967-68 में हुई 25 करोड़ रुपयों की वृद्धि की अपेक्षा इस वर्ष 130 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई। फिर भी, बैंकों की कुल जमाराशियों में कारोबारी जमाराशियों के हिस्से में मामूली वृद्धि हुई। अर्थात् वह 23.0 प्रतिशत से बढ़ कर 23.2 प्रतिशत हुआ। कारोबारी लेखों की सभी श्रेणियों (उद्योग, व्यापार आदि) के लेखों की संख्या और जमाराशियों में इस वर्ष जो वृद्धि हुई वह कारोबारी कार्यकलाप के पुनर्विक्रम का परिचायक हो सकती है।

112. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा किए जाने वाले निवेशों के स्वरूप में परिवर्तन पाया गया। इस वर्ष अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का मुकाब 'अन्य न्यासी' प्रतिभूतियों (नगरपालिकाओं, पत्तन न्यासों, बिजली बोर्डों, औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्तीय निगमों, भूमिबन्धक बैंकों आदि की प्रतिभूतियों) में निवेश करने की ओर अधिक रहा है। बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की अपेक्षा 'अन्य न्यासी' प्रतिभूतियों में अपने निवेश को तेजी से बढ़ा रहे हैं; इसके फलस्वरूप, कुल निवेशों में सरकारी प्रतिभूतियों का हिस्सा जहां मार्च 1967 में 82 प्रतिशत था वहां यह घट कर मार्च 1968 में 80 प्रतिशत और मार्च 1969 में और घट कर 79 प्रतिशत हो गया। इसके साथ ही, कुल निवेशों में 'अन्य न्यासी' प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों का प्रतिशत जहां 1967 में 11.9 था वहां यह 1968 में बढ़ कर 14.9 और 1969 में और बढ़ कर 16.1 हो गया। बैंकों के कुल निवेशों में इन दो प्रकारों की प्रतिभूतियों का हिस्सा बराबर अधिक रहा; कुल निवेशों में उनका अनुपात जहां मार्च 1967 में 94 प्रतिशत था वहां यह मार्च 1969 में बढ़ कर 95.2 प्रतिशत हो गया। शेष में से, कम्पनियों के शेयरों और डिबेंचरों में किए गए निवेशों का प्रतिशत जहां मार्च 1967 के अंत में 2.3 था वहां यह मार्च 1969 के अंत में 2.7 प्रतिशत हो गया।

बैंकों की आमदानियाँ, खर्च और लाभ

113. 1969 के वर्ष के लिए बैंकों की आमदानियों, उनके खर्च और लाभ की पूरी जानकारी अब तक प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके सात सहायक बैंकों के प्रकाशित लेखों से यह पता लगता है कि वाणिज्य बैंकों की आय और व्यय में 1968 की अपेक्षा 1969 में कम वृद्धि हुई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके सहायक

बैंकों के (कराधान की व्यवस्था करने के बावजूद, परंतु अन्य विनियोजन करने के पक्ष में) लाभ की श्रेणियों में 1968 के 6.02 करोड़ रुपयों से बढ़ कर 1969 में 6.42 करोड़ रुपये हो गई। इन बैंकों की आय में हुई वृद्धि की दर 1969 में 14.3 प्रतिशत रही जब कि वह 1968 में 18.5 प्रतिशत थी। इसका प्रमुख कारण यह है कि 1968 की अपेक्षा 1969 में बैंक ऋण में धीमी गति से वृद्धि हुई। व्यय के दो महत्वपूर्ण घटकों अर्थात् जमाराशियों तथा उधारों पर प्रदा किए गए व्याज और स्थापना व्यय में भी 1968 की अपेक्षा 1969 में कम वृद्धि हुई। इस प्रकार, व्याज की अदायगियों में जहां 1968 में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहां 1969 में वह घट कर 16 प्रतिशत हो गई, जब कि स्थापना व्यय में हुई वृद्धि 1968 के 19.2 प्रतिशत से कम होकर 1969 में 14.0 प्रतिशत हो गई। इसके फलस्वरूप, इन बैंकों के कुल व्यय में 1968 के 19.0 प्रतिशत की तुलना में 1969 में 14.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। छोटे उधारकर्ताओं की संख्या में भारी वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप लेखों के पर्यवेक्षण के खर्च में वृद्धि होने के बावजूद 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की 1968 की अपेक्षा 1969 में समग्र रूप से अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त हुआ।

114. 31 दिसम्बर 1969 को विदेश स्थित भारतीय बैंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वह 7 ही बनी रही परंतु उगांडा बैंकिंग संशोधन अधिनियम, 1969 और नाइजीरिया की संघ सरकार द्वारा जारी की गई कम्पनी अधिनियम सं० 51 के उपबंधों के अनुसार उगांडा में स्थित बैंक ऑफ बड़ोदा और बैंक ऑफ इंडिया की 5 शाखाओं और नाइजीरिया में स्थित बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा को सहायक कम्पनियों के रूप में परिवर्तित कर देने और बैंक ऑफ इंडिया की अवन शाखा का राष्ट्रीयकरण कर देने के परिणामस्वरूप उनके कार्यालयों की संख्या पाकिस्तान स्थित कार्यालयों की छोड़ कर 60 से घट कर 56 हो गई। यदि देखा जाए तो दिसम्बर 1969 के अंत में भारतीय बैंकों के कार्यालयों की संख्या मलेेशिया में सबसे अधिक अर्थात् 11 थी और उसके बाद केन्या, ब्रिटेन और सिंगापुर का स्थान आता है जहां वह संख्या क्रमशः 10, 9 और 6 थी। मुख्यतः नाइजीरिया, उगांडा और अवन में भारतीय बैंकों को प्रभावित करने वाली जो पूर्वावलंबित घटनाएँ हुईं उनके कारण विदेश स्थित भारतीय बैंकों की कुल वेयताएँ/आस्तियाँ 1969 में 211 करोड़ रुपयों से घट कर 205 करोड़ रुपये हो गईं अर्थात् उनमें 3 प्रतिशत की कमी हुई, विदेश-स्थित भारतीय बैंकों की कुल जमाराशियाँ 1969 के अंत में 158 करोड़ रुपये हो गईं जबकि वे पिछले वर्ष 161 करोड़ रुपये थीं। मुख्यतः ब्रिटेन में दिए गए अधिमों में कमी हो जाने के कारण ऋणों और अधिमों में भी तेजी से कमी हुई और वे 66 करोड़ रुपयों से घट कर 51 करोड़

सारणी 19—भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों, जमाराशियों और ऋण में वृद्धि

(करोड़ रुपयों में)

	कार्यालय		जमाराशियाँ (अन्तर्गत जमाराशियों को छोड़ कर)			ऋण			
	जोड़	वार्षिक वृद्धि	मार्च जमाराशियाँ	माघ-जमाराशियाँ	कुल जमाराशियाँ	वार्षिक वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि	बैंक ऋण	वार्षिक वृद्धि प्रतिशत वृद्धि
जून 1965 के अंत में	5727	+ 498	1275.1	1433.0	2708.1	+ 323.4	+ 13.6	2068.4	+ 294.6 + 16.6
जून 1966 के अंत में	6139	+ 412	1477.3	1645.9	3123.2	+ 415.1	15.3	2271.4	203.0 + 9.8
जून 1967 के अंत में	6620	+ 481	1664.6	1852.4	3517.0	+ 393.8	+ 12.6	2631.1	+ 359.7 + 15.8
जून 1968 के अंत में	7041	+ 424	1874.8	2094.2	3969.0	+ 452.0	12.9	3102.9	+ 471.8 + 17.9
जून 1969 के अंत में	8045	+ 1001	2103.5	2542.3	4645.8	+ 676.8	+ 17.0	3598.8	+ 495.9 + 16.0
जून 1970 के अंत में*	9938	+ 1893	2307.3	2932.5	5239.8	+ 594.0	+ 12.8	4227.6	+ 628.8 + 17.5

*अनुमानित

नोट : कार्यालयों की संख्या को छोड़ कर, ये आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 की प्रांग 42(2) के अधीन बैंकों द्वारा भेजी गई मासाधिक विवरणियों पर आधारित हैं।

सारणी 20—वाणिज्य बैंक व्यवसाय की प्रवृत्तियों का विहंगावलोकन
(जून के अंतिम शुक्रवार को)

(करोड़ रुपये)

	1961	1966	1967	1968	1969	1970
I बैंकों की संख्या						
(i) अनुसूचित बैंक	85	76	75	73	73	72
(ii) गैर अनुसूचित बैंक	249	31	24	19	16	14
II कर्मचारियों की संख्या						
(i) अनुसूचित बैंक	4250	6139	6620	7044	8045	9938
(ii) गैर अनुसूचित बैंक	776	240	216	203	217	193
III कुल जमाराशियाँ						
(i) अनुसूचित बैंक	1775.8	3123.2	3517.0	3969.1	4645.8	5239.8
(ii) गैर अनुसूचित बैंक	43.4	25.0	24.5	26.2	28.0	23.5
IV ढाग जमाराशियाँ						
(i) अनुसूचित बैंक	725.3	1477.3	1664.6	1874.8	2103.5	2307.3
(ii) गैर अनुसूचित बैंक	12.6	9.1	9.1	10.2	11.7	10.6
V सावधि जमाराशियाँ						
(i) अनुसूचित बैंक	1050.5	1645.9	1852.4	2094.3	2542.3	2932.5
(ii) गैर अनुसूचित बैंक	30.8	15.9	15.4	16.0	16.3	12.9
VI राष्ट्रीय आय में जमाराशियों का प्रतिशत	12.6	14.4	14.6	14.1	15.2@	16.6@
VII कुल बैंक ऋण						
(i) अनुसूचित बैंक	1282.8	2271.4	2631.1	3102.9	3598.8	4227.6
(ii) गैर अनुसूचित बैंक	27.6	15.0	15.1	12.8	16.4	11.3
VIII ऋण जमा अनुपात						
(i) अनुसूचित बैंक	72.2	72.7	74.8	78.2	77.5	80.7
(ii) गैर अनुसूचित बैंक	63.6	60.0	61.6	48.9	58.6	48.1
IX सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश						
(i) अनुसूचित बैंक	548.8	918.8	922.6	975.6	1126.3	1187.6
(ii) गैर अनुसूचित बैंक	11.0	5.6	5.4	6.6	6.7	6.0
X निवेश जमा अनुपात						
(i) अनुसूचित बैंक	30.9	29.4	26.2	24.6	24.2	22.7
(ii) गैर अनुसूचित बैंक	25.3	22.4	22.0	25.2	23.9	25.5
XI नकदी और रिजर्व बैंक आंकड़ों के पास रक्काया						
(i) अनुसूचित बैंक	144.6	195.3	258.8	269.5	380.3	340.8
(ii) गैर अनुसूचित बैंक	3.2	1.7	1.9	2.1	2.5	2.0
XII नकदी जमा अनुपात						
(i) अनुसूचित बैंक	8.1	6.3	7.4	6.8	8.2	6.5
(ii) गैर अनुसूचित बैंक	7.4	6.8	7.8	8.0	8.9	8.5

नोट : 1. 1961 के आंकड़े अनुसूचित बैंकों के हैं।

2. अंतिम स्तंभ में दिए गए गैर अनुसूचित बैंकों के आंकड़े अक्टूबर, 1969 के हैं।

3. जून, 1970 के आंकड़े अंतिम हैं।

@वर्तमान मूल्यों के अनुसार राष्ट्रीय आय पर आधारित हैं (अनुमानित)।

रुपये हो गए। इनके विपरीत, खरीदे और भुनाए गए बिलों की राशि 37 करोड़ रुपयों से बढ़ कर 40 करोड़ रुपये हो गई, निवेशों की राशि 25 रोड़ रुपयों से बढ़ कर 31 करोड़ रुपये हो गई और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि 19 करोड़ रुपयों से बढ़ कर 22 करोड़ रुपये हो गई। चल आस्तियों* में इस वर्ष 8 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई अर्थात् वे बढ़ कर 85 करोड़ रुपये हो गई और जमा राशियों में उनका अनुपात बढ़ कर 54 प्रतिशत हो गया अर्थात् उक्त अनुपात में 6 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई।

भुगतान शेष

115. आलोच्य वर्ष में विदेशी अदायगियों की स्थिति में और सुधार होता रहा। आरक्षित विदेशी मुद्रा निधि में जहाँ 1968-69 (जुलाई-जून) में 1,180 लाख डालरों की वृद्धि हुई वहाँ 1969-70 (जुलाई-जून) में 2,780 लाख डालरों की वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय समझौते के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जलमुद्रा के उद्देश्यपूर्ण निर्माण के उपाय के रूप में 28 जुलाई 1969 को अमल में लाई गई विशेष आह्वन अधिकार योजना के अधीन पहले वितरण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1 जनवरी 1970 को भारत के लिए विशेष आह्वनार्थ 1,260 लाख डालर नियत किए; इस कारण इस वर्ष आरक्षित विदेशी मुद्रा निधि में वृद्धि हुई। इसके विपरीत, इस वर्ष अ. मु. कोष को जो 1870 लाख डालर वापस आया किए गए वे पिछले वर्ष की अपेक्षा 590 लाख डालर अधिक थे। अ. मु. कोष के साथ हुए लेनदेनों, विशेष आह्वन अधिकारों और कोष को की गई वापसी अदायगियों—अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की विशेष जमा राशियों की वापसी अदायगी और अक्टूबर 1969 में ड्यूक मार्क का पुनर्मूल्यन होने के बाद

देश की आरक्षित आस्तियों के एक घटक के रूप में रहने वाले ड्यूक मार्क में हुई मूल्य-वृद्धि को छोड़ देने पर 1969-70 में आरक्षित निधियों में 3,470 लाख डालरों की वृद्धि हुई जबकि 1968-69 में उनमें 2,610 लाख डालरों की वृद्धि हुई।

116. भारत के भुगतान शेष की स्थिति और आरक्षित विदेशी मुद्रा निधि में सुधार होने के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उसे परिवर्तनीय मुद्राओं के बदले में विशेष आह्वन अधिकार योजना के अन्य सहभागियों से आह्वन के विशेष अधिकार स्वीकार करने योग्य घोषित किया। जुलाई 1970 के प्रारंभ में कोष ने यह निश्चय किया कि जुलाई—सितम्बर 1970 की तिमाही के लिए 140 लाख डालरों के बराबर की अधिकतम विशेष आह्वन अधिकार राशि के लिए भारत को अधिकृत किया जा सकता है। इस प्रकार, भारत ने अगस्त के प्रारंभ में अन्य सहभागियों से 15 लाख डालरों के बराबर की विशेष आह्वन अधिकार राशि स्वीकार की।

117. बालू और पूंजी लेखों से संबंधित भुगतान शेष के उन लेनदेनों का विवरण अब तक उपलब्ध नहीं है जिनके अंतिम परिणाम के रूप में जुलाई 1969—जून 1970 में देश की आरक्षित विदेशी मुद्रा निधि में उल्लेखनीय सुधार हुआ। भुगतान शेष के अद्यतन विस्तृत संकलन 1969 के कैलेण्डर वर्ष से ही संबंधित है।

*इनमें नकदी, केंद्रीय बैंक के पास बकाया राशि, अन्य बैंकों में बालू लेखों में बकाया राशि, मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि और खरीदे और भुनाये गये बिल शामिल हैं।

सारणी 21—भारत का भुगतान शेष (प्रारम्भिक)

(करोड़ रुपयों में)

	जनवरी-मार्च 1969	अप्रैल-जून 1969	जुलाई-सितम्बर 1969	अक्टूबर-दिसम्बर 1969	जनवरी-दिसम्बर 1969	जनवरी-दिसम्बर 1968
(क) बालू लेखा						
आयात-लागत बीमा और भाड़ा महित						
(अ) गैर-सरकारी	147.9	149.8	157.9	152.6	608.2	672.5
(आ) सरकारी	245.9	203.3	272.5	233.3	955.0	1153.7
कुल आयात (अ+आ)	393.8	353.1	430.4	385.9	1563.2	1826.2
नियति-जहाज तक निःशुल्क	343.7	343.1	352.5	358.7	1398.0	1349.7
ध्यापार शेष	— 50.1	— 10.0	— 77.9	— 27.2	— 165.2	— 476.5
मुद्रांतर सोने की आयाजाही (वास्तविक)	—	—	—	—	—	—
सरकारी अंतरण अदायगी (वास्तविक)	+ 24.3	+ 7.3	+ 7.8	+ 4.0	+ 43.4	+ 11.9
बूसरे अवश्य लेन-देन (वास्तविक)	— 20.0	— 1.4	— 17.6	— 11.9	— 50.9	— 33.6
बालू लेखा (वास्तविक)	— 45.8	— 4.1	— 87.7	— 35.1	— 172.7	— 498.2
(ख) भूल-चूक (वास्तविक)	+ 6.2	— 32.4	— 14.8	+ 10.6	— 30.4	— 143.6
(ग) पूंजी लेखा गैर-सरकारी पूंजी (वास्तविक)	+ 1.6	— 16.2	— 2.8	— 9.7	— 27.1	— 9.8
(अ) दीर्घावधि	+ 0.6	— 17.2	— 3.0	— 9.8	— 29.4	— 13.0
(आ) अल्पावधि	+ 1.0	+ 1.0	+ 0.2	+ 0.1	+ 2.3	+ 3.2
बैंक व्यवसाय की पूंजी (वास्तविक)	— 16.9	+ 4.6	+ 14.8	— 6.2	— 3.7	+ 12.9
सरकारी पूंजी (वास्तविक)	+ 120.1	+ 99.9	+ 129.8	+ 60.5	+ 410.3	+ 653.5
(अ) ऋण	+ 347.9	+ 164.5	+ 130.8	+ 134.7	+ 777.9	+ 886.5†
(आ) अ. मु. कोष	— 28.5	— 37.5	—	— 45.1	— 111.1	— 73.2
(इ) ऋण परिशोधन	— 36.2	— 29.6	— 47.5	— 72.6	— 185.9	— 166.7
(ई) विविध	— 163.1	+ 2.5	+ 46.5	+ 43.5	+ 70.6	+ 6.9
पूंजी लेखा (वास्तविक)	+ 104.8	+ 88.3	+ 141.8	+ 44.6	+ 379.5	+ 656.6
(घ) आरक्षित निधि में घटक (क+ख+ग)						
वृद्धि () कमी (—)	+ 65.2	+ 51.8	+ 39.3	+ 20.1	+ 176.4*	14.8

*अंशतः गोपित

*इनमें मूल्य-वृद्धि के कारण हुए परिवर्तन शामिल नहीं हैं।

118. 1969 के कैलेण्डर वर्ष के भुगतान शेष के आंकड़ों के अनुसार, कुल आयात बिल में, विशेषकर आयात संबंधी मुक्त विदेशी मुद्रा परिचय में, भारी कमी हुई। निर्यातों में भी वृद्धि हुई परंतु उनका योगदान साधारण था। 1968 की अपेक्षा विदेशी सहायता की मात्रा के कम होने पर भी आरक्षित निधि पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में उसका भी योगदान था। यद्यपि बाता देश राहत देने के कतिपय उपाय बराबर करते रहे, फिर भी ब्याज आदि चुकाने का बोझ बना ही रहा।

समय प्रवृत्तियाँ

119. इस वर्ष कुल आयात बिल में 263.0 करोड़ रुपये की कमी हुई जबकि निर्यातों में 48.3 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और व्यापार संबंधी घाटे में 311.3 करोड़ रुपये की कमी हुई अर्थात् व्यापार घाटे की राशि 165.2 करोड़ रुपये हो गई। इसके अतिरिक्त सरकारी अंतरण अदायगी लेनदेन सहित प्रमुख लेखों के घाटे में 14.2 करोड़ रुपये की कमी हुई। इसके परिणामस्वरूप चालू लेखों के घाटे में भारी कमी हुई और वह 498.2 करोड़ रुपये से घट कर 172.7 करोड़ रुपये हो गया। चालू लेखों और 'भूल-चूक' को मिला कर देखा जाए तो 1969 में कुल घाटे की राशि 203.1 करोड़ रुपये हो गई जो 1968 के कुल घाटे की लगभग एक-तिहाई के बराबर थी। पूंजीगत लेनदेनों से वास्तविक प्राप्ति की मात्रा अपेक्षाकृत कम थी।

आयात

120. जैसा कि पहले कहा गया है, कुल आयात बिल की राशि 1,563.2 करोड़ रुपये थी जो 1968 की राशि की तुलना में 263.0 करोड़ रुपये कम थी। इस कमी में से आधे से अधिक कमी निजी वित्तीय साधनों से आयात किए जाने के कारण हुई और शेष कमी विदेशी सहायता से किए जाने वाले आयातों की मात्रा के कम हो जाने के कारण हुई। कुल आयात बिल में हुई कमी के लगभग आधे हिस्से का कारण यह था कि अनाजों की देशी पूर्ति की स्थिति में सुधार होने के फलस्वरूप अनाजों के आयात पर कम परिस्थिति किया गया था। इसके अतिरिक्त, रई और प्रलोह धातुओं के आयात पर किए गए परिचय में भी कमी हुई। इसके अलावा, आयात प्रतिस्थापन में बराबर प्रगति होती रही और साथ ही, निवेश कार्य में सामान्य रूप से उत्साह बना रहा, इन कारणों से मशीनों और परिवहन उपकरणों के आयातों पर किए गए परिचय में कमी हुई।

121. यदि क्षेत्रवार देखा जाए तो गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्रों पर किए गए आयातों में 1968 की अपेक्षा कमी हुई। गैर सरकारी क्षेत्र के आयातों में 64.3 करोड़ रुपये की कमी हुई अर्थात् उनकी राशि 608.2 करोड़ रुपये हो गई। यद्यपि सभी प्रमुख मदों के आयातों में कमी हुई परंतु रई और मशीनों के आयातों में हुई कमी विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। सरकारी आयातों में 198.7 करोड़ रुपये की कमी हुई और उनकी राशि 955.0 करोड़ रुपये हो गई; इस कमी में से लगभग तीन-चौथाई कमी निजी वित्तीय साधनों से और विदेशी सहायता से खरीदे जाने वाले, दोनों प्रकार के अनाजों के आयातों में हुई कमी के कारण हुई।

निर्यात

122. 1966 में निर्यातों में पाई गई कमी के बावजूद उनमें जो वृद्धि होने लगी वह क्रमिक रूप से तीसरे वर्ष अर्थात् 1969 में भी जारी रही और इस वर्ष निर्यातों की राशि बढ़ कर 1398.0 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। फिर भी, इस वर्ष हुई 48.3 करोड़ रुपये, या 4 प्रतिशत, की वृद्धि 1968 के 10 प्रतिशत की अपेक्षा बहुत कम थी। 1969 में निर्यातों में हुई धीमी वृद्धि का कारण मुख्यतः कतिपय पण्यों के विश्व सूखों में हुई गिरावट और अंशतः निर्यात के लिए माल की कम उपलब्धि है। कुल निर्यात में जो साधारण वृद्धि हुई वह परम्परेतर मदों, विशेषकर इंजीनियरी माल, चमड़े से बनी चीजों और समुद्री उत्पादों के कारण हुई। निर्यातों की

परम्परागत मदों में जो कमी हुई वह मुख्यतः चाय, जूट से बनी चीजों और वनस्पति तेलों के निर्यातों में हुई कमी के कारण हुई।

प्रमुख लेन-देन

123. प्रमुख लेनदेन के लेखों में, सरकारी अंतरण अदायगी संबंधी लेनदेनों के फलस्वरूप 1968 के 11.9 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष 43.4 करोड़ रुपये का अधिशेष रहा (सारणी 21)। यह सुधार मुख्यतः अन्न-सहायता और ब्याज राहत अनुदानों तथा पी. ए. 480 प्रतिरूप निधियों से अनुदानों के रूप में हुई अधिक प्राप्तियों के कारण हुआ। अन्य प्रमुख लेनदेनों के संबंध में, चूंकि बहुत अधिक मात्रा में राशि बाहर गई, अतः घाटा 33.6 करोड़ रुपये से बढ़ कर 50.9 करोड़ रुपये हो गया। कुल अदायगियों की राशि 454.7 करोड़ रुपये थी जो 1968 की अपेक्षा 24.2 करोड़ रुपये अधिक थी; निवेश आय लेखों पर अधिक मात्रा में जो राशि बाहर गई वह इस वृद्धि के अधिकांश भाग का कारण थी। इन लेन-देनों के संदर्भ में जो राशि बाहर गई उसका आधे से अधिक भाग निवेश आय लेखों में की गई अदायगियों से सम्बन्धित था; उनमें इस वर्ष 15.1 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और इस प्रकार वह 248.3 करोड़ रुपये हो गई; केवल ऋणों और साख के संबंध में अर्ध किए गए ब्याज की राशि इस वर्ष 186.8 करोड़ रुपये थी जब कि वह 1968 में 178.4 करोड़ रुपये थी। इसके अतिरिक्त, बीमा और फुटकर सेवा संबंधी लेनदेनों के संबंध में जो राशि बाहर गई उसमें भी वृद्धि हुई परंतु गैर सरकारी अंतरण अदायगियों के संदर्भ में बाहर गई राशि में कमी होने के कारण कुछ सीमा तक इस वृद्धि का समायोजन हो गया। विदेशों में प्रचलित उच्चतर ब्याज दरों और गैर सरकारी एकपक्षीय अंतरणों के कारण निवेश-आय की जो अधिक प्राप्ति हुई उससे कुल प्राप्ति में इस वर्ष 6.9 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई अर्थात् वे 403.8 करोड़ रुपये हो गई।

पूंजीगत लेनदेन

124. जैसा कि पहले कहा गया है, पूंजीगत लेनदेनों के संदर्भ में 379.3 करोड़ रुपये की वास्तविक प्राप्ति हुई जबकि 1968 में 656.6 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। इस वर्ष तीनों क्षेत्रों से सम्बन्धित वास्तविक प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस वर्ष बड़ी मात्रा में ऋणों की वापसी अदायगी की गई और तेल कंपनियों ने निधियों को स्वदेश भेजा; इन कारणों से गैर सरकारी पूंजी की आयातजाली से सम्बन्धित लेखों में बाहर भेजी जाने वाली वास्तविक राशि 9.8 करोड़ रुपये से बढ़ कर 27.1 करोड़ रुपये हो गई। बैंक पूंजी के अधीन जहां पिछले वर्ष 12.9 करोड़ रुपये की वास्तविक प्राप्ति हुई वहां इस वर्ष 3.7 करोड़ रुपये की वास्तविक राशि बाहर गई। जो वास्तविक राशि बाहर गई उसके लगभग समूचे अंश का कारण अधिकृत व्यापारियों की विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं में हुई वृद्धि थी। इसके विपरीत, 1968 में उनकी विदेशी मुद्रा वेयताओं में कमी होने के बावजूद उनकी विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं में जो भारी कमी हुई वह वास्तविक प्राप्ति का कारण थी।

125. सरकारी क्षेत्र के अधीन 410.3 करोड़ रुपये की जो वास्तविक राशि प्राप्त हुई वह 1968 की अपेक्षा 243.2 करोड़ रुपये कम थी। इस क्षेत्र को प्राप्त होने वाली राशि का सबसे बड़ा घटक विदेशी सहायता ऋण है; उसके उपयोग की राशि 1968 के 891.4 करोड़ रुपये से घट कर इस वर्ष 780.6 करोड़ रुपये हो गई क्योंकि पी. एल. 480 प्रतिरूप निधि से प्राप्त होने वाले ऋणों के वितरण में कमी हो गई थी। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से की गई पुनर्खरीदों (111.1 करोड़ रुपये) और ऋण परिशोधन अदायगियों (188.1 करोड़ रुपये) के रूप में जो राशि बाहर गई वह भी 1968 की अपेक्षा अधिक थी। फुटकर पूंजीगत लेनदेनों के कारण जाह 1968 में 6.9 करोड़ रुपये की वास्तविक प्राप्ति हुई थी वहां इस वर्ष 70.6 करोड़ रुपये की वास्तविक राशि बाहर गई। इस क्षेत्र को प्राप्त होने वाली वास्तविक राशि पर इन सभी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

सारणी 22—चालू लेखों में भारत का क्षेत्रवार भुगतान शेष (प्रारंभिक)

(करोड़ रुपये में)

	जनवरी-मार्च	अप्रैल-जून	जुलाई-सितम्बर	अक्टूबर-दिसम्बर	जनवरी-दिसम्बर	जनवरी-दिसम्बर
	1969	1969	1969	1969	1969	1968
स्टॉलिंग क्षेत्र						
आयात—लागत बीमा और भाड़ा सहित	66.6	64.5	61.0	63.0	255.4	300.0
निर्यात—जहाज तक निःशुल्क	89.0	85.2	86.0	91.2	351.4	388.8
व्यापार शेष	+22.4	+20.7	+25.0	+27.9	+96.0	+88.8
मुद्रतर सोने के लेन-देन (वास्तविक)	—	—	—	—	—	—
सरकारी अंतरण अदायगी (वास्तविक)	+4.5	+0.2	—0.1	+2.7	+7.3	+2.5
दूसरे प्रदृश्य लेन-देन (वास्तविक)	+4.5	+1.6	+6.0	—1.3	+10.8	+20.4
चालू लेखा (वास्तविक)	+31.4	+22.5	+30.9	+29.3	+114.1	+111.7
बालर क्षेत्र						
आयात—लागत बीमा और भाड़ा सहित	125.0	122.2	144.8	102.3	494.3	680.5
निर्यात—जहाज तक निःशुल्क	78.9	71.1	71.1	69.5	290.6	262.3
व्यापार शेष	—46.1	—51.1	—73.7	—32.8	—203.7	—418.2
मुद्रतर सोने के लेन-देन (वास्तविक)	—	—	—	—	—	—
सरकारी अंतरण अदायगी (वास्तविक)	+22.3	+5.1	+5.8	+8.7	+41.9	+25.2
दूसरे प्रदृश्य लेन-देन (वास्तविक)	+6.5	+7.5	—4.3	+0.6	+10.3	+22.0
चालू लेखा (वास्तविक)	+17.3	—38.5	—72.2	—23.5	—151.5	—371.0
प्राथमिक सहयोग और विकास संगठन के देश						
आयात—लागत बीमा और भाड़ा सहित	48.7	43.6	48.4	53.7	194.4	234.1
निर्यात—जहाज तक निःशुल्क	34.8	30.1	32.8	34.6	132.3	131.8
व्यापार शेष	—13.9	—13.5	—15.6	—19.1	—62.1	—102.3
मुद्रतर सोने के लेन-देन (वास्तविक)	—	—	—	—	—	—
सरकारी अंतरण अदायगी (वास्तविक)	+0.6	+2.2	+3.1	+4.0	+9.9	+0.6
दूसरे प्रदृश्य लेन-देन (वास्तविक)	—7.9	—9.6	—6.9	—9.9	—34.3	—41.0
चालू लेखा (वास्तविक)	—21.2	—20.9	—19.4	—25.0	—86.5	—143.9
शेष गैर स्टॉलिंग क्षेत्र						
आयात—लागत बीमा और भाड़ा सहित	153.5	122.8	176.2	166.6	619.1	611.6
निर्यात—जहाज तक निःशुल्क	141.0	156.7	162.6	163.4	623.7	566.8
व्यापार शेष	—12.5	+33.9	—13.6	—3.2	+4.6	—44.8
मुद्रतर सोने के लेन-देन (वास्तविक)	—	—	—	—	—	—
सरकारी अंतरण अदायगी (वास्तविक)	—	—	—	—	—	—
दूसरे प्रदृश्य लेन-देन (वास्तविक)	—13.1	+9.1	—2.1	+6.0	—0.1	—0.7
चालू लेखा (वास्तविक)	—25.6	+43.0	—15.7	+2.8	+4.5	—45.7
अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ						
आयात—लागत बीमा और भाड़ा सहित	—	—	—	—	—	—
निर्यात—जहाज तक निःशुल्क	—	—	—	—	—	—
व्यापार शेष	—	—	—	—	—	—
मुद्रतर सोने के लेन-देन (वास्तविक)	—	—	—	—	—	—
सरकारी अंतरण अदायगी (वास्तविक)	—3.1	—0.2	—1.0	—11.4	—15.7	—15.0
दूसरे प्रदृश्य लेन-देन (वास्तविक)	—10.0	—10.1	—10.3	—7.3	—37.7	—34.3
चालू लेखा (वास्तविक)	—13.1	—10.3	—11.3	—18.7	—53.4	—49.3

क्षेत्रीय

126. सभी क्षेत्रों से सम्बन्धित हमारी चालू लेखा स्थिति में सुधार हुआ। स्टलिंग क्षेत्र संबंधी अधिशेष में 2.4 करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि हुई; साथ ही, समग्र गैर-स्टलिंग क्षेत्र संबंधी घाटे में 327.1 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय कमी हुई। अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में 53.4 करोड़ रुपये का हमारा घाटा था जो 1968 की अपेक्षा कुछ अधिक था। निवेश आय लेखे पर जो अधिक राशि बाहर गई वह इसका प्रमुख कारण थी।

127. सभी क्षेत्रों में विद्यमान हमारे व्यापार शेष में सुधार हुआ। स्टलिंग क्षेत्र के हमारे व्यापार अधिशेष में वृद्धि हुई, डालर क्षेत्र और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के देशों के हमारे व्यापार घाटों में कमी हुई और "शेष गैर-स्टलिंग क्षेत्र" का हमारा घाटा अधिशेष में बदल गया। "शेष गैर-स्टलिंग क्षेत्र" से किए जाने वाले आयातों को छोड़ कर अन्य सभी क्षेत्रों से किए गए आयातों में पर्याप्त कमी हुई। समग्र गैर-स्टलिंग क्षेत्र से किए गए आयातों में कमी हुई सभी आयातों में हुई कुल कमी के 80 प्रतिशत से अधिक थी। स्टलिंग क्षेत्र को किए गए निर्यातों में कमी हुई परंतु गैर-स्टलिंग क्षेत्र को, विशेषकर "शेष गैर-स्टलिंग क्षेत्र" और डालर क्षेत्र को, किए गए निर्यातों में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाने से उस कमी का बहुत कुछ समायोजन हो गया।

128. सरकारी अन्तरण अदायगी संबंधी लेनदेन सहित अदृश्य लेनदेनों के लेखे में स्टलिंग क्षेत्र संबंधी अधिशेष में कमी हुई और व्यापार शेष में हुई वृद्धि से उसकी आंशिक पूर्ति हो गई। इसके विपरीत, इन लेनदेनों के कारण गैर-स्टलिंग क्षेत्र संबंधी अधिशेष में वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप चालू लेखे की स्थिति में और सुधार हुआ।

129. वाणिज्यिक सूचना और ग्रंथ संकलन महानिदेशालय द्वारा संकलित 1969-70 के वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के लिए उपलब्ध विदेशी व्यापार संबंधी आंकड़ों के अनुसार व्यापार संबंधी घाटे की राशि 1968-69 के 7340 लाख डालरों से कम होकर 2060 लाख डालर रह गई है। 1969-70 में प्रतिकूल व्यापार संतुलन में जो कमी हुई वह आयातों में हुई 4550 लाख डालरों की कमी और निर्यातों में हुई 730 लाख डालरों की वृद्धि के कारण हुई।

130. 1969-70 (अप्रैल-मार्च) में 18,840 लाख डालरों के निर्यात (वाणिज्यिक सूचना और ग्रंथ संकलन महानिदेशालय के आंकड़ों) हुए अर्थात् निर्यातों में 1968-69 के 13 प्रतिशत की तुलना में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहली तिमाही (अप्रैल-जून 1969) के निर्यातों की स्थिति संतोषजनक थी क्योंकि निर्यातों में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। परंतु अपने पांच महीनों में जो निर्यात हुए उनकी मात्रा असंतोषजनक थी, अतः 1969-70 के पहले आठ महीनों की अवधि (अप्रैल-नवंबर) में वृद्धि की दर कम होकर मात्रा 1 प्रतिशत रह गई। निर्यातों की वृद्धि दर से होने वाली कमी को काबू में लाने के लिए एक निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम बनाया गया। इस प्रोत्साहन कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं : (i) पुराने स्टॉकों और नियत उत्पादन में से निर्यातों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना और (ii) देशी और आयात की गई कच्ची सामग्री और अन्य मूल वस्तुओं की पर्याप्त सप्लाई द्वारा बेकार रहने वाली क्षमता का निर्यातों के संवर्धन में पूर्ण उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन देना। उक्त कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निर्यातों को सुरक्षित प्रोत्साहन देना था ताकि योजना आयोग द्वारा निर्यातों के लिए स्थूल रूप से निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में जो कमी रह गई हो उसे 1969-70 में जहां तक हो सके, पूरा किया जा सके। चूंकि कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए अधिकांश उपाय दीर्घकालीन स्वरूप के थे अतः निर्यातों पर उनका प्रभाव केवल 1970-71 में पड़ सकता था। फिर भी, 1969-70 की अंतिम तिमाही (जनवरी-मार्च 1970) में निर्यातों में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि अंशतः प्रोत्साहन कार्यक्रम की सफलता थी। 1970-71 के पहले दो महीनों (अप्रैल और मई 1970) में किया गया निर्यात

1969-70 की तदनुसूची अवधि की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक था। फिर भी, कलकत्ता बंदरगाह के नाविकों की हड़ताल के कारण जून 1970 में निर्यातों में जो बड़ी भारी कमी हुई (जून 1969 के स्तर की तुलना में 18 प्रतिशत) उससे अप्रैल-जून 1970 में निर्यातों की मात्रा में कमी हुई जो अप्रैल-जून 1969 में किए गए निर्यातों के स्तर से 3 प्रतिशत कम थी।

131. पश्चिमी यूरोप को छोड़ कर अन्य सभी क्षेत्रों को किए गए निर्यातों में 1969-70 में वृद्धि हुई। अफ्रीका (21 प्रतिशत), एशिया और ओशियानिया (10 प्रतिशत) और पूर्वी यूरोप (15 प्रतिशत) को किए गए निर्यातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। एशिया और ओशियानिया के अंतर्गत प्रमुख रूप से जापान को किए गए निर्यातों में 13 प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण एशिया और सुदूरपूर्व देशों के आर्थिक आयोग के देशों को किए गए निर्यातों में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अमेरिका को किए गए निर्यातों में भी थोड़ी-सी वृद्धि (1.5 प्रतिशत) हुई। फिर भी, पश्चिमी यूरोप को किए गए निर्यातों में 13 प्रतिशत की कमी हुई जिसका कारण यह था कि ब्रिटेन को किए गए निर्यातों में 18 प्रतिशत की और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को किए गए निर्यातों में 10 प्रतिशत की कमी हुई थी।

132. 1969-70 में निर्यातों की वृद्धि-दर में जो कमी हुई उसका कारण यह था कि चाय, जूट से बनी वस्तुओं, तिलहन, तेलों और खलियों, काजू की गिरी और कच्ची मैंगनीज जैसे माल के निर्यातों में कमी हुई। चाय, काजू की गिरी, तिलहन, तेलों और खलियों और कच्ची मैंगनीज के निर्यातों में यूनिट मूल्य और परिमाण दोनों ही दृष्टियों से कमी हुई। चाय के निर्यातों से प्राप्त होने वाली आमदनी में पिछले वर्ष 320 लाख डालरों की कमी हुई थी और 1969-70 में उसमें 430 लाख डालरों की और कमी हो गई। बहुत अधिक मात्रा में चाय की उपसब्धि के कारण 1969-70 में चाय का यूनिट मूल्य कम होकर रु. 7.15 प्रति कि. ग्रा. हो गया जबकि वह 1968-69 में रु. 7.79 प्रति कि. ग्रा. और 1967-68 में रु. 8.86 प्रति कि. ग्रा. था। जूट से बनी वस्तुओं के निर्यातों में पिछले वर्षों के समान कमी की प्रवृत्ति पाई गई यद्यपि 1969-70 में हुई कमी (5 प्रतिशत) की मात्रा पिछले वर्ष में हुई कमी (7 प्रतिशत) की तुलना में कम ही थी। मंदी के कारण अमेरिका से प्राप्त होने वाले आर्डरों में कटौती किए जाने और प्रतिस्थापित माल तथा पाकिस्तान की तरफ से होने वाली प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप पिछले चार वर्षों में जूट से बनी वस्तुओं में 28 प्रतिशत की संचयी कमी हुई। खलियों, तिलहनों और तेलों के निर्यातों पर उनकी अपर्याप्त देशी सप्लाई का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सूती धागे और उससे बनी वस्तुओं के मामले में सूती धातों के निर्यातों में हुई कमी की पूर्ति सूती धागे के निर्यातों में हुई वृद्धि से की गई। सूती धातों के निर्यातों में पाकिस्तान, हांगकांग और जापान की प्रतिस्पर्धा और ब्रिटेन में लागू आयात प्रतिबंधों के कारण कमी हुई। सूती धागे के निर्यातों में 127 प्रतिशत की जो वृद्धि हुई उसका मुख्य कारण यह था कि बर्मा, युगोस्लेविया, चेकोस्लोवाकिया और संयुक्त अरब गणतंत्र को अधिक मात्रा में निर्यात किए गए थे।

133. इस्पात के कतिपय वर्गों में होने वाली कमी और कतिपय इंजीनियरी उद्योगों में उत्पादन को प्रभावित करने वाले दूसरे प्रतिबंधों के बावजूद इंजीनियरी माल के निर्यातों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। देश में इस्पात की भारी कमी होने के कारण लोहे और इस्पात के निर्यातों की मात्रा में कमी हुई परंतु अधिक मूल्य के कारण निर्यातों से प्राप्त आमदनी में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वर्ष खनिज लोहे, रासायनिक पदार्थों, खाल, छाल, चमड़े और उससे बनी वस्तुओं मसालों, मछली और उससे बनी वस्तुओं के निर्यातों से प्राप्त आमदनी में भी पर्याप्त वृद्धि हुई।

134. 1966-67 से 1969-70 तक के चार वर्षों में निर्यातों में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे यह पता चलता है कि समग्र निर्यातों की वार्षिक वृद्धि पर 2.7 प्रतिशत थी। दो प्रमुख परम्परागत वस्तुओं अर्थात्

सारणी 23—भारत के मुख्य निर्यात

(दस लाख अमेरिकी डालरों में)

	1965-66	1968-69	1969-70	1969-70 में प्रतिशत परिवर्तन	
				1965-66 की तुलना में	1968-69 की तुलना में
(क) मर्चे जिनमें वृद्धि हुई					
सूती धागा और उससे बनी वस्तुएं	148	134	154	+ 4	+ 15
खनिज लोहा	89	118	126	+ 12	+ 7
इंजीनियरी माल	37	92	120	+ 224	+ 30
खाल, छाल और चमड़ा तथा उनसे बनी वस्तुएं	79	104	119	+ 51	+ 14
लोहा और इस्पात	26	105	116	+ 346	+ 10
मसाले	49	34	46	- 6	+ 35
रासायनिक पदार्थ	23	32	40	+ 74	+ 25
मछली और उससे बनी वस्तुएं	14	30	42	+ 200	+ 40
(ख) मर्चे जिनमें कमी हुई					
जूट का धागा और उससे बनी हुई वस्तुएं	384	291	276	- 28	- 5
चाय	241	209	166	- 31	- 21
काजू की गिरी	58	81	77	+ 33	- 5
तिलहन, तेल और खसी	82	91	73	- 11	- 20
मोती, तराशे गए/न तराशे गए	31	60	56	+ 81	- 7
बहुमूल्य और मध्यम बहुमूल्य पर्यटन कच्ची मैंगनीज	23	18	15	- 35	- 17
(ग) जोड़	1693	1811	1884	+ 11	+ 4

स्रोत :—वाणिज्यिक सूचना और श्रंक संकलन महानिदेशालय

जूट की वस्तुओं और चाय के निर्यातों में जहाँ क्रमशः 8 प्रतिशत और 9 प्रतिशत की मिश्रित कमी हुई वहाँ नई मर्चों के निर्यातों में काफी अधिक वृद्धि हुई। लोहे और इस्पात के निर्यात में सबसे अधिक मिश्रित वृद्धि (45 प्रतिशत) हुई; उसके बाद इंजीनियरी वस्तुओं (34 प्रतिशत), मछली और उससे बनी वस्तुओं (32 प्रतिशत) और रासायनिक पदार्थों (15 प्रतिशत) के निर्यातों में वृद्धि हुई।

135. वाणिज्यिक सूचना और श्रंक संकलन महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार 1969-70 (अप्रैल-मार्च) में किए गए आयातों की राशि 20,900 लाख डालर थी, इससे पता चलता है कि इस वर्ष आयातों में 1968-69 के आयात स्तर की तुलना में 17 प्रतिशत की कमी हुई।

136. इस वर्ष कुल आयातों में जो कमी हुई वह अनाजों और अनाजेतर पदार्थों की कमी के कारण हुई जबकि पिछले वर्ष अनाजेतर पदार्थों के आयातों में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। (दाएँ से बिध) अनाजों के आयातों में 1969-70 में 23 प्रतिशत की कमी हुई। इसका मुख्य कारण यह था कि अच्छी फसल के कारण सप्लाई की स्थिति संतोषजनक हो गयी थी। मुख्यतः उर्वरकों के देशी उत्पादन में वृद्धि

होने के कारण इस वर्ष किये गये उर्वरकों के आयात का परिमाण 1968-69 के आयात परिमाण के आधे से भी कम था। परन्तु मुख्य रूप से दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों के भारी आयातों के कारण खनिज तेलों के आयातों में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अपरिष्कृत तेल के आयातों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऊन, पशु और वनस्पति तैलों, तथा फागज और फागज के बीजों के आयात पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक थे। मशीनों और परिवहन उपकरणों के आयातों में 1969-70 में 24 प्रतिशत की कमी हुई; इस से आयात प्रतिस्थापनों में की गयी और प्रगति का पता चलता है। इस कमी के एक अंग का कारण पिछले वर्षों में उद्योगों में पायी गयी मशीन का विलंब से बड़ा प्रभाव हो सकता है।

137. 1966-67 से 1969-70 तक के चार वर्षों में समग्र आयातों आयातों में 29 प्रतिशत की कमी हुई; यह कमी प्रमुख रूप से अनाजों पटसन और मेस्ता, मशीनों और परिवहन उपकरण, लोहे और इस्पात तथा अलौह धातुओं के क्षेत्रों में हुई। अनाजेतर आयातों को प्रत्यक्ष भाँटा में कम करके 1965-66 की तुलना में 1969-70 में औद्योगिक उत्पादन का जो स्तर उच्चतर बनाये रखा गया उससे संभवतः भारती अर्थव्यवस्था पर पड़े आयात प्रतिस्थापन के प्रभाव का परिचय मिलता है।

सारणी 24— भारत के मुख्य आयात

(बस लाख अमेरिकी डालरों में)

पण्य	1965-66	1968-69	1969-70	1969-70 में प्रतिशत परिवर्तन	
				1965-66 की तुलना में	1968-69 की तुलना में
1. अन्न (काजू को छोड़ कर)	712	495	391	45	21
उनमें से दालों से भिन्न अनाज और उनसे बनी चीजें	676	449	348	49	23
2. रुई	97	120	110	13	8
3. पटसम और मेस्ता	53	22	7	87	68
4. काजू	32	42	37	16	12
5. खनिज तेल	143	177	183	28	3
उनमें से					
(क) अगणिष्ठन और अंशतः परिष्कृत पेट्रोलियम	73	128	128	75	—
(ख) दूसरे	70	49	55	21	12
6. रासायनिक पदार्थ	221	378	246	11	35
उनमें से					
(क) उर्वरक	82	186	90	10	52
(ख) दूसरे	139	192	156	12	19
7. मशीनें और परिवहन उपकरण	1034	685	524	49	24
उनमें से					
(क) बिजली की मशीनों को छोड़ कर अन्य मशीनें	701	488	372	47	24
(ख) बिजली की मशीनें	184	109	85	54	22
(ग) परिवहन उपकरण	149	88	67	55	24
8. लोहा और इस्पात	206	115	108	48	6
9. अलौह धातु	145	119	99	32	17
10. कच्चा रबड़ (कृत्रिम और सुधारे गए रबड़ को मिला कर)	10	7	13	30	86
11. ऊत और दूसरे पशुओं का रोम	11	15	23	109	53
12. पशु और वनस्पति तेल और तर्प	32	26	39	22	50
13. कागज, कागज के बोर्ड और उनसे बनी चीजें	28	24	32	14	33
14. मोती और तराशे न गए/तराशे गए बहुमूल्य और मध्यम बहुमूल्य पत्थर	3	37	38	1167	3
15. दूसरे	232	283	240	3	15
जोड़	2959	2545	2090	29	18

स्रोत :—आणिज्यिक सूचना और श्रक संकलन महानिदेशालय ।

सारणी 25—विदेशी सहायता*

(बस लाख अमेरिकी डालरों में)

	ऋण**	अनुदान	पी. एल. 480 सहायता @	जोड़ (1+2+3)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1. मार्च 1966 के अंत तक वितरित न की गई रकम	2,235	115	226††	2,576
2. प्राधिकृत				
(क) 1966-67 में	1,469	106	524	2,099
(ख) 1967-68 में	603	22	324	949
(ग) 1968-69 में	1,088	91	66	1,275
(घ) 1969-70 में	697	35	98	830
जोड़	3,857	254	1,042	5,153
3. प्रयुक्त				
(क) 1966-67 में	903	126	480	1,509
(ख) 1967-68 में	1,074	81	415	1,570
(ग) 1968-69 में	888	87	113	1,088
(घ) 1969-70 में	1,026	34	143	1,203
जोड़	3,891	328	1,151	5,370
4. मार्च 1970 के अंत तक वितरित न की गई रकम	2,186†	42†	108@@	2,336

*इसमें (क) अमेरिकी पी. एल. 480 शीपक II और III के अधीन दिए गए अनुदान और

(ख) 1967-68 में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखी गई विशेष जमा राशियां शामिल नहीं हैं। इन जमा राशियों में से सरकार को दिया गया 150 लाख डालरों का ऋण भी 1968-69 के ऋणों में शामिल किया गया है।

**इसमें पी. एल. 480 परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा ऋणों की अधिकृत और प्रयुक्त रकमें शामिल हैं।

@इसमें अमेरिकी पी. एल. 480 शीपक I कार्यक्रम के अधीन माल के आयात के लिए रखी गई खपता जमा राशियों का पता लगता है, अतः इन निधियों से ऋणों और अनुदानों के रूप में वितरित की गई राशि स्तंभ 1 और 2 में शामिल नहीं की गई है।

††गतावधिक करारों के लिए 1,840 लाख अमेरिकी डालरों का समायोजन किया गया।

†नवम्बर 1967 में डेनिश क्रोनर और पीड स्टर्लिंग और अगस्त 1969 में फ्रेंच फ्रांक के अवमूल्यन के लिए तथा अक्टूबर 1969 में जूष मार्क के पुनर्मूल्यन के लिए समायोजित किया गया।

@@@गतावधिक करारों के लिए 90 लाख डालरों का समायोजन किया गया।

सारणी 26—बिदेशी सहायता की उपलब्धि

कुल ग्रीर वास्तविक

(दस लाख अमेरिकी डालरों में)

वर्ष	प्रयुक्त कुल सहायता	ऋण परि- शोधनार्थ अदायगियां	व्याज की अदायगियां	कुल ऋण भार (2+3)	उपलब्ध सहायता की वास्तविक रकम (1-4)
	1	2	3	4	5
1961-62	711	121	70	191	520
1962-63	933	101	81	182	751
1963-64	1,239	113	96	209	1,030
1964-65	1,520	145	110	255	1,265
1965-66	1,622	162	141	303	1,319
1966-67	1,509	210*	153	363	1,146
1967-68	1,570	275*	163	438	1,132
1968-69	1,088	276*	182@	458	630
1969-70	1,203	317*	189@	506	697

*इसमें नीचे दिये गये पुनर्निर्माण/स्थगित ऋणों के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70
जापान		3	6	17
अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक		—	—	15
अमेरिका		—	—	6
कनाडा		—	—	1
जोड़		3	6	39

@अमेरिका द्वारा 1968-69 और 1969-70 में प्रतिवर्ष 10 लाख डालरों का जो ब्याज स्थगित किया गया वह इसमें शामिल नहीं है।

बिदेशी सहायता

138. बिदेशी सहायता के प्राधिकार दूसरी योजना अवधि के 10,600 लाख डालरों के वार्षिक औसत से बढ़कर तीसरी योजना अवधि में 12,200 लाख डालर और 1966-67 में 20,990 लाख डालर हो गये। परन्तु बाद में प्राधिकारों में पर्याप्त मात्रा में कमी हुई और उनमें काफी घट-बढ़ भी हुई। 1967-68 (अप्रैल-मार्च) में उनकी राशि तेजी से घटकर 9,490 लाख डालर या उससे कम पिछले वर्ष के स्तर के 45 प्रतिशत तक पहुँच गयी। 1968-69 में उक्त प्राधिकार राशि बढ़कर 12,750 लाख डालर हो गयी। किन्तु पुनः 1969-70 में 1967-68 के स्तर से भी कम होकर 8,300 लाख डालर हो गयी। 1968-69 की तुलना में 1969-70 में प्राधिकारों में हुई लगभग 88 प्रतिशत की कमी ऋणों की कमी के कारण हुई। अमेरिका से मिलने वाले प्राधिकारों में तेजी से कमी हो जाने के कारण ऋणों में एक वर्ष की अवधि में 3,910 लाख डालरों की कमी हो गयी थी। अधिकृत अनुदानों में भी 1968-69 की तुलना में 560 लाख डालरों की कमी हुई। केवल पी०एल० 480 शीर्षक I के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सहायता पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी सी अधिक (20 लाख डालर) थी।

139. फिर भी, 1969-70 के वित्तीय वर्ष में उपयोग की गयी बिदेशी सहायता राशि में थोड़ा सा सुधार हुआ। यह राशि 12,030

लाख डालर थी अर्थात् 1968-69 की तुलना में 1,150 लाख डालर या 11 प्रतिशत अधिक थी। किसी अवधि में उपयोग की जाने वाली राशि सामान्यतः पिछली अवधियों में प्राधिकृत की गयी राशि पर निर्भर करती है। आलोच्य वर्ष के उच्चतर स्तर से प्रायोजनेतर ऋणों के अधिक उपयोग का पता चलता है। अधिकृत सहायता की ब्याज-अदायगी के संदर्भ में बिदेशी मुद्रा का जो परिचय होता है उसकी राशि भी 1968-69 के 4,580 लाख डालरों* से बढ़कर 1969-70 में 5,060 लाख डालर* हो गयी। इसमें इस वर्ष की हमारी निर्यात आमदनियों का 27 प्रतिशत और उपयोग की गयी कुल बिदेशी सहायता राशि का 42 प्रतिशत सम्मिलित है। फिर भी चूंकि यह वृद्धि प्रयुक्त राशि में हुई वृद्धि से कम थी अतः सहायता कार्यक्रमों के अधीन प्राप्त बिदेशी वित्त की

*इसमें अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अमेरिका, जापान और कनाडा ने देय ऋणों को पुनर्व्यवस्थित कर या उनकी अदायगियों को स्थगित कर जो राहत प्रदान की वह शामिल नहीं है। अन्यथा, ऋणों के लिये जो ब्याज आदि चुकाने पड़ते उनकी राशियाँ 1968-69 और 1969-70 में क्रमशः 5,000 लाख डालर और 5,500 लाख डालर हो गयी होती।

सारणी 27—कुल विदेशी सहायता

(दस लाख अमेरिकी डालरों में)

1	ऋण	अनुदान	पी.एल. 480/665 सहायता और अन्य देशों की मुद्रा के रूप में सहायता	
			जोड़	जोड़
प्राधिकृत				
1. दूसरी योजना तक	3,145	545	2,411	6,101
2. तीसरी योजना की अवधि में	4,887	278	947	6,112
3. 1966-67 में	1,469	106	524	2,099
4. 1967-68 में	603	22	324	949
5. 1968-69 में	1,088	91	96	1,275
6. 1969-70 में	697	35	98	830
जोड़	11,889	1,077	4,400	17,366
प्रयुक्त				
1. दूसरी योजना तक	1,788	485	1,155	3,428
2. तीसरी योजना की अवधि में	4,009	223	1,793	6,025
3. 1966-67 में	903	126	480	1,509
4. 1967-68 में	1,074	81	415	1,570
5. 1968-69 में	888	87	113	1,088
6. 1969-70 में	1,026	34	143	1,203
जोड़	9,688	1,036	4,099	14,823

नोट :—कृपया सारणी 25 की पाद टिप्पणियाँ देखें।

सारणी 28—स्रोत के अनुसार कुल विदेशी सहायता

(दस लाख डालरों में)

	मार्च 1970 तक प्राधिकृत राशि				मार्च 1970 तक प्रयुक्त राशि			
	ऋण	अनुदान	पी.एल. 480/665 सहायता और अन्य देशों की मुद्रा के रूप में सहायता	जोड़	ऋण	अनुदान	पी.एल. 480/665 सहायता और अन्य देशों की मुद्रा के रूप में सहायता	जोड़
अ.पु.वि. बैंक/अ.वि.संघ	2,191	—	—	2,191	1,938	—	—	1,938
				(12.6)				(13.1)
अमेरिका	4,076	362	4,400	8,838	3,589	353	4,099	8,041
				(50.9)				(54.2)
मोडियन समाजवादी जनतंत्र संघ	1,362	16	—	1,378	844	14	—	858
				(8.0)				(5.8)
पश्चिम जर्मनी	1,191	23	—	1,214	1,042	22	—	1,064
				(7.0)				(7.2)
ब्रिटेन	1,172	14	—	1,186	1,024	10	—	1,034
				(6.8)				(7.0)
जापान	488	1	—	489	429	1	—	430
				(2.8)				(2.9)
रूस	1,409	661	—	2,070	822	636	—	1,458
				(11.9)				(9.8)
जोड़	11,889	1,077	4,400	17,366	9,688	1,036	4,099	14,823
				(100.0)				(100.0)

नोट :—कृपया सारणी 25 की पाद-टिप्पणियाँ देखें। कोष्ठकों में दिये हुए आंकड़े कुल राशि के प्रतिशत हैं।

वास्तविक राशि 6,970 लाख डालर थी जो एक वर्ष पहले की राशि की तुलना में 670 लाख डालर अधिक थी।

140. पिछले वर्ष की तरह 1969-70 में ऋण की राशि अधिकृत सहायता से अधिक थी। उनकी मात्रा कुल सहायता प्राधिकारों का 84 प्रतिशत थी, जिसमें पी० एल० 480 सहायता @ और अनुदानों का अंश क्रमशः 12 प्रतिशत और 4 प्रतिशत था। 1969-70 में अधिकृत किये गये ऋणों का लगभग 45 प्रतिशत (3,150 लाख डालर) ऋण प्रायोजनेतर कार्यों की सहायता के लिये और 9 प्रतिशत (610 लाख डालर) ऋण राहत के लिये नियत था और शेष 46 प्रतिशत ऋण विशिष्ट प्रायोजनाओं के लिये लिया गया था। प्रायोजनाओं के लिये, लिये गये ऋण की मात्रा पिछले वर्ष के 17 प्रतिशत से बढ़कर 1969-70 में 46 प्रतिशत हो गयी क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, अन्तर्राष्ट्रीय विकास की अमेरिकी एजेंसी और अमेरिकी एक्जिम्ब बैंक द्वारा दी गयी सारी राशि और इटली तथा कनाडा से प्राप्त सहायता का अधिकांश भाग विशिष्ट प्रायोजनाओं के लिये नियत था। जापान, नीदरलैंड और बेल्जियम द्वारा दी गयी सारी प्राधिकृत सहायता की तरह ब्रिटेन और पश्चिम जर्मनी द्वारा दी गयी प्राधिकृत सहायता का अधिकांश भाग भी पहले की तरह विशिष्ट प्रायोजनाओं से संबंध नहीं किया गया था। इसके अलावा पश्चिम जर्मनी, नीदरलैंड और बेल्जियम ने, सामान्य रूप से ही सही, अपने प्राधिकारों की शर्तों को लचीला बना दिया था। पश्चिम जर्मनी द्वारा दिये गये (ऋणों की सहायता के लिये दिये गये ऋणों से भिन्न) ऋणों की व्याज दर 1968-69 में प्राधिकृत किये गये ऋणों की वार्षिक 3 प्रतिशत की व्याज दर से 1/2 प्रतिशत कम थी और 1969-70 में दिये गये प्राधिकारों की अनुग्रह अवधि पिछले वर्ष से अधिक थी। जहाँ पिछले वर्ष 7 वर्ष की अनुग्रह अवधि दी गयी थी वहाँ इस वर्ष 8 वर्ष की अवधि निर्धारित की गयी थी और उनकी समाप्ति की अवधि भी जहाँ पिछले वर्ष 25 वर्ष थी वहाँ इस वर्ष उसे बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया गया। नीदरलैंड ने भी व्याज दर में इसी प्रकार की कटौती की और ऋणों की समाप्ति अवधि को 26 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया। बेल्जियम ने अपने द्वारा प्राधिकृत किये गये ऋणों की व्याज दर को बहुत कम कर दिया अर्थात् उक्त दर को वार्षिक 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया और साथ ही, अनुग्रह और समाप्ति अवधियों को भी क्रमशः 7 से 10 वर्ष तक और 24 से 29 वर्ष तक बढ़ा दिया। किन्तु इसके विपरीत, आलोच्य वर्ष में पी० एल० 480 सहायता की शर्तों को और कड़ा कर दिया गया। दिसम्बर, 1968 करार में परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा ऋणों के 40 प्रतिशत का जो अंश निर्धारित था उसे बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया।

141. 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1970 तक प्राधिकृत की गयी विदेशी सहायता की कुल राशि 1,17,660 लाख डालर थी जिसका 68 प्रतिशत (1,18,890 लाख डालर) ऋणों के रूप में, 26 प्रतिशत (44,000 लाख डालर) पी० एल० 480/665 और अन्य देशों की मुद्रा के रूप में अमेरिका से प्राप्त सहायता के रूप में और शेष 6 प्रतिशत (10,770 लाख डालर) अनुदानों के रूप में थे। मार्च 1970 के अन्त तक उपयोग में लायी गयी सहायता की राशि 1,48,230 लाख डालर थी जिसमें 96,880 लाख डालर ऋणों के रूप में, 40,990 लाख डालर पी० एल० 480 और उसी प्रकार की सहायता के रूप में और 10,360 लाख डालर अनुदानों के रूप में प्राप्त हुए थे।

142. कुल प्राधिकृत राशि का लगभग 51 प्रतिशत और उपयोग की गयी कुल राशि का लगभग 54 प्रतिशत अमेरिका से प्राप्त हुआ था।

@ इसमें ऋणों के अन्तर्गत आने वाले पी० एल० 480 परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा ऋण शामिल नहीं हैं।

कुल प्राधिकृत और उपयोग की गयी राशि का लगभग 13 प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त हुआ था। काफ़ी अधिक मात्रा में वित्तीय सहायता देने वाले अन्य देश क्रमशः सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ, पश्चिम जर्मनी और ब्रिटेन थे।

143. भारत को दी गयी कुल अमेरिकी सहायता का लगभग आधा भाग पी० एल० 480 शीर्षक I कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त हुआ। 1969-70 में इस कार्यक्रम के अधीन प्राधिकृत राशि 2,480 लाख डालर थी; इसका अधिकांश भाग अनाजों अर्थात् गेहूँ (1,450 लाख डालर), चावल (180 लाख डालर) और ज्वार (140 लाख डालर) खरीदने और शेष राशि सूत (400 लाख डालर) और सोयाबीन तेल (280 लाख डालर) खरीदने के लिये नियत किया गया था। समुद्री भाड़ा-खर्चों के एक अंश की वित्तीय सहायता करने के लिये 30 लाख डालर की राशि दी गयी थी। पी० एल० 480 सहायता का अधिकांश भाग (1,500 लाख डालर) या 60 प्रतिशत) ऋणों के रूप में दिया गया। मार्च 1970 के अन्त तक प्राधिकृत की गयी पी० एल० 480 सहायता की कुल राशि 46,370 लाख डालर थी जिसमें से खपता जमादारियों पर 43,250 लाख डालर और परिवर्तनीय मुद्रा ऋणों के रूप में 3,120 लाख डालर दिये गये थे। उक्त कार्यक्रम के अधीन पण्यों के आयात से प्रोद्भूत खपता प्रतिरूप निधियों का बंटवारा नीचे लिखे अनुसार किया गया है :—

पी० एल० 480 प्रतिपक्ष निधियों का बंटवारा

	रकम (10 लाख डालरों में)	कुल राशि में प्रतिशत
1. भारत सरकार को दिये गये ऋण	2,643	61.1
2. भारत सरकार को दिये गये अनुदान	839	19.4
3. कुल परिक्षोघन के अधीन गैर सरकारी उद्यमों को दिये गये ऋण	281	6.5
4. अमेरिकी सरकार के उपयोग के लिए	562	13.0
जोड़	4,325	100.0

144. पिछले वर्ष की तरह भारत सहायता संघ ने 1969-70 में नये पुनर्वित्त ऋण प्रदान कर देय ऋणों की प्रदायगियों को स्थगित कर, ऋणों के कार्यक्रम में परिवर्तन कर, अथवा व्याज को रद्द/कम कर के ऋण राहत-सहायता प्रदान की। इस वर्ष प्राप्त ऋण राहत-सहायता की राशि 1,110 लाख डालर थी जो पिछले वर्ष की राशि की अपेक्षा 180 लाख डालर अधिक थी। क्योंकि ब्रिटेन ने इस वर्ष ऐसी ऋण राहत-सहायता प्रदान की जो सामान्यतः 1970-71 में ही प्रदान की जाती।

145. भारत सहायता संघ ने मई 1970 में पेरिस में हुई अपनी बैठक में 1970-71 के लिए 6,000 लाख डालरों की प्रायोजनेतर सहायता और 1,000 लाख डालरों की ऋण राहत-सहायता देना स्वीकार किया और इसके अलावा, 4,000 लाख डालरों की प्रायोजना सहायता की आवश्यकता को भी स्वीकार किया। परंतु पिछले अनुभव के आधार यह कहना कठिन है कि क्या वास्तविक प्राधिकार इन सीमाओं तक पहुँचेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थिति

146. आलोच्य अवधि में ड्यूयू मार्क और फ्रेंच फ्रांक का पुनर्सूच्य हो जाने, दक्षिण अफ्रीकी सोने की धिक्की की समस्या के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और दक्षिण अफ्रीकी के बीच करार हो जाने और

सारणी 29—ऋण राहत संबंधी सहायता

(10 लाख अमेरिकी डालरों में)

	1968-69		1969-70	
	प्राधिकृत	प्रयुक्त	प्राधिकृत	प्रयुक्त
(क) पुनर्निर्माण ऋणों के रूप में				
1. आस्ट्रिया	0.9	0.9	1.1	1.1
2. बेल्जियम	1.1	1.1	1.1	1.1
3. फ्रान्स	5.0	3.7	—†	1.3††
4. जर्मन (पश्चिम)	14.6	14.4	15.5	17.2
5. इटली	5.5	—	7.3	—
6. ब्रिटेन	18.0	18.0	36.0	36.0
जोड़ क	45.1	38.1	61.0	56.7
(ख) अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों के रूप में				
1. अ.पु.वि. बैंक	15.0	15.0	15.0	15.0
2. अमेरिका	8.7	8.7	8.7	8.7
3. कनाडा	0.9	0.9	0.9	0.9
जोड़ ख	24.6	24.6	24.6	24.6
(ग) अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों के कार्यक्रमों में परिवर्तन के रूप में				
1. जापान	16.8	16.8	19.6	19.6
जोड़ ग	16.8	16.8	19.6	19.6
(घ) अनुदानों के रूप में (ध्यान में राहत)				
1. कनाडा	1.1	1.1	—	—
2. जर्मन (पश्चिम)	4.8	4.8	4.8	5.0
जोड़ घ	5.9	5.9	4.8	5.0
(ङ) ध्यान में कटौती				
1. आस्ट्रिया	0.5	0.5	0.5	0.5
2. नीदरलैंड्स	0.6	0.6	0.6	0.7
जोड़ ङ	1.1	1.1	1.1	1.1
कुल जोड़	93.5*	86.5	111.1	107.0

*इसमें 1968-69 और 1969-70 में प्रतिवर्ष प्राप्त 80.0 लाख डालर की नकदी सहायता शामिल नहीं है।

†अप्रैल 1970 में 1969-70 के लिए 50.0 लाख डालरों की राशि के लिए फ्रेंच वायव्यों के करार पर हस्ताक्षर किये गये।

††यह 1968-69 के ऋणों की प्रयुक्त राशि का शेष है।

पिछली रिपोर्ट में उल्लिखित विशेष आहरण अधिकारों की योजना का कार्यान्वयन किये जाने के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थिति में काफी सुधार हुआ। अगस्त 1969 में फ्रेंच फ्राच में 11.1 प्रतिशत का अव-मूल्यन हो जाने और अक्टूबर 1969 में ड्यूस मार्क में 9.3 प्रतिशत का अधिमूल्यन हो जाने के बाद सट्टेबाजी की भारी प्रतिविधियों और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय विनिमयों की अस्त अवस्थिति

में कमी आयी। 1970 के प्रारंभ से विनिमय बाजारों में कनाडा के डालर की बहुत मजबूत स्थिति और कनाडा की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में वृद्धि की बढ़ती हुई गति के कारण कनाडा के अधिकारियों ने 31 मई 1970 को कनाडा के डालर के वर्तमान सम मूल्य को रद्द कर दिया। इसका विनिमयों पर तुरंत प्रभाव यह पड़ा कि वे बाजार में अधिक चलन में आ गये। निधि के सदस्यों ने विशेष आहरण अधिकार योजना को स्वीकार कर निधि में अंतर्राष्ट्रीय करार के आधार पर एक विशेष आहरण अधिकार खाता खोल कर अंतर्राष्ट्रीय चलमुद्रा का विशेष निर्माण किया। इस कदम से सोने के सट्टेबाजों की प्रत्याशाएं असफल हो गयीं और इस कारण जिन अल्पावधि निवेशकों ने सोने के आधिकारिक मूल्य में वृद्धि होने की प्रतीक्षा में सोने का संग्रहण किया था वे 1969 के मध्य से अपने संग्रह को बाहर निकालने लग गये। दक्षिण अफ्रीकी सोने की भारी बिक्री का करार होने की प्रत्याशा से बाजार में और गिरावट आयी। सोने का संग्रह करने के काम में लगी जाने वाली निधियों से उधार लेकर उसकी सहायता से संग्रह किये गये सोने के मूल्य में होने वाली वृद्धि के कारण सोने का अंतर्राष्ट्रीय मुक्त बाजार मूल्य, प्रारंभ में जहाँ प्रति औंस 43 अमेरिकी डालर था वहाँ दिसंबर 1969 में घटकर प्रति औंस 35 अमेरिकी डालर के आधिकारिक स्तर पर पहुँच गया। 1958 के बाद पहली बार सोने का मूल्य इस स्तर पर पहुँचा था।

147. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी मूल्य के संवर्धन में इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई यद्यपि 1969 के अंत में प्रमुख औद्योगिक देशों के आयातों की वृद्धि दर में मंदी के कुछ लक्षण दिखाई देने लगे थे। यह वृद्धि दर 1968 के 12 प्रतिशत की तुलना में 1969 में 14 प्रतिशत थी। पहले की तरह कम विकसित देशों के व्यापार में वृद्धि की दर कम ही थी। यद्यपि उसमें 11 प्रतिशत की कमी पायी गयी फिर भी वह 1968 के स्तर की तुलना में 1.5 प्रतिशत अधिक ही थी मुख्यतः ब्रिटेन, अमेरिका, और फ्रांस की स्थिति में अनुकूल परिवर्तन आने और पश्चिम जर्मन की स्थिति में प्रतिकूल गतिविधियों के कारण केवल अंशतः संतुलन होने के परिणामस्वरूप औद्योगिक देशों की समन्वित समग्र भुगतान स्थिति में सुधार हुआ अर्थात् 1968 में जहाँ उसमें 26 अरब डालरों का घाटा था वहाँ 1969 में लगभग उतनी ही राशि बकाया थी। औद्योगिक देशों की भारी मांग के कारण हुए निर्यातों से अधिक धामदानी हुई और उससे कम विकसित देशों के चालू लेखे के घाटे की राशि 68 अरब डालरों से घटकर 61 अरब डालर हो गयी। पूँजीगत लेखे में कम उपलब्धि होने से उसकी राशि 79 अरब डालरों से थोड़ी-सी कम होकर 78 अरब डालर हो गयी; इससे कम विकसित देशों की समग्र अन्तर्राष्ट्रीय अधिशेष की राशि 1968 के 11 अरब डालरों से बढ़कर 17 अरब डालर हो गयी।

148. अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में आलोच्य वर्ष में यद्यपि काफी सुधार हुआ, फिर भी कतिपय मुख्य समस्याएँ वैसी ही बनी रहीं। अमेरिका के चालू लेखे में कमी हुई, जिससे अधिशेष की राशि 14 अरब डालरों से कम होकर 9 अरब डालर हो गयी। गैर सरकारी पूँजी भी काफी मात्रा में बाहर गयी और इन दोनों कारणों से लगभग 70 अरब डालरों का घाटा हुआ जब कि 1968 में लगभग उतनी राशि बकाया थी। फिर भी, देश की मुद्रा स्फीति की स्थिति तथा भुगतान शेष संबंधी समस्याओं का सामना करने के लिए अमेरिकी मुद्रा अधिकारियों ने जो कड़ी मुद्रा नीति अपनायी उसके परिणामस्वरूप अमेरिका को पर्याप्त मात्रा में विदेशी अल्पावधि निधियाँ प्राप्त हुई और अमेरिकी बैंकों को विदेशों से भारी मात्रा में ऋण लेने के लिए प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार उपलब्ध निधियाँ घाटे को पूरा करने के लिए पर्याप्त थीं और 1969 में अमेरिकी भुगतान

शेष के समग्र अधिषेध की राशि 28 अरब डालर हो गयी थी जब कि 1968 में यह राशि 14 अरब डालर थी। कुल मिलाकर अमेरिका के भुगतान शेष की स्थिति विश्व-मुद्रा व्यवस्था की उल्लेखनीय शोचनीय स्थिति बनी रही।

149. पिछले दो वर्षों में अंतराष्ट्रीय मुद्रा स्थिति और समायोजन प्रणाली के संबंध में काफी विचार विमर्श किया गया है। किसी समय इस संबंध में ऐसा लगा कि निर्धारित सम मूल्यों की वर्तमान प्रणाली के अधीन विनिमय दरों में जो लचीलापन विद्यमान है उसे और बढ़ाने के पक्ष में राष्ट्रों का मत रहा हो। परंतु आलोच्य वर्ष के अंतिम भाग में ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ प्रभावशाली राष्ट्रों का दृष्टिकोण अधिक लचीलापन लाने के विरोध में था। इन विपरीत परिणामों के कारण यह चिंता उत्पन्न हुई कि बाजार विनिमय दरों को अधिक लचीला बनाने से राष्ट्रीय प्राधिकारियों पर दूसरे क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्रवाइयां करने का दायित्व आ पड़ेगा और वे बकाया डालर को रोके रखना चाहेंगे। इसके अलावा यूरोप के मुख्य औद्योगिक देश यह महसूस करते हैं कि निर्धारित वर्तमान सम मूल्यों में यदि परिवर्तन किया जाए तो उससे सामान्य बाजार व्यवस्थाओं की स्वस्थ कार्यप्रणाली को और साथ ही सामान्य बाजार मुद्रा बनाने के उनके दीर्घकालीन उद्देश्य को खतरा होगा।

150. अंतराष्ट्रीय व्याज दरों की स्थिति भी पहले की तरह शोचनीय रही। जहां अंतराष्ट्रीय क्षेत्र के एक वर्ष की यह प्रत्याशा थी कि इस वर्ष अंतराष्ट्रीय मुद्रा सहकारिता और यूरोपीय चलमुद्रा संबंधी पुनर्निर्धारण से संबंधित व्यवस्थाओं में परिवर्तन होंगे, वहां उसके विपरीत अंतराष्ट्रीय व्याज दरें पिछले वर्ष के उच्च स्तरों से कम नहीं हो सकीं। देश की मुद्रा स्फाति की स्थिति को रोकने और भुगतान शेष के ह्रास की स्थिति का सामना करने के लिए अमेरिका ने जिस मुद्रा नीति का प्रयोग किया उससे व्याज दरों में सामान्यतः वृद्धि हुई और यूरोपीय डालर बाजार में भी अंतराष्ट्रीय पारेषण की प्रणाली की व्यवस्था की गयी। प्रमुख उधारकर्ताओं के लिए यूरोपीय डालर ऋण पर वाणिज्य बैंकों द्वारा जो व्याज लिया जाता है उसको दर जून 1970 के अंत में 9.9 प्रतिशत थी और मुख्य औद्योगिक देशों में देशी कंपनी बांधों को व्याज दर 8.4 प्रतिशत और 11.5 प्रतिशत के बीच थी। पिछले कुछ समय से अंतराष्ट्रीय व्याज दरें अत्यधिक उच्च स्तर पर रही हैं और उनसे यह आभास मिसता है कि राष्ट्रीय निवेश के प्रयत्नों, विशेषकर पूंजी रहित विकासशील देशों के ऐसे प्रयत्नों के सामने गंभीर कठिनाइयां उपस्थित होंगी।

151. आलोच्य वर्ष की दूसरी छमाही में निधि के विशेष आहरण अधिकारों के रूप में निर्मित अंतराष्ट्रीय चलमुद्रा का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। यद्यपि विशेष आहरण अधिकार योजना गरीब देशों के विकास कार्यों की आवश्यकताओं के अनुकूल निधि का वितरण नहीं करती है, फिर भी यह स्पष्ट है कि ऐसे देशों द्वारा जो कुल निधि उपयोग में लायी गयी थी वह उक्त योजना के अधीन वितरित की गयी प्रारंभिक निधि का तीसरा अंश थी। संपन्न राष्ट्रों द्वारा राष्ट्रहित तथा वातावरण संबंधी कार्यक्रमों के संबंध में धनदायी गयी राष्ट्रीय नीतियों तथा उनकी प्रवृत्तियों को देखते हुए और साथ ही, उन देशों द्वारा की गयी अंतराष्ट्रीय विकास संधि निधियों की संपूर्ति और गरीब राष्ट्रों को दी गयी द्विराष्ट्रीय सहायता के संबंध में उनके द्वारा किये गये कार्य को भी देखते हुए यह वांछनीय प्रतीत होता है कि निर्मित चलमुद्रा और विकास संबंधी आवश्यकताओं के बीच सुनिश्चित रूप से ताल-मेल बरथा जाए। जुलाई 1970 में की गयी स्वीकृति के अनुसार अगले 3 वर्षों के लिए अंतराष्ट्रीय विकास संधि निधि में की गयी 8,000 लाख डालरों की राशि की संपूर्ति

संतोषजनक प्रतीत होती है, परंतु कम विकसित देशों को दी जानेवाली कुल सहायता राशि की मात्रा को, विशेषकर व्याज भ्राम्यगी के उनके बढ़ते हुए भार को देखते हुए बढ़ाना आवश्यक है।

152. अगस्त 1968 में विश्व बैंक द्वारा गठित किये गये पियर्सन आयोग ने जिसका उल्लेख पिछली रिपोर्ट में किया गया था सितंबर 1969 में विश्व बैंक को 'विकास में साझेदार' नामक रिपोर्ट पेश की जो विकास और अंतराष्ट्रीय सहायता की आधिकारिक छानबीन प्रस्तुत करती है। पिछले वर्षों के रिकार्ड के विश्लेषण के आधार पर पियर्सन आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि अधिक संपन्न देश विश्व के गरीब देशों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करें तो अधिकांश गरीब देश 30 वर्षों में प्रगति कर आत्मनिर्भर हो सकते हैं। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि यद्यपि विकास का रिकार्ड मिश्रित था, फिर भी वह 'सामान्यतः अपेक्षित स्तर से काफी अच्छा' था। आयोग ने इस बात की ओर संकेत किया "हाल ही के वर्षों में सहायता घटकर हो गयी है, तत्संबंधी नियम कठोर हो गये हैं और शर्तें अधिक प्रतिबंधक हो गयी हैं।" आयोग ने यह सिफारिश की है कि मुख्यतः आर्थिक विकास कार्य के आधार पर निर्धारित अधिक स्पष्ट मानदंड के अनुसार नियत की जानेवाली विकास सहायता को बढ़ाने और अधिक स्पष्ट रूप से निर्धारित किये गये आर्थिक लक्ष्यों की दिशा में साझेदारी के साथ संयुक्त प्रयत्न किया जाना चाहिए। अन्य बातों के साथ साथ आयोग ने यह सिफारिशों की हैं कि (क) आधिकारिक विकास सहायता की मात्रा को कुल राष्ट्रीय उत्पाद के 1968 के औसत 0.39 प्रतिशत से बढ़ाकर 1975 तक और किसी भी परिस्थिति में 1980 के पहले त्रैल्यक वाता वेश के कुल राष्ट्रीय उत्पाद का 0.7 प्रतिशत कर दिया जाए, (ख) आधिकारिक सहायता के बहु-वैश्वीय षटको की मात्रा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 1975 तक कम से कम 20 प्रतिशत कर दिया जाए; (ग) सहायता निधियां कम से कम 3 वर्षों की अवधियों के लिए दी जाएं (घ) अंतराष्ट्रीय विकास संधि सहायता में भी पर्याप्त वृद्धि की जाए; विकसित देश अपने लिए नियत किये गये विशेष आहरण अधिकारों के एक अंश को अंतराष्ट्रीय विकास संधि को प्रदान कर उक्त सहायता में अपेक्षित यह वृद्धि कर सकते हैं। व्याज दरों में कटौती करने, ऋण की पुनर्दी अवधि को बढ़ाने और कमरा: ऋण को निर्बंध बनाने की भी आयोग ने सिफारिशों की हैं। यह आशा की जाती है कि सहायता के वर्तमान असंतोषजनक राष्ट्रीय वातावरण में मूलतः परिवर्तन लाने और विश्व के गरीब देशों की भीम प्रगति के लिए मार्ग तैयार करने में पियर्सन आयोग की रिपोर्ट से सहायता मिलेगी।

मूल्यांकन और संभावनाएं

153. पिछले पैराग्राफों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुई प्रगति का जो विश्लेषण किया गया है उससे पिछले 12 महीनों में उत्पादन को बढ़ाने और विकास के लिए वित्तीय साधन जुटाने के संबंध में अर्थ व्यवस्था को जो सफलता प्राप्त हुई उसका परिचय मिलता है। उक्त अवधि इसलिए भी उल्लेखनीय है कि इस अवधि में प्राधिकारियों ने बैंकिंग, औद्योगिक नीति और समाज कल्याण नीति के क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कदम एक वर्ष पहले 14 प्रमुख वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना है जिसकी भूमिका में यह उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की राष्ट्रीय नीति और अग्रताओं के अनुरूप पूर्ति की जाए। इसका तत्काल परिणाम यह हुआ कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के प्रमुख यूनिटों के बीच परिचालन संबंधी उनकी समस्याओं के संबंध में अधिक मात्रा में सहयोग स्थापित हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण कदम अग्रणी बैंक योजना है जिसके अंतर्गत बैंकों के लिए जिले नियत किये गये जहाँ उन्हें बैंक

व्यवसाय के विकास की क्षमता का सर्वेक्षण, सांस्थानिक निधि और ऋण के बीच विद्यमान अंतर की जाँच और उम्र अंतर को दूर करने के लिए सक्रिय प्रयत्न करने होंगे। इन प्रयत्नों का परिणाम यह होना चाहिए कि बैंकिंग प्रणाली 'क्षेत्रीय' दृष्टिकोण अपनाये और इस प्रकार आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अपने योगदान में वृद्धि करे। इसके साथ ही, वाणिज्य और सहकारी बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रमों की गति को भी बढ़ाया गया है और बैंकों ने अधिक जमाराशियाँ जुटाने और कृषि तथा लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने लघु और मझौले उद्योगों के विकास के लिए विशेष रूप से सापेक्षतः कम विकसित क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए अपनी तरफ से अनेक कदम उठाये हैं। अल्पावधि और मध्यावधि ऋणों के सांस्थानिक स्वरूप को इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित किया गया है कि वह पहले की अपेक्षा आयोजना प्रक्रिया के अधिक निकट हो। जहाँ तक उद्योग के क्षेत्र का संबंध है औद्योगिक लाइसेन्सीकरण नीति में विभिन्न व्यापक परिवर्तन घोषित किये गये हैं और मझौली और छोटी आयोजनाओं के संदर्भ में लाइसेन्सीकरण नीति को पर्याप्त मात्रा में उदार बना दिया गया है। इसके अलावा, मूल, नाजुक और समस्यास्पद उद्योगों के लिए भ्रष्टा के आधार पर आवश्यक मूल सामग्री उपलब्ध करायी जाएगी। भारत सरकार के चालू वित्तीय वर्ष के बजट में विभिन्न प्रकार की वित्तीय आस्तियों के रूप में बचत की राशि बढ़ाने के लिए उल्लेखनीय प्रोत्साहन दिये गये हैं। अर्थव्यवस्था की कम सुविधाओं वाले क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए विभिन्न विशेष योजनाओं की भी घोषणा की गयी है। इन सभी प्रयत्नों से एक ऐसा अनुकूल वातावरण निर्मित हो जाता है जिससे अर्थव्यवस्था बराबर विकास की दिशा में अग्रसर हो सके।

154. फिर भी, अर्थव्यवस्था संबंधी कतिपय बिस्वाजनक पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। इनमें से अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू मूल्यों की पुनः बढ़ती हुई प्रवृत्ति है जिससे आलोच्य वर्ष के पहले के दो बर्षों के दौरान मूल्य स्थायिता पर बाधा पड़ी है। वाणिज्य फसलों के उत्पादनों में हुई कमी और कम अवधि में आयतों की व्यवस्था करने में होनेवाली कठिनाइयाँ कुछ सीमा तक इस मूल्य वृद्धि के कारण हैं। इस कारण इस बात की अधिक आवश्यकता हो जाती है कि अनाजों की ही तरह वाणिज्य फसलों की कृषि संबंधी टेक्नोलॉजी में भी प्रगति की जाए। परन्तु मूल्य स्थिति का अधिक गंभीर पहलू यह है कि अनाजों के उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन जैसे उन क्षेत्रों में भी जहाँ सफाई में सुधार हुआ है, मूल्य बराबर बढ़ते ही रहे हैं।

155. भारी माँग के कारण मूल्यों पर जो बनाव पड़ा उसे कुछ हद तक कम किया गया। इस तथ्य का संकेत मुद्रा पुँति और मीयादी जमाराशियों में हुई कम वृद्धि से मिलता है। यद्यपि वाणिज्यिक क्षेत्रों की बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण में पिछले वर्षों की दर पर ही वृद्धि होती रही फिर भी मुद्रा विस्तार की दर में कमी हुई। सरकार को बैंकों द्वारा दिये गये वास्तविक ऋण से बाटे की वित्तीय व्यवस्था का जो परिमाण मालूम होता है उसमें आलोच्य वर्ष में पर्याप्त मात्रा में कमी दिखाई पड़ी। इसके कारण इस प्रकार ये, अधिक वित्तीय साधन जुटाये गये और सरकारी व्यय में कुछ कमी हुई जिससे सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रमों के कम होने का पता चलता है। फिर भी सरकारी क्षेत्र में और अधिक मात्रा में बचत करने के लिए गुंजाइश है। फिलहाल राष्ट्रीय आय में सरकारी बचतों का अनुपात प्रतिशत के आसपास है। बचतों की अनुमानित मात्रा तक पहुँचने के लिए चौथी योजना के अंत तक इस अनुपात को 3.8 प्रतिशत तक बढ़ा देने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की कार्यप्रणाली में सुधार करने, वाणिज्यिक निष्कर्ष कार्यों और विविधोद्देश्यवाली नदी बाटी योजनाओं में होनेवाली

हानियों में कमी करने और राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय साधन जुटाये जाने से इस लक्ष्य तक तक पहुँचने में बहुत कुछ सहायता मिल सकती है।

156. अर्थव्यवस्था के घरेलू क्षेत्र की बचत में भी वृद्धि हुई है। वित्तीय आस्तियों के रूप में की जानेवाली बचतों के लिए दी गयी विभिन्न कर संबंधी रियायतों तथा छोटी बचतों की नयी योजनाओं से निश्चित रूप से इस संबंध में पर्याप्त सहायता प्राप्त होगी। परन्तु बैंकिंग प्रणाली को अधिक मात्रा में जमा राशि जुटाकर महत्वपूर्ण योगदान देना होगा। विशेषकर बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में जमा राशि जुटाने के लिए सुनिश्चित प्रयत्न करना होगा। कृषि संबंधी टेक्नोलॉजी में सुधार कर आय में वृद्धि कर देने से कृषि क्षेत्र की बचत की क्षमता अग्रसर ही तेजी से बढ़ेगी। फिर भी, इस क्षेत्र में बचत की प्रवृत्ति काफ़ी कम है। यह क्षेत्र अपनी जल आस्तियों अधिकांशतः जल-मुद्रा के रूप में ही बनाये रखता है और कृषि व्यवसाय में निवेश की गयी राशि को टोड़कर यह क्षेत्र शेष राशि को अधिकांशतः गहनों में लगता है और साथ ही असंगठित मुद्रा बाजार में निवेश करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जमाराशि जुटाने संबंध में बैंकों ने जो विभिन्न योजनाएँ घोषित कीं उनका अभी इन प्रवृत्तियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। अतः बैंकों को इस क्षेत्र में बचत को बढ़ाने के लिए जमाराशि जुटाये जाने के संबंध में क्रान्तिकारी कदम उठाने होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जमाराशि जुटाने में जो सफलता मिली है उसका प्रमुख कारण बैंकों द्वारा इन क्षेत्रों में आर्थिक कार्यक्रमों के लिए अधिक मात्रा में दी गई ऋण-सुविधाएँ हैं। यदि बैंक ग्रामीण क्षेत्रों से बचत की राशि को एकत्र कर उसे शहरी क्षेत्रों में अंतरित करनेवाली संस्थाओं के रूप में ही काम करते रहे तो जमाराशि जुटाने के उनके प्रयत्नों को केवल सीमित मात्रा में सफलता मिलने की संभावना है। अग्रणी बैंक योजना के अन्तर्गत किये जानेवाले सर्वेक्षणों से इन क्षेत्रों में संस्थानिक निधि और ऋण के बीच विद्यमान अंतर का पता लगाने में पर्याप्त सहायता मिलेगी। सर्वेक्षणों के बाव इस अंतर को दूर करने के लिए वाणिज्य और सहकारी दोनों बैंकों को शीघ्र योजनाबद्ध प्रयत्न होंगे।

157. जैसा कि पहले देखा जा चुका है, अर्थव्यवस्था की पूर्ति के संबंध में भी कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में अच्छी प्रगति की गयी है। जहाँ तक कृषि का संबंध है, मानसून की अब तक की स्थिति संतोषजनक रही है और यह प्रत्याशा की जा सकती है कि अग्रणीकृत प्रतिकूल परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः आगामी वर्ष अनाजों और कृषि से प्राप्त कच्ची सामग्री की सफाई की दृष्टि से संतोषजनक वर्ष सिद्ध होगा। परन्तु वर्तमान कैलेण्डर वर्ष की पहली तिमाही में औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि की दर में कमी होने से कुछ संकेत प्राप्त हुए हैं। विशेषकर पूँजीगत माल के उद्योगों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तयनुरूपी अवधि की तुलना में बहुत अधिक कमी हुई है। आलोच्य वर्ष में औद्योगिक स्थिति का एक दूसरा रूप यह था कि उस क्षेत्र के उत्पादन की वृद्धि-दर में बहुत अधिक असमानताएँ थीं। तीनों बर्गों के उद्योगों में वास्तव में ऐसे अनेक उद्योग हैं जिनके उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक कमी हुई है।

158. कृषि-आय में वृद्धि होने और इस कारण विभिन्न बर्गों के उपभोक्ता माल की माँग बढ़ने की संभावना को देखते हुए यह आवश्यक होगा कि औद्योगिक उत्पादन बढ़ती हुई माँग के अनुरूप बहुत अधिक वृद्धि की जाए। पर्याप्त मात्रा में कच्ची सामग्री की व्यवस्था कर जहाँ कहीं आवश्यक हो वहाँ आयात करके भी उनकी पूर्ति कर और साथ ही छेती में काम आने वाली दूसरी चीजों की भी व्यवस्था कर वर्तमान उत्पादन क्षमता के उपयोग की मात्रा को बढ़ाने पर ही इस लक्ष्य की

पीछे पूर्ति हो सकती है। यदि दीर्घकालीन पृष्ठभूमि में देखा जाए तो अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन की बराबर बढ़ाने की क्षमता अभी हो सकती है जब सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में उचित मात्रा में निवेश किये जायें। चूंकि चौथी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है अतः सरकारी क्षेत्र में किये जानेवाले निवेश के संबंध में यह प्रत्याशा की जा सकती है कि उस में उत्पादन की वृद्धि की दर के अनुरूप वृद्धि होगी। परंतु गैर-सरकारी क्षेत्र की स्थिति शोचनीय ही है। कृषि और लघु उद्योग में किये जाने वाले निवेश में जहां वृद्धि हो रही है, वहां ऐसा मालूम होता है कि बड़े उद्योग क्षेत्र में किये जानेवाले निवेश की वृद्धि में कमी हो रही है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि निवेश के लिए वित्तीय सहायता करने वाली संस्थाएं अब पहले की तरह वित्तीय साधनों की कमी का नहीं। परंतु उचित निवेश योग्य योजनाओं की कमी का सामना कर रही हैं। यदि यही स्थिति जारी रही तो उसका निश्चित ही देश के भावी आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कृषि-प्राय में पर्याप्त वृद्धि होने की संभावना तथा इस कारण विभिन्न वर्गों के स्थाई और अस्थायी उपभोक्ता माल, कृषि संबंधी मशीनों और उपकरणों की मांग में भी पर्याप्त मात्रा में वृद्धि होने की प्रत्याशा से मुद्रा स्फुटि के खबाब तेजी से बढ़ते रहेंगे यदि उद्योग क्षेत्र आवश्यक क्षमता का निर्माण कर उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए अपने आपको सशक्त न बना ले। यदि दीर्घकालीन पृष्ठभूमि में निवेश की संतोषजनक स्थिति को बनाये रखना है तो लंबी निर्माण अवधिवाली आयोजनाओं पर तत्कास ध्यान देना होगा। औद्योगिक लाइसेंसिकरण की नीति में महत्वपूर्ण उद्योगों को अग्रता के आधार पर सभी आवश्यक मूल सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में जो बल दिया जाता है उससे इस दिशा में पर्याप्त सुविधा होगी।

159. पिछले बारह महीनों की अवधि में अर्थव्यवस्था की गति-विधियों में जो महत्वपूर्ण विशेषता पायी गयी वह आरक्षित विदेशी मुद्रा निधियों में हुई पर्याप्त वृद्धि है। इसका प्रमुख कारण मुख्यतः आयातों में की गयी भारी कटौती है; यह कटौती अंशतः अनाजों के उत्पादन में हुई वृद्धि और उद्योग क्षेत्र में आयात की जानेवाली मशीनों के स्थान पर देशी मशीनों के उपयोग में की गयी प्रगति के कारण और अंशतः निवेश कार्य में की गई पूर्वोक्लिखित कमी के कारण वर्तमान संकेतों के अनुसार आयातों में पायी जाने वाली कमी की प्रवृत्ति में पीछे ही परिवर्तन होने की संभावना है और इस कारण यह भी संभव है कि आरक्षित निधियों पर फिर एक बार दबाव पड़े। पिछले बारह महीनों में निर्यातों की वृद्धि दर में जो कमी पायी गयी वह इस संदर्भ में चिंता का कारण है। इस स्थिति से इस बात का भी संकेत मिलता है कि अगले दस वर्षों में ऐसी विकास-नीति के लिए, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरतापूर्ण प्रगति करना हो, न्यूनतम आवश्यकता के रूप में स्वीकृत औसतन वार्षिक 7 प्रतिशत तक निर्यातों को बढ़ाने के लिए कितना प्रयत्न करना होगा।

II. औद्योगिक वित्त की गतिविधियां

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और विदेशी ऋण देनेवाली अन्य संस्थाएं

160. संगठित औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए तथा पूंजीगत और इंजीनियरी सामान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष रूप से मध्यावधि एवं दीर्घकालीन सहायता प्रदान करने तथा पुनर्निर्माण/पुनर्भाजन की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चलाई गई अपनी योजनाओं

को जारी रखने के अतिरिक्त भारतीय विकास बैंक (भा. औ. वि. बैंक) ने ऐसी नीतियां निर्धारित कीं जिनका उद्देश्य विशेषकर देश के अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों में छोटे और छोटे-मझोले उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देना है। मियादी ऋण देनेवाली अन्य संस्थाओं के सहयोग से भा. औ. वि. बैंक ने पिछड़े क्षेत्रों की औद्योगिक क्षमता का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण-कार्य भी प्रारंभ किया है।

161. भा. औ. वि. बैंक द्वारा 1968-70 के दौरान मंजूर की कुल सहायता (गारंटियों को छोड़ कर) की राशि 66.6 करोड़ रुपये थी जो 1968-69 की तत्सम्बन्धी राशि के बराबर थी। प्रत्यक्ष औद्योगिक ऋणों और निर्यात ऋणों के पुनर्वित्त को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों के अधीन दी गई सहायता में वृद्धि हुई इस वर्ष भा. औ. वि. बैंक के कार्यकलापों का एक विशेष पहलू यह रहा कि आस्थगित अवायगी के आधार पर पूंजीगत और इंजीनियरी सामानों तथा सेवाओं का निर्यात करने वालों को प्रत्यक्ष ऋण देने और गारंटी सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विसंबर 1968 में प्रारंभ की गई योजना के अधीन निर्यातों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि की गयी। निर्यातों के लिए मंजूर किये गये प्रत्यक्ष ऋणों और गारंटियों की कुल राशि 1968-69 के 7.1 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1969-70 में 11.2 करोड़ रुपये हो गयी जबकि वर्ष के अंत में कुल मंजूरियों की राशि 18.4 करोड़ रुपये थी। इस वर्ष जिन वस्तुओं के निर्यात के लिए सहायता मंजूर की गई वे हैं : वस्त्र उद्योग की मशीनें, इस्पात की पटरियां, मोटर जैसिस पारेषण लाइन स्तंभ, तबिये के तथा एसी० एस० ग्रार० संवाहक और किवाइबंदी एवं पाइपबंदी का सामान। साथ ही मध्यावधि निर्यात ऋणों के पुनर्वित्त में भी मंजूरियों में उल्लेखनीय कमी हुई और उनकी राशि 1968-69 के 7.3 करोड़ रुपयों से घटकर 1969-70 में 1.3 करोड़ रुपये रह गई। इस प्रकार की सहायता के लिए आनेवाले आवेदनों का सिलसिला कुछ ढीला पड़ गया है क्योंकि निर्यातक संभवतः ब्याज की कम औसत-दर का लाभ उठाने के लिए उस योजना को अपनाने लगे हैं जो निर्यात के लिए प्रत्यक्ष रूप से ऋण और गारंटियां देने के लिए चलाई गई है। निर्यात को छोड़कर औद्योगिक संस्थानों की दी गई प्रत्यक्ष सहायता (ऋण व हमीवारी सहायता) की राशि 1968-69 के 18.4 करोड़ रुपयों से घटकर 1969-70 में 13.8 करोड़ रुपये हो गई। प्रत्यक्ष सहायता मंजूर करते समय भा. औ. वि. बैंक अनेक छोटी तथा मझोली आयोजनाओं तथा मध्यवर्गीय तकनीशियन-उद्यमकृतियों द्वारा प्रवर्तित और/या अल्प-विकसित क्षेत्रों में स्थित आयोजनाओं की ओर बराबर ध्यान देता रहा। बैंक द्वारा दी गई अप्रत्यक्ष सहायता भी पिछले वर्ष की अपेक्षा छोटे और मध्यवर्गीय उद्यमकृतियों को अधिक प्राप्त हुई। इस प्रकार 1969-70 में औद्योगिक ऋणों के लिए 966 आवेदनों पर 15.7 करोड़ रुपयों का पुनर्वित्त मंजूर किया गया जब कि 1968-69 में 321 आवेदनों पर 14.1 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त मंजूर किया गया। इस राशि में से 895 आवेदनों पर 6.8 करोड़ रुपयों का पुनर्वित्त लघु उद्योग इकाइयों और छोटे सड़क परिवहन वाहनों को दिये गए ऋणों के लिए मंजूर किया गया। जिन मशीन निर्माताओं को बैंक की पुनर्भाजन योजना का लाभ पहुंचा उनकी संख्या 1968-69 के 104 से बढ़कर 1969-70 में 121 हो गई तथा उपभोक्ता-खरीदारों की संख्या 335 से बढ़कर 455 हो गई। 1969-70 में पुनर्भाजन किये गये बिलों की राशि 24.1 करोड़ रुपये थी जो पिछले वर्ष की राशि से 8.6 करोड़ रुपये अधिक है और इस प्रकार योजना के प्रारंभ से लेकर इसका कुल जोड़ 61.4 करोड़ रुपये हो गया है। जुलाई 1969-जून 1970 की अवधि में भा. औ. वि. बैंक ने अपनी निधियों में से भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (भा. औ. वि. निगम) के डिपेंडेंसी में 0.5 करोड़ रुपयों का अग्रिमदान किया। इस वर्ष के कार्यकलाप की एक विशेषता यह रही कि सहायता

के वितरण में वृद्धि हुई और उसकी राशि 1968-69 के 48.7 करोड़ रुपये से बढ़कर 1969-70 में 52.3 करोड़ रुपये हो गयी।

162. इसके विपरीत मियादी ऋण देनेवाली अन्य अखिल भारतीय संस्थाओं के कार्यक्रमों में 1969-70 (अप्रैल-मार्च) के दौरान ह्रासोन्मुख प्रवृत्ति दिखाई दी। इस प्रकार भा. औ. नि. निगम की मंजूरीयों (रुपया और विदेशी मुद्रा ऋण हमीवारी और प्रत्यक्ष अभिवान) की जो राशि 1969-69 में 37.0 करोड़ रुपये थी वह 1967-70 में घटकर 22.4 करोड़ रुपये रह गई यद्यपि इसके द्वारा वितरित की गई 19.8 करोड़ रुपये की राशि 1968-69 (16.2 करोड़ रुपये) की प्रवेक्षा अधिक थी। मंजूरीयों में हुई लगभग सारी कमी विदेशी मुद्रा ऋणों के अधीन हुई। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (भा. औ. वि. निगम) की कुल मंजूरीयों (रुपया और विदेशी मुद्रा ऋण हमीवारी व प्रत्यक्ष अभिवान) की राशि भी जो 1969-70 में 21.0 करोड़ रुपये थी 1968-69 के 22.7 करोड़ रुपये के मुकाबले में कम है साथ ही इसके वितरण की राशि भी 1968-69 के 19.5 करोड़ रुपये से कम हो कर 1969-70 में 17.5 करोड़ रुपये के बराबर रह गई।

163. अप्रैल-मार्च की अवधि में (मद्रास औद्योगिक एवं निवेश निगम सहित) 18 राज्य वित्तीय निगमों (रा. वि. निगमों) द्वारा मंजूर किये गये कुल ऋणों की राशि में 68.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 1968-69 के 19.3 करोड़ रुपये से बढ़कर 1969-70 में 32.5 करोड़ रुपये हो गई। उसी अवधि में वितरित की गई राशि 21.5* करोड़ रुपये थी जो पिछले वर्ष के 17.4 करोड़ रुपये से अधिक थी। 31 मार्च 1970 को बकाया रहने वाले ऋणों की राशि 104.6 करोड़ रुपये थी जो 31 मार्च 1969 को बकाया रहनेवाली राशि से 12.7 करोड़ रुपये अधिक थी। 1969-70 की 32.5 करोड़ रुपये की कुल मंजूरीयों और 21.5 करोड़ रुपये की वितरित राशियों में लघु उद्योगों का अंश क्रमशः 19.8 करोड़ रुपये (60.9 प्रतिशत) और 12.1 करोड़ रुपये (56.3 प्रतिशत) था। प्रायः सभी रा. वि. निगमों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों के ब्याज की प्रभावी दर वार्षिक 7 प्रतिशत और 9 प्रतिशत के बीच रही और उक्त दर दूसरे उद्योगों के संदर्भ में वार्षिक 8 प्रतिशत और 9 प्रतिशत के बीच रही; तथापि भा. औ. वि. बैंक से रियायती पुनर्वित्त लिये जाने की हालत में यह दर 8 प्रतिशत और 8 1/4 प्रतिशत के बीच रही। कुछ रा. वि. निगमों ने ठंडे गोदाम, होटल और परिवहन जैसे उद्योगों को दिये गए ऋणों पर थोड़ी सी अधिक दर लगाई।

164. भा. औ. वि. बैंक ने कम विकसित क्षेत्रों में प्रायोजनाओं की स्थापना के लिए सुगमतर शर्तों पर प्रत्यक्ष सहायता देने की योजना जुलाई 1970 में घोषित की। इस योजना के अधीन बैंक ने यह निश्चय किया है कि निविष्ट पिछड़े जिलों/क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों को ब्याज की वर्तमान 8 प्रतिशत की सामान्य दर के वजाय 7 प्रतिशत की रियायती दर पर प्रत्यक्ष ऋण दिया जाए, ऋण की वापसी अदायगी की प्रारंभिक अनुग्रह अवधि को 3 वर्ष से बढ़ा कर 5 वर्ष कर दिया जाए, ऋण की अदायगी के लिए 15-20 वर्ष की दीर्घतर अवधि की इजाजत दी जाए और ऋण के अनाहृत वकालतों पर लिये जानेवाले वायदा प्रभार को घटाया जाए। हमीवारी के मामलों में बैंक अपने हमीवारी कमीशन को घटा देगा और इसके अतिरिक्त पिछड़े क्षेत्रों की प्रायोजनाओं

की गेयर-पूजी में प्रवेक्षाकृत अधिक मात्रा में अभिवान करेगा। इस योजना के अधीन ग्राम तौर पर उन प्रायोजनाओं के मामलों में रियायतें दी जायेंगी जिनकी लागत एक करोड़ रुपये से अधिक न हो; बृहत्तर प्रायोजनाओं के लिए अत्यन्तमक आधार पर रियायती वित्त दिया जाएगा।

165. पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के संदर्भ में रा. वि. निगमों और बैंकों की रुचि को बढ़ाने तथा ऐसे क्षेत्रों को अधिक मात्रा में संस्थागत वित्त प्रदान कराये जाने के उद्देश्य से भा. औ. वि. बैंक ने अप्रैल 1970 में यह निश्चय किया कि सभी बैंकों और राष्ट्रीय वि. निगमों को निविष्ट पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थिति छोटी और मझोली इकाइयों को उनके द्वारा दिये जानेवाले 20 लाख रुपये तक के सभी योग्य ऋणों के सिलसिले में पूर्ण रूप से 3 1/2 प्रतिशत की रियायती दर पर पुनर्वित्त प्रदान किया जाए वशर्ते कि प्रायनिक ऋणदाता द्वारा लगाई गई ब्याज की प्रभावी दर 6 प्रतिशत से अधिक न हो। पुनर्वित्त की शर्तें निश्चित करते समय भा. औ. वि. बैंक वायदा प्रभार का विसर्जित वापसी अदायगी की दीर्घतर अवधि और 2 या 3 वर्ष से अधिक की प्रारंभिक अधिस्थगन अवधि प्रारंभिक वर्षों में मूलधन और ब्याज की किस्तों की अदायगी का आस्थगन आदि उन प्रोत्साहनों को भी ध्यान रखेगा जो वित्तीय संस्थाओं द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में छोटे और मझोले प्रकार की प्रायोजनाओं को दिये जायेंगे। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने रा. वि. निगमों तथा बैंकों को अधिक संख्या में लघु इकाइयों की सहायता करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से 13 मई 1970 से छोटे उद्योग संस्थानों को दिये जानेवाले उन ऋणों की न्यूनतम राशि को जो पुनर्वित्त पाने के योग्य हों और जो ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत आते ह. रु. 20,000 से घटाकर रु. 10,000 कर दिया है। मशीनी बिलों के पुनर्भाजन के क्षेत्र में, राज्य बिजली बोर्डों को उनके भारी पूंजी लागतवाले विस्तार कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिए अनुपूरक वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भा. औ. वि. बैंक ने 24 मार्च, 1970 से राज्य बिजली बोर्डों के संदर्भ में उस अधिकतम वार्षिक सीमा को जहाँ तक कोई उपभोक्ता-खरीदार इस योजना के अधीन सुविधाएँ प्राप्त कर सकता है, 50 लाख से बढ़ा कर रु. 100 लाख कर दिया है अपने विकासात्मक कार्यों के अंतर्गत भा. औ. वि. बैंक ने पिछड़े क्षेत्रों को औद्योगिक क्षमता का पता लगाने और वहाँ उद्योग की मूल आवश्यकताओं से संबंधित सुविधाओं की प्राप्ति तथा कच्चे माल की सप्लाई की स्थिति को आकलन और उन उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक उस क्षेत्र की विपणन क्षमता का निर्धारण करने के लिए, जो ऐसे क्षेत्रों में लाभप्रद रूप से प्रारंभ किये जा सकते हैं, सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया है। इस प्रकार के दो सर्वेक्षण असम राज्य और त्रिपुरा के संघ-शासित क्षेत्र में जून 1970 में किये जा चुके थे। अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे सर्वेक्षणों को योजना बनाई गई है।

166. इस वर्ष भा. औ. वि. बैंक ने कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली में अपने क्षेत्रीय कार्यालय खोले। ये कार्यालय लगभग 20 लाख रुपये तक की प्रत्यक्ष एवं पुनर्वित्त सहायता के आवेदनों पर विचार करने के साथ-साथ आस्थगित अदायगी पर की गई मशीनों की विक्री से उद्भूत होनेवाले थ्रिलो-डिबन्तपत्रों के प्रत्येक सेट का 5 लाख रुपये तक पुनर्भाजन भी करेंगे। इसके अतिरिक्त, बंबई में स्थित प्रधान कार्यालय में एक अलग अनुभाग स्थापित किया गया है जो उपर्युक्त सीमाओं तक के पुनर्वित्त और पुनर्भाजन की सहायता के लिए पश्चिमी क्षेत्र से प्राप्त होनेवाले आवेदनों पर विचार करेगा। बैंक ने क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता और मार्गदर्शन के लिए तथा सहायता की मंजूरीयों के संबंध में निर्णय लेने के लिए क्षेत्रीय समितियों का गठन करने का भी निश्चय किया है; कलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालय के लिए क्षेत्रीय समिति का गठन किया

* इसमें दोनों वर्षों में प्रतिवर्ष 0.5 करोड़ की गारंटियों पर जो राशि वितरित की गई वह शामिल नहीं है।

जा चुका है। भा. श्री. बि. बैंक ने राज्य और केन्द्रीय सरकारों की एजेंसियों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा औद्योगिक हितों के विकासों के साथ संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से अन्य राज्यों की राजधानियों में छोटे शाखा कार्यालय खोलने का निश्चय भी किया है।

लघु उद्योगों के लिए वित्त व्यवस्था

167. ऋण गारंटी योजना में समुचित संशोधन करने के सुझाव देने के लिए बैंक ने जो कार्यकारी बल नियुक्त किया था उसने प्रकृष्ट 1969 में अपनी रिपोर्ट देते हुए बीमा सिद्धान्तों पर आधारित स्वचालन राशि की प्रणाली लागू किये जाने की सिफारिश की थी। सरकार ने उक्त दल द्वारा योजना के संदर्भ में सिफारिश किये गए संशोधनों को स्वीकार कर लिया है और संशोधित उपबंध 1 फरवरी, 1970 से लागू कर दिये गये हैं। संशोधित योजना के अन्तर्गत, प्रत्येक अनुमोदित ऋण संस्था द्वारा गारंटी संगठन के साथ करार निष्पादित किये जाने पर सभी योग्य अभिषेकों को स्वचालन आधार पर गारंटी उपलब्ध कराई जाती है। जो ऋण संस्थाएँ इस योजना में शामिल होती हैं उनको एक वैधानिक विवरणिका के रूप में अपने सभी योग्य अभिषेकों के विषय में रिपोर्ट देने की आवश्यकता है जिसके आधार पर उनसे हर तिमाही में वार्षिक एक प्रतिशत के 1/10 की दर से गारंटी शुल्क लिया जाता है। व्यवस्था में किये गये इस परिवर्तन से ऋण संस्थाओं के कार्यभार में पर्याप्त कमी होने तथा लघु उद्योगों को शीघ्र ऋण मिलने की प्राप्ति है। अब तक (सभी प्रमुख वाणिज्य बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों को मिलाकर) 117 अनुमोदित ऋण संस्थाएँ संशोधित योजना में शामिल हो चुकी हैं। ऋण संस्थाओं को गारंटियाँ उपलब्ध कराने में स्वचालन के उक्त तथ्य का समावेश किये जाने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणिकाओं की सत्यता की जाँच कराने के लिए उनकी शाखाओं/कार्यालयों के नमूना-परीक्षण किये जाएँ। यह काम गारंटी संगठन ने अपने हाथ में ले लिया है।

168. योजना में किये अन्य मुख्य परिवर्तन इस प्रकार हैं, (i) साखपत्रों, ऋण तथा आस्थगित अवयवियों की गारंटियों और लघु उद्योग की ऋणों की तरफ से खोले गये स्वीकृति साखपत्रों की पहली बार गारंटी योजना क्षेत्र के अंतर्गत लाना, इससे निष्पादन गारंटियों को छोड़कर बाँचे सभी प्रकार की ऋण सुविधाएँ इस गारंटी योजना के अंतर्गत आ जाती हैं; (ii) गारंटी आच्छादन की उस सीमा के बदले में, जो पहले मंजूर की गई सीमा, उसके उपयोगीकरण और किसी उधारकर्ता की अंतिम बाकीदारी राशि पर निर्भर करती थी, अब बाकीदारी राशि या गारंटीकृत राशि में से जो भी कम हो उसके 75 प्रतिशत के निर्धारित आच्छादन की व्यवस्था करना; (iii) गारंटीकृत अभिषेकों के संदर्भ में गारंटी संगठन से वसूल की जा सकने वाली अधिकतम राशि को कार्यकारी पूँजी अभिषेकों के संबंध में 2 लाख रुपये प्रति खाते से बढ़कर 7.5 लाख रु. प्रति खाता किया जाना और मियादी ऋणों के संबंध में प्रति उधारकर्ता 2.50 लाख रुपये की प्रतिरिक्त वृद्धि किया जाना।

169. पिछले वर्षों में इस योजना ने काफी प्रगति की है। मार्च 1970 के अंत में बकाया रहनेवाली गारंटियों की राशि 567 करोड़ रुपये (अनन्तिम) थी जब कि वह 30 जून, 1969 को 241 करोड़ रुपये थी। 164 अभिषेकों के संबंध में गारंटी देयताएँ उत्पन्न हुई और योजना के प्रारंभ से 30 जून, 1970 तक बाकीदारियों में सरकार के अंश की राशि 20.81 लाख रुपये थी। गारंटी संगठन ने अब तक बाँचे चुकाये गए खातों के संदर्भ में 5.95 लाख रुपये की राशि वसूल की है जो योजना के प्रारंभ से दिसंबर 1969 तक 39 अभिषेकों के संबंध में की गयी 3.77 लाख रुपये की पूरी वसूली को दर्शाती है। दिसंबर 1969 के अंत में जिन अभिषेकों के बारे में यह सूचित किया गया

है कि वे चुकाये नहीं गये हैं, (अर्थात् ऋण संस्थाओं द्वारा वापस मांगे गए ऋण जिनके लिए अभी बाँचे पेश नहीं किये गये हैं) उनकी संख्या और राशि क्रमशः 351 और 103.13 लाख रुपये थी। ऐसे मामलों में, यदि गारंटी संगठन की राय में खातों के अनुपोषण द्वारा कमजोर ऋणों के पुनर्जीवित होने की संभावना हो तो वर्तमान ऋण सुविधाओं को जारी रख कर अथवा आवश्यक होने पर प्रतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान कर उन ऋणों को प्रदान किये गये अभिषेकों का अनुपोषण किये जाने की वांछनीयता का महत्व ऋण संस्थाओं को समझाने के प्रयत्न किये जाते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जहाँ तक गारंटी संगठन का संबंध है वह ऐसे प्रयोजनों के लिए दिये गये/जारी रखे गये अभिषेकों के संर्भेद में गारंटी आच्छादन बराबर देता आ रहा है। इस वर्ष इस योजना के कार्यक्षेत्र को 'कस्टम सेवा' ऋणों (अर्थात् ऐसे संस्थान जो कृषि की मशीनें, जैसे तालर, पहियोंवाले ट्रैक्टर, गाहने की मशीनें, कटाई की संयुक्त मशीनें और नलकूपों की खुराई तथा संयंत्रों के संरक्षण के उपकरण आदि किराये पर देने का काम करते हैं), खदान ऋणों और समुद्री डीजल इंजनों की सेवाएँ और मरम्मत करने वाली ऋणों के लिए भी लागू कर दिया गया।

170. बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में अप्रैल 1970 को समाप्त हुए दस महीनों की अवधि में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा लघु उद्योगों के निमित्त मंजूर की गई ऋण सीमाओं की राशि में 161.7 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और वह अप्रैल 1970 के अंतिम शुक्रवार को 745.2 करोड़ रुपये थी, जब कि 1968-69 की उसी अवधि में मंजूर की गई ऋण सीमाओं में हुई वृद्धि की राशि 170.9 करोड़ रुपये थी। जिन ऋणों को वित्तीय सहायता दी गई उनकी संख्या में 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह 56,983 से बढ़कर 83,805 हो गई। अप्रैल 1970 के अंतिम शुक्रवार को बकाया रहनेवाले अभिषेकों की कुल राशि 397.7 करोड़ रुपये थी जो जून 1969 के अंत के स्तर से 112.1 करोड़ रुपये अधिक थी। स्टेट बैंक आफ इंडिया और उसके सहायक बैंकों द्वारा मंजूर की गई ऋण सीमाओं की राशि अप्रैल 1970 के अंत में 281.1 करोड़ रुपये थी और इससे 37,982 ऋणों को लाभ पहुँचा। उक्त राशि और ऋणों की संख्या में जून 1969 के अंत में रहनेवाली स्थिति की अपेक्षा क्रमशः 32 प्रतिशत और 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई। स्टेट बैंक आफ इंडिया समूह द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये कुल ऋण की जो राशि अप्रैल 1970 के अंत में 154.8 करोड़ रुपये थी वह जून 1969 के अंत के स्तर से 51.8 करोड़ रुपये अधिक थी। यह वृद्धि पिछले वर्ष की उसी अवधि में हुई वृद्धि से लगभग डेढ़ गुनी है। स्टेट बैंक आफ इंडिया और उसके सहायक बैंकों द्वारा प्रदान की गयी वित्तीय सहायता का अधिकांश भाग उनकी "उद्योगीकृत" योजना के अंतर्गत आता है। स्टेट बैंक आफ इंडिया और उसके सहायक बैंकों द्वारा इस योजना के अधीन मार्च 1970 के अंत तक मंजूर की गई कुल सीमाओं (कार्यकारी पूँजी और मियादी वित्तीय सहायता) की राशि 260.6 करोड़ रुपये थी जो मार्च 1969 के अंत की तत्संबंधी राशि से 80.0 करोड़ रुपये अधिक थी। मार्च 1970 के अंत में 146.9 करोड़ रुपये की जो कुल बकाया राशि थी वह मार्च 1969 के अंत के स्तर से 54.8 करोड़ रुपये अधिक थी। आलोच्य अवधि में स्टेट बैंक आफ इंडिया और उसके सहायक बैंकों द्वारा कारीगरों तथा योग्य उद्यमकर्तियों को वित्तीय सहायता देने के लिए 1967 में तैयार की गयी योजना में और आगे प्रगति हुई। मार्च 1970 के अंत तक जिन ऋणों को वित्त प्रदान किया गया उनकी संख्या 297 थी और उन्हें दी गई सहायता की कुल राशि 3.35 करोड़ रुपये थी; इसके विपरीत मार्च 1969 के अंत तक ऐसी 98 ऋणों को 0.90 करोड़ रुपये का वित्त प्रदान किया गया था। स्टेट बैंक आफ इंडिया समूह ने लघु उद्योग

की इकाइयों को दिये जाने वाले ऋण के संबंध में अपनी क्रियाविधि को पर्याप्त रूप से सरल कर दिया है। इस प्रकार उन सभी लघु इकाइयों को, जिनकी कार्यकारी पूंजी संबंधी आवश्यकताएँ 50,000 रुपये से अधिक न हों, ताला और बाबी तथा मंडी और फैक्ट्री किस्म के खाते, जिनमें पर मोवरड्राफ्ट, माजिनों के लिए मोवरड्राफ्ट, आदि कई खातों के बजाय एक ही खाते में घुटिबंधक के आधार पर ऋण सुविधाएँ दी जाएँगी। साथ ही, ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं के क्षेत्रों में स्थित वस्तुकारों/कारीगरों/लघु इकाइयों को गरीबता से ऋण दिलाने के उद्देश्य से एक विशेष योजना प्रारंभ की गई है जिसके अनुसार ऐसे क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को 5,000 रुपये की सीमा तक रियायती ध्याज दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

171. जिन 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण जुलाई 1969 में किया गया था उनसे वित्तीय सहायता प्राप्त करनेवाली लघु उद्योग इकाइयों की संख्या विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जून 1969 के अन्त से अप्रैल 1970 के अन्त तक इन बैंकों द्वारा वित्तपोषित इकाइयों की कुल संख्या में 13,145 की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि में यह वृद्धि 6,787 थी। अप्रैल 1970 को समाप्त हुए वस महीनों में इन बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की बकाया राशि 1968-69 की तदनुकूपी अवधि के 38.7 करोड़ रुपये की तुलना में 52.2 करोड़ रुपये थी।

172. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके सहायक बैंकों से अनुप्रतिरित होकर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ोदा, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र समेत कई बैंकों ने उन योग्य उद्यमकर्तृओं को वित्तीय सहायता देने के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं जिनके पास आवश्यक तकनीकी योग्यता और लघु उद्योग की ठोस योजनाएं तो हैं किन्तु अपने निजी वित्तीय संसाधनों का अभाव है। बहुत से बैंकों ने लघु उद्योगों को वित्त दिलाने के लिए माजिन, जमानत, व्याज की दर आदि के संबंध में अपनी शर्तों को उबार बना दिया है। कुछ बैंकों ने लघु उद्योग क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम संभालने के लिए अलग से विभाग/अनुभाग खोल दिए हैं जबकि सभी प्रमुख बैंकों ने अपने अधिकारियों को लघु उद्योगों के प्रभावी वित्तपोषण के संबंध में प्रशिक्षण देने के लिए भी योजनाएं बनाई हैं।

173. मार्च 1969 में लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों के साथ-साथ छोटे सड़क परिवहन चालकों को दिये गये ऋणों तथा लघु उद्योगों के लिए उद्योग आस्थान स्थापित करने के निमित्त दिये गये ऋणों को भी राष्ट्रीय ऋण परिषद द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के उद्देश्य के लिए सहायता-योग्य ऋणों की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया। इसी प्रकार फरवरी 1970 में जल परिवहन चालकों को दिये गये ऋणों को भी इन लक्ष्यों की पूर्ति के उद्देश्य के लिए सहायता योग्य ऋणों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया। जून, 1969 के अन्त में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा छोटे सड़क और जल परिवहन चालकों के लिए मंजूर की गई ऋण सीमाएं मार्च, 1970 के अन्तिम शुक्रवार को जून 1969 के अन्त में रहनेवाली स्थिति की तुलना में तिगुनी से भी अधिक थीं। अप्रैल 1970 के अन्तिम शुक्रवार तक 10,669 इकाइयों के संबंध में दी गई मंजूरीयों की कुल राशि 34.4 करोड़ रुपये थी; इसके विपरीत जून, 1969 के अन्त में 3,091 इकाइयों के संदर्भ में उक्त राशि 11.1 करोड़ रुपये थी, जबकि इन दो अवधियों में बकाया रहनेवाली राशि क्रमशः 28.3 करोड़ रुपये तथा 8.2 करोड़ रुपये थी। जहाँ तक उद्योग आस्थानों का प्रश्न है, अप्रैल, 1970 के अन्तिम शुक्रवार तक 8 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने ऐसे आस्थान स्थापित करने के लिए 1.15 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किये थे और इसके अन्तर्गत 31 खाते धार्य, इस संदर्भ में बकाया रहनेवाली राशि 36 लाख रुपये थी।

174. लघु उद्योगों की ऋण संबंधी एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधियों को एक ही मंच पर लाने के उद्देश्य से यह जरूरी समझा गया कि राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य में लघु उद्योगों के लिए राज्य-स्तरीय समन्वय समिति का गठन करें। बैंक की सहलाह पर असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों तथा दिल्ली प्रशासन ने ऐसी समितियों का गठन कर दिया है। बिहार सरकार ने उद्योग के लिए समग्र रूप से एक समन्वय समिति का गठन किया है।

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया

175. 1969-70 के दौरान यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूनिटों की बिक्री में और ज्यादा वृद्धि हुई। 30 जून 1970 को समाप्त हुए वर्ष में 22.83 करोड़ रुपये के यूनिट बेचे गये जबकि पिछले वर्ष 17.16 करोड़ रुपये के यूनिट बेचे गये थे। पुनः खरीदे गये यूनिटों की राशि पिछले वर्ष के 1.67 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष 2.04 करोड़ रुपये थी। बेचे गये और बकाया यूनिटों के कुल मूल्य की राशि 30 जून 1970 को 77.44 करोड़ रुपये थी और ट्रस्ट के यूनिटधारियों की कुल संख्या 3,33,000 से अधिक थी। यूनिटों की बिक्री में जो बराबर वृद्धि हुई है उससे निवेश के माध्यम के रूप में उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता का संकेत मिलता है।

176. समाज के विभिन्न वर्गों में वयत को बढ़ावा देने के अपने मूल उद्देश्य के अनुसरण में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई 1970 से 'बाल-उपहार योजना' प्रारम्भ की। इस योजना में नाबालिग बच्चे के माता-पिता, रिश्तेदार अथवा किसी अन्य व्यक्ति को एक ऐसी सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है जिसके अधीन उस नाबालिग बच्चे के नाम यूनिट जारी किये जाएंगे जो उनका एकमात्र हिताधिकारी हों। इसके अतिरिक्त जिस बच्चे के नाम यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया गया हो वह केवल 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन यूनिटों का लेन-देन कर सकेगा। तब तक इस प्रकार से खरीदे गये यूनिटों से होनेवाली आय का नये यूनिटों में अपने आप निवेश होता रहेगा और जब वह बच्चा 21 वर्ष का होगा तब उसके नाम यूनिटों के रूप में सुविधापूर्वक पूंजी का संचयन हो गया होगा जो विवाह, शिक्षा आदि उसकी प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध होगा।

177. निवेश करनेवाली जनता के बीच यूनिटों की बिक्री का प्रचार करने के लिए एजेंटों का जो जाल बिछाया गया है उसमें और विस्तार हुआ। पिछले वर्ष के 1,775 अनुमोचित एजेंटों की तुलना में 30 जून 1970 को अनुमोचित एजेंटों की संख्या 2,303 थी; अनुमोचित स्टॉक दलालों की तदनुकूपी संख्या क्रमशः 286 और 315 थी। ट्रस्ट के काउंटरों में यूनिटों की जो बिक्री होती है उसके अलावा ट्रस्ट की प्रारंभिक पूंजी में अभिदान करने वाले प्रमुख बैंकों की सभी शाखाओं और देश भर के 15,000 से भी अधिक डाक-घरों में यूनिट बेचे जाते हैं।

178. 31 मार्च 1970 को ट्रस्ट के निवेश की कुल राशि 84.61 करोड़ रुपये थी। इसमें से निगमित उपक्रमों के साधारण शेयरों में 29.23 करोड़ रुपये (34.5 प्रतिशत) अधिमान शेयरों में 11.40 करोड़ रुपये (13.5 प्रतिशत) डिबेंचरों में 34.35 करोड़ रुपये (40.6 प्रतिशत) और सरकारी प्रतिभूतियों तथा वित्तीय निगमों और बिजली बोर्डों के बांडों में 4.88 करोड़ रुपये (5.8 प्रतिशत) लगाये गये। 4.75 करोड़ रुपये (5.6 प्रतिशत) की बाकी राशि ऐसे डिबेंचरों और अधिमान शेयरों के निमित्त दी गई अधिम जमाराशि जिनकी हामीवारी

के लिए ट्रस्ट ने स्वीकृति दी थी तथा गेयर खरीदने के लिए दिये गये आवेदन-शुल्क खजाना जिलों और अधिम बोली जमाराशि की परिचायक है।

III. बैंक विभाग और संगठन

179. जिस घटना-क्रम ने बैंक व्यवसाय को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित किया है वह है 14 जुलाई 1969 से 14 भारतीय बैंकों* का राष्ट्रीयकरण किया जाना। भारत सरकार ने 19 जुलाई, 1969 को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अध्यादेश, 1969 के नाम से एक अध्यादेश जारी करके उन 14 बड़े भारतीय बैंकों के कारोबार को अपने हाथ में ले लिया जिनकी जमाराशियां जून 1969 के अन्तिम शुक्रवार को 50 करोड़ रुपये से कम नहीं थीं। इस अधिवेशन के पश्चात् प्रत्येक बैंक का कारोबार उसकी प्राप्ति, देयताओं, अधिकारों प्राप्ति के साथ एक नये सांविधिक निगमित निकाय के रूप में गठित किये गये तदनुसार नये बैंक में अंतरित किया गया और उसके अधिकार में लाया गया। प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक का सामान्य अधीक्षण एवं कार्य संचालन एक अभिरक्षक (कस्टोडियन) के सुपुर्द किया गया और उसे उन सब शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया जो बैंक द्वारा प्रयोग में लाई जा सकती हों। राष्ट्रीयकरण से तत्काल-पूर्व जो व्यक्ति प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के अध्यक्ष पद पर आसीन थे उन्हें तदनुसार नये बैंक का अभिरक्षक नियुक्त कर दिया गया।

180. अध्यादेश जारी किय जाने के तुरन्त पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय में कुछ प्रादेश याचिकाएं दाख की गईं और 22 जुलाई 1969 को 12 न्यायाधीशों के एक पूरे बेंच ने अध्यादेश के तीन विषयों के संबंध में दाख की गई प्रादेश याचिकाओं का निपटारा होने तक, एक अंतरिम रोक आदेश जारी कर दिया। इस रोक आदेश के अधीन केन्द्रीय सरकार पर ये प्रतिबंध लगाये गये कि 14 बैंकों में से किसी के लिए भी सलाहकार बोर्ड नियुक्त न किया जाए, बकों के उन 14 अध्यक्षों में से, जिन्हें अब अभिरक्षक का पद सौंपा गया था, किसी को भी उनके पद से न हटाया जाए और उन 14 बैंकों में से किसी को भी वर्तमान बैंक विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के बिना कोई हिदायत न दी जाए।

181. इस अध्यादेश के स्थान पर 25 जुलाई, 1969 को एक विधेयक पेश किया गया जो कुछ संशोधनों के साथ संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किय जाने पर 9 अगस्त 1969 को अधिनियम बन गया। अध्यादेश के स्थान पर अधिनियम के आने के तुरन्त पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यादेश के संदर्भ में जारी किय गये रोक आदेश को 11 अगस्त

1969 को रद्द कर दिया किन्तु अधिनियम के विरुद्ध फिर से दाख की गई प्रादेश-याचिकाओं के कारण 8 सितम्बर 1969 को एक नया रोक आदेश जारी कर दिया। इस दूसरे रोक आदेश ने सरकार को सलाहकार बोर्डों की नियुक्ति करने से तो नहीं रोका, फिर भी, अभिरक्षकों को पद से हटाने और 14 बैंकों में से किसी को भी हिदायतें जारी करने से संबंधित पहले के प्रतिबन्धों को फिर से लगा दिया।

182. सर्वोच्च न्यायालय ने 10 फरवरी 1970 को, बैंकिंग कंपनियों के अर्जन के संबंध में संसद की वैधानिक क्षमता की हिमायत करते हुए भी यह निर्णय दिया कि प्रथमतः 14 बैंकिंग कंपनियों के साथ भेदभाव बरता गया है क्योंकि उपक्रमों के अर्जन के बाद उन्हें बैंक व्यवसाय चलाने से प्रतिनिष्ठ कर दिया गया है जब कि दूसरे बैंकों को ऐसा करने की इजाजत है; साथ ही सरकार द्वारा दी जानेवाली प्रस्तावित क्षतिपूर्ति की रकम निर्धारित करने के लिए अधिनियम में विहित सिद्धांत और तरीके अवैध हैं। चूंकि न्यायालय द्वारा अवैध करार दिये गये उपबन्धों को मुख्य अधिनियम से पृथक नहीं किया जा सकता था अतएव समूचे अधिनियम को को रद्द कर दिया गया।

183. केन्द्रीय सरकार ने जिन 14 बैंकों के कारोबार को उक्त अधिनियम के प्राधिकार के अधीन 19 जुलाई, 1969 को अपने हाथ में ले लिया था वे इस अधिनियम के अवैध करार दिये जाने के कारण फिर से अपनी पूर्वस्थिति में पहुँच गये। 14 फरवरी 1970 को एक नया अध्यादेश जारी किया गया जिसमें पहले के अधिनियम के आपत्तिजनक उपबन्ध नहीं थे। इस अध्यादेश के अधीन सरकार ने हमें से प्रत्येक बैंक के कारोबार को मूल तिथि अर्थात् 19 जुलाई, 1969 से फिर से अपने हाथ में ले लिया। इस अध्यादेश में उन 14 लिमिटेड कंपनियों में से प्रत्येक को जिनके कारोबार को अधिकार में ले लिया गया था, दी जानेवाली क्षतिपूर्ति को निर्धारित करने के लिए कोई मिश्रित प्रस्तुत नहीं किया गया जैसा कि अवैध करार हो गये अधिनियम में किया गया था बल्कि 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से प्रत्येक के लिए क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित कर दी गई जो संबंधित बैंकिंग कंपनी से तद्विषयक आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर उसे दे दी जानी थी। इन बैंकिंग कंपनियों को इस संबंध में तीन विकल्प दिये गये अथवा इन में से किन्हीं को समन्वित रूप से भी वे स्वीकार कर सकते थे। वे विकल्प इस प्रकार हैं—नकदी, सम-मूल्य पर वार्षिक 4% प्रतिशत व्याजवाली केन्द्रीय सरकार की 10 वर्षीय प्रतिभूतियां और सममूल्य पर वार्षिक 5% प्रतिशत व्याजवाली केन्द्रीय सरकार की 30 वर्षीय प्रतिभूतियां। चौदह बैंकों में से दो बैंकों (इलाहाबाद बैंक लि० और दि इंडियन ओवरसीज बैंक लि०) ने क्षतिपूर्ति की समूची रकम की अदायगी के लिए नकदी के विकल्प को चुना और शेष बारह बैंकों ने अंशतः नकदी के रूप में तथा अंशतः सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में क्षतिपूर्ति की अदायगी की मांग की। पहले दो बैंकों को क्षतिपूर्ति की पहली किस्त अदा की जा चुकी है तथा शेष बैंकों को समूची क्षतिपूर्ति की अदायगी की जा चुकी है।

184. 14 फरवरी 1970 को जारी हुए उपर्युक्त अध्यादेश के स्थान पर बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) विधेयक 27 फरवरी 1970 को संसद में पेश किया गया और मार्च 1970 के समाप्त होने से पहले ही दोनों सदनों ने इसे बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया। 31 मार्च 1970 को इस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल गई।

185. इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिजर्व बैंक से सलाह करके इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने

* दि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, लिमिटेड,

दि बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड,

दि पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड,

दि बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड,

दि युनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड,

कनारा बैंक लिमिटेड,

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड,

देना बैंक लिमिटेड,

सिटीकेट बैंक लिमिटेड,

दि यूनिन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड,

दि इंडियन बैंक लिमिटेड,

इलाहाबाद बैंक लिमिटेड,

दि बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड, और

दि इंडियन ओवरसीज बैंक लिमिटेड

के लिए एक योजना तैयार करने का प्राधिकार प्राप्त है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सदस्य नये बैंकों के निदेशक-बोर्ड के गठन, उनकी पूंजी के स्वरूप, पुनर्निर्माण और समामेलन की भी व्यवस्था होगी। अधिनियम द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक निदेशक-बोर्ड में बैंक के कर्मचारियों तथा जमाकर्तारों के प्रतिनिधियों और किसानों, श्रमिकों और वस्तुकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करनेवाले अन्य व्यक्तियों का सम्मिलित किया जाना आवश्यक होगा। केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह उक्त योजना में निरूपित व्यापक निदेशक-बोर्ड का गठन होने तक इन 14 बैंकों में से प्रत्येक के लिए एक पहला निदेशक-बोर्ड नियुक्त करे जिसके सदस्यों की संख्या मान से अधिक न हो और वे सक्षम तथा कार्य करेंगे जब तक योजना के अधीन व्यापक निदेशक बोर्ड का गठन नहीं होता। इस अधिनियम से सरकार को रिजर्व बैंक के गवर्नर से सलाह करके ऐसे नीतिविवेक मामलों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों को ह्दयायतें जारी करने की शक्ति भी प्राप्त है जिनमें जनता का हित निहित हो।

186. प्रादेश याणिकाओं से उत्पन्न हुई अनिश्चितता की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए निदेशक-बोर्डों की नियुक्ति करना उचित नहीं समझा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सितम्बर 1969 में सभी 14 बैंकों को सलाह दी कि नियमित निदेशक-बोर्डों की नियुक्ति होने तक वे वरिष्ठ अधिकारियों की एक आंतरिक प्रबन्ध समिति का गठन करें जिसके पाम धे सभी मामले भेजे जा सकें जो सामान्यतः निदेशक-बोर्ड के पास भेजे जाते हों। बैंक ने प्रत्येक आंतरिक प्रबन्ध समिति के लिये अपना एक अधिकारी मनोनीत किया और इसकी बैठक महीने में दो-चार बार होती थी। निदेशक-बोर्ड के अभाव में अधिकारियों पर जो जिम्मेदारी आ गई थी उसे ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने 22 जनवरी 1970 को एक विधिक निदेश जारी किया जिसके अनुसार सभी 14 बैंकों को कुछ लेन-देनों के संबंध में रिजर्व बैंक का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक हो गया। इन में से कुछ महत्वपूर्ण लेनदेन इस प्रकार थे:—(1) 25 लाख रुपयों से अधिक कुछ विशेष प्रकार के अधिम प्रदान करना, (2) मिश्रित पूंजी कम्पनियों के शेयरों और डिबेंचरों में 1 लाख रुपये से अधिक निवेश करना अथवा उन पर 5 लाख रुपयों से अधिक अधिम प्रदान करना, (3) वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारियों की नियुक्ति करना और उनके सेवा-काल को बढ़ाना, (4) भूमि/भवनों पर निश्चित राशियों से अधिक व्यय करना और 1969 के लाभ में से प्रावधान करना। 14 फरवरी 1970 को अध्यादेश जारी होने और 31 मार्च 1970 को अधिनियम के पारित होने पर भी रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये उपर्युक्त विधिक निदेश बराबर लागू रहे।*

187. केन्द्रीय सरकार ने रिजर्व बैंक के परामर्श के साथ 18 जुलाई 1970 को प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के पहले निदेशक-बोर्ड का गठन किया। पहले निदेशक-बोर्ड के प्रत्येक निदेशक का कार्यकाल तब तक होगा जब तक धारा 9 के अधीन तैयार की गई योजना के अन्तर्गत व्यापक निदेशक-बोर्ड का गठन नहीं हो जाता। सरकार रिजर्व बैंक के परामर्श के साथ व्यापक निदेशक-बोर्ड के गठन की योजना बना रही है।

188. राष्ट्रीयकृत बैंकों को यह निदेश भी दिया गया है कि वे वर्तमान बैंकों के विदेशी कारोबार को तदनुकूल नये बैंकों को अंतरित करने की यथोचित व्यवस्था करें। इन प्रकार का अंतरण अधिकांश मामलों में किया जा चुका है किन्तु उगांडा में स्थित दो ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंकों अर्थात् बैंक ऑफ वंडीवा और बैंक ऑफ इंडिया ने

जिनका उल्लेख अध्याय 1 में किया गया है स्थानीय कानूनी व्यवस्था का पालन करने हुए महायक कंपनियां गठित कर ली हैं। उगांडा की सरकार ने इन महायक कंपनियों के अधिकांश शेयर खरीद लिये हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों की मनेषिया में स्थित शाखाओं के संबंध में जहां सरकारी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित बैंकों को बैंक कारोबार चलाने की अनुमति नहीं है, सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बराबर ध्यान दे रहे हैं।

189. जैसा कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रमुख में कहा गया है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य मोटे तौर पर इस प्रकार है—“अर्थ व्यवस्था के उतार-चढ़ाव पर नियंत्रण रखना और राष्ट्रीय नीतियों तथा लक्ष्यों के अनुकूल अर्थ-व्यवस्था के विकास की आवश्यकताओं की अधिक अच्छे ढंग से पूर्ति करना”। राष्ट्रीयकृत बैंक उधारकर्ता के स्वरूप और समाजिक स्थिति पर विचार किये बिना उत्पादन संबंधी विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों, विशेषकर किसानों, लघु उद्योगों और स्वनियोजित व्यावसायिक वर्गों की आवश्यकताओं की अधिक मात्रा में पूर्ति करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। नये और प्रगतिशील उद्यमकर्तारों की अभिवृद्धि को सक्रिय प्रोत्साहन देना और देश के विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों के लिए नये अवसर पैदा करना भी राष्ट्रीयकृत बैंकों का एक प्रमुख लक्ष्य होगा।

190. इन लक्ष्यों के संदर्भ में बैंकों के दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली में अनेक परिवर्तन करने की आवश्यकता थी। विशेष रूप से उनके लिए आवश्यक हो गया कि वे ऋणों की जमानत संबंधी अपनी धारणाओं को पुनर्निर्धारित करें; उन क्षेत्रों की स्थानीय विकास क्षमता और विकास आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दें जहां उनकी शाखाएं स्थित हैं; कम विकसित क्षेत्रों और पिछड़े वर्गों की आवश्यकताओं की ओर अधिक ध्यान दें; विकासात्मक एवं सीमांसी वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाओं के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करें; यह सुनिश्चित करें कि बैंक की निधियों में से बड़े उधारकर्तारों को उत्पादक उपयोग के लिए वास्तव में आवश्यक राशि से अधिक राशि उपलब्ध न हो; और सट्टे बाजी तथा दूसरे अनुत्पादक प्रयोजनों के लिए ऋणों का उपयोग किये जाने पर रोक लगाएं। इसके साथ-साथ उनसे यह अपेक्षा भी की गई कि वे एक समन्वित शाखा-विस्तार कार्यक्रम के जरिए देश के हर भाग से और घनाक्षय व्यापारियों से लेकर उन्नीछि गृहिणियों तक के समाज के सभी वर्गों से जमा-राशि जुटाने के अपने प्रयत्नों को गहन बनाएं।

191. जब तक उपर्युक्त मामला न्यायालय के विचाराधीन रहा तब तक सरकार ने 14 बैंकों को न तो कोई हिरापरें दीं और न कोई ऐसा कदम उठाया जिसे बैंकों के आंतरिक प्रबन्ध में हस्तक्षेप माना जा सकता हो। प्रधान मंत्री ने 30 सितम्बर, 1969 को स्टेट बैंक के अध्यक्ष और 14 अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में उन्हें सरकार का सामान्य दृष्टिकोण समझाया। इसके प्रतिबिम्बित बार-बार किये गये अनीपचारिक विचार-विमर्शों के जरिए सरकारी अधिकारियों के बीच अनेक विषयों पर समझौता लाया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी समय-समय पर अपनी सलाह और सेवाएं प्रदान कीं। ऐसे सभी अनीपचारिक उपाय अमफल नहीं हुए हैं। राष्ट्रीयकरण के स्वीकृत लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों ने जनता के साथ अपने संपर्क को बढ़ाने और अधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार के विकास कार्य के अपने प्रयासों को बराबर जारी रखा।

192. उन्होंने संगठनात्मक परिवर्तन करके लघु उद्योगों तथा कृषि अधिम संबंधी प्रस्तावों पर कार्यवाई करने के लिए अलग-अलग विभाग या अनुभाग खोले। इन कार्य को चलाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी

*ये निदेश 14 अगस्त, 1970 को जारी लें लिये गये।

वर्ग की नियुक्ति की गई है तथा परामर्श के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की गई हैं। क्षेत्रीय अधिकारी भी भरती किये गये हैं जिनका प्रमुख कार्य संभाव्य ग्राहकों की खोज करना, उनसे संपर्क स्थापित करने उनकी आवश्यकताओं का आंकना, नियमित रूप से प्रस्ताव तैयार करना और उन्हें अनुभागों के सामने पेश करना और आवश्यक होने पर उन्हें प्रधान कार्यालयों में भिजवाने का प्रबन्ध करना होगा। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो अधिम दिये गये हैं उनका समुचित उपयोग होता है तथा ऋणों के प्रतिवेध होते ही उनकी श्रमूलो करवाने की व्यवस्था भी वे करेंगे। बैंकों से प्राप्त होनेवाली विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का क्षेत्रीय भाषाओं के समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के जरिए प्रचार करने के लिए भी व्यवस्थाएं की गयी हैं। शाखाओं के मैनेजर्स को उच्चतर अधिकारियों से पूछे बिना ही यथासंभव अधिकारिक प्रस्तावों पर संजूरीयां देने की शक्ति प्रदान कर दी गयी है।

193. सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यवाहकों ने अपनी क्रिया-विधि में सुधार करने और अपने ही बीच तथा जनता और राज्य सरकारों के साथ पहले से अच्छा मतबन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से एक समन्वय समिति का गठन किया है जिसमें ऐसे मामलों पर विस्तारपूर्वक विचार किया जाता है जिनमें उनकी परस्पर विवक्षणी हो और जो जनता के हित में हों।

194. छोटे उधारकर्ताओं के विभिन्न वर्गों को ऋण देने में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा उठाये जानेवाले जोखिम से उन्हें बचाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के उद्देश्य से सरकार ने एक समिति का गठन किया है जो ऐसे ऋणों के बीम के लिए समुचित योजना तैयार करेगी। समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है और सरकार ने एक नये ऋण गारंटी की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

195. सरकारी खजाने के कारोबार तथा उससे संबंधित अन्य कारोबार को जो इस समय उन स्थानों पर, जहां रिजर्व बैंक के कार्यालय नहीं हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके सहायक बैंकों द्वारा किया जाता है, क्रमिक रूप से राष्ट्रीयकृत बैंकों के सुपुर्व करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया गया जो इस संबंध में योजना तैयार करेगी। सरकारी खजाने के कारोबार तथा उससे संबंधित अन्य कारोबार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के सुपुर्व किये जाने की योजना को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है।

196. रिजर्व बैंक ने इस बातों पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया कि क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सभी विदेशी शाखाओं को अपने अधिकार में लेकर उनका कारोबार संभालने के लिए एक संस्था की स्थापना करना वांछनीय होगा तथा क्या ऐसी संस्था को भारतीय बैंकों के समूचे विदेशी मुद्रा संबंधी कारोबार को सौंप दिया जा सकता है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उस पर विचार किया जा रहा है।

197. असम पुनर्गठन (मेमोराल) अधिनियम, 1969 की धारा 75 के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 में संशोधन करके इसकी धारा 21क को मेमोराल के स्वायत्त राज्य के लिए भी लागू कर दिया गया।

अग्रणी बैंक योजना और शाखा-विस्तार

198. रिजर्व बैंक द्वारा दिसम्बर 1969 में बजाई गई अग्रणी बैंक योजना देश-भर में बड़े पैमाने पर जमाराशि जुटाने और अर्थ व्यवस्था के कमजोर क्षेत्रों का विवेक जानेवाले ऋण में वृद्धि

करने के दुहरे उद्देश्य को पूर्ति को दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह स्मरण होगा कि अर्थ व्यवस्था में विद्यमान ऋण संबंधी अन्तर की समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयुक्त संगठन की जरूरतें बनाने के प्रयत्न पर विचार करने की दृष्टि से अक्टूबर 1968 में राष्ट्रीय ऋण परिषद् के अनुमोदन के साथ प्रोफेसर डी० आर० गाडगील की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल का गठन किया गया था। अक्टूबर 1969 में प्रकाशित उक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट में जो नयी महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक यह थी कि स्थानीय समस्याओं का पता लगाने और उनका अध्ययन करके उस क्षेत्र के लिए एक समन्वित ऋण योजना तैयार करने के लिए धाणिश्रम बैंकों को क्षेत्रीय दृष्टिकोण प्रदान करने की आवश्यकता है। इस दल का यह विचार था कि कृषि जिला देग की प्रमुख प्रशासनिक इकाई है अतएव यह नितांत आवश्यक हो जाता है कि क्षेत्रीय दृष्टिकोण के अन्तर्गत जिले को ही सब से निचली इकाई बनाया जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने भी इस बात का सुनिश्चित करने के लिए कि देश के कम बैंक सुविधावाले जिलों में उपरि बैंक सुविधाओं की व्यवस्था हो, एक समन्वित कार्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से अगस्त 1969 में श्री एफ० के० एफ० सरोजन को अध्यक्षता में बैंकों की एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ साथ इस बात की सिफारिश की थी कि बैंकों के लिए जिले निविष्ट कर दिए जाएं जहां वे अपनी शाखाओं को बढ़ाने और ऋण सुविधाओं का विस्तार करने के संदर्भ में बैंक व्यवसाय के विकास की क्षेत्रीय प्रामता का सर्वेक्षण करने में अग्रणी रहेंगे। रिजर्व बैंक ने इन मिशनों को स्वीकार करके अग्रणी बैंक योजना बनाई जिसके अधीन स्टेट बैंक (समूह और उसके सात सहायक बैंक) 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों और दो अन्य भारतीय बैंकों के लिए जिले नियत कर दिये गये। वस्तुतः बृहत् बम्बई, कलकत्ता और मद्रास तथा दिल्ली जंशेगढ़ और गोवा के संवर्णित क्षेत्रों को छोड़कर शेष सारे देश को इस योजना के प्रवर्तित लाया जा चुका है। अग्रणी बैंक की यह जिम्मेवारी होगी कि वह अपने लिए नियत किये गये जिलों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करने, शाखा बैंकिंग का विकास तथा ऋण सुविधाओं का विस्तार करने के संबंध में अग्रणी के रूप में अपना योगदान प्रदान करे। किसी जिले के अग्रणी बैंक से विशेष रूप से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह (1) अपने जिले के संसंधनों और बैंकिंग विकास की संभाव्यता के संबंध में सर्वेक्षण-कार्य करे, (2) ऐसी औद्योगिक तथा धाणिज्यिक इकाइयों और दूसरे ऐसे संस्थानों तथा फार्मों की संख्या का सर्वेक्षण करे जिन्होंने बैंकों में खाते नहीं खोले हैं अथवा जो अनित्यायतः सहकारों पर निर्भर रहे हैं, (3) जिले में कृषि एवं औद्योगिक उत्पादनों के विपणन, और मोदार्नों तथा भंडार घरों की उपलब्धि की सुविधाओं तथा ऋण से विपणन के सहयोगन की व्यवस्था की जांच करे, (4) उर्वरकों तथा कृषि के काम आनेवाले अन्य वस्तुओं के संग्रहण और उतारणों की मरम्मत तथा सेवाई से संबद्ध सुविधाओं का सर्वेक्षण करे, (5) छोटे उधारकर्ताओं और किसानों का परामर्श देने और ऋणों के अधिकतम उपयोग के अनुपरीक्षण और निरीक्षण के लिए कर्मचारियों की भरती करे और उन्हें प्रशिक्षण दे, (6) ऋण देनेवाले अन्य प्राथमिक एजेंसियों को सहायता करे, तथा (7) शेष मामलों में सरकारी और अर्थ सरकारी एजेंसियों से संपर्क और मेलजोल बनाये रखे। यद्यपि अन्य बैंकों को शाखाएं खोलने से रोका नहीं जाता तथापि अग्रणी बैंक से यह आशा की जाती है कि वह सहयोगी समूह के नेता के रूप में कार्य करे और जिले में जमाराशि जुटाने तथा वहां की वास्तविक एवं संभाव्य ऋण आवश्यकताओं का पता लगाने और उनकी पूर्ति करने में उस जिले में काम करनेवाले दूसरे बैंकों का सहयोग प्राप्त करे। जिलों की नियत करने में बैंक ने निम्नलिखित अनेक महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखा है; जिले आयपग हों ताकि कामकाज लाभप्रद मिड हो सकें, विकास कार्य और

शाखा पर्यवेक्षण के लिए नियंत्रण स्थलों की व्यवस्था हो और संबंधित जिलों की संख्या और उनके संसाधन-आधार के संबंध में संबंधित बैंकों को सौंपी गई जिम्मे-वारी के बीच व्यापक अनुरूपता लायी जाए। रिज़र्व बैंक ने संबंधित बैंकों द्वारा किये जानेवाले सर्वेक्षण के लिए एक विशद प्रारूप तैयार किया है और आवश्यक आंकड़े इकट्ठे करने के लिए उसे उन बैंकों में भुमा दिया है। कुछ जिलों का सर्वेक्षण बैंकों द्वारा किया जा चुका है और तत्संबंधी रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को दी जा चुकी हैं।

199. रिज़र्व बैंक ने दिसम्बर 1969 में शाखा-विस्तार कम नया कार्यक्रम बनाया जिसके अन्तर्गत सरकार क्षेत्र के 22 बैंकों और गैर-सरकारी क्षेत्र के 8 बैंकों को 1970 के दौरान 1350 कार्यालय खोलने होने जिन में से 1186 कार्यालय बैंक सुविधारहित केन्द्रों में होने चाहिए। सरकारी क्षेत्र के 22 बैंकों को कुल 1350 कार्यालयों में से 1300 कार्यालय खोलने होंगे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत न केवल बैंक सुविधारहित 453 शहर (1961 की जनगणना के वर्गीकरण के अनुसार आते हैं परन्तु अन्य ऐसे बैंक सुविधारहित केन्द्र भी आते हैं जिनके बारे में रिज़र्व बैंक की यह राय हो कि वहाँ के बहुत हुए कृषि संबंधी कारो-बार की श्रमता के कारण या सरकारी खजाने का काम संभालने के लिए ऐसे स्थानों पर बैंक कार्यालय होने चाहिए। जिन स्थानों पर खजाने अथवा उप-खजाने स्थित हैं वहाँ विभागीय रूप से चलाये जानेवाले खजानों/उप-खजानों को बैंकिंग खजानों/उप-खजानों में बदलने की नीति के अनुसरण में बैंक यथासमय सरकारी नकदी के कारोबार को संभाल लेंगे।

200. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आनेवाले 30 बैंकों को ऐसे बैंक सुविधारहित शहरों/केन्द्रों, खजाना केन्द्रों आदि के नामों की एक सूची दी गई है जहाँ उन्हें कार्यालय खोलने की आवश्यकता है और प्रत्येक बैंक से यह कहा गया है कि वह उन केन्द्रों के नाम सूचित करे जहाँ वह 1970 के पूर्वार्ध में कार्यालय खोलने का विचार रखता हो। रिज़र्व बैंक ने यह लक्ष्य निर्धारित किया था कि 1970 के पूर्वार्ध (जनवरी-जून) में सम्बन्धित बैंक सुविधारहित शहरों/केन्द्रों में कम से कम 400 कार्या-लय प्रारम्भ हों। यह संख्या उन बैंक सुविधारहित केन्द्रों के प्रतिरिक्त है जो कार्यालय खोलने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा या तो स्वेच्छा से खुले गये हों या जो ग्रामीण बैंक योजना के अन्तर्गत उनके लिए नियत किये गये ऐसे जिलों में हों जहाँ वे अपने कार्यालय खोलना चाहते हों। साथ ही, इस अवधि में 200 कार्यालय ऐसे केन्द्रों में भी खोले जाने थे जहाँ प्रतिरिक्त बैंक सुविधारणों की आवश्यकता है। इस प्रकार 1970 के पूर्वार्ध में कुल मिलाकर 600 कार्यालय खोले जाने का लक्ष्य था। रिज़र्व बैंक ने ऐसे प्रत्येक बैंक को उसके लिए नियत किये गये केन्द्रों के संबंध में भारी पैमाने पर लाइसेंस जारी किये हैं। वस्तुतः, जून 1970 की समाप्ति तक 875 कार्यालय खोलकर, जिनमें से 741 कार्यालय बैंक सुविधारहित केन्द्रों में हैं बैंक निर्धारित किये गये लक्ष्य से भी आगे बढ़ गये हैं।

201. रिज़र्व ने वाणिज्य बैंकों से यह भी कहा है कि वे वर्ष 1970 के लिए महानगरों तथा पत्तन शहरों के साथ बैंक सुविधायुक्त केन्द्रों में कार्यालय खोलने का कार्यक्रम तैयार करें। बैंक ने शहरी केन्द्रों में शाखाओं का विस्तार करने के कार्यक्रम पर विचार करते समय एक और ग्रामीण और कस्बेवाले केन्द्रों तथा दूसरी और शहरी केन्द्रों में बैंकों द्वारा नये कार्यालय खोले जाने के उत्तरदायित्व का सम्यक् बंटवारा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा है। यदि बैंकों ने पहले से ही भारी पैमाने पर खोले गये लाइसेंसों के अनुसार तथा ग्रामीण बैंक योजना के अन्तर्गत अधिक संख्या में ग्रामीण तथा कस्बेवाले केन्द्रों में अपने कार्यालय खोल दिये हों तो उन्हें शहरी केन्द्रों में कार्यालय खोलने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध प्रदान किया जाना चाहिये। बैंकों से यह भी कहा गया कि वे

नई शाखाएं खोलने के लिए शहरी केन्द्र चुनते समय व्यापारिक एवं औद्योगिक गतिविधियों में हुई वृद्धि तथा उपनगरीय रिहायशी क्षेत्रों में तेजी से होने वाली प्रगति के कारण अधिक मात्रा में अमा राशि जुटाये जाने के लिए उत्पन्न होनेवाले अवसर पर ध्यान दें। बैंकों से इस सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव रिज़र्व बैंक के पास मार्च 1970 के अन्त तक भेजने के लिए कहा गया था। विभिन्न बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने और प्रत्येक बैंक के लिए नियत किये जानेवाले कार्यालयों की संख्या को अंतिम रूप से निर्धारित करने के बाद रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय किया है कि जैसे ही बैंक शहरी केन्द्रों में कार्यालय खोलने के लिए योग्य हो आते हैं, उन्हें लाइसेंस दे दिये जाए। शहरी केन्द्रों में नये कार्यालय खोलने के लिए निम्नलिखित अनुपात में लाइसेंस जारी किये जाएंगे; उन बैंकों के मामले में, जिनके लिए 60 प्रतिशत से अधिक कार्यालय 31 दिसम्बर, 1969 को ग्रामीण और कस्बेवाले केन्द्रों में थे, दिसम्बर 1969 के बाद ग्रामीण और कस्बेवाले केन्द्रों में खोले गये हर दो कार्या-लयों के पाछे शहरी केन्द्र में एक कार्यालय; अन्य बैंकों के संबंध में यह अनुपात कस्बेवाले और ग्रामीण केन्द्रों में खोले गये हर तीन कार्यालयों के पीछे शहरी केन्द्र में एक कार्यालय होगा।

202. वाणिज्य बैंकों ने 1969-70 में कुल 1873 नये कार्यालय खोले जबकि 1968-69 तथा 1967-68 में क्रमशः 1,024 और 425 नये कार्यालय खोले गये थे। इनमें से 425 कार्यालय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके सहायक बैंकों ने खोले और 14 राष्ट्रीयकृत भारतीय बैंकों ने 1185 कार्यालय खोले। इस वर्ष खोले गये 1873 कार्यालयों में से 1271 कार्यालय बैंक सुविधारहित केन्द्रों में खोले गये जिनमें स्टेट बैंक ऑफ और उसके सहायक बैंकों का अंश 312 है और 14 राष्ट्रीय-कृत बैंकों का अंश 821 है।

203. समासेलन, विलयन, आस्थितियों और देयताओं के अन्तरण, कार्यालयों के सम-पक्ष, आदि से कार्यालयों की संख्या में हुए परिवर्तन के कारण अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों की संख्या में 1893 की वृद्धि हुई। फिर भी इस अवधि में गैर-अनुसूचित बैंकों के कार्यालयों की संख्या में 24 की कमी हुई है। जून 1970 के अन्त में अनुसूचित और गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों की कुल संख्या 10,000 को पार कर गई जिसमें अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंकों के कार्यालयों की संख्या क्रमशः 9938 और 193 थी। जून 1969 के अन्त में तदनुसूची संख्याएं क्रमशः 8045 और 217 थीं (सारणी 31)।

सारणी 30 :—भारत में वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों की संख्या

	30 जून 1969 को	30 जून 1970 को
1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1569	1875
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहायक बैंक	893	1080
3. 14 राष्ट्रीयकृत बैंक	4133	5318
4. विदेशी बैंक	130	131
5. ग्रन्थ अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1320	1554
6. गैर अनुसूचित बैंक	217	193
मभी वाणिज्य बैंक	8262	10131

संगठनात्मक मामले

204. प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के लिए निवेशकबोर्ड का गठन किये जाने का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। बैंक विनियमन अधिनियम,

1949 की धारा 10 के जो 1 फरवरी 1969 को लागू हुई, निदेशक-बोर्ड के स्वरूप से संबन्ध रखती है। गैर-सरकारी क्षेत्र के उन नौ भारतीय बैंकों में से जिनकी जमाराशियां इस करोड़ रुपये और इससे अधिक थीं, 8 बैंकों ने विधिक उपबन्धों का पालन किया तथा एक बैंक के निदेशक-बोर्ड का गठन विधिसंगत नहीं है। संबन्धित बैंक द्वारा आवश्यक उपबन्धों के पालन की व्यवस्था की जा रही है।

205. दस करोड़ रुपये से कम जमाराशियों वाले बैंकों के संदर्भ में भारत सरकार ने उन्हें संबद्ध उपबन्धों का पालन करने के लिए पहले 1 फरवरी 1970 तक का समय दिया था जिसे अब 1 अगस्त, 1970 तक बढ़ा दिया गया है। इस समय इस श्रेणी में 39 बैंक आते हैं जिनमें से 20 बैंकों ने अपने निदेशक-बोर्डों का पुनर्गठन कर लिया है और बाकी 17 बैंकों से इस मामले में बातचीत की जा रही है। इस श्रेणी के अन्य दो बैंकों में से एक बैंक अपनी आस्थियों तथा वेयताओं को किसी अन्य बैंक में अन्तर्लित कर देने की व्यवस्था कर रहा है तथा दूसरा बैंक इस समय स्वयं-परिसमापन की प्रक्रिया में है।

206. गैर-सरकारी क्षेत्र के 29 भारतीय बैंकों ने बैंक विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10 के अनुसार रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से पूर्णकालीन अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। रिज़र्व बैंक ने 6 अन्य बैंकों के मामले में पूर्णकालीन अध्यक्षों की नियुक्ति के प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है तथा 5 अन्य बैंकों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। जिन शेष 8 बैंकों ने अभी तक इस धारा के उपबन्धों का पालन नहीं किया है उन्हें इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने उन बैंकों के लिए जिनकी जमाराशियां 1 फरवरी 1969 को 25 करोड़ रुपये से कम थीं, इस समय सीमा को 1 अगस्त, 1970 तक बढ़ा दिया है।

बैंकों का निरीक्षण

207. बैंकों की वित्तीय स्थिति तथा उनकी कार्यविधि का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से सभी बैंकों का प्राथमिक निरीक्षण करने की रिज़र्व बैंक की नीति के अनुसरण में बैंक विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अधीन जुलाई 1969 से जून 1970 तक की अवधि में 29 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों तथा 7 गैर-अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण किया गया। तीन बैंकों के सम्बन्ध में इस बात का पता लगाने के लिए अधिनियम की धारा 45 के अधीन निरीक्षण किया गया कि क्या उनकी समापन कार्रवाइयों में कोई वास्तविक अनियमितताएं बरती गई हैं। इनके अतिरिक्त, बैंक विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44 (1) के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन से दो बैंकों का निरीक्षण किया गया था।

208. जोड़ते जाण्ड्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण उनकी बढ़ी हुई जिम्मेदारी के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक समझा गया कि बैंकों के निरीक्षण की वर्तमान प्रणाली को नया रूप दिया जाए। मार्च 1970 में बम्बई में हुए बैंक परिचालन और विकास विभाग के अध्यक्षों के सम्मेलन में बैंकों के निरीक्षण के उद्देश्यों और तन्त्र पर विचार किया गया। इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि बैंकों के निरीक्षण का उद्देश्य उनके प्रत्येक लेन-देन की सवीक्षा मात्र करने के बजाय श्रमशक्ति के नियोजन तथा प्रशिक्षण, निवेश एवं ऋण संबन्धी कार्यक्रमों के प्रबन्ध, लाभ नियोजन, साख-मूल्यन, औद्योगिक संबन्ध, नियंत्रण एवं सूचना प्रणाली

और विकास कार्य जैसी विभिन्न विधाओं में प्रत्येक बैंक द्वारा किये गये कार्यों का समग्र मूल्यांकन होना चाहिये। बैंकों की अलग-अलग श्रेणियों धर्मात्, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समूह, राष्ट्रीयकृत बैंकों, गैर-सरकारी क्षेत्र के भारतीय बैंकों और विदेशी बैंकों पर एक जैसे मानक लागू नहीं किये जाने चाहिये। किसी बैंक की आन्तरिक नियंत्रण व्यवस्था में मजबूती लाना भी इन निरीक्षणों का ध्येय होना चाहिये जिससे कि निरीक्षण की वर्तमान प्रक्रिया में विद्यमान लेखा-परीक्षण तत्व को यथासमय उन्हें अन्तर्लित किया जा सके। इस बात पर भी सामान्यतः सहमति व्यक्त की गई कि निरीक्षण की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर एक ऐसी प्रणाली लागू की जाए जिसमें उनकी कार्य-पद्धति एवं प्रगति के परीक्षण और उनकी वित्तीय स्थिति के मूल्यांकन के साथ साथ उनके त्वरित निरीक्षण तथा शाखाओं के निरीक्षण के लिए भी व्यवस्था की गई हो। निरीक्षण की नई प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि विभाग के अधिकारियों को आवश्यक होने पर भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता/प्रहसबाबाद, राष्ट्रीय बैंक-प्रबन्ध संस्थान, बम्बई और वाणिज्य बैंकों के प्रशिक्षण संस्थानों के साथ-साथ अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देकर सक्षम बनाया जाए। बदलती हुई परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में निरीक्षण की वर्तमान नियम-मुक्तिका में परिशोधन करने की आवश्यकता भी समझी गई। यह काम बैंक परिचालन और विकास विभाग में खोले गये एक विशेष अनुभाग को सौंपा गया है। इस अनुभाग को जल्दी से निरीक्षण की कार्यवाही को पूरा करने के लिए यथोचित उपाय निकालने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अन्य राज्यों में (जहाँ इस समय विभाग का कोई कार्यालय नहीं है) विभाग के कार्यालय खोलने का निश्चय भी किया गया है ताकि स्थानीय क्षेत्रों से चनिष्ठ संपर्क स्थापित किया जा सके, उनकी आवश्यकताओं के बारे में अधिक अच्छी जानकारी प्राप्त करके उनका मूल्यांकन किया जा सके और साथ ही, पर्याप्त विवेकशीलकरण के द्वारा मामलों को शीघ्रता से निपटाया जा सके। रिज़र्व बैंक के निदेशों पर कार्य करने वाले और उसके औपचारिक प्रेषण के अधीन रहने वाले बैंकों में बैंक विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 के अधीन अतिरिक्त निदेशकों के रूप में नियुक्त किये गये रिज़र्व बैंक के अधिकारियों को ये हिदायतें दी गई हैं कि वे इन बैंकों को दिये गये निदेशों को कार्यान्वित करने में हुई प्रगति पर निगरानी रखने के अलावा इन बैंकों द्वारा विकास-कार्यों के क्षेत्र में की गई प्रगति पर भी विशेष निगरानी रखें। उपर्युक्त निर्णयों के अनुसरण में केन्द्रीय बैंक परिचालन एवं विकास विभाग में खोले गये विशेष अनुभाग ने वाणिज्य बैंकों की शाखाओं का केन्द्रवार निरीक्षण करने के लिए आवश्यक हिदायतें जारी कर दी हैं और क्षेत्रीय कार्यालयों से कुछ चुने हुए केन्द्रों में प्रयोगात्मक रूप से ऐसे निरीक्षण करने के लिए कह दिया है।

209. आलोच्य अवधि में पिछले साल के 9 बैंकों को मिलाकर 39 बैंकों से टिप्पणियां/अभिलेखन/मख प्राप्त हुए। इन टिप्पणियों/अभिलेखनों/मतों/की जांच करने के बाद 11 मामलों में निदेश जारी किये गये और 7 मामलों में प्राथमिक प्रगति-रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया। सात मामलों में त्रिशिष्ट कदम उठाने की सलाह दी गई। पांच बैंकों के मामलों में कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं समझी गई। बाकी 9 मामले विचाराधीन थे। कुछ मामलों में बैंकों के प्रतिनिधियों को संबन्धित संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पाये गये प्रमुख दोषों की ओर उनका विशेष ध्यान आकषिप्त करने तथा उन्हें संबन्धित बैंक की कार्यप्रणाली में पाये गये मुख्य दोषों का शीघ्रता से निराकरण करने की आवश्यकता को समझने की दृष्टि से औपचारिक विचार विमर्श के लिए बुलाया गया। जिन मामलों में निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर संबन्धित बैंकों के कार्यकलाप पर कठोरतर नियंत्रण की आवश्यकता अनुभव की गई, उन

सारणी 31—भारत में अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंकों के कार्यालयों की संख्या में हुई घट-बढ़

	अनुसूचित वाणिज्य बैंक						
	1967		1968		1969		1970*
	जनवरी- जून	जुलाई- दिसम्बर	जनवरी- जून	जुलाई- दिसम्बर	जनवरी- जून	जुलाई- दिसम्बर	जनवरी- जून
	1	2	3	4	5	6	7
1. कितने नये कार्यालय खोले गये	207 (36)	196 (47)	222 (37)	443 (50)	565 (24)	772 (65)	1068 (190)
2. मनामेला, विलयन, आस्तिगों और देयताओं के अन्तरण और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में जोड़े जाने और उससे निकाले जाने के कारण हुए परिवर्तन	+4	+6	+10	+1	+1	+53	+3
3. कितने वर्तमान कार्यालय बन्द किये गये	—7 (—2)	—6 (—1)	—4 (—1)	—6	—3	—3	—
4. कार्यालयों की संख्या में घट-बढ़	+204	+196	+228	+438	+563	+822	+1071
5. अवधि के अन्त में कार्यालयों की संख्या	6620	6816	7044	7482	8045	8867	9938

गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंक

	1967		1968		1969		1970*
	जनवरी- जून	जुलाई- दिसम्बर	जनवरी- जून	जुलाई- दिसम्बर	जनवरी- जून	जुलाई- दिसम्बर	जनवरी- जून
	8	9	10	11	12	13	14
	3	—	7	5	11	21	12
1. कितने नये कार्यालय खोले गये	3	—	7	5	11	21	12
2. मनामेला, विलयन, आस्तिगों और देयताओं के अन्तरण और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में जोड़े जाने और उससे निकाले जाने के कारण हुए परिवर्तन	—6	—6	—10	—1	—1	—53	—3
3. कितने वर्तमान कार्यालय बन्द किये गये	—2	—1	—3	—	—	—1	—
4. कार्यालयों की संख्या में घट-बढ़	—5	—7	—6	+4	+10	—33	+9
5. अवधि के अन्त में कार्यालयों की संख्या	216	209	203	207	217	184	193

सभी वाणिज्य बैंक

	1967		1968		1969		1970*
	जनवरी- जून	जुलाई- दिसम्बर	जनवरी- जून	जुलाई- दिसम्बर	जनवरी- जून	जुलाई- दिसम्बर	जनवरी- जून
	15	16	17	18	19	20	21
	210	196	229	448	576	793	1080
1. कितने नये कार्यालय खोले गये	210	196	229	448	576	793	1080
2. मनामेला, विलयन, आस्तिगों और देयताओं के अन्तरण और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में जोड़े जाने और उससे निकाले जाने के कारण हुए परिवर्तन	—2	—	—	—	—	—	—
3. कितने वर्तमान कार्यालय बन्द किये गये	—9	—7	—7	—6	—3	—4	—
4. कार्यालयों की संख्या में घट-बढ़	+199	+189	+222	+442	+573	+789	+1080
5. अवधि के अन्त में कार्यालयों की संख्या	6836	7025	7247	7689	8262	9051	10131

नोट : 1. कोष्ठकों के आंकड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं।

2. इन आंकड़ों में प्रशासनिक, आन्तरिक सम्भाषी गैर बैंकिंग कार्यालय और भारत के बाहर स्थित कार्यालय शामिल नहीं हैं।

*अनुमानित।

में संबन्धित बैंकों को उचित निदेश दिये गये और उनमें उनका पायन करने के लिए कहा गया। जो बैंक पिछले निरीक्षणों के बाद दिये गये निदेशों के अधीन पहले से ही काम कर रहे हैं उनके सम्बन्ध में वर्तमान निदेशों को समुचित हेर-फेर के बाद जारी रखा गया। निरीक्षण के पूर्ण होने और उनके आधार पर अंतिम कार्रवाई किये जाने के बीच के समयान्तर को कम करने के उद्देश्य से निरीक्षण रिपोर्टों की प्रतियां भेजते समय 3 बैंकों से विशेष कदम उठाने और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टें भेजने के लिए कहा गया। इस समय 29 बैंक (20 अनुसूचित तथा 9 गैर अनुसूचित) रिजर्व बैंक द्वारा किये गये निदेशों के अधीन कार्य कर रहे हैं और आवधिक प्रगति रिपोर्टें भेज रहे हैं। इन में से 19 बैंकों के मामलों में उनके/उनकी बोर्ड मिति की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रेषकों की प्रतिनिधित्व की गई है। निदेशों के अधीन कार्य करने वाले बैंकों के अतिरिक्त हम समय 32 अन्य बैंक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टें भेजा करते हैं।

210. आलोच्य अवधि में निदेशों के अधीन कार्य करने वाले और औपचारिक प्रेषण के अधीन रहने वाले राष्ट्रीयकृत न किये गये 23 बैंकों के सम्बन्ध में बैंक अधिनियम अधिनियम, 1949 की धारा 36 कक्ष के अधीन अतिरिक्त निदेशों की नियुक्ति की गई। 18 बैंकों के मामलों में उन्हें जारी किये गये निदेशों को वापस ले लेने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त निदेशों को हटा दिया गया।

211. बैंकों के संघटन और उनकी कार्यप्रणाली में पाये गये दोषों का निराकरण करने के सम्बन्ध में उनके द्वारा की गयी प्रगति जुलाई 1969 से जून 1970 तक के वर्ष के दौरान बताया गयी। बैंक ने इस अवधि में 9 बैंकों के मामलों में उनकी कार्यप्रणाली में किये गये सुधारों को देखते हुए तथा 5 बैंकों का अन्य बैंकों से सम्मेलन हो जाने के फलस्वरूप उनके नाम जारी किये गये निदेशों को वापस ले लिया। परिणामतः रिजर्व बैंक के निदेशों के अधीन कार्य करने वाले बैंकों की संख्या 43 से घटकर 29 हो गयी। इसी प्रकार आलोच्य अवधि में रिजर्व बैंक के औपचारिक अथवा अनौपचारिक प्रेषण में रहनेवाले बैंकों की संख्या भी 42 से घटकर 27 हो गई। एक और बैंक के मामले में निदेशों को वापस ले लेने और उसके कार्यकलाप के प्रेषण की व्यवस्था को समाप्त कर देने का प्रस्ताव है। बैंकों ने आम तौर पर अपनी कार्य प्रणाली में पाये गये दोषों का निराकरण करने के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं।

बैंकों का विलयन

212. देश के बैंक संघटन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से बैंक ने कमजोर बैंकों के सम्मेलन अथवा उनकी आस्थियों तथा देयताओं के अन्तर्ण की नीति को जारी रखा। जुलाई 1969 से जून 1970 तक की अवधि में 4 प्राणिय बैंकों का इस प्रकार अन्तर्णन कर दिया गया, जून 1970 के अन्त में देश में काम करने वाले प्राणिय बैंकों की कुल संख्या 86 थी जिनमें से 72 अनुसूचित बैंक थे।

213. आलोच्य वर्ष में बैंक विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के अधीन दो बैंकों का सम्मेलन किया गया तथा दो अन्य बैंकों ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293 (1) (क) के अधीन स्वीकृत आस्थिया और देयताएं दूसरे बैंकों में अन्तर्ण कर दी। (सारणी 32)।

सारणी 32—बैंकों का विलयन, सम्मेलन तथा आस्थियों और देयताओं का अन्तर्ण

वर्ष	बैंक विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के अधीन स्वीकृत सम्मेलन	बैंक विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के अधीन अधिनियम विलयन	दूसरे विनियम*	कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 293 (1) (क) के अधीन आस्थियों और देयताओं का अन्तर्ण	जोड़
1960	2	—	—	5	7
1961	1	30	2	3	36
1962	3	1	2	5	11
1963	2	1	4	15	22
1964	7	9	1	62	79
1965	5	4	3	21	33
1966	—	—	2	5	7
1967	—	—	3	6	9
जनवरी 1968					
जून 1969	—	2	—	2	4
जुलाई 1969					
जून 1970	—	2	—	2	4
जोड़	20	49	17	126	212

*स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और/या उसके सहायक बैंकों द्वारा अधिकार में ले लिये गये बैंक।

214. आलोच्य अवधि (जुलाई 1969-जून 1970) में केन्द्रीय सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आवेदन पर बैंक विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के अधीन और 2 बैंकों* के अधिस्थगन के आदेश जारी किये। इससे नितम्बर 1960 से अब तक अधिस्थगन आदेश के अन्तर्गत रहनेवाले बैंकों की संख्या 60 हो गई है और इन बैंकों की कुल जमा राशियाँ 49.95 करोड़ रुपये हैं। अधिस्थगन आदेश के अधीन रखे गये दोनों बैंकों अर्थात् बैंक ऑफ बिहार लिमिटेड तथा नेशनल बैंक ऑफ लाहौर लिमिटेड का भ्रमण: 9 नवम्बर, 1969 तथा 23 फरवरी 1970 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सम्मेलन किया जा चुका है।

215. जिन 60 बैंकों के नाम अधिस्थगन आदेश जारी किये गये थे उनमें से 49 का अन्य बैंकों के साथ सम्मेलन कर दिया गया। इनमें से 30 बैंकों के जमाकर्ताओं के नाम सम्मेलन की संबन्धित योजनाओं के आरंभ में ही अंतरक बैंकों की बहियों में उनके नाम रहनेवाली पूरी बकाया जमा राशियों को जमा कर दिया गया। दूसरे 11 बैंकों के जमाकर्ताओं के सम्बन्ध में अगरी बैंकों की बहियों में तत्काल बमूली योग्य आस्थियों के अनुपात में राशि जमा की गयी; इसके अलावा प्रत्येक जमाकर्ता को उसके नाम जमा रहनेवाली राशि या रु० 250/—, इनमें से जो भी कम हो, की अधिमानी अदायगी की गयी। इन 11 बैंकों में से 4 बैंकों के जमाकर्ताओं को अब पूरी अदायगी की जा चुकी है।

* (1) बैंक ऑफ बिहार लिमिटेड और (2) नेशनल बैंक ऑफ लाहौर लिमिटेड।

1962 में जमा बीमा निगम की स्थापना होने के बावजूद जिन 8 बैंकों का दूसरे बैंकों के साथ विलयन किया गया था उनके जमाकर्ताओं को अंतरक बैंक की तत्काल बचली शेष्य धास्तियों की सीमा तक आनुपातिक राशि प्राप्त हुई; जिन मामलों में आनुपातिक जमा राशि रु० 1500/- अथवा जमाकर्ता के खाने की बकाया जमा राशि, इनमें से जो भी कम हो, से कम थी उनमें जमा बीमा निगम ने अपनी संबंधित योजनाओं के अन्तर्गत ऐसे अन्तर को पूरा कर दिया।

216. अधिस्थगन आदेश के अधीन रहने वाले परन्तु दूसरे बैंकों में समाहित न किये गये शेष 11 बैंकों में से दो त्रिवेणी बैंकों अर्थात् तृतीय बैंक लिमिटेड और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिनकी जमा राशियाँ भारत के शत्रु परिसंपत्ति अभिरक्षक के अधिकार में रख दी गयी थीं, के संबंध में भारत सरकार ने (जैसा कि पिछली रिपोर्ट में कहा गया था) प्रबंध की योजनाएँ तैयार की। इन योजनाओं के अनुसार जमाकर्ताओं/लेनदारों को निर्धारित दरों पर अदायगी की जा रही है। एक बैंक को स्वेच्छिक परिसमापन की अनुमति प्रदान की गई तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आवेदन किये जाने पर तीन बैंकों को अंततः बैंक विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 38 के अधीन परिसमाप्त कर देने का आदेश दे दिया गया। एक बैंक को बैंक विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44 क के अधीन एक दूसरे बैंक के साथ स्वेच्छा से समािलन करने की अनुमति दी गई तथा एक अन्य बैंक के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा उसकी व्यवस्था की योजना मंजूर की गयी और उसके विघटन के लिए आदेश जारी किया गया। दो बैंकों के मामलों में सरकार ने उनके निवेशकों द्वारा इस बात का जिम्मा लेने की गारंटी देने पर कि यदि आवश्यक हुआ तो वे अपनी निजी धास्तियों में से भुगतान कर देंगे, अधिस्थगन आदेश को समाप्त हो जाने दिया गया और एक बैंक के सिलसिले में अधिनिस्थगन आदेश की अवधि समाप्त होने पर उसे समाप्त हो जाने दिया गया और इसके साथ ही संबंधित बैंक को बैंक विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अधीन लाइसेंस दिये जाने से इंकार किया गया।

217. बैंक विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के अधीन की गयी समािलन योजना के अनुसार जमाकर्ताओं को पूरी अदायगी करने के बाद अंतरी बैंकों के पास रहनेवाली अतिरिक्त राशि को अन्तरिक बैंकों के शेयरधारियों को अदा कर देना होगा। 10 अन्तरक बैंकों के शेयरधारियों को पूरी अदायगी की जा चुकी है और दूसरे 10 अन्तरक बैंकों के शेयरधारियों को आनुपातिक अदायगी की जा रही है ?

218. दि कमर्शियल बैंक लिमिटेड कोल्हापुर ने बम्बई के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके प्रार्थना की कि व्यवस्था योजना के अधीन 1 अप्रैल, 1968 को या उसके पहले जमाकर्ताओं को पांचवें और अन्तिम किस्त की जो शेष राशि (5 प्रतिशत) अदा करनी है उसे अदा करने की अवधि को और बढ़ाया जाय। दि बैंक ऑफ कराच लि० ने दि कमर्शियल बैंक लि० के नयी निधि संबंधी कारोबार को हाथ में ले लिया है। दि कमर्शियल बैंक लि० अब पुरानी निधि संबंधी अपने कारोबार को भी दि० बैंक ऑफ कराच लि० को अन्तरित कर देने की कार्रवाई कर रहा है और तत्संबन्धी आवश्यक औपचारिकताओं का पालन किया जा रहा है। भूतपूर्व पूर्वी पंजाब के उच्च न्यायालय द्वारा मंजूर की गयी व्यवस्थागत योजना के अधीन कार्य करने वाले दि साहु-कारा बैंक लि० के सम्बन्ध में यह आशा की जाती है कि वह जल्द किये गये शेयरों की 1.10 लाख रुपयों की बिक्री राशि से 'बन्द निधि' को समाप्त कर देगा। यह बैंक नयी निधि संबंधी अपने कारोबार को न्यू बैंक ऑफ इंडिया के नाम अन्तरित करने के सम्बन्ध में उस बैंक से बातचीत

कर रहा है। हिमालय बैंक लि० के नयी निधि संबंधी कारोबार को स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ने अपने अधिकार में ले लिया है। पुरानी निधि के सभी लेनदारों को 6 प्रतिशत की दर पर यथानुपात अदायगी की गयी है; इस से मंजूर की गयी योजना के अनुसार लेनदारों को देय 14,16,033 रुपयों में से उन्हें अदा की गयी कुल राशि की मात्रा 76 प्रतिशत हो गयी है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा मंजूर की गयी व्यवस्थागत योजना के अधीन कार्य करने वाले दि बैंक ऑफ भोपाल लि० भोपाल ने योजना के उपबन्धों के अनुसार आवश्यक निधियों को युनाइटेड कमर्शियल बैंक के नाम अन्तरित कर दिया है ताकि जमाकर्ताओं को पूरी राशि की अदायगी की जा सके। उच्च न्यायालय ने योजना को विघटित करने का आदेश दिया है और बैंक ने अब स्वेच्छिक परिसमापन करने का विचार किया है।

बैंकों का लाइसेंसिकरण

219. आलोच्य वर्ष में बैंक विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अधीन चार बैंकों को लाइसेंस दिये गये। बैंकिंग कम्पनियों को पहले दिये गये लाइसेंसों में से कोई लाइसेंस रद्द नहीं किया गया परन्तु एक बैंक को लाइसेंस देने से इंकार किया गया। इस प्रकार जिन बैंकों के लाइसेंस रद्द किये गये उनकी संख्या 36 ही रह गयी और जिन बैंकों को लाइसेंस देने से इंकार किया गया उनकी संख्या बढ़कर 281 हो गयी। इस वर्ष लाइसेंसिकृत बैंकों की संख्या 54 से बढ़कर 58 हो गयी जिसमें से 56 बैंक अनुसूचित वाणिज्य बैंक थे। इन 58 बैंकों (14 राष्ट्रीयकृत बैंकों को मिलाकर) जिन्हें लाइसेंस प्रदान किया गया है और 8 अनुसूचित बैंकों (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके 7 सहायक बैंक) जिनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है के पास जून, 1970 के अन्त में सभी वाणिज्य बैंकों की कुल जमा राशियों का 98.9 प्रतिशत था।

परिसमापन कार्रवाइयाँ

220. आलोच्य वर्ष में चार गैर अनुसूचित बैंक उच्च न्यायालय द्वारा विघटित कर दिये गये। दो बैंकों ने बैंक विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44 (1) के अधीन रिजर्व बैंक से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद स्वेच्छिक परिसमापन कर दिया और दो बैंकों का परिसमापन न्यायालय द्वारा किया गया। बैंक विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44 (1) के अधीन चार गैर अनुसूचित बैंकों को प्रमाणपत्र दिये गये ताकि वे स्वेच्छिक परिसमापन कर सकें। रिजर्व बैंक ने विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 द के अधीन बैंकों के परिसमापकों द्वारा पेश की गयी 198 विवरणियों की जांच पड़ताल की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कानूनी आवश्यकताओं का पालन किया गया है या नहीं और परिसमापन की कार्रवाइयों में अनुचित विलम्ब तो नहीं हुआ है। आलोच्य अवधि में परिसमाप्त होनेवाले 8 बैंकों के सम्बन्ध में बैंक विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 द के अधीन निरीक्षण रिपोर्टों की एक-एक प्रति केन्द्रीय सरकार और सम्बन्धित उच्च न्यायालयों को भेजी गयी।

ऋण प्राधिकरण योजना

221. नवम्बर 1965 से रिजर्व बैंक की ऋण नीति के एक अंश के रूप में ऋण प्राधिकरण योजना अमल में रही है। इस योजना के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को चाहिए कि वह जमानती और/या गैर जमानती आधार पर किसी एक पार्टी को। करोड़ रुपये या उससे अधिक राशि की कोई नयी ऋण सीमा (वाणिज्य बिल सम्बन्धी बट्टों को मिलाकर परन्तु ऋण पत्रों और गारंटी सीमाओं को छोड़कर) या

कोई ऐसी सीमा जिससे ऐसी पार्टों द्वारा संपूर्ण बैंक संघटक (सहकारी क्षेत्र को मिलाकर) से प्राप्त की गयी कुल ऋण सीमा एक करोड़ रुपया या उस से अधिक हो जाए संजूर करने के पहले रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदित प्राप्त कर ले। इस वर्ष बैंक ऋण को योजनागत प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाने के प्रयत्न के एक अंश के रूप में इस योजना को एक नया रूप दिया गया है। आवेदक जिस उद्देश्य के लिए ऋण प्राप्त करना चाहता हो वही उद्देश्य अब तक प्राधिकरण का मुख्य मानक रहा है। ऋण के अन्तिम उपयोग को अधिक स्पष्ट रूप से निर्धारित करने और बैंक ऋण के उचित उपयोग और वितरण को सुनिश्चित करने के लिए ऋण के मूल्यांकन की एक ऐसी व्यापक प्रणाली बनायी जा रही है जिसमें अधिक स्टॉक संचित किये जाने, कम्पनियों को परस्पर ऋण दिये जाने, उनमें परस्पर निवेश किये जाने, दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए अल्पावधि निधियों का उपयोग किये जाने आदि पहलुओं का भी मूल्यांकन शामिल है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ऋण संबंधी प्रस्तावों का उचित मूल्यांकन करने और उनका वित्तीय निष्पत्ति करने के संबंध में आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिए बैंक कतिपय फार्म भ्रमल में लाया है।

222. इस वर्ष योजना के अधीन ऋण सीमाओं के प्राधिकरण के लिए बैंकों से 908 आवेदन प्राप्त हुए; पिछले वर्ष (1968-69) प्राप्त हुए 30 आवेदन भी विचाराधीन थे। अधिकांश आवेदनों में मांगी गयी ऋण सीमाएं कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने और रक्षा निर्यात कार्य में लगी हुई संस्थाओं और दूसरे अधिमार्ग उद्योगों के विस्तार/आधुनिकीकरण आदि की वित्तीय सहायता के संदर्भ में प्रेषित थीं। कुल मिलाकर इस वर्ष 871 आवेदनों को निबटारा गया और 41 आवेदनों के संबंध में बैंकों से मांगे गये विवरणों की प्रतीक्षा थी और 26 आवेदनों की जांच पड़ताल की जा रही थी।

ऋण-सूचना

223. रिजर्व बैंक का ऋण-सूचना विभाग बैंकों और दूसरी अधि-सूचित वित्तीय संस्थाओं से उनके द्वारा ग्राहकों को दी जानेवाली ऋण सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित करता रहा। जिन संस्थाओं ने ऐसी जानकारी मांगी उन्हें अलग-अलग ग्राहकों के सम्बन्ध में समेकित रूप में आवश्यक जानकारी दी गयी। जुलाई 1969 से जून, 1970 तक की अवधि में इस विभाग ने 30 आवेदक बैंकों को 1,938 आवेदनों के सम्बन्ध में ऋण-संबन्धी जानकारी प्रदान की।

समाशोधन-गृह-सुविधाएं

224. देश में बैंक सुविधाओं को बढ़ाने की रिजर्व बैंक की नीति के एक अंश के रूप में आसोच्य वर्ष में समाशोधन-गृह सुविधाओं को और बढ़ाया गया। इस अवधि (जून-जुलाई) में छः समाशोधन गृह स्थापित किये गये; इससे देश में कार्य करने वाले कुल समाशोधन गृहों की संख्या 105 हो गयी। इनमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहायक बैंकों द्वारा क्रमशः 9, 78 और 18 समाशोधन गृहों का प्रबन्ध किया जाता है।

जूट उद्योग संबंधी अध्ययन दल

225. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि उत्पादन और निर्यात के संदर्भ में जूट उद्योग की अल्पावधि ऋण संबंधी आवश्यकताओं की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए मार्च, 1969 में एक अध्ययन दल का गठन किया गया। उसके बाद दल से यह भी प्रार्थना की गयी कि वह जूट के पक्के वितरण आवेशों के माध्यम से जूट की वस्तुओं का व्यापार करने की प्रणाली पर प्रारोपित बोधों और उन पर बैंकों से प्राप्त की जानेवाली ऋण सुविधाओं के सम्बन्ध में प्राप्त

होनेवाली कतिपय शिकायतों की जांच करे। दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और उसकी सिफारिशें विचाराधीन हैं।

गैर बैंकिंग कंपनियों पर नियंत्रण

226. निगमित गैर बैंकिंग क्षेत्र में जमाराशि के विनियमन और नियंत्रण के सम्बन्ध में इस वर्ष कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई। फिर भी कुछ वर्षों के चिट फंडों की संख्या में थोड़ी-सी वृद्धि हुई है और अभी-अभी अनेक 'वित्तीय निगमों' की भी स्थापना हुई है जो वास्तव में सांख्यिकी के फर्म हैं और जनता से जमाराशि स्वीकार करते हैं। ये संस्थाएं अधिकांशतः मैसूर राज्य तक ही सीमित हैं परन्तु उनमें से कुछ संस्थाएं आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी कार्य करती हैं।

227. चिट-फंडों के अभिवाताओं के हितों की सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्न पर सम्बन्धित राज्य सरकारों से विचार घिमर्श किया गया। रिजर्व बैंक के अनुरोध पर तमिलनाडु सरकार ने स्थानीय चिट-फंड अधिनियम 1961 को उस राज्य के सभी जिलों के लिए लागू कर दिया है। आन्ध्र प्रदेश और मैसूर इस उद्देश्य के लिए स्थानीय अधिनियम बनाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और केरल में जहां चिट-फंड और कुरी फंड परम्परागत रूप से अधिक प्रचलित और लोकप्रिय रहे हैं राज्य की दूसरी गैर-सरकारी कम्पनियों और अलग-अलग व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए चिट-फंड और कुरी फंड चलाने के उद्देश्य से नवम्बर 1969 में एक सरकारी निगम स्थापित किया गया।

228. गैर बैंकिंग कम्पनी विभाग द्वारा जमाराशियों के सम्बन्ध में जारी किये गये विदेशों के उपबन्ध फिलहाल साक्षिदारी के फर्मों के लिए लागू नहीं हैं और साथ ही यह भी वैधानिक रूप से सम्भव नहीं है कि बैंक किसी ऐसे फर्म के नाम कोई निदेश जारी करे जिसकी अधि-दत्त पूंजी एक लाख रुपया या उससे कम है। फिर भी "वित्त निगम" सम्बन्धित जिलों में भ्रमल में रहने वाले साहूकार-अधिनियमों के नियंत्रण में आते हैं। इन अधिनियमों के उपबन्धों को उन पर लागू करने के प्रश्न पर राज्य सरकारों के परामर्श के साथ विचार किया जा रहा है।

जमा बीमा निगम

229. इस वर्ष दो बैंकों की जमा देयताएं और उनके समान ही आस्तियां दूसरे बीमाकृत बैंकों में अन्तर्गत की गयीं और दो बैंकों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समामेलन किया गया। इस कारण बीमा-कृत बैंकों की संख्या जहां जून, 1969 के अन्त में 87 थी वहां जून, 1970 के अन्त में घटकर 83 हो गयी। इस वर्ष कोई नया बैंक बीमाकृत बैंक के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया। दो समामेलित बैंकों अर्थात् नेशनल बैंक ऑफ लाहौर और बैंक ऑफ बिहार को बीमा-कृत जमाराशियों के संदर्भ में निगम की देयता उत्पन्न हुई। इनमें से एक बैंक के मामले में निगम की देयता को निर्धारित कर अदा कर दिया गया जब कि एक अन्य बैंक के मामले में बैंक के जमाकर्ताओं की सूची की जांच करने के बाद देयता निर्धारित की जाएगी। 1962 में निगम की स्थापना हो जाने के बाद जून, 1970 के अन्त तक उसके द्वारा अदा किये गये दावों की राशि 103.44 लाख रुपये है जबकि सम्बन्धित बैंकों से प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त राशि 36.11 लाख रुपये है।

230. सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ निगम ने 1 अप्रैल, 1970 से किसी रजिस्ट्रीकृत वाणिज्य बैंक के किसी एक जमाकर्ता को देय राशियों के सम्बन्ध में बीमा रक्षा की सीमा को ₹ 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया है। इस वृद्धि के परिणामस्वरूप अनुमान है कि जमा लेखों की कुल संख्या में पूर्णतः प्रतिरक्षित जमा लेखों का प्रतिशत 90.8 से बढ़कर 96.8 हो गया है और कुल निर्धारणीय जमाराशियों में

बीमाकृत जमा राशियों का प्रतिशत 50.8 प्रतिशत से बढ़कर 61.0 प्रतिशत हो गया है। बैंकों द्वारा वेय प्रीमियम की दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ अर्थात् उसकी दर बीमाकृत जमा राशि के प्रत्येक 100 रुपये पर वार्षिक 5 पैसे थी। 19 जुलाई, 1969 को 14 प्रमुख वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाने के फलस्वरूप बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का प्रजन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 में उन नये बैंकों को बीमाकृत बैंकों के रूप में जारी रखने की व्यवस्था की गयी है।

231. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लिखित जमा बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम 1968 के उपबन्ध अमल में नहीं लाये गये; क्योंकि विभिन्न राज्यों ने अब तक आवश्यक अधिनियम नहीं बनाया है जिससे कि सम्बन्धित राज्यों के सहकारी बैंकों को जमा बीमा-रक्षा के योग्य बनाया जा सके। आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तथा गोवा, दमन और दीव राज्यों ने अब आवश्यक विधान पारित कर दिये हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब दूसरी राज्य सरकारों के साथ इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार विमर्श कर रहा है।

बैंक आयोग

232. पिछली रिपोर्ट में बैंक आयोग की नियुक्ति और उसके विचारणीय विषयों का उल्लेख किया गया था। उक्त आयोग ने मार्च 1969 में अपना कार्य प्रारम्भ किया और वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों, मकौले और लघु उद्योगों के उधारकर्ताओं और वेशी तथा विदेशी व्यापार में लगे हुए व्यापारियों को विभिन्न चरणों में प्रश्नावलियाँ भेजीं। आयोग ने बैंक संघटन पर रिपोर्ट पेश करने के लिए निम्नलिखित पांच अध्ययन दल नियुक्त किये हैं। (क) बैंक संघटन के खर्च (ख) बैंक संघटन को प्रभावित करने वाला विधान (ग) वेशी बैंकर (घ) बैंक प्रणालियाँ और (ङ) गैर बैंकिंग वित्तीय विनौलियाँ। इन अध्ययन दलों में सम्बन्धित क्षेत्रों के विशेषज्ञों और व्यवसायिक बैंकरों को सम्मिलित किया गया है। बैंक संघटन को प्रभावित करने वाले विधान से सम्बन्धित कार्यकारी दल ने अपनी प्रश्नावलियों के दो सेट जारी किये हैं। जमाकर्ताओं को बैंकों से प्राप्त होने वाली सेवाओं का सर्वेक्षण कार्य राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् को सौंपा गया है और लघु उद्योगों तथा छोटे उधारकर्ताओं का सर्वेक्षण कार्य बैंक आयोग की तरफ से विश्वविद्यालयों और दूसरी शैक्षणिक संस्थाओं ने देश भर के 21 केन्द्रों में प्रारम्भ किया है। आर्थिक विकास संस्थान बैंकों की विभागीय गतिविधियों का अध्ययन कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आर्थिक विभाग के ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था प्रभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध बैंक-सुविधाओं का एक नमूना सर्वेक्षण कार्य समाप्त किया। इसी प्रकार के दो और अध्ययन कार्य दो विश्वविद्यालयों ने प्रारम्भ किये हैं। राष्ट्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान ने कर्मचारी प्रबन्ध सहित सहकारी बैंकों के परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन प्रारम्भ किया है।

233. आयोग ने अब तक तमिलनाडु, केरल, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, मेघालय, मैसूर, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश राज्यों और हिमाचल प्रदेश के संघ शासित क्षेत्र का दौरा किया है और राज्य सरकारों वाणिज्य और सहकारी बैंकों वाणिज्य मंडलों बड़े और छोटे उद्योगों के प्रतिनिधियों और बैंक संघटन से सम्बन्धित दूसरी संस्थाओं के साथ विचार विमर्श किये हैं। अपनी असम-यात्रा के दौरान आयोग ने नागालैंड की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की।

राष्ट्रीय ऋण-परिषद

234. पिछली रिपोर्ट में राष्ट्रीय ऋण परिषद् द्वारा 5 अध्ययन दलों के नियुक्त किये जाने और जमा राशि जुटाने तथा सड़क परिवहन जालकों को दी जाने वाली ऋण-सुविधाओं के सम्बन्ध में अध्ययन दलों

द्वारा की गयी सिफारिशों का उल्लेख किया गया था। सामाजिक उद्देश्यों के कार्यान्वयन की संघटनात्मक रूपरेखा का अध्ययन करने के लिए गठित अध्ययन दल (प्रो० डी० आर० गाडगील दल के अध्यक्ष हैं) ने अर्थ व्यवस्था में भौगोलिक और परिवर्तनात्मक दृष्टि से विद्यमान ऋण सम्बन्धी विषयों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अक्टूबर, 1969 में अपनी रिपोर्ट पेश की। दल ने प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं का स्थूल मूल्यांकन करते हुए उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिस सीमा तक सांस्थानिक ऋण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं उसका निर्धारण किया और अनेक मामलों के अध्ययनों के आधार पर इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि कतिपय वर्गों के उधारकर्ताओं विशेषकर छोटे उधारकर्ताओं और समाज के कमजोर वर्गों को सांस्थानिक ऋण विस्तृत हो उपलब्ध नहीं हो रहा है। विभिन्न राज्यों तथा किसी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच किये जाने वाले ऋण वितरण में विद्यमान असमानता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया और स्थानीय स्थितियों के आधार पर देश में ऋण तथा बैंक संघटन का विकास करने की विस्तृत योजनाएं बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इस उद्देश्य के लिए दल ने क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की। दल के मतानुसार क्षेत्रीय दृष्टिकोण के संघर्ष में जिला निम्नतम यूनिट होना चाहिये क्योंकि इसी यूनिट के आधार पर क्लिहाल सहकारी ऋण का विन्यास किया जाता है।

235. तैयार की जाने वाली प्रत्येक जिला योजना के निम्नलिखित तीन पहलू होंगे: (i) विशिष्ट स्थानों में शाखाएं या नये यूनिट स्थापित करना (ii) ऋण संघटन के अन्तर्गत या विभिन्न संघटनों के बीच सम्बन्ध स्थापित करना और (iii) उचित नीतियाँ और क्रियाविधियाँ बनाना।

236. पहलू (i) के सम्बन्ध में दल ने यह सिफारिश की कि राष्ट्रीयकृत या राष्ट्रीयकृत न किये गये बैंकों तथा सहकारी बैंकों को चाहिए कि वे नयी शाखाएं खोलें। इसके अलावा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में जहां स्थितियाँ अनुकूल हों नये बैंक यूनिट प्रारम्भ किये जाने चाहिए। प्राथमिक सहकारी समितियों के अलावा योजना में विपणन और संसाधन समितियों के गठन के कार्यक्रम को भी शामिल करना चाहिए और जहां प्राथमिक समितियाँ सक्षम न हों वहां इन समितियों को संक्रांति-कालीन उपाय के रूप में उत्पादन के लिए ऋण प्रदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

237. दल के अनुसार योजना के पहलू (ii) के सम्बन्ध में सामान्य तथ्य यह होना चाहिए कि जहां सरकारी संघटन के उचित यूनिट पर्याप्त रूप से मजबूत हों वहां सहकारी संघटन के भीतर सामान्य सम्बन्ध बनाये रखे जाएं। जहां ऐसी स्थिति न हो वहां अस्तित्वरहित या कमजोर सहकारी संस्थाओं से अपेक्षित कार्य वाणिज्य बैंक यूनिटों द्वारा किये जाने चाहिए। इसके अलावा जहां आवश्यक समझा जाए, जिला सहकारी बैंकों को अन्तरिम उपाय के रूप में तब तक अलग अलग व्यक्तियों के साथ कारोबार करने की अनुमति दी जानी चाहिए जब तक वाणिज्य बैंकों या सक्षम प्राथमिक समितियों की स्थापना न हो जाए। किसी जिले के लिए निर्धारित ऋण योजना में ऋण और बैंक व्यवसाय को अन्य कार्यक्रमों के साथ समन्वित कर देने के सम्बन्ध में ध्यान दिया जाना चाहिए।

238. पहलू (iii) के सम्बन्ध में दल ने इस बात पर जोर दिया कि आगे सभी ऋण संस्थाएं गोचर जमानत के बदले कार्य क्षमता पर खर दें। दल ने जिला योजनाओं की रूपरेखा बनाने और उसको कार्यान्वित करने में राष्ट्रीयकृत बैंकों के विशेष योगदान पर भी जोर दिया।

239. बड़ी मात्रा में और कमजोर क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दो पूर्व-शर्तें इस प्रकार हैं: (i) उधार देने के कार्य को बिक्री, उत्पादन और विपणन सम्बन्धी गतिविधियों के साथ समन्वित कर देना, और (ii) भविष्य निधियों, बीमा, संभाव्य बोनस या बचत जमा योजनाओं के रूप में, जिनके आधार पर प्रारम्भिक भ्रमि विया जा सकता हो, प्रत्येक व्यक्ति के किसी न किसी प्रकार की न्यूनतम वित्तीय प्राप्ति का निर्माण करने में समर्थ बनाना।

240. दल का यह विचार था कि उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए तत्काल एक तंत्र का गठन किया जाए। इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से राज्य सरकारों के प्रयत्न से जिला या क्षेत्रीय समितियां गठित की जानी चाहिए; इसके साथ ही एक अखिल भारतीय तंत्र भी गठित किया जाना चाहिए जिसे ऋण सहायता सम्बन्धी स्थायी सलाहकारी समिति का नाम दिया जा सकता हो। उसमें वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक, योजना आयोग, राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंकों और सहकारी बैंकों के वरिष्ठ प्रतिनिधि, छोटे उधारकर्ताओं तथा अन्य उधारकर्ताओं को सम्मिलित करना चाहिए। रिजर्व बैंक इस समिति का कार्यकारी तंत्र होगा और इस उद्देश्य के लिए दल ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया में ऋण योजना सम्बन्धी एक विशिष्ट विभाग के गठन किये जाने की सिफारिश की है।

241. जैसे की पहले कहा जा चुका है, रिजर्व बैंक ने विसम्बर 1969 में ग्रामीण बैंक योजना बनाने समय दल की सिफारिशों को ध्यान में रखा। जिन क्षेत्रों में केन्द्रीय सहकारी बैंक वित्तीय रूप से कमजोर हों उन क्षेत्रों की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को वाणिज्य बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान कराये जाने की दल की सिफारिश के संदर्भ में रिजर्व बैंक ने पाँच राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश के 52 जिलों में एक योजना प्रारम्भ की है। ऋण सम्बन्धी विषयों को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ने एक ऋण-योजना और बैंक-विकास अनुभाग का भी गठन किया है।

242. स्वर्गीय श्री वी० टी० दहेजिया की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल इन बातों का अध्ययन करने के उद्देश्य से गठित किया गया कि उद्योग और व्यापार क्षेत्रों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं के कहां तक बढ़ने की सम्भावना है और ऐसी प्रवृत्तियों को किस प्रकार नियंत्रित किया जाए। उक्त दल ने सितम्बर 1969 में अपनी रिपोर्ट पेश की।

243. अध्ययन दल का एक प्रमुख निष्कर्ष यह था कि अधिकांश औद्योगिक यूनिटों में गैर बालू प्राप्ति प्राप्त करने के लिए अल्पावधि बैंक ऋणों और दूसरी बालू देयताओं का उपयोग करने की प्रवृत्ति रहती है। दल के मतानुसार, पूंजीगत बाजार में 1962 से होने वाली सामान्य मंदी की प्रवृत्ति और मध्यावधि ऋणों की तुलना में अल्पावधि ऋणों के आवेदन पत्रों के मूल्यांकन के सीमित स्वरूप और मध्यावधि ऋणों के लिए नियत वापसी अदायगी की शर्तें इस प्रवृत्ति के कारण हैं। दल के मतानुसार बैंकों की ऋण देने की वर्तमान प्रणाली के कारण उद्योग क्षेत्र के कतिपय यूनिटों को अपने गैर बालू निवेशों की वित्तीय सहायता के लिए अल्पावधि ऋण पर अधिक मात्रा में निर्भर रहना पड़ता है। बैंक नकदी ऋण सीमाओं के रूप में कार्यकारी पूंजीगत भ्रमि प्रदान करते हैं जिन्हें मांग पर ही वापस ग्रहण किया जा सकता है। बैंकों द्वारा जमानत के पक्ष पर जोर दिये जाने के कारण यह प्रणाली सुविधाजनक पायी गयी। बालू प्राप्ति की जमानत पर दिये जाने के बावजूद इन अल्पावधि भ्रमियों का अनिवार्यतः अल्पावधि उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि नकदी ऋण भ्रमि अब अल्पावधिक या स्वयं परिसमाप्त होने वाले नहीं रहे।

इस प्रकार अपने कार्यकलापों को जारी रखने के लिए यूनिटों को स्थायी रूप से कार्यकारी पूंजीगत भ्रमियों के अधिकांश भाग की आवश्यकता होती है। इसलिए, उधारकर्ता-यूनिट की वित्तीय योजना बनाने समय इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि पूर्ण अस्थायी आवश्यकताओं से भिन्न कार्यकारी पूंजी के रूप में उसकी कितनी निधियां स्थायी रूप से बन्व पड़ी हैं और इसके साथ ही, मीयादी वित्त की व्यवस्था करना भी इस बात पर आवश्यक हो जाता है कि उचित ऋण-ईक्विटी अनुपात को बनाये रखा जाए। दल का यह विचार था कि यदि दीर्घकालीन प्राप्तियों को प्राप्त करने के लिए बैंक ऋण का उपयोग करने की इस प्रवृत्ति को नियंत्रण में रखने का प्रयत्न नहीं किया जाए तो अगले कुछ वर्षों में यह प्रवृत्ति और बढ़ जाएगी; अतः इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए दल ने निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की:

(क) ऋण के लिए प्राप्त आवेदनपत्रों का मूल्यांकन उधारकर्ताओं द्वारा पेश किये जाने वाले नकदी की आवाजाही के विश्लेषण और तत्सम्बन्धी पूर्वानुमानों से विदित होने वाली वर्तमान और प्रायोजनगत कुल वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

(ख) नकदी ऋण लेखों में रहने वाले बकायों को (i) उत्पादन के निर्धारित स्तर को बनाये रखने के लिए कच्ची सामग्री, निर्मित सामग्री तथा अन्य वस्तुओं का जो अनिवार्य न्यूनतम स्तर किसी उद्योग को अपने पास रखना है उसके, और (ii) लेख के घटने-बढ़ने वाले अंश के रूप में विश्लेषण-निर्धारित अल्पावधि अंश के बीच विभाजित कर देना चाहिए। लेख का उक्त दूसरा अंश सामग्री, कर, लाभांश तथा बोनस सम्बन्धी अवयवों आदि में होने वाली अल्पकालीन वृद्धि जैसे अस्थायी उद्देश्यों के लिए निधियों की आवश्यकताओं का परिचायक है। इसके सिलसिले में जिये जाने वाले उधारों को कम समय में बिक्रियों की राशि से समाप्तोचित किया जाता है। जहां कम्पनी की ऋण चुकाने की क्षमता अच्छी है और उसके अन्य अनुपात शोचनीय नहीं हैं वहां नकदी ऋण उधारों में से अनिवार्य न्यूनतम आवश्यकताओं के अंश को अलग किया जा सकता है और उसे वापसी अदायगी के निश्चित कार्यक्रम के अधीन सामान्य मीयादी ऋण के रूप में रखा जा सकता है। जहां कम्पनी की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और उसकी अनिवार्य न्यूनतम आवश्यकताओं का अंश बढ़ा है वहां उस स्थिति में निम्नलिखित संभाव्य समाधानों का प्रयास किया जा सकता है: प्रतिरिक्त ईक्विटी और अधिमान्य पूंजी जारी करना, लम्बी अवधि वाले डिबेंचर जारी करना, प्रयत्नों और उनके मिश्रों द्वारा दीर्घावधि जमा-राशियों और गैर-जमानती ऋण प्राप्त करना। जहां अनिवार्य न्यूनतम आवश्यकताओं के अंश को सामान्य मीयादी ऋण के रूप में रखा जाना है वहां ऐसे प्रस्ताव का व्यापक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऋण के अन्तिम उपयोग, न्यूनतम वित्तीय अनुपातों को बनाये रखने, वापसी अदायगी के दायित्व, श्रेयों और डिबेंचरों में किये जाने वाले निवेशों पर प्रति-बन्ध आदि से सम्बन्धित कार्यों को दस्तावेजों में जोड़ देना चाहिए। नकदी ऋण लेख के अनिवार्य न्यूनतम आवश्यकता सम्बन्धी तत्त्व को निर्धारित करने में बैंकों को कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं; अतः माल के न्यूनतम स्तरों के मानकों का उद्योगवार अध्ययन करना उपयोगी होगा। कार्यकारी पूंजी के लिए मीयादी आधार पर इस स्वरूप के ऋण देने के सुझाव देने का यह आशय नहीं है कि विस्तार-

शील औद्योगिक यूनिटों को ऋण सहायता न दी जाए या बैंकों द्वारा उद्योग को विये गये ऋण के वर्तमान स्तर को तत्काल कम कर दिया जाए। उधारकर्ता को केवल अधिक वित्तीय अनुशासन में रहना होगा और ऐसे ऋणों की वापसी प्रदायगी निश्चित भवधि में करनी होगी। इससे बैंक की निधियों का अधिक प्रभावकारी उपयोग हो सकेगा। बैंकों के नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट लेखों से सम्बन्धित इन प्रस्तावित परिवर्तनों का निगम क्षेत्र के अधिकांश यूनिटों पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। लेवल उन यूनिटों पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है जिनके वर्तमान अनुपात घटकर शून्य अनुपात या 1.5 और उससे कम अनुपात तक पहुँच गये हैं। बैंकों द्वारा विये जाने वाले प्रतिरिक्त ऋणों में होनेवाली वृद्धि पर रोक लगाने के एक सहायक उपाय के रूप में यह वांछनीय होगा कि नकदी ऋण लेखों में उपयोग न की गयी सीमाओं पर वायदा प्रभार लगाया जाए और यदि आवश्यक हो तो न्यूनतम व्याज सम्बन्धी शर्त भी जोड़ी जाए। इसके अलावा, बैंकों को चाहिए कि वे मीयादी बिल जारी कर उधार बिक्रियों को बहुत अधिक बढ़ाने का प्रयत्न करें। इससे न केवल खरीददार को वित्तीय अनुशासन में रहने की विवशता होगी, परन्तु पूर्ति करने वाले या उत्पादक को भी अपने वित्तीय बायबों को वास्तविक रूप से योजना-बद्ध करने में सहायता मिलेगी। हुंडी बाजार के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह मीयादी बिलों पर लगने वाले मुद्रांक-शुल्क में कमी करने के सम्बन्ध में विचार करे।

244. सरकारी क्षेत्र के बैंकों की समन्वय समिति ने 13 जनवरी 1970 और 20 मार्च 1970 की अपनी बैठकों में ऋण सीमाओं पर वायदा प्रभार लगाये जाने के प्रश्न पर विचार किया और इस बात से समिति की सामान्य सहमति थी कि ऋण सीमाओं पर वायदा प्रभार लगाये जाने की आवश्यकता है। 28 मार्च 1970 को रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के नाम यह निर्देश जारी किया कि वे 1 अप्रैल 1970 से 10 लाख और उससे अधिक पयों की ऋण सीमा के उपयोग न किये गये अंशों पर वार्षिक 1 प्रतिशत की दर पर वायदा प्रभार लगायें (जिसका उल्लेख अध्याय I में किया गया है)। रिजर्व बैंक की ऋण प्राधिकार क्रियाविधियों को इस प्रकार सरल और कारगर बना दिया गया है कि ऋण का अन्तिम उपयोग सही रूप से हो; इसके विवरण पहले दिये जा चुके हैं। फरवरी 1970 में इस उद्देश्य से वाणिज्य बैंकों और रिजर्व बैंक के अधिकारियों के एक अध्ययन दल का गठन किया गया कि व्यापार और उद्योग क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने के माध्यम के रूप में हुंडियों के उपयोग को व्यापक बनाने के प्रश्न पर विचार किया जाए। अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और रिजर्व बैंक उस पर विचार कर रहा है। यह भी प्रस्ताव है कि प्रत्येक प्रमुख उद्योग के लिए एक अध्ययन दल की नियुक्ति की जाए जो उद्योग के प्रतिनिधि संगठनों के परामर्श के साथ स्टॉक संबंधी मानक निर्धारित करे। इन अध्ययन दलों का गठन किया जा रहा है।

245. वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि को ऋण प्रदान किये जाने से संबंधित योजनाओं को कार्यन्वित करने के लिए क्षेत्रगत/प्रामोचनागत दृष्टिकोण अपनाने जाने के संबंध में गठित अध्ययन दल (अध्यक्ष: श्री पी० एन० डामरी) ने कृषि को वित्तीय सहायता देने के संदर्भ में एक क्षेत्रीय/जिलावार दृष्टिकोण की सिफारिश की है और उक्त दल ने यह भी कहा है कि वाणिज्य बैंकों को चाहिए कि वे ऋण के अन्तरालों का पता लगाने के लिए ऋण क्षेत्र की अन्य ऋणदाता संस्थाओं के साथ मिलकर समन्वित

रूप से योजना बनायें। दल ने पट्टेबारी और काश्तकारी के सुधार भूमि, धारण की उच्च सीमाओं, कृषि ऋण की राहत, साहकारी के विनियमन आदि से संबंधित राज्य अधिनियमों का परीक्षण करने के साथ यह कहा है कि इन अधिनियमों के कुछ उपबंध कृषि-अर्थव्यवस्था की वर्तमान आवश्यकताओं के संदर्भ में पुराने हो चुके हैं और उसने यह सिफारिश की कि इन अधिनियमों का परीक्षण करने और सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया जाये ताकि कृषि को वाणिज्य बैंक अधिक सहयोग प्रदान कर सके। वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर रिजर्व बैंक द्वारा दिसम्बर 1968 में आयोजित विचार गोष्ठी के बारे में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया जा चुका है; उक्त विचार गोष्ठी ने भी इसी प्रकार की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के अनुसार, राज्य सरकारों के अधिनियमों का परीक्षण करने के लिए रिजर्व बैंक के गवर्नर ने श्री प्रार० के० तलवार की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया; वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों, रिजर्व बैंक आफ इंडिया और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि उक्त दल के सदस्य थे।

IV सहकारी बैंक व्यवसाय की गतिविधियाँ

246. सरकारी बैंक व्यवसाय के स्वरूप को वित्तीय और प्राथमिक दृष्टि से सक्षम बनाने की अपनी नीति के अनुसार बैंक बराबर (i) सहकारी ऋण-व्यवस्था में विद्यमान कमजोर यूनिटों को पुनः प्रतिष्ठित करने और पुनः सक्षम बनाने की ओर विशेष ध्यान देता रहा, (ii) कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंकों के क्षेत्रों में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को वाणिज्य बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता विलगाकर कृषि को विये जाने वाले उत्पादन और निवेश ऋण की मात्रा को बनाये रखने की संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं करता रहा, (iii) भूमि और विकास बैंकों सहित सहकारी ऋण संस्थाओं की ऋण नीतियों और कार्यक्षमता में अधिक मात्रा में अनुशासन और सुधार लाने का प्रयत्न करता रहा, (iv) सहकारी ऋण संस्थाओं को रिजर्व बैंक द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के क्षेत्र को व्यापक बनाता रहा और (v) राज्य/केन्द्रीय/शहरी बैंकों के कर्मचारियों के लिए रिजर्व बैंक के सहकारी बैंकर प्रशिक्षण कालेज में अनेक विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करता रहा।

247. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लिखित ग्रामिण भारतीय ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति की अन्तरिम सिफारिशों के आधार पर छोटे कृषकों के विकास अधिकरण, ग्रामीण बिजली निगम और कृषि पुनर्वित्त निगम से संबंधित प्रस्तावों को चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है। ग्रामीण बिजली निगम अन्य संस्थाओं के साथ-साथ ग्रामीण बिजली सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा; उसकी स्थापना जुलाई 1969 में हुई और चार राज्यों में छोटे कृषकों के घाट विकास अधिकरणों की स्थापना से संबंधित योजनाओं को भी अनुमोदित किया गया है।

248. पुनरीक्षण समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट जुलाई 1969 में प्रस्तुत की। समिति ने इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया कि ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में रिजर्व बैंक अपनी भूमिका को बराबर जारी रखे और उसने यह सिफारिश भी की कि रिजर्व बैंक की इस क्षेत्र से संबंधित नीतियों के निर्धारण, पुनरीक्षण और गंभीरता का कार्य समुचित शक्त-युक्त एक उच्च निकाय को सौंप दिया जाना चाहिए। जब तक इस संबंध में रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम में संशोधन न किया जाये तब तक ग्रामीण और सहकारी ऋण से संबंधित स्थायी सहाकारी समिति को प्रस्तावित कृषि ऋण बोर्ड के रूप में समुचित रूप से पुनर्गठित करने की आवश्यकता थी। तदनुसार, फरवरी 1970 में उक्त समिति को रिजर्व बैंक के कृषि ऋण बोर्ड के रूप में पुनर्गठित किया गया; उक्त बोर्ड के अध्यक्ष गवर्नर, उपाध्यक्ष ग्रामीण ऋण के प्रभारी उप गवर्नर कृषि ऋण विभाग के मुख्य अधिकारी सचिव-सचिव और ग्यारह सदस्य हैं।

यह प्रस्ताव है कि समिति की अन्य बातों के साथ-साथ समय पर और पर्याप्त मात्रा में कृषि के लिए आवश्यक उत्पादन और निवेश ऋण उपलब्ध कराने के लिए रिजर्व बैंक और विकास संबंधी अन्य अधिकरणों द्वारा विभिन्न प्रगतिशील उपायों के अंगण में जाने से संबंधित दूसरी सिफारिशों को भी कृषि ऋण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ पेश किया जाए।

249. सहकारी बैंकों के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र की वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित कार्य-कारी दल की जिन सिफारिशों का उल्लेख पिछले वर्ष की रिपोर्ट में किया गया था, उनके अनुसरण में राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि (i) सहकारी संसाधन समितियों को अवशुद्ध पूँजी ऋण देने के लिए वे अपने स्वायत्त दीर्घावधि वित्तीय साधनों के 15 प्रतिशत अथवा अपने कुल जमा राशि-साधनों के 5 प्रतिशत में से जो भी अधिक हो, उसका निवेश कर सकते हैं और (ii) वे विपणन-व-संसाधन समितियों तथा संसाधन समितियों की प्रतिभूतिरहित अग्रिम देने के संबंध में समितियों की निजी निधियों से संबंधित मानदंडों को उदार बना दें। कार्यकारी दल की सिफारिश के अनुसार वर्तमान औद्योगिक सहकारी समितियों को लाभप्रवण इकाईयाँ बनाने की दृष्टि से उनका पुनर्गठन करने के निमित्त उपयुक्त क्षेत्रीय अध्ययनों का प्रारंभ कर आवश्यक उपाय भी किये गये हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग से विचार विमर्श करने के पश्चात् यह स्वीकार किया गया कि सहकारी खादी और ग्रामोद्योग समितियों को केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से कार्यकारी पूँजी दिलाने की योजना महाराष्ट्र में प्रयोगात्मक रूप से लागू की जाए।

कृषि ऋण के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएँ

250. सहकारी ऋण पद्धति की कमजोरियों के कारण, प्रमुख रूप से देश के कुछ भागों में बहुत से किसानों की विशेषकर कृषि उत्पादन में टेक्नोलॉजी के विकास के संदर्भ में ऋण के अभाव का सामना करना पड़ा। इस कारण यह अनुभव किया जाने लगा कि जब तक सहकारी ऋण पद्धति ऋण संबंधी कमियों को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम न हो जाये तब तक अस्थायी भ्रवधि के लिए ही सही, अन्य सांस्थानिक स्रोतों के माध्यम से उनकी ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति किये जाने की आवश्यकता है। इस कारण प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना चलाने के लिए वाणिज्य बैंकों की सहायता प्राप्त करने की कार्यवाही गयी।

वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को वित्तीय सहायता

251. जिन क्षेत्रों में केन्द्रीय सहकारी बैंक वित्तीय दृष्टि से कमजोर थे और उत्पादन तथा निवेश ऋण की भारी मांग की पूर्ति करने में असमर्थ थे उन क्षेत्रों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को वाणिज्य बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान कराने की एक योजना रिजर्व बैंक ने प्रस्तावित की जो पांच राज्यों अर्थात् पांड्य प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मैसूर और उत्तर प्रदेश के कतिपय जिलों में लागू की जाएगी। इस प्रस्ताव का राष्ट्रीय ऋण परिषद् के अध्ययन दल और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकारी दल ने अनुमोदन किया तथा राज्य सरकारों और संबंधित सहकारी बैंकों ने इस योजना को कार्यान्वित करने की सहमति दी। इस योजना के अन्तर्गत चूने हुए जिलों के वाणिज्य बैंकों की शाखाएँ शाखा कार्यालयों के 10 से 15 मील तक के क्षेत्रफल में स्थित एक संघटित क्षेत्र में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी। यद्यपि इस योजना का तात्कालिक उद्देश्य यह है कि जहाँ तक हो सके, इस क्षेत्र में विद्यमान ऋण के भारी अन्तराल को समाप्त किया जाये, तथापि इसका दीर्घकालीन उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब इस योजना में वाणिज्य बैंक सक्रिय भाग लेते हैं तब सहकारी पद्धति किसी भी दशा में कमजोर न पड़े। इसलिए राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे केन्द्रीय सहकारी बैंकों को पुनः प्रतिष्ठित करने और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को पुनः मजबूत बनाने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम बनाएं। इस कार्यक्रम को उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत के रूप में एक साथ लागू किया जाना चाहिए। जून 1970

तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समुदाय और 12 अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित 20 वाणिज्य बैंकों ने अपनी 326 शाखाओं के माध्यम से पांच राज्यों के 50 जिलों में 2,121 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को चुन लिया है। कुछ मामलों में इस योजना के अधीन बैंक खरीफ 1970 कार्यक्रम की वित्तीय सहायता करने लगे हैं। योजना के अधीन समितियों की वित्तीय सहायता करने वाले अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को रिजर्व बैंक से 4½ प्रतिशत व्याज की रियायती दर पर पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त हो सकती है।

सहकारी विकास

252. चूंकि उपर्युक्त उपाय कृषि उत्पादन के व्यापक दृष्टि में केवल संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं के रूप में थे, इसलिए दीर्घावधि लक्ष्य यही था कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों को पुनः प्रतिष्ठित करने और प्राथमिक ऋण समितियों को पुनर्गठित करने तथा पुनः मजबूत बनाने की योजनाओं को गति प्रदान करने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम बनाकर उसी समय उसे लागू कर दिया जाए। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे प्रत्येक केन्द्रीय बैंक के लिए विशेष योजनाएँ बनाएँ ताकि अन्य बातों के अलावा विशेष रूप से निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की जा सकें: (i) अग्रिम राशियों की वसूली के लिए राज्य सरकार के मार्ग-दर्शन में एक सम्मिलित अभियान चलाना, (ii) ऋणों की वसूली समय पर किये जाने के लिए प्रशासनिक और पर्यवेक्षी व्यवस्थाओं को मजबूत करना (iii) ऋण देने की नीतियों और प्रणालियों में सुधार करना (iv) जहाँ-कहाँ भी उचित हो वहाँ ऋण और जमा राशि जुटाकर और राज्य सरकार से अतिरिक्त शेयर पूँजी का अग्रदान प्राप्त कर के बैंक के साधनों को सुदृढ़ बनाना और (v) शाखा विस्तार के कार्यक्रम के द्वारा जमा राशि जुटाने के कार्य को गति देने के लिये कारवाई करना। बैंकों ने यह स्वीकार कर लिया है कि वह सहकारी क्षेत्र में अवशुद्ध विकास वाले इलाकों के केन्द्रीय सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की शीयर पूँजी में अग्रदान करने से सम्बन्धित राज्य सरकारों के ऐसे ऋण आवेदन पत्रों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा। जैसा कि रिपोर्ट में अन्यत्र बताया गया है बैंक यह भी प्रयत्न करता आ रहा है कि सहकारी बैंकों की जमा राशियों को भी बीमे की सुविधा दी जाये। इससे जमा राशि जुटाने के कार्य को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिलने की आशा है। सहकारी बैंकों को पुनः प्रतिष्ठित करने और पुनर्गठित करने के उनके अपने प्रयत्नों में सहायता पहुँचाने के लिए बैंक के कृषि ऋण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों की सेवाएँ भी उपलब्ध की गयीं।

253. जनवरी और जून, 1970 के बीच ग्रामीण ऋण के प्रभावी उप गवर्नर ने सहकारी आंदोलन और सहकारी विकास से सम्बन्धित समस्याओं के सभी पहलुओं पर आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और काश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ वार्षिक विचार-विमर्श किया। वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की वित्तीय सहायता की योजनाओं के संदर्भ में और इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कि कृषि ऋण के क्षेत्र में सहकारी बैंकों और वाणिज्य बैंकों के कार्यक्रमों में उत्तम और निकट समन्वय स्थापित हो, इस वर्ष कुछ राज्यों के संबंध में वाणिज्य बैंकों के प्रतिनिधियों को भी उप गवर्नर के विचार-विमर्शों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। इन विचार-विमर्शों में लगातार पायी जाने वाली जिन कमजोरियों का उल्लेख किया गया और उनके उपचार संबंधी जो उपाय सुझाये गये वे निम्नलिखित बातों से सम्बन्धित थे; सहकारी बैंकों द्वारा जमा राशि जुटाया जाना, बढ़ती हुई अग्रिम राशियाँ फसल ऋण प्रणाली को स्थानीय परिस्थितियों के संदर्भ में आवश्यक समझे जाने वाले संशोधनों के साथ लागू करना, प्राथमिक ऋण समितियों के स्वरूप को स्वीकार किये गये स्वरूप के अनुरूप पुनर्गठित करना, कृषि क्षेत्र की वित्तीय सहायता के क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों द्वारा अधिकाधिक भाग लेने के संदर्भ में सहकारी बैंकों और वाणिज्य बैंकों के कार्य के बीच समन्वय स्थापित करना आदि।

सहकारी ऋण : नीति, प्रणाली और परिचालन

254. मौसमी कृषि सम्बन्धी कार्यों और फसलों के विपणन की वित्तीय सहायता करने के लिए राज्य सहकारी बैंकों को अत्यावधि वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में इस वर्ष बैंक की जो मूल नीति थी वह पिछले वर्ष की नीति के समान ही रही। मौसमी कृषि सम्बन्धी कार्यों और फसलों के विपणन की वित्तीय सहायता करने के लिये बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों के लिए बैंक दर से 2 प्रतिशत कम व्याज की रियायती दर पर जो कुल ऋण सीमाएँ मंजूर कीं वे 1968-69 के 337.52 करोड़ रुपये से बढ़कर 1969-70 में 370.16 करोड़ रुपये हो गयीं। उन में से ग्राहकित कुल राशि 1968-69 के 411.15 करोड़ रुपये की तुलना में 425.09 करोड़ रुपये थी जब कि वापसी अदायगी की कुल राशि 1968-69 के 365.23 करोड़ रुपये की तुलना में 394.06 करोड़ रुपये थी। बकाया राशि 30 जून, 1969 के 183.09 करोड़ रुपये की तुलना में 30 जून, 1970 को 214.11 करोड़ रुपये थी। दो राज्य सहकारी बैंकों के लिए रूई और कपास के विपणन की वित्तीय सहायता के निमित्त मंजूर की गयी विशेष अत्यावधि ऋण सीमाएँ 1968-69 के 8.35 करोड़ रुपये की तुलना में 1969-70 में 7.75 करोड़ रुपये थीं। उनमें से ग्राहकित राशि 9.33 करोड़ रुपये, वापसी अदायगियों की राशि 8.24 करोड़ रुपये और 30 जून, 1970 को बकायों की राशि 1.99 करोड़ रुपये थी। 1968-69 की तदनुसूची राशियाँ क्रमशः 7.20 करोड़ रुपये, 7.50 करोड़ रुपये और 0.90 करोड़ रुपये थीं। मौसमी कृषि संबंधी कार्यों और फसलों के विपणन की वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने के अतिरिक्त बैंक ने दो राज्य सहकारी बैंकों को सामान्य बैंकिंग के उद्देश्यों के लिए बैंक दर पर 23.46 करोड़ रुपये की अत्यावधि वित्तीय सहायता प्रदान की जब कि 1968-69 में 23.5 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की थी। इस शीर्ष के अधीन 30 जून, 1970 को बकाया राशि 0.23 करोड़ रुपये थी। रासायनिक खादों के स्टॉक रखने और वितरण करने की वित्तीय सहायता करने के लिए बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन सरकारी गारंटी पर बैंक दर पर ऋण सीमाएँ मंजूर करता रहा। 1969 के कैलेंडर वर्ष के दौरान मंजूर की गयी सीमाओं, ग्राहकियों और वर्ष के अंत में बकायों की राशि क्रमशः 31.00 करोड़ रुपये, 40.57 करोड़ रुपये और 14.06 करोड़ रुपये थी। 1970 की तदनुसूची राशि जून, 1970 के अंत तक क्रमशः 11.00 करोड़ रुपये, 2.35 करोड़ रुपये और 2.35 करोड़ रुपये थी। कृषि के काम आने वाली वस्तुओं के वितरण के लिए आवश्यक ऋण की वित्तीय व्यवस्था करने में वाणिज्य बैंक जब अपना योग देने लगे तब विसंवर 1969 में बैंक ने सहकारी बैंकों और विपणन महासंघों को रासायनिक खादों के कारोबार की वित्तीय सहायता के लिए वाणिज्य बैंकों से संपर्क स्थापित करने की सलाह दी। बैंक ने इस कार्य के लिए केवल उन्हीं मामलों में अभिमत देना जारी रखा जहाँ वाणिज्य बैंकों से आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त करने में किसी विशिष्ट कठिनाई का सामना करना पड़ा हो। रिपोर्ट के वर्ष के दौरान बैंक ने कृषि पुनर्वित्त निगम के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4उ) के अधीन न्यासी प्रतिभूतियों पर बैंक दर पर पहली बार 2 करोड़ रुपये की अत्यावधि ऋण सीमा मंजूर की। उसमें से निगम ने 1.65 करोड़ रुपये तक की राशि का उपयोग किया और अप्रैल, 1970 में उस राशि का पूरा भुगतान कर दिया जिससे 30 जून, 1970 को कोई राशि बकाया नहीं रही।

255. मध्यावधि कृषि ऋण के क्षेत्र में बैंक द्वारा अपनायी गयी सामान्य नीति यह थी कि कुओं, पम्प सेटों जैसे स्पष्ट उद्देश्यों के लिए दिये जाने वाले ऋणों को प्रोत्साहित किया जाए और मेढबंदी, भूमि सुधार, बैलों की खरीद जैसे उद्देश्यों के लिए दिये जाने वाले ऋणों की अनावश्यक वृद्धि को विशेषकर उन संदर्भों में जहाँ ऋण के उपयोग की जाँच-पड़ताल की

संतोषजनक व्यवस्था न हो, रोका जाए। विभिन्न कृषि कार्यों के लिए मध्यावधि वित्त के मानकों के औचित्य का निर्धारण करने के संदर्भ में बैंक ने मध्यावधि निवेशवाली योजनाओं की आर्थिक और तकनीकी संभावना के संबंध में कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा किये गये उपलब्ध उपयोगी अध्ययनों का लाभ उठाया। ग्रामीण और सहकारी ऋण की स्थायी सलाहकार समिति की सिफारिशों का पालन करते हुए कृषि कार्यों के लिए बैंक से प्राप्त की गयी निधियों में से प्रधान किसे गये मध्यावधि ऋणों की जमानत के संबंध में अगस्त, 1969 में कतिपय छूटें दी गयीं। तदनुसार विजलीचालित पम्प सेटों, तेल इंजनों की खरीद और कुओं की खुदाई के लिए 1,501 रुपये और 3,500 रुपये के बीच के मध्यावधि ऋण भूमि को बंधक रखने की शर्त पर जोर दिये बिना ही दिये जा सकते थे, लेकिन इसके लिए दृष्टिबंधक, मार्जिन राशि आदि कुछ अन्य शर्तों का पालन करना आवश्यक था। बैंक ने इस वर्ष अधिनियम की धारा 46क (2) (ख) के साथ पठित धारा 17 (4क) के अधीन राज्य सहकारी बैंकों को दी गयी मध्यावधि अभिमत सुविधा को सहकारी विपणन समितियों/महासंघों के शेयर खरीदने में कृषकों की वित्तीय सहायता करने के लिए भी प्रचार किया जिससे वे कपास की धुलाई और दबाई करने वाले जैसे संसाधन यूनितों, मूंगफली के तेल की मिलों और चावल मिलों की स्थापना कर सकें या उनके शेयर प्राप्त कर सकें। चीनी के कारखानों के पूंजीगत परिचय में वृद्धि होने और परिणामतः सदस्यों के अधिक भ्रंशदान की आवश्यकता उत्पन्न होने के कारण अक्टूबर, 1969 में बैंक ने यह निश्चय किया कि सहकारी चीनी कारखानों के शेयर खरीदने के लिए ऋण की व्यक्तिगत उच्चतम सीमा को कतिपय शर्तों के अधीन रु० 1,125 से बढ़ाकर रु० 2,250 कर दिया जाए। रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर से 1½ प्रतिशत कम की रियायती दर पर इस वर्ष मंजूर किये गये मध्यावधि ऋणों की राशि पिछले वर्ष मंजूर किये गये 19.00 करोड़ रुपये की तुलना में 18.30 करोड़ रुपये थी। उनमें से ग्राहकित राशि पिछले वर्ष के 9.02 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष 11.48 करोड़ रुपये थी। बैंक दर पर कोई मध्यावधि ऋण मंजूर नहीं किया गया। 30 जून, 1970 को 20.45 करोड़ रुपये बकाया थे जिनमें बैंक दर पर मंजूर की गयी मध्यावधि सीमाएँ (0.08 करोड़ रुपये) भी शामिल हैं जब कि 30 जून, 1969 को यह राशि 17.60 करोड़ रुपये थी।

256. उद्योगों के 22 मुख्य वर्गों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(2) (खख) के अधीन उनके अपने उत्पादन और विपणन संबंधी कार्यकलापों की वित्तीय व्यवस्था के लिए बैंक दर पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने के निमित्त 'अनुमोदित' कुटीर और लघु उद्योगों की सूची में सम्मिलित किये जाने पर किसी जिला औद्योगिक सहकारी बैंक या प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक के लिए इस उद्देश्य के निमित्त मंजूर की जा सकने वाली ऋण सीमा की अधिकतम राशि को उसकी निजी पूंजी के चार गुने तक बढ़ा दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(2) (खख) अथवा (4) (ग) के अधीन प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को अलग-अलग फर्मों और मिश्रित पूंजी कम्पनियों आदि के स्वामित्ववाले अनुमोदित कुटीर और लघु उद्योगों के उत्पादन और विपणन संबंधी कार्यकलापों की वित्तीय व्यवस्था के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित शर्तों की रिपोर्ट के वर्ष के दौरान अंतिम रूप दे दिया गया और उनके संबंध में परिपक्व जारी किये गये।

257. 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(2) (खख) अथवा 4(ग) के अधीन हथकरघा बुनकरों की सहकारी समितियों (सूती, रेशमी और ऊनी) तथा पावरलूम समितियों के उत्पादन और विपणन संबंधी कार्यकलापों की वित्तीय सहायता करने के निमित्त बैंक दर से 1½ प्रतिशत कम की दर पर ग्यारह राज्य सहकारी बैंकों के लिए 8.18 करोड़ रुपये की ऋण

सीमाएँ मंजूर की गयीं जबकि पिछले वर्ष 9 राज्य सहकारी बैंकों के लिए 7.37 करोड़ रुपये की ऋण सीमाएँ मंजूर की गयी थीं। उनमें से आहूति राशि पिछले वर्ष के 8.12 करोड़ रुपये की तुलना में 9.49 करोड़ रुपये थी और वित्तीय वर्ष 1969-70 के अन्त में बकाया राशि 6.42 करोड़ रुपये थी जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त में यह राशि 5.63 करोड़ रुपये थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(2) (क) अथवा (4) (ग) के अधीन शिखर हथकरघा बुनकर समितियों के वाणिज्य और व्यापार संबंधी लेन-देनों की वित्तीय सहायता के निमित्त चार राज्य सहकारी बैंकों के लिए 0.69 करोड़ रुपये की ऋण सीमाएँ मंजूर की गयीं जबकि पिछले वर्ष 1.02 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गयी थी। उनमें से आहूति राशि 0.11 करोड़ रुपये थी और वित्तीय वर्ष के अन्त में 0.06 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। बैंक को 22 अनुमोदित वर्गों के अधीन आने वाले औद्योगिक यूनिटों की वित्तीय सहायता करने के निमित्त राज्य सहकारी बैंकों के लिए ऋण सीमाएँ मंजूर करने का कोई अवसर अब तक नहीं मिला।

258. 1 फरवरी 1970 से परिणोदित ऋण गारन्टी योजना के लागू हो जाने पर बैंक ने राज्य और केन्द्रीय और सहकारी बैंकों को परिणोदित योजना के अधीन उपलब्ध गारन्टी सुविधाओं का लाभ उठाने की सलाह दी।

259. देश के कुछ भागों में दैवी प्रकोप से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण बैंक ने 5 राज्य सहकारी बैंकों के लिए बैंक दर से 1½ प्रतिशत कम की दर पर 11.40 करोड़ रुपये तक की मध्यावधि ऋण सीमाएँ मंजूर कीं। ये ऋण सीमाएँ अधिनियम की धारा 46ख(2) के साथ पठित धारा 17 (4क) के अधीन अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि में मंजूर की गयीं। 4 बैंकों द्वारा उनमें से ली गयी राशि 3.01 करोड़ रुपये थी और 30 जून 1970 को 4.35 करोड़ रुपये बकाया थे जब कि 30 जून 1969 को यह राशि 5.18 करोड़ रुपये थी। इसके अतिरिक्त 2 राज्य सहकारी बैंकों के लिए धारा 17(4) (क) के अधीन उनके कृषि ऋण स्थिरीकरण निधियों के निवेशों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकारी और न्यासी प्रतिभूतियों पर बैंक दर पर 1.88 करोड़ रुपये की ऋण सीमाएँ मंजूर की गयीं जिनसे वे केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वेध अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित कर सकें। राज्य सहकारी बैंकों की स्थिरीकरण निधियों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को 75 प्रतिशत अनुदान और 25 प्रतिशत ऋण के रूप में सहायता दिये जाने के जिस तरीके का पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था उसे आलोच्य वर्ष में भी जारी रखा गया। 1969-70 के वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार की सहायता के रूप में भारत सरकार ने 2.01 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जब कि 1968-69 में यह राशि 5.00 करोड़ रुपये थी। मध्यावधि ऋणों की क़िस्तों के मामले में और कुछ परिस्थितियों में दैवी प्रकोप के समय पर, परिवर्तन की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों की स्थिरीकरण निधियों का उपयोग करने की अनुमति दी गयी लेकिन हमके लिए बैंक की राष्ट्रीय निधि का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। सभी राज्य सरकारों ने कृषि ऋण (राहत और गारन्टी) निधियों की स्थापना कर ली है। 1969-74 की चौथी योजना में राज्य योजनाओं के लिए कुल 1.98 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी। 1969-70 के दौरान निधियों में किये गये अंशदान की राशि 0.10 करोड़ रुपये थी और 31 मार्च 1970 की निधियों में कुल 1.66 करोड़ रुपये की राशि जमा थी।

260. कुछ राज्य सरकारों ने सहकारी संस्थाओं की ओर से अपने द्वारा दी गयी गारन्टियों पर गारन्टी कमीशन/शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा था। कुछ अधिमों के मामले प्रस्तावित में शुल्क गारन्टी की राशि

के 1½ प्रतिशत के बराबर थे। राज्य सहकारी बैंक और राज्य भूमि विकास बैंक जैसी सहकारी ऋण संस्थाओं के लिए और उनकी ओर से राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली गारन्टियों के संबंध में गारन्टी शुल्क लगाने से उन संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले उधार अधिक मंहगे पड़ेंगे जिससे अंतिम उधारकर्ता से लिये जाने वाले व्याज की दर अधिक हो जाएगी। इसलिए बैंक ने राज्य सरकारों को सलाह दी कि वे सहकारी संस्थाओं की ओर से दी जाने वाली गारन्टियों के संबंध में किसी प्रकार का गारन्टी-शुल्क न लें। इस सलाह को ध्यान में रखते हुए 10 राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि किसी प्रकार का गारन्टी-शुल्क लगाने का उनका इरादा नहीं है।

261. राज्य सहकारी बैंकों के गारन्टी सम्बन्धी काराबार में हुई वृद्धि का वंछित हुए बैंक ने दिसंबर 1969 में इस प्रकार के काराबार के लिए कतिपय विशालनिर्देश जारी किये। किसी राज्य सहकारी बैंक द्वारा निष्पादित की जाने वाली गारन्टियों की कुल राशी के लिए एक उच्चतम सीमा का सुझाव दिया गया। ऐसी कुल राशी उस बैंक की निजी निधियों के दान से अधिक नहीं होनी चाहिए, किंतु प्रतिभूतिरहित गारन्टियों का योग उसकी निजी निधियों के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

262. 1969-70 के वित्तीय वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि में से राज्य सरकारों को दिये जाने वाले ऋणों के क्षेत्र का विस्तार कर उसके अंतर्गत प्राथमिक भूमि विकास बैंकों और निसांत सघनात्मक आधार पर प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की शेयर पूंजी में राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले योगदान का भी सम्मिलित किया गया। केवल वे ही प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक शेयर पूंजी अंशदान के योग्य थे जिन्होंने पहले से ही सघु उद्योगों की वित्तीय सहायता करना शुरू कर दिया था अथवा जो इस संबंध में निश्चित कार्यक्रम बना चुके थे। यह निर्णय प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के संबंध में ग्रामीण और सहकारी ऋण की स्थायी सलाहकार समिति की सिफारिश पर तथा शहरी बैंकों के संबंध में सहकारी बैंकों द्वारा उद्योगों को वित्तीय सहायता दिये जाने से सम्बन्धित कार्यकारी दल की सिफारिश पर लिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 46क (2) (क) के साथ पठित धारा 17(4) (कक) के अधीन राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि में से 1969-70 के वित्तीय वर्ष में 14 राज्य सरकारों के लिए 7.29 करोड़ रुपये (0.20 करोड़ रुपये के नवीकरण को छोड़कर) के ऋण मंजूर किये गये ताकि वे 2 राज्य सहकारी बैंकों, 70 केन्द्रीय सहकारी बैंकों, 2,624 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, 6 केन्द्रीय विकास बैंकों, 254 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों और 4 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की शेयर पूंजी में अंशदान कर सकें। उक्त राशि में से 1969-70 के वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकारों द्वारा आहूति की गयी कुल राशि 6.80 करोड़ रुपये थी जब कि 1968-69 में वह 3.92 करोड़ रुपये थी। इस मद में राज्य सरकारों के नाम कुल बकाया राशि 31 मार्च 1970 को 33.83 करोड़ रुपये थी जब कि 31 मार्च 1969 को यह राशि 31.19 करोड़ रुपये थी।

263. पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष बैंक ने 1970-71 के लिए भूमि विकास बैंकों के द्विचक्र कार्यक्रम के बारे में चर्चा और निर्णय करने के लिए जनवरी 1970 में केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों, भारत सरकार आदि के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई। 1969-70 के लिए अनुमोदित 113.00 करोड़ रुपये के कार्यक्रम की तुलना में 1970-71 के लिए 141.20 करोड़ रुपये के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। यह परिकल्पना की गयी कि सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं तथा भारत सरकार से मिलने वाले सहायता की राशि 44 करोड़ रुपये होगी। यह आशा की

गयी है कि डिवेंचर कार्यक्रम के लिए वाणिज्य बैंक 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था करेंगे। भूमि विकास बैंकों के डिवेंचर कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त सहायता प्राप्त कराने के लिए की गयी व्यवस्थाओं को दृष्टि में रखते हुए बैंक भूमि विकास बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर और साथ ही उन बैंकों की वित्तीय तथा परिचालन संबंधी सुवृद्धता पर भी बल देता रहा। 90 प्रतिशत ऋण उत्पादक कार्यों के लिए दिए जाएँ जिनमें से 70 प्रतिशत ऋण सहज प्रत्यक्ष उत्पादक कार्यों के लिए दिए जाएँ और सहायता की योग्यता उनके वसूली कार्य पर निर्भर होगी—पिछले वर्ष निर्धारित की गयी इन दोनों शर्तों को 1969-70 के लिए भी जारी रखा गया। प्राथमिक स्तर पर (या जहाँ प्राथमिक बैंक न हों वहाँ शिखर स्तर पर) वे भूमि विकास बैंक पूरी सहायता प्राप्त करने योग्य थे जिनकी मांग संबंधी बकाया राशि 15 प्रतिशत या उससे कम थी जबकि अधिक बकाया राशि वाले बैंक क्रमिक रूप से कम सहायता प्राप्त करने योग्य थे। 1969-70 के वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों ने 113.75 करोड़ रुपये के सामान्य डिवेंचर जारी किये जिनमें वाणिज्य बैंकों से प्राप्त भ्रंशदान की राशि 31.84 करोड़ रुपये थी जबकि 1968-69 में यह राशि 22.86 करोड़ रुपये थी। सामान्य डिवेंचरों में बैंक के भ्रंशदान की राशि 4.20 करोड़ रुपये थी और भारत सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और राज्य सरकारों के भ्रंशदानों की राशि 52.36 करोड़ रुपये थी। 1969-70 के वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों ने 5.10 करोड़ रुपये के ग्रामीण डिवेंचर जारी किये जिनमें बैंक का भ्रंशदान 1.16 करोड़ रुपये था। सामान्य और ग्रामीण डिवेंचरों में बैंक द्वारा किये गये भ्रंशदानों की कुल राशि 30 जून 1970 को क्रमशः 30.80 करोड़ रुपये और 9.57 करोड़ रुपये थी जब कि 30 जून 1969 को वह राशि क्रमशः 28.52 करोड़ रुपये और 8.97 करोड़ रुपये थी।

264. हाल ही के वर्षों में भूमि विकास बैंकों के कार्यों और परिचालनों में पर्याप्त वृद्धि हुई थी। अतः बैंक ने उन बैंकों के निरीक्षण क्षेत्र को भी व्यापक बना दिया ताकि उनके कार्यों और परिचालनों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। इस दिशा में जारी किये गये विस्तृत दिशा-निर्देशों के लक्ष्य इस प्रकार थे; ऋण देने से संबंधित उनकी नीतियों में सुधार किया जाए, साधनों का उत्तम प्रबंध हो, पर्यवेक्षण के लिए समुचित कर्मचारी-वर्ग की नियुक्ति की जाए, तकनीकी विभागों की स्थापना की जाए आदि।

सहकारी बैंक विनियमन

265. 30 जून 1970 को बैंक विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आनेवाले सहकारी बैंकों की कुल संख्या 1317 थी; उनमें से 28 राज्य सहकारी बैंक, 366 केन्द्रीय बैंक और 923 प्राथमिक सहकारी बैंक थे; वर्ष के आरम्भ में उनकी संख्या 1,348 थी। सहकारी बैंकों की संख्या में जो कमी हुई वह मुख्य रूप से कतिपय कृष्येतर ऋण समितियों को प्राथमिक सहकारी बैंकों की सूची से हटा देने के कारण हुई। 1969-70 के दौरान बैंक विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 22 के अधीन 10 सहकारी बैंकों—2 केन्द्रीय और 8 प्राथमिक सहकारी बैंकों—को भारत में बैंक कारोबार शुरू करने के लिए लाइसेंस दिये गये। इस प्रकार लाइसेंस-प्राप्त सहकारी बैंकों की कुल संख्या बढ़ाकर 24 हो गयी। 30 जून 1969 को सहकारी बैंकों के कार्यालयों की संख्या 4,137 थी; यह संख्या 31 मार्च 1970 तक बढ़कर 4,399 तक पहुँच गयी। 1 जुलाई 1969 से 1 जून 1970 तक की अवधि में राज्य और प्राथमिक सहकारी बैंकों को नये कार्यालय खोलने के लिए 51 लाइसेंस दिये गये जबकि 1968-69 में 35 लाइसेंस दिये गये थे। इस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को एक लाइसेंस दिया गया जिससे वह अपने प्रधान कार्यालय को जबलपुर से हटाकर भोपाल में स्थापित कर सके। बैंक विनियमन अधि-

नियम, 1949 की धारा 53 के अधीन भारत सरकार ने पाँच सहकारी बैंकों को बैंक विनियमन अधिनियम की धारा 11(1) के उपबंधों का पालन करने के संबंध में 28 फरवरी 1970 तक एक वर्ष के लिए छूट प्रदान की। इसी प्रकार से छूट 6 सहकारी बैंकों को एक मार्च 1969 से 2 वर्ष के लिए दी गयी। जिन 28 सहकारी बैंकों को दी गयी छूट की अवधि 28 फरवरी 1970 को समाप्त हो गयी थी उनमें से 3 बैंकों को 1 मार्च 1970 से एक और वर्ष तक के लिए छूट दी गयी। अब तक 7 सहकारी बैंकों ने बैंक विनियमन अधिनियम की धारा 11(1) के उपबंधों का पालन किया है और एक बैंक का समामेलन कर दिया गया है तथा एक दूसरे बैंक का परिसमापन होने वाला है। छः सहकारी बैंकों के आवेदन पत्रों के संबंध में भारत सरकार से छूट के लिए सिफारिश की गयी है और शेष आवेदन पत्र बैंक के विचाराधीन हैं।

266. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों को हुई और कापस की जमानत पर बिये जाने वाले अधिमों पर सीमित नियंत्रण रखने के संबंध में जारी किये गये एक निदेश का उल्लेख किया गया था। रिपोर्ट के वर्ष के दौरान उक्त निदेश परिशोधित किया गया। तदनुसार ऋण के समग्र स्तर का संगठन पहले की तरह अक्टूबर 1968 के अंतिम शुक्रवार के बजाय अब अक्टूबर 1969 के अंतिम शुक्रवार को भारत में रहने वाली देयताओं में एक निश्चित प्रतिशत के अनुसार की जाती है।

267. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में जमा बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 के अधिनियमन के संबंध में उल्लेख किया गया था। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा, दमन व दीव राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम इस उद्देश्य से संशोधित किये गये कि सहकारी बैंकों के अधिलेखन, पुनर्गठन, समामेलन और परिसमापन आदि से संबंधित अधिकार रिजर्व बैंक को प्राप्त हो सकें। बैंक अन्य राज्य सरकारों के साथ सहकारी समितियों के अधिनियमों के संशोधन के संबंध में बातचीत कर रहा है ताकि उन राज्यों के सहकारी बैंकों को भी जमा बीमा का लाभ प्रदान किया जा सके।

268. आलोच्य अवधि में बैंक विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अधीन 13 राज्य सहकारी बैंकों, 246 केन्द्रीय सहकारी बैंकों, 2 राज्य औद्योगिक सहकारी बैंकों, 9 जिला औद्योगिक सहकारी बैंकों और 568 प्राथमिक सहकारी बैंकों का निरीक्षण किया गया। 568 प्राथमिक सहकारी बैंकों में से 101 बैंकों का निरीक्षण बैंक विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35(1) के अधीन रिजर्व बैंक को और से राज्य सहकारी बैंकों के अधिकारियों द्वारा किया गया। 18 केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों, 4 शिखर सहकारी हथकरषा बुनकर समितियों और एक शिखर सहकारी विपणन समिति का निरीक्षण स्वीकृत आधार पर किया गया। 17 राज्य सहकारी बैंकों, 391 केन्द्रीय सहकारी बैंकों, 3 राज्य औद्योगिक सहकारी बैंकों और 19 जिला औद्योगिक सहकारी बैंकों की निरीक्षण रिपोर्टों की प्रतियाँ संबंधित बैंक को दी गईं रिपोर्ट के वर्ष के दौरान 18 केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों, 3 राज्य हथकरषा बुनकर समितियों और 3 शिखर विपणन समितियों की निरीक्षण रिपोर्टें भी संबंधित संस्थाओं को दी गयीं।

कृषि पुनर्वित्त निगम

269. 1969-70 के दौरान निगम ने कृषि विकास की निम्नलिखित 142 योजनाओं के लिए पुनर्वित्त मंजूर किया: लघु सिंचाई (62), भूमि विकास (11), खेतों का मशीनीकरण (7), बागान और बागवानी का विकास (54), मूर्तिपालन (1), डेरी (1) और मछली उद्योग (3) का विकास और गोबामों का निर्माण (3)। इन योजनाओं के कुल वित्तीय परिचय की राशि 92.78 करोड़ रुपये थी जबकि निगम के वायवों की राशि 70.92 करोड़ रुपये थी। इनमें वे पाँच योजनाएँ

शामिल नहीं हैं जिनके लिए वर्ष के दौरान मंजूरी तो नहीं दी गयी थी लेकिन बाद में वित्तीय सहायता कर्गवाली संस्थाओं द्वारा यह मंजूरी वापस ले ली गयी थी।

270. आर्थिक अवधि में मंजूर की गयी 142 योजनाओं में से 85 योजनाओं का कार्यान्वयन केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों द्वारा किया जाना है। उनके मामलों में संबंधित बैंकों द्वारा जारी किये जाने वाले विशेष विकास डिबेंचरों में अंगदान के रूप में पुनर्वित्त की व्यवस्था की गयी है। नात योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सहकारी बैंकों द्वारा और गेप 50 योजनाओं का कार्यान्वयन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा किया जाना है और उनके मामलों में ऋण के रूप में पुनर्वित्त की व्यवस्था की गयी है।

271. इस वर्ष निगम ने पहले मंजूर की गयी कुछ योजनाओं के वित्तीय परिण्यों में कटौती करने और विशेष विकास डिबेंचरों के जारी किये जाने की अवधि को बढ़ाने के लिए कुछ योजनाओं को पुनर्व्यवस्थित करने की स्वकृति दी। पुनर्व्यवस्था आदि के कारण पहले से मंजूर की गयी कुछ योजनाओं के परिण्यों में होने वाले परिवर्तनों पर यदि ध्यान दिया जाये तो 30 जून 1970 को समाप्त हुए सात वर्षों के अपने कार्य-काल के दौरान निगम द्वारा मंजूर की गयी योजनाओं की कुल संख्या 371 है और निगम के कुल परिण्यों और बायदों की राशि क्रमशः 259.51 करोड़ रुपये और 214.89 करोड़ रुपये है।

272. इस वर्ष निगम ने 28.60 करोड़ रुपयों की राशि का वितरण किया जिससे जून 1970 के अन्त तक वितरित की गयी कुल राशि 59.09 करोड़ रुपये हो गयी। इस वर्ष वितरित किये गये 28.60 करोड़ रुपयों में से 26.75 करोड़ रुपये केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों, 1.29 करोड़ रुपये राज्य सहकारी बैंकों और 0.56 करोड़ रुपये अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में वितरित किये गये। इस वर्ष तीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और 1 राज्य सहकारी बैंक ने क्रमशः 1.88 लाख रुपयों और 9.11 लाख रुपयों के मूल धन की वापसी करायी की। 5 जनवरी 1970 को निगम ने पहली बार 10 करोड़ रुपयों के लिए 5½% कृषि पुनर्वित्त निगम बांड, 1982 को पहली सीरीज जारी की जिसमें 10 करोड़ रुपयों से अधिक 10 प्रतिशत तक प्राप्त अधिदान राशि को रख लेने की व्यवस्था थी। इन बांडों के लिए 11 करोड़ रुपयों की अधिदान राशि प्राप्त हुई जिसमें से विभिन्न भविष्य निधि न्यासों से प्राप्त 6,23,000 रुपयों के अधिदान की राशि उन्हें इस लिए लौटा दी गयी कि उन प्राये-दन पत्रों के संबंध में न्यासियों या उनके बैंकों के निजी नाम पर बांड जारी करने की जो मांग की गयी थी उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। अन्तिम नियतन की राशि 10,93,77,000 रुपये थी।

273. 1 जुलाई, 1969 से 30 जून 1970 तक की अवधि के दौरान निगम ने भारत सरकार से 19.00 करोड़ रुपयों के ऋण लिये जिससे उसके द्वारा किये गये ऋणों की कुल राशि 44.75 करोड़ हो गयी।

274. इस वर्ष निगम के कार्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि कृषि के आधुनिकीकरण और उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किये जानेवाले पूंजी निवेश की वित्तीय सहायता करने के लिये उसने अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (अं०पु०वि० बैंक) तथा उससे संश्लेष विकास संघ (अं०वि० संघ) के साथ सक्रिय सम्पर्क स्थापित किया। तीन परियोजनाओं अर्थात् तराई बीज परियोजना (अं०पु०वि० बैंक) गुजरात कृषि ऋण परियोजना (अं०वि० संघ) और पंजाब कृषि ऋण परियोजना (अं०वि० संघ) को अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। अं०पु०वि० बैंक/अं०वि० संघ, भारत सरकार, निगम और संबंधित वित्तीय सहायता करनेवाली संस्थाओं के बीच हुए समझौते के अधीन अं०पु०वि० बैंक तराई

परियोजना के लिए भारत सरकार को 130 लाख डालर (9.75 करोड़ रुपये) के ऋण प्रदान करेगा जिसमें से 6.75 करोड़ रुपयों की राशि निगम द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। अं०वि० संघ भारत सरकार को गुजरात परियोजना के लिए 350 लाख डालर (26.25 करोड़ रुपये) और पंजाब परियोजना के लिये 275 लाख डालर (20.63 करोड़ रुपये) के ऋण प्रदान करेगा और निगम द्वारा उपलब्ध करायी जानेवाली राशि क्रमशः 26.03 करोड़ रुपये और 20.63 करोड़ रुपये होगी। निगम को ये राशियां भारत सरकार से ऋण के रूप में नियमित शर्तों पर प्राप्त होंगी।

275. इस वर्ष पुनर्वित्त की मंजूरी से संबंधित नीति और कार्य-विधि में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये :

(क) लघु सिंचाई योजनाओं के संबंध में केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों द्वारा जारी किये गये विशेष विकास डिबेंचरों में राज्य सरकारों ने 10 प्रतिशत अंगदान करने की जो विशेष रियायत दी थी उसे 30 जून 1971 तक बढ़ा दिया गया।

(ख) 14 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् यह निर्णय किया गया कि इन बैंकों को कृषि पुनर्वित्त निगम की ओर से रखी गयी उपबंधक, उप-दृष्टिबंधक जैसी जमानतों को अब पंजीकृत नहीं कराना होगा जैसा कि पहले कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 125 और 135 के अनुपालन में कराना पड़ता था।

(ग) वाणिज्य बैंकों की शीघ्र-से-शीघ्र पुनर्वित्त प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से उनकी सहायता करने के लिए निगम ने वाणिज्य बैंकों से प्राप्त योजनाओं की जांच-पड़ताल के कार्य को विकेंद्रित कर दिया। नवम्बर 1969 से ऐसी योजनाओं की जांच-पड़ताल निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाने लगी हैं जिनमें निगम से प्राप्त की जानेवाली पुनर्वित्त सुविधाओं की राशि 5 लाख रुपयों से अधिक न हो। चाय, काफी, रबड़ और इलायची के बागानों के विकास से संबंधित 5 लाख रुपयों या उनसे कम राशि वाली योजनाओं के संबंध में भरे जाने वाले फार्मों को भी सरल बनाया गया है ताकि छोटे बागान मालिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो सके।

(घ) जुलाई 1968 से निगम ने क्षेत्रीय विकास दृष्टिकोण का आग्रह किये बिना कतिपय शर्तों के अधीन पम्प सेट ट्रैक्टर आदि खेती के काम आनेवाले उपकरणों की खरीद के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा उनके विभिन्न कार्यालयों के माध्यम से दिये जाने वाले छुट-पुट अग्रिमों के लिए भी पुनर्वित्त देना शुरू कर दिया था। यह सुविधा अस्थायी उपाय के रूप में उस समय दी गयी जब वाणिज्य बैंकों को क्षेत्रीय विकास दृष्टिकोण के आधार पर योजनाएँ तैयार करने का अनुभव बिल्कुल नहीं था ताकि वे निगम द्वारा प्रदान की जानेवाली पुनर्वित्त सुविधाओं में अधिक रुचि ले सकें। चूंकि वाणिज्य बैंक अब परियोजना के आधार पर योजनाएँ तैयार करने के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर चुके हैं अतः मार्च 1970 में निगम ने खेती के काम आने वाले उपकरणों आदि की खरीद के लिए वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये जाने वाले छुट-पुट अग्रिमों के लिये पुनर्वित्त प्रदान करने की सुविधा को समाप्त कर देने का निश्चय किया। वाणिज्य बैंकों द्वारा क्षेत्रीय विकास दृष्टिकोण के आधार पर बनायी गयी योजनाओं के लिए निगम पहले की तरह पुनर्वित्त प्रदान करता रहेगा।

(४) बैंकों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों को देखते हुए निगम ने यह निश्चय किया है कि वह प्रतिभूति के रूप में रखे जाने वाले उन पम्प-सेटों के संबंध में उधारकर्ता द्वारा सम्पूर्ण बीमा पालिसी लिये जाने का आग्रह नहीं करेगा जिनके लिए निगम से प्राप्त पुनर्वित्त सहायता के अधीन वित्तीय व्यवस्था की गयी हो।

276. बंगलूर, कलकत्ता, चण्डीगढ़, कोयम्बतूर (अब मद्रास में स्थानान्तरित), हैदराबाद, कानपुर और नई दिल्ली में स्थित सात क्षेत्रीय कार्यालयों के अलावा निगम ने 1 जुलाई 1969 से 30 जून 1970 तक की अवधि में अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, पटना और विवेन्द्रम में क्षेत्रीय कार्यालय खोले तथा महाराष्ट्र की योजनाओं की देख-भाल करने के लिए बम्बई में एक अलग यूनिट की स्थापना की।

V. विदेशी मुद्रा नियंत्रण की गतिविधियाँ

277. विदेशी मुद्रा नियंत्रण के क्षेत्र में पिछले वर्ष यात्रा, अध्ययन आदि से संबंधित नियमों को उदार बनाने की जो प्रक्रिया शुरू की गयी थी उसे आलोच्य वर्ष के दौरान और आगे बढ़ाया गया। 1 मार्च 1970 से लागू की गयी विदेश यात्रा योजना, 1970 के अधीन अब भारत के निवासी 'पी' फार्म की औपचारिकताओं का पालन किये बिना ही अपनी इच्छा के अनुसार एक बार विदेश यात्रा कर सकते हैं बशर्ते कि ऐसी यात्रा करने की तारीख से तीन वर्ष पहले की अवधि में उन्होंने भारत से बाहर के किसी देश (नेपाल, सोलोम और मारीशस को छोड़कर) की यात्रा नहीं की हो। इस योजना के अधीन यात्रा के लिए किसी भी हवाई कम्पनी या जहाजरानी कम्पनी से टिकट प्राप्त किये जा सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति एयर-इंडिया या भारतीय जहाजरानी निगम और मुगल लाइन (हज यात्रियों को छोड़कर) के किसी भी जहाज से यात्रा करेंगे उन्हें 100 अमेरिकी डालरों की विदेशी मुद्रा मिल सकेगी। जून 1970 तक लगभग 11,000 व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा चुके थे।

278. सम्मेलनों में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा करने के संबंध में आगे से उन मामलों में समस्याओं की संख्या पर पाबंदी नहीं लगायी जायेगी जहाँ विदेश में रहने के खर्चों के संदर्भ में किसी संस्था से सहायता मिलती हो।

279. अब यह भी निष्पन्न किया गया है कि चाहे बैंक द्वारा दी गयी रकम किसी भी मुद्रा में क्यों न हो अथवा परमिट में उल्लिखित यात्रा के देश कोई भी क्यों न हो, यदि यात्री अमेरिकी डालर ट्रेवलर चेक लेना चाहें तो उन्हें कुछ अपवादों को छोड़कर प्राधिकृत व्यापारी ऐसे चेक दे सकते हैं।

280. विदेशों में अध्ययन करने के लिए दी जानेवाली विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित नियमों को उदार बनाया गया है। अब तक भारत की द्विती परीक्षा में प्राप्त 60 प्रतिशत अंक इस उद्देश्य के लिए योग्यता अंक निर्धारित थे; अब उन्हें बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है। शिक्षा के उन सभी क्षेत्रों में जिनके लिए भारत में न तो द्विती कोर्स की व्यवस्था है और न ही कोई उपयुक्त डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध है इस बात पर जोर दिये बिना ही विदेशी मुद्रा प्रदान की जाएगी कि सम्बन्धित छात्र का प्रेज्युएट होना जरूरी है।

281. जहाँ किसी छात्र द्वारा प्राप्त की गयी विदेशी छात्रवृत्ति का वार्षिक मूल्य 300 पाँड या उसके बराबर या उससे कम हो वहाँ छात्र को प्राप्य विदेशी मुद्रा के कोटे में कोई समायोजन नहीं किया जायेगा जैसा कि पहले किया जाता था। किंतु जहाँ छात्रवृत्ति का मूल्य 300 पाँड या उसके बराबर की मुद्रा से अधिक हो वहाँ केवल 300 पाँड से अधिक राशि के संबंध में समायोजन किया जायेगा।

282. अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी अपने कुछ सहायक बैंकों से कार्यालयों में अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा प्रदान करने का अधिकार दिया गया है।

283. होटलों को विदेशी मुद्रा के परिवर्तन के लिए लाइसेंस देने से सम्बन्धित नीति को भी इस वर्ष उदार बनाया गया है। अब विदेशी मुद्रा के परिवर्तन के लिए प्रतिबन्धित लाइसेंस उसके लिए आवेदन करने वाले किसी भी होटल, (या आई० एम० सी० ए० अथवा आई० डब्ल्यू० सी० ए० जैसी किसी भोजन और निवासयुक्त स्थापना) को न्यूनतम व्यापार के आशवासन या गारंटी पर जोर दिये बिना ही दिये जायेंगे।

284. इस वर्ष गैर-रिहायशी (विदेशी) लेखों के नाम से एक नये प्रकार का गैर-रिहायशी लेखा चालू किया गया। गैर-रिहायशी (विदेशी) लेखों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्राधिकृत व्यापारी इस प्रकार के लेखों में रहनेवाली निधियों को लेखाधारी का अनुदेश प्राप्त होने पर बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुमोदन के ही बाहर भेज सकते हैं। लेखों में रहने वाली निधियों पर अजित व्याज की राशि भारतीय आय कर से मुक्त है।

285. मस्कट और ओमान की सल्तनत ही फारस की खाड़ी का एक मात्र ऐसा राज्य था जहाँ 1966 के बाद भी भारतीय रुपये के विशेष नोट प्रचलित थे और अब 8 मई, 1970 से उसने रियास सदी नाम की अपनी मुद्रा जारी कर दी है। इसलिए उस सल्तनत में पहले प्रचलित भारतीय मुद्रा नोटों को वापस ले लेने की व्यवस्था की गयी है। मस्कट और ओमान में नयी मुद्रा के जारी हो जाने के पश्चात् भारतीय रुपया अब भारत से बाहर कहीं भी प्रचलित नहीं है।

286. जून 1970 को समाप्त हुए वर्ष में विभिन्न उद्देश्यों के निमित्त विदेश यात्रा के लिए दी गयी विदेशी मुद्रा और 'पी' फार्म से सम्बन्धित आंकड़े निम्नलिखित सारणी में दिये गये हैं।

i. विदेशी मुद्रा परमिट

यात्रा का उद्देश्य	परमिटों की संख्या	विदेशी मुद्रा की मंजूरी की गयी राशि। (लाख रुपयों में)
कारोबार	9,840	634
उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण	6,578	906
चिकित्सा	479	47
अध्ययन और	667	32
सम्मेलनों में भाग लेना	848	18
त्रिविध	7,893	136
जोड़	26,305	1,773

ii "पी" फार्म

यात्रा का उद्देश्य	अनुमोदित 'पी' फार्मों की संख्या
परिवार के मुख्या से मिलना	10,753
रिश्तेदारों/मित्रों से मिलना	14,003
नियत बुद्धि	369
नौकरी	4,675
उत्सवास	6,557
अध्ययन/प्रशिक्षण	5,873
त्रिविध	15,865
जोड़	58,095

VI. रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित विचार गोष्ठीयां और सर्वेक्षण

287. फरवरी 1970 में रिज़र्व बैंक ने व्यवसाय और विकास पर एक चार दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी आयोजित की। उक्त विचार गोष्ठी में विकसित और विकासशील देशों के अनेक केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों, उप गवर्नरों, कई बरिष्ठ अधिकारियों बैंकरों और अर्थ-शास्त्रियों ने भाग लिया। विचार गोष्ठी का यह उद्देश्य था कि विचारों का आदान-प्रदान हो और विकासशील देशों के बैंक व्यवसाय और वित्तीय प्रणाली को विकास सम्बन्धी नयी और विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की प्रक्रिया में उत्पन्न समस्याओं और उस संदर्भ में प्राप्त अनुभवों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। विचार गोष्ठी में सबके लिए स्वीकार्य निष्कर्षों पर पहुंचने का प्रयत्न नहीं किया गया। उद्घाटन सत्र के बाद विचार गोष्ठी में बैंक व्यवसाय और विकास के विषय पर निम्नलिखित परिप्रेक्ष्य में विचार विमर्श किया गया; (i) वाणिज्य बैंक व्यवसाय और विकास (ii) वित्तीय सहायता देनेवाली विशिष्ट एजेंसियां और (iii) केन्द्रीय बैंक व्यवसाय और विकास।

288. विचार गोष्ठी में पेश किये गये निबंधों और गोष्ठी की कार्य-शर्तों को रिज़र्व बैंक ने पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है।

289. वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि को दी जानी वाली वित्तीय सहायता पर हुई विचार गोष्ठी और राष्ट्रीय ऋण परिषद के अध्ययन दल द्वारा दिये गये सुझावों के अनुरार रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने सितंबर 1969 में वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि को दिये जाने वाले ऋणों से सम्बन्धित राज्य अधिनियमों के सम्बन्ध में एक विशेष दल गठन किया है। उक्त दल की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

290. बैंक और राज्य वित्तीय निगमों और दूसरी ऋणदाता संस्थाओं के प्रतिनिधियों के बीच उनकी कार्य प्रणालियों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं और दूसरे महत्वपूर्ण विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक ने मार्च, 1970 में राज्य वित्तीय निगमों के प्रतिनिधियों के चौदहवें सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया उनमें बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों के कार्यकलापों के बीच समन्वय लाना, वित्तीय साधनों को बढ़ाना और राज्य वित्तीय निगमों की सामर्थ्यता को बढ़ाने के तरीके शामिल थे। सम्मेलन में किये गये विचार विमर्शों के सत्रों में बैंक ने दो कार्यकारी दल गठित किये जिनमें से एक दल राज्य वित्तीय निगमों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक उपायों के सुझाव देगा और दूसरा दल औद्योगिक आस्थानों (सरकारी क्षेत्र के आस्थानों को छोड़कर) को वित्तीय सहायता देने से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करेगा। सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह था कि पिछले क्षेत्रों का विकास करने के लिए वहां के कारखानों को लचीली गतों पर किसी प्रकार ऋण प्रदान किया जाए। विचार-विमर्श किये गये दूसरे विषयों में निम्नलिखित विषय शामिल थे; लघु उद्योगों को राज्य वित्तीय निगमों द्वारा दी जानेवाली वित्तीय सहायता में तथ्य कतिपय विशिष्ट लक्ष्यों को निर्धारित कर वृद्धि करने की प्रणालियां, छोटे मूल्यों के लिए घलग अनुभाग खोलना, क्रियाविधियों को सरल बनाना, आदि।

291. कृषि-ऋण विभाग के अधिकारियों ने अप्रैल 1970 में महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद और पूना जिलों में इस बात का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय अध्ययन कार्य प्रारम्भ किया कि क्या अखिल भारतीय सहकारी केंद्रीय भूमि विकास बैंक संघ की स्थायी समिति ने क्रमशः बढ़ने वाली आय की जा परिकल्पना की है उसके आधार पर वापसी अदायगी की क्षमता का निर्धारण करना भूमि विकास बैंक द्वारा दीर्घाधि ऋण जारी किये जाने के संदर्भ में व्यावहारिक रूप से उपयोगी होगा। फसल ऋण प्रणाली का गुणात्मक मूल्यांकन करने के लिए उक्त विभाग के

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडू, पंजाब और मध्य प्रदेश राज्यों में भी विशेष अध्ययन किये गये।

292. अगस्त 1968 में सांख्यिकी विभाग ने वर्तमान औद्योगिक स्थिति और निकट भविष्य में संभाव्य गतिविधियों का एक सर्वेक्षण किया। उक्त अध्ययन पर आधारित रिपोर्ट बैंक के बुलेटिन के अप्रैल, 1969 के अंक में प्रकाशित की गयी। इसी प्रकार का अध्ययन पुनः 1969 में किया गया और इस दूसरे अध्ययन की रिपोर्ट बैंक के बुलेटिन के मार्च 1970 के अंक में प्रकाशित की गयी।

293. बैंकिंग आयोग के अनुरोध पर आर्थिक विभाग के ग्रामीण सर्वेक्षण प्रभाग ने चूने हुए बारह राज्यों में से प्रत्येक राज्य के एक-एक जिले में उपलब्ध बैंक सुविधाओं का क्षेत्रीय अध्ययन किया और अपने प्रमुख निष्कर्षों की एक रिपोर्ट आयोग को पेश की। उक्त अध्ययन का उद्देश्य यह था कि वाणिज्य और सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा कस्बे वाले और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सेवाओं की जो व्यवस्था की गयी है उसकी मात्रा का मूल्यांकन किया जाए और ऐसी संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के क्षेत्र को बढ़ाने तथा उनमें सुधार करने की सम्भावनाओं का संकेत दिया जाए। कृषि ऋण विभाग के अनुरोध पर इस प्रभाग ने महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के दो प्रमुख ग्राम-उत्पादन क्षेत्रों में भी अध्ययन कार्य किया। उक्त अध्ययन का उद्देश्य इस बात की जांच करना था कि क्या यह आवश्यक होगा कि बैंक उन जिलों में ग्रामों की खेती की वित्तीय सहायता के लिए अल्पवधि ऋण के स्थान पर माध्यमि ऋण ऋण की तरह आगे भी देना रहे। आलोच्य वर्ष में प्रभाग ने राजस्थान के जोधपुर जिले के केवल एक ही गांव में बहुत अधिक संख्या में ट्रैक्टरों के इक्कठे किये जाने की जांच करने के लिए क्षेत्रीय अध्ययन किया। उक्त अध्ययन का उद्देश्य यह था कि कृषि व्यवसाय में ट्रैक्टरों का उपयोग करने से उत्पादन में होने वाली वृद्धि और लागत में होने वाली बचत का ट्रैक्टरों के मालकों और उन्हें किराये पर लेनेवालों पर जो प्रभाव पड़ता है उसका मूल्यांकन किया जाए। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था पर विशेष कर कृषि भूमिकों पर ट्रैक्टरों का जो प्रभाव पड़ता है उसका भी अध्ययन करने का विचार है। इनके अलावा प्रभाग ने अपने नियमित अध्ययनों को भी जारी रखा जिनमें सहकारी बैंकों के अग्रिमों और जमा राशियों का सर्वेक्षण शामिल है। उसने 1964 से 1968 तक के वर्षों में किये गये आठ क्षेत्रीय अध्ययनों के आधार पर "सिंचाई विकास के लिए कृषिकों को दिये जाने वाला बैंक ऋण और विषय का सूक्ष्म विश्लेषण प्रधान अध्ययन" नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित की।

294. 1969-70 में आर्थिक विभाग के राजकोषीय विश्लेषण-प्रभाग ने स्थानीय प्राधिकारियों की 1965-66 और 1966-67 की वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धी सर्वेक्षण के आंकड़ों एकत्र किये सर्वेक्षण के परिणामों का विश्लेषण करने वाला एक संज्ञ रिज़र्व बैंक आफ इंडिया के बुलेटिन में प्रकाशनाय तैयार किया जा रहा है। इस अवधि में 1967-68 और 1968-69 का दूसरा सर्वेक्षण कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्थावरक के वार्षिक सर्वेक्षण के सम्बन्ध में सर्वेक्षण के लिए प्राप्त 31 मार्च 1969 तक के आंकड़ों का अध्ययन किया जा रहा है।

295. आर्थिक विभाग के अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रभाग द्वारा किये गये अवर्गीकृत प्राप्त सम्बन्धी (अर्थात् 10,000 रुपये से कम राशि या उसके समान राशि की प्राप्तियां, जिनके सम्बन्ध में प्राधिकृत व्यापारियों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे उनके उद्देश्यवार विवरण विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग को पेश करें) सर्वेक्षण का जो उल्लेख पिछली रिपोर्ट में किया गया था उसके परिणामों का इस वर्ष अन्तिम रूप दिया गया और इन परिणामों का विश्लेषण बैंक के बुलेटिन के मार्च,

1970 के अंक में प्रकाशित किया गया। सर्वेक्षण परिणामों द्वारा प्राप्तियों का जो उद्देश्यवार स्वरूप मालूम हुआ है उसका अब भुगतान शेष के आकड़ों में इन प्राप्तियों के उद्देश्यवार वितरण के लिए उपयोग किया जा रहा है। उद्देश्यवार वितरण को अद्यतन बनाने के लिए वर्ष की एम तिमाही में बराबर सर्वेक्षण किया जा रहा है। तबुनुसार 1969 के वर्ष में अक्टूबर से दिसम्बर तक की तिमाही का सर्वेक्षण किया गया जिसके परिणामों पर अभी कार्यवाई की जा रही है। 1970 की जुलाई से सितंबर तक की तिमाही का सर्वेक्षण अभी हो रहा है। भारतीय और विदेशी जहाजरानी कंपनियों और हवाई कंपनियों की प्राप्तियों और माल भाड़े तथा यात्री-किराये की अदायगियों का सर्वेक्षण वार्षिक आधार पर किया जाता रहा।

296. उक्त प्रभाग विदेशी कंपनियों और भारतीय मिश्रित पूंजी कंपनियों की शाखाओं से विदेशों में किये जाने वाले निवेश के सर्वेक्षण की तिमाही रिपोर्टें मंगाता रहा। मुख्यतः इन रिपोर्टों पर आधारित "19-65-66 और 1966-67 में भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति" शीर्षक एक लेख बैंक के बुलटन के अगस्त 1969 के अंक में प्रकाशित किया गया। उक्त लेख में अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति की समीक्षा के अलावा दो वर्षों के भुगतान शेष के लेखों की सयी श्रेणियाँ भी प्रस्तुत की गयी हैं जो बैंक के बुलटन के नवम्बर 1967 के अंक में प्रकाशित के क्रम में थीं।

VII. शिक्षा और प्रशिक्षण

297. राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान ने प्रशिक्षण अनुसंधान और परामर्श के क्षेत्रों में अपनी क्षमता को स्थापित करने की विद्या में प्रारम्भिक कदम उठाये। विभिन्न शाखाओं के संकायों में दस सर्वस्य पदभार ग्रहण कर चुके हैं और भाषा की जाती है कि 1970 के अंत तक यह संख्या पच्चीस तक पहुँच जायेगी। राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान ने बैंक-उद्योग की प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं का अध्ययन किया है और वह बैंक के कर्मचारी प्रशिक्षण कालेजों के सहयोग से एक व्यापक प्रशिक्षण-प्रणाली तैयार कर रहा है। अपने अपने कर्मचारी प्रशिक्षण कालेजों को मजबूत बना कर और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना कर अब अलग अलग बैंकों में इन योजना को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। कार्यापालक-विकास पाठ्यक्रमों के आयोजन की तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं और भाषा की जाती है कि पाठ्यक्रमों में 1970-71 में लगभग 250 वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। आधुनिक प्रबन्ध तकनीकों का उपयोग करते हुए विभिन्न अनुसंधान प्रयोजनाएँ शुरू की गयी हैं और अलग अलग बैंकों को परामर्शी सेवा प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान ने बैंक उद्योग के समक्ष तत्काल उपस्थित निम्नलिखित समस्याओं पर छः गोष्ठियों का आयोजन किया; 'लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देना' 'कृषि को वित्तीय सहायता देना' 'जमा-राशि जुटाना' 'ग्राहक सेवा' 'बैंक उद्योग का प्रबन्धकीय विकास' और 'नियंत्रणों को वित्तीय सहायता देना' वरिष्ठ बैंक और बैंकों के अध्यक्षों अभिरक्षकों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया इससे इन समस्याओं का उद्योगवार अध्ययन करने में सहायता मिली।

298. वाणिज्य बैंकों के पर्यवेक्षक कर्मचारियों को उन पर पड़ने वाली जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम बनाने के लिए रिजर्व बैंक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करता रहा। आलोच्य अवधि में बैंक प्रशिक्षण कालेज बम्बई में तीन वरिष्ठ पाठ्यक्रम, दो मध्यवर्ती पाठ्यक्रम, कृषि वित्त पर दो पाठ्यक्रम और विदेशी मुद्रा, कर्मचारी तथा संगठन और औद्योगिक वित्त में दो प्रत्येक पर एक एक पाठ्यक्रम चलाये गये। आलोच्य अवधि में संगठन और प्राणालियों पर एक नया पाठ्यक्रम चलाया गया। यह पाठ्यक्रम वाणिज्य बैंकों के उन अधिकारियों के लिए है जो संगठन

और प्राणाली विभाग में फैलाहाल काम कर रहे हैं, या जिन्हें संगठन और प्राणालियों से सम्बन्धित कार्य के सीपे जाने की सम्भावना है। आलोच्य अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त बैंक अधिकारियों की कुल संख्या 361 (विदेशों के 6 अधिकारियों को मिलाकर जब 1954 में कालेज की स्थापना हुई तब से लेकर अब तक वाणिज्य बैंकों के पर्यवेक्षक कर्मचारियों के लिए चलाये गये विभिन्न पाठ्यक्रम में, 3,573, कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। बैंक प्रशिक्षण कालेज बम्बई में रिजर्व बैंक के ग्रेड I स्टाफ आफिसर के लिए केन्द्रीय बैंक संघ-टन पाठ्यक्रम 1 नामक एक नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है भाषा है कि पहला पाठ्यक्रम नवम्बर, 1970 में शुरू होगा। उक्त पाठ्यक्रमों के उद्देश्यों इस प्रकार हैं: (क) बैंक के ग्रेड I स्टाफ आफिसरों में विकासशील देश की आर्थिक गतिविधियों के स्वरूप का मूल्यांकन करने की क्षमता उत्पन्न करना (ख) केन्द्रीय बैंक व्यवसाय के सिद्धान्त और व्यवहार के सम्बन्ध में विशेषकर रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कार्यकलापों के संदर्भ में उनके ज्ञान को नवीकृत करना और (ग) प्रबन्ध की आधुनिक तकनीकों से उन्हें अवगत कराना और बैंक के विभिन्न विभागों के कार्यों की बुनायादी जानकारी प्रदान करना जिससे कि वे एक वर्ष से दूसरे वर्ष में सरलता से स्थानांतरित किये जा सकें।

299. राज्य केन्द्रीय और शहरी सहकारी बैंकों के प्रबन्ध कर्मचारियों के लिए रिजर्व बैंक सहकारी बैंक व्यवसाय पर भी पाठ्यक्रम की व्यवस्था करता रहा। उचित स्थान के अभाव में ये पाठ्यक्रम पहले की तरह बैंक प्रशिक्षण कालेज बम्बई में ही चलाये गये। परन्तु सितम्बर 1969 में बैंक के पूना स्थित नव निर्मित भवन में सहकारी बैंक प्रशिक्षण कालेज कार्य करने लगा। अब तक रिजर्व बैंक मुख्यतः राज्य केन्द्रीय और शहरी सहकारी बैंकों के उच्चतर कर्मचारियों (अर्थात् प्रधान कार्यालयों के कार्यपालक अधिकारियों) के लिए पाठ्यक्रम चलाता आ रहा है। रिजर्व बैंक का यह उद्देश्य है कि राज्य/केन्द्रीय सहकारी बैंकों भूमि विकास बैंकों आदि के शाखा प्रबन्धकों के लिए पाठ्यक्रम चलाया जाए। सहकारी बैंक प्रशिक्षण कालेज का उद्घाटन हो जाने से आगे ऐसे पाठ्यक्रम चलाना संभव हो गया है। आलोच्य वर्ष में राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबन्ध कर्मचारियों के लिए दो पाठ्यक्रम चलाये गये जिनमें से एक पाठ्यक्रम बंबई प्रशिक्षण कालेज में और दूसरा पाठ्यक्रम पूना के सहकारी बैंक प्रशिक्षण कालेज में चलाया गया और शहरी बैंकों के प्रबन्ध कर्मचारियों के लिए तीन पाठ्यक्रम अर्थात् बम्बई के बैंकों प्रशिक्षण कालेज में एक पाठ्यक्रम और पूना के सहकारी बैंक प्रशिक्षण कालेज में पाठ्यक्रम चलाये गये इन दो पाठ्यक्रमों में भाग लेनेवाले कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 66 और 79 (विदेशों के दो कर्मचारियों को मिलाकर) थी अब तक उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की कुल संख्या क्रमशः 277 और 194 है।

300. आलोच्य अवधि में पूना के सहकारी बैंक प्रशिक्षण कालेज निम्नलिखित नये पाठ्यक्रम शुरू किये गये :—

- (क) भूमि विकास बैंकों के कर्मचारियों के लिए प्रायोजनगत परियोजना और मूल्यांकन पर तीन तीन सप्ताहों के दो पाठ्यक्रम,
- (ख) राज्य/केन्द्रीय सहकारी बैंकों के शाखा प्रबन्धकों के लिए 6 सप्ताहों की अवधि का एक पाठ्यक्रम, और
- (ग) वाणिज्य बैंकों के माध्यवर्ती कर्मचारियों अर्थात् एजेंटों, प्रबन्धकों लेखापालों और क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों के लिए जो के लिए जो वाणिज्य बैंकों की ग्रामीण शाखाओं में वास्तव में कृषि के लिए वित्तीय व्यवस्था करने का कार्य करते हैं, कृषि वित्त पर 8 सप्ताहों का एक पाठ्यक्रम।

301 सहकारी बैंकों के प्रबन्ध कर्मचारियों के लिए जिये बैंक द्वारा चलाये पाठ्यक्रमों में अनिवार्यतः "बैंकिंग नीतियों पद्धतियों और क्रियाविधियों का विषय सम्मिलित रहता है। चूंकि सहकारी बैंक के कार्य-पालक अधिकारी को बैंकर और प्रबंधक दोनों की भूमिकाएँ भ्रदा करनी पड़ती हैं अतः बैंक ने वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान पुना के साथ एक सहयोग करार किया ताकि बैंकिंग के अलावा प्रशिक्षण विषयों में 'कारोबारी प्रबन्ध' और सहकारिता सिद्धांत को भी सम्मिलित किया जाए। सहकारी बैंकर प्रशिक्षण कालेज के आहूते में ही वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान कार्य कर रहा है ताकि एक ऐसी पारस्परिक व्यवस्था हो सके जिससे कि एक संस्था के प्राध्यापक दूसरी संस्था के पाठ्यक्रमों में भाग ले सकें। वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान के निदेशक को सहकारी बैंकर प्रशिक्षण कालेज के निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है, और वे दोनों संस्थाओं के कार्यक्षेत्रों में समन्वय स्थापित करेंगे।

302. कर्मचारी प्रशिक्षण कालेज, मद्रास नियमित रूप से अवर पर्यवेक्षी कर्मचारी वर्ग के लिये केन्द्रीय बैंक संघटन पर सामान्य पाठ्यक्रम और बैंक परिचालन और विकास विभाग तथा कृषि ऋण विभाग के पर्यवेक्षी कर्मचारी वर्ग के लिए निरोधन पाठ्यक्रम चलाता रहा। हाल ही में कालेज में केन्द्रीय बैंक संघटन पर "ग्रेड II स्टाफ आफिसरों (सीधे भर्ती किये गये) के लिए विभागीय प्रशिक्षण समाप्त करने पर सामान्य पाठ्यक्रम नामक एक विशेष पाठ्यक्रम शुरू किया गया। स्टाफ आफिसरों को अन्य विषयों के साथ प्रबंध संबंधी आधुनिक सिद्धांतों और मानवीय संबंधों की जानकारी देना उक्त पाठ्यक्रम का उद्देश्य था। कालेज में अब तक प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों और पर्यवेक्षी कर्मचारियों की संख्या 2,549 है। कलकत्ता को छोड़कर दूसरे सभी स्थानों, अर्थात् बम्बई, मद्रास और नई दिल्ली में स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में बैंक के अवर और वरिष्ठ क्लर्कों के लिये पाठ्यक्रम चलाये जाते रहे। प्राणा की जाती है कि कलकत्ता केन्द्र पुनः गौध ही खोला जाएगा। विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में अब तक प्रशिक्षण प्राप्त कुल क्लर्क कर्मचारियों की संख्या 5,263 है। भारतीय प्रशासी कर्मचारी कालेज हैदराबाद के साथ की गयी स्थायी व्यवस्थाओं के अंतर्गत उस कालेज द्वारा चलाये जानेवाले प्रबंधकीय विकास पाठ्यक्रमों के लिये भी अधिकारियों को भेजा गया। वाणिज्य बैंकों के प्रबंध कर्मचारियों के लिए बैंकर प्रशिक्षण कालेज में चलाये जानेवाले बैंक संघटन संबंधी तथा अन्य पाठ्यक्रमों के लिए और साथ ही, अखिल भारतीय प्रबंध संस्थाओं और राज्य स्तरीय संस्थाओं, उत्पादित परिषदों, प्रबंध संस्थानों ऐसी ही दूसरी संस्थाओं द्वारा प्रबंधकीय विकास पर आयोजित किये जानेवाले अत्याधिक पाठ्यक्रमों के लिए भी अधिकारियों को भेजा जाता है। कतिपय केन्द्रीय बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से चलाये जानेवाले ("दक्षिण पूर्व एशिया न्यूजीलैंड आस्ट्रेलिया" पाठ्यक्रम कहलाने वाले) केन्द्रिय बैंक व्यवस्था संबंधी पाठ्यक्रम और बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा चलाये जाने वाले पाठ्यक्रम और कतिपय विदेशी संस्थाओं द्वारा आयोजित ऐसे दूसरे पाठ्यक्रमों के लिए भी जो बैंक के हित के हों, अधिकारियों को भेजा जाता है। बैंक अपने अधिकारियों को अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, पश्चिम जर्मनी आदि देशों की बैंकिंग संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए भेजता आ रहा है। ग्रेड III के वर्तमान और भावी वरिष्ठ स्टाफ आफिसरों के लिए केन्द्रीय बैंक संघटन और प्रबंध संबंधी तकनीकों का अग्रणी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने वाली एक संस्था की स्थापना करने का भी विचार है। ग्रेड I स्टाफ आफिसरों के लिए केन्द्रीय बैंक संघटन संबंध पाठ्यक्रम चलाने में अनुभव प्राप्त करने के बाद बैंक इस पाठ्यक्रम का आयोजन करेगा।

303. इस वर्ष बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 1968-69 का हिन्दी रूपान्तर और मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट 1968-69 और भारतीय

उद्योग में विदेशी सहयोगी की सर्वेक्षण रिपोर्ट, 1968 के संक्षिप्त हिन्दी संस्करण प्रकाशित किये। कृषि पुनर्वित्त निगम, जमा बीमा निगम, भारतीय और औद्योगिक विकास बैंक और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की वार्षिक रिपोर्टों का हिन्दी में अनुवाद करने का कार्य भी बैंक ने अपने हाथ में लिया है। 1967 में संशोधित राजभागा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों का पालन करने के लिये बैंक प्रिय थिजनि/नोट/सूचनाएँ/मार्ग, नोटिस और अधिसूचनाएँ हिन्दी और अंग्रेजी में साथ साथ जारी करता रहा। जनता, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से हिन्दी में प्राप्त पत्रों को स्वीकार किया गया और जहाँ जहाँ आवश्यक था, वहाँ उन पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया। बैंक अपने कर्मचारियों की मुद्रिधा के लिए विभिन्न केन्द्रों में स्वेच्छिक आधार पर हिन्दी कक्षाएँ चलता रहा। हिन्दी में दक्षता प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से (क) बैंक द्वारा चलायी जानेवाली कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकें उन्हें दी गयीं और (ख) हिन्दी की विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर कर्मचारियों को 100 रुपये का मानदेय दिया गया। जो कर्मचारी ऐसी कक्षाओं में आने में असमर्थ थे उन्हें भारत सरकार के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा चलाये जानेवाले पत्राचार पाठ्यक्रमों से हिन्दी सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया और इस संबंध में श्रेणी III के कर्मचारियों के मामले में ऐसे पाठ्यक्रमों के मुक्तकों की प्रतिपूर्ति करने की भी व्यवस्था की गयी है।

VIII. लेखा और अन्य विषय

304. 30 जून 1970 को समाप्त हुए लेखा वर्ष में विधिक और अन्य व्यवस्थाएँ करने के बाद बैंक की आय पिछले वर्ष के 99.35 करोड़ रुपये की तुलना में 105.45 करोड़ रुपये थी। बैंक के इस वर्ष के कुल व्यय की राशि पिछले वर्ष के 29.35 करोड़ रुपये की तुलना में 30.45 करोड़ रुपये थी। केन्द्रीय सरकार को भ्रदा करने के लिए उपलब्ध वास्तविक लाभ की राशि 75 करोड़ रुपये थी जब कि पिछले वर्ष यह राशि 70 करोड़ रुपये थी।

305. इस वर्ष राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि, राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि में जो अंशदान किये गये उनकी राशि क्रमशः 17 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये और 20 करोड़ रुपये थी जबकि 1968-69 में यह राशि क्रमशः 12 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये, और 20 करोड़ रुपये थी।

306. 1969-70 के आय में 6.10 करोड़ रुपये की जो वृद्धि हुई वह प्रमुख रूप से प्रतिभूतियों में किये गये निदेशों, विदेशी मुद्रा पुत्री, तथा बैंकों, राज्य सरकारों आदि को दिये गये ऋणों और अधिमों पर अधिक मात्रा में व्याज प्राप्त होने तथा रुपया और विदेशी लजाना बिलों पर अधिक मात्रा में बट्टा प्राप्त होने के कारण हुई। व्यय में 1.10 करोड़ रुपये की जो वृद्धि हुई वह मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से स्थापना व्यय में हुई वृद्धि के कारण हुई; (i) पंचाट कर्मचारियों को बढ़ी हुई दरों पर महंगाई भत्ता दिया गया, (ii) श्रेणी III के ग्रंथकर्मचारियों/भी० ए० आ० आ० भी० उल्लिखित कर्मचारियों को प्रतिपूरक भत्ते का वकाया दिया गया और (iii) स्वामान्तरण का विकल्प देनेवाले स्टाफ आफिसरों का उच्चतर दर पर किराया भत्ता दिया गया। पिछले वर्ष प्राप्त की गयी संपत्तियों पर इस वर्ष लगाये गये मूल्य-ह्रास और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके महायक कार्यालयों को भ्रदा किये गये एजेंसी प्रभारों में वृद्धि होने के कारण भी 1969-70 में किये गये व्यय में वृद्धि हुई।

लेखा परिक्षक

307. रिजर्व बैंक के लेखों की लेखा-परीक्षा बंबई के मेसर्स ए० एफ० फ्रंमन एण्ड कंपनी बंबई के मेसर्स ब्रह्माय्या एण्ड कंपनी मद्रास

श्रीर मैमर्स राय एण्ड राय, कलकत्ता द्वारा की गयी जिन्हें भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 50 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गयी अधिसूचना सं एफ 3 (50)बी० सी० 69 तारीख 5 दिसम्बर 1969 द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्ति किया था।

केन्द्रीय बोर्ड

308. अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त होने के कारण 4 मई, 1970 के पूर्वाह्न से श्री एल० के० झा बैंक के गवर्नर के पद भार से मुक्त हुए। उनके स्थान पर श्री बी० एन० आशारकर उसी तारीख से गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए और 15 जून 1970 को बैंक की सेवा से निवृत्त होने तक उन्होंने कार्य भार संभाला। श्री ए० बक्शी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त होने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार 8 सितंबर 1969 के अधिरात्र से बैंक के उप-गवर्नर के पद से मुक्त हुए। उप-गवर्नर के रूप में श्री जे० जे० अंजारिया की सेवा अवधि 31 जनवरी 1970 को समाप्त हो गयी थी, परंतु केन्द्रीय सरकार ने फरवरी 1970 के अंत तक एक महीने के लिए उनकी सेवा-अवधि को बढ़ा दिया। सर्वश्री एल० के० झा, बी० एन० आशारकर और जे० जे० अंजारिया ने बैंक के साथ अपने संबंधों की अवधि में जो समूल्य सेवाएँ की थीं उनके लिए बोर्ड इस अवसर पर उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता है। बैंक के उप-गवर्नर के पद से निवृत्त होने के तुरंत बाद 10 अप्रैल 1970 को श्री जे० जे० अंजारिया का जो आकस्मिक वेहावसान हो गया उसके प्रति बोर्ड अपना खेद व्यक्त करता है।

309. श्री एम० जगन्नाथन ने 16 जून 1970 के पूर्वाह्न से पाँच वर्ष की अवधि के लिए गवर्नर का पद भार ग्रहण किया। डा० प्रार० के० हजारी ने 27 नवंबर 1969 के पूर्वाह्न से पाँच वर्ष की अवधि के लिए बैंक के उप-गवर्नर का पद भार ग्रहण किया।

310. श्री एन० ए० पान्डीवाला प्रो० सी० एन० वकील क्रमशः 14 जनवरी 1970 और 23 जनवरी 1970 को अपनी पदावधि समाप्त होने पर बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशकों के पद से निवृत्त हुए। सेवा निवृत्त निदेशकों की सेवाओं के प्रति बोर्ड अपना आभार प्रदर्शित करता है।

311. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 8 (1) (घ) के अधीन 25 अक्टूबर 1969 से डा० आर्द० जी० पटेल के स्थान पर श्री ए० बक्शी केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किये गये। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 8(1) (ग) के अधीन श्री पी० वी० गजेन्द्रगडकर और डा० ए० एम० खुसरौ 28 फरवरी 1970 से केन्द्रीय बोर्ड के निदेशकों के रूप में नामित किये गये।

312. हम वर्ष केन्द्रीय बोर्ड की सात बैठकें हुईं जिनमें से साँ बैठकें बम्बई में हुईं और मद्रास, कलकत्ता, नई दिल्ली, जयपुर और पटना में एक-एक बैठक हुई। केन्द्रीय बोर्ड की समिति की वाचन बैठकें हुईं जिनमें से पाँच बैठकें नई दिल्ली में एक-एक बैठक मद्रास और कलकत्ता में और बाकी बैठकें बम्बई में हुईं।

313. 1 मार्च 1970 से श्री वी० जी० पेडारकर कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये हैं। कार्यपालक निदेशक श्री० के० सी० मित्रा 28 जून 1970 को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के तकनीकी

सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत यमन अरब गणतंत्र में केन्द्रीय बैंक की स्थापना करने में वहाँ के प्राधिकारियों की सहायता करने के निमित्त कार्यभार ग्रहण करने के लिए भारत से खाना हुए।

स्थानीय बोर्ड

314. श्री जे० ड० सेठी ने 14 जनवरी 1970 से उत्तरी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड के सदस्य का पद त्याग कर दिया।

कार्यालय खोलना और बन्द करना संगठन और प्रबंध में परिवर्तन।

315. 3 नवंबर 1969 से हैदराबाद में इशू विभाग का अपने आप में पूर्ण एक कार्यालय खोला गया जिसका मुद्रागत कार्य-क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश है।

बैंक की भवन

(क) कार्यालय भवन

316. मद्रास कार्यालय के उप भवन का निर्माण कार्य समाप्त हो चुका है और नागपुर में उप भवन का निर्माण कार्य समाप्त होने वाला है। बंगलूर में प्रधान कार्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है और जयपुर, भुवनेश्वर तथा बिर्बेद्रम के प्रस्तावित कार्यालय भवन और उप भवन, हैदराबाद का प्रधान कार्यालय भवन और बम्बई में मिट के भूतले में बनाया जाने वाला कार्यालय भवन अभी योजना की स्थिति में है। इशू विभाग के उप कार्यालय और बैंकिंग विभाग के अनुभाग खोलने के लिए अहमदाबाद में एक भवन और भुवनेश्वर में राज्य सरकार के अपने भवन का एक भाग पट्टे पर लेने की व्यवस्था की जा रही है। एनाकुलन में विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग की एक शाखा खोलने के लिए एक भवन लिया गया है।

(ख) आवास भवन

317. सभी प्रमुख केन्द्रों में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के आवास की व्यवस्था करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बैंक इन आवासों के लिए भारी मात्रा में आर्थिक सहायता प्रदान करता है। बैंक ने अब तक बम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली, मद्रास, नागपुर, पटना और कानपुर में ग्रेड I के स्टाफ आफिसरों, ग्रेड II के स्टाफ आफिसरों, क्लर्कों और अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए क्रमशः 149, 366, 1376 और 432 आवासों की व्यवस्था की है। इससे इन केन्द्रों के कुल कर्मचारियों के लगभग 15 प्रतिशत कर्मचारियों को आवास प्राप्त हुआ है।

318. मद्रास में अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए 120 फ्लैटों का एक कालोनी का निर्माण कार्य समाप्त हो चुका है और मद्रास में ग्रेड I के स्टाफ आफिसरों के लिए 12 फ्लैटों की और बम्बई में क्लर्कों और अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए क्रमशः 240 और 192 फ्लैटों की कालोनियों का निर्माण कार्य समाप्त होने वाला है। लक्नो और अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए नई दिल्ली में 272 फ्लैटों और कलकत्ता में 156 फ्लैटों का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। आशा है कि ग्रेड I और ग्रेड II के स्टाफ आफिसरों के लिए बंगलूर में 56 फ्लैटों और क्लर्कों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए कानपुर और नागपुर में क्रमशः 224 और 104 फ्लैटों का निर्माण कार्य कुछ ही महीनों में शुरू हो जाएगा। नई दिल्ली और बम्बई में ग्रेड I और ग्रेड II के स्टाफ आफिसरों के लिए और भुवनेश्वर, मद्रास और बंगलूर में श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों के लिए और कालोनियों का निर्माण करने का कार्य अभी योजना की स्थिति में है। कानपुर में ग्रेड I और II के स्टाफ आफिसरों और हैदराबाद तथा मद्रास में क्लर्कों और अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रस्तावित आवासों के लिए आर्किटेक्टों की नियुक्ति करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

319. ऐसे क्षेत्रों में जहाँ कोई भूमि प्राप्त नहीं की गयी है या जहाँ आवासों की संख्या अपर्याप्त है, कर्मचारियों के लिए आवास भवन का निर्माण करने के निमित्त बैंक उपयुक्त भूमि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता आ रहा है।

320. स्टाफ आवासों के लिए कम्पनी पट्टे पर प्लैट लेने की योजना जारी है क्योंकि जिन शहरों में बैंक के कार्यालय स्थित हैं वहाँ की आवास स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।

मालिक-कर्मचारी संबंध

321. रिजर्व बैंक के श्रेणी II और III के कामगार कर्मचारियों के सम्बन्ध में मध्यस्थ के पंचाट के कार्यान्वयन की बढ़ायी गयी श्रवधि 5 अप्रैल, 1970 को समाप्त हुई। रिजर्व बैंक के प्रबन्धकों और श्रेणी II और श्रेणी III के कामगार कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ के बीच वेतनमानों और भत्तों के परिशोधन, छुट्टी किराया रियायतों, चिकित्सा सहायता आदि के सम्बन्ध में 1 जून, 1970 से बातचीत चल रही है। रिजर्व बैंक के प्रबन्धकों और अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कामगार महासंघ के बीच श्रेणी IV के कर्मचारियों के वेतनमानों, भत्तों और दूसरी सेवा शर्तों से सम्बन्धित जो करार हुआ था उसकी श्रवधि 31 दिसम्बर, 1968 को समाप्त हुई। महासंघ ने अपनी मांगों का प्रपत्र पेश किया है और 12 जून, 1970 से उस पर बातचीत शुरू हुई है।

कर्मचारियों के लिए आवास-ऋण-योजना

322. आसोज्य वर्ष में जो आवास ऋण मंजूर किये गये उनका विवरण आगे दिया जाता है:-

	समितियों की संख्या	राशि रु०
(क) नयी सहकारी गृह निर्माण समितियाँ	11	59,43,065
पहले ही गठित की गयी सहकारी गृह-निर्माण समितियों को दिये गये अन्रिक्त ऋण	8	2,37,690
	जोड़	61,80,755
(ख) अलग-अलग कर्मचारी	कर्मचारियों की संख्या	
नये ऋण	69	13,69,830
उन कर्मचारियों को अन्रिक्त ऋण, जिन्होंने पहले ऋण प्राप्त किये थे	24	66,672
	जोड़	14,36,502

1961 में योजना के अमल में आने से लेकर अब तक मंजूर किये गये "समिति-ऋणों" और "व्यक्ति ऋणों" की कुल राशि क्रमशः रु० 2,07,80,355.00 और रु० 50,97,455.00 है। कुल मिलाकर 1227 कर्मचारियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

30 जून, 1970 को तुलन-पत्र

इशू विभाग

देयताएं		प्रास्तियां	
	रु. पै.		प. रु. पै.
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	14,03,72,578. 00	सोने का सिक्का और बुलियन :	
संचालन में नोट	4026,53,93,366. 50	(क) भारत में रखा हुआ	182,53,10,862. 72
जारी किये गये कुल नोट		(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	—
		जिवेयी प्रति-भूतियाँ जोड़	396,41,99,950. 11
		रुपये का सिक्का	578,95,10,812. 83
		भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियाँ	54,08,40 185. 37
		देशी विनियम बिल और दूसरे वाणिज्य- पत्र	3407,54,14,946. 30
कुल देयताएं		कुल प्रास्तियाँ	4040,57,65,944. 50

वैकिंग विभाग

देयताएं		प्राप्तियां	
	रु०	रु०	रु०
चुकता पूंजी	5,00,00,000.00	नोट	14,03,72,578.00
प्रारक्षित निधि	150,00,00,000.00	रुपये का सिक्का	1,43,563.00
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	172,00,00,000.00	छोटा सिक्का	4,55,261.27
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	37,40,00,000.00	खरीदे और भुगये गये बिल	—
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	95,00,00,000.00	(क) देशी	—
जमा राशियां		(ख) विदेशी	—
(क) सरकारी		(ग) सरकारी खजाना बिल	12,95,49,600.96
(i) केन्द्रीय सरकार	58,13,22,772.04	विदेशों में रखा हुआ ऋण * * *	98,48,79,980.21
(ii) राज्य सरकारें	16,21,55,803.40	निवेश * *	124,53,55,153.90
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	186,94,83,593.84	(i) केन्द्रीय सरकार को	—
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	14,40,34,831.91	(ii) राज्य सरकारों को @	31,65,00,000.00
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	79,01,125.01	ऋण और अग्रिम	
(iv) अन्य बैंक	32,28,422.36	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को †	308,32,05,000.00
(ग) अन्य	166,98,04,194.93	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को ††	224,09,53,540.61
देय बिल	22,62,49,363.71	(iii) दूसरों को	
अन्य देयताएं	56,75,37,035.32	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं)	2,72,41,993.32
कुल देयताएं	982,17,17,142.52	निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) ऋण और अग्रिम	
		(i) राज्य सरकारों को	31,32,24,745.48
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	20,28,30,736.98
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को	—
		(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	9,57,02,235.00
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से	
		ऋण और अग्रिम	
		राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	4,34,96,520.00
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं)	
		निधि से ऋण अग्रिम और निवेश	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	26,26,71,044.00
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांड्स/डिबेंचरों में निवेश	—
		अन्य प्राप्तियां	70,51,35,189.79
		कुल प्राप्तियां	982,17,17,142.52

अंशतः चुकता शेषों पर फुटकर देयता रु० 8,99,992.80 (पौण्ड 50,000 के स्टॉक निवेशों को रु० 100-5.5556 पौण्ड की दर पर बदला गया।)

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

** (i) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

(ii) इसमें विदेशों में रखे गये 50,000 पौण्ड और 4,947,500 अमेरिकी डालर शामिल हैं (रु० 3,80,06,242.80 के समान राशि)।

@राष्ट्रीय कृषि (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से प्रवृत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं:

† रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मोयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 157,45,80,000 रुपये शामिल हैं।

†† राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

आर० सी० सखदेवा,
मुख्य लेखापाल,
तारीख, 23 जुलाई, 1970

एस० जगन्नाथन, गवर्नर
पी० एन० डमरी उप-गवर्नर
आर० के० हजारी, उप-गवर्नर

30 जून, 1970 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

प्राय	रु०	पै०
भ्याज, भांजन, विनियम, कमीशन आदि*	—	105,44,62,572.48
व्यय		
स्थापना	—	14,84,25,555.34
निदेशकों और स्थानीय बोर्ड के सदस्यों की फीम और व्यय	—	80,418.98
लेखा परीक्षकों की फीस	—	37,500.00
किराया, कर, बीमा, बिजली, आदि	—	86,14,192.57
विधि प्रभार	—	1,15,500.31
ढाक और तार खर्च	—	9,51,349.58
कोष-प्रेषण	—	62,30,611.32
लेखन सामग्री, आदि	—	25,11,268.94
प्रतिभूति-छपाई (बैंक, मोटो फार्म आदि)	—	4,73,48,430.99
बैंक संपत्ति का मूल्य ह्रास और मरम्मतें	—	1,24,38,485.83
एजेंसी प्रभार	—	6,99,48,774.92
कर्मचारी निधि और अधिवाषिकी निधि में अंशदान	—	7,32,000.00
विविध व्यय	—	70,28,204.49
उपलब्ध वास्तविक शेष राशि	—	75,00,00,279.21
जोड़	—	105,44,62,572.48
केन्द्रीय सरकार को देय अधिशेष	—	75,00,00,279.21
प्रारक्षित निधि लेखा		
30 जून, 1970 को शेष		150,00,00,000.00
लाभ-हानि लेखों से अंतरित किया गया		कुछ नहीं
जोड़		150,00,00,000.00

* रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 47 के अनुसार नियमित या आवश्यक व्यवस्थाएं करने के बाद।

प्रार० सी० सचिवेवा,
मुख्य लेखापाल

एस० जगन्नाथन गवर्नर
पी० एन० डमरी, उप गवर्नर
प्रार० के० हजारी, उप गवर्नर

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में,

हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधोहस्ताक्षरित लेखा परीक्षक इसके द्वारा 30 जून, 1970 तक के रिजर्व बैंक के तुलना-पत्र तथा लेखों पर केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

हमने केन्द्रीय कार्यालय और कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के कार्यालयों के लेखों और उनसे सम्बन्धित प्रमाणपत्रों और वाउचरों से और साथ ही वृत्त कार्यालयों से और शाखाओं के मैनेजरों द्वारा पेश की गयी प्रमाणित उन विवरणियों से जो उक्त तुलना-पत्र में जोड़ी गयी हैं, उपर्युक्त तुलना-पत्र की जांच कर ली है और हम यह सूचित करते हैं कि हमने केन्द्रीय बोर्ड से जो जो स्पष्टीकरण और जानकारी मांगी है, वह सारा स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गयी है और संतोषजनक है। हमारी राय में तुलना-पत्र पूर्ण और सही तुलना-पत्र है; इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 और उसके अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा निर्धारित विवरण दिये गये हैं और इस उक्त अधिनियम और विनियम के अनुसार प्राप्ति का मूल्य निर्धारण किया गया है। जहां तक हमारी जानकारी है, तुलना-पत्र हमें दिये गये स्पष्टीकरणों और बैंक की बहियों के अनुसार उचित ढंग से तैयार किया गया है ताकि हमसे बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके।

तारीख 23 जुलाई, 1970

बहदुरा एण्ड कंपनी } लेखा परीक्षक
राज एण्ड राय }
ए० एफ० कर्गुसन एण्ड कंपनी }
[सं. 3 (15)-बी० सी०/71]
के. सुब्रह्मण्यम्, उप सचिव

(Department of Banking)

New Delhi, the 12th December, 1972

ANNUAL REPORT OF THE WORKING OF THE
RESERVE BANK OF INDIA AND TREND AND PRO-
GRESS OF BANKING IN INDIA FOR THE YEAR
JULY 1, 1969—JUNE 30, 1970.

S.O. 266.—In accordance with Section 52(e) of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Central Board of Directors has submitted to the Government of India the following Report on the working of the Reserve Bank of India and Trend and Progress of Banking in India for the year ended June 30, 1970.

I. OVERALL TRENDS IN THE ECONOMY

During the Bank's accounting year July 1969 to June 1970, the Indian economy registered good progress on several fronts. The output of all important agricultural commodities showed increase, that in the case of foodgrains and jute and mesta being sizeable. Industrial production also maintained a good rate of growth. National income at constant prices during 1969-70 (fiscal) is estimated to have increased by 5 to 5½ per cent which corresponds closely to the average annual rate of growth postulated in the Fourth Five-Year Plan. Foreign exchange reserves recorded a substantial increase mainly as a result of a steep decline in imports. Exports continued to grow though the rate of growth was much smaller than that a year earlier. The rate of growth of monetary resources was somewhat smaller than last year. The net bank credit to Government exerted a much smaller expansionary impact on monetary resources than in the preceding year, indicating the greater degree of balance in the budgetary operations of the Government sector. As against these favourable developments, there was some worsening in the price situation. The relative price stability, experienced over the last two years, was replaced by a rising trend.

2. Investment in the economy continued to rise, particularly in agriculture and small-scale industry. There was a moderate increase in the assistance sanctioned during the year as well as disbursements against earlier sanctions by the term-lending institutions. The small-scale industrial sector in particular was sanctioned a larger volume of assistance. Several measures were announced in the budget of the Government of India to encourage savings in the form of financial assets such as small savings instruments, bank deposits, Government securities and stocks and shares. The stock market remained subdued during the greater part of the year under review, but became active following the tax concessions granted in the budget for 1970-71 for investing in stocks and shares.

3. The budgetary policy was designed to give a further momentum to productive forces and at the same time ensure the well-being of the needy and the poor. Indirect tax measures were designed to provide impetus to export promotion and import substitution and to restrain consumption. Taxes on investment or producer goods as well as corporation taxes were not changed in order that the uptrend in production is maintained. With a view of mobilising larger savings, the rates of interest on some of the existing media of small savings were stepped up and new media of small savings yielding higher rates of interest but not qualifying for tax concessions were introduced. In order to combine growth with greater regard for welfare of the most needy sections of the society, the budget for 1970-71 provided for specific programmes such as (i) special schemes for small farmers in 45 districts spread throughout the country, (ii) selected rural works programmes particularly in areas prone to famine (iii) schemes for supply of drinking water in those areas having no easy access to this basic requirement, (iv) social security benefit for industrial workers and government employees, (v) nutritional programme for children

and (vi) setting up of an Urban Development Corporation with an authorised capital of Rs. 10 crores for financing slum clearance, housing and urban land development.

4. Monetary policy continued to be operated with the objective of stimulating economic growth and at the same time, curbing inflationary trends in the economy. Nationalisation of 14 major commercial banks enabled considerable re-orientation of bank lending so as to accelerate the process of development, particularly in those sectors of the economy like agriculture, small-scale industry which hitherto had not received sufficient attention from commercial banks. Increasing emphasis was placed on mobilisation of deposits on a massive scale throughout the country.

Output, Prices and Policy Measures

5. During 1969-70, despite delay in the onset of monsoon and deficient rainfall in certain areas in the initial months, agricultural production recorded substantial progress. Foodgrains production which stood at 95 million tonnes in 1967-68 and at 94 million tonnes in 1968-69 rose to 100 million tonnes during 1969-70. Output of rice is estimated to have increased by 2.3 million tonnes to 42 million tonnes and of wheat by 1.3 million tonnes to 20 million tonnes. The final estimate of raw jute and mesta production is placed higher at 6.8 million bales as against 3.8 million bales in 1968-69. Output of groundnuts at 5.1 million tonnes also showed an increase of about 11 per cent over last year. Output of raw cotton is estimated by trade slightly higher at 6.1 million bales as against 6.0 million bales last year. Production of sugarcane in terms of gur continued to show improvement, total production during 1969-70 being estimated at 12.5 million tonnes as against 12 million tonnes in the preceding year.

Table I — Trends in Agricultural Production

	Unit	1968-69 (Final Esti- mates)	1969-70 Esti- mates)
1. Foodgrains	Million tonnes	94.1	100.00**
(i) Rice	-do-	39.8	42**
(ii) Wheat	-do-	18.7	20**
2. Raw Cotton	Million bales@	5.3 (6.0)†	(6.1)†
3. Raw Jute Mesta . . .	-do-	3.8*	6.8@@
4. Groundnuts	Million tonnes	4.6*	5.1@@
5. Sugarcane (in terms of gur)	-do-	12.0	(12.5)‡

@ Bale of 180 kgs.

* Partially revised estimate.

@@ Final Estimate.

** Provisional.

† Trade estimate, including non-commercial production.

‡ Trade estimate.

6. For the calendar year 1969 the overall rate of growth in industrial production was marginally higher at 6.9 per cent as against 6.4 per cent in 1968. During the first nine months of the year under review, i.e., July 1969 to March 1970, the rate of growth in industrial production slackened to 5.8 per cent as against 7.4 per cent in the corresponding period last year.

Table 2—Growth Rates—Index Numbers of Industrial Production

(Base : 1960=100)

Group	Average Index for July-March		
	1967-68	1968-69	1969-70
General Index	154.1	165.5	175.1
Seasonally Adjusted		(+7.4)	(+5.8)
<i>Based on Uses</i>			
Basic Industries	181.3	201.7	217.4
		(+11.3)	(+7.8)
Capital Goods Industries	205.2	219.1	214.8
		(+6.8)	(+2.0)
Intermediates Goods Industries	143.2	150.4	158.7
		(+5.0)	(+5.5)
Consumer Goods Industries	130.9	138.6	149.3
		(+5.9)	(+7.7)
Consumer Durable Goods	189.3	223.1	242.1
		(+17.9)	(+8.5)
<i>Based on Inputs</i>			
Agro-based Industries	120.1	122.1	128.7
		(+1.7)	(+5.4)
Metal-based Industries	198.6	221.3	224.9
		(+11.4)	(+1.6)
Chemical-based Industries	184.4	221.4	239.3
		(+20.1)	(+8.1)

Note:—Figures in brackets represent percentage change over previous year.

7. Among the major groups of industries, classified according to their uses, 'basic industries' recorded a lower rate of increase at 7.8 per cent during the period under review as against 11.3 per cent in the corresponding period last year. 'Capital goods industries' registered an absolute decline of 2.0 per cent as against a rise of 6.8 per cent in the corresponding period last year. The growth rate in the case of 'intermediate goods industries' and 'consumer goods industries' continued its uptrend, the overall rate of increase in the case of the former being 5.5 per cent as against 5.0 per cent and in the case of the latter, 7.7 per cent as against 5.9 per cent last year. Analysis of industries according to inputs shows that agriculture-based industries which have nearly 44 per cent weightage in the general index were able to improve their performance, their growth rate rising to 5.4 per cent as against 1.7 per cent last year. This improvement is largely due to substantial increase in output of sugar and tea and some increase in cotton spinning output. The growth rates of metal-based and chemical-based industries slackened to 1.6 per cent and 8.1 per cent as against 11.4 per cent and 20.1 per cent, respectively, last year.

8. Among 'basic industries', mining and quarrying and manufacture of fertilisers registered lower rates of increase. The output of iron and steel basic industries remained virtually at last year's level due mainly to labour troubles, lack of proper maintenance and some technological defects in one of the public sector steel plants. Fertiliser production slowed down partly because of lower offtake and partly because of shortage of basic inputs. However, heavy inorganic chemicals, manufacture of cement, and copper smelting and rolling mills improved their rates of growth.

9. Among 'capital goods industries' prime movers, boilers and steam generating plants, industrial machinery, rail-road equipment and motor vehicles registered substantial declines. However, there was significant improvement in manufacture of electrical motors and furnaces, electrical cables and electrical machinery, apparatus and appliances, etc., reflecting the rising tempo of investment by the State Electricity Boards.

10. Among 'intermediate goods industries', production of cotton spinning rose by 3.8 per cent, manufacture of batteries by 13.3 per cent and synthetic resins and plastics by 2.7 per cent. The rate of growth in petroleum refinery products was slightly lower at 8.7 per cent as against 10.4 per cent last year. The jute goods output remained static during the nine month period in contrast to a decline of 18.3 per cent during the corresponding period of 1968-69.

11. Among 'consumer goods industries', the food manufacturing group (sugar, tea and vanaspati together) registered a significant increase of 20.4 per cent as against an increase of 0.1 per cent in the corresponding period last year. Paper and paper products also improved their performance. The growth rates in consumer durables such as communication equipment, motor cycles and bicycles slowed down. Production of woolen/worsted fabrics and fine and pharmaceutical chemicals declined by 7.8 per cent and 7.0 per cent, respectively, as against increases of 46.3 per cent and 36.3 per cent in the corresponding period last year.

12. With the rising tempo of investment in the small-scale industrial sector, estimates of output in this sector registered an impressive increase of 11.2 per cent during 1969-70 as against 8.2 per cent in 1968-69.

13. Data on utilisation of industrial capacity are available only upto the end of December 1969. According to these data the level of capacity utilisation as measured by the percentage ratio of average monthly production to the installed capacity, as at the end of 1969 showed improvement. Among basic industries, caustic soda, ammonium sulphate, urea, sulphuric acid, fertilisers, cement, finished steel and steel pipes and tubes significantly improved their capacity utilisation. However, among capital goods industries, in respect of motor vehicles, and power transformers the capacity utilisation was lower than in 1968.

14. The slow-down in the rate of industrial production was due mainly to the tight supply position of agricultural raw materials and shortages of special categories of steel faced by the engineering and allied industries. The pick-up of investment in the public and private sector of the organised industry was also not adequate to provide a strong stimulus to industrial growth. Labour relations continued to remain disturbed in many important sectors of industry during 1969. The mandays lost on account of strikes and lock-outs during 1969 were 16.68 million as against the annual average of 5.8 million man days lost between 1961 and 1965.

15. Price situation during the year under review, particularly during the latter half, has been causing serious concern. The post-harvest decline in prices came abruptly to an end from mid-November and since then the general price index exhibited a disconcertingly sharp upward trend which continued till the close of the year. The annual average of the general index registered an increase of 4.6 per cent in contrast with a nominal decline of 0.2 per cent in the preceding year. Between June-end 1969 and June-end 1970 the extent of increase was, however, lower at 4.0 per cent in the corresponding period last year. The following table shows the variations in the price movements during the year which fall into three broad phases.

Table 3—Seasonal Variations in Wholesale Prices
(Base : 1961-62=100)

Groups/Commodities	End-June 1969 and End-July 1969	End-July 1969 and November 15, 1969	November 15, and End-June 1970	End-June 1969 and End-June 1970
All Commodities	+1.0 (+2.0)	-4.2 (+0.8)	+7.5 (+4.5)	+4.0 (+7.4)
Food Articles	+1.3 (+2.4)	-7.4 (-3.7)	+7.9 (+3.8)	+1.2 (+2.4)
Rice	+1.2 (+0.4)	-4.3 (-7.4)	+6.7 (+5.2)	+3.4 (-2.2)
Wheat	+3.2 (+22)	-3.8 (+5.0)	-0.1 (-0.3)	-0.9 (+7.0)
Pulses	+3.0 (+0.9)	-6.1 (+5.0)	+2.7 (+7.1)	-0. (+13.5)
Edible Oils	+2.7 (+6.6)	-11.9 (+25.0)	+25.3 (+19.7)	+13.5 (+59.4)
Liquor and Tobacco	-1.5 (+2.9)	-6.4 (+10.1)	-1.0 (+3.7)	-8.8 (+17.5)
Fuel, Power, Light and Lubricants	+0.8 (+0.8)	+0.5 (+0.3)	+2.8 (+3.0)	+4.2 (+4.2)
Industrial Raw Materials	+2.5 (+4.3)	-9.1 (+13.3)	+16.4 (+12.4)	+8.4 (+32.8)
Cotton Raw	+1.1 (+0.8)	-5.8 (+3.2)	+18.2 (+6.5)	+12.6 (+10.9)
Jute Raw and Mesta	+3.5 (+9.7)	-30.4 (+38.1)	+23.6 (-4.7)	+10.9 (+44.4)
Oilseeds	+3.3 (+8.5)	-10.8 (+19.5)	+23.2 (+22.5)	+13.6 (+58.7)
Groundnuts	+4.1 (+11.9)	-22.9 (+23.8)	+37.8 (+38.4)	+10.7 (+91.8)
Chemicals	-1.6 (-0.1)	+7.8 (+5.6)	-2.6 (+3.8)	+3.4 (+9.5)
Machinery & Transport Equipments	+0.3 (—)	+2.8 (+6.7)	+5.7 (+0.5)	+8.9 (+1.2)
Manufactures	+0.4 (-0.7)	+2.5 (+3.6)	+4.6 (+3.3)	+7.7 (+7.8)

Note:—Figures in brackets indicate the percentage variations over the corresponding period last year.

16. The first phase was a continuation of the rising trend noticed since February 1969. In this phase, barring 'liquor and tobacco' and 'chemicals', all the major groups showed a rise. During the second phase, i.e., between end-July and mid-November, 1969, the general index registered a decline of 4.2 per cent mainly as a result of a fall of 7.4 per cent under 'food articles' and 9.1 per cent under 'industrial raw materials'. But 'manufactures', 'machinery and transport equipment', 'fuel, power, light and lubricants' and 'chemicals' continued to register increases. In the third phase, the general index registered an increase of 7.5 per cent. The rise is spread over almost all the major sub-groups. 'Food articles' recorded an increase of 7.9 per cent, 'industrial raw materials' 16.4 per cent and 'manufactures' 4.6 per cent.

17. The rise of 4.0 per cent over the year was brought about mainly by industrial raw materials and manufactures. The contribution of food articles to the price increase was smaller than last year. The increase in food articles was lower at 1.2 per

cent as against 2.4 per cent last year. The price index for rice showed an increase of 3.4 per cent as against a decline of 2.2 per cent last year, while that for wheat showed a nominal fall of 0.9 per cent as against a rise of 7.0 per cent last year. Pulses also noted a similar trend showing a nominal fall of 0.7 per cent as against a substantial rise of 13.5 per cent last year. The prices of edible oils rose during most part of the year, the extent of rise over the year being 13.5 per cent on the top of an increase of 59.4 per cent last year. Gur prices, (monthly averages) however, declined by 25.8 per cent as against 55.6 per cent last year. Prices of sugar remained more or less steady.

18. The rise of 8.4 per cent under 'industrial raw materials' reflected the tight supply position of major agricultural raw materials in relation to demand. The availability of raw cotton, raw jute and oilseeds, though higher than in the preceding year was much below 1967-68 levels.

Table 4—Availability¹ of Raw Materials for Industries

	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70 (Estimates)
Raw Cotton (lakh bales) September-August				
Production ²	53.1	65.4	60.2	60.7
Imports	7.8	7.8	4.3	8.2
Availability ³	82.2	92.4	86.2	88.6
Mill Consumption (lakh bales)	57.6	61.7	62.0	64.0
Raw Jute and Mesta (lakh bales) July-June				
Production	65.8	75.9	38.4	67.5
Imports	16.5	—	6.5	—
Availability	94.0	94.6	64.9	75.5
Mill Consumption (lakh bales)	72.0	71.3	58.5	65.5
Major Oilseeds ⁴ (million tonnes) July-June				
Production	6.4	8.3	7.1	7.8

1. Availability is defined as production + imports + opening stocks.

2. Trade estimate, including non-commercial production.

3. Exports of raw cotton (Bengal Deshi) during 1969-70 season (upto June) amounted to 2.0 lakh bales as against 1.7 lakh bales in the corresponding period of 1968-69.

4. Groundnuts, rapeseed and mustard, linseed, sesamum and castorseed.

19. The prices of raw cotton registered a decline between end-August and mid-October 1969, but thereafter rose continuously till the close of the year, reflecting a rising trend in mill consumption.

20. Prices of groundnuts showed a rise of 10.7 per cent over and above a sizeable rise of 91.8 per cent in the preceding year. The oilseeds group as a whole showed an increase of 13.6 per cent this year as against 58.7 per cent last year. The price index of raw jute and mesta showed a decline of 10.9 per cent over the year. But this decline over the year conceals the pressure on raw jute prices which started from mid-October 1969. Raw jute and mesta prices which rose sharply during 1968-69 recorded a precipitate fall from a high level of 200.6 on February 8, 1969 to 105.6 by October 11, 1969, in view of the prospects of a bumper raw jute crop during 1969-70. The declining trend was arrested and reversed following rising trends in jute goods production and the governmental measures to purchase at a minimum support price, raw jute through the S.T.C. Apart from rising mill demand, the scaling down of the estimates of raw jute crop for 1969-70 from the earlier expectation of 76 to 80 lakh bales to 67.5 lakh bales and the initial pessimistic outlook of the 1970-71 crop also helped to sustain the rising trend. Between mid-October 1969 and end-June 1970 the price index rose by 47.9 per cent from 105.6 to 156.2.

21. The other two important groups namely 'machinery and transport equipment' and 'manufactures' registered increase of about 8-9 per cent each, the prices of manufactured articles having been rising almost continuously throughout the year. The rise in manufactured articles reflected mainly substantial increases in wages granted to labour in two major industries, viz. jute textile and cotton textile, in August and October, 1969, respectively, and the rise in prices of industrial raw materials.

22. The All-India Consumer Price Index for Working Class (Base : 1960-100) recorded an increase of 3.9 per cent between June 1969 and June 1970 as against a rise of 1.1 per cent during the corresponding period last year.

23. The policy measures oriented towards strengthening of the technological base for accelerating productivity in agriculture were continued during 1969-70. The area covered under the High-Yielding Varieties Programme increased to 10.9 million hectares in 1969-70 from 9.2 million hectares in 1968-69. Like wise, the area under multiple cropping was sought to be increased from 6.07 million hectares in 1968-69, to 7.87 million hectares in 1969-70. Since the fulfilment of the targeted production under the new strategy depends on the timely and adequate availability of water, the accent on minor irrigation programme was continued and extended. Consequently, institutional investment on minor irrigation works was expected to be stepped up to Rs. 115 crores during 1969-70 from Rs. 106 crores in 1968-69. The establishment of Rural Electrification Corporation would further accelerate investment in minor irrigation schemes. The initiation of schemes for development of agriculture in dry farming regions and the progress made in setting up of Small Farmers' Development Agencies in selected districts were important agricultural policy measures taken during the year. The consumption of fertilisers, though increased to 2.1 million tonnes during 1969-70 from 1.8 million tonnes in 1968-69, fell short of the postulated annual increase of about 25 per cent. The slow-down in the rate of fertiliser consumption was due to a number of factors such as delay in the onset of monsoon in some parts of the country, application of doses lower than the recommended ones, lack of adequate distribution arrangements and a number of restrictive practices adopted by several States preventing free movement of fertilisers from factories to consuming points. With a view to stepping up fertiliser consumption, trading in fertilisers has been de-licensed. Further, the commercial banks have been advised to provide larger credit for stocking of fertilisers and to meet adequately the credit needs of farmers for purchase of fertilisers on more liberal terms. To induce agriculturists to step up their investment in agriculture and to reduce the risk of price fluctuations, Government continued its policy of fixing remunerative prices for procurement of foodgrains and of intensifying procurement operations. The system of fixing minimum support prices for major agricultural commodities was also continued.

24. Procurement of foodgrains during 1968-69 totalled 6.2 million tonnes consisting of 3.3 million tonnes of rice, 0.5 million tonnes of *kharif* coarse grains and 2.4 million tonnes of wheat

against the target of 7.9 million tonnes. Procurement of foodgrains till about the end of June 1970 was marginally lower at 5.6 million tonnes as against 5.8 million tonnes in the corresponding period last year. The target for *kharif* foodgrains procurement (1969-70) has been placed at 5.5 million tonnes and that for *rabi* grains (1970-71) at 3.7 million tonnes. Considering the progress made so far, it appears that the procurement of foodgrains during 1969-70 is likely to be of the same order as last year. In view of the improvement in domestic production, foodgrains imports were scaled down from 5.7 million tonnes in 1968 to 3.9 million tonnes in 1968. Imports of foodgrains during 1970 are likely to be reduced further to 3 million tonnes. Consequent on the increased open-market availability, the pressure on public distribution eased further; the quantity of foodgrains issued during 1969 amounted to 9.6 million tonnes as against 10.4 million tonnes in 1968. The stocks of foodgrains with Central and State Governments at the end of May 1970 stood at 4.7 million tonnes as against 5.0 million tonnes at the end of May 1969. Government stocks of foodgrains will continue to experience reduced pressure on account of withdrawal of statutory rationing in several towns and cities and the consequent reduction in the total population covered under statutory rationing from 25.6 million in 1968 to 22.6 million during 1969. As regards the informal rationing, the pressure is also not expected to be higher than last year because of somewhat larger availability of foodgrains.

25. The tight supply position of agricultural raw materials in relation to demand was sought to be overcome by larger imports. The raw cotton imports were sought to be stepped up from 4.3 lakh bales to over 8 lakh bales. Import programme of soyabean oil and other edible oils and fats was also stepped up. Further, to discourage the holding of excess inventories with the help of bank funds, the Reserve Bank tightened effective January 21, 1970 the selective credit controls on bank advances against the security of all oilseeds and vegetable oils, indigenous cotton as well foodgrains by stiffening the margin rates and reducing the ceilings on advances of individual banks against these commodities. The minimum rate of interest to be charged on advances against these commodities was fixed at 10 per cent. On April 28, this was raised to 12 per cent in respect of advances against oilseeds and cotton. The Bank also withdrew the ceiling rate of $9\frac{1}{2}$ per cent of interest on advances of scheduled banks. Simultaneously, the Textile Commissioner imposed a limit of $2\frac{1}{2}$ months' average monthly consumption on stocks of Indian cotton to be held in the cities of Bombay and Ahmedabad, 4 months' consumption in Assam and $3\frac{1}{2}$ months' consumption in other areas. However, higher stock limits were fixed in the case of mills exporting 20 per cent or more of their production or executing orders for defence purposes, Growers' Co-operative Spinning Mills and Mills under Authorised Controllers. Following further increases in prices, stock limits were reduced by one months' average consumption in all cases on February 17, 1970. In view of the sharp decline in raw jute prices which continued till about September and relative improvement in supply position, the Government of India abolished all production and purchase restrictions on jute mills from August 1969. Further, with a view to supporting raw jute prices, minimum purchase quotas by mills were introduced from September 1969 onwards.

26. With a view to stimulating industrial production, the Government continued to follow its policy of liberal imports so as to replenish the inventories of raw materials and components which were run down considerably and to ensure that production does not suffer for want of important imported raw materials and components. Industrials units exporting 25 per cent (instead of 10 per cent earlier) or more of their production were given greater preference in the matter of sources of supply. Besides, import substitution which too provided an impetus to many industries in recent years, has been carried a step further by banning the import of 159 items and by restricting import of 56 other items. The Budget for 1970-71 provided incentives to export-oriented industries by either reducing or abolishing export duties, and to import-substituting industries by raising the import duties on machinery, motor vehicle parts, pharmaceutical chemicals, non-electricals instruments, apparatus and appliances (However, some exception was made in the case of imported machinery required for initial setting up of projects or for substantial expansion of existing projects.)

27. In the case of industrial products upward revision of prices was granted so as to compensate for the increase in cost of production. A programme of improvement and renovation was

initiated in steel plants and balancing equipment is being installed in certain crucial sectors for orienting production to the changing demand pattern. With the completion of heavy engineering projects at Ranchi and the hydro-electrical plants at Tiruchi and Hyderabad, domestic production possibility for a significant proportion of the equipment needed for power generation and steel-making has been considerably improved. The Schemes for providing term finance assistance for production of capital goods and export of capital goods on deferred payment basis as also for the purchase of indigenous machinery on deferred payment basis initiated by the I.D.B.I. and the Reserve Bank were continued during the year under review.

28. To accelerate industrial development a firm and comprehensive policy of industrial licensing has been evolved. Under the new industrial licensing policy, there would be a list of core industries consisting of basic, critical and strategic industries in the economy. In addition to the core sector, all new investment propositions of over Rs. 5 crores would be deemed to be in the heavy investment sector. Except for industries reserved for the public sector, undertakings belonging to the larger industrial houses together with foreign concerns and subsidiaries or branches of foreign companies would be allowed to participate in and contribute to the establishment of industries in the core and heavy investment sector. In the middle sector involving investment ranging from Rs. 1 crore to Rs. 5 crores, licence applications of parties other than undertakings belonging to larger industrial houses would be given special consideration and licences would be issued liberally except where foreign exchange implications necessitate careful scrutiny. New undertakings or substantial expansion of units requiring investment of Rs. 1 crore or less will not be required to take a licence under the Act. The existing policy for the reservation of small-scale sector would be continued and the area of such reservation would be extended wherever this sector can be expected to meet the growth in demand adequately. As a result of this change in licensing policy and improving the administrative efficiency, it will be possible for industrial houses and newcomers to set up industries quickly and add to the production potential. Immediately after the close of the year under review, a number of licences have been granted to industrial houses in the private sector to expand their industrial capacity and augment their production particularly in the fields of chemical fertilisers, aluminium, freezers and chillers, caustic soda, calculating machines, jute carpet backing, bread and biscuit-making and canning machinery.

29. The Government established in March 1970 a separate Bureau of Industrial Costs and Prices which is expected to assist Government in the determination and revision of industrial prices and in watching cost-price behaviour in the industrial sector. Healthy industrial practices are also likely to be ensured through the provision of the Monopoly and Restrictive Trade practices Act, 1969 which came into effect from June 1, 1970.

Budgetary Operations@

30. The budgetary trends during the fiscal year 1969-70* were characterised by a slackening in the rate of growth of revenue receipts of Central and State Governments and a modest increase in the rate of growth in their revenue disbursements. The combined revenue receipts of the Centre and States which had increased by 11.1 per cent during 1968-69 rose by only 7.6 percent during 1969-70 (Table 5). The slower rate of growth in revenue receipts was attributable mainly to non-tax revenues. The growth rate in respect of non-tax receipts, worked out to 5.4 per cent in 1969-70 as against 19.2 per cent in 1968-69. The rate of growth in tax receipt showed a modest decline from 8.9 per cent in 1968-69 to 8.3 per cent in 1969-70 mainly due to the decline in revenue yield from custom (for the third year in succession) and from land revenue. The combined receipts of the Centre and States on capital account, however, increased by 18.5 per cent during 1969-70 as against a decline of 4.9 per cent during 1968-69.

@ All the amounts mentioned in this Section are in respect of the fiscal year (April-March) unless stated otherwise.

* All references to figures relating to 1969-70 represent revised estimates unless stated otherwise.

31. The rate of growth in revenue disbursements during 1969-70 (12.9 per cent) exceeded the growth in revenue receipts, though as compared with the growth rate in disbursements during 1968-69 (11.9 per cent), it was not significantly large. The increase during 1969-70 in revenue disbursements was shared both by developmental expenditure (13.4 per cent) and non developmental expenditure (13.3 percent).

32. In the case of Centre, developmental expenditure on revenue account showed a larger increase during 1969-70 (15.4 per cent) than non-developmental expenditure (8.3 per cent). However, in the case of States, non-developmental expenditure showed a faster rise (22.6 per cent) than developmental expenditure (13.0 per cent); a special factor for this was the substantial increase in the provision for famine relief expenditure by States affected by drought and floods. The provision for famine expenditure which had risen only moderately from Rs. 87 crores in 1967-68 to Rs. 90 crores in 1968-69 was stepped up to as much as Rs. 154 crores in 1969-70.

33. The combined disbursements of Centre and States on capital account increased by 12.9 per cent during 1969-70 as against a decline of 4.1 per cent during 1968-69.

34. As compared to budget estimates for 1969-70, aggregate disbursements of Centre increased by Rs. 221 crores to Rs. 5,776 crores in the revised estimates; aggregate receipts rose by Rs. 185 crores to Rs. 5,486 crores (Table 6). In the case of States, aggregate receipts at Rs. 4,790 crores in 1969-70 exceeded by Rs. 332 crores the budgeted amount, mainly on account of increase in transfer of resources from Centre (Table 7). Aggregate disbursements at Rs. 4,936 crores showed a smaller increase of Rs. 139 crores over budget provision; the increase was mainly under non-developmental items and loans and advances.

35. The budget estimates of Centre and States for 1969-70 had placed the overall deficit (as measured by the net increase in outstanding Treasury bills of Centre, withdrawal from cash balances of Centre and States, net sale of securities held by States in their cash balance investment account and net transfer from Revenue Reserve Funds of States) at Rs. 593 crores. The revised estimates for 1969-70 place the overall deficit at Rs. 436 crores as against the deficit of Rs. 274 crores in 1968-69. As compared to the budget forecast, the overall deficit of States declined from Rs. 339 crores to Rs. 146 crores and that of Central Government increased from Rs. 254 crores to Rs. 290 crores in 1969-70.

36. The deterioration in the case of the Centre and the improvement in the case of the States reflected, in part, the impact of the substantial increase in the quantum of resources transferred from Centre to States in the form of loans and divisible taxes over the budget estimates. The increase in the provision of loans to States was a sequel to the stepping up of loans to States affected by drought and floods, as well as provision of special assistance to States to cover the gap in their resources. The increase in divisible taxes followed mainly the implementation of the recommendations embodied in the final Report of the Fifth Finance Commission which was submitted in July 1969.

37. The strain on the resources of the Centre arising from the increase in loans to States and in 'States' share in divisible taxes was mitigated to a large extent by sizeable increases in non-tax revenue, internal market loans and miscellaneous items of capital receipts on the one hand, and savings in disbursements under development and defence items, in net interest payments and in grants to States, on the other.

38. The magnitude of the actual deficit of the Centre and States for 1969-70 is not yet available. However, an indication of the likely actual deficit is available in the amount of net Reserve Bank credit to Centre and States; such credit increased by Rs. 12.70 crores during the fiscal year 1969-70 as against increase of Rs. 241.89 crores in 1968-69. The net credit by Reserve Bank to Central Government increased by Rs. 81.16 crores during 1969-70 as compared to an increase of Rs. 128.63 crores during 1968-69; the net credit to States declined by Rs. 68.46 crores in contrast to an increase of Rs. 113.26 crores in the preceding year. Even so, some States had outstanding overdrafts with the Reserve Bank at the end of March 1970 though the level of total outstanding overdrafts was lower than at the end of March 1969.

Table 5—Combined Receipts and Disbursements of Central and State Governments

													(Rupees		Crores)	
					1968-69 (Accounts)			1969-70 (a) (Budget Estimates)			1969-70 (Revised Estimates)			1970-71 (a) (Budget Estimates)		
					Centre	States	Total	Centre	States	Total	Centre	States	Total	Centre	States	Total
I. Total Receipts (A+B)					4047	3051	7098	4434	3112	7546	4621	3265	7886	4691	3538	8229
					(—5.0)	(+23.5)	(+5.5)	(+9.6)	(+2.0)	(+6.3)	(+14.2)	(+7.0)	(+11.1)	(+1.5)	(+8.4)	(+4.3)
A. Revenue Receipts					2523	2322(b)	4845	2676	2380(b)	5056	2652	2564(b)	5216	2962	2850(b)	5812
					(+6.0)	(+17.3)	(+11.1)	(+6.1)	(+2.5)	(+4.3)	(+5.1)	(+10.4)	(+7.6)	(+11.7)	(+11.2)	(+11.4)
Of which :																
Tax Receipts					2019	1708(b)	3727	2197	1798(b)	3995	2110	1927(b)	4037	2390	2168(b)	4558
					(+4.2)	(+14.9)	(+8.9)	(+8.8)	(+5.3)	(+7.2)	(+4.5)	(+12.8)	(+8.3)	(+13.3)	(+12.5)	(+12.9)
B. Capital Receipts					1524(c)	729	2253	1758(c)	732	2490	1969(c)	701	2670	1729(c)	688	2417
					(—18.9)	(+48.8)	(—4.9)	(+15.4)	(+0.4)	(+10.5)	(+29.2)	(—3.8)	(+18.5)	(—12.2)	(—1.7)	(—9.4)
II. Total Disbursements					3742	3630	7372	4209	3930	8139	4251	4071	8322	4514	4077	8591
					(+1.1)	(+10.8)	(+5.7)	(+12.5)	(+8.3)	(+10.4)	(+13.6)	(+12.1)	(+12.9)	(+6.2)	(+0.1)	(+3.2)
Of which :																
Developmental					817	2110	2927	1047	2300	3347	1020	2317	3337	1152	2472	3624
Outlay (a+b)					(+9.2)	(+17.5)	(+15.1)	(+28.2)	(+9.0)	(+14.3)	(+24.8)	(+9.8)	(+14.0)	(+12.9)	(+6.7)	(+8.6)
(a) Revenue					318	1595	1913	373	1839	2212	367	1803	2170	425	1912	2337
(b) Capital					(+12.4)	(+16.5)	(15.8)	(+17.3)	(+15.3)	(+15.6)	(+15.4)	(+13.0)	(+13.4)	(+15.8)	(+6.0)	(+7.7)
(b) Capital					499	515	1014	674	461	1135	653	514	1167	727	560	1287
					(+7.3)	(+20.9)	(+13.8)	(+35.1)	(—10.5)	(+11.9)	(+30.9)	(—0.2)	(+15.1)	(+11.3)	(+8.9)	(+10.3)
Plan Outlay							2361(d)			2271(d)			2239(d)			2637 (d)
							(+7.1)			(—3.8)			(—5.2)			(+17.8)
Non-developmental Outlay (a+b)					174	1003	2757	2048	1100	3148	2095	1184	3279	2158	1115	3273
					(—14.2)	(—4.7)	(—8.2)	(+16.8)	(+9.7)	(+14.2)	(+19.4)	(+18.0)	(+18.9)	(+3.0)	(—5.8)	(—0.2)
(a) Revenue					1825	993	2818	1953	1124	3077	1976	1217	3193	2042	1157	3199
					(+7.7)	(+10.6)	(+8.7)	(+7.0)	(+13.2)	(+9.2)	(+8.3)	(+22.6)	(+13.3)	(+3.3)	(—4.9)	(+0.2)
(b) Capital					—71	10	—61	95	—24	71	119	—33	86	116	—42	74
						(—83.3)								(—2.5)		(—14.0)
III. Overall Surplus (+) or Deficit (—)																
(I—II)					+305	—579	—274(e)	+225	—818	593(e)	+370	—806	—436(e)	+177	—539	—362(e)

Notes :—(i) Figures are adjusted for inter-governmental transfers and hence differ from those given in budget papers and in Table 6. The combined overall position, however, remains unchanged.

(ii) Figures in brackets indicate per cent increase (+) or decrease (—) over the previous year.

(a) Includes effects of budget proposals.

(b) Includes States' share in Central taxes.

(c) Excludes Treasury bills receipts (net).

(d) Comprises Plan outlay of Centre, States and Union Territories.

(e) As measured by the net increase in outstanding Treasury bills of Centre, withdrawal of cash balances of Centre and States, net sales of securities held by States in their cash balances investment account and net transfer from revenue reserve funds of States.

Table 6—Overall Budgetary Position of Centre

								(Rupees Crores)		
								1969-70 (Budget Estimates)	1969-70 (Revised Estimates)	1970-71* (Budget Estimates)
I. Aggregate Receipts (A + B)								5301	5486	5450
A. Revenue Receipts								2957	2924	(5573)
of which :										3118
Tax Revenue								2196	2110	(3241)
B. Capital Receipts								2344	2562	2267
of which :										(2390)
Internal Loans (Gross)								500	535	2332
External Loans (Gross)								850	714	455
II. Aggregate Disbursements								5555	5776	5800
of which :										
(a) Developmental Outlay								1047	1020	1152
(b) Non-Developmental Outlay								2048	2095	2158
(c) Discharge of Internal Loans								394	394	293
(d) Discharge of External Loans								208	180	200
III. Overall Deficit (I—II)								254	290	350
										(227)

Note :—Figures of receipts and disbursements in this Table do not agree with those in Table, 5 because of adjustments for inter-governmental transfers.

*Figures in brackets are after taking into account the estimated yield from additional tax measures.

Table 7—Overall Budgetary Position of States

								(Rupees Crores)		
								1969-70 (Budget Estimates)	1969-70 (Revised Estimates)	1970-71* (Budget Estimates)
I. Aggregate Receipts (A + B)								4458	4790	4755
A. Revenue Receipts (i+ii)								2934	3131	(4824)
of which :										3315
(i) States' own Revenue Receipts								1863	1953	(3384)
(ii) Resources transferred from Centre (a + b)								1071	1178	2099
(a) Shared Taxes								517	611	(2123)
(b) Grants from Centre								554	567	1216
B. Capital Receipts (i+ii)								1524	1659	(1261)
(i) States' own Capital Receipts								732	701	682
of which :										(727)
Market Borrowing (Gross)								145	177	534
(ii) Loans from Centre (Gross)								792	958	1440
II. Aggregate Disbursements								4797	4936	4959
of which :										
(a) Developmental Outlay								2300	2317	2472
(b) Non-Developmental Outlay								1381	1456	1394
(c) Repayment of Loans to Centre								586	593	603
(d) Loans & Advances to third Parties								378	433	381
(e) Repayment of Market Loans								89	89	62
III. Overall Deficit								339	146	204
										(135)

Note :—Figures of receipts and disbursements in this Table do not agree with those in Table 5 because of adjustments for inter-governmental transfers.

*Figures in brackets are after taking into account estimated yield from additional tax measures.

39. In the period March 31 to June-end (last Friday) 1970, net Reserve Bank credit to Government sector declined by Rs. 89 crores compared to a decline of Rs. 7 crores in the corresponding period of 1969. Net Reserve Bank credit to Central Government declined by Rs. 10 crores during March 31 to June-end 1970 (in contrast to an increase of Rs. 185 crores during March 31 to June-end 1969) and to State Governments by Rs. 79 crores (compared to a decline of Rs. 192 crores in the corresponding period last year).

40. The Union budget for 1970-71 was framed against the background of favourable economic conditions which permitted a vigorous effort to stimulate economic growth. The overall rate of growth in income in 1969-70, the first year of the Fourth Five-Year Plan, is anticipated to be of the order of 5 to 5.5 per cent (as constant prices)—the same as projected for the Fourth Five-Year Plan period. To sustain the pace of growth, the budget has considerably, stepped up the provision for developmental outlay, particularly that resulting in capital formation. The budgetary provision for gross capital formation shows a step-up of about 13 per cent over 1969-70. On the other hand, consumption expenditure is estimated to rise by 5 per cent over 1969-70 as against a rise of 7.2 per cent in 1969-70 over 1968-69 reflecting the Government's policy to keep such increases within reasonable limits. As a result, savings of Government Administration as a per cent of revenue receipts are expected to increase from 2.9 in 1969-70 to 7.6 in 1970-71. Net savings of Government, including savings of departmental commercial undertakings, are expected to finance 66.4 per cent of net investment of Government and departmental and commercial undertakings in 1970-71 as against 33.9 per cent in 1969-70. The budgeted pattern of outlay reflects the concern of the Government not only for growth with stability but also for the well-being of the needy and the poor sections of the community; towards the latter objective, provision has been made for specific programmes directed towards small farmers and agricultural labour, rural water supply schemes, nutritional programmes for children, social security benefits for industrial workers and Government employees in particular.

41. The aggregate receipts on revenue and capital accounts for 1970-71 (including yield from Additional tax measures) are estimated at Rs. 5,573 crores, showing an increase of Rs. 87 crore (1.6 per cent) over 1969-70. As aggregate disbursements are placed at Rs. 5,800 crores, showing a smaller increase of Rs. 24 crores (0.4 per cent) over 1969-70 the overall deficit is estimated to be Rs. 227 crores—lower by Rs. 63 crores than the deficit of Rs. 290 crores for 1969-70. The overall deficit is expected to form 3.9 per cent of total disbursements in 1970-71 as compared to 5.0 per cent in 1969-70.

42. For 1970-71, States have budgeted for aggregate receipts on revenue (at 1969-70 rates of taxation) and capital accounts at Rs. 4,755 crores, which are lower than in 1969-70 by Rs. 35 crores (0.7 per cent). This decline is the net result of an expected fall in the aggregate quantum of transfer of resources, from the Centre to States and an increase in States' own resources. Aggregate disbursements at Rs. 4,959 crores are higher by Rs. 23 crores than in 1969-70. Whereas developmental expenditure has been stepped up by Rs. 155 crores (6.7 per cent), non-developmental expenditure has been reduced by Rs. 62 crores (4.3 per cent) and loans and advances by Rs. 52 crores (12.0 per cent). Own resources of States will finance 56.2 per cent of total disbursements in 1970-71 as compared to 53.8 per cent in 1969-70. The budgeted overall deficit at Rs. 204 crores is Rs. 58 crores more than in 1969-70. The overall deficit is made up of a surplus of Rs. 15 crores on revenue account and a deficit of Rs. 219 crores on capital account. To meet a part of the overall deficit, States have proposed additional tax measures estimated to yield Rs. 24 crores in 1970-71. To this should be added States' share of Rs. 45 crores in the yield from additional tax measures introduced by the Centre and the improvement of Rs. 2 crores over the budget estimates in the actual market borrowings of the State Governments. These would reduce the overall budgeted deficit to Rs. 133 crores. Further, in respect of shared taxes, grants-in-aid and loans from the Centre, the credit taken in the State budgets is lower by Rs. 171 crores than that provided in the Central Government budget. Making allowance for this factor the budgetary position of the State Governments would indicate an overall surplus of Rs. 38 crores during 1970-71 as against an overall deficit of Rs. 146 crores in 1969-70.

43. Reference was made in last year's Report to the presentation to the Parliament of the revised draft of the Fourth Five-Year Plan, 1969-70 to 1973-74. The final document of the Plan was presented to Parliament on May 18, 1970. The final version bears the imprint of the Government's new socio-economic policies and embodies the objectives of growth with stability and social justice. The total outlay in the final Plan has been raised by Rs. 484 crores—from Rs. 24,398 crores in the draft Plan to Rs. 24,882 crores. While the share of the public sector in total outlay has been stepped up by Rs. 1,504 crores—from Rs. 14,398 crores (59 per cent) to Rs. 15,902 crores (64 per cent), the share of private sector has been reduced by Rs. 1,020 crores—from Rs. 10,000 crores (41 per cent) to Rs. 8,980 crores (36 per cent).

44. Of the total public sector outlay of Rs. 15,902 crores, the outlay for the Centre (including Union Territories and Centrally sponsored schemes) and the States at Rs. 9,296 crores and Rs. 6,606 crores, respectively, are higher than the outlays (Rs. 8,332 crores and Rs. 6,606 crores, respectively) provided in the draft Plan.

45. The public sector outlay comprises Rs. 13,655 crores of investment and Rs. 2,247 crores of current expenditure. Sector-wise, the shares of outlays on agriculture and allied sectors (including irrigation and flood control) and power projects are now slightly higher at 24 per cent and 16 per cent respectively, as against 22 per cent and 14 per cent of the total outlay in the draft Plan. On the other hand, the shares, of outlays on industries and minerals, transport and communications and social services are somewhat lower at 21 per cent, 20 per cent and 16 per cent, respectively, as against 22 per cent each on industries and minerals, and transport and communications and 17 per cent on social services provided in the draft Plan. The miscellaneous items claim the remaining three per cent of the outlay, almost the same as in the draft Plan.

46. The increased outlay in the public sector has been made possible by the expected improvement in budgetary resources (at 1968-69 rates of taxation) from Rs. 10,839 crores in the draft Plan to Rs. 11,854 crores and an upward revision in the target of additional mobilisation from Rs. 2,709 crores to Rs. 3,198 crores—Rs. 2,100 crores by Central Government and Rs. 1,098 crores by State Governments—in the final Plan. The quantum of deficit financing is retained at the level of Rs. 850 crores envisaged in the draft Plan. The pattern of financing the public sector outlay is indicated in Table 8.

47. The Plan outlay of the public sector for 1969-70 is placed at Rs. 2,239 crores as against Rs. 2,361 crores in 1968-69, a decline of Rs. 122 crores (5.2 per cent). For 1970-71, the Plan outlay is placed at Rs. 2,637 crores, an increase of Rs. 398 crores or 18 per cent over the outlay for 1969-70. The aggregate outlays during the first two years thus work out to 31 per cent of the total public sector outlay estimated for the Fourth Plan. The outlays are projected at 1968-69 prices in the Plan document. However, there has been a rise of 4.0 per cent in 1969-70 (April-March) in the whole sale price index (Base : 1961-62=100). This would reduce the Plan outlays in real terms.

48. The measures of additional mobilisation (including changes in postal tariffs and in railway passenger fares and freights) undertaken by the Central Government are estimated to yield Rs. 202.5 crores during 1970-71. This comprises Rs. 168.3 crores on account of tax measures (including States' share), Rs. 26 crores on account of upward revision of railway fares and freights and Rs. 8.2 crores on account of changes in postal and telegraph tariffs made in 1970-71. The yield next year is estimated higher at Rs. 223.5 crores since some of the modifications, in respect of income and wealth taxes will become fully effective from 1971-72. The tax measures proposed by States in 1970-71 are estimated to yield Rs. 23.7 crores during 1970-71 and Rs. 26.0 crores in a full year. The additional mobilisation undertaken by the Centre (including Railways and Posts and Telegraphs) and States during 1969-70, the first year of the Fourth Plan, was estimated to yield Rs. 176.9 crores in a full year. All these measures of additional mobilisation may be expected to yield around Rs. 1,850 crores—Rs. 1,519 crores by Centre and Rs. 331 crores by State Governments—during the five years of the Plan (or 57.8 per cent of the target).

Table 8—Estimates of Resources for The Fourth Plan
(1969-74)

	Draft Plan		Final Plan	
	Amount	Per cent to total	Amount	Per cent to total
I. Budgetary Resources at 1968-69 rates of taxation (1+2)	10,839	75.3	11,854	74.5
1. Domestic Budgetary Resources (i to x)	8,325	57.8	9,240	58.1
(i) Balance from Current Revenues	2,455	17.1	1,673	10.5
(ii) Contribution of Public Enterprises	1,730	12.0	2,029	12.8
(iii) Retained Profits of Reserve Bank	165	1.1	202	1.3
(iv) Market Borrowings of Central and State Governments (net)	1,166	8.1	1,415	8.9
(v) Borrowings by Financial Institutions including F.C.I.	—	—	405	2.5
(vi) Small Savings	800	5.6	769	4.8
(vii) Annuity Deposits, Compulsory Deposits, Prize Bonds and Gold Bonds	—104	—0.7	—104	—0.7
(viii) State Provident Funds	640	4.4	660	4.2
(ix) Miscellaneous Capital Receipts (net)	1,130	7.8	1,685	10.6
(x) Loans from L.I.C., etc. and State Enterprises' Market Borrowings (gross)	343	2.4	506	3.2
2. External Assistance (net)	2,514	17.5	2,614	16.4
II. Additional Resource Mobilisation	2,709	18.8	3,198	20.1
III. Deficit Financing	850	5.9	850	5.4
IV. Aggregate Resources for the Plan (I+II+III)	14,398	100.0	15,902	100.0

Source : Planning Commission, Government of India, Fourth Five-Year Plan (1969-74)—Draft and Final.

49. The tax measures of the Centre for 1970-71 are designed to achieve greater equality of income and wealth, restrain consumption, check speculative increases in urban land values and plug loopholes in tax laws which facilitate avoidance of tax. The budget also contains certain measures to liberalise the incentives for savings and investment. Of the total yield of Rs. 168.3 crores for 1970-71 from the additional tax measures, proposals in regard to Union excise duties account for Rs. 133.3 crores or nearly 80 per cent. The proposals in regard to Union excise duties are confined by and large, to final consumer goods and are so designed as to safeguard, to the extent possible, the consumption of the poor sections of the community. The policy of conversion of specific rates of Union excise duties into *ad valorem* rates initiated in the previous budget has been carried further. In regard to income tax, the marginal rates of tax chargeable on incomes in the slabs over Rs. 40,000 have been stepped up; relief is provided to low income groups by increasing the basic exemption limit and by extending the system of deductible allowances to assesses using public conveyances for the purpose of employment. In respect of the wealth-tax (including additional wealth-tax on urban lands and buildings) the slab rates have been raised. While the rates structure of corporate taxation has not been changed, provision has been introduced to disallow expenditure on entertainment and on maintenance of guest houses in computing taxable income.

50. Concessions for savings and investment have been further liberalised. The amount of exemption for purposes of income tax in respect of dividend and interest incomes from certain investments has been raised from Rs. 2,000 to Rs. 3,000; the choice of assets has also been widened. The amount of exemption for the purpose of wealth-tax has also been raised from Rs. 1.2 lakhs to Rs. 1.5 lakhs. The category of financial assets qualifying for such exemption has been widened to include among others, deposits in banking companies, State Financial Corporations and Co-operate Banks,

Government securities and company shares.

51. Nine States, namely, Assam, Gujarat, Jammu and Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Mysore, Nagaland, Orissa and Tamil Nadu have proposed additional measures; Rajasthan and Uttar Pradesh have proposed measures to raise additional revenue as well as concessions. Bihar and West Bengal, on the other hand, have announced tax concessions. In the net, additional measures are expected to yield Rs. 23.7 crores in 1970-71 and Rs. 26.0 crores in a full year as against the estimated yield of Rs. 38.3 crores (Rs. 47.8 crores in a full year) in 1969-70 from fresh measures (including post-budget measures).

52. The response to the market borrowing programme of the Centre and States during the financial year 1969-70 was satisfactory. The combined net receipts during the year amounted to Rs. 224 crores which is Rs. 72 crores more than the net amount raised (Rs. 152 crores) in 1968-69.

53. The Centre's borrowing programme during 1969-70 was completed in two phases as in the earlier year. The 5½ per cent 1999 Loan floated on April 30, 1969, for an amount of Rs. 250 crores, brought in Rs. 275 crores—Rs. 107 crores in cash and Rs. 168 crores by conversion. The 4½ per cent Loan 1976 issued on July, 1, 1969 for Rs. 250 crores yielded Rs. 260 crores (Rs. 99 crores in cash and Rs. 161 crores by conversion). After providing for cash repayments (Rs. 65 crores) on account of maturing loans not tendered for conversion, net market borrowings of the Centre in 1969-70 amounted to Rs. 141 crores — Rs. 60 crores more than in 1968-69.

54. On September 1, 1969, fifteen State Governments issued 5½ per cent Development Loans maturing in 12 years for an aggregate amount of Rs. 155 crores. While two Loans were issued at par, all the others were issued at a discount of 50 paise (i.e., at an issue price of Rs. 99.50). Maturing loans of 12 States amounting to Rs. 88 crores were offered for conversion into their respective loans. All the loans were over-subscribed; the over-subscription in most cases exceeding 10 per cent of the notified amount. Subscriptions accepted after partial allotment amounted to Rs. 171 crores; cash subscriptions amounted to Rs. 125 crores and conversion to Rs. 46 crores. Net borrowings after providing for repayment in cash of unconverted portion of maturing loans (Rs. 42 crores), amounted to Rs. 83 crores as against Rs. 70 crores in 1968-69.

55. Of the total net market borrowings of Rs. 244 crores by the Central and State Governments during 1969-70 the initial intake of securities by the public (i.e., investors other than the Reserve Bank of India and State Governments) amounted to Rs. 161 crores (72.0 per cent of total net borrowings) in 1969-70 as against Rs. 98 crores (64.5 per cent of total net borrowings) in 1968-69. The net open market sales of securities by the Reserve Bank to public showed a decline from Rs. 88 crores in 1968-69 to Rs. 18 crores in 1969-70. The net absorption of securities by the public during the financial year 1969-70 thus amounted to Rs. 179 crores (80.0 per cent of total net borrowings) as against Rs. 186 crores in 1968-69 (122.3 per cent of total) and Rs. 145 crores (89.5 per cent of total) in 1967-68.

56. The gift-edged market continued to rule steady throughout the year (July 1969—June 1970) as a result of institutional support. The All-India Index for Government and Semi-Government Securities (base : 1961-62=100) rose marginally to 99.3. While the index for Central Government securities remained more or less steady around 98.9, those of State Government securities and semi-Government securities rose by about one point and two points, respectively, to 100.5 and 101.3. This relative improvement in these securities is attributable to banks, support to long-term trustee securities issued by bodies like Electricity Boards, Industrial Finance Corporation, etc. following the Reserve Bank's directive to banks on the eve of the 1969 slack season requiring them to deploy their resources for investment in these securities so as to help revive demand for several capital goods industries and give added impetus to agricultural output and industrial development. Besides, Bank's open market policy continued to be directed towards maintaining orderly and active trading conditions in the market and alignment of yield pattern to the general structure of interest rates. Purchases and sales of securities during the accounting year aggregated Rs. 315.3 crores and Rs. 345.3 crores, respectively, resulting in net sales of Rs. 30.0 crores as compared to Rs. 53.4 crores in the preceding year.

57. The budget of the Central Government for 1970-71 has taken credit for gross internal borrowings of Rs. 455 crores as against Rs. 535 crores (gross) raised during 1969-70*. As loans maturing in 1970-71 are smaller at Rs. 293 crores than in the previous year (Rs. 394 crores), net receipts at Rs. 162 crores would be higher than during 1969-70 (Rs. 141 crores) by Rs. 20 crores. In the first phase of its borrowing programme, the Central Government issued on April, 11 1970, the 5½ per cent Loan, 2000, at par for an amount of Rs. 275 crores. The 4 per cent Loan 1970 was offered for conversion. The subscriptions amounted to Rs. 290 crores, the whole of which was retained; of this Rs. 150 crores were in cash and Rs. 140 crores in conversion. Allowing for cash repayment (Rs. 38 crores) in respect of the maturing loan not tendered for conversion, net market borrowings from this loan would amount to Rs. 112 crores, or nearly 70 per cent of the budgeted amount, leaving Rs. 50 crores to be raised during the remaining part of the current fiscal year.

58. On July 1, 1970, fifteen State Governments announced the issue at par of 5½ per cent Development Loans maturing in 12 years for an aggregate amount of Rs. 142.50 crores. Maturing loans of State Governments (with an outstanding amount of Rs. 56.91 crores) were offered for conversion into the new loans of the respective State Governments. Total subscriptions aggregated Rs. 164 crores—Rs. 131 crores in cash and Rs. 33 crores by way of conversion; all the loans were oversubscribed. Subscription after partial allotment amounted to Rs. 157 crores. Allowing for cash repayment (Rs. 24 crores) on account of maturing loans not tendered for conversion, net market borrowings of States would amount to Rs. 100 crores, Rs. 17 crores more than in 1969-70.

59. Net collections of small savings during the fiscal year 1968-70, according to provisional figures, are placed at about Rs. 129 crores (including Rs. 5 crores from the new schemes introduced since March 16, 1970), exceeding the collections during the preceding year by Rs. 16 crores; these are lower than the budget estimates for 1969-70 by Rs. 6 crores. For 1970-71, the Union budget has taken credit for Rs. 140 crores under small savings. The budget embodied a number of incentives to promote small savings. These incentives include enhancement of the rates of interest (free of income tax) on certain existing media and introduction of new media bearing higher (taxable) rates of return. The new small savings media are post office time deposits, and recurring deposit schemes (carrying interest subject to income tax), 'blocked' savings accounts in post offices (carrying interest free of income tax) and the 7-Year National Savings Certificates II, III (carrying interest free of income tax) and IV issues (carrying interest subject to income tax). The 10-Year Defence Deposit Certificates and 12-Year National Defence Certificates (carrying interest free of income tax), and the 10-Year National Savings Certificates (carrying interest subject to income tax) have been discontinued.

60. Net receipts from the Public Provident Fund Scheme estimated at Rs. 5 crores in the 1969-70 budget are placed at Rs. 2 crores in the revised estimates; actual collections, however,

amounted to about Rs. 1.6 crores (provisional), as compared with about Rs. 1 crore in 1968-69. In 1970-71, Rs. 5 crores are expected from this source.

Private Corporate Sector

61. Although the investment climate improved as a result of tax concessions provided by the last three Central budgets, the investment activity in the private corporate sector did not show significant increase over the preceding year. The stagnation in public sector investment expenditure on industrial projects and the difficulty in making necessary arrangements for foreign exchange finance in the absence of a clear picture about the project assistance were mainly responsible for the lack of a significant pick-up in investment activity in the private corporate sector. The equity prices which suffered a sharp set back after the imposition of the ban on forward trading in securities towards the close of last year (July 1968—June 1969) recovered much of their lost ground and tended to froge ahead following substantial tax concessions granted to investments in stocks and shares.

62. Corporate performance improved during 1969-70. A preliminary study of the dividend announcements by public limited companies shows that of the 520 public limited companies which closed their accounts between April-December 1969, 164 or 32 per cent of companies raised the dividend rates and another 156 or 30 per cent paid the same rates as in the previous year. Of the remaining 200 companies, 63 companies or 12 per cent reduced their dividends as against 98 companies or 19 per cent last year. The number of companies paying 'nil' dividends was lower at 137 as compared with 149 last year. In regard to the actual dividend rates* there was also a marked increase in the number of companies paying dividends between 6 and 10 per cent from 132 (25 per cent) in 1968-69 to 157 (30 per cent) in 1969-70. In the higher dividend ranges also, there was a larger number of companies this year relatively to last year.

63. Consents/acknowledgements of proposals accorded to non-government public limited companies for capital issues in the form of shares (excluding bonus) and debentures were substantially higher during 1969-70 (July-June) at Rs. 89.1* crores as against Rs. 59.5 crores in 1968-69 (July-June). Consents for 'initial' issues increased to Rs. 19.5 crores from Rs. 11.3 crores in the previous year, and consents for 'further' issues increased to Rs. 69.6 crores from Rs. 48.2 crores. Security-wise, consents for equity issues at Rs. 43.4 crores were substantially higher by Rs. 17.7 crores and those for debenture issues were similarly higher at Rs. 37.8 crores as compared with Rs. 23.9 crores in 1969-70. Consents for preference shares decreased to Rs. 7.8 crores from Rs. 9.9 crores. Consents for bonus issues by non-government public limited companies amounted to Rs. 45.6 crores in 1969-70 as compared with Rs. 17.8 crores in 1968-69. With a view to protecting the interest of the general investors, the Government issued new guidelines for issue of bonus shares, important among which are : (a) bonus issues are not to be permitted in lieu of dividend, (b) there should be a time lag of at least 18 months between two bonus issue announcements and (c) not more than two bonus issues should be allowed to a company over a period of 5 years.

64. The new capital issue activity recovered during July 1969—June 1970* and the total amount issued through both prospectus and rights to rose Rs. 75.8 crores* from Rs. 57.8 crores in 1968-69. The rise was mainly in equity and preference issues which was accompanied by a slight increase in debenture issues. Initial issues spurted up to Rs. 22.5 crores from a low level of Rs. 10.4 crores in 1968-69. The public response to capital issues indicated a definite improvement, some of the issues having been over-subscribed to a large extent. The institutional investors continued to provide the underwriting support but due to better public response the proportion of the amount devolving on underwriters declined to 27 per cent in 1969 from 38 per cent in the previous year.

65. The movements in equity prices in the major stock exchanges fall broadly into two phases, the first phase covering the period July 1969 to mid-February 1970 and the second-phase from mid-February to June 1970. In the first phase, equity prices declined sharply following the imposition of ban

*Preliminary date

on forward trading in shares in the last week of June 1969. The apprehensions in some quarters regarding curbs on flow of credit to the private sector following the nationalisation of 14 major commercial banks and strikes in jute textiles and certain other industries were other contributory factors. The Reserve Bank's All-India Index of Prices of variable Dividend Industrial Securities (base : 1961-62=100) was marked down from the end-June 1969 level of 99.3 to 89.2 by mid-August. After a short-lived recovery lasting upto mid-October on account of reports of purchase of shares by institutional investors, good corporate news and shortage of good floating scrips, the stock prices resumed their downward trend as the expectations regarding early resumption of forward trading in shares did not materialise. There was a strike in protest against ban on forward trading in shares from December 4 to 18 in stock exchanges of Bombay, Calcutta, Delhi and Ahmedabad. The index dropped to the lowest level of the year at 87.3 in the first week of February 1970. In the second phase, with the announcement (i) on February 7, 1970 of the appointment of an expert committee to re-examine the possibilities regarding the forward trading in shares and (ii) on 14th February of higher compensation for renationalised banks, stock prices tended to move up. This recovery was accelerated further by the proposals of the Central budget for 1970-71 to maintain the corporate tax structure unchanged so as to provide stable climate for investment decisions and to raise the combined income-tax exemption limit to Rs. 3,000 for income arising from investments in units of the Unit Trust of India, shares of Indian companies, Government securities, rural debentures and bank deposits. With the renewed buoyancy, equity prices gradually rose to 100.6 by June end—a level higher than 99.3 as at the end of June, 1969.

66. Financial assistance sanctioned by the term-lending institutions* during 1969-70 (April-March) and their disbursements recorded a rise as compared with their levels in the previous year owing mainly to an increase in the assistance of SFCs to the small-scale industrial sector. Aggregate financial assistance sanctioned by all the institutions in form of loans, underwriting of and direct subscriptions to shares and debentures was higher at Rs. 149.9 crores @ in 1969-70 (April-March) than at Rs. 132.3 crores in 1968-69. Disbursements were also higher at Rs. 114.0 crores† in 1969-70 as compared with Rs. 85.8 crores in the preceding year. The Industrial Development Bank sanctioned loans‡ amounting to Rs. 50.2 crores @ during 1969-70 as against Rs. 46.1 crores in 1968-69 and its disbursements were substantially higher at Rs. 43.3 crores @ in 1969-70 as against Rs. 27.4 crores in the previous year.

67. The underwriting and investment operations of the Unit Trust of India and the Life Insurance Corporation lent considerable support to the private corporate sector. In the previous year the Life Insurance Corporation sanctioned Rs. 14.4 crores for the underwriting of and direct subscriptions to shares and debentures. The Unit Trust of India also sanctioned underwriting of and direct subscriptions to the shares to the extent of Rs. 10 crores** in 1969-70 which was almost at the same level as in the previous year. The Credit Guarantee Scheme for the small-scale industries recorded substantial progress. The amount of outstanding guarantees at the end of March 1970 stood at Rs. 535.9 crores as against Rs. 240.9 crores on June 30, 1969. Procedures for extension of assistance in the form of guarantee under the Scheme were further streamlined by the Government so as to expedite the flow of credit to small-scale industries.

68. Except for temporary spells of easiness in the beginning of the year under review, between mid-December 1969 and mid-January 1970, and again towards the end of the year, the silver section in the Bombay bullion market remained, on the whole, firm following reports of larger unauthorised exports and higher overseas advices. The quotation rose from Rs. 457 per Kg. as at the end of June, 1969, after temporary fluctuations, to a high of Rs. 526 by April, 1970. Thereafter the quotation hovered between Rs. 499 and Rs. 524.50, till May-end 1970 before closing for the year at Rs. 504. At this level the price showed a net gain of Rs. 47 per Kg. over the year.

69. In the international market, Silver ruled firm during the greater part of the year owing to improved outlook of demand for silver following the introduction of a bill in the U.S. Senate to mint Eisenhower Memorial Coins but towards the end of year heavy speculative selling pressure erased a

good part of the gains made earlier. The quotation after touching 200 cents in November closed for the year at 161.2 cents as against the closing quotation of 156 cents as on June 30 last year.

70. In the Bombay bullion market the easiness in gold prices noticed towards the close of last year proved temporary. The prices again firmed up following the promulgation of Gold Control (Amendment) Ordinance on July 3, 1969, replaced subsequently by the Gold Control (Amendment) Act, 1969 on August 29, 1969. The price of standard gold moved up steadily from the June-end level of Rs. 167.50 per ten grams to Rs. 184 by August 25, 1969 and after fluctuating between Rs. 177.75 and Rs. 183 in September rose almost continuously to reach a high of Rs. 186.56 per ten grams on the eve of the Dussera day (October 18, 1969). This firmness continued till end-November, the price of gold moving narrowly between Rs. 181 and Rs. 185 per ten grams. Following the reports in early December of a slump in the international price of gold the rising trend received a set-back and the price eased to Rs. 170 per ten grams by December 10, 1969 and continued to rule easy till early February 1970. This spell of easiness came to an end as a result of reported decline in the supply of standard gold in the market following the introduction of new measures by the mint authorities requiring the disclosure of identity of the sellers of gold ornaments brought for refining. The price of standard gold shot up to a new high of Rs. 192 on February 24, 1970. Although subsequently the price was not maintained at this high level the firmness was sustained throughout the rest of the year owing to seasonal demand for gold. Barring a temporary decline to Rs. 183.50 on March 18, and again on April 4, 1970, the quotation moved within a narrow range of Rs. 184 and Rs. 191.50 before closing for the year at Rs. 185.50. At this level, the quotation showed a net rise of Rs. 18 per ten grams over the year.

71. In the international free market for gold, the most striking development was the complete alignment of the free market price with the official price of gold. Several factors contributed to the forging of this alignment : (i) the continued sales of gold by South Africa to meet its balance of payments deficit, (ii) the devaluation of the French franc on August 8, and revaluation of the Deutsche Mark on October 24, (iii) the improvement in the United Kingdom's balance of payments position and (iv) the ratification of Special Drawing Rights Scheme in early October. These developments sparked off heavy speculative selling pressure as a result of which the free market price of gold slumped to \$ 35 per ounce by December 9, 1969 and continued to remain around that level till the close of the year.

Investment Finance for Agriculture

72. Finance for investment in agriculture provided by institutional agencies showed considerable increase during the last two years (Table. 9). This was largely the result of substantially higher level of loan commitments and disbursements by the Agricultural Refinance Corporation and ordinary debentures floated by co-operative land development/mortgage Banks during the last two years. The number of schemes sanctioned and the total disbursements by the Agricultural Finance Corporation Ltd. also increased considerably during 1969-70.

73. The year witnessed the setting up of the Rural Electrification Corporation Ltd. in July 1969. The Corporation was set up with a view to stepping up the pace of rural electrification through: (i) financing rural electrification schemes in priority areas, (ii) subscribing to special rural electricity bonds to be issued by electricity boards and (iii) providing block capital loans to rural electric co-operatives to be organised in different States. The Corporation started functioning in January 1970. Allocations made by it will be additive to the normal provisions available. Its involvement, though modest now, is likely to grow in view of its crucial role in accelerating rural electrification programmes in the country. Its resources would also increase to the extent of Rs. 150 crores as a result of the provision made in the Fourth Plan.

* IDBI, IFCI, ICICI, SFCs and SIDCs.

@ Provisional.

† Including disbursements on account of guarantees.

‡ Including refinance to banks and rediscounts.

** Preliminary data.

Table 9—Investment finance for agriculture

(Rupees crores)																
Year (July-June)	Debtures floated by Central Co-operative		Agricultural Refinance Cor- poration (ARC)				Refinance Corpora- tion (AFC)				Rural Electrification Corporation (REC)				Reserve	Bank of India
	Land Mortgage Development Banks		No. of schemes**	Total outlay	ARC's commit- ments	Disbur- sements during the year	No. of schemes sanc- tioned	Total outlay	AFC'S commit- ments†	Disbur- sements during the year	No. of schemes sanc- tioned	Total outlay	REC's commit- ments	Disbur- sements during the year	Medium-Term Loans	
	Ordi-	Rural de-													Amount sanctioned	Drawals during the year
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1960-61	9.97	1.55											4.68	5.69
1961-62	10.50	2.38*											9.56	7.39
1962-63	19.25	1.57											9.31	4.18
1963-64	23.34	1.84	3	2.23	2.01								14.01	7.45
1964-65	34.81	3.23	8	11.02	9.35	0.45							14.39	7.91
1965-66	43.10	4.33	14	13.31	10.31	4.45							14.11	7.45
1966-67	52.05	2.93	13	9.18	7.36	2.08							15.49	9.12
1967-68	64.51	1.57	87	67.08	58.13	5.67							16.57	9.12
1968-69	103.42‡	5.00	108	79.21	69.32	17.84	6	61.50	4.20@	2.52			19.00	9.02
1969-70	114.72	1.10	142	92.78	70.92	28.60	23	46.74	29.31†	15.04	50	31.11	30.28	11.48

Note : Figures of investment finance made available by commercial banks, other than by way of contribution to the debentures floated by land mortgage/development banks and participation with the Agricultural Finance Corporation, are not available. Similarly, figures of investment finance provided by Co-operation Cooperative credit agencies out of their own funds are also not available.

* Includes special development debentures of Rs. 13.5 lakhs.

** Excluding schemes sanctioned but subsequently withdrawn.

† Includes participation by member-banks.

Reference to participation in respect of 4 schemes involving an outlay of Rs. 4.20 crores. Participation in respect of the remaining two schemes involving an outlay of Rs. 57.30 crores is yet to be finalised.

‡ Refers to participation in respect of 19 schemes involving an outlay of Rs. 29.31 crores. Participation in respect of four schemes involving an outlay of Rs. 17.43 crores is yet to be finalised.

‡ Revised.

74. During the Fourth plan, land development banks are likely to expand their loan operations to Rs. 700 crores—a target fixed on the basis of the available resources. The Agricultural Refinance Corporation has a refinance target of Rs. 200 crores.

Trends in Money Supply

75. During the year 1969-70 (July-June) increase in money supply with the public at Rs. 578 crores was higher than that in the preceding year (Rs. 566 crores). However, the rate of increase slackened to 9.6 per cent in the current year as against 10.3 per cent in 1968-69. Total monetary resources, which comprise currency with the public and aggregate deposits of banks, recorded a smaller increase at Rs. 991 crores or 11.4 per cent as against Rs. 1039 crores or 13.5 per cent in 1968-69. Component-wise the increase under currency continued to be larger than the increase in deposit money, reflecting the continued growth in agricultural incomes. The expansion in currency component during 1969-70 was Rs. 386 crores or Rs. 45 crores more than that in last year, while the increase in deposit money at Rs. 192 crores was Rs. 33 crores smaller than last year. The rate of growth of time deposits also slackened considerably from Rs. 473 crores or 21.5 per cent in 1968-69 to Rs. 413 crores or 15.4 per cent. During 1969-70 net bank credit to Government registered a marginal increase of Rs. 6 crores as against a sizeable increase of Rs. 433 crores in 1968-69. On the other hand, the net foreign exchange assets position of banking sector this year exerted a much larger expansionary impact on money supply than last year. Following considerable decline in payments for imports and some increase in earnings from exports the net foreign exchange assets of the banking sector registered a larger increase of Rs. 285 crores than Rs. 153 crores last year. Bank credit to the commercial sector also exerted a much larger expansionary impact on money supply than last year, the increase of Rs. 736 crores being Rs. 95 crores larger than the increase during the preceding year. In assessing the magnitude of expansion in bank credit to commercial sector, it has to be borne in mind that a good part of this credit is on account of advances to public sector undertakings including the Food Corporation of India as well as to State Governments for commercial purposes such as food procurement and purchase and distribution of fertilisers. Table 11 would provide some idea of the magnitude of such advances in the total bank credit to the commercial sector as also of their variations over the period ended December 1969.

Seasonal Trends

76. The slack season of 1969 (May-October) witnessed a smaller contraction in money supply (Rs. 73 crores) than in the 1968 slack season. The contraction in money supply stemmed mainly from a decline in net bank credit to Government and the commercial sector (*i.e.*, adjusted for variation in time deposits of banks), which was partly offset by an accrual of Rs. 45 crores to net foreign exchange assets of the banking sector.

77. During the busy season period of 1969-70, *i.e.*, November 1969 to April 1970, money supply expansion was higher at Rs. 695 crores or 11.9 per cent against Rs. 107 crores or 11.4 per cent in the 1968-69 busy season. The expansion in currency component at Rs. 512 crores was about Rs. 100 crores larger than last busy season, while increase in demand deposits was smaller by Rs. 13 crores. Increase in time deposits was also smaller by Rs. 38 crores than in the 1968-69 busy season.

78. The increase in net bank credit to Government during the 1969-70 busy season was much smaller at Rs. 130 crores as against Rs. 324 crores in the corresponding period last year. However, the increase in foreign exchange assets at Rs. 181 crores was higher by Rs. 48 crores than in the 1968-69 busy season. Credit to commercial sector expanded by Rs. 569 crores in 1969-70 season as against a rise of Rs. 470 crores in the last busy season. Thus during the 1969-70 busy season, larger increases in net foreign exchange assets and bank credit to the commercial sector were responsible for larger increase in money supply.

79. During the current slack season *i.e.*, the 1970 slack season so far there is a contraseasonal expansion in money supply as in the corresponding period of the 1969 slack sea-

son. While net credit to Government continues to be smaller, both foreign exchange assets and credit to commercial sector were higher during this slack season so far than in the corresponding period last year.

Banking Trends and Credit Policy.

80. During the year the strain on the resources of the scheduled commercial banks increased owing to larger expansion in bank credit and a slow-down in the rate of deposit growth. Banks' recourse to Reserve Bank credit was substantially higher than last year. The Reserve Bank, therefore, tightened its credit control measures to reduce to some extent the banks' access to refinance facilities available in respect of their lending to priority sectors. Some of the concessions in respect of these refinance facilities were withdrawn. In the context of the upward pressure on prices, excessive build up of inventories in industry of agricultural raw materials in short supply was curbed by stiffening the margin requirements and lowering of ceiling limits in respect of bank advances against the security of these commodities.

81. Total scheduled commercial banks' credit recorded an increase of Rs. 628.8 crores as compared with the expansion of Rs. 495.9 crores in 1968-69. The rate of increase in credit in 1969-70 was 17.5 per cent as compared with 16.0 per cent in 1968-69. Aggregate deposits, on the other hand, showed a smaller rise of Rs. 594.0 crores as compared with the rise of Rs. 676.8 crores in 1968-69. The rate of growth in deposits thus declined from 17.0 per cent in 1968-69 to 12.8 per cent in 1969-70. The credit-deposit ratio at the end of the year stood at a high level of 80.7 per cent, which was 3.2 per cent higher than at the end of June 1969. Of the total increase in deposits, time deposits accounted for 66 per cent as in 1968-69. Scheduled commercial banks' investments in Government securities showed an increase of only Rs. 61.3 crores, as against a much larger increase of Rs. 150.7 crores in 1968-69. In view of this, the investment-deposit ratio at 22.7 per cent was lower by 1.5 percentage points than the ratio a year ago. Cash and balances with the Reserve Bank showed a decrease of Rs. 39.5 crores as against an increase of Rs. 110.8 crores in 1968-69. As a result, the cash ratio declined from 8.2 per cent in June 1969 to 6.5 per cent in June 1970. The outstanding level of banks' borrowings from the Reserve Bank at the end of June 1970 was much higher at Rs. 291.5 crores than the level of Rs. 172.2 crores at the end of June 1969.

82. The credit policy announced on the eve of 1969 slack season was referred to in the previous Report. The 1969 slack season witnessed a substantial growth in deposits of Rs. 348 crores, relatively to the increase of Rs. 239 crores in the 1968 slack season. It was, however, not much higher than the increase of Rs. 325 crores in the 1968-69 busy season. The rate of growth in deposits in the 1969 slack season was slightly lower at 7.8 per cent as compared to 7.9 per cent in 1968-69 busy season which preceded it but was higher when compared to 6.2 per cent in 1968 slack season. Of the total increase in deposits, only about 67 per cent was in the form of time deposits, whereas the proportion in the 1968 slack season was 95 per cent. Bank credit on the other hand, recorded a contra-seasonal rise of Rs. 31 crores as against a contraction of Rs. 43 crores in the slack season of 1968. Even so, the credit-deposit ratio stood lower at 72.9 per cent at the end of October 1969—as compared to 73.7 per cent a year ago.

83. In response to the Governor's request to banks on the eve of the slack season, to invest their surplus funds in Government securities as well as in other approved securities, the banks increased substantially their holdings of Government securities by Rs. 208 crores and of other approved securities by Rs. 31 crores in the 1969 slack season as compared to Rs. 134 crores and Rs. 5 crores, respectively, in the 1968 slack season. The investment-deposit ratio of banks moved up by nearly 3 points during the season and stood at 31.8 per cent at the end of October 1969, as compared with 31.3 per cent a year ago. The increase in cash and balances with the Reserve Bank was somewhat smaller than in the 1968 slack season, but the cash ratio showed a marginal rise of 0.1 per cent to 6.4 per cent at the end of the 1969 slack season. Borrowings from the Reserve Bank by scheduled commercial banks declined from Rs. 101.0 crores at the end of April 1969 to Rs. 33.5 crores at the end of October 1969, which was about Rs. 3 crores higher than the

Table 10—Trends in Money Supply and Monetary Resources

(Annual)

(Rupees crores)

	Variations during July-June		
	1967-68	1968-69	1969-70
1. Currency with the Public	+235 (+7.3)	+341 (+9.9)	+386 (+10.2)
2. Demand Deposits	+276 (+15.7)	+22.5 (+11.1)	+192 (+8.5)
3. Money Supply (1+2)	+510 (+10.3)	+566 (+10.3)	+578 (+9.6)
4. Time Deposits	+258 (+13.2)	+473 (+21.5)	+413 (+15.4)
5. Total Monetary Resources	+768 (+11.1)	+1039 (+13.5)	+991 (+11.4)
6. Net Bank Credit to Government	+171 (+4.1)	+433 (+9.9)	+6 (+0.1)
7. Net Foreign Exchange Assets of the Banking Sector	+81 (+81.0)	+153@ (+84.6)	+285 (+71.4)
8. Government's Net Currency Liabilities to the Public	—2 (—0.6)	+33 (+10.4)	+11 (+3.2)
9. Total (6+7+8)	+250 (+5.4)	+619@ (+12.7)	+302 (+5.4)
10. Bank Credit to Commercial Sector	+570 (+18.6)	+641 (+17.6)	+736 (+17.2)
11. Net Non-Monetary Liabilities of Reserve Bank	—8	—95@	—60
12. Net Non-Monetary Liabilities of other Banks	—44	—126	+13
13. Total (9+10)	+820 (+10.6)	+1260@ (+14.8)	+1038 (+10.5)

Note : Figures in brackets represent percentage variations.

@Excluding changes due to revaluation of gold held in the Issue Department of the Reserve Bank with effect from February 1, 1969.

Table 11—Outstanding of Scheduled Commercial Bank Credit to Public Sector

(Rupees Crores)

	June 28, 1968	December 27, 1968	June 27, 1969	December 26, 1969*
(i) Government Companies and Corporations	223.38 (+142.2)	299.88 (+34.2)	—224.97 (+25.0)	165.37 (—26.5)
(ii) Other Government Bodies	10.08 (+2.9)	14.44 (+43.2)	14.90 (+3.2)	18.97 (+27.3)
(iii) State Governments	22.86 (+26.7)	18.46 (—19.2)	87.58 (+374.4)	30.95 (—64.7)
(iv) State Electricity Boards	10.92 (+248.9)	10.74 (+1.6)	23.13 (+115.4)	19.07 (—17.6)
(v) Grand Total	267.24 (+116.9)	343.52 (—28.5)	350.58 (+2.1)	234.36 (—33.2)
(vi) Total Scheduled Commercial Bank Credit	3102.89 (+13.9)	3068.99 (—1.1)	3598.77 (+17.3)	3615.92 (+0.5)
(vii) Proportion of Credit to Public Sector to total Scheduled Commercial Bank Credit	8.6	11.2	9.7	6.5

Note : Figures in brackets indicate percentage changes over the previous period.

*Provisional.

Table 12 — Trends in Money Supply and Monetary Resources
(Seasonal)

								(Rupees crores)			
								Variations during the			
								Slack Season		Busy Season	
								1968	1969	1968-69	1969-70
1. Currency with the Public	-126 (-3.6)	-149 (-4.0)	+411 (+12.2)	+512 (+14.1)
2. Demand Deposits	-5 (-0.2)	+76 (+3.6)	+196 (+10.0)	+183 (+8.2)
3. Money Supply (1+2)	-131 (-2.4)	-73 (-1.2)	+607 (+11.4)	+695 (+11.9)
4. Time Deposits	+230 (+10.6)	+248 (+9.6)	+200 (+8.4)	+162 (+5.7)
5. Monetary Resources (3+4)	+99 (+1.3)	+175 (+2.1)	+807 (+10.5)	+857 (+9.9)
6. Net Bank Credit to Government	+36 (+0.8)	-14 (-0.3)	+324 (+7.4)	+130 (+2.8)
7. Net Foreign Exchange Assets of the Banking Sector	+9 (+5.0)	-45 (+11.3)	+133@ (+67.7)	+181 (+40.9)
8. Government's Net Currency Liabilities to the Public	-8 (-2.6)	— (—)	+33 (+10.5)	+13 (+3.9)
9. Total (6+7+8)	+37 (+0.8)	+31 (+0.6)	+490@ (+10.0)	+324 (+5.9)
10. Bank Credit to Commercial Sector	+56 (+1.6)	+136 (+3.3)	+470 (+12.9)	+569 (+13.4)
11. Net Non-Monetary Liabilities of Reserve Bank of India	+2	+15	-77@	-76
12. Net Non-Monetary Liabilities of other banks	+4	-7	-76	-40
13. Total (9+10)	+93 (+1.1)	+167 (+1.7)	+960@ (+11.2)	+893 (+9.2)

Note : Figures in brackets represent percentage variations.

@ Excluding changes due to revaluation of gold held in the Issue Department of the Reserve Bank with effect from February 1, 1969.

Table 13—Annual Variations in Important Banking Data

								(Rupees crores)			
								June 1967	Variation during the year ended June 1967	June 1968	Variation during the year ended June 1968
								June 1969	Variation during the year ended June 1969	June 1970*	Variation during the year ended June 1970
1. Total Bank Credit	2631.1	+359.7	3102.9	+471.8
2. Total Investments	1069.9	+20.4	1160.7	+90.8
(a) in Government securities	922.6	+3.8	975.6	+53.0
(b) in other approved securities	147.3	+16.6	185.1	+37.8
3. Cash and Balances with the Reserve Bank of India	258.8	+63.5	269.5	+10.7
4. Money at call	57.7	-4.5	50.6	-7.1
5. Aggregate Deposits	3517.0	+393.8	3969.0	+452.0
(a) Demand	1664.6	+187.3	1874.8	+210.2
(b) Time	1852.4	+206.5	2094.2	+241.8
6. Borrowings from Reserve Bank of India	11.5	+9.0	103.5	+92.0

* Provisional.

Source : Returns submitted under Section 42(2) of the Reserve Bank of India Act, 1934, except in respect of borrowings from the Reserve Bank of India which are based on borrowing advices from regional offices of the Reserve Bank of India.

Table 14—Seasonal Variations in Scheduled Commercial Banks' Data

(Rupees Crores)

	Slack Season 1968	Busy Season 1968-69	Slack Season 1969	Busy Season 1969-70	Slack Season Upto	
					June 26 1970*	June 27 1969
1. Bank Credit	— 42.9	+426.9	+ 31.3	+561.6	+173.4	+137.6
2. Investments in Government Securities and other approved securities	+138.7	— 2.4	+239.5	— 53.9	+ 34.5	+ 73.4
(a) in Government securities	+133.9	— 43.0	+208.3	—101.0	+ 22.5	+ 68.5
(b) in other approved securities	+ 4.8	+ 40.6	+ 31.2	+ 47.1	+ 12.0	+ 4.9
3. Cash in hand and balances with Reserve Bank	+ 30.2	+ 20.2	+ 26.7	+ 6.8	+ 26.4	+ 99.4
4. Money at call and short notice	+ 34.6	+ 6.7	— 25.8	— 14.2	+ 4.4	+ 3.2
5. Aggregate Deposits	+238.9	+324.9	+348.1	+318.5	+133.2	+205.8
(a) Demand	+ 12.3	+145.1	+115.0	+170.3	+ 42.6	+124.1
(b) Time	+226.6	+179.8	+233.1	+148.2	+ 90.6	+ 81.7
6. Borrowing from the Reserve Bank	— 81.9	+ 70.8	— 67.5	+203.0	+ 55.0	+ 71.2

* Provisional.

Notes : (1) Data are based on weekly returns submitted by banks under section 42(2) of the Reserve Bank of India Act, 1934, except in respect of borrowings from the Reserve Bank of India which are based on weekly borrowing advices from regional offices of the Reserve Bank of India.

(2) The variations are based on the last Friday figures of April and October.

Table 15— Seasonal Pattern of Principal Ratios of Scheduled Commercial Banks

(Rupees crores)

	October, 1968		April, 1969		October, 1969		April, 1970		June, 1970*		June, 1969	
	Amo- unt	Per- cent- age	Amo- unt	Per- cent- age	Amo- unt	Per- cent- age	Amo- unt	Per- cent- age	Amo- unt	Per- cent- age	Amo- unt	Per- cent- age
1. Bank Credit	3034.4	73.7	3461.3	78.0	3492.6	72.9	4054.2	79.4	4227.6	80.7	3598.8	77.5
2. Investments in Government and other approved securities	1288.0	31.3	1285.6	28.9	1525.1	31.8	1471.2	28.8	1505.7	28.7	1358.9	29.2
(a) in Government securities	1100.8	26.8	1057.8	23.8	1266.1	26.4	1165.1	22.8	1187.6	22.7	1126.3	24.2
(b) in other approved securities	187.2	4.5	227.8	5.1	259.0	5.4	306.1	6.0	318.1	6.0	232.6	5.0
3. Cash & Balances with Reserve Bank	260.7	6.3	280.9	6.3	307.6	6.4	314.4	6.2	340.8	6.5	380.3	8.2
4. Money at call and Short Notice	78.2	—	84.9	—	59.1	—	44.9	—	49.3	—	88.1	—
5. Aggregate Deposits	4115.1	100.0	4440.0	100.0	4788.1	100.0	5106.6	100.0	5239.8	100.0	4645.8	100.0
(a) Demand	1834.3	44.6	1979.4	44.6	2094.4	43.7	2264.7	44.3	2307.3	44.0	2103.5	45.3
(b) Time	2280.8	55.4	2460.6	55.4	2693.7	56.3	2841.9	55.7	2932.5	56.0	2542.3	54.7
6. Borrowings from Reserve Bank	30.3	—	101.0	—	33.5	—	236.5	—	291.5	—	172.2	—

Note : (1) The percentages are ratios to aggregate deposits.

(2) Data are based on weekly returns submitted by banks under section 42(2) of the Reserve Bank of India Act, 1934, except in respect of borrowings from Reserve Bank of India which are based on weekly borrowing advices received from regional offices of the Reserve Bank of India. All figures relate to the Friday of the month.

* Provisional

level a year ago. In view of the comfortable resources position of the banking system and the continuance of the refinancing facilities by the Reserve Bank for the priority sectors, the money market remained easy during the 1969 slack season. The call rate at Bombay declined from the busy season's closing level of 4 per cent to 3.1 per cent in the third week of August 1969, but thereafter it rose steadily to 4 per cent at which level it remained till the end of the slack season as compared to the level of 3.5 per cent at the end of the 1968 slack season. In Calcutta, the call rate rose from 3.7 per cent at the end of April to 4.6 per cent in the second week of May 1969, but declined to 2.9 per cent at the end of August. Thereafter it moved upto 3.7 per cent at the end of the 1969 slack season. In the 1968 slack season, the call rate at Calcutta ruled between 3.1 per cent and 4.8 per cent and closed at 4.1 per cent.

84. On September 1, 1969, the Reserve Bank issued a directive, in terms of which the payment of interest on current accounts and on deposits for periods upto 14 days, as well as the payment of brokerage on deposits by banks was prohibited. The rates of interest fixed on other categories of deposits were not revised and kept at the same levels as were in force under the earlier All-India Inter-Bank Agreement on Deposit Rates.

85. During the 1969 slack season some procedural relaxations in Credit Authorisation Scheme and Bill Market Scheme were also made. In May 1969 certain categories of advances were exempted from the requirements of Reserve Bank's prior authorisation. Important among these categories, were advances to State Governments, Food Corporation of India and State Co-operative Banks for financing food procurement operations, advances against Government and other trustee securities and advances to State Electricity Boards and public sector undertakings. In August 1969, further exemptions were granted from the prior authorisation requirement, in respect of the purchase and discount of inland documentary bills and supply bills drawn on quasi-Government bodies.

86. In pursuance of the recommendations of the Fertiliser Credit Committee, set up by the Fertiliser Association of India, the Bank reduced in August 1969 the minimum amount of usance promissory notes in respect of advances granted for distribution of fertilisers, from Rs. 50,000 to Rs. 25,000 and the minimum amount that can be borrowed by a bank at a time from Rs. 5 lakhs to Rs. 1 lakh. The Reserve Bank also made a similar concession for refinancing advances granted by banks to small-scale industries.

Credit Policy For 1969-70 Busy Season

87. At a meeting with the Chairmen/Chief Executives of major banks on November 1, 1969, the Governor of the Reserve Bank reviewed banking trends in the 1969 slack season and indicated the Bank's policy for the 1969-70 busy season. It was felt that although there was a favourable outlook for agricultural production and the revival in industrial output and the rising trend in exports continued, the banking system would not be faced with any problem of inadequacy of funds to meet the credit requirements, in view of the improved liquidity position and the likely addition to their resources by way of fresh deposits during the busy season. In view of this and to maintain a degree of stability in Bank's credit policy with a view to helping banks to plan their operations, there was no basic change in the credit policy for the busy season of 1969-70. Refinance at 4½ per cent, irrespective of net liquidity ratio, was available: (i) against packing credits to exporters of metallurgical and engineering products; (ii) upto an amount equivalent to the increase in export credit over the prescribed base period (November 1968 to April 1969); and (iii) upto an amount equivalent to the total of short-term outstanding credit to agriculture and small-scale industries (guaranteed by the Credit Guarantee Organisation). In addition, refinance at the Bank rate, irrespective of the net liquidity ratio, was continued (i) against packing credit to exporters of goods other than metallurgical and engineering, and against post-shipment export credit and (ii) in respect of advances to State Governments, their agencies and Food Corporation of India for food procurement operations. Further, the increase in credit to export sector over the prescribed base period, continued to be treated as liquid assets of banks for the purpose of computation of net liquidity ratio. Finally, as in the past, the Reserve Bank agreed to consider giving discretionary accommodation to banks, in deserving cases, at the Bank rate, if they ex-

perienced sudden or specially heavy demands on credit from particular sectors.

88. However, unlike in the busy season of 1968-69 the pace of credit expansion increased considerably from early part of the busy season of 1969-70. The credit expansion during the first three months of the season amounted to Rs. 277 crores as compared to Rs. 112 crores in the corresponding period of 1968-69 season. At the same time, there was a contra-seasonal rise in prices and the monthly average index of wholesale prices during January 1970 was 6.8 per cent higher than the level a year ago. In a letter to banks on February 5, 1970 the Governor drew the banks' attention to the sharp rise in bank credit as well as in the borrowings of banks from the Reserve Bank during the season and pointed out that the credit expansion was larger than what was warranted by genuine production and marketing needs. He, therefore, advised the banks to exercise adequate credit restraint and to make a careful analysis of the directions in which the credit expansion had taken place during the season. In order to reduce the recourse by banks to refinancing facilities of the Reserve Bank and to restrain credit expansion, the refinance facility at the Bank rate in respect of food procurement advances irrespective of a bank's net liquidity ratio, was withdrawn, and the availability of refinance at 4½ per cent upto the total of short-term lending to agriculture was discontinued and only direct lending to agriculture was made eligible for refinance at Bank rate. The banks were also asked to step up their holdings of assets which are included in their statutory liquidity ratio, from 25 per cent to 26 per cent of their aggregate demand and time liabilities within a month.

89. Subsequently, on February 18, 1970, the Chairmen/Chief Executives of the banks and the Governor of the Reserve Bank reviewed credit and deposit trends during the first three months of 1969-70 busy season. As credit expansion continued to grow in the 1969-70 busy season, the Governor asked the bankers to exercise the utmost caution in extending credit and exercise greater vigilance in the matter of end-use of credit. The Governor also urged the banks to rely more on the resources, which they could mobilise by way of deposits than on recourse to the Reserve Bank. As the banks continued to have large recourse to the Reserve Bank's refinancing facilities, the availability of refinance to banks was further restricted to an amount equivalent to an increase in credit to the priority sectors over the prescribed base period. Simultaneously, the minimum net liquidity ratio qualifying for Bank rate refinance was also raised from 30 to 31 per cent, which was to be stepped up further to 32 per cent by the last Friday of April 1970. Banks were also asked to step up their assets in respect of statutory liquidity ratio from 26 to 27 per cent by the last Friday of April 1970.

90. The Bank also took certain additional measures to curb credit expansion and, to encourage deposit mobilisation by banks. On January 21, 1970, the Bank removed the ceiling rate of interest on advances, which was fixed at 9½ per cent on March 2, 1968 and which was applicable to the larger Indian scheduled commercial banks and foreign banks operating in India. However, in order to maintain the cost of export credit at a reasonable low level, the Bank continued the ceiling rate at 6 per cent for export credit granted by banks (both pre-shipment and post-shipment). Following the removal of the ceiling rate of 9½ per cent on advances and the upward revision of the rates of interest on certain categories of postal deposits, the Reserve Bank raised on March 28, 1970 by 1 to ½ per cent the rate payable by banks on deposits for periods of two years and above, while retaining the rates of interest on savings deposits and the rates on fixed deposits for period of less than two years at the previous levels. The new rates came into effect from April 1, 1970. At the same time, with a view to bringing about a more rational allocation of credit and to induce the borrowers to exercise greater care in estimating their credit requirements, the Reserve Bank issued on March 28, 1970 a directive to banks asking them to levy a commitment charge of 1 per cent per annum effective April 1, 1970, on the unutilised portion of credit limits of Rs. 10 lakhs and above. Suitable exemptions have been granted in respect of credit limits for inland, export and import bills, packing credit for exports, letters of credit opened for imports, trust receipts facilities in connection with the import of goods, procurement operations as well as credit limits granted to State Trading Corporation for the purpose of storage and distribution of soyabean and sunflower oil.

91. Following the withdrawal of the refinance facility at Bank rate in respect of food procurement advances from February 5, 1970, the banks which continued to finance food procurement operations found it difficult to meet the growing financial

requirements of other priority sectors as well as some of the industries like the sugar industry which were faced with the problem of carrying a large volume of stocks. The Bank, therefore, agreed in April 1970 to refinance at Bank rate 80 per cent of the increase in advances granted by banks for food procurement purposes over the average level of such advances in the quarter ended March 1970. This facility was made available till the third Friday of July 1970 after which it was to be reduced to 50 per cent of the outstanding level of such advances.

Selective Credit Controls

92. As regards selective credit control measures, following considerable improvement in supplies and the fall in prices of raw jute, the Bank withdrew in September 1969 the restrictions imposed in October 1968 on advances against raw jute to parties other than jute mills, as well as on advances against Pucca Delivery Orders for jute goods. However, in view of the tight supply position in respect of oilseeds, vegetable oils and raw cotton and the sharp rise in their prices in recent months, the Reserve Bank of India issued a directive on January 21, 1970, tightening the control on credit against oilseeds, vegetable oils and cotton and kapas. In terms of this directive, the control on advances against foodgrains was also stiffened in order to discourage holding of excess stocks with the help of bank finance. The minimum margin on advances against oilseeds and vegetable oils (including vanaspati) was raised uniformly for advances to all parties to 60 per cent of the value of stocks. The margin for advances against foodgrains was raised to 50 per cent. The permissible levels of credit were reduced to 70 per cent of the average aggregate level of advances maintained by a bank in 1967 in the case of oilseeds and vegetable oils and to 80 per cent of the 1968 level in the case of foodgrains. The minimum margin on advances against cotton and kapas to the parties other than mills was also raised from 50 to 60 per cent and the control was reimposed on advances to cotton textile mills with a minimum margin of 40 per cent and a ceiling which for every six-month-period commencing from November 1969 to April 1970 would be equivalent to 85 per cent of the peak level of the corresponding period in the year 1967-68 (November-October). Advances against stocks of imported cotton and to exporters of cotton and kapas continued to be exempted from the directive. To reinforce the impact of these controls, the Bank also prescribed a minimum rate of 10 per cent on advances against foodgrains, oilseeds, vegetable oils (including vanaspati) and cotton and kapas. Advances granted by banks to the Food Corporation of India, State Governments and their approved agents for food procurement and distribution continued to be exempted from the provisions of this directive. On March 11, 1970 advances against imported sunflower oil were completely exempted from the control. The Bank directed the banks on March 17, 1970 not to grant credit facilities to parties affected by the directive of January 21, 1970 by way of clean advances or discount of clean bills. The banks were also advised on April 11, 1970 to exercise utmost caution in extending credit against demand documentary bills with a view to preventing the misuse of such credit by their clients. In view of the persisting rise in the prices of oilseeds, vegetable oils and cotton and kapas, the Bank directed the banks on April 28, 1970 to raise the minimum rate of interest charged on such advances from 10 per cent to 12 per cent per annum in respect of all borrowers. The minimum margin on advances against indigenous cotton and kapas to parties other than cotton mills was also raised from 60 to 75 per cent. Some relaxations were made in respect of advances against raw cotton to mills owned or managed by the Government as well as to the financially weak mills.

93. Owing to the improved supply position and the considerable fall in the price of gur, the Bank withdrew its control on advances against gur on January 21, 1970. To overcome the difficulties experienced by the roller flour mills in making payments in respect of wheat purchases from the Food Corporation of India, the Bank advised the banks on April 10, 1970, to charge a reduced margin of 25 per cent for advances to roller flour mills as against the earlier margin of 50 per cent. The Bank also removed the ceiling restrictions on advances granted by banks to roller flour mills against wheat supplied by the Food Corporation of India. On April 28, 1970 bank advances against barley were exempted from control.

94. Following the large increase in the production of sugar and the decline in the free market prices of sugar, the Bank withdrew on May 4, 1970 its control on bank advances against sugar imposed on April 27, 1963. Earlier, bank advances against

sugar were subject to a minimum margin of 45 per cent, in respect of parties other than sugar mills and to mills in respect of stocks which had left the factory premises and on which excise duty had been paid. Subsequently on May 30, 1970, the Bank advised the banks to provide additional finance to sugar mills to enable them to continue the crushing activity. The banks were also advised to fix the same margin for levy and free sugar, the latter being based on the tariff value fixed by the Government or the market value, whichever is lower.

95. On representations received from the vanaspati manufacturing units that they experienced difficulties in securing bank credit, the Bank relaxed on June 8, 1970, its restrictions on advances to vanaspati units and registered oil mills; these manufacturing units were exempted from the existing ceiling restrictions on bank credit. Banks were also asked to charge a lower margin of 40 per cent for advances against vegetable oils to vanaspati units. This reduced margin would, however, apply only to stocks to vegetable oils equivalent to six weeks consumption of each factory located in Northern and Eastern Zones and to four weeks consumption of each factory in the Southern and Western Zones, worked out on the basis of a specified weekly consumption. The Bank also exempted from control advances granted to solvent extraction units against the extracted oil, in cases where the value of raw material exceeds the value of de-oiled cakes to be exported. The ceiling limit on advances against non-edible vegetable oils, excluding linseed and castorseed oils, has also been removed.

Banking Trends during 1969-70 Busy Season

96. The busy season of 1969-70 witnessed a much larger expansion in bank credit than the 1968-69 season. The pace of deposit accretion during this busy season on the other hand, was somewhat slower than in the busy season of the preceding year. Scheduled commercial banks' credit expanded by Rs. 562 crores as compared with an expansion of Rs. 42 crores and Rs. 509 crores in the busy seasons of 1968-69 and 1967-68, respectively. Excluding food procurement advances, credit expansion in 1969-70 busy season was also much higher at Rs. 589 crores than in the earlier busy season at Rs. 419 crores. A security-wise analysis of bank credit (based on estimates) in the 1969-70 busy season showed that there has been a substantial decline in advances against foodgrains as against a small rise in the 1968-69 season, while the increase in the credit against oilseeds, and cotton and kapas, was smaller than in the 1968-69 season. Advances against vegetable oils (including vanaspati) and raw jute rose by a much larger amount than in 1968-69 season. Advances against sugar increased by Rs. 102 crores as compared with Rs. 99 crores in 1968-69 season, which indicates that the sugar industry did not increase its recourse to bank finance to a much greater extent than in the previous year. Among manufactures, credit against cotton textiles showed a sharp increase, which reflected the accumulation of finished goods held by the industry. The increase in credit against jute textiles was only slightly larger than in 1968-69 season. Advances against iron and steel and engineering goods also showed a substantial increase of Rs. 58 crores as against a fall of Rs. 13 crores in 1968-69 busy season. On the other hand, credit against chemicals, dyes, drugs and pharmaceuticals showed a sharp fall of Rs. 19 crores as against a substantial rise of Rs. 48 crores in the previous busy season. Unsecured advances also showed a smaller expansion of Rs. 36 crores as compared with Rs. 56 crores in the previous busy season.

97. Deposit accretion in 1969-70 busy season was somewhat smaller at Rs. 319 crores as compared with Rs. 325 crores in the 1968-69 busy season. As a result, the credit-deposit ratio at the end of April 1970 was higher at 79.4 per cent as compared with 78.0 per cent at the end of April 1969. The increase in demand deposits was larger than time deposits during the busy season of 1969-70 as against a larger rise in time deposits in 1968-69 season. In fact, the rise in time deposits amounting to Rs. 148 crores was much less than the rise of Rs. 233 crores recorded in the 1969 slack season. Even in 1968-69 busy season, time deposits showed a rise of Rs. 180 crores. To some extent the slower growth in time deposits could be attributed to the rise in prices and to the pressure of demand for funds during the 1969-70 busy season.

98. The disinvestment in Government securities during the last busy season was much larger at Rs. 101 crores than the decline of Rs. 43 crores in the 1968-69 busy season. Consequently,

Table 16—Seasonal Trends in Bank Credit : Security-Wise Classification

(Rupees crores)

	Busy Season 1967-68	Slack Season 1968	Busy Season 1968-69	Slack Season 1969	Busy Season 1969-70†
Seasonal Advances**	+359.7	-152.5	+206.8	-192.0	+123.0
Paddy & Rice	+ 63.0	- 36.6	+ 41.1	- 29.0	- 7.7
Wheat	+ 12.4	+ 69.8	- 33.7	+ 14.4	- 59.4
Other foodgrains	+ 29.9	- 10.9	+ 9.0	- 3.1	+ 17.2
Sugar	+123.0	-104.6	+ 98.9	- 44.6	+102.4
Gur	+ 4.5	- 5.2	+ 3.7	- 3.6	+ 8.9
Groundnuts	+ 8.2	- 7.1	+ 11.8	- 13.7	+ 5.9
Other oilseeds	+ 6.8	- 5.7	+ 13.9	- 17.0	+ 9.0
Vegetable oils	+ 11.2	+ 2.2	+ 1.6	- 10.2	+ 10.2
Cotton and kapas	+ 83.4	- 49.4	+ 68.1	- 86.9	+ 40.4
Raw Jute	+ 19.2	- 18.1	+ 1.0	- 6.1	+ 10.6
Tea	- 1.9	+ 17.5	- 8.6	+ 7.8	- 14.5
Non-Seasonal Advances‡	-135.6	+ 89.6	+131.4	+185.0	+365.5
Cotton Textiles	+ 22.5	+ 14.8	+ 0.5	+ 1.0	+ 27.9
Jute Textiles	- 3.7	+ 9.4	+ 6.1	- 0.8	+ 7.1
Iron, steel and engineering goods*	+ 6.0	+ 31.1	- 12.7	+ 44.9	+ 58.3
Chemicals, dyes, paints, drugs and pharmaceuticals§	+ 23.2	+ 21.5	+ 48.2	+ 7.4	- 19.2
Electrical goods	+ 7.5	+ 4.7	- 6.7	+ 18.4	n.a.
Assets of industrial concerns—fixed or floating	+ 0.3	+ 9.3	+ 4.7	+ 10.3	+ 5.0
Shares of joint stock companies	+ 2.1	- 0.8	+ 3.0	- 1.5	+ 2.6
Government and other trustee securities	- 2.7	- 0.4	- 1.7	+ 0.6	n.a.
Gold and silver bullion and ornaments	+ 1.2	+ 3.6	+ 1.5	+ 8.4	n.a.
Total Secured Advances	+495.3	- 62.9	+338.2	- 7.0	+488.5
Unsecured Advances	+ 3.5	+ 33.3	+ 55.8	+ 25.2	+ 35.6
Total Advances	+498.8	- 29.6	+394.0	+ 18.2	+524.1

Source : Fortnightly/Monthly Survey of Banks' advances classified according to security. These figures may not tally with those given in Table 14 as these relate to reporting branches only.

* Includes advances against vehicles.

† Estimates based on mid-April 1970 returns received from selected branches of banks.

‡ Including plantations other than tea.

§ Includes advances against fertilisers.

** Excluding plantations other than tea.

n.a.—not available.

the investment-deposit ratio declined from 26.4 per cent at the beginning of the season to 22.8 per cent at the end of April 1970, which was lower than the level of 23.8 per cent at the end of April 1969. Cash and balances with the Reserve Bank during the season showed a rise of Rs. 7 crores as compared with the rise of Rs. 20 crores during the 1968-69 busy season. Thus, the cash ratio stood at 6.2 per cent at the end of April 1970 as compared with 6.3 per cent a year ago. Outstanding borrowings from the Reserve Bank at Rs. 237 crores at the end of April 1970 were at a much higher level than at the end of 1968-69 busy season (Rs. 101 crores). During the 1969-70 busy season they also showed a substantial increase of Rs. 203 crores as compared to the rise of Rs. 71 crores in the 1968-69 busy season. Owing to the considerable pressure of demand for credit and the curtailment of refinance facilities by the Reserve Bank, the inter-bank call money rate in Bombay and in Calcutta rose to a much higher level in the 1969-70 busy season than in the previous busy season. Thus the call rate in Bombay, which moved between 4 and 4½ per cent till February 6, 1970 rose sharply thereafter and touched 8.9 per cent by April 3, 1970. Subsequently, the rate moved down to 6½ per cent on April 24, 1970. In Calcutta also, the rate gradually moved up to 4.8 per cent by the first week of February 1970 and shot up to 9 per cent by April 3, 1970, but thereafter it eased to 6.2 per cent on April 24, 1970. The highest levels touched in the 1968-69 busy season in Bombay and Calcutta were 5 per cent and 6.1 per cent, respectively, and the rate at the end of that busy season was also much lower at 4 per cent in Bombay and 3.75 per cent in Calcutta.

99. Scheduled commercial banks' credit continued to increase during the first two months of the 1970 slack season and the increase in credit amounted to Rs. 173.4 crores as compared with the rises of Rs. 137.6 crores and Rs. 25.6 crores, respectively, in the corresponding period of 1969 and 1968. The increase in credit for food procurement was larger at Rs. 107.0 crores as compared to Rs. 80 crores in the corresponding period of 1969.

Credit expansion against sugar, tea, chemicals and drugs, as well as assets of industrial concerns was also higher during the first two months of 1970 slack season than in 1969. On the other hand, aggregate deposits increased by Rs. 133.2 crores in the first two months of 1970 slack season as compared with Rs. 205.8 crores and Rs. 93 crores during the corresponding periods of 1969 and 1968 seasons. Consequently, the credit-deposit ratio continued to be much higher at 80.7 per cent than the corresponding levels of 77.5 per cent and 78.2 per cent in 1969 and 1968 seasons. As the banks' resources position had been under strain for sometime, borrowings from the Reserve Bank continued to rise and reached a record level of Rs. 307 crores as on June 19, 1970. During the subsequent week, they declined to Rs. 291.5 crores which was still Rs. 119.3 crores higher than the level a year ago. The call money market therefore continued to remain tight, with the interbank borrowing rate quoting at 6.5 per cent in Bombay and 7.1 per cent in Calcutta. A year ago the rate stood much lower at 3.5 per cent in both the centres.

100. The Reserve Bank informed the banks that the refinance facilities under its Bill Market Scheme would be continued beyond June 1970 to enable them to meet the credit requirements of the priority sectors. These facilities would be available in respect of banks' short-term direct lending to agriculture including credit granted to primary co-operative societies in the selected States as well as for short-term lending to small-scale industries covered by the guarantee of the credit Guarantee Organisation. The amount of refinance would not, however, exceed the total of outstanding bank loans to these sectors. Refinance facilities in respect of bank advances for food procurement and distribution of fertilisers would also continue to be available after June 30, 1970.

Export Finance

101. As regards exports, the Bank continued to provide refinance against export credit granted by banks (both packing

credit and post-shipment credit) under its Pre-Shipment Credit Scheme and its Export Bills Credit Scheme. The procedural requirements under the Pre-Shipment Credit Scheme were modified or waived wherever necessary, taking into account the special circumstances and trade practices of exporters of individual commodities. In June 1969, loans and advances granted by banks against freight differential claims were also made eligible for interest subsidy under the Export Credit (Interest Subsidy) Scheme, as they are considered a part of post-shipment credit. Accordingly, these advances are also subject to the ceiling rate of interest of 6 per cent per annum applicable to other types of export credit.

102. There has been a steady increase in the amount of refinance availed of by scheduled commercial banks from the Reserve Bank of India in respect of export credit granted by them. At the end of June 1970, the outstanding amount of refinance by Reserve Bank of India stood at Rs. 53.9 crores in respect of packing credit for exports and Rs. 52.3 crores in respect of post-shipment credit. The banks also continued to avail themselves of the interest subsidy in regard to export credit provided by them. During the period under review, claims for interest subsidy from 40 eligible commercial banks were received and an aggregate amount of Rs. 3.52 crores was paid to them. Out of this amount, Rs. 1.60 crores represented subsidy in respect of pre-shipment credit and Rs. 1.92 crores for post-shipment credit.

103. The Bank extended its scheme of refinance under Section 17(3A) of the Reserve Bank of India Act and the scope of Export Credit (Interest Subsidy) Scheme to cover also pre-shipment advances by banks to manufacturers of machine tools, construction contractors and tanners. Bonafide manufacturer-exports of machine tools can avail the selves of packing credit advances from banks even without the prior lodgement of firm export orders/letters of credit, subject to certain conditions. Banks can also make advances to bonafide contractors at the rate of interest applicable to export finance to meet their initial working capital requirements for execution of contracts abroad subject to certain safeguards. Similarly, tanners who supply exportable quality leather to the State Trading Corporation for feeding footwear fabricators producing shoes for export through the Corporation were also made eligible for packing credit advances from banks at 6 per cent subject to certain conditions. These advances would be eligible for refinance from the Reserve Bank and also for interest subsidy under the Export Credit (Interest Subsidy) Scheme.

104. In July 1969, in order to overcome the difficulties of the diamond exporters and in view of the special trading practices in regard to diamond exports, banks were allowed to grant pre-shipment advances without insisting on the lodgement of letters of credit/firm export orders. The advances would be given at the concessional rate of interest not exceeding 6 per cent under the Pre-Shipment Credit Scheme against rough diamonds imported or purchased locally for the purpose of cutting and polishing them for ultimate export.

105. Export credit given by banks is also exempted for the purposes of 'norm' relating to unsecured advances and guarantees given by banks. In July the Bank decided to exclude for purposes of this 'norm' unsecured advances made to exporters in respect of exports made on consignment basis where the consignees give an undertaking to remit the sale proceeds or return the goods direct to the bank. The Industrial Development Bank also continued to make available refinance facilities to eligible banks against medium-term export credit granted to exporters primarily for export of capital and engineering goods. The details of such assistance have been referred to in Chapter II.

Advances to Agriculture, Small-Scale and other Sectors

106. The nationalisation of 14 major Indian banks on July 19, 1969 gave an added impetus to banks' lending to the priority sectors such as agriculture and small-scale industries and there has been a greater involvement of banks in these and other socially desirable sectors. The measures taken by the nationalised banks in this regard have been described in Chapter III of the Report.

107. Scheduled commercial banks' advances for agricultural purposes rose from Rs. 188.4 crores in June 1969 to Rs. 286.1 crores in March 1970, while the number of such accounts increased from 2.67 lakhs to 7.10 lakhs during the same period. In particular, the amount of direct credit given to farmers rose from Rs. 53.6 crores to Rs. 150.4 crores during the period and the number of accounts in this regard from 2.6 lakhs to 6.9 lakhs. Advances by the 14 nationalised banks to agriculture doubled from Rs. 62 crores at the end of June 1969 to Rs. 124 crores at the end of March 1970 and the number of these accounts with them rose from 1.27 lakhs to 3.12 lakhs.

108. As regards advances to the small-scale sector (comprising small-scale industries, road transport operators and industrial estates), scheduled commercial banks' advances rose from Rs. 294 crores in June 1969 to Rs. 419 crores in March 1970 and the number of accounts increased from 85,280 to 1.35 lakhs. The bulk of advances to the small-scale sector was in respect of advances to the small-scale industries, which rose from Rs. 286 crores in June 1969 to Rs. 394 crores in March 1970. The number of accounts in the case of small-scale industries rose from 81,706 to 1.24 lakhs. The 14 nationalised banks accounted for about 50 per cent of the increase in advances to small-scale industries, the amount provided by them rising from Rs. 148 crores to Rs. 199 crores during this period. There has also been a sharp increase in credit to road transport operators. Banks have also stepped up their assistance to exports—another priority sector—and the amount of credit (both packing credit and post-shipment credit) for exports increased from Rs. 264.4 crores at the end of June 1969 to Rs. 304.1 crores at the end of March 1970.

109. Consequent on the nationalisation of 14 major banks, there has also been a shift in emphasis of these banks from credit worthiness of the borrower to the credit worthiness of the project to be financed. This is evidenced by the larger amounts lent by these banks to the other sectors like retail trade and self-employed persons and for purposes of higher education. Thus, advances by 14 nationalised banks rose between June, 1969 and March, 1970 from Rs. 19 crores to Rs. 41 crores in the case of retail trade and small business, from Rs. 33 lakhs to Rs. 6.56 crores in the case of self-employed and from Rs. 46 lakhs to Rs. 1.80 crores for education. There was a sharp increase in the number of small borrowers as shown by the rise in number of accounts in respect of retail trade and small business from 28,037 to 71,148 and the number of accounts of self-employed persons, from 422 to 22,233 during the period of nine months.

110. Thus, the amount of bank credit made available to agriculture, small-scale sector and exports taken together increased from Rs. 745.94 crores as at the end of June, 1969 to Rs. 1,008.75 crores at the end of March, 1970, its proportion to total bank credit rising from 20.7 per cent to 25.3 per cent.

111. The total number of deposit accounts with scheduled commercial banks increased by 22 lakhs to 183 lakhs between March 31, 1968 and March 31, 1969. The increase in personal accounts was 19 lakhs, of which as many as 16 lakhs represented savings deposit accounts. Personal accounts comprising current, savings and fixed deposit accounts, continued to form the bulk of the total number of deposit accounts accounting for 88 per cent of the total. The outstanding amount of deposits with banks increased by Rs. 522 crores during the year ending March 31, 1969, of which the rise in personal deposits was Rs. 259 crores. In 1968, on the other hand, the increase in personal deposits was Rs. 275 crores out of a total increase in deposits of Rs. 454 crores. As a result, the proportion of personal deposits in the total deposits declined from 57.3 per cent in March, 1968 to 56.4 per cent in March, 1969. The average amount per account also showed a decline from Rs. 1,612 to Rs. 1,586. On the other hand, the increase in the number of business accounts and deposits was much larger than in 1968. Thus, the number of business accounts increased by 94,000 in 1968-69 as compared to 56,000 in 1967-68, while the deposits in these accounts increased by as much as Rs. 131 crores as against a rise of Rs. 25 crores in 1967-68. The share of business deposits in the total deposits of banks, however, rose marginally from 23.0 per cent to 23.2 per cent. All categories of business accounts (industry, trade, etc.) showed increases both in the number of accounts and in deposits during the year, which may be attributed to the revival of business activity.

112. The pattern of investments of schedule commercial banks has shown a shift in favour of 'other trustee' securities (securities of Municipalities, Port Trusts, Electricity Boards,

Table 17—Scheduled Commercial Banks' Advances to Agriculture, Small-Scale Sector and Exports

(Rupees crores)

	SBI and Subsidiaries		14 Nationalised Banks		Total Public Sector Banks		Other Scheduled Commercial Banks		Total	
	No. of Accounts	Amount	No. of Accounts	Amount	No. of Accounts	Amount	No. of Accounts	Amount	No. of Accounts	Amount
1. Total for Agricultural Purposes*										
June 1969	37740	99.91	126741	62.42	164481	162.33	102545	26.08	267026	188.41
March 1970	204715	125.34	312403	124.20	517118	249.54	192570	36.54	709688	286.08
of which : Direct Finance to Farmers*										
June 1969	37031	11.06	122989	29.16	160020	40.22	97378	13.39	257398	53.61
March 1970	203419	46.53	299679	82.85	503098	129.38	188905	21.05	692003	150.43
2. Total for Small-Scale Sector (A+B+C)										
June 1969	37688	103.01	36801	153.79	74489	256.80	10791	37.30	85280	294.10
March 1970	55774	155.22	63309	214.86	119083	370.08	16047	48.51	135130	418.59
(A) Road Transport Operators										
June 1969	2	..	2322	5.48	2324	5.48	1207	2.74	3531	8.22
March 1970	1215	2.98	8071	15.88	9286	18.86	1870	5.47	11156	24.33
(B) Small-Scale Industries										
June 1969	37686	103.01	34446	148.05	72132	251.06	9574	34.54	81706	285.60
March 1970	54559	152.24	55217	198.72	109776	350.96	14167	42.94	123943	393.90
(C) Loans for setting up Industrial Estates										
June 1969	—	—	33	0.26	33	0.26	10	0.02	43	0.28
March 1970	—	—	21	0.26	21	0.26	10	0.10	31	0.36
3. Exports										
June 1969	—	70.42	—	123.97	—	194.69	—	68.74	—	263.43
March 1970**	—	84.00	—	147.77	—	231.77	—	72.31	—	304.08

Source : Special returns received from banks.

Note : The figures are as on the last Friday of the month.

* Including development finance to plantations.

** Provisional.

.. Below Rs. 50 thousand.

Table 18—Advances to Other Sectors by 14 Nationalised Banks

(Rupees lakhs)

	June 1969		March 1970	
	No. of Accounts	Amount	No. of Accounts	Amount
Retail Trade and Small Business	28037	1922	71148	4129
Self-employed	422	33	22233	656
Education	594	46	4035	180

Note : The figures relate to the last Friday of the month.

Source : Special returns received from banks.

Industrial Finance Corporation, State Financial Corporations, Land Mortgage Banks, etc). The banks have been increasing their investments in 'other trustee' securities at a faster pace than in Government securities, with the result that the share of Government securities in total investments declined from 82 per cent in March, 1967 to 80 per cent in March, 1968 and further to 79 per cent in March, 1969. At the same time, the proportion of investments in 'other trustee' securities to the total has increased from 11.9 per cent in 1967 to 14.9 per cent in 1968 and further to 16.1 per cent in 1969. These two types of securities continued to form the bulk of the total investments of banks, their proportion in the total increasing from 94 per cent in March, 1967 to 95.2 per cent in March, 1969. Of the balance, shares and debentures of companies accounted for 2.7 per cent at the end of March, 1969, as compared to 2.3 per cent at the end of March, 1967.

Banks' Earnings, Expenses and Profits

113. A complete picture of banks' earnings, expenses and profits for the year 1969 is not yet available. However, it would

appear from the published accounts of the State Bank of India and its seven subsidiaries that both income and expenditure of commercial banks have recorded a smaller rate of increase in 1969 than in 1968. The balance of profit (after providing for taxation, but before making other allocations) of the State Bank of India and its subsidiaries rose to Rs. 6.42 crores in 1969 from Rs. 6.02 crores in 1968. The rate of increase in income of these banks worked out to 14.3 per cent in 1969 as compared to 18.5 per cent in 1968. This is mainly due to the slower rate of growth in bank credit during the year 1969 than in 1968. The two important components of expenditure namely, interest paid on deposits and borrowings, as well as establishment expenses also showed a smaller rate of increase in 1969 than 1968. Thus, the increase in interest payments slowed down from 17 per cent in 1968 to 16 per cent, while that of establishment expenses dropped from 19.2 per cent in 1968 to 14.0 per cent in 1969. Consequently, the total expenditure of these banks recorded an increase of 14.8 per cent in 1969 as against 19.0 per cent in 1968. Despite increase in the unit cost of supervision of accounts consequent on substantial increase in the number of small borrowers, the 14 nationalised banks made larger gross profits on the whole in 1969 than they did in 1968.

114. The number of Indian banks operating abroad remained unchanged at 7 on December 31, 1969, but their offices excluding offices in Pakistan showed a decline from 60 to 56, following the conversion of 5 branches of Bank of Baroda and Bank of India in Uganda and the branch of the Bank of India in Nigeria into subsidiary companies in terms of the provisions of the Uganda Banking Amendment Act, 1969 and the Companies Decree No. 51 by the Federal Government of Nigeria and nationalisation of the Aden branch of the Bank of India. Country-wise, Malaysia had at the end of December, 1969 the largest number of Indian banks' offices *viz.*, 11, followed by Kenya, U.K. and Singapore with 10, 9 and 6 offices, respectively. Total liabilities/assets of Indian banks abroad decreased from Rs. 211 crores to Rs. 205 crores or by 3 per cent during the year 1969 mainly owing to the developments affecting Indian banks in Nigeria, Uganda and Aden, mentioned earlier. Total de-

posits of Indian banks abroad at the end of 1969 amounted to Rs. 158 crores as compared with Rs. 161 crores in the preceding year. Loans and advances decreased sharply from Rs. 66 crores to Rs. 51 crores largely in view of the decline in advances in the U.K. On the other hand, bills purchased and discounted increased from Rs. 37 crores to Rs. 40 crores, investments from Rs. 25 crores to Rs. 31 crores and money at call and short notice from Rs. 19 crores to Rs. 22 crores. The liquid assets* increased during the year by Rs. 8 crores to Rs. 85 crores and their ratio to deposits at 54 per cent showed a rise of 6 percentage points.

*Comprising cash in hand, balances with the Central Bank, balances in current account with other banks, money at call and short notice and bills purchased and discounted.

Table 19—Growth in Scheduled Commercial Bank's Offices, Deposits and Credit in India

	(Rupees crores)									
	Offices		Deposits (excluding inter-bank deposits)					Credit		
	Total	Annual Increase	Demand Deposits	Time Deposits	Aggregate Deposits	Annual Increase	Percentage Rise	Bank Credit	Annual Increase	Percentage Rise
End—June 1965	5727	+ 498	1275.1	1433.0	2708.1	+323.4	+ 13.6	2068.4	+294.6	+ 16.6
End—June 1966	6139	+ 412	1477.3	1645.9	3123.2	+415.1	+ 15.3	2271.4	+203.0	+ 9.8
End—June 1967	6620	+ 481	1664.6	1852.4	3517.0	+393.8	+ 12.6	2631.1	+359.7	+ 15.8
End—June 1968	7044	+ 424	1874.8	2094.2	3969.0	+452.0	+ 12.9	3102.9	+471.8	+ 17.9
End—June 1969	8045	+1001	2103.5	2542.3	4645.8	+676.8	+ 17.0	3598.8	+495.9	+ 16.0
End—June 1970*	9938	+1893	2307.3	2932.5	5239.8	+594.0	+ 12.8	4227.6	+628.8	+ 17.5

*Provisional.

Note : Data are based on weekly returns submitted by banks under Section 42(2) of the Reserve Bank of India Act, 1934, except number of offices.

Table 20—Commercial Banking Trends at a Glance
(as on the last Friday of June)

	(Rupees crores)					
	1961	1966	1967	1968	1969	1970
I. Number of Banks						
(i) Scheduled Banks	85	76	74	73	73	72
(ii) Non-Scheduled Banks	249	31	24	19	16	14
II. Number of Offices						
(i) Scheduled Banks	4250	6139	6620	7044	8045	9938
(ii) Non-Scheduled Banks	776	240	216	203	217	193
III. Aggregate Deposits						
(i) Scheduled Banks	1775.8	3123.3	3517.0	3969.1	4645.8	5239.8
(ii) Non-Scheduled Banks	43.4	25.0	24.5	26.2	28.0	23.5
IV. Demand Deposits						
(i) Scheduled Banks	725.3	1477.3	1664.6	1874.8	2103.5	2307.3
(ii) Non-Scheduled Banks	12.6	9.1	9.1	10.2	11.7	10.6
V. Time Deposits						
(i) Scheduled Banks	1050.5	1645.9	1852.4	2094.3	2542.3	2932.5
(ii) Non-Scheduled Banks	30.8	15.9	15.4	16.0	16.3	12.9
VI. Deposits as percentage of National Income	12.6	14.4	14.6	14.1	15.2@	16.6@
VII. Total Bank Credit						
(i) Scheduled Banks	1282.8	2271.8	2631.1	3102.9	3598.8	4227.6
(ii) Non-Scheduled Banks	27.6	15.0	15.1	12.8	16.4	11.3
VIII. Credit-Deposit Ratio						
(i) Scheduled Banks	72.2	72.7	74.8	78.2	77.5	80.7
(ii) Non-Scheduled Banks	63.6	60.0	61.6	48.9	58.6	48.1
IX. Investment in Government Securities						
(i) Scheduled Banks	548.8	918.8	922.6	975.6	1126.3	1187.6
(ii) Non-Scheduled Banks	11.0	5.6	5.4	6.6	6.7	6.0
X. Investment-Deposit Ratio						
(i) Scheduled Banks	30.9	29.4	26.2	24.6	24.2	22.7
(ii) Non-Scheduled Banks	25.3	22.4	22.0	25.2	23.9	25.5
XI. Cash and Balances with RBI						
(i) Scheduled Banks	144.6	195.3	258.8	269.5	380.3	340.8
(ii) Non-Scheduled Banks	3.2	1.7	1.9	2.1	2.5	2.0
XII. Cash-Deposit Ratio						
(i) Scheduled Banks	8.1	6.3	7.4	6.8	8.2	6.5
(ii) Non-Scheduled Banks	7.4	6.8	7.8	8.0	8.9	8.5

Notes :—1. The figures for 1961 relate to scheduled banks.

2. The figures for Non-Scheduled Banks in the last column relate to October, 1969.

3. The figures for June, 1970 are provisional.

(@) Based on National Income at current prices (estimated).

Balance of Payments

115. The external payments position continued to show further improvement during the year under review. Foreign exchange reserves increased substantially by \$ 278 million during 1969-70 (July-June) as against \$ 118 million in 1968-69 (July-June). Reserves benefited during the year on account of the allocation to India by the I.M.F. on January 1, 1970 of S 126 million in Special Drawing Rights; the first allotment under the Scheme which came into force on July 28, 1969 as a device for the deliberate creation of international liquidity by international agreement. On the other hand, repayments to the I.M.F. at \$ 187 million were \$ 59 million higher than in the previous year. Excluding transactions with the I.M.F.—allocation of SDRs as well as repayments to the Fund—refund of I.B.R.D. special deposits and the appreciation of the Deutsche Mark component of the country's reserve assets following the revaluation of DM in October, 1969, the increase in reserves during 1969-70 would amount to \$ 347 million as against that of \$ 261 million in 1968-69.

116. As a result of the improvement in the balance of payments position and in the foreign exchange reserves, India became subject to designation by the I.M.F. for the acceptance of SDRs from other SDR participants in exchange for convertible currencies. At the beginning of July, 1970, the Fund decided that India could be designated for a maximum amount of SDRs equivalent to \$ 14 million for the quarter July-September, 1970. Early in August, India thus accepted \$ 1.5 million equivalent in SDRs from other participants.

117. Details of current and capital account balance of payments transactions of which the end result was the impressive improvement in the country's foreign exchange reserves in July, 1969-June 1970 are not yet available. The latest detailed balance of payments compilations relate only to the calendar year 1969.

118. According to the balance of payments statistics for the calendar year 1969, there was a sizeable reduction in the aggregate import bill, particularly the free foreign exchange outlay on imports. Exports also showed a rise, but their contribution was marginal. The flow of external assistance, though on a smaller scale than in 1968, was also a contributory factor in

alleviating the pressure on the reserves. The debt service charges, however, remained burdensome, despite some measure of relief which continued to be provided by the donor countries.

Overall Trends

119. The aggregate import bill declined over the year by Rs. 263.0 crores, while exports increased by Rs. 48.3 crores, and the trade deficit was narrowed down by Rs. 311.3 crores to Rs. 165.2 crores. In addition, the deficit on invisible account, including official transfer payment transactions, contracted by Rs. 14.2 crores. Consequently there, was a sizeable reduction in the deficit on current account from Rs. 498.2 crores to Rs. 172.7 crores. Taking the current account and the "errors and omissions" together, the total deficit in 1969 amounted to Rs. 203.1 crores which was about one-third of that in 1968. The net inflow from capital transactions was on a relatively reduced scale.

Imports

120. As observed earlier, the aggregate import bill at Rs. 1,563.2 crores was lower than in 1968 by Rs. 263.0 crores. More than half of this decline was on account of imports financed out of own resources and the balance represented the fall in aid-financed imports. Nearly half of the fall in the aggregate import bill was accounted for by the lower outlay on foodgrain imports following the improved domestic supply position. In addition there was also a reduction in the outlay on imports of raw cotton and non-ferrous metals. Further, the continued progress in import substitution coupled with the moderate tempo of investment activity led to a reduction in the outlay on imports of machinery and transport equipment.

121. Sector-wise, imports on private as well as Government accounts were lower than in 1968. Private imports fell by Rs. 64.3 crores to Rs. 608.2 crores. Though all major items registered a fall, it was particularly significant in raw cotton and machinery. Government imports dropped by Rs. 198.7 crores to Rs. 955.0 crores, about three-fourths of the decline being accounted for by food-imports, both aid-financed and bought from own resources.

Table 21—India's Balance of Payments (Preliminary)

(Rupees crores)

	January-March 1969	April-June 1969	July-September 1969	October-December 1969	January-December 1969	January-December 1968
A. Current Account						
Imports c.i.f.						
(a) Private	147.9	149.8	157.9	152.6	608.2	672.5
(b) Government	245.9	203.3	272.5	233.3	955.0	1153.7
Total Imports (a+b)	393.8	353.1	430.4	385.9	1563.2	1826.2
Exports f.o.b.	343.7	343.1	352.5	358.7	1398.0	1349.7
Trade Balance	-50.1	-10.0	-77.9	-27.2	-165.2	-476.5
Non-Monetary Gold Movement (net)						
Official Transfer Payment (net)	+24.3	+7.3	+7.8	+4.0	+43.4	+11.9
Other Invisibles (net)	-20.0	-1.4	-17.6	-11.9	-50.9	-33.6
Current Account (Net)	-45.8	-4.1	-87.7	-35.1	-172.7	-498.2
B. Errors and Omissions (net)	+6.2	-32.4	-14.8	+10.6	-30.4	-143.6
C. Capital Account Private Capital (net)	+1.6	-16.2	-2.8	-9.7	-27.1	-9.8
(a) Long-term	+0.6	-17.2	-3.0	-9.8	-29.4	-13.0
(b) Short-term	+1.0	+1.0	+0.2	+0.1	+2.3	+3.2
Banking Capital (Net)	-16.9	+4.6	+14.8	-6.2	-3.7	+12.9
Official Capital (Net)	+120.1	+99.9	+129.8	+60.5	+410.3	+653.5
(a) Loans	+347.9	+164.5	+130.8	+134.7	+777.9	+886.5†
(b) I. M. F.	-28.5	-37.5		-45.1	-111.1	-73.2
(c) Amortisation	-36.2	-29.6	-47.5	-72.6	-185.9	-166.7
(d) Miscellaneous	-163.1	+2.5	+46.5	+43.5	-70.6	+6.9
Capital Account (Net)	+104.8	+88.3	+141.8	+44.6	+379.5	+656.6
D. Movement in Reserves (A+B+C)						
Increase (+)/Decrease (-)	+65.2	+51.8	+39.3	+20.1	+176.4*	+14.8

†Partly revised.

*Excludes changes due to appreciation.

Exports

122. After the set-back in 1966, exports registered a rise for the third year in succession to amount to Rs. 1,398.0 crores in 1969. However, the increase over the year at Rs. 48.3 crores, or 4 per cent, was much lower than in 1968, when it was 10 per cent. The slower rise in exports in 1969 reflected largely the fall in world prices for some of the commodities and partly the lower export availabilities. The marginal improvement in the total was brought about entirely by non-traditional items, notably engineering goods, leather manufactures and marine products. The set-back in the exports of traditional items was mainly accounted for by tea, jute manufactures and vegetable oils.

Invisibles

123. On invisible account, official transfer payment transactions resulted in a surplus of Rs. 43.4 crores as against Rs. 11.9 crores in 1968 (Table 21). The improvement reflected mainly larger receipts by way of food aid and interest relief grants and grants from P.L. 480 counterpart funds. As regards the other invisible transactions, the deficit widened from Rs. 33.6 crores to Rs. 50.9 crores due to the larger gross outgo. Gross payments at Rs. 454.7 crores were higher than in 1968 by Rs. 24.2 crores, the bulk of which represented the increased outgo on investment income account. Payments on investment income account, which amount to more than half of the total gross outgo, increased over the year by Rs. 15.1 crores to Rs. 248.3 crores; interest payments on loans and credits alone amounted to Rs. 186.8 crores as against Rs. 178.4 crores in 1968. In addition there was an increase in the outgo on account of insurance and miscellaneous services transactions, but this was moderated to some extent by the reduced outgo under private transfer payments. Gross receipts also increased over the year by Rs. 6.9 crores to Rs. 403.8 crores mainly as a result of larger investment income, following the higher interest rates prevailing abroad, and increased private unilateral transfers.

Capital Transactions

124. Capital transactions, as mentioned earlier, resulted in a net inflow of Rs. 379.5 crores as against Rs. 656.6 crores in 1968. The net flows pertaining to all the three sectors were adversely affected during the year. Following larger repayments of loans and repatriation of funds by oil companies, the net outflow on account of private capital movements increased from Rs. 9.8 crores to Rs. 27.1 crores. Under banking capital, there was a changeover from a net inflow of Rs. 12.9 crores to a net outflow of Rs. 3.7 crores. Almost the entire net outflow resulted from an increase in authorised dealers' foreign currency assets. In 1968, on the other hand, there was a sizeable reduction in their foreign currency assets which, though accompanied by a reduction in their foreign currency liabilities, resulted in a net inflow.

125. The net inflow under the official sector at Rs. 410.3 crores was lower than in 1968 by Rs. 243.2 crores. Utilisation of external assistance loans, which constitute the largest component of inflow into this sector, dropped from Rs. 891.4 crores in 1968 to Rs. 780.6 crores following the declaration in the disbursement of P.L. 480 counterpart fund loans. The outgo by way of repurchases from the I.M.F. (Rs. 111.1 crores) and amortisation payments (Rs. 188.1 crores) were also larger than in 1968. Miscellaneous capital transactions resulted in a net outflow (Rs. 70.6 crores) as against a net inflow (Rs. 6.9 crores) in 1968. All these together affected adversely the net inflow into this sector.

Regional Trends

126. The current account position with all the regions showed an improvement. While the surplus with the sterling area increased marginally by Rs. 2.4 crores, the deficit with the non-sterling area as a whole markedly narrowed down by Rs. 327.1 crores. The deficit with international institutions, which amounted to Rs. 53.4 crores, was, however, somewhat higher than in 1968 due mainly to the larger outgo on investment income account.

127. With all the regions there was an improvement in the trade balance. While the trade surplus with the sterling area increased, the trade deficits with the dollar area and O.E.C.D.

countries declined, and the deficit with the 'rest of non-sterling area' changed over to a surplus. Imports from all the regions, excepting those from the 'rest of non-sterling area', were marked down considerably, with the fall in imports from the non-sterling area as a whole accounting for more than 80 per cent of the reduction. Exports to the sterling area declined but the fall was more than made up by marked increase in exports to the non-sterling area, particularly to the 'rest of non-sterling area' and the dollar area.

128. On invisible account, including official transfer payment transactions, there was a drop in the surplus with the sterling area which offset in part the gain in the trade balance. With the non-sterling area, on the other hand, there was an increase in the surplus on account of these transactions which contributed further to the improvement in the current account position.

129. According to the statistics of foreign trade compiled by the DGCIS which are available for the financial year 1969-70 (April-March) the trade deficit narrowed down considerably to \$ 206 million from \$ 734 million in 1968-69. The reduction in the adverse trade balance during 1969-70, was due to a decline in imports of \$ 455 million and an increase in exports of \$ 73 million.

130. Exports (DGCIS data) during 1969-70 (April-March) at \$ 1,884 millions showed a growth rate of 4 per cent as compared with 13 per cent in 1968-69. The export performance during the first quarter (April-June 1969) was satisfactory with exports showing a 12 per cent rise. However, the poor performance in the next five months brought down the growth rate during the first eight months (April-November) of 1969-70 to barely 1 per cent. With a view to arresting the deceleration in the rate of growth of exports, a crash programme of exports was launched. The salient features of the crash programme are (i) encouragement for increasing exports ex-stocks and from scheduled production and (ii) encouragement for a fuller utilisation of idle capacity for exports through adequate supply of raw materials and other inputs both indigenous and imported. The main objective of the programme was to provide an immediate boost to exports so as to make good as far as possible in 1969-70, the shortfall in exports from the broad target set by the Planning Commission. Since a number of measures in the programme were of a somewhat long-term nature, they would have an impact on exports only in 1970-71. Nevertheless, in the last quarter of 1969-70 (January-March 1970) exports recorded an increase of 11 per cent reflecting partly the success of the crash programme. In the first two months of 1970-71 (April and May 1970), exports were 5 per cent higher than in the corresponding period of 1969-70. However, the sharp decline in exports in June 1970 (18 per cent over June 1969 level) due to the strike by bargemen at Calcutta port brought down exports during April-June 1970 to a level which was 3 per cent lower than that in April-June 1969.

131. Exports to all regions except Western Europe showed an increase during 1969-70. Significant increases were recorded in exports to Africa (21 per cent), Asia and Oceania (10 per cent) and Eastern Europe (15 per cent). Under Asia and Oceania, exports to ECAFE countries increased by 11 per cent mainly due to a rise of 13 per cent in exports to Japan. Exports to the USA also registered a modest increase (1.5 per cent). However, exports to Western Europe were lower by 13 per cent as a result of a decline of 18 per cent in exports to the U.K. and 10 per cent in exports to EEC countries.

132. The slowing down of the growth rate in exports during 1969-70 was due to lower exports of items like tea, jute manufactures, oilseeds, oils and oilcakes, cashew kernels and manganese ore. Exports of tea, cashew kernels, oilseeds, oils and oilcakes and manganese ore slumped both in terms of unit value and quantum. Export earnings from tea declined further by \$ 43 million in 1969-70, having declined by \$ 32 million in the previous year. There was a glut in the world tea market which reduced the unit value to Rs. 7.15 paise per kg. in 1969-70 as compared with Rs. 7.79 paise per kg. in 1968-69 and Rs. 8.86 paise per kg. in 1967-68. The decline in jute manufactures was the continuation of the downtrend of earlier years though the magnitude of decline in 1969-70 (5 per cent) was smaller than in the previous year (7 per cent). The cut-back in orders from the USA due to the recession and the keen competition from substitutes as well as from Pakistan resulted in a cumulative decline of 28 per cent in the value of exports of jute manufactures in the past four years. Exports

Table 22—India's Regional Balance of Payments on Current Account (Preliminary)

(Rupees crores)

	January-March 1969	April-June 1969	July-September 1969	October-December 1969	January-December 1969	January-December 1968
Sterling Area						
Imports c.i.f.	66.6	64.5	61.0	63.3	255.4	300.0
Exports f.o.b.	89.0	85.2	86.0	91.2	351.4	388.8
Trade Balance	+ 22.4	+ 20.7	+ 25.0	+ 27.9	+ 96.0	+ 88.8
Non-Monetary Gold Movement (Net)
Official Transfer Payments (Net)	+ 4.5	+ 0.2	— 0.1	+ 2.7	+ 7.3	+ 2.5
Other Invisible (Net)	+ 4.5	+ 1.6	+ 6.0	— 1.3	+ 10.8	+ 20.4
Current Account (Net)	+ 31.4	+ 22.5	+ 30.9	+ 29.3	+ 114.1	+ 111.7
Dollar Area						
Imports c.i.f.	125.0	122.2	144.8	102.3	494.3	680.5
Exports f.o.b.	78.9	71.1	71.1	69.5	290.6	262.3
Trade Balance	— 46.1	— 51.1	— 73.7	— 32.8	— 203.7	— 418.2
Non-Monetary Gold Movement (Net)
Official Transfer Payments (Net)	+ 22.3	+ 5.1	+ 5.8	+ 8.7	+ 41.9	+ 25.2
Other Invisibles (Net)	+ 6.5	+ 7.5	— 4.3	+ 0.6	+ 10.3	+ 22.0
Current Account (Net)	+ 17.3	— 38.5	— 72.2	— 23.5	— 151.5	— 371.0
O.E.C.D. Countries						
Imports c.i.f.	48.7	43.6	48.4	53.7	194.4	234.1
Exports f.o.b.	34.8	30.1	32.8	34.6	132.3	131.8
Trade Balance	— 13.9	— 13.5	— 15.6	— 19.1	— 62.1	— 102.3
Non-Monetary Gold Movement (Net)
Official Transfer Payments (Net)	+ 0.6	+ 2.2	+ 3.1	+ 4.0	+ 9.9	— 0.6
Other Invisibles (Net)	— 7.9	— 9.6	— 6.9	— 9.9	— 34.3	— 41.0
Current Account (Net)	— 21.2	— 20.9	— 19.4	— 25.0	— 86.5	— 143.9
Rest of Non-Sterling Area						
Imports c.i.f.	153.5	122.8	176.2	166.6	619.1	611.6
Exports f.o.b.	141.0	156.7	162.6	163.4	623.7	566.8
Trade Balance	— 12.5	+ 33.9	— 13.6	— 3.2	+ 4.6	— 44.8
Non-Monetary Gold Movement (Net)
Official Transfer Payments (Net)
Other Invisibles (Net)	— 13.1	+ 9.1	— 2.1	+ 6.0	— 0.1	— 0.7
Current Account (Net)	— 25.6	+ 43.0	— 15.7	+ 2.8	+ 4.5	— 45.7
International Institutions						
Imports c.i.f.
Exports f.o.b.
Trade Balance
Non-Monetary Gold Movement (Net)
Official Transfer Payments (Net)	— 3.1	— 0.2	— 1.0	— 11.4	— 15.7	— 15.0
Other Invisible (Net)	— 10.0	— 10.1	— 10.3	— 7.3	— 37.7	— 34.3
Current Account (Net)	— 13.1	— 10.3	— 11.3	— 18.7	— 53.4	— 49.3

of oilcakes, oilseeds and oils suffered due to inadequate domestic supply of these commodities. In the case of cotton yarn and manufactures, the decline in the exports of cotton piecegoods was more than made good by increased exports of cotton yarn. The decline in exports of cotton piecegoods was due to competition from Pakistan, Hong Kong and Japan and import restrictions in the U.K. Exports of cotton yarn increased by 127 per cent mainly due to larger exports to Burma, Yugoslavia, Czechoslovakia and the U.A.R.

133. Exports of engineering goods increased by 30 per cent, despite the shortage of certain categories of steel and other restraints that affected production in some engineering industries. The acute domestic shortage of steel reduced the quantity of iron and steel exports but in view of better price realisation, export earnings increased by 10 per cent. Export earnings from iron ore, chemicals, hides, skins, leather and leather manufactures, spices and fish and fish preparations also showed sizeable increases during the year.

Table 23—India's Principal Exports

Commodities	(U. S. \$ million)				
	1965-66	1968-69	1969-70	Percentage change in 1969-70	
				Over 1965-66	Over 1968-69
1	2	3	4	5	6
A. Items Showing a rise					
Cotton yarn and manufactures	148	134	154	+4	+15
Iron ore	89	118	126	+42	+7
Engineering goods	37	92	120	+224	+30
Hides, skins, leather including manufactures	79	104	119	+51	+14
Iron and steel	26	105	116	+346	+10
Spices	49	34	46	-6	+35
Chemicals	23	32	40	+74	+25
Fish and fish preparations	14	30	42	+200	+40
B. Items showing a fall					
Jute yarn and manufactures	384	291	276	-28	-5
Tea	241	209	166	-31	-21
Cashew kernels	58	81	77	+33	-5
Oilseeds, oils and oilcakes	82	91	73	-11	-20
Pearls, precious and semi-precious stones, unworked/worked	31	60	56	+81	-7
Manganese ore	23	18	15	-35	-17
C. TOTAL	1693	1811	1884	+11	+4

Source : DGCIS

134. During the four years 1966-67 to 1969-70, exports increased by 11 per cent showing an annual compound growth rate of 2.7 per cent. While the two major traditional exports viz., jute manufactures and tea declined by 8 per cent and 9 per cent per annum, compounded, there was substantial growth in exports of newer items. Iron and steel recorded the largest annual compound rate of growth (45 per cent), followed

by engineering goods (34 per cent), fish and fish preparations (32 per cent) and chemicals (15 per cent).

135. Imports, according to the DGCIS data, amounted to \$2,090 million during 1969-70 (April-March) showing a decline of 18 per cent from the level in 1968-69.

Table 24 — India's Principal Imports

Commodities	(U. S. \$ million)				
	1956-66	1968-69	1969-70	Percentage change in 1969-70	
				Over 1956-66	Over 1968-69
1	2	3	4	5	6
1. Food (excluding cashewnuts)	712	495	391	-45	-21
Of which :					
Cereals and cereal preparations	676	449	348	-49	-23
2. Raw cotton	97	120	110	+13	-8
3. Raw jute and mesta	53	22	7	-87	-68
4. Cashewnuts	32	42	37	+16	-12
5. Mineral oils	143	177	183	+28	+3
Of Which :					
(a) Petroleum, crude and partly refined	73	128	128	+75	-
(b) Others	70	49	55	-21	+12
6. Chemicals	221	378	346	+11	-35
Of which :					
(a) Fertilisers	82	186	90	+10	-52
(b) Others	139	192	156	+12	-19
7. Machinery and transport equipment	1034	685	524	-49	-24
Of which :					
(a) Machinery other than electric	701	488	372	-47	-24
(b) Electrical machinery	184	109	85	-54	-22
(c) Transport equipment	149	88	67	-55	-24
8. Iron and steel	206	115	108	-48	-6
9. Non-ferrous metals	145	119	99	-32	-17
10. Crude rubber (including synthetic and reclaimed)	10	7	13	+30	+86
11. Wood and other animal hair	11	15	23	+109	+53
12. Animal and vegetable oils and fats	32	26	39	+22	+50
13. Paper, paper board and manufactures thereof	28	24	32	+14	+33
14. Pearls and precious and semi-precious stones, unworked/worked	3	37	38	+1167	+3
15. Others	232	283	240	+3	-15
TOTAL	2959	2545	2090	-29	-18

Source : DGCIS

136. The decline in total imports in the current year was in foodgrains as well as non-foodgrain imports, while in the previous years, non-foodgrain imports had increased by 6 per cent. Imports of foodgrains (*i.e.*, cereals) declined by 23 per cent during 1969-70 mainly on account of comfortable supply position due to better crops. Fertiliser imports were less than half of those in 1968-69 largely as a result of an increase in domestic production. Imports of mineral oils were, however, higher by 3 per cent, mainly on account of larger imports of other petroleum products import of crude oil did not show any change. Imports of wool, animal and vegetable oils and paper and paper boards were higher than in the previous year. Imports of machinery and transport equipment registered a decline of 24 per cent in 1969-70, partly reflecting a further progress of import substitution. A part of the decline may also be due to lagged effect of the recession in industry in earlier years.

137. In the four years 1966-67 to 1969-70, overall imports declined by 29 per cent, the main areas accounting for the decline being foodgrains, raw jute and mesta, machinery and transport equipment, iron and steel and non-ferrous metals. The fact that a higher level of industrial output in 1969-70 as compared with 1965-66, has been sustained with a sharply lower level of non-foodgrain imports possibly points to the working of an import substitution effect in the Indian economy.

External Assistance

138. Authorisations of external assistance increased from an annual average of \$ 1,060 million during the Second Plan period to that of \$ 1,222 million during the Third Plan period and to \$ 2,099 million in 1966-67. Subsequently, however, the authorisations have substantially declined and also fluctuated considerably. They dropped sharply in 1967-68 (April-March) to \$ 949 million, or 45 per cent of the level in the preceding year. In 1968-69, they rose to \$ 1,275 million to fall even below the 1967-68 low to \$ 830 million in 1969-70. About 88 per cent of the drop in authorisations during 1969-70 as compared to 1968-69 was accounted for by loans, which declined over the year by \$ 391 million due to a sharp fall in authorisations from the U.S.A. Grants authorised also were \$56 million lower than in 1968-69. Only P.L. 480 Title I assistance was marginally higher (by \$ 2 million) than in the previous year.

Table 25—External Assistance*

(U.S. \$ million)				
Loans**	Grants	P. L. 480	Total	
		Aid @	(1+2+3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1. Amount undisbursed as at the end of March 1966	2,235	115	226††	2,576
2. Authorisations during				
(a) 1966-67	1,469	106	524	2,099
(b) 1967-68	603	22	324	949
(c) 1968-69	1,088	91	96	1,275
(d) 1969-70	697	35	98	830
Total	3,857	254	1,042	5,153
3. Utilisation during				
(a) 1966-67	903	126	480	1,509
(b) 1967-68	1,074	81	415	1,570
(c) 1968-69	888	87	113	1,088
(d) 1969-70	1,026	34	143	1,203
Total	3,891	328	1,151	5,370
4. Amount undisbursed as at the end of March 1970	2,186@	42†	108@@	2,336

*Excludes (a) grants under U. S. P. L. 480 Titles II and III and (b) special deposits placed by the I.B.R.D. with the Reserve Bank of India during 1967-68. Loan of \$ 15 million given to the Government out of I.B.R.D. deposits is included under loans in 1968-69.

**Includes authorisations and utilisation of P.L. 480 Convertible Local Currency Credits.

@ Represents rupee deposits against import of goods under U.S. P. L. 480 Title I programme; disbursements out of these funds by way of loans and grants are, therefore, excluded from columns 1 and 2.

††Adjusted for the lapsed agreements by \$ 184 million.

@ Adjusted for the devaluation of pound sterling and Danish kroner in November 1967, of French franc in August 1969 and for the revaluation of Deutsche mark in October 1969.

@@Adjusted for the lapsed agreements by \$ 9 million.

139. Utilisation of external assistance, however, showed some improvement during the financial year 1969-70. It amounted to \$ 1,203 million, \$ 115 million or 11 per cent higher than in 1968-69. Utilisation in a period normally depends on authorisations in the preceding periods. The higher level in the year under review reflected mainly larger utilisation of non-project loans. Foreign exchange outlay on servicing of the official assistance also rose from \$458 million* in 1968-69 to \$ 506 million* in 1969-70. This formed 27 per cent of our export earnings for the year, and 42 per cent of gross external aid utilisation. However, as this rise was smaller than the increase in utilisation, the net inflow of foreign resources under assistance programmes was higher over the year by \$ 67 million at 697 million.

Table 26—Inflow of Foreign Assistance :
Gross and Net

Year	(U.S. \$ million)				
	Gross aid utilisation	Amortisation pay-ments	Interest pay-ments	Total debt service (2+3)	Net in-flow of aid (1-4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1961-62	711	121	70	191	520
1962-63	933	101	81	182	751
1963-64	1,239	113	96	209	1,030
1964-65	1,520	145	110	255	1,265
1965-66	1,622	162	141	303	1,319
1966-67	1,509	210*	153	363	1,146
1967-68	1,570	275*	163	438	1,132
1968-69	1,088	276*	182@	458	630
1969-70	1,203	317*	189@	506	697

*Excludes figures of debt rescheduling/postponement as under :

	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70
Japan		3	6	17
I.B.R.D.		—	—	15
U.S.A.		—	—	6
Canada		—	—	1
Total		3	6	39

@Excludes figures of postponement of interest by the U.S.A. amounting to \$ 3 million each in 1968-69 and 1969-70.

140. As in the last year, loans dominated the aid authorised during 1969-70. They accounted for 84 per cent of the total aid authorisations, the shares of P.L. 480 aid@and grants being 12 per cent and 4 per cent, respectively. About 45 per cent (\$ 315 million) of the loans authorised in 1969-70 was non-project aid, 9 per cent \$ 51 million) for debt relief and the balance of 46 per cent formed loans tied to specific projects. The share of loans tied to projects has shot up over the year from 17 per cent to 46 per cent during 1969-70 as the entire amount provided by the I.B.R.D., the D.A., the U.S.A.I.D. and U.S. Eximbank and a large part of the assistance from Italy and Canada were tied to specific projects. A major part of the authorisations made by the U.K. and West Germany continued to be united to any projects as were the entire authorisations by Japan, the Netherlands and Belgium. Besides, West Germany, the Netherlands and Belgium liberalised, albeit, marginally, the terms of their authorisations. The rate of interest of West German loans (other than *bebt* refinancing credit) was $\frac{1}{2}$ per cent lower than the rate of 3 per cent per annum on the loans authorised in 1968-69 and the 1969-70 authorisation carried a longer grace period (8 years as against 7 years in the previous year as also longer maturities (30 years as against 25 years in the previous

*Excluding debt relief provided in the form of rescheduling and postponement of payments due by the IBRD, the USA, Japan and Canada, but for which the debt service payments would have been \$ 500 million and \$ 550 million, respectively, in 1968-69 and 1969-70.

@Excluding P. L. 480 Convertible Local Currency Credits, which are covered under loans.

year). The Netherlands also effected a similar reduction in the rate of interest and increased the maturity from 26 years to 30 years. In respect of the loan authorised by Belgium, the interest rate was reduced by a larger amount, from 3 to 2 per cent per annum, while grace and maturity periods were increased from 7 to 10 years and 24 to 29 years respectively. On the other hand, the terms of P. L. 480 assistance were further toughened during the year under review. The share of Convertible Local Currency Credits was raised to 60 per cent from 40 per cent applicable to the December 1968 agreement.

141. Cumulatively, external assistance authorised from August 15, 1947 to March 21, 1970 amounted to \$ 17,366 million, of which 68 per cent (\$ 11,889 million) was in the form of loans, 26 per cent (\$ 4,400 million) in the form of P.L. 480/665 and Third Country Currency assistance from the U.S.A. and the balance of 6 per cent (\$ 1,077 million) by way of grants. Assistance utilised up to the end of March 1970 is placed at \$ 14,823 million, \$ 9,688 million by way of loans, \$ 4,099 million by way of P.L. 480 aid and similar assistance and \$ 1,036 million in the form of grants.

142. The U. S. A. accounted for about 51 per cent of the total cumulative authorisations and about 54 per cent of the total cumulative utilisation. The I.B.R.D. and I.D.A. together accounted for about 13 per cent of authorisations as well as of the utilisation. Other countries that provided sizeable assistance were the U.S.S.R., West Germany and the United Kingdom in that order.

143. About one-half of the total U.S. aid to India has been under P.L. 480 Title I programme. Authorisations under this programme during 1969-70 amounted to \$ 248 million, a major portion of which was allocated for the purchase of foodgrains viz., wheat (\$ 145 million), rice (\$ 18 million and grains sorghum (\$ 14 million); and the balance for the purchase of cotton (\$ 40 million) and soyabean oil (\$ 28 million). An amount of \$ 3 million was also provided to finance a part of ocean freight costs. A major part (\$ 150 million or 60 per cent) of the P. L. 480 assistance was provided on credit terms. The total P. L. 480 assistance authorised up to the end of March 1970 amounted to

Table 27—Aggregate External Assistance

		(U.S. \$ million)			
		Loans	Grants	P. L. 480/665 Aid and Third Country Currency Assistance	Total
Authorisations					
1. Up to the Second Plan		3,145	545	2,411	6,101
2. During Third Plan		4,887	278	947	6,112
3. During 1966-67		1,469	106	524	3,099
4. During 1967-68		603	22	324	949
5. During 1968-69		1,088	91	96	1,275
6. During 1969-70		697	35	98	830
Total		11,889	1,077	4,440	17,366
Utilisation					
1. Up to the Second Plan		1,788	485	1,115	3,428
2. During Third Plan		4,009	223	1,793	6,025
3. During 1966-67		903	126	480	1,509
4. During 1967-68		1,074	81	415	1,570
5. During 1968-69		888	87	113	1,088
6. During 1969-70		1,026	34	143	1,203
Total		9,688	1,036	4,099	14,823

Note : Please refer to footnotes to Table 25.

Table 28—Aggregate External Assistance—Source-wise

		(\$ million)							
		Authorised upto March 1970				Utilised upto March 1970			
		Loans	Grants	P. L. 480/665 Aid and Third Country Currency Assistance	Total	Loans	Grants	P. L. 480/665 Aid and Third Country Currency Assistance	Total
I.B.R.D./I.D.A.		2,191	—	—	2,191 (12.6)	1,934	—	—	1,984 (13.1)
U.S.A.		4,076	362	4,400	8,838 (50.9)	3,589	353	4,099	8,041 (54.2)
U.S.S.R.		1,362	10	—	1,378 (8.0)	844	14	—	858 (5.8)
West Germany		1,191	23	—	1,214 (7.0)	1,042	22	—	1,064 (7.2)
United Kingdom		1,172	14	—	1,186 (6.8)	1,024	10	—	1,034 (7.0)
Japan		488	1	—	489 (2.8)	429	1	—	430 (2.9)
Others		1,409	661	—	2,070 (11.9)	822	636	—	1,458 (9.8)
TOTAL		11,889	1,077	4,400	17,366 (100.0)	9,688	1,036	4,099	14,823 (100.0)

Note : Please refer to footnotes to Table 25. Figures in brackets represent percentages to the total.

\$ 4,637 million, \$ 4,325 million against rupee deposits and \$ 312 million in the form of Convertible Currency Credits. The rupee counterpart funds accruing from the import of commodities under the programme have been allocated in the following manner :—

Allocation of P.L. 480 Counterpart Funds

	Amount (\$ million)	Percent- age to the total
1. Loans to the Government of India	2,643	61.1
2. Grants to the Government of India	839	19.4
3. Loans to private enterprise under the Cooley Amendment	281	6.5
4. For the use of the U.S. Government	562	13.0
Total	4,325	100.0

144. As in the last year, the Aid-India Consortium provided during 1969-70 debt relief assistance either in the form of fresh refinancing credits, postponements of payments due, re-scheduling of debt or cancellation/reduction of interest. The amount of debt relief assistance received during the year amounted to \$ 111 million, \$ 18 million larger than in the previous year because the U.K. made available the debt relief assistance which would have normally been made available in 1970-71.

145. For the year 1970-71, the Aid-India Consortium at its meeting held in Paris in May 1970 agreed on non-project assistance of \$ 600 million and debt relief assistance of about \$ 100 million and also recognised the need for project assistance amounting to \$ 400 million. However, on past experience, it is difficult to say whether actual authorisations would add up to these levels.

Table 29—Debt Relief Assistance
(U.S. \$ million)

	1968-69		1969-70	
	Autho- risation	Utilisa- tion	Autho- risation	Utili- sation
A. By way of refinancing credits				
1. Austria	0.9	0.9	1.1	1.1
2. Belgium	1.1	1.1	1.1	1.1
3. France	5.0	3.7	—@	1.3†
4. Germany (West)*	14.6	14.4	15.5	17.2
5. Italy	5.5	—	7.3	—
6. United Kingdom	18.0	18.0	36.0	36.0
Total A	45.1	38.1	61.0	56.7
B. By way of postponement of payments				
1. I.B.R.D.	15.0	15.0	15.0	15.0
2. U.S.A.	8.7	8.7	8.7	8.7
3. Canada	0.9	0.9	0.9	0.9
Total B	24.6	24.6	24.6	24.6
C. By way of re-scheduling of payments				
1. Japan	16.8	16.8	19.6	19.6
Total C	16.8	16.8	19.6	19.6
D. By way of Grants (Interest relief)				
1. Canada	1.1	1.1	—	—
2. Germany (West)	4.8	4.8	4.8	5.0
Total D	5.9	5.9	4.8	5.0
E. Interest reduction				
1. Austria	0.5	0.5	0.5	0.5
2. Netherlands	0.6	0.6	0.6	0.6
Total E	1.1	1.1	1.1	1.1
GRAND TOTAL	93.5*	86.5	111.1	107.0

*Excludes cash assistance amounting to \$ 8.0 million each in 1968-69 and 1969-70.

@The Agreement for French commitments for 1969-70 was signed in April, 1970 for an amount of \$ 5.0 million.

†Represents utilisation of the 1968-69 credit.

International Monetary Situation

146. The international monetary situation improved considerably during the year under review as a result of the revaluation of the Deutsche mark and the French franc, agreement between the International Monetary Fund and South Africa on the question of sales of South African gold and the activation of the Fund's Special Drawing Rights Scheme, which was referred to in the last Report. The heavy speculative movements and consequent disorderly conditions on the international exchanges subsided after the devaluation of the French franc in August 1969 by 11.1 per cent and the upvaluation of the Deutsche mark in October 1969 by 9.3 per cent. Following the very strong position of the Canadian dollar in the exchange markets since the beginning of 1970 and a rising rate of growth of Canada's foreign exchange reserves, the Canadian authorities suspended on May 31, 1970 the existing par value of the Canadian dollar which promptly appreciated on the exchanges on being left to float on the market. Adoption by the members of the Fund of the scheme for deliberate creation of international liquidity by international agreement through a Special Drawing Rights Account in the Fund materially influenced the expectations of speculators in gold, short-term investors, who had built up their gold holdings in anticipation of an increase in the official price of gold, began to liquidate the holdings by the middle of 1969. Prospects of an agreement on future sales of South African gold further influenced the market downward. With the impact of an increase in the cost of holding gold with borrowed funds working in the same direction, the free market international price of gold thus sharply eased from the peak of U.S. \$ 43 per ounce in the spring to the official level of U.S. \$ 35 in December 1969 which was reached for the first time since 1958.

147. International trade too grew more impressively than in the preceding year in terms of value ; though at the end of 1969 some signs of a moderation of the growth rate began to appear in the imports of major industrial countries. In 1969, the rate of growth was 14 per cent while it was 12 per cent in 1968. As in the past, the growth of trade of the less developed countries lagged behind, but at 11 per cent was still 1.5 percentage points better than in 1968. Mainly as a result of the favourable turn in the position of the U.K., the U.S.A. and France, only partly offset by an opposite movement in the case of West Germany, the combined overall payments position of the industrial countries improve to a near balance in 1969 from that of a deficit of \$ 2.6 billion in 1968. The higher export earnings flowing from the larger demand from industrial countries reduced the current account deficit of the less developed countries from \$ 6.8 billion to \$ 6.1 billion. With inflow on capital account slightly reduced from \$ 7.9 billion to \$ 7.8 billion, the overall payments surplus of the less developed countries improved from \$1.1 billion in 1968 to \$1.7 billion in 1969.

148. Much as the international scene improved during the year under review, some major problems remained. There was a deterioration in the U.S. current account as a result of which the surplus contracted from \$ 1.4 billion to \$ 0.9 billion. There was also a substantial outflow of private capital and the two together resulted in a deficit of as much as \$ 7 billion in contrast to a position of near balance in 1968. The stringent monetary policy pursued by the U.S. monetary authorities to meet the domestic inflationary situation and balance of payments problems, however, resulted in attracting a substantial volume of foreign short-term funds to the U.S.A. and encouraging the U.S. banks to borrow abroad heavily. This inflow of funds more than covered the deficit and actually the U.S. balance of payments ended up with a larger overall surplus of \$ 2.8 billion in 1969 as against \$ 1.4 billion in 1968. All the same the balance of payments position of the U.S. remained an important disquieting feature of the world monetary system.

149. In the last two years, there has been a considerable amount of discussion of the international monetary situation and the adjustment mechanism. At one time opinion seemed to favour greater flexibility in exchange rates than available under the present system of fixed parities. In the latter part of the year under review, however, opinion in some influential quarters appeared to have reservations about greater flexibility. There is concern over the adverse repercussions that increased flexibility in market exchange rates might have on national authorities' obligations to undertake corrective measures in other fields, and on national authorities' willingness to hold dollar balances. Further, major industrial countries on the Continent view

departure from the present regime of fixed parities as a threat to the smooth working of the common market arrangements and to their long-term objective of evolving a common market currency.

150. The position in regard to international interest rates too continues to cause general anxiety. Contrary to the expectations of a section of international opinion, the changes during the year in the arrangements for international monetary co-operation and the European currency realignments, international interest rates failed to ease from the high levels reached in the preceding year. Active use of monetary policy by the U. S. to combat domestic inflation and deal with the balance of payments deterioration pushed rates higher generally, the Euro-dollar market providing the mechanism for quick international transmission. At the end of June 1970, commercial bank's Euro-dollar lending rate to prime borrowers was 9.9 per cent and domestic corporate bond yields in leading industrial countries varied between 8.4 per cent and 11.5 per cent. International rates have for some time been at historically high levels and portend serious difficulties for national investment efforts, particularly in capital-starved developing countries.

151. During the second half of the year under review, there has been widespread use of the created international liquidity in the form of the Fund's Special Drawing Rights. Although the SDR Scheme does not link the allocations with the developmental needs of the poor countries it is significant that the total utilisation of SDRs by such countries amounted to under a third of their initial allocation. In the context of national policies and attitudes of richer countries in respect of their domestic welfare and environment programmes, and in the context of their performance in respect of replenishment of IDA funds and bilateral developmental aid to poorer countries, it would appear desirable to provide for a positive relationship between created liquidity and developmental needs. IDA replenishment for the next 3 years at about \$ 800 million, which has been agreed to in July 1970, appears satisfactory. But the total aid flow to the less developed countries needs to be stepped up especially in view of the amounting burden of debt servicing payments.

152. An authoritative examination of development and international aid appeared in the form of the report "Partners in Development" presented in September 1969 to the World Bank by the Pearson Commission set up by it in August 1968, as referred to in the last year's Report. On the basis of the analysis of the record of recent years, the Pearson Commission came to the judgement that the majority of the world's poorer countries can achieve self-sustaining growth in 30 years if adequate assistance is provided to them by the richer countries. The Commission emphasized that though the record of development was mixed, it was "far better than generally realized." It pointed out that "in recent years the volume of aid has stagnated, the terms have hardened and the conditions have become more restrictive." The Commission advocates a partnership based on joint effort towards clearly defined economic goals and increases in development aid to be allocated on the basis of increasingly explicit criteria based primarily on economic performance. The Commission recommended *inter alia* that (a) official development assistance be raised from the 1969 average of 0.39 per cent of GNP to 0.7 per cent of each donor country's Gross National Product by 1975 and in any case not later than 1980; (b) the multilateral component of official aid should rise from 10 per cent to a minimum of 20 per cent by 1975; (c) aid funds should be made available for periods of at least 3 years; (d) the IDA assistance should be substantially increased, which could be accomplished through developed countries making available to the IDA a part of the SDR's allocated to them. The Commission has also recommended a reduction in the interest rate, lengthening of the maturity periods and progressive untying of credit. The Pearson Commission's Report, it is hoped, would change fundamentally for the better the present rather unfavourable international climate for aid, and pave the way for a rapid growth of the world's poorer economies.

Assessment and Prospects

153. The developments in the Indian economy reviewed in the foregoing paragraphs indicate the degree of success achieved by the economy during the past twelve months in stepping up output and mobilising resources for development. This period has also been notable for the several important measures taken by the authorities in the fields of banking, industrial policy and

social welfare policy. Foremost amongst these is the nationalisation of the 14 major commercial banks a year ago with the objective of ensuring that the developmental needs of all sectors of the economy are served by the banking system in conformity with national policy and priorities. An immediate consequence of this has been a much greater degree of co-ordination between the major units of the Indian banking system in regard to their operational problems. Another measure is the Lead Bank scheme under which banks have been allotted districts where they are required to survey the potential for banking development, to identify institutional and credit gaps and to take the initiative in endeavouring to fill them. This should result in orienting the banking system towards an 'area' approach and thus increasing its involvement in the process of economic development. Alongside of this, branch expansion programmes of commercial and co-operative banks have been speeded up and the banks themselves have announced a variety of schemes to attract more deposits and to provide credit to agriculture and small-scale industries. The IDBI on its part has taken several steps to promote the development of small and medium industries with special attention to the relatively under-developed areas in the country. Thus the institutional structure for short and long-term credit has been geared up much more closely to the planning process than at any time in the past. In regard to industry, several far-reaching changes have been announced in the Industrial Licensing Policy and in the case of medium and small-sized projects licensing policy has been liberalised considerably. Further, for basic, critical and strategic industries essential inputs will be made available on a priority basis. In the Budget of the Government of India for the current financial year significant incentives have been given for increasing savings in the form of various types of financial assets. Various special schemes designed to improve the lot of the less-privileged sectors of the economy have also been announced. All these developments provide a favourable climate for the economy to move on to a path of sustained high rate of growth.

154. Attention needs to be given, however, to certain aspects of the economy which give rise to concern. The most important of these is the re-emergence of a rising trend in prices, thus disturbing the relative price stability witnessed during the two years previous to the year under review. To some extent the price rise is due to the short-falls in the outputs of commercial crops and difficulties in arranging for imports in a short period. This emphasises the need to make the same kind of progress in agricultural technology of the major commercial crops as has been done in the case of foodgrains. But the more serious aspect of the price situation is that even where supplies have improved as in the case of foodgrains and industrial output, prices continue to move upwards.

155. The pressure on prices emanating from the demand side was somewhat reduced as indicated by the slower rate of growth of both money supply and time deposits. The decline in the rate of monetary expansion has taken place despite bank credit to the commercial sector expanding almost at the same rate as in the earlier years. The quantum of deficit financing as measured by the net bank credit to Government showed a very considerable reduction during the year under review. This was the result of better resource mobilisation as well as some short-falls in governmental expenditure reflecting lower level of public sector activity. There is, however, still a good deal of leeway to be made up in the matter of raising savings in the governmental sector. Currently the ratio of governmental savings to national income is in the neighbourhood of 1 per cent. To achieve the estimated volume of savings this ratio needs to be raised to 3.8 per cent by the end of Fourth Plan. Improvements in the working of public sector enterprises, reduction of the losses on commercial irrigation works and multi-purpose river valley schemes and resource mobilisation by State Governments can make a major contribution towards achieving this.

156. There has also to be a stepping-up in the savings on the part of the household sector of the economy. The various tax concessions given to savings in the form of financial assets as well as the new schemes of small savings should no doubt be of considerable help in this matter. But the major role will have to be played by the banking system by stepping up deposit mobilisation. In particular, banks have to make a concerted effort in mobilising deposits in the rural areas. With increasing incomes made possible by improvements in agricultural technology, the savings potential in the agricultural sector is bound to increase rapidly. However, the savings habits in this sector are considerably undeveloped. It continues to hold its

liquid assets largely in the form of currency, and its investments other than those in farm business largely take the form of jewellery or deposits in the unorganised money market. The various schemes of deposit mobilisation announced by the banks do not seem to have had as yet any significant impact on such habits. Banks will therefore have to develop appropriate strategies in deposit mobilisation to garner the savings of this sector. An important factor in the success of deposit mobilisation in the rural areas is the extent of credit facilities made available banks for economic activity in these areas. If banks continue to act merely as institutions mopping up savings from the rural areas and transferring them to the urban centres, they are not likely to have more than only a limited response to their efforts at deposit mobilisation. The surveys under the Lead Bank scheme will be of considerable help in revealing the existing institutional and credit gaps in these areas. These will have to be followed up by systematic and expeditious efforts by banks both commercial and co-operative to remove these gaps.

157. On the supply side of the economy, as has already been observed, good progress has been made in increasing output both in agriculture and industry. As far as agriculture is concerned, the progress of the monsoon so far has been satisfactory and it may be expected that barring unforeseen adverse developments, the forthcoming year should prove a good one from the point of view of supplies of foodgrains and raw materials of agricultural origin. On the industrial front, however, there have been some signs of a slowing down in the rate of growth of output during the first quarter of the current calendar year. Capital goods industries in particular show an absolute decline in output as compared to the corresponding period last year. Another feature of the industrial situation during the year under review is the high degree of variability in rates of growth; indeed there are quite a number of industries in all the three groups which have shown substantial declines in their output as compared to the previous year.

158. With the prospect of an increase in agricultural income and therefore, of a rise in demand for various types of consumer goods, it will be necessary to achieve a high rate of growth of industrial production to match the growing demand. In the short run, this can be achieved by increasing the utilisation of existing capacity through the provision of adequate raw materials, imported wherever necessary, and other inputs. Over a longer perspective, however, the ability of the economy to continue to increase output will depend primarily on the maintenance of a proper volume of investment in both public and private sectors. With the finalisation of the Fourth Five Year Plan, investment in the public sector can now be expected to proceed apace at the appropriate rate of growth. As regards the private sector, however, the position is not free from anxiety. While investment in agriculture and small-scale industry has been rising, there appears to be a slackening in the growth of investment in the large-scale sector of the industry. It is significant in this context that investment financing institutions have been suffering, not as in the past, from a dearth of resources but on the contrary from a dearth of suitable investment propositions. A continuation of such a state of affairs cannot fail to have serious adverse repercussions on the country's future economic development. With the prospect of sizeable increase in agricultural income and therefore in the demand for various types of consumer goods—durable and non-durable—agricultural machinery and equipment, inflationary pressures can build up rapidly unless industry has equipped itself to increase output by building up the necessary capacity. Projects with long gestation periods in particular require urgent attention if a satisfactory tempo of investment is to be maintained over a long-term perspective. The emphasis in the industrial licensing policy to make available all the necessary inputs on a priority basis to industries in the core sector will be of considerable benefit in this respect.

159. A notable feature of the working of the economy during the past twelve months is the substantial accretion to foreign exchange reserves. This is due largely to a sharp reduction in imports, a reflection, partly of the increase in foodgrains output and the progress of import substitution in industry and partly of the slow-down in investment activity commented upon earlier. On current indications the declining trend of imports is likely to be reversed soon and the reserves once again are likely to come under pressure. The declaration in the rate of growth of exports witnessed during the past twelve months gives cause for concern in this context. It also indicates the magnitude of the efforts that require to be made to attain on an average the 7 per cent per annum rate of growth in exports

over the next decade that has been considered as the minimum necessary for the development strategy aiming at self-reliant growth.

II. DEVELOPMENTS IN INDUSTRIAL FINANCE

Industrial Development Bank of India and other Term-lending Institutions

160. Apart from continuing its schemes for providing medium and long-term direct assistance and refinance/rediscount facilities for the development of the organised sector of the industry and promotion of exports of capital and engineering goods, the Industrial Development Bank of India (IDBI) adopted policy measures aimed at promoting the development of small and small-medium industries, particularly in the relatively underdeveloped regions in the country. To identify the industrial potential of backward region, the IDBI has also initiated regional surveys in collaboration with other term-lending institutions.

161. Total assistance sanctioned by the IDBI during 1969-70 (excluding guarantees) aggregated Rs. 66.6 crores or of the same magnitude as in 1968-69. Except direct industrial loans and refinance of export credits, assistance under all the other categories showed increases. A special feature of the IDBI's operations during the year was the step-up in assistance for financing exports under the scheme for direct loans and guarantee facilities to exporters of capital and engineering goods and services on deferred payment basis, which was introduced in December 1968; direct loans and guarantees for exports sanctioned rose from Rs. 7.1 crores in 1968-69 to Rs. 11.2 crores in 1969-70 with total sanctions aggregating Rs. 18.4 crores at the end of the year. The assistance sanctioned during the year covered exports of textile machinery, steel rails, automobile chassis, transmission line towers, copper and ACSR conductors and shuttering and scaffolding materials. At the same time, there was a marked decline in sanctions of refinance of medium-term export credits from Rs. 7.3 crores in 1968-69 to Rs. 1.3 crores in 1969-70. The flow of applications for such assistance has slackened with the introduction of the scheme for direct loans and guarantees for exports to which the exporters are switching presumably to take advantage of the lower average rate of interest. Direct assistance (loan and underwriting assistance) to industrial concerns (other than for exports) decreased from Rs. 18.4 crores in 1968-69 to Rs. 13.8 crores in 1969-70. In sanctioning direct assistance, the IDBI continued to pay attention to a number of small and medium projects and those promoted by middle class technician-entrepreneurs and/or located in less developed areas. Its indirect assistance was also spread over a larger number of small and medium borrowers than in the preceding year. Thus refinance of industrial loans was sanctioned in respect of 1966 applications for Rs. 15.7 crores in 1969-70 as compared to 321 applications for Rs. 14.1 crores in 1968-69. Of this amount, refinance sanctioned in respect of loans granted to small-scale industrial units and small road transport operators was Rs. 6.8 crores in respect of 895 applications. The number of machinery manufacturers who benefited from the Bank's rediscounting scheme increased from 104 in 1968-69 to 121 in 1969-70 and the number of purchasers from 335 to 455. The amount of bills rediscounted during 1969-70 at Rs. 24.1 crores was higher than the previous year's figure by Rs. 8.6 crores, bringing the total since inception of the scheme to 61.4 crores. During the period July 1969-June 1970 the IDBI subscribed Rs. 0.5 crore to the debentures of ICICI from its own funds. A feature of operations during the year was the step-up in disbursement of assistance from Rs. 48.7 crores in 1968-69 to Rs. 52.3 crores in 1969-70.

162. The operations of other all-India term-lending institutions on the other hand showed a declining trend during 1969-70 (April-March). Thus, sanctions of the ICICI (rupee and foreign currency loans, underwriting and direct subscriptions) declined from Rs. 37.0 crores in 1968-69 to Rs. 22.4 crores in 1969-70 though its disbursements at Rs. 19.8 crores were higher than in 1968-69 (Rs. 16.2 crores). The decrease in sanctions was almost entirely under foreign currency loans. Total sanctions of the IFCI (rupee and foreign currency loans, underwriting and direct subscriptions) were also lower at Rs. 21.0 crores in 1969-70 as compared to Rs. 22.7 crores in 1968-69 and its disbursements also declined from Rs. 19.5 crores in 1968-69 to Rs. 17.5 crores in 1969-70.

163. The total loans sanctioned by the 18 State Financial Corporations (including MHC) during the period April-March increased by 68.4 per cent to Rs. 32.5 crores in 1969-70 from

Rs. 19.3 crores in 1968-69. Disbursements during the same period were higher at Rs. 21.5* crores than Rs. 17.4* crores during the previous year. The loans outstanding on March 31, 1970 stood at Rs. 104.6 crores, registering a net increase of Rs. 12.7 crores over March 31, 1969. Of the total sanctions and disbursements at Rs. 32.5 crores and Rs. 21.5 crores during 1969-70. The share of small-scale industries was Rs. 19.8 crores (60.9 per cent) and Rs. 12.1 crores (56.3 per cent), respectively. The effective lending rates of all the SFCs to small-scale industries ranged generally between 7 per cent and 9 per cent per annum, and to other industries between 8 per cent and 9 per cent per annum; the rates were, however, within 8 per cent and 8 per cent, respectively, if concessional refinance was taken from the IDBI. Slightly higher rates were charged by some SFCs on loans to industries like cold storage, hotel and transport.

164. The IDBI's scheme for direct assistance on softer terms for the setting up of projects in the less developed areas was announced in July 1970. Under this scheme the Bank has decided to extend direct loans to industrial units in specified backward districts/areas at a concessional rate of 7 per cent as against the present normal rate of 8 per cent; extend the initial grace period for repayment of loans from the normal period of 3 years to 5 years; allow longer repayment period of 15-20 years and reduce the commitment charge on the undrawn balance of the loan. In cases of underwriting, the Bank would charge lower underwriting commission and in addition, subscribe relatively heavily to the share capital of projects in backward areas. Concessions under the scheme would be generally available for cases where the total project cost does not exceed Rs. 1 crore; concessional finance for bigger projects would be extended on a selective basis.

165. In order to stimulate the interest of SFCs and banks in fostering the industrial development of the backward regions and to encourage the flow of institutional finance to such regions, the IDBI decided in April 1970 to provide refinance to banks and SFCs, to the full extent, at a concessional rate of 3½ per cent, in respect of all eligible loans in specified backward districts/areas to small and medium-scale units upto Rs. 20.00 lakhs, provided the effective rate charged by the primary lender does not exceed 6 per cent. While deciding its terms of refinance, the IDBI would also take into account incentives, such as dispensing with levy of commitment charge, longer repayment period with an initial moratorium for more than 2 or 3 years, deferment of payment of instalments of principal and interest in the initial years, etc. which the financial institutions might offer to small and medium sized projects in the backward areas. To enable the SFCs and banks to assist a large number of small-scale units, the IDBI lowered, effective May 13, 1970, the minimum amount of loans to be eligible for refinance to small scale industrial concerns covered under the Credit Guarantee Scheme from Rs. 20,000 to Rs. 10,000. In the sphere of rediscounting of machinery bills, in order to provide the State Electricity Boards with supplementary finance for carrying out their expansion programmes involving large capital expenditure, the IDBI raised, with effect from March 24, 1970, the maximum yearly limit upto which a single purchaser-user can avail of the facilities under the scheme from Rs. 50 lakhs to Rs. 100 lakhs in respect of State Electricity Boards. As a part of developmental and promotional functions the IDBI has undertaken surveys to identify industrial potential in the backward areas and assess the infrastructure facilities available, supply of raw materials and market prospects for development of industries which could be advantageously located in such areas. The first two surveys of this type, covering the State of Assam and the Union Territory of Tripura, were completed in June 1970. Similar surveys have been planned for other areas also.

166. During the year, the IDBI opened a regional office each at Calcutta, Madras and New Delhi. Besides dealing with requests for direct and refinance assistance upto Rs. 20 lakhs or so, these offices will also rediscount bills/promissory notes arising out of sale of indigenous machinery on deferred payment basis upto Rs. 5 lakhs for each set of bills. Besides, a separate cell has been constituted at the head office in Bombay to attend to requests for refinance and rediscounting assistance, upto the above-mentioned limits emanating from the Western Region.

*Excluding disbursements on account of guarantees of Rs. 0.5 crore in each of the two years.

The Bank has also decided to form Regional Committees to help and guide the regional offices and to take decisions for sanction of assistance; a committee for the Calcutta Regional Office has already been constituted. The IDBI has also decided to open small branch offices at the other State Capitals to establish liaison with the State and Central Government agencies, banks and other financing institutions and bodies of industrial interests.

Financing of Small-Scale Industries

167. The Working Group appointed by the Bank to suggest suitable modifications in Credit Guarantee Scheme submitted its report in October 1969 recommending a system of automatic cover based on principles of insurance. The Government approved the amendments to the Scheme as recommended by the Working Group and the modified provisions were brought into force from February 1, 1970. Under the modified Scheme, the guarantee is made available to all eligible advances on an automatic basis, in terms of an agreement executed by each approved credit institution with the Guarantee Organisation. The credit institutions which join the Scheme are required to report all their eligible advances in quarterly statements which form the basis for charging the guarantee fee at 1/10 of 1 per cent per annum on a quarterly basis. This change in procedure is expected to result in considerable saving of labour for the credit institutions and to expedite the flow of credit to the small-scale sector. So far, 117 approved credit institutions (including all the major commercial banks and the State Financial Corporations have joined the modified Scheme. The element of automaticity thus introduced in extending guarantees to credit institutions has necessitated test checks of the branches/offices of credit institutions to verify the correctness of the particulars given in their statements. This work has been taken in hand by the Guarantee Organisation.

168. The other major changes effected in the scheme are (i) the extension, for the first time, of scope of the guarantee to letters of credit, loan and deferred payments guarantees and acceptance credits opened on behalf of small-scale industrial units, i.e. covering all types of credit facilities except performance guarantees, (ii) replacement of extent of guarantee cover, which previously depended on the limit sanctioned, its utilisation and the ultimate amount defaulted by the borrower by a fixed coverage of 75 per cent of the amount defaulted or of the amount guaranteed, whichever is lower, (iii) raising of the maximum amount recoverable from the Guarantee Organisation in respect of guaranteed advances from Rs. 2 lakhs per account to Rs. 7.5 lakhs in respect of working capital advances and a further amount of Rs. 2.50 lakhs in respect of term loans per borrower.

169. The Scheme has made considerable progress over the years. The amount of outstanding guarantees at the end of March 1970 stood at Rs. 567 crores (provisional) as against Rs. 241 crores on June 30, 1969. The guarantee obligations arose in respect of 164 advances, the Government's share of the amount in default being Rs. 20.81 lakhs, since the inception of the Scheme up to June, 30, 1970. The Guarantee Organisation has so far recovered Rs. 5.95 lakhs in respect of claims paid accounts which represent full recoveries in 39 advances aggregating Rs. 3.77 lakhs from the inception of the scheme up to December 1969. The number and amount of advances notified to be in default (i.e. advances recalled by the credit institutions but no claims submitted so far) stood at 351 and Rs. 103.13 lakhs, respectively, as at the end of December 1969. In such cases, if in the opinion of the Guarantee Organisation, nursing of the accounts is likely to resuscitate the sick units, efforts are made to impress upon the credit institutions the desirability of nursing the advances granted to them by continuing the existing credit facilities or by extending additional accommodation, wherever necessary. It may be mentioned that the Guarantee Organisation on its part has been extending guarantee cover in respect of advances granted/continued for such purposes. The scope of the Scheme was extended during the year to 'custom service' units (i.e. concerns engaged in hiring out agricultural machinery such as crawlers and wheeled tractors, threshers, combine harvestors and equipment for tubewell boring, plant protection, etc.), mining units and units engaged in servicing and repairing of marine diesel engines.

170. During the period of ten months ending April 1970 there was a substantial stepping up in the flow of financial assistance from banks to small-scale industries. The total credit

limits sanctioned by the scheduled commercial banks to small scale industries increased by Rs. 161.7 crores to Rs. 754.2 crores as on the last Friday of April 1970, the increase in limits sanctioned in the corresponding period of 1968-69 being Rs. 170.9 crores. The number of units financed increased from 56,983 to 83,805 or by 47 per cent. The amount of outstanding advances aggregated Rs. 397.7 crores as on the last Friday of April 1970 which showed a rise of Rs. 112.1 crores over the end-June 1969 level. The total limits sanctioned by the State Bank of India and its subsidiaries as at the end of April 1970 amounted to Rs. 281.1 crores covering 37,982 units registering an increase of 32 per cent and 47 per cent, respectively, over the position as on the last Friday of June 1969. The total credit extended by the State Bank of India Group to small-scale industries as at the end of April 1970 amounted to Rs. 154.8 crores showing an increase of Rs. 51.8 crores over the level at end of June 1969. This increase was about one and a half times the increase in the corresponding period of the previous year. The bulk of the financial assistance provided by the State Bank of India and its subsidiaries is covered under their 'liberalised Scheme.' The total limits (working capital as well as term finance), sanctioned by the State Bank of India and its subsidiaries under the scheme as at the end of March 1970 amounted to Rs. 260.6 crores recording an increase of Rs. 80.0 crores over the end-March 1969 figures. The total outstanding as at the end of March 1970 amounted to Rs. 146.9 crores showing an increase of Rs. 54.8 crores over the level as at the end of March 1969. The scheme for extending financial support to craftsmen and other qualified entrepreneurs formulated by the State Bank of India and its subsidiaries in 1967 made further progress during the period under review. The number of units assisted as at the end of March 1970 was 297 for an aggregate limit of Rs. 3.35 crores as against 98 units for limits of Rs. 0.90 crore as at the end of March 1969. The State Bank of India Group has considerably simplified its lending procedure for small-scale units. Thus all small-scale units whose working capital requirements do not exceed Rs. 50,000/- will be granted credit facilities on hypothecation basis on a single account in lieu of several accounts such as the lock and key, mandi type, factory type, overdraft against bills, overdrafts for margins, etc. Further, in order to accelerate the flow of credit to artisans/craftsmen/small units located in Rural Industries Projects, a special scheme has been introduced in terms of which financial assistance upto Rs. 5,000/- at a concessional rate of interest is made available to units located in these areas.

171. The performance of the 14 major banks, which were nationalised in July 1969, was particularly notable in respect of the number of small-scale industrial units financed by them. Between end-June 1969 and end-April 1970, the total number of units financed by these banks recorded an increase of 13,145 as against a rise of 6,787 in the corresponding period of 1968-69. The increase in the amount of outstanding advances by these banks during the ten months ended April 1970 was Rs. 52.2 crores as against Rs. 38.7 crores in the corresponding period of 1968-69.

172. Following the lead given by the State Bank of India and its subsidiaries, a number of banks including Central Bank of India, Punjab National Bank, Bank of India, Bank of Baroda, United Bank of India, Allahabad Bank, Union Bank of India, Syndicate Bank and Bank of Maharashtra have formulated special schemes for providing finance to qualified entrepreneurs, who have requisite technical ability and worthwhile small-scale industrial projects but do not possess necessary financial resources of their own. Most of the banks have also liberalised their terms and conditions with regard to margin, security, rate of interest, etc. for financing small-scale industries. Some banks have established separate departments/cells to look after the financing of the small-scale industrial sector while all the major banks have also evolved schemes for training their officials in effective financing of small-scale industries.

173. In March 1969, advances to small road transport operators and loans granted for setting up of industrial estates for small-scale industries were made eligible along with lending to small-scale industries, for the purpose of fulfilment of targets prescribed by the National Credit Council. Similarly in February 1970, advances to water transport operators were also included for the purpose of these targets. The total limits sanctioned by the scheduled commercial banks to small road and water transport operators as on the last Friday of April 1970 showed an increase of more than three times as compared with the position as at the end of June 1969. The total sanctions as on the last Friday of April 1970 amounted to Rs. 34.4 crores in respect of 10,669 units as against Rs. 11.1 crores in respect of 3,091 units at end-June 1969; the outstandings were

Rs. 28.3 crores and Rs. 8.2 crores, respectively. As regards industrial estates, as on the last Friday of April 1970, eight scheduled commercial banks had sanctioned loans to the extent of Rs. 1.15 crores covering 31 accounts for setting up such estates; the amount outstanding was Rs. 36 lakhs.

174. With a view to bringing together, on a common platform, the representatives of the various agencies catering to the credit and other needs of small industries, it was felt desirable that the State Governments should set up State Level Co-ordination Committee for small-scale industries in each State. At the instance of the Bank, such Committees have been set up by the Governments in Assam, Haryana, Madhya Pradesh, Punjab, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal and by the Delhi Administration; Bihar has set up a Co-ordination Committee for industry as a whole.

Unit Trust of India

175. The Unit Trust of India recorded a further rise in the sale of units during 1969-70. Sale of units during the year ended June 30, 1970 amounted to Rs. 22.83 crores as compared with Rs. 17.16 crores in the preceding year. Repurchases of units by the Trust were at Rs. 2.04 crores as against Rs. 1.67 crores. As on June 30, 1970, the aggregate value of units sold and outstanding amounted to Rs. 77.44 crores, the total number of unit-holders registered with the Trust being over 3,33,000. The sustained expansion in sales would indicate the growing popularity of units as a medium of investment.

176. In pursuance of its basic objective of promoting savings among various sections of the community, the Unit Trust of India introduced a 'Children's Gift Plan' effective July 1, 1970. The Plan seeks to provide to parents, relatives of a minor child and others a facility whereby units will be issued in favour of a minor child who is the sole beneficiary. Further, the child in whose name the unit certificate has been issued, can deal with the units only from the date on which he completes the age of 21. Meanwhile, the income on the units held will be deemed to have been reinvested in further units. By the time the child attains the age of 21 years, capital in the form of units would have been accumulated in favour of the child in a convenient manner which would be available for major needs such as the beneficiary's marriage, education, etc.

177. There was further expansion in the network of agents who canvass sale of units among the investing public. The number of approved agents as on June 30, 1970 stood at 2,303 as compared with 1,775 a year ago; the corresponding figures for approved stock brokers were 315 and 286. Besides sales over the counter, units are on sale at all branches of leading banks which have contributed to initial capital of the Trust and over 15,000 post offices throughout the country.

178. Total investments of the Trust as on March 31, 1970 aggregated Rs. 84.61 crores. Of these, ordinary shares of corporate enterprises accounted for Rs. 29.23 crores (34.5 per cent), preference shares for Rs. 11.40 crores (13.5 per cent), debentures for Rs. 34.35 crores (40.6 per cent) and Government securities and bonds of financial corporations and electricity boards for Rs. 4.88 crores (5.8 per cent). The balance of Rs. 4.75 crores (5.6 per cent) represented advance deposits for debentures and preference shares which the Trust had agreed to underwrite, application money for purchase of shares, treasury bills and advance call deposits.

III. BANKING LEGISLATION AND ORGANISATION

179. The major development affecting the banking system was the nationalisation of 14 Indian banks* with effect from

* Central Bank of India Limited,
The Bank of India Limited,
The Punjab National Bank Limited,
The Bank of Baroda Limited,
The United Commercial Bank Limited,
Canara Bank Limited,
United Bank of India Limited,
Dena Bank Limited,
Syndicate Bank Limited,
The Union Bank of India Limited,
Allahabad Bank Limited,
The Indian Bank Limited,
The Bank of Maharashtra Limited and
The Indian Overseas Bank Limited.

July 19, 1969. The Government of India promulgated an Ordinance called the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance, 1969 on July 19, 1969 in terms of which the Central Government acquired the undertakings of the 14 major Indian banks which had deposits of not less than Rs. 50 crores each on the last Friday of June 1969. After the take-over the undertaking of each bank including its assets, liabilities, rights, etc. Was transferred to and vested in the corresponding new bank which became a new statutory corporate body. The general superintendence and direction of affairs of each of the nationalised banks was vested in a Custodian who was authorised to exercise all powers that might be exercised by the bank. The Chairman of each of the nationalised banks who was holding office as such immediately prior to the nationalisation was appointed as Custodian for the corresponding new bank.

180. Immediately after the promulgation of the Ordinance, some writ petitions were filed in the Supreme Court and a full bench of 12 Judges passed on July 22, 1969 an interim stay order pending the disposal of the writ petitions in respect of three matters in the Ordinance. Under the stay order the Central Government was prevented from appointing any Advisory Board for any of the 14 banks, removing any of the 14 Chairmen of the banks who were given the designation of Custodians, and issuing any directions to any of the 14 banks contrary to the existing provisions of the Banking Regulation Act.

181. A Bill to replace the Ordinance was introduced on July 25, 1969 and was passed with certain amendments by both the Houses and became an Act on August 9, 1969. Immediately after the replacement of the Ordinance by the Act, the Supreme Court vacated on August 11, 1969 the stay order in respect of the Ordinance and issued a fresh stay order on September 8, 1969 following writ petitions filed against the Act. The second stay order did not debar the Government from appointing Advisory Boards but earlier prohibitions in respect of removal of Custodians and issue of directions by Government to any of the 14 banks were reimposed.

182. On February 10, 1970, the Supreme Court, while upholding the legislative competence of Parliament in the matter of acquisition of the undertakings of the banking companies, held firstly that there had been a hostile discrimination against the 14 banking companies insofar as they had been debarred after the acquisition of the undertakings from carrying on banking business when other banks were permitted to do so and secondly, the principles and methods laid down in the Act for determining the quantum of compensation proposed to be paid by the Government were invalid. As the provisions held void by the Court were not severable from the main Act, the entire was struck down.

183. The undertakings of the 14 banks which had been acquired by the Central Government with effect from July 19, 1969 under the authority of the Act reverted to those companies following the Act, being declared void. A fresh Ordinance was issued on February 14, 1970 which did not contain the offending provisions of the earlier Act. Under this Ordinance, the Government again took over the undertaking of each of these banks with effect from the original date, i.e.; July 19, 1969. This Ordinance, unlike the void Act, did not set out any principles for the determination of the compensation to be paid to each of the 14 limited companies whose undertakings were acquired, but fixed a specific amount of compensation to each of the 14 nationalised banks to be paid within 60 days from the date the banking company applies for it. These banking companies were given three options or any mix of these, i.e.; in the form of cash, 10 year Central Government securities at par carrying 4½ per cent interest per annum, and 30-year Central Government securities at par carrying interest at 5½ per cent per annum. Of the 14 nationalised banks, two banks (Allahabad Bank Ltd. and the Indian Overseas Bank Ltd.) opted for payment of the entire amount of compensation in cash and the remaining 12 banks opted for payment of compensation, partly in cash and partly in Government securities. In the case of the former two banks, the first instalment of compensation in cash has since been paid and in the case of the latter the entire compensation has been paid.

184. The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill to replace the Ordinance issued on February 14, 1970 was introduced in Parliament on February 27, 1970 and was passed without any amendment by both the House towards the end of March, 1970. The Bill received the assent of the President on March 31, 1970.

185. Under Section 9 of the Act, the Central Government is authorised to make a scheme, after consultation with the Reserve Bank for carrying out the provisions of the Act, which may provide, *inter alia*, for the constitution of the Board of Directors of the corresponding new banks, their capital structure, reconstruction and amalgamation. The statute prescribes that each Board of Directors will have to include representatives of employees and depositors of the bank and such other persons as may represent the interests of farmers, workers and artisans. Pending the constitution of such a broad-based Board of Directors envisaged under the scheme, the Central Government is empowered to appoint, in respect of each of the 14 banks, the first Board of Directors consisting of not more than 7 persons who would continue to hold office till the broad-based Board of Directors is constituted under the scheme. The Act also empowers the Government to issue to nationalised banks directives on matters of policy involving public interest after consultation with the Governor of the Reserve Bank.

186. In view of the uncertainty arising out of the writ petitions, the Government did not consider it advisable to appoint Boards of Directors for the nationalised banks. Pending the constitution of regular Boards of Directors, each of the 14 banks was advised by the Reserve Bank of India in September 1969 to form an Internal Management Committee of senior officials to which all matters that might normally have been brought before the Boards of Directors could be referred. The Bank provided an official nominee for each Internal Management Committee which met a few times every month. Having regard to the responsibilities devolving on the Custodians in the absence of Board of Directors, the Reserve Bank issued a statutory direction on January 22, 1970 requiring each of the 14 banks to obtain the prior approval of the Reserve Bank before putting through certain transactions. Important among these transactions were (i) grant of certain types of advances in excess of Rs.25 lakhs, (ii) investments in excess of Rs.1 lakh in shares and debentures of joint stock companies or advances against them above Rs. 5 lakhs, (iii) appointments and extension of services of senior executives, (iv) expenditure on land/buildings above specified amounts and making provisions out of profits for 1969. Even after the promulgation of the Ordinance on February 14, 1970 and the passing of the Act on March 31, 1970, these statutory directions of the Reserve Bank continued to be in force.*

187. On July 18, 1970, Central Government in consultation with the Reserve Bank of India constituted the first Board of Directors for each of the nationalised banks. Every Director of the first Board of Directors shall hold office until the broad-based Board of Directors is constituted in accordance with the scheme made under Section 9. The Government in consultation with the Reserve Bank is working out the details of a scheme for constituting a more broad-based Board of Directors.

188. The nationalised banks have also been instructed to take suitable steps for effecting the transfer of the foreign business of the existing banks to the corresponding new banks. While such transfer has been effected in most of the cases, in Uganda, the two nationalised banks concerned, viz; Bank of Baroda and Bank of India, as mentioned in Chapter II have formed subsidiary companies to comply with the local legal requirements. The Government of Uganda has since, acquired majority shares in these subsidiaries. As regards the branches of the nationalised banks in Malaysia where State-owned or State-controlled banks are not permitted to carry on banking business, the matter is engaging the attention of Government and the Reserve Bank of India.

189. The broad aims of nationalisation of banks as stated in the preamble to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, are "to control the heights of the economy and to meet progressively and serve better the needs of development of the economy in conformity with national policy and objectives." It will be the endeavour of the nationalised banks to ensure that the needs of productive efforts of diverse kinds irrespective of size and social status of the borrower and, in particular, those of farmers, small-scale industries and self-employed professional groups, are met in an increasing measure. It will also be a primary objective of nationalised banks to foster actively the growth of new and progressive entrepreneurs and to create fresh opportunities for backward areas in different parts of the country.

*These were withdrawn on August 14, 1970.

190. In the context of these objectives, a number of changes in the banks attitudes and methods of work were called for. Particularly, it became necessary for them to re-orient the concept of security for loans, to pay special attention to the growth potential and developmental needs of local areas where the branches are situated, to take better care of the requirements of under-developed areas and backward sections of the population, to forge close relations with developmental and term financing institutions, to reach mutual understanding with State Governments, to ensure that large borrowers do not have more access to resources of the bank than is actually required for productive use and to prevent use of credit for speculative and other unproductive purposes. Simultaneously, they were required to intensify their efforts, through a co-ordinated branch expansion programme, for mobilisation of deposits in all parts of the country and from all sections of the people, ranging from affluent businessman to the harassed housewife.

191. During the pendency of the suit the Government refrained from giving any directions to the 14 banks or taking any steps which would constitute interference with the internal management of the banks. The Prime Minister had a meeting with the Chairman of the State Bank and the 14 Custodians on September 30, 1969 and explained to them the Government's general attitude. Further, broad understandings were arrived at between Government officials and banks' management through frequent informal discussions. The Reserve Bank of India also lent its advice and good offices. All these informal approaches have not been unsuccessful. In keeping with the accepted aims and objectives of nationalisation, the nationalised banks continued to make efforts to improve the public relations and identify themselves in a growing measure with viable development in diverse forms.

192. They effected organisational changes to set up different cells or departments to handle proposals for advances to small-scale industries as well as to agriculture. To handle the work, trained staff have been appointed and services of experts have been secured for consultation. Field officers have also been recruited, whose primary function would be to find out prospective customers, contact them for ascertaining their requirements, prepare regular proposals and put them before the cells and, where necessary, arrange to transmit them to head offices. They would also ensure proper utilisation of advances granted and arrange to effect the recovery of loans as and when due. Arrangements have been made for giving extensive publicity through newspapers and periodicals in regional languages regarding the type of facilities provided by the banks. Powers have been vested in branch managers to sanction as many proposals as possible without reference to higher authorities.

193. For improvement of their working procedure and reaching a better understanding among themselves as well as with public and the State Governments, the chief executives of the public sector banks set up a Co-ordination Committee in which matters of mutual concern and public interest are discussed and examined in depth.

194. With a view to instituting a comprehensive scheme to cover the credit risks incurred by banks and other financial institutions in granting loans to various categories of small borrowers, the Government set up a Committee to evolve a suitable scheme to provide for insurance of such credits. The Committee has submitted its report to the Government and the proposal for establishing a new credit guarantee organisation has been approved by the Government.

195. In order to entrust progressively to the nationalised banks the Government Treasury and other allied business which are handled at present by the State Bank of India and its subsidiaries at places where the Reserve Bank does not have offices, a Committee has been set up to evolve a scheme for this purpose. Details of the scheme for entrusting the conduct of Government Treasury and other allied business to the nationalised banks are being finalised.

196. An expert committee was set up by the Bank to examine whether it would be desirable to establish a single institution to take over and run all the foreign branches of the public sector banks and whether such institution should handle the entire foreign exchange business of Indian banks. The committee has since submitted its report which is under consideration.

197. In terms of Section 75 of the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act 1969, the Reserve Bank of India Act, 1934 was amended to make Section 21A of the latter Act also applicable to the autonomous State of Meghalaya.

Lead Bank Scheme and Branch Expansion

198. The Lead Bank Scheme introduced by the Reserve Bank in December 1969 marks a major step towards the implementation of the two-fold objective of mobilisation of deposits on a massive scale throughout the country and of stepping up of lending to weak sectors of the economy. It may be recalled that a Study Group was constituted in October 1968 with the approval of the National Credit Council under the Chairmanship of Prof. D.R. Gadgil to go into the question of building up of an appropriate organisational framework for the banking system for meeting the problems of credit gaps of the economy. One of the important recommendations of the report of the Study Group published in October 1969 was that an area approach would need to be adopted by the commercial banks to identify and study local problems and evolve an integrated credit plan for the area. The Group was of the view that the lowest unit under the area approach has to be necessarily indetified with the district which is the main administrative unit of the country. In August 1969, the Governor of the Reserve Bank of India also appointed a Committee of Bankers, with Shri F.K.F. Nariman as the Chairman, to evolve a co-ordinated programme for ensuring the setting up of adequate banking facilities in the under-banked districts of the country. The Committee in its report, *inter alia*, recommended that banks would be allotted specific districts where they would take the lead in surveying the potential of banking development in extending branch banking and expanding credit facilities. The Reserve Bank accepted these principles and evolved the Lead Bank Scheme, under which districts were allotted to the State Bank Group (State Bank and its 7 subsidiaries), the 14 nationalised banks and 2 other Indian banks. Virtually, the whole of the country, except Greater Bombay, Calcutta and Madras and the Union Territories of Delhi, Chandigarh and Goa, has been covered in this way. A Lead Bank would be responsible for taking a leading role in surveying the credit needs, development of branch banking and extension of credit facilities in the districts allotted to it. More specifically a Lead Bank in a district would be required. (i) to survey the resources and potential for banking development in its district, (ii) to survey the number of industrial and commercial units and other establishments and farms which do not have banking accounts for which depend primarily on money-lenders, (iii) to examine the facilities for marketing of agricultural produce and industrial production, storage and warehousing space and the linking of credit with marketing in the district, (iv) to survey the facilities for stocking of fertilisers and other agricultural inputs and for the repair and servicing of the equipment, (v) to recruit and train staff for offering advice to small borrowers and farmers and for the follow-up and inspection of end-use of loans, (vi) to assist other primary lending agencies, and (vii) to maintain contacts and liaison residually with Government and quasi-Government agencies. While the other banks are not precluded from opening branches, the Lead Bank is expected to act as consortium leader and invoke the co-operation of other banks operating in the district in mobilisation of deposits, locating actual and potential credit needs and catering for these. In allotting the districts the Bank kept in view a number of important factors such as the contiguity of districts for ensuring viability of operations, provision of control points for developmental work and branch supervision as also a broad correspondence between the responsibilities allocated in terms of number of districts and resource-base of banks concerned. The Reserve Bank has drawn up a detailed proforma for the conduct of the survey by the concerned banks and has circulated it to them for collecting the necessary data. Some of the districts have already been surveyed by the banks and reports have been submitted to the Reserve Bank.

199. The Reserve Bank drew up in December 1969 a fresh programme of branch expansion under which 22 public sector banks and 8 private sector banks are required to open during the year 1970, 1,350 offices, of which 1,186 offices would be at unbanked centres. The 22 public sector banks are required to open 1,300 offices out of the total 1,350 offices. This programme covers not only the 453 unbanked towns (as per the 1961 Census classification), but also other unbanked centres

which in the opinion of Reserve Bank of India, should be served by bank offices because of their potential for developing agricultural business or for taking over treasury work. At places which are treasury and sub-treasury centres, banks will take over in due course Government cash work in pursuance of the policy of converting departmentally managed treasuries/sub-treasuries into banking ones.

200. The 30 banks which are covered by this programme have been supplied with a list specifying the names of unbanked towns/centres, treasury centres, etc. where they were required to open offices and each bank has been asked to indicate the names of centres where it proposes to open offices in the first half of 1970. The Bank has laid down that during the first half of 1970 (January-June) the concerned banks should open a minimum 400 offices in unbanked towns centres. This is in addition to unbanked centres which may be identified by the banks themselves or in the districts allotted to them under the Lead Bank Scheme where they would like to establish their offices. Further, 200 offices were to be opened during this period in centres which need additional banking facilities. Thus a total number of 600 offices was to be opened in the first half of 1970. The Reserve Bank has issued bulk licences to each of the banks in respect of the centres allotted to them. The banks have actually exceeded the target by opening 875 offices upto the end of June 1970 of which 741 are at unbanked centres.

201. The Bank has also asked the commercial banks to draw up a programme of opening offices in banked centres, including metropolitan centres and port towns for the year 1970. In considering the programme of expansion of offices in urban centres, the Bank kept in view the need to distribute more equitably the burden on banks of opening branches as between the rural and semi-urban centres on the one hand and the urban centres on the other. If the banks opened a number of offices in rural and semi-urban areas in terms of bulk licences already issued to them, as well as under the Lead Bank Scheme, they should be given sufficient scope for opening offices in urban centres. While choosing urban centres for opening more branches, the banks were required to keep in view the scope for better deposit mobilisation due to increase in business and industrial activities and the rapid development of suburban residential areas. The banks were asked to submit proposals in this regard to the Reserve Bank by the end of March 1970. After considering the proposals received from the various banks and finalising the number of offices to be allotted to each bank, the Bank has decided to issue licences as and when the banks become eligible for opening offices at urban centres. The licences will be issued to them for opening offices at urban centres in the ratio of one office in urban centre for every two offices opened after December 1969 in rural and semi-urban centres in the case of banks which had more than 60 per cent of their offices in rural and semi-urban areas as on December 31, 1969; in the case of other banks, the ratio is one office in urban centre for every three offices in semi-urban and rural centres.

202. In 1969-70, commercial banks opened as many as 1873 new offices as against 1024 offices in 1968-69 and 425 offices in 1967-68. Of these, State Bank of India and its Subsidiaries accounted for 425 offices and 14 nationalised Indian banks opened 1185 offices. Of the 1873 offices opened during the year, 1271 were at unbanked centres, the share of State Bank and its Subsidiaries being 312 offices and that of 14 nationalised banks being 821.

Table 30—Number of offices Commercial Banks in India

	As on June 30, 1969	As on June 30, 1970
1. State Bank of India.	1569	1875
2. Subsidiaries of State Bank of India	893	1060
3. 14 Nationalised Banks	4133	5318
4. Foreign Banks	130	131
5. Other Scheduled Commercial Banks	1320	1554
6. Non-Scheduled Banks	217	193
All Commercial Banks	8262	10131

203. Allowing for the change in the number of offices due to amalgamations, mergers, transfer of assets and liabilities, closure of offices, etc.; the number of offices of scheduled commercial banks increased by 1893. Offices of non-scheduled banks, however, declined by 24 during the period. At the end of June 1970 the total number of offices of scheduled and non-scheduled commercial banks exceeded the 10,000 mark, the number of scheduled and non-scheduled banks' offices being 9938 and 193, respectively. At the end of June 1969 the corresponding figures were 8045 and 217, respectively (Table 31).

Organisational Matters

204. Mention has already been made of the constitution of Boards of Directors for nationalised banks. Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949 which came into force from February 1, 1969, deals with the composition of the Board of directors of banking companies in the private sector. Out of 9 Indian banks in the private sector with deposits of Rs. 10 crores and above, 8 banks complied with legal provisions while in the case of another, its Board is not in conformity with law. The bank is taking steps to comply with the requisite provisions.

205. As regards banks having deposits below Rs. 10 crores, the Government of India allowed them time to comply with the relevant provisions initially upto February 1, 1970 which date has since been extended upto February 1, 1971. There are at present 39 banks in this category and a of these, 20 have reconstituted their Boards of Directors while the matter is being pursued with the remaining 17 banks. Of the other two banks in this category, one is taking steps for transfer of its assets and liabilities to another bank while the other is in a process of self-liquidation.

206. In accordance with Section 10B of the Banking Regulation Act, 1949, 29 Indian banks in the private sector have already appointed whole-time Chairmen with the approval of the Reserve Bank. In respect of 6 other banks, the Reserve Bank has agreed in principle to the proposals for appointment of whole-time Chairmen, while the proposals of 5 other banks are under consideration. The remaining 8 banks which have yet to comply with the provisions of this Section have been advised to take early steps in this regard. The Government of India has extended the time limit in this regard upto February 1, 1971 in respect of banks with deposits less than Rs. 25 crores as on February 1, 1969.

Inspection of Banks

207. In pursuance of the Bank's policy of periodical inspections of all banks with a view to assessing their financial position as well as methods of operation, 29 scheduled commercial banks and 7 non-scheduled banks were inspected under Section 35 of the Banking Regulation Act, 1949, during the period July 1969 to June 1970. Three banks were inspected under Section 45Q of the Act for judging whether there were any substantial irregularities in their winding up proceedings. Besides, two banks were inspected for the purpose of issue of a certificate under Section 44(1) of the Banking Regulation Act, 1949.

208. In the context of the wider role assigned to banks following the nationalisation of the fourteen major commercial banks, a re-orientation of the present system of bank inspections was called for. The objectives and mechanism of bank inspections were discussed at a Conference of the Heads of the Department of Banking Operations and Development held at Bombay in March 1970. It was agreed that the objectives of bank inspections should be the evaluation of the overall performance of each bank in different aspects like manpower planning and training, investment and credit portfolio management, profit planning, credit appraisal, industrial relations, control and reporting systems and developmental activities rather than a mere scrutiny of individual transactions. The same standards should not be applied to different categories of banks, i.e., State Bank of India Group, nationalised banks, Indian banks in the private sector and foreign banks. The inspections should aim at strengthening the bank's internal control system with a view to transferring to them in due course the audit element incorporated in the present inspection procedure. It was also generally agreed that the present system of inspection of banks should be replaced by a system which would provide for an examination

Table 31—Number of Offices opened and closed by Scheduled and Non-Scheduled Commercial Banks in India

	Scheduled Commercial Banks								Non-Scheduled Commercial Banks								All Commercial Banks							
	1967		1968		1969		1970*		1967		1968		1969		1970*		1967		1968		1969		1970*	
	Jan.- June	July- Dec.	Jan.- June	July- Dec.	Jan.- June	July- Dec.	Jan.- June		Jan.- June	July- Dec.	Jan.- June	July- Dec.	Jan.- June	July- Dec.	Jan.- June		Jan.- June	July- Dec.	Jan.- June	July- Dec.	Jan.- June	July- Dec.	Jan.- June	
1. New offices opened	207 (36)	196 (47)	222 (37)	443 (50)	565 (24)	772 (65)	1068 (190)		3	..	7	5	11	21	12		210	196	229	448	576	793	1080	
2. Changes due to amalgamation, mergers, transfers of assets and liabilities and inclusion in and exclusion from the second schedule to the R.B.I. Act, 1934	+4	+6	+10	+1	+1	+53	+3		—6	—6	—10	—1	—1	—53	—3		—2	
3. Existing offices closed	—7 (—2)	—6 (—1)	—4 (—1)	—6	—3	—3	..		—2	—1	—3	—1	..		—9	—7	—7	—6	—3	—4	..	
4. Overall variation in the number of offices	+204	+196	+228	+438	+563	+822	+1071		—5	—7	—6	+4	+10	—33	+9		+199	+189	+222	+442	+573	+789	+1080	
5. Number of offices at the end of the period	6620	6816	7044	7482	8045	8867	9938		216	209	203	207	217	184	193		6836	7025	7247	7689	8262	9051	10131	

Note :—1. Figures within brackets relate to the State Bank of India.

2. Data exclude administrative, seasonal, temporary, non-banking offices and offices outside India.

*Provisional.

of systems and performances and assessment of the financial position as also for *ad hoc* inspections and inspections of branches. To implement the new system of inspection, it was considered necessary to equip officers of the Department by giving them training wherever necessary, at the Indian Institute of Management Calcutta/Ahmedabad, National Institute of Bank Management, Bombay and other training institutions including those of the commercial banks. It was also felt that the existing Inspection Manual should be revised in the context of the changed circumstances. This task has been entrusted to a Special Cell set up in the Department. The Cell is also entrusted with the responsibility of devising the steps necessary to speed up the process of inspection. It was also decided to open offices of the Department in other States (where there is no office of the Department at present), so as to have closer contact with the local areas, better knowledge and appreciation of their needs as also to facilitate speedier disposal of the cases through adequate decentralisation. Officers of the Reserve Bank who have been appointed as additional directors under Section 36 AB of the Banking Regulation Act, 1949 in banks which are working under directions and are under formal observation, have been instructed to watch the performance in regard to developmental activities of these banks and not merely the progress of the implementation of the directions issued to them. In accordance with the above decisions, the Special Cell set up at the Central Department of the Banking Operations and Development has issued necessary instructions for carrying out centre-wise inspections of branches of commercial banks and has advised the regional offices to conduct such inspections at certain selected centres on an experimental basis.

209. During the period under review, comments/representations/observations were received from 39 banks including 9 banks carried over from the previous year. After examining the comments/representation/observations, directions were issued in 11 cases, while 7 were asked to submit periodical progress reports. Specific steps were advised in 7 cases. No action was considered necessary in the case of 5 banks. The remaining 9 cases were under consideration. In certain cases, representatives of banks were called for informal discussion with a view to specifically bringing to their notice the main defects in the working of the institutions concerned and impressing upon them the need for taking expeditious steps for removing the major defects in the banks' working. In cases where the findings of the inspection called for stricter control over the affairs of the concerned banks, suitable directions were issued to them for compliance. In the case of banks which are already working under certain directions issued following their earlier inspections, the directions were continued with suitable modifications. With a view to reducing the time-lag between the completion of the inspection and taking final action thereon while forwarding copies of inspection reports, 3 banks were asked to take certain specific steps and to submit quarterly progress reports. There are at present 29 banks (20 scheduled and 9 non-scheduled) working under directions issued by the Reserve Bank and submitting periodical progress reports. Out of these, in 19 cases, observers have been deputed to attend Board/Committee meetings of the banks. Besides the banks working under directions, there are at present 32 other banks which are submitting quarterly progress reports.

210. During the period under review, additional directors under Section 36AB of the Banking Regulation Act, 1949 were appointed in the case of 23 non-nationalised banks which were working under directions and also under formal observation. In the case of 6 banks, the additional directors were later withdrawn consequent on the withdrawal of the directions issued to these banks.

211. The progress made by the banks in the elimination of defects noticed in their structure and methods of operation was maintained during the year July 1969 to June 1970. In the light of improvements effected in their working, the Bank withdrew the directions issued to nine banks during the period while the directions issued to five banks were withdrawn consequent on their amalgamation with other banks. Consequently, the number of banks working under directions issued by the Reserve Bank declined from 43 to 29. Similarly, the number of banks subject to Reserve Bank's observation, either formal or informal, declined from 42 to 27 during the period under review. It is proposed to withdraw directions and to discontinue the arrangement for observation of the affairs in the case of one more bank. The banks have generally taken the required steps for the rectification of defects noticed in their working.

Bank Mergers

212. The Bank continued the policy of amalgamation or the transfer of liabilities and assets of weaker banks with a view to strengthening the banking structure in the country. During the period July 1969 to June 1970 four commercial banks were absorbed in this manner. The total number of commercial banks operating in the country at the end of June 1970 was 86 of which 72 were scheduled banks.

213. During the year under review, two banks were amalgamated under Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949, while two other banks transferred their agreed assets and liabilities to other banks, in terms of Section 293(1)(a) of the Companies Act, 1956 (Table 32).

214. During the period under review (July 1969-June 1970), the Central Government on the application of the Reserve Bank of India passed orders of moratorium on two more banks* under Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949. This brings the total number of banks under order of moratorium since September 1960 to 60, with deposits amounting to Rs. 49.95 crores. Both the Bank of Behar Ltd., and the National Bank of Lahore Ltd., which were subject to moratoria, have since been amalgamated with the State Bank of India, with effect from November 9, 1969 and February 23, 1970, respectively.

215. Of the 60 banks which were granted moratoria, 49 were amalgamated with other banks. Among these, depositors of 30 banks were given full credit for the entire deposits outstanding in the books of the transfer or banks at the very commencement of the relative schemes of amalgamation. The depositors of 11 other banks received credits in the books of the transferee bank in proportion to the readily realisable assets in addition to the preferential payment made to each depositor of the amount standing to his credit or Rs. 250 whichever was less. Of these 11 banks, the depositors of 4 banks have since received full payment. In the case of the 8 banks which were merged with other banks after the establishment of the Deposit Insurance Corporation in 1962, the depositors received *pro rata* credits to the extent of readily realisable assets of the transferor banks; in cases where the amount of *pro rata* credit was short of Rs. 1,500 or the balance in depositors' account whichever was less, the difference was made good by Deposit Insurance Corporation as provided for in the relative schemes.

Table 32—Bank Mergers, Amalgamations and Transfers of Assets and Liabilities

Year	Voluntary Amalgamations under Section 44A of the Banking Regulation Act, 1949	Compulsory Mergers under Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949	Other Mergers	Transfer of Assets and Liabilities under Section 293(1) (a) of the Companies Act, 1956	Total
1960	2	5	7
1961	1	30	2	3	36
1962	3	1	2	5	11
1963	2	1	4	15	22
1964	7	9	1	62	79
1965	5	4	3	21	33
1966	2	5	7
1967	3	6	9
Jan. 1968—June 1969	..	2	..	2	4
July 1969—June 1970	..	2	..	2	4
Total	20	49	17	126	212

†(1) Bank of Behar Ltd., and

(2) National Bank of Lahore Ltd.

†Banks taken over by the State Bank of India and/or subsidiaries.

216. Out of the remaining 11 banks which were under moratoria but were not amalgamated with other banks, Government of India has (as indicated in the previous report) framed schemes of administration in respect of two foreign banks, *viz.*, the Habib Bank Ltd., and the National Bank of Pakistan whose assets had been vested in the Custodian of Enemy Property for India. According to these schemes, payments are being made to the depositors/creditors at stipulated rates. One bank was allowed to go into voluntary liquidation and three banks were finally ordered to be wound up on an application made by the Reserve Bank of India under Section 38 of the Banking Regulation Act, 1949. One bank was allowed to amalgamate voluntarily with another bank under Section 44A of the Banking Regulation Act, 1949 while in the case of another a scheme of arrangement was sanctioned by High Court and an order was passed for its dissolution. The Government allowed moratoria to lapse in the case of 2 banks on their directors giving a guarantee undertaking to make payments from their personal assets, if necessary, while in the case of one bank the moratorium was allowed to lapse on its expiry and simultaneously the bank was refused licence under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949.

217. In terms of the scheme of amalgamation under Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949, the shareholders of the transferor banks were required to be paid the surplus amount left with the transferee banks after paying the depositors in full. The shareholders of 10 transferor banks have been paid in full, while *pro rata* payments are being made to the shareholders of the 10 other transferor banks.

218. The Commercial Bank Ltd., Kolhapur, filed a petition in the High Court of Bombay requesting for further extension of time for making payment of the balance (5 per cent) of the fifth and final instalment, which was payable to the depositors under the scheme of arrangement on or before April 1, 1968. The Bank of Karad Ltd., has taken over the New Fund business of the Commercial Bank Ltd. The Commercial Bank Ltd., is now taking steps to transfer the old fund business also to the Bank of Karad Ltd., and the necessary formalities thereto are being complied with. The Sahukara Bank Ltd., which has been working under a scheme of arrangement sanctioned by the High Court of former East Punjab, is expected to wind up the closed fund out of the sale proceeds of the forfeited shares amounting to Rs. 1.10 lakhs. The bank is negotiating with the New Bank of India Ltd. for the transfer of its New Fund business to it. The New Fund business of the Himalaya Bank Ltd., has been acquired by the State Bank of Patiala. A *pro rata* payment to all the creditors of the Old Fund at the rate of 6 per cent, has been made thereby bringing the total amount paid to creditors to 76 per cent out of a sum of Rs. 14,16,033 due to them according to the scheme sanctioned. The Bank of Bhopal Ltd., Bhopal, which was working under the scheme of arrangement sanctioned by the High Court of Madhya Pradesh has transferred the necessary funds, as per provisions of the scheme, to the United Commercial Bank for making payment to the depositors in full. The High Court has passed orders for the dissolution of the scheme and the bank subsequently has proposed to go into voluntary liquidation.

Licensing of Banks

219. During the period under review, four banks were granted licences under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949. No licence granted to banking companies earlier was cancelled, but licence was refused to one bank. Consequently, the number of banks, licences of which have been cancelled remained at 36 and that of banks which have been refused licence increased to 281. During the year the total number of licensed banks increased from 54 to 58 of which 56 were scheduled commercial banks. The 58 banks (including 14 banks which have been nationalised) which have been granted a licence and the 8 scheduled banks (State Bank of India and its seven Subsidiaries) which do not require a licence, together accounted for 98.9 per cent of aggregate deposits of all commercial banks as at the end of June 1970.

Liquidation Proceedings

220. During the year under review, four non-scheduled banks were dissolved by the High Court. Two banks went into voluntary liquidation after obtaining a certificate from the Reserve Bank under Section 44(1) of the Banking Regu-

lation Act, 1949, while two banks went into Court liquidation. Certificates under Section 44(1) of the Banking Regulation Act, 1949 were issued to four non-scheduled banks to enable them to go into voluntary liquidation. The Bank scrutinised 198 returns submitted by the liquidators of banks under Section 45R of the Banking Regulation Act, 1949, with a view to ensuring that the legal requirements were complied with and that the liquidation proceedings were not unduly delayed. During the period under review, a copy each of the Inspection report under Section 45Q of the Banking Regulation Act, 1949 in respect of 8 banks in liquidation was forwarded to the Central Government and the respective High Courts.

Credit Authorisation Scheme

221. Since November 1965, a Credit Authorisation Scheme has been in operation as part of the Reserve Bank's credit policy. In terms of this Scheme, all scheduled commercial banks are required to obtain the Reserve Bank's prior authorisation before sanctioning any fresh credit limit (including commercial bill discounts but excluding letters of credit and guarantee limits) of Rs. 1 crore or more to any single party or any limit that would take the total limit enjoyed by such party from the *entire banking system* (including co-operative sector) to Rs. 1 crore or more, on secured and/or unsecured basis. During the year, there has been a re-structuring of the Scheme as part of the effort at aligning bank credit with Plan priorities. Hitherto, the main criterion for authorisation has been the purpose for which the applicant sought credit. With a view to ascertaining the end-use of credit more closely and ensuring proper use and dispersal of bank credit, a comprehensive system for appraisal of credit including such aspects as excessive inventory build-up, inter-corporate lending/investments, diversion of short-term funds for long-term purposes, etc., is being evolved. With this end in view, the Bank has introduced certain forms designed to collect the requisite information for a proper evaluation and financial appraisal of credit proposals.

222. During the year, 908 applications were received from banks for authorisation of credit limits under the Scheme; 30 applications received during the previous year (*i.e.*, 1968-69) were also pending. The credit limits covered by most of the proposals were for the purpose of meeting the working capital requirements and for financing expansion/modernisation, etc. of concerns engaged in defence/export-oriented and other priority industries. In all, 871 applications were disposed of during the year and in respect of 41 applications, further particulars called for from banks were awaited and 26 applications were under scrutiny.

Credit Information

223. The Credit Information Division of the Reserve Bank continued to collect information from banks and other notified financial institutions, in respect of credit facilities allowed by them to their customers. The required information was furnished in a consolidated form in respect of individual customers to the institutions which applied for it. During the period July 1969 to June 1970, the Division furnished credit information in respect of 1,938 applications to 30 applicant banks.

Clearing House Facilities

224. During the period under review, the clearing house facilities were further expanded as part of the Bank's policy of extension of banking facilities in the country. Thus during the period (July-June) six clearing houses were established, bringing the total number of clearing houses functioning in the country to 105. Of these, 9 are managed by the Reserve Bank of India, 78 by the State Bank of India, and 18 by the Subsidiaries of the State Bank of India.

Working Group on Jute Industry

225. Reference was made in the previous year's Report to the constitution of a Working Group in March 1969 to look into the problems of short-term credit needs of the jute industry for production and exports. Subsequently, the Group was also requested to examine certain complaints regarding the alleged abuses of the system of trading in jute goods through the medium of jute Pucca Delivery Orders (PDOs) and the availing of bank credit facilities against them. The Group has since submitted its Report and its recommendations are under consideration.

Control over Non-Banking Companies

226. There was no important development during the year in regard to the regulation and control of deposits in the corporate non-banking sector. There has, however, been some increase in recent years in the number of chit funds and latterly a number of "finance corporations," which are really partnership firms, have been promoted and they have also been accepting deposits from the public. These firms are mostly confined to Mysore State, but a few of them also operate in Andhra Pradesh and Tamil Nadu.

227. The question of protecting the interests of subscribers of the chit funds was taken up suitably with the State Governments concerned. At the instance of the Reserve Bank, the Tamil Nadu Government has extended the local Chit Funds Act, 1961 to all the districts in that State. Andhra Pradesh and Mysore have been considering the question of enacting local legislation for this purpose and in Kerala, where chit funds and kuries have been traditionally very common and popular, a public sector corporation was constituted in November 1969 to run chitties and kuries in competition with other private companies and individuals in the State.

228. The provisions of the directions issued by the Department of Non-Banking Companies in regard to deposits are not applicable at present to partnership firms and it is not also legally possible for the Bank to issue any directions to any firm with a subscribed capital of one lakh of rupees or less. The "finance corporations" are, however, governed by the provisions of the Moneylenders Acts as they are in force in the respective States. The question of enforcing the provisions of these Acts is being considered in consultation with the State Governments.

Deposit Insurance Corporation

229. The number of insured banks declined to 83 at the end of June 1970 from 87 at the end of June 1969 as a result of transfer by two banks of the deposit liabilities and equivalent assets to other insured banks and amalgamation of two banks with State Bank of India. During the year, no new bank was registered as an insured bank. The liability of the Corporation in respect of the insured deposits arose in the case of the two amalgamated banks, namely, the National Bank of Lahore and the Bank of Behar. In the case of one of these banks, the Corporation's liability was determined and paid, while in the case of the other bank, it will be determined after the scrutiny of the list of depositors of the bank. The claims met by the Corporation since its inception in 1962 to the end of June 1970 aggregated Rs. 103.44 lakhs as against the receipt by way of reimbursement from the concerned banks to the extent of Rs. 36.11 lakhs.

230. With the previous approval of the Government, the Corporation has increased, with effect from April 1, 1970, the limit of insurance cover in respect of amounts due to any one depositor at a registered commercial bank from Rs. 5,000 to Rs. 10,000. As a result of this increase, the percentage of fully protected accounts to the total number of deposit accounts is estimated to have increased from 90.8 to 96.8 and that of insured deposits to the total assessable deposits from 50.8 to 61.0. The rate of premium payable by insured banks remains unchanged at 5 paise per Rs. 100 of insured deposits per annum. Consequent on the nationalisation of 14 major commercial banks on July 19, 1969, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 provides for the continuance of the corresponding new banks as insured banks.

231. The provisions of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968 to which a reference was made in the last year's Report, have not been brought into force, pending enactment of the necessary legislation by the various States so as to make the co-operative banks in the respective States eligible for deposit insurance cover. The States of Andhra Pradesh, Maharashtra and Madhya Pradesh and Goa, Daman and Diu have since passed the necessary legislation and the Reserve Bank of India is actively pursuing the matter with other State Governments.

Banking Commission

232. In the previous Report, mention was made of the appointment of the Banking Commission and its terms of reference. The Commission which started functioning in March 1969 sent questionnaires in stages to commercial banks, co-operative banks, State Governments and Union Territories, borrowers from medium and small-scale industries and traders

engaged in domestic and foreign trade. The Commission has constituted five Study Groups to report on banking, viz. (a) banking costs, (b) legislation affecting banking, (c) indigenous bankers, (d) bank procedures and (e) non-banking financial intermediaries. These Study Groups include experts in their respective fields and professional bankers. The Study Group on legislation affecting banking has issued two sets of its questionnaires. A survey of bank services to depositors has been entrusted to the National Council of Applied Economic Research and another survey of small-scale industries and small borrowers has been undertaken on behalf of the Banking Commission by Universities and other academic bodies at 21 centres all over the country. A study of the portfolio behaviour of banks is being made by the Institute of Economic Growth. A sample survey of banking facilities in rural areas was completed by the Division of Rural Economics of the Economics Department, Reserve Bank of India. Two similar studies have been undertaken by two Universities. The National Institute of Co-operative Management has undertaken a study of several aspects of working of co-operative banks including personnel management.

233. The Commission has visited the States of Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Orissa, Assam, Meghalaya, Mysore, Punjab, Haryana, Madhya Pradesh and the Union Territory of Himachal Pradesh so far and held discussions with the State Governments, commercial and co-operative banks, chambers of commerce, representatives of industry, large and small, and other interests concerned with banking. The Commission also met the official representatives of the Government of Nagaland during its visit to Assam.

National Credit Council

234. A mention was made in the last year's Report about the appointment by the National Credit Council of 5 Study Groups and the recommendations of the Study Groups on Deposit Mobilisation and Credit Facilities for Road Transport Operators. The Study Group (with Prof. D.R. Gadgil as its Chairman) on Organizational Framework for Implementation of Social Objectives referred to the geographical and functional credit gaps in the economy and submitted its Report in October 1969. The Group made a rough assessment of the credit requirements of the major economic sectors and the extent to which the institutional credit facilities were not available to meet them and focussed attention, with the help of several case studies, on the virtual non-availability of institutional credit to certain types of borrowers, particularly small borrowers and weaker sections of the community. Attention was drawn to the uneven geographical distribution of credit as between different States and between different regions in a State and the necessity to make detailed plans for the development of credit and banking in the country on the basis of local conditions was emphasised. For this purpose the Group recommended the adoption of an area approach. The district, according to the Group, should be the lowest unit under an area approach because it is the unit in relation to which the co-operative credit structure is at present organised.

235. Each district plan to be formulated will have three aspects: (i) that of establishment of branches or new units at particular places, (ii) that of formulating relationships within a structure or as between structures, and (iii) the formulation of proper policies and procedures.

236. In regard to aspect (i), the Group recommended that new branches would have to be opened by the named nationalised or non-nationalised banks as well as by co-operative banks. In addition, new banking units both in rural and urban areas may have to be started where conditions so warrant. Apart from primary co-operative societies the plan should include a programme for formation of marketing and processing societies and these should be allowed as a transitional measure to extend credit for production where the primary societies are not strong.

237. In regard to aspect (ii) of the plan, the general principle according to the Group, should be that the relations within co-operative structure would be maintained on the normal lines wherever the appropriate units in the structure are sufficiently strong. Where this is not the case, the functions expected to be performed by non-existent or weak co-operative institutions will have to be undertaken by corresponding commercial banking units. In addition, where it is deemed necessary, district co-operative banks should be allowed to deal with individuals as an interim measure till such time as commercial banks or strong primary societies are established. The credit plan for a district will have to pay attention to integration of credit and banking business with the other activities.

238. In regard to aspect (iii), the Group emphasised the necessity of a shift on the part of all credit institutions in the emphasis from tangible security to operational viability. The Group also stressed the special responsibility of nationalised banks in formulating and implementing the district plans.

239. The two pre-conditions required for making finance available on a larger scale and to weaker sections are: (i) integrating the lending business with sale, production and marketing activities, and (ii) making it possible for everybody to build up some kind of minimum financial asset in the shape of provident funds, insurance, bonus expectations or savings deposit schemes on which the initial advance could be made.

240. The Group was of the view that in order to implement its recommendations, an apparatus should be immediately evolved. For this purpose, district or zonal committees should be formed preferably at the initiative of the State Governments. Simultaneously, an all-India machinery should be constituted which may be called the Standing Advisory Committee on Credit Assistance. It should consist of senior representatives of the Ministry of Finance, the Reserve Bank, Planning Commission, nationalised commercial banks and co-operative banks as well as borrowers including small borrowers. The Reserve Bank will be the executive arm of this committee and for this purpose the Group has recommended the establishment of a specialised Department of Credit Planning in the Reserve Bank of India.

241. As mentioned earlier, the Reserve Bank kept in view the recommendations of the Group in formulating the Lead Bank Scheme introduced in December 1969. As regards Study Group's recommendation that commercial banks should finance primary agricultural credit societies in areas where central co-operative banks are financially weak, the Reserve Bank has introduced a scheme initially in 52 districts of the 5 States, viz., Andhra Pradesh, Mysore, Uttar Pradesh, Haryana and Madhya Pradesh. The Reserve Bank has also set up a Credit Planning and Banking Development Cell to formulate guidelines for meeting credit gaps.

242. The Study Group appointed under the Chairmanship of the late Shri V. T. Dehejia to study the extent to which the credit needs of industry and trade are likely to be inflated and how such trends could be checked, submitted its report in September, 1969.

243. A major finding of the Group was that there was a tendency on the part of a number of industrial units to utilise short-term bank credit and other current liabilities for acquisition of non-current assets. This was, in the opinion of the Group, due to the general sluggish conditions in the capital market since 1962 and the limited nature of the appraisal of applications for short-term loans as compared to medium-term loans and stipulation of repayment scheduled for medium-term loans. According to the Group, the prevalent lending system of banks appeared to have greatly assisted certain units in industry on increased reliance on short-term debt to finance their non-current investment. The working capital advances of banks are granted by way of cash credit limits which are only technically repayable on demand. The system was found convenient in view of the emphasis placed by banks on the security aspect. These short-term advances though secured by current assets were not necessarily utilised for short-term purposes. The result was that cash credit advances no longer remained short-term or self-liquidating. Thus a substantial part of the working capital advances is permanently needed by the units to carry on their operations. Therefore, in the financial planning of the borrowing unit it is necessary to see what would be its permanent lock-up of funds in working capital as distinct from its purely temporary requirements and to arrange for term finance subject to observance of a proper debt-equity ratio. The Group was of the view that unless measures are taken now to check his tendency for diversion of bank credit for acquiring long-term assets it would assume wider dimension in the next few years and recommended the following measures for checking this tendency:—

(a) Appraisal of credit applications should be made with reference to the total financial situation, existing and projected, as shown by cash flow analysis and forecasts submitted by borrowers.

(b) Outstandings in cash credit accounts should be distinguished as between (i) "the hard core" which would represent the minimum level of raw materials, finished goods and stores which the industry is required to hold for maintaining a given level of production and (ii) the strictly short-term component which would be the fluctuating part of the account. The latter part of the account would represent the requirements of funds for temporary purposes, e.g. short-term increases in inventories, tax, dividend and bonus payments etc., the borrowings being adjusted in a short period out of sales. Where the company's debt-paying capacity is good and its other ratios not unhealthy, the hard core element in the cash credit borrowings could be segregated and put on a formal term loan basis and subject to repayment schedule. Where the financial position is not too good or the size of the hard core is large, the possible solutions to be attempted would be: additional issue of equity or preference capital, a debenture issue with a long maturity, the bringing of long-term deposits and unsecured loans by the promoters and their friends. Where the hard core is to be placed on a formal term loan basis, the proposal should be subject to a detailed appraisal. The documents should contain covenants in regard to the end-use of the loan, maintenance of minimum financial ratios, repayment obligations, restrictions on investments in shares and debentures, etc. As the determination of the hard core element of the cash credit account may present some practical difficulties to banks, it would be worthwhile to attempt a study of industry-wise norms for minimum inventory levels. The intention in suggesting this type of lending on a term basis for working capital is not to deny credit assistance to expanding industrial units or to bring down immediately the present level of bank credit to industry. The borrower would only be subject to a greater financial discipline and a repayment of such loans over a period of time; this will provide a more effective use of bank's funds. The proposed changes in the cash credit/overdraft accounts of banks would have little impact on a majority of units in the corporate sector. Only units which witnessed a deterioration in the current ratio resulting now in a negative ratio or a current ratio of 1:5 and below are likely to be affected. As a complementary measure to check the extension of extra bank credit, it would be desirable to levy a commitment charge on the unutilised limits in cash credit accounts coupled, if necessary, with minimum interest clause. Also, banks should promote the practice of culminating credit sales by issue of usance bills. This would not only impose financial discipline on the purchaser but also help the supplier or producer to plan his financial commitments in a realistic manner. With a view to encouraging the development of bill market, the Central Government should consider reduction in the stamp duty on usance bills.

244. The Co-ordination Committee of Public Sector banks considered the question of a commitment charge on credit limits at its meetings held on January 13, 1970 and March 20, 1970 and there was a general agreement on the need to levy a commitment charge on credit limits. On March 28, 1970, the Reserve Bank issued a directive to scheduled commercial banks requiring them to levy a commitment charge on the unutilised portions of credit limits of Rs. 10 lakhs and above, at the rate of 1 per cent per annum with effect from April 1, 1970 (referred to in Chapter I). The Reserve Bank's credit authorisation procedures have been streamlined to achieve proper end-use of credit, details of which are given earlier. A Group consisting of officers of commercial banks and the Reserve Bank was constituted in February 1970 to consider the questions relating to enlarging the use of bills of exchange as an instrument for providing credit to trade and industry. The Study Group has submitted its report which is under the consideration of the Reserve Bank. It is also proposed to appoint a Study Group for each major industry which would work out inventory norms in consultation with the associations representing the industry. These Study Groups are being set up.

245. The Study Group (with Shri P. N. Damry as the Chairman) on area/project approach in implementing schemes for extending commercial banks' credit to agriculture, recommended an area/district-wise approach in financing agriculture and that commercial banks should plan in a co-ordinated manner along with other lending institutions in this field to identify the credit gaps. The Group, after examining the State enactments relating to land tenure and tenancy reforms, ceilings on land holdings, agricultural debt relief, regulation of money lending, etc., stated that some of the provisions in these enactments were outmoded in the light of current requirements of the agricultural economy and recommended that

an expert group might be constituted to examine these enactments and make suggestions with a view to enlarging the commercial banks' participation in agriculture. The Seminar on Financing of Agriculture by Commercial Banks held by the Reserve Bank in December 1968, to which a reference was made in last year's Report, had also made a similar recommendation. In pursuance of this recommendation, the Governor of the Reserve Bank set up an expert group with Shri R. K. Talwar as Chairman, and representatives of commercial banks, co-operative banks, Reserve Bank of India and State Governments as its members to examine the State Government enactments.

IV. DEVELOPMENTS IN CO-OPERATIVE BANKING

246. In pursuance of its policy to bring about a financially and economically viable co-operative banking structure, the Bank continued to (i) pay special attention towards rehabilitating and revitalising the weaker units in the co-operative credit structure, (ii) make transitional arrangements for maintaining the flow of production and investment credit for agriculture in the areas of weak central Co-operative banks by involving the commercial banks to finance the primary agricultural credit societies in such areas, (iii) endeavour in bringing about a greater degree of discipline and improvement in the lending policies and operational efficiency of co-operative credit institutions including land and development banks, (iv) widen scope and range of the Bank's financial accommodation to the co-operative credit institutions and (v) introduce a number of special training courses at the Bank's Co-operative Bankers' Training College for the personnel of State/Central/urban banks.

247. Based on the interim recommendations of the All-India Rural Credit Review Committee mentioned in the last year's Report, the proposals concerning the Small Farmers' Development Agency, the Rural Electrification Corporation and the Agricultural Refinance Corporation have been included in the Fourth Five-Year Plan. The Rural Electrification Corporation which, among others, will finance rural electric co-operatives was set up in July 1969 and the schemes for establishing eight small farmers, development agencies in four States have also been approved.

248. The Review Committee submitted its final Report in July 1969. Emphasising the need for the Bank continuing its role in the sphere of rural credit, the committee recommended that the formulation, review and modification of the Bank's policies in this sphere should be placed in the hands of a high-powered body with appropriate status. Pending amendment to the Reserve Bank of India Act in this regard, the Standing Advisory Committee on Rural and Co-operative Credit was required to be suitably reconstituted as the proposed Agricultural Credit Board. Accordingly, the Committee has been reconstituted in February 1970 as the Agricultural Credit Board of the Bank with the Governor as Chairman, the Deputy Governor in charge of rural credit as its Vice-Chairman, the Chief Officer of the Agricultural Credit Department as the Member-Secretary and eleven members. The other recommendations of the Committee which, among others, related to the adoption of various progressive measures both by the Reserve Bank and other agencies of development for ensuring the timely and adequate flow of production and investment credit for agriculture, are proposed to be placed before the Credit Board for its consideration.

249. In pursuance of the recommendations of the Working Group on Industrial Financing through Co-operative Banks, a reference to which was made in the last year's Report, the State and central co-operative banks have been advised (i) that they could invest 15 per cent of their disposable long-term resources or 5 per cent of their total deposit resources, whichever is more, in providing block capital loans to co-operative processing societies, and (ii) that they liberalise the standards as related to the societies owned funds adopted in providing clean advances to marketing-cum-processing societies and to processing societies. Measures to bring about the reorganisation of the existing industrial co-operative societies with a view to making them viable units as recommended by the Working Group, have also been initiated by taking up appropriate field studies for the purpose. Following the discussions with the Khadi and Village Industries Commission, it was agreed to implement the scheme of providing working capital to the Khadi and Village Industries Co-operative through central co-operative banks on a pilot basis, in Maharashtra.

Transitional Arrangements for Agricultural Credit

250. The weaknesses of the co-operative credit structure, more particularly in certain parts of the country, resulted in a large number of agriculturists experiencing shortage of credit especially in the context of the technological developments taking place in agricultural production. This highlighted the need for meeting their credit needs even for a temporary period, through other institutional sources, till such time as the co-operative credit structure itself could be effectively strengthened to fill in the credit gaps. Action was therefore taken to seek the aid of the commercial banks in sponsoring a scheme for financing the primary agricultural credit societies.

Financing of Primary Agricultural Credit Societies by Commercial Banks

251. In areas where the central co-operative banks were financially weak and unable to meet the huge demand for production and investment credit, a scheme of financing the primary agricultural credit societies by commercial banks was proposed by the Reserve Bank for implementation in certain districts in five States viz., Andhra Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh, Mysore and Uttar Pradesh. This proposal was endorsed by the Study Group of the National Credit Council and the Working Group of the nationalised banks as well and also agreed to by the State Governments and the co-operative banks concerned for implementation. Under the scheme, branches of commercial banks in the selected districts will finance primary agricultural credit societies in compact areas within a radius of about 10 to 15 miles of the branch offices. While the immediate objective of the scheme is to fill in, to the extent possible, the large credit gaps in this sphere, the long-term objective is to ensure that in the process of active involvement of the commercial banks, the co-operative system is under no circumstances weakened and, therefore, the State Governments have been asked to draw up a positive programme for rehabilitation of central co-operative banks and revitalisation of primary agricultural credit societies. This programme is to be implemented simultaneously as an integral part of the scheme. Up to June 1970, 20 commercial banks including the State Bank of India group and 12 other public sector banks have selected 2,121 primary agricultural credit societies in 50 districts of the five States through their 326 branches. In some cases the banks have commenced financing of *khairif* 1970 operations under the scheme. The scheduled commercial banks financing the societies under the scheme are eligible for refinance facility from the Bank at a concessional rate of interest of 4½ per cent.

Co-operative Development

252. As the measures mentioned above were only transitional expedients in the larger interest of agricultural production, the long-term objective was to draw up and implement simultaneously a positive programme of rehabilitation of the central co-operative banks and speeding up of the schemes of reorganisation and revitalisation of the primary credit societies. The State Governments have been advised to draw up special schemes in respect of each of the central banks so as to provide, among others, specifically for (i) a concerted drive under the guidance of the State Government for the recovery of overdues, (ii) strengthening the administrative and supervisory arrangements for timely recovery of loans, (iii) rationalisation of loaning policies and procedures, (iv) strengthening of the resources of the banks, wherever appropriate, by loan-cum-deposits and additional share capital contribution from State Government, and (v) action to stimulate mobilisation of deposits through a programme of branch expansion. The Bank has agreed to consider sympathetically the loan applications of State Governments for share capital contribution to central co-operative banks and primary agricultural credit societies in the areas of retarded growth in the co-operative sphere. As mentioned elsewhere in the Report, the Bank has also been trying to secure the benefit of insurance to the deposits of co-operative banks, which is expected to serve as an important incentive to deposit mobilisation. The services of the Regional Offices of the Bank's Agricultural Credit Department were also made available in assisting the co-operative banks in their efforts in rehabilitation and reorganisation.

253. Between January and June 1970, the Deputy Governor in charge of rural credit held annual discussions on all aspects

of problems relating to the co-operative movement and development with the representatives of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Goa, Gujarat, Haryana, Jammu and Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Mysore, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura and Uttar Pradesh States. In the context of the schemes of financing the primary agricultural credit societies by commercial banks and to ensure better and closer co-ordination of the activities of cooperative and commercial banks in the sphere of agricultural credit, the representatives of commercial banks were also invited to attend the Deputy Governor's discussions this year in respect of some of the States. The persisting weakness and the remedial measures suggested during such discussions related to mobilisation of deposits by co-operative banks, mounting overdues, adoption of the crop loan system with such modifications as were considered necessary in the context of local conditions, reorganisation of the structure at the primary level on the accepted pattern, co-ordination between the working of co-operative banks and commercial banks since the latter had come forward in a fairly large way in financing the agricultural sector, etc.

Co-operative Credit : Policy, Procedures and Operations

254. The basic policy followed by the Bank in regard to the provision of short-term financial accommodation to the State co-operative banks for financing seasonal agricultural operations and marketing of crops continued to be the same during the year as in the last year. The total credit limits sanctioned by the Bank to the State co-operative banks for financing seasonal agricultural operations and marketing of crops at the concessional rate of interest of 2 per cent below the Bank rate increased from Rs. 337.52 crores in 1968-69 to Rs. 370.16 crores during 1969-70. Drawals aggregated Rs. 425.09 crores as against 411.15 crores in 1968-69 while repayments were Rs. 394.06 crores as against Rs. 365.23 crores in 1968-69. The outstanding as on June 30, 1970 stood at Rs. 214.11 crores as compared with Rs. 183.09 crores as on June 30, 1969. The special short-term credit limits sanctioned to two State co-operative banks for financing the marketing of cotton and *kapas* during 1969-70 were Rs. 7.75 crores as against Rs. 8.35 crores during 1968-69. The drawals were Rs. 9.33 crores, repayments Rs. 8.24 crores, and the outstandings as on June 30, 1970 Rs. 1.99 crores. The corresponding figures for 1968-69 were Rs. 7.20 crores, Rs. 7.50 crores and Rs. 0.90 crores, respectively. In addition to the accommodation for financing seasonal agricultural operations and marketing of crops, the Bank provided short-term finance amounting to Rs. 23.46 crores as against Rs. 23.05 crores in 1968-69 at the Bank rate to two State co-operative banks for general banking purposes and the outstanding under this head as on June 30, 1970 stood at Rs. 0.23 crore. The Bank continued to sanction credit limits for financing the stocking and distribution of chemical fertilisers at the Bank rate against Government guarantee under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act. During the calendar year 1969, the limits sanctioned, drawals and outstanding at the end of the year were Rs. 31.00 crores, Rs. 40.57 crores and Rs. 14.06 crores, respectively. The corresponding figures for 1970 upto the end of June 1970 were Rs. 11.00 crores, Rs. 2.35 crores and Rs. 2.35 crores. With the emergence of commercial banks as a significant source of credit for the distribution of agricultural inputs, the Banks had advised the co-operative banks and marketing federations in December 1969 to approach commercial banks for financing the business in chemical fertilisers and the Bank had continued its advances for the purpose only where any specific difficulty was experienced in obtaining the required finance from commercial banks. During the year under report, the Bank sanctioned for the first time a short-term credit limit of Rs. 2 crores to the Agricultural Re-finance Corporation against trustee securities at Bank rate under Section 17(4E) of the Reserve Bank of India Act. The limit was availed to the extent of Rs. 1.65 crores by the Corporation and the entire amount was repaid in April 1970 leaving no amount outstanding as on June 30, 1970.

255. In the sphere of medium-term agricultural credit the general policy adopted by the Bank was to encourage loans for such identifiable purposes as wells, pump-sets, etc., and to discourage an undue expansion of credit for purposes such as bunding, reclamation, purchase of bullocks, etc., particularly where the arrangements for verification of utilisation were not satisfactory. In determining the reasonableness of the norms for medium-term finance for various agricultural purposes, the Bank had drawn on the useful studies conducted by the Agricultural Refinance Corporation wherever available, regarding the economic and technical feasibility of the schemes involving the medium-term investment. Following the recommendations of the

Standing Advisory Committee on Rural and Co-operative Credit, certain relaxations in regard to the security for medium-term loans for agricultural purposes issued out of funds availed of from the Bank, were made in August 1969. Accordingly medium-term loans between Rs. 1,501 and Rs. 3,500 for the purchase of electric pumpsets, oil engines and for digging of wells could be issued without insisting on mortgage of land but subject to certain other conditions such as hypothecation, margin money, etc. During the year the Bank had extended the facility of granting medium-term advances to State co-operative banks under Section 17 (4AA) read with Section 46A(2)(b) of the Act for financing agriculturists for the purchase of shares in co-operative marketing societies/federations for setting up or acquiring shares in the processing units such as cotton ginning and pressing, groundnut oil mills and rice mills. In view of the increase in the capital outlay in the sugar factories and the consequent need for larger contribution from members, the Bank had decided to enhance in October 1969 the individual ceiling of loans for purchase of shares in co-operative sugar factories from Rs. 1,125 to Rs. 2,250 under certain conditions. The medium-term loans sanctioned by the Reserve Bank during the year at a concessional rate of 1 1/2 per cent below the Bank rate amounted to Rs. 18.30 crores against Rs. 19.00 crores sanctioned last year. Drawals were Rs. 11.48 crores against Rs. 9.02 crores during the previous year. No medium-term loans were sanctioned at the Bank rate. The outstanding as on June 30, 1970 were Rs. 20.45 crores inclusive of those under medium-term limits sanctioned at Bank rate (Rs. 0.08 crores) as against Rs. 17.60 crores as on June 30, 1969.

256. With the inclusion of 22 broad groups of industries in the list of 'approved' cottage and small-scale industries for accommodation under Section 17(2)(bb) of the Reserve Bank of India Act at the Bank rate for financing their production and marketing activities, the maximum amount of credit limit that can be sanctioned to a district industrial co-operative bank or primary (urban) co-operative bank for the purpose had been increased to four times its owned funds. The terms and conditions relating to the financial accommodation under Section 17(2)(bb) or 4(c) of the Reserve Bank of India Act to primary (urban) co-operative banks for financing the production and marketing activities of the approved cottage and small-scale industries owned by the individual firms and joint stock companies, etc., were finalised and circulated during the year under report.

257. During the financial year ended March 31, 1970, eleven State co-operative banks were sanctioned credit limits aggregating Rs. 8.18 crores as against Rs. 7.37 crores to 9 State co-operative banks last year under Section 17(2) (bb) or 4(c) of the Reserve Bank of India Act, at 1 1/2 per cent below the Bank rate for financing the production and marketing activities of handloom weavers' co-operative societies (cotton, silk and woollen) and powerloom societies. The drawals amounted to Rs. 9.49 crores as against Rs. 8.12 crores during the previous year and the outstanding at the end of the financial year 1969-70 stood at Rs. 6.42 crores as against Rs. 5.63 crores at the end of the previous financial year. Four State co-operative banks were sanctioned credit limits aggregating Rs. 0.69 crore under Section 17(2)(a) or 4(c) of the Reserve Bank of India Act for financing commercial and trade transactions of apex handloom weavers' societies as against Rs. 1.02 crores sanctioned last year. Drawals aggregated Rs. 0.11 crore and the outstanding balance at the end of the financial year was Rs. 0.06 crore. The Bank had so far no occasion to sanction credit limits to State co-operative banks for financing industrial units coming under the 22 approved groups.

258. Following the introduction of the revised credit guarantee scheme from February 1, 1970, the Bank advised the State and Central co-operative banks to take advantage of the guarantee facilities available under the revised scheme.

259. Due to the occurrence of natural calamities in certain parts of the country, the Bank sanctioned medium-term credit limits to the extent of Rs. 11.40 crores at 1 1/2 per cent below the Bank rate to 5 State co-operative banks, out of the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund for conversion of short-term loans into medium-term loans under Section 17(4AA) read with Section 46B(2) of the Act. The drawals made by 4 banks aggregated Rs. 3.01 crores and the outstanding as on June 30, 1970 were Rs. 4.35 crores as against Rs. 5.18 crores as on June 30, 1969. Besides, 2 State co-operative banks were sanctioned credit limits aggregating Rs. 1.88 crores at the Bank rate under Section 17(4)(a) against Government and trustee securities representing the investments of their agricultural Credit

Stabilisation Funds to enable them in turn to convert short-term loans due from central co-operative banks into medium-term loans. The pattern of assistance by way of 75 per cent grant and 25 per cent loan to State Governments to build up stabilisation funds of the State co-operative banks as indicated in the last year's Report continued for the year under review. During the financial year 1969-70, the Government of India made a provision of Rs. 2.01 crores as against Rs. 5.00 crores in 1968-69 by way of central assistance to State Governments. The stabilisation funds of State and central co-operative banks were permitted to be utilised for granting conversion facilities to the instalments of medium-term loans as well in times of natural calamities under certain conditions but without recourse to the National Fund of the Bank. All the State Governments have set up the Agricultural Credit (Relief and Guarantee) Funds. An aggregate provision of Rs. 1.98 crores was made in the State Plans for the Fourth Plan—1969-74. The contributions to the funds during 1969-70 were Rs. 0.10 crores and the total amount to the credit of the funds stood at Rs. 1.66 crores as on March 31, 1970.

260. Some State Governments had proposed charging guarantee commission/fees for the guarantees extended by them on behalf of co-operative institutions. The fees proposed were as high as $\frac{1}{4}$ per cent of the guaranteed amounts in respect of certain advances. Levy of guarantee fees in respect of the guarantees extended by the State Governments for and on behalf of co-operative credit institutions, viz., the State-co-operative banks and the State land development banks, would make borrowings of the latter costlier and consequently result in an increase in the rate of interest charged to the ultimate borrowers. The Bank had, therefore, advised the State Governments not to charge any guarantee fee in respect of guarantees extended on behalf of co-operative institutions. Following this advice, 10 State Governments have indicated that they have no intention of charging any guarantee fee.

261. In the context of the increase in the guarantee business of the State-co-operative banks, the Bank issued certain guidelines for such business in December 1969. A ceiling was suggested for the aggregate amount of guarantees to be executed by a State co-operative bank and that such aggregate should not exceed one time its owned funds, while the total of unsecured guarantees should not exceed 25 per cent of its owned funds.

262. The scope of loans from the National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund of the Reserve Bank of India to the State Governments was extended during financial year 1969-70 to cover State participation in the share capital of primary land development banks and, on a very selective basis, in primary (urban) co-operative banks. Only such of those primary (urban) co-operative banks as had already undertaken the financing of small-scale industries or had a definite programme in that behalf were eligible for share capital contribution. The decision in respect of the primary land development banks was taken on the recommendation of the Standing Advisory Committee on Rural and Co-operative Credit and in respect of the urban banks as recommended by the Working Group on Industrial Financing through Co-operative Banks. Loans amounting to Rs. 7.29 crores (excluding renewal of Rs. 0.20 crore) were sanctioned to 14 State Governments during the financial year 1969-70 out of the National Agricultural Credit (Long-term Operations) Fund under Section 17(4) (AA) read with Section 46A(2)(a) of the Reserve Bank of India Act for contribution to the share capital of 2 State-co-operative banks, 70 central co-operative banks, 2,624 primary agricultural credit societies, 6 central land development banks, 254 primary land development banks and 4 primary (urban) co-operative banks. The aggregate of draws of the State Governments during the financial year 1969-70 amounted to Rs. 6.80 crores as against Rs. 3.92 crores during 1968-69. The total amount outstanding against the State Governments on this account was Rs. 33.83 crores as on March 31, 1970 as against Rs. 31.19 crores as on March 31, 1969.

263. As in previous years, a meeting of the representative of Central Land Development banks, Government of India, etc. was convened by the Bank in January 1970 to discuss and decide the debenture programme of land development banks for the year 1970-71. A programme of Rs. 141.20 crores was approved for 1970-71 as compared to Rs. 113.00 crores for 1969-70. The support from public sector institutions as well as of the Government of India had been placed at Rs. 44 crores. The commercial banks were expected to provide Rs. 30 crores to the debenture programme. In view of the arrangements made for

ensuring adequate support to the debenture programmes of land development banks, the Bank continued to lay emphasis on the purposes for which loans would be disbursed by the land development banks and on their financial and operational soundness. The conditions that 90 per cent of the loans advanced should be for productive purposes of which 70 per cent for easily identifiable productive purposes, and that eligibility for support would depend on the recovery performance as laid down in the previous year, were continued during 1969-70 also. Land development banks with overdues of 15 per cent of the demand or less at primary level (or apex level where there are no primaries) were eligible for full support while those with higher overdues were eligible for lower support on a graded scale. The central land development banks floated during the financial year 1969-70 ordinary debentures of Rs. 113.75 crores to which the contributions from commercial banks were of the order of Rs. 31.84 crores as against Rs. 22.86 crores in 1968-69. The Bank's contributions for the ordinary debentures were Rs. 4.20 crores and those of Government of India, Life Insurance Corporation of India, State Bank of India and State Governments were Rs. 57.36 crores. During the financial year 1969-70, the central land development banks also floated rural debentures aggregating Rs. 5.10 crores, the Bank's contribution during the period being Rs. 1.16 crores. The Bank's total holding of ordinary and rural debentures were Rs. 30.80 crores and Rs. 9.57 crores as on June 30, 1970 as against Rs. 28.52 crores and Rs. 8.97 crores, respectively, as on June 30, 1969.

264. The Bank had considerably expanded the scope of its inspections of the land development banks with a view to keeping a close watch on their working and operations which have increased considerably in recent years. Detailed guidelines issued in this regard aim at orientation of their lending policies, better management of the resources, appointment of adequate staff for supervision, creation of technical cells, etc.

Co-operative Banking Regulation

265. As on June 30, 1970 there were 1,317 co-operative banks—28 State, 366 central and 923 primary—coming under the purview of the Banking Regulation Act as against 1,348 co-operative banks at the beginning of the year. The decline in the number of co-operative banks was mainly due to the deletion of certain non-agricultural credit societies from the list of primary co-operative banks. During the year 1969-70, 10 co-operative banks—2 central and 8 primary co-operative banks—were issued licences to commence banking business in India under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949 (as applicable to co-operative societies) raising the total number of licensed co-operative banks to 24. The number of offices of the co-operative banks which stood at 4,137 as on June 30, 1969 increased to 4,399 as on March 31, 1970. During the period July 1, 1969 to June 1, 1970 State and primary co-operative banks were granted 51 licences for opening new offices as against 35 licences granted during 1968-69. Another licence issued to the Madhya Pradesh State Co-operative Bank during the year was for shifting its Head Office from Jabalpur to Bhopal. Five co-operative banks were granted exemption by the Government of India under Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 from complying with the provisions of Section 11(1) of the Banking Regulation Act for a period of one year up to February 28, 1970 and 6 co-operative banks were given similar exemption for a period of 2 years with effect from March 1, 1969. Of the 28 co-operative banks whose period of exemption expired on February 28, 1970, 3 were granted exemption for a further period of one year with effect from March 1, 1970, 7 co-operative banks have since complied with the provisions of Section 11(1) of the Banking Regulation Act, one has been amalgamated and another is under liquidation. The applications from six co-operative banks had been recommended for exemption to the Government of India and the remaining are under consideration of the Bank.

266. A reference was made in the last year's Report to a directive to the State and central co-operative banks imposing a limited control on the advances against the security of cotton and *kapas*. During the year under report the directive has been modified according to which the aggregate level of credit is computed in terms of certain percentage of liabilities in India on the last Friday of October 1969 instead of last Friday of October 1968 as was done previously.

267. Mention was made in the last year's Report about the enactment of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968. The Co-operative Societies Acts in the

States of Andhra Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh and Goa, Daman and Diu have been amended with a view to vesting in the Reserve Bank, powers relating to the super-session, reconstruction, amalgamation and liquidation, etc., of the co-operative banks. The Bank is pursuing with other State Governments the question of amending the Co-operative Societies Acts so as to extend the benefit of the deposit insurance to the co-operative banks in these States.

268. Thirteen State co-operative banks, 246 central co-operative banks, 2 State industrial co-operative banks, 9, district industrial co-operative banks and 568 primary co-operative banks were inspected under Section 35 of the Banking Regulation Act, 1949 during the period under review. Out of 568 primary co-operative banks, 101 were inspected by the officers of the State co-operative banks on behalf of the Reserve Bank under Section 35(1) of the Banking Regulation Act, 1949. Besides, 18 central land development banks, 4 apex handloom weavers' co-operative societies and 1 apex marketing co-operative society were inspected on a voluntary basis. Copies of inspection reports of 17 State co-operative banks, 391 central co-operative banks, 3 State industrial co-operative banks and 19 district industrial co-operative banks were furnished to the banks concerned. Inspection reports relating to 18 central land development banks, 3 State handloom weavers' societies and 3 apex marketing societies were also furnished to the concerned institutions during the year under Report.

Agricultural Refinance Corporation

269. During the year 1969-70, the Corporation sanctioned refinance in respect of 142 schemes of agricultural development such as minor irrigation (62), land development (11), farm mechanisation (7), development of plantation and horticulture (54), development of poultry (1), dairy (1) and fishery (3), and construction of godowns (3). The total financial outlay involved in these schemes was of the order of Rs. 92.78 crores, the Corporation's commitments being Rs. 70.92 crores. This excludes five schemes sanctioned during the year but subsequently withdrawn by the financing institutions.

270. Out of 142 schemes sanctioned during the year under review, 85 schemes are to be implemented through the central land development banks, the refinance provided in their cases being in the form of contribution towards the special development debentures to be floated by the concerned banks. Seven schemes are to be implemented through State co-operative banks and the remaining 50 by scheduled commercial banks, the refinance in their cases being in the form of loans.

271. During the year the Corporation approved reduction in the financial outlays in respect of some schemes sanctioned earlier as also the re-phasing of some schemes so as to extend the period of floatation of the special development debentures. Taking into consideration the changes in the outlay of some schemes sanctioned earlier as a result of rephasing etc., the total number of schemes sanctioned by the Corporation during its seven years of working ended June 30, 1970 is 371, the total outlay and Corporation's commitment being Rs. 259.51 crores and Rs. 214.89 crores, respectively.

272. The disbursements made by the Corporation during the year amounted to Rs. 28.60 crores, raising the total disbursements as at the end of June 1970 to Rs. 59.09 crores. Out of the amount of Rs. 28.60 crores disbursed during the year, a sum of Rs. 26.75 crores was disbursed to the central land development banks, Rs. 1.29 crores to State co-operative banks and Rs. 0.56 crores to scheduled commercial banks. During the year 3 scheduled commercial banks and 1 State co-operative banks made repayments towards principal amounting to Rs. 1.88 lakhs and Rs. 9.11 lakhs, respectively. The first series of bonds under the caption 5½ per cent Agricultural Refinance Corporation Bonds, 1982 was issued by the Corporation for the first time on January 5, 1970 for Rs. 10 crores with the provision to retain the subscriptions received upto 10 per cent in excess of the sum of Rs. 10 crores. Out of the subscription of Rs. 11 crores received towards these Bonds, a sum of Rs. 6,23,000 received on account of subscription from the various Provident Fund Trusts was refunded to them since the bonds in respect of these applications could not be issued in the personal name of their Trustees or their bankers as asked for. The final allotment made was Rs. 10,93,77,000.

273. During the period from July 1, 1969 to June 30, 1970 the Corporation borrowed a sum of Rs. 19.00 crores from the Government of India thus raising the total borrowings to Rs. 44.75 crores.

274. A noteworthy feature of the working of the Corporation during the year was its active association with the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and its affiliate the International Development Association (IDA), in financing capital investment for modernizing and increasing the productive capacity of agriculture. Three Projects, viz., The Tarai Seeds Project (IBRD) and the Gujarat Agricultural Credit Project (IDA) and the Punjab Agricultural Credit Project (IDA) have been approved. Under the agreements between IBRD/IDA, the Government of India, the Corporation and the financing institutions concerned, the IBRD will provide loans to the Government of India for the Tarai Project to the extent of \$ 13.00 million (Rs. 9.75 crores), of which Rs. 6.75 crores will be made available through the Corporation. IDA will provide loans to the Government of India to the extent of \$ 35 million (Rs. 26.25 crores) for the Gujarat Project and \$ 27.5 million (Rs. 20.63 crores) for the Punjab Project, the amounts to be made available through the Corporation being Rs. 26.03 crores and Rs. 20.63 crores, respectively. The Corporation will receive these amounts as loans from the Government of India, on usual terms and conditions.

275. During the year the following important changes in regard to the policy and procedure for the sanction of refinance were made :

(a) The special concession of 10 per cent contribution by State Governments to the special development debentures floated by central land development banks in respect of minor irrigation schemes was further extended upto June 30, 1971.

(b) Consequent to the nationalisation of 14 scheduled commercial banks it was decided that these banks need not register charges such as sub-mortgage, sub-hypothecation, etc. created in favour of the Agricultural Refinance Corporation as they were earlier required to do in compliance with Sections 125 and 135 of the Companies Act, 1956.

(c) With a view to helping commercial banks in obtaining refinance as quickly as possible the Corporation decentralised the work of scrutiny of schemes received from commercial banks. Effective from November 1969, scrutiny of schemes which involve refinance facilities from the Corporation for an amount not exceeding Rs. 5 lakhs is being done by the Corporation's Regional Offices. The form in which a scheme of development of plantation i.e., tea, coffee, rubber and cardamom involving a sum of Rs. 5 lakhs or less is to be submitted has also been simplified to suit the needs of small planters.

(d) The Corporation had been providing since July 1968, refinance for sporadic advances given by scheduled commercial banks through their various offices for purchase of farm equipment including pump-sets, tractors, etc. subject to certain conditions without insistence on an area development approach. This facility was provided as a temporary measure at a time when commercial banks had practically no experience in preparing schemes on an area development basis, to stimulate interest among commercial banks in the refinance facilities offered by the Corporation. As commercial banks have now acquired sufficient experience in formulating schemes on a project basis, the Corporation decided in March 1970 to withdraw the facility of providing refinance for sporadic advances granted by scheduled commercial banks for purchase of farm equipments, etc. The Corporation would continue to refinance schemes formulated by commercial banks on an area development basis.

(e) In view of the difficulties experienced by the banks, the Corporation has decided not to insist on the borrowers taking a comprehensive insurance policy for the pump-sets financed under refinance facility from the Corporation which are also offered as security.

276. In addition to the seven regional offices at Bangalore, Calcutta, Chandigarh, Coimbatore (since shifted to Madras), Hyderabad, Kanpur and New Delhi, the Corporation during the period July 1, 1969 to June 30, 1970 opened regional offices at Ahmedabad, Bhopal, Bhubaneswar, Jaipur, Patana and Trivandrum and a separate unit at Bombay to look after schemes from Maharashtra.

V. DEVELOPMENTS IN EXCHANGE CONTROL

277. In the sphere of Exchange Control, the process of liberalisation of the Rules relating to travel, studies, etc. initiated last year was further carried forward during the year under review. Under the Foreign Travel Scheme, 1970, introduced with effect from 1st March 1970 residents of India can now undertake one trip abroad of their choice without complying with 'P' form formalities provided they have not visited any place outside India (other than Nepal, Ceylon and Mauritius) during the period of three years immediately preceding the date of the journey to be undertaken. Passages under the Scheme can be booked for travel by any airline or shipping line but those who travel on the services of Air-India or by any of the ships of the Shipping Corporation of India and the Moghul Line (excepting those going on Haj pilgrimage) will be entitled to release of exchange of U.S.\$ 100. About 11,000 persons availed of this Scheme upto June 1970.

278. In the matter of travel abroad to attend conferences in future no restriction on numbers would be imposed in cases where there is hospitality from the institutional source in respect of the expenses of the stay abroad.

279. It has also been decided to permit authorised dealers to issue U.S. dollar travellers cheques to travellers who desire to have them irrespective of the currency in which the amount released is expressed or the countries to be visited as specified in the permit subject to certain exceptions.

280. The Rules relating to release of exchange for studies abroad have also been liberalised. The qualifying marks which were 60 per cent in a degree examination in India previously, have been lowered to 55 per cent. For all those fields of study where a degree course does not exist in India nor is an adequate diploma course available, foreign exchange will be released without insisting that the student concerned should be a graduate.

281. Where the annual value of the foreign scholarship secured by a student is £300/- or its equivalent or less, no adjustment in the exchange quota admissible to the student will be made as was the practice previously; where the scholarship exceeds £300/- or its equivalent the adjustment will be made only in respect of the excess over £300/-.

282. Powers have also been delegated to the State Bank of India to release exchange for studies at some of their own offices as well as at the offices of some of their subsidiaries.

283. The policy governing the issue of money changers' licences to hotels has also been liberalised this year. Restricted money changers' licence will be issued to any hotel (or other lodging and boarding establishment such as Y.M.C.A. or Y.W.C.A.) applying for it without insisting on an undertaking or guarantee for a minimum turnover.

284. A new type of non-resident account styled the Non-resident (External) Account has been introduced this year. A noteworthy feature of the Non-resident (External) Account is that funds held in such an account can be remitted abroad by the authorised dealer on receipt of instructions from the account-holder without obtaining any further approval of the Reserve Bank of India. The interest earned on the funds in the account is exempt from Indian Income tax.

285. The Sultanate of Muscat and Oman, the only Persian Gulf State in which Indian Rupee Special Notes were in circulation after 1966, has introduced its own currency known as the Rial Saidi with effect from the 8th May 1970. Arrangements have, therefore, been made to retire the Indian currency notes which were in circulation in the Sultanate. With the introduction of a new currency in Muscat and Oman, Indian Rupee is no longer in circulation anywhere outside India.

286. The following table gives data relating to release of foreign exchange and grant of 'P' form clearance for travel abroad for various purposes during the year ended June 1970.

I. Foreign Exchange Permits

Purpose of Travel	No. of Permits	Amount of Exchange Sanctioned (Rs. lakhs)
Business	9,840	634
Higher studies/training	6,578	906
Medical treatment	479	47
Study tours	667	32
Attending conferences	848	18
Miscellaneous	7,893	136
Total	26,305	1,773

II. 'P' Forms

Purpose of Travel	No. of 'P' Forms Approved
Joining head of family	10,753
Visits to relatives/friends	14,003
Export promotion	369
Employment	4,675
Emigration	6,557
Studies/training	5,873
Miscellaneous	15,865
Total	58,095

VI. SEMINARS AND SURVEYS ORGANISED BY THE RESERVE BANK

287. In February 1970, the Bank sponsored a four-day international seminar on Banking and Development. The participants in the Seminar included Governors, Deputy Governors and a number of senior officials of several Central Banks, bankers and economists from developed and developing countries. The object of the Seminar was to obtain an exchange of views and a comparison of mutual experience and problems that arose in the process of adaptation and orientation of the banking and financial system in developing countries to the new and varied needs of development. There was no attempt at the Seminar to draw agreed conclusions. After the inaugural session, the Seminar discussed the theme of Banking and Development in terms of (i) Commercial Banking and Development, (ii) Specialised Financing Agencies and (iii) Central Banking and Development.

288. The proceedings of and the papers presented at the Seminar have been published in a book form by the Bank.

289. In pursuance of the suggestions made by the Seminar on Financing of Agriculture by commercial Banks and by a study group of the National Credit Council, the Governor of the Bank has set up in September 1969, an Expert Group on State Enactments having a bearing on commercial banks' lending to agriculture. The report is being finalised.

290. The Fourteenth Conference of the representatives of the SFCs was convened in Bombay in March 1970 by the Reserve Bank for exchange of views between the Bank and representatives of the SFCs and other lending institutions on the problems confronting them in their operations and other matters of vital interest. Some of the important subjects considered by the Conference included the question of co-ordination of the activities of banks and SFCs and mobilisation of resources and ways of increasing profitability of SFCs. In the light of discussions, the Bank set up two working groups, of which one would be concerned with suggesting measures for strengthening the financial position of the SFCs and the other with studying the problem of financing industrial estates (other than in the public

sector). Another important item discussed was the provision of credit on soft terms to units located in backward areas in order to promote development of these areas. The other items discussed included methods of increasing SFCs' assistance to small-scale industries through the fixation of certain targets to be achieved, setting up of separate cells for small units, undertaking surveys, simplification of procedures, etc.

291 Field studies were undertaken by the officers of the Agricultural Credit Department in the month of April 1970 in Aurangabad and Poona districts of the Maharashtra State to find out whether the assessment of the repaying capacity on the basis of incremental income as envisaged by the Standing Advisory Committee of the All-India Central Land Development Banks Co-operative Union would be of practical utility in regard to the issue of long-term loans by Land Development Banks. With a view to making a qualitative assessment of the Crop Loan System, special studies were also undertaken by the regional offices of the Department in the States of Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Punjab and Madhya Pradesh.

292 The Department of Statistics had carried out in August 1968 a survey of current industrial situation and likely developments in the near future. The report on the study was published in the April 1969 issue of the Bank's Bulletin. Similar study was carried out in 1969 and a report of this second study was published in March 1970 issue of the Bank's Bulletin.

293. At the instance of the Banking Commission, the Division of Rural Surveys of the Economic Department conducted a Field Study on Banking Facilities in one district each in twelve selected States and submitted a Report embodying the main findings to the Commission. The object of the study was to assess the extent of banking services provided by commercial and co-operative banks and primary agricultural credit societies in semi-urban and rural areas and to indicate the scope for extending as well as improving the services provided by these institutions. At the instance of the Agricultural Credit Department, the Division also conducted a field study in two major sugarcane growing areas in Ahmednagar district in Maharashtra State. The object of the study was to examine whether it was necessary for the Bank to provide medium-term credit in place of short-term credit, as at present, for financing the cultivation of sugarcane in that district. During the period under review, the Division initiated a field study to inquire into the concentration of a large number of tractors in a single village in Jodhpur district in Rajasthan. The purpose of the study is to assess the output-raising and cost-saving effects of tractors on the farm business of both the owners and hirers of tractors. The impact of tractors on the village economy, especially on agricultural labourers is also proposed to be studied. Besides, the Division continued its regular surveys including the Survey of Co-operative Bank Advances and Deposits. It also brought out a publication entitled "Bank Credit to Farmers for Irrigation Development: Studies in Micro-analysis of Feasibility" based on eight field studies conducted during the years 1964—68.

294 During the year 1969-70, the Division of Fiscal Analysis Economic Department, consolidated the data on Survey of Finances of Local Authorities, 1965-66 and 1966-67. The article analysing the results of the Survey is under preparation for publication in the Reserve Bank of India Bulletin. The next Survey covering 1967-68 and 1968-69 has also been initiated during the period. In respect of the annual Survey of Ownership of Central and State Government Securities the data received for the Survey as on March 31, 1969 are being processed.

295. The results of the survey, undertaken by the Division of International Finance, Economic Department, of unclassified receipts (i.e. receipts in amounts below Rs. 10,000 or its equivalent for which no purpose-wise details are required to be reported to the Exchange Control Department by the authorised dealers) referred to in last year's Report were finalised during the year and an analysis of the results was published in the March 1970 issue of the Bank's Bulletin. The purposewise pattern thrown up by the survey results is now being used for attempting the purpose wise distribution of these receipts in the balance of payments statistics. With a view to keeping up-to-date the purpose-wise pattern, the survey has been placed on a continuing basis covering one quarter of a year. Accordingly, for the year 1969, the survey conducted covered the quarter October-December, the results of which are currently being processed. For the year 1970, the survey covering the quarter

July-September is in progress. The survey of freight and passage fare payments and receipts relating to Indian and foreign shipping and airline companies continued to be undertaken on an annual basis.

296. The Division also continued to call for quarterly foreign investment survey reports from branches of foreign companies and Indian joint stock companies. Based primarily on these reports, an article on "Indian's International Investment Position in 1965-66 and 1966-67" was published in the August 1969 issue of the Bank's Bulletin. Besides reviewing the international investment position, the article presented the new series of balance of payments account for the two years, which is in continuation of the series published in the November 1967 issue of the Bank's Bulletin.

VII. EDUCATION AND TRAINING

297. The National Institute of Bank Management (NIBM) took the initial steps towards establishing its capabilities in areas of training, research and consultancy. Ten faculty members in various disciplines have already joined and the number is expected to reach twenty-five by the end of 1970. The NIBM has reviewed the training needs of the banking industry and is developing a comprehensive training system in collaboration with the Staff Training Colleges of the banks. Steps are now being taken to implement these schemes in the individual banks by strengthening the Staff Training Colleges and establishing regional training centres. Preparations have been completed for Executive Development Courses which are expected to cover approximately 250 senior executives during 1970-71. Several research projects have been initiated, using modern management techniques, and consultancy service is being provided to individual banks. The NIBM organised six workshops, on urgent issues facing the banking industry viz., "Financing Small-scale Industry," "Financing Agriculture," "Deposit Mobilisation," "Customer Service," "Management Development in the Banking Industry" and "Financing Exports". Senior bankers and Chairmen/Custodians of banks participated in these programmes which helped to forge an industrywide approach to these issues.

298. The Bank continued to sponsor and organise the training courses for the supervisory staff of commercial banks to equip themselves to shoulder responsibilities developing on them. During the period under review, the Bankers' Training College at Bombay conducted three Senior Courses, two Intermediate Courses, two courses on Agricultural Finance, one course each on Foreign Exchange, Personnel and Organisation and Industrial Finance. A new course on Organisation and Methods was introduced at the College during the period under review. The course is intended for the officers of commercial banks who are at present working in the Organisation and Methods Department or are likely to be entrusted with Organisation and Methods assignments. The total number of bank officials who received training in the College during the period is 361 (including 6 officials from foreign countries). Since the inception of the College in 1954, 3,573 officials have received training in the different courses conducted for the supervisory staff of commercial banks. A new course called Central Banking Course I, is being instituted for the Staff Officers Grade I of the Bank at the Bankers' Training College, Bombay. The first course is expected to start in November 1970. The objectives of the course are: (a) to develop amongst Staff Officers Grade I of the Bank the capacity to appreciate the nature of the economic processes in a developing country, (b) to refresh them in the theory and practice of Central Banking with particular reference to the operations of the Reserve Bank of India and (c) to expose them to the modern techniques of management and to give them the basic understanding of the job carried out in the different Departments of the Bank in order to foster intergroup mobility.

299. The Bank also continued arrange courses on co-operative banking for the managerial staff of State, central and urban co-operative banks. In the absence of suitable accommodation, courses were conducted in the past at the Bankers' Training College, Bombay. However, in September 1969 the Co-operative Bankers' Training College started functioning at the Bank's newly constructed premises at Poona. So far the Bank has been conducting courses mainly for the higher personnel (i.e. executives at the headquarters) of the State, central and urban co-operative banks. It has been the Bank's intention to run courses for Branch Managers of State/central co-operative banks, land development banks, etc. With the inauguration

of the Co-operative Bankers' Training College, introduction of these courses has been possible. During the period under review two courses were conducted for the managerial staff of State and central co-operative banks, one course at the Bankers' Training College, Bombay and the other at the Co-operative Bankers' Training College, Poona and three courses were conducted for the managerial staff of urban co-operative banks, one course at the Bankers' Training College, Bombay and two at the Co-operative Bankers' Training College, Poona. The number of officials who participated in these two courses was 66 and 79, respectively (including 2 officials from foreign countries). The total number of officials who received training in the above courses so far was 277 and 194 respectively.

300. The following new courses were introduced at the Co-operative Bankers' Training College, Poona during the period under review :—

- (a) two courses of 3 weeks each were conducted in Project Planning and Appraisal for the personnel of the Land Development Banks;
- (b) a course for Branch Members of State/central co-operative banks for a period of 6 weeks; and
- (c) a course on agricultural finance for middle level personnel of commercial banks, viz., agents, managers, accountants and field inspectors who are actually handling agricultural finance in the rural branches of the commercial banks, for a period of 8 weeks.

301. The courses conducted by the Bank for the managerial personnel of co-operative banks cover essentially 'banking policies, practices and procedures'. Since an executive of a co-operative bank has to be both a banker and a manager, the Bank entered into a collaboration agreement, with the Vaikunth Mehta National Institute of Co-operative Management, Poona so as to include besides 'banking', 'business management' and 'co-operative principles' in the training ingredients. The Vaikunth Mehta National Institute of Co-operative Management has been housed in the Co-operative Bankers' Training College campus to enable a reciprocal arrangement for talks by the faculty of one institution in the courses of the other. The Director, Vaikunth Mehta National Institute of Co-operative Management who has been appointed as the Director of the Co-operative Bankers' Training College as well will coordinate the activities of the two institutions.

302. The Staff Training College, Madras continued to conduct the General Course on central banking for junior supervisory staff and the Inspection Course for officers and supervisory staff of the Department of Banking Operations and Development and the Agricultural Credit Department on a regular basis. Recently, a special course in central banking entitled "General Course for Staff Officers Grade II (Direct Recruits) on completion of departmental training," was introduced at the College. The objective of the Course was to expose the Staff Officers *inter alia* to the modern concept of management including human relations. The total number of officers and supervisory staff who have so far received training in the College is 2,549. Except at Calcutta, the Zonal Training Centres at all other places viz., Bombay, Madras and New Delhi continued to conduct courses for the Junior and senior clerks of the Bank. The Calcutta Centre is expected to be reopened shortly. The total number of clerical staff who have so far received training in the various Zonal Training Centres is 5,263. Under the standing arrangements with the Administrative Staff College of India, Hyderabad, officers were also sent to the management development courses conducted by the College. Officers are also sent to the banking and other courses conducted in the Bankers' Training College for the managerial staff of commercial banks and also to the

short-term courses on management development organised by the All-India Management and State Level Associations, Productivity Councils, Management Institutes and similar other bodies. Officers are also sent to the central banking course conducted jointly by some of the Central Banks (called the SEANZA Course) and the course conducted by the Bank of England, and other courses of interest to the Bank, organised by some foreign institutes. The Bank has also been sending officers for training in banking institutions in U.S.A., U.K., Australia, West Germany, etc. Institution of a residential training course in Central Banking and Management techniques for the present and the prospective Senior Staff Officers Grade III is also under contemplation. The formulation of this course will be taken up after the Bank has gained experience in conducting the Central Banking Course for Staff Officers Grade I.

303. During the year, the Bank brought out Hindi version of the Annual Report of the Bank 1968-69 and abridged Hindi versions of the Report on Currency and Finance, 1968-69 and the Survey Report on Foreign Collaboration in Indian Industry, 1968. The Bank also undertook the work of translating the Annual Reports of Agricultural Refinance Corporation, Deposit Insurance Corporation, Industrial Development Bank of India and Unit Trust of India into Hindi. In order to comply with the provisions of the Official Languages Act, 1963 as amended in 1967, the Bank issued Press Communiques (Notes/Releases/Summaries, Notices and Notifications simultaneously in Hindi and English. Letters and communications received in Hindi from the public, the Central Government and the State Governments were entertained and replied to in Hindi, wherever necessary. Hindi classes continued to be conducted by the Bank at various centres on a voluntary basis for the benefit of the Bank's staff. As an incentive to the Staff for acquiring proficiency in Hindi, (a) text books prescribed for the courses for which classes were conducted by the Bank, were made available to them and (b) an honorarium of Rs. 100/- was paid to the employees for passing different examinations in Hindi. The employees who were not able to attend such classes, were encouraged to join the correspondence courses in Hindi organised by the Central Hindi Directorate of the Government of India and, as an incentive, reimbursement of the fees for such courses was also permitted in the case of the members of the staff belonging to Class III.

VIII. ACCOUNTS AND OTHER MATTERS

304. During the accounting year ended the 30th June 1970, the Bank's income, after making statutory and other provisions, amounted to Rs. 105.45 crores as against Rs. 99.35 crores in the previous year. The total expenditure for the year amounted to Rs. 30.45 crores as against Rs. 29.35 crores in the previous year. The net profit set aside for payment to Central Government was Rs. 75 crores as against Rs. 70 crores paid last year.

305. The contributions to the National Agricultural Credit (Long-term Operations) Fund, the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund and the National Industrial Credit (Long-term Operations) Fund were Rs. 17 crores, Rs. 2 crores and 20 crores, respectively, as against Rs. 12 crores, Rs. 2 crores and Rs. 20 crores, respectively, during 1968-69.

306. The rise of Rs. 6.10 crores in the income during 1969-70 was mainly due to increased interest earned on investments in securities, foreign currency holding, loans and advances to banks, State Governments, etc. as also larger discount on Rupees and Foreign Treasury Bills. The increase of Rs. 1.10 crores in the expenditure was mainly on account of establishment charges owing to payment of (i) dearness allowance at enhanced rates to the award staff, (ii) arrears of compensatory allowance to the Graduates/C.A.I.I.B. Employees in Class III and (iii) house rent allowance at higher rate to the Staff Officers opting for transferability. Depreciation charged this year on properties acquired in the previous year and a rise in the agency charges paid to State Bank of India and its subsidiaries also accounted for the increase in the expenditure for 1969-70.

Auditors

307. The accounts of the Bank have been audited by M/s. A.F. Ferguson & Co., Bombay, M/s. Brahmayya & Co., Madras and M/s. Ray & Ray, Calcutta who were appointed by Government of India as auditors of Reserve Bank of India by the notification No. F. 3(50)-BC/69 dated 5th December 1969 issued in exercise of the powers conferred by Section 50 of the Reserve Bank of India Act.

The Central Board

308. Shri L.K. Jha relinquished charge of the office of Governor of the Bank as from the forenoon of the 4th May 1970 on his appointment as India's Ambassador to the U.S.A. Deputy Governor, Shri B.N. Adarkar, succeeded him as Governor with effect from the same date and held that post till his retirement from the Bank on the 15th June 1970. Consequent upon his appointment as the Secretary to the Government of India, Department of Banking, Ministry of Finance, Shri A. Baksi ceased to be a Deputy Governor of the Bank under the provisions of sub-section (1) of Section 11 of the Reserve Bank of India Act, 1934, with effect from the afternoon of 8th September 1969. Shri J.J. Anjaria whose term of appointment as Deputy Governor of the Bank expired on the 31st January 1970, was granted an extension by the Central Government for a month till the end of February 1970. The Board would like to take this opportunity of placing on record its appreciation of the eminent services rendered by Sarvashri L.K. Jha, B.N. Adarkar and J.J. Anjaria during their association with the Bank. The Central Board regrets to record the sudden death of Shri J.J. Anjaria on 10th April 1970 shortly after he retired as Deputy Governor of the Bank.

309. Shri S. Jagannathan assumed charge as Governor with effect from the forenoon of the 16th June 1970 for a period of five years. Dr. R.K. Hazari assumed charge as Deputy Governor of the Bank on the forenoon of 27th November 1969 for a period of five years.

310. Shri N.A. Palkhivala and Prof. C.N. Vakil retired as Directors of the Central Board of the Bank on expiry of their terms of appointment on the 14th January 1970 and 23rd January 1970, respectively. The Board wishes to place on record its appreciation of the services rendered by the retired Directors.

311. Shri A. Baksi was nominated as Director of the Central Board in terms of Section 8(1)(d) of the Reserve Bank of India Act, 1934, with effect from the 25th October 1969 *vice* Dr. I.G. Patel. Shri P.B. Gajendragadkar and Dr. A.M. Khusro were nominated as Directors of the Central Board of the Bank under Section 8(1)(c) of the Reserve Bank of India Act, 1934, with effect from the 28th February 1970.

312. Seven meetings of the Central Board were held during the year, two of which were held in Bombay and one each in Madras, Calcutta, New Delhi, Jaipur and Patna. The Committee of the Central Board held fifty-two meetings, of which five were held in New Delhi, one each in Madras and Calcutta and the rest in Bombay.

313. Shri V.G. Pendharkar has been appointed as Executive Director with effect from the 1st March 1970. Executive Director Shri K.C. Mittra left India on the 28th June 1970 to take up an assignment under the I.M.F. Technical Assistance Programme to assist the authorities in Yemen Arab Republic in establishing a Central Bank there.

Local Boards

314. Shri J.D. Sethi resigned his office as a Member of the Northern Area Local Board, New Delhi with effect from the 14th January 1970.

Opening and Closing of Offices and Changes in the Organisation and Management

315. A full-fledged office of the Issue Department was set up at Hyderabad from November 3, 1969 with Andhra Pradesh as its Currency Jurisdiction.

Bank's Premises**A Office Premises**

316. The annexe building at Madras has been completed, while the annexe building at Nagpur is nearing completion. The construction of the main office building at Bangalore has been taken up and the proposed office buildings and annexes at Jaipur, Bhubaneswar and Trivandrum and the main office building at Hyderabad and office building in the Mint compound

at Bombay are in the planning stage. Arrangements are in progress for taking on lease a building at Ahmedabad and a portion of a State-owned building at Bhubaneswar for opening Sub-offices of the Issue Department and Sections of the Banking Department. At Ernakulam, premises have been taken for opening a branch of the Exchange Control Department.

B. Residential Quarters

317. Every effort is being made to provide residential quarters, which are heavily subsidised, for the various categories of staff at all important centres. The Bank has so far provided 149 quarters for Staff Officers Grade I, 366 for Staff Officers Grade II, 1,376 for clerical staff and 432 for subordinate staff at Bombay, Calcutta, New Delhi, Madras, Nagpur, Patna and Kanpur, covering approximately 14 per cent of the total staff at these centres.

318. The construction of a colony of 120 flats for subordinate staff has been completed at Madras and other colonies of 12 flats for Staff Officers Grade I at Madras and 240 for clerical staff and 192 for subordinate staff at Bombay are nearing completion. Construction of 272 flats at New Delhi and 456 flats at Calcutta for clerical and subordinate staff has since commenced, while construction of 56 flats at Bangalore for Staff Officers Grade I and Grade II and 224 flats at Kanpur and 104 flats at Nagpur for the clerical and subordinate staff is expected to commence within a few months. Further construction of colonies for Staff Officers Grade I and II at New Delhi and Bombay and for Class III and IV staff at Bhubaneswar, Madras and Bangalore is in the planning stage. Proposals for appointment of architects for the proposed quarters for Staff Officers Grade I and II at Kanpur and clerical and subordinate staff at Hyderabad and Madras are under consideration.

319. The Bank is continuing its efforts to secure suitable land for construction of Staff quarters at centres where no plot has been secured or where the number of quarters provided is inadequate.

320. The scheme of taking flats on company lease for staff officers continues as there is no improvement in the housing situation in the cities where offices of the Bank are located.

Employer-Employee Relations

321. The extended period of operation of the Award of the Arbitrator in respect of workmen employees in Class II and III in Reserve Bank expired on 5th April 1970. Negotiations are being held with effect from 1st June 1970 between the management of the Reserve Bank and the All-India Reserve Bank Employees' Association representing the workmen employees in Class II and III for revision of pay scales and allowances, leave fare concessions, medical aid, etc. The agreement between the management of the Reserve Bank and the All-India Reserve Bank Workers' Federation governing pay scales, allowances and other service conditions of Class IV employees expired on 31st December 1968. The Federation has since submitted a Charter of Demands and negotiations thereon have commenced with effect from 12th June 1970.

Employees' Housing Loans Scheme

322. During the year under report Housing Loans were sanctioned as under:

	No. of Societies	Amount Rs.
A. New Co-operative Housing Societies	11	59,43,065
Additional loans to Co-operative Housing Societies already formed	8	2,37,690
Total		61,80,755
B. Individual members of Staff	No. of Employees	
New Loans	69	13,69,830
Additional loans to employees who had already availed of loans earlier	24	66,672
Total		14,36,502

The total amount of 'Society' and 'Individual' loans sanctioned since the introduction of the scheme in 1961 amounts to Rs. 2,07,80,355.00 and Rs. 50,97,455.00, respectively. In all 1,227 employees have availed themselves of this facility.

RESERVE BANK OF INDIA
BALANCE SHEET AS AT JUNE 30, 1970
ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES				ASSETS			
	Rs.	P.			Rs.	P.	
Notes held in the Banking Department	14,03,72,578.00			Gold Coin and Bullion:—			
Notes in circulation	4026,53,93,366.50			(a) Held in India	182,53,10,862.72		
				(b) Held outside India		
				Foreign Securities	386,41,99,950.11		
Total Notes issued			4040,57,65,944.50	Total			578,95,10,812.83
				Rupee Coin			54,08,40,185.37
				Government of India Rupee Securities			3407,54,14,946.30
				Internal Bills of Exchange and other Commercial Paper
Total Liabilities			4040,57,65,944.50	Total Assets			4040,57,65,944.50

LIABILITIES				ASSETS			
	Rs.	P.			Rs.	P.	
Capital Paid-up	5,00,00,000.00			Notes	14,03,72,578.00		
Reserve Fund	150,00,00,000.00			Rupee Coin	1,43,563.00		
National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund	172,00,00,000.00			Small Coin	4,55,261.27		
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	37,00,00,000.00			Bills Purchased and Discounted:—			
National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund	95,00,00,000.00			(a) Internal		
				(b) External		
Deposits:—				(c) Government Treasury Bills	12,95,49,600.96		
(a) Government				Balances held Abroad*	98,48,79,980.21		
(i) Central Government	58,13,22,772.04			Investments**	124,53,55,153.90		
(ii) State Governments	16,21,55,803.40			Loans and Advances to:—			
(b) Banks				(i) Central Government	31,65,00,000.00		
(i) Scheduled Commercial Banks	186,94,83,593.84			(ii) State Governments@		
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	14,40,34,831.91			Loans and Advances to:—			
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	79,01,125.01			(i) Scheduled Commercial Banks†	308,32,05,000.00		
(iv) Other Banks	32,28,422.36			(ii) State-Co-operative Banks††	224,09,53,540.61		
(c) Others	166,98,04,194.93			(iii) Others	2,72,41,993.32		
Bills Payable	22,62,49,363.71			Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund			
Other Liabilities	56,75,37,035.32			(a) Loans and Advances to:—			
				(i) State Governments	34,32,24,745.48		
				(ii) State Co-operative Banks	20,28,30,736.98		
				(iii) Central Land Mortgage Banks		
				(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	9,57,02,235.00		
				Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund			
				Loans and Advances to State Co-operative Banks	4,34,96,520.00		
				Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund			
				(a) Loans and Advances to the Development Bank	26,26,71,044.00		
				(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank		
				Other Assets	70,51,35,189.79		
Total Liabilities			982,17,17,142.52	Total Assets			982,17,17,142.52

Contingent liability on partly paid shares Rs. 8,99,992.90 (Sterling Investments of £50,000 converted@ Rs. 100=£5.5556).

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**† Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund.

(ii) Includes £ 50,000 and U.S. \$ 4,947,500 held abroad (equivalent of Rs. 3,80,06,242.80).

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund.

†Includes Rs. 157,45,80,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

††Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

R.C. SACHDEVA, Chief Accountant

S. JAGANNATHAN, Governor.
P.N. DAMRY, Deputy Governor.
R.K. HAZARI, Deputy Governor.

Dated, the 23rd July, 1970.

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1970

INCOME		Rs.	P.
Interest, Discount, Exchange, Commission, etc.†		105,44,62,572.48	
EXPENDITURE			
Establishment		14,84,25,555.34	
Directors' and Local Board Members' Fees and Expenses		80,418.98	
Auditors' Fees		37,500.00	
Rent, Taxes, Insurance, Lighting, etc.		86,14,192.57	
Law Charges		1,15,500.31	
Postage and Telegraph Charges		9,51,349.58	
Remittance of Treasure		62,30,611.32	
Stationery, etc.		25,11,268.94	
Security Printing (Cheque, Note Forms, etc.)		4,73,48,430.99	
Depreciation and Repairs to Bank Property		1,24,38,485.83	
Agency Charges		6,99,48,774.92	
Contributions to Staff and Superannuation Funds		7,32,000.00	
Miscellaneous Expenses		70,28,204.49	
Net available balance		75,00,00,279.21	
Total		105,44,62,572.48	
Surplus Payable to the Central Government		75,00,00,279.21	

RESERVE FUND ACCOUNT

By Balance on 30th June, 1970	150,00,00,000.00
By transfer from Profit and Loss Account	Nil
Total	150,00,00,000.00

† After making usual or necessary provisions in terms of Section 47 of the Reserve Bank of India Act.

S. JAGANNATHAN, Governor.
P.N. DAMRY, Deputy Governor.
R.K. HAZARI, Deputy Governor.

R.C. SACHDEVA, Chief Accountant

REPORT OF THE AUDITORS

TO THE PRESIDENT OF INDIA,

We, the undersigned Auditors of the Reserve Bank of India, do hereby report to the Central Government upon the Balance Sheet and Accounts of the Bank as at 30th June, 1970.

We have examined the above Balance Sheet with the Accounts, Certificates and Vouchers relating thereto of the Central Office and of the Offices at Calcutta, Bombay and Madras and with the Returns submitted and certified by the Managers of the other Offices and Branches, which Returns are incorporated in the above Balance Sheet, and report that where we have called for explanations and information from the Central Board such information and explanations have been given and have been satisfactory. In our opinion, the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing the particulars prescribed by and in which the assets have been valued in accordance with the Reserve Bank of India Act, 1934 and Regulations framed thereunder and is properly drawn up so as to exhibit a true and correct view of the State of the Bank's affairs according to the best of our information and the explanations given to us, and as shown by the Books of the Bank.

Dated, the 23rd July, 1970.

BRAHMAYYA & CO.,
RAY & RAY
A.F. FERGUSON & CO., } Auditors.

[No. F. 3 (15)-BC/72]
K. YESURATNAM, Under Socy.

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 3rd January, 1973

S.O. 267.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and of all other powers enabling him in this behalf, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in respect of persons employed in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, namely:—

1. (1) These rules may be called the General Provident Fund (Central Services) First Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, in the Fifth Schedule, in paragraph 2, after the entry "Director, National Fire Service College, Nagpur" the following entries shall be inserted namely:—

Senior Deputy Accountant General (Admn.)/Deputy Pradesh, Hyderabad;

Senior Deputy Accountant General (Admn.)/Deputy Accountant General (Admn.), Assam, Meghalaya and Nagaland, Shillong;

Senior Deputy Accountant General (Admn.), Bihar Ranchi;

Senior Deputy Accountant General (Admn.)/Deputy Accountant General (Admn.), Central, Calcutta;

Senior Deputy Accountant General (Admn.), Central Revenues, New Delhi;

Senior Deputy Accountant General (Admn.), Jammu and Kashmir, Srinagar;

Senior Deputy Accountant General (Admn.)/Deputy Accountant General (Admn.), Kerala, Trivendrum;

Senior Deputy Accountant General (Admn.), Madhya Pradesh, Gwalior;

Senior Deputy Accountant General (Admn.)/Deputy Accountant General (Admn.), Maharashtra, Bombay;

Senior Deputy Accountant General (Admn.)/Deputy Accountant General (Admn.), Mysore, Bangalore;

Senior Deputy Accountant General (Admn.)/Deputy Accountant General (Admn.), Orissa, Bhubaneswar;

Senior Deputy Accountant General (Admn.), Tamil Nadu, Madras;

Senior Deputy Accountant General (Admn.)/Deputy Accountant General (Admn.), Rajasthan, Jaipur;

Senior Deputy Accountant General (Admn.), West Bengal, Calcutta;

Senior Deputy Accountant General (Admn.), U.P., Allahabad;

Senior Deputy Accountant General (Admn.)/Deputy Accountant General (Admn.), Commerce, Works and Miscellaneous, New Delhi."

[No. 13(8)—E.V.(B)/72]

S. S. L. MALHOTRA, Under Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1973

का. आ. 268.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार रबड़ आइस बैग निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नीलिखित नियम एल्लुचारा बनाती है।

1. इन नियमों का नाम रबड़ आइस बैग निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम 1973 है।

2. रबड़ आइस बैग निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 के, नियम 4 में:—

(क) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नीलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जायगा अर्थात्:—

"उपनियम (3) के अधिन सूचना तथा घोषणा की प्राप्ति पर, अभिकरण रबड़ आइस बैगों के परीक्षण का निरीक्षण, निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार यह देखने के लिए करेगा कि वह निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 की धारा 8 के अधिन मान्यताप्राप्त विनिर्देश के या यथास्थिति, निर्यात सविज्ञा में दिए गए किन्हीं अन्य विनिर्देशों के या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। (ख) उपनियम (5) के अंत में निम्नीलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा: "परन्तु, जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं हो गया है वहां वह सात दिन की उक्त अवधि के भीतर ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर देगा तथा इसके लिए कारण सहित निर्यातकर्ता को ऐसे इंकार के बारे में संसूचित करेगा।"

[फा. सं. 6(26)/72 नि. नि. तथा नि. सं.]

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 3rd February, 1973

S.O. 268.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Rubber Ice Bags (Inspection) Rules, 1966.

1. These rules may be called the Export of Rubber Ice Bags (Inspection) Amendment Rules, 1973.

2. In rule 4 of the Export of Rubber Ice Bags (Inspection) Rules, 1966—

(a) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"On receipt of the intimation and declaration under sub-rule (3), the Agency shall inspect the consignment of ice bags as per the instructions issued by the Export Inspection Council from time to time with a view to seeing that the same conforms to the specification recognised under section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963, or, as the case may be, any other specifications stipulated in the export contract or the approved sample."

(b) The following proviso shall be added at the end of sub-rule (5):

"Provided that where the agency is not so satisfied, it shall within the said period of 7 days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with reason therefor."

[No. 6(26)/72-EI&EP]

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1973

का. आ. 269.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार रबड़ की गर्म पानी की बोतलों निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाती है।

1. इन नियमों का नाम रबड़ की गर्म पानी की बोतलों निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 है।

2. रबड़ की गर्म पानी की बोतलों निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 के नियम 4 में :—

(क) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“उपनियम (3) के अधीन सूचना तथा घोषणा की प्राप्ति पर, अभिकरण, रबड़ की गर्म पानी की बोतलों (शीतलों) के परीक्षण का निरीक्षण, निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किए आदेशों के अनुसार यह देखने के लिए करेगा कि वह निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त विनिर्देशों या, यथास्थिति निर्यात संविदा में दिए गए अन्य विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं।”

(ख) उपनियम (5) के अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा :—“परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं हो गया है, वहां वह 15 दिन की उक्त अवधि के भीतर ऐसा प्रमाणपत्र देने से इंकार कर देगा तथा इसके लिए कारण सहित ऐसे इंकार के बारे में निर्यातकर्ता को संसचित करेगा।”

[फा. सं. 6(26)/72 नि. नि. तथा नि. सं.]

S.O. 269.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Rubber Hot Water Bottles (Inspection) Rules, 1966.

1. These rules may be called the Export of Rubber Hot Water Bottles (Inspection) Amendment Rules, 1973.

2. In rule 4 of the Export of Rubber Hot Water Bottles (Inspection) Rules, 1966—

(a) for sub-rule (4) the following sub-rule shall be substituted namely :

“On receipt of the intimation and declaration under sub-rule (3), the Agency shall inspect the consignment of rubber hot water bottles (bags) as per the instructions issued by the Export Inspection Council from time to time with a view to seeing that the same conforms to the specification recognised under section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 or as the case may be, any other specifications stipulated in the export contract or the approved sample.”

(b) The following proviso shall be added at the end of sub-rule (5) :

“Provided that where the agency is not so satisfied, it shall within the said period of 7 days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with reason therefor.”

[No. 6(26)/72-EI&EP]

का. आ. 270.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, रबड़ पट्टे निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाती है।

1. इन नियमों का नाम रबड़पट्टे निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 है।

2. रबड़-पट्टे निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 के नियम 4 में :—

(क) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“उपनियम (3) के अधीन सूचना तथा घोषणा की प्राप्ति पर, अभिकरण रबड़ पट्टों के परीक्षण का निरीक्षण, निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार यह देखने के लिए करेगा कि वह निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 6 के अधीन, यथास्थिति, मान्यताप्राप्त विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं।”

(ख) उपनियम (5) के अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा :—

“परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं हो गया है, वहां वह 15 दिन की उक्त अवधि के भीतर ऐसा प्रमाणपत्र देने से इंकार कर देगा तथा इसके लिए कारण सहित निर्यातकर्ता को ऐसे इंकार के बारे में संसचित करेगा।”

[फा. सं. 6(26)/72 नि. नि. तथा नि. सं.]

S.O. 270.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Rubber Belts (Inspection) Rules, 1966.

1. These rules may be called the Export of Rubber Belts (Inspection) Amendment Rules, 1973.

2. In rule 4 of the Export of Rubber Belts (Inspection) Rules, 1966—

(a) for sub-rule (4) the following sub-rule be substituted namely :

“On receipt of the intimation and declaration under sub-rule (3), the Agency shall inspect the consignment of rubber belts as per the instructions issued by the Export Inspection Council from time to time with a view to seeing that the same conforms to the specifications recognised under section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 or the approved sample, as the case may be.”

(b) The following proviso shall be added at the end of sub-rule (5) :

“Provided that where the agency is not so satisfied, it shall within the said period of 15 days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with reason therefor.”

[No. 6(26)/72-EI&EP]

का. आ. 271.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, रबड़ पट (बेल्टिंग) निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाती है।

1. इन नियमों का नाम रबड़ पट (बेल्टिंग) निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 है।

2. रबड़ पट (बेल्टिंग) निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 के नियम 4 में :—

(क) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रौढ स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“उपनियम (3) के अधीन सूचना तथा घोषणा की प्राप्ति पर, अभिकरण, रबड़ पटों (बेल्टिंग) के परीक्षण का निरीक्षण नियति निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार यह देखने के लिए करेगा कि वे निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 8 के अधीन, यथास्थिति, मान्यताप्राप्त विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं।”

(ख) उपनियम (5) के अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा :—

“परन्तु, जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं हो गया है, वहां वह 15 दिनों की उक्त अवधि के भीतर ऐसा प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर देगा तथा इसके लिए कारण सक्षि निर्यातकर्ता को ऐसे इंकार के बारे में संसूचित करेगा।”

[फा. सं. 6(26)/72 नि. नि. तथा नि. सं.]

S.O. 271.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Rubber Belting (Inspection) Rules, 1966.

1. These rules may be called the Export of Rubber Belting (Inspection) Amendment Rules, 1973.

2. In rule 4 of the Export of Rubber Belting (Inspection) Rules, 1966—

(a) for sub-rule (4) the following sub-rule shall be substituted namely :

“On receipt of the intimation and declaration under sub-rule (3), the Agency shall inspect the consignment of rubber beltings as per the instructions issued by the Export Inspection Council from time to time with a view to seeing that the same conforms to the specifications recognised under section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 or the approved sample, as the case may be.”

(b) The following proviso shall be added at the end of sub-rule (5) :

“Provided that where the agency is not so satisfied, it shall within the said period of 15 days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with reason therefor.”

[No. 6(26)/72-EI&EP]

का. आ. 272.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, रबड़ दस्ताने निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाती है।

1. इन नियमों का नाम रबड़ दस्ताने (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 है।

2. रबड़ दस्ताने निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 के नियम 4 में :—

(क) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रौढ स्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

“उपनियम (3) के अधीन सूचना तथा घोषणा की प्राप्ति पर, अभिकरण रबड़ दस्ताने के परीक्षण का निरीक्षण नियति निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार यह देखने के लिए करेगा कि वह निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 8 के अधीन मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के या, यथा स्थिति निर्यात संविदा में दिए गए अन्य विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं।”

(ख) उपनियम (5) के अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा :—

“परन्तु, जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं हो गया है, वहां वह 7 दिन की उक्त अवधि के भीतर ऐसा प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर देगा तथा इसके लिए कारण सहित, निर्यात कर्ता को ऐसे इंकार के बारे में संसूचित करेगा।”

[फा. सं. 6(26)/72 नि. नि. तथा नि. सं.]

S.O. 272.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Rubber Gloves (Inspection) Rules, 1966.

1. These rules may be called the Export of Rubber Gloves (Inspection) Amendment Rules, 1973.

2. In rule 4 of the Export of Rubber Gloves (Inspection) Rules, 1966—

(a) for sub-rule (4) the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“On receipt of the intimation and declaration under sub-rule (3), the Agency shall inspect the consignment of rubber gloves as per the instructions issued by the Export Inspection Council from time to time with a view to seeing that the same conforms to the specifications recognised under section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 or, as the case may be, any other specifications stipulated in the export contract or the approved sample.”

(b) The following proviso shall be added at the end of sub-rule (5) :

“Provided that where the agency is not so satisfied, it shall within the said period of 7 days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with reason therefor.”

[No. 6(26)/72-EI&EP]

का. आ. 273.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, रबड़ होज निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1967 में और संशोधन करने के लिए निम्नीलिखित नियम एतद्वारा बनाती हैं।

1. इन नियमों का नाम रबड़ होज निर्यात (निरीक्षण), संशोधन नियम, 1973 है।

2. रबड़ होज निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1967 के नियम 4 में :—

(क) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नीलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“उपनियम (3) के अधीन सूचना तथा घोषणा की प्राप्ति पर, अभिकरण रबड़ होज के परीक्षण का निरीक्षण, निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार यह देखने के लिए करेगा कि वे यथास्थिति, उपर्युक्त मानक विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं।

(ख) उपनियम (5) के अंत में निम्नीलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा :—

“परन्तु, जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं हो गया है, वहां वह 7 दिन की उक्त अवधि के भीतर ऐसा प्रमाणपत्र देने से इंकार कर देगा तथा इसके लिए कारण सहित निर्यात कर्ता को ऐसे इंकार के बारे में संसूचित करेगा।”

[फा. सं. 6(26)/72 नि. नि. तथा नि. सं.]

S.O. 273.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Rubber Hoses (Inspection) Rules, 1967.

1. These rules may be called the Export of Rubber Hoses (Inspection) Amendment Rules, 1973.

(a) for sub-rule (4) the following sub-rule shall be substituted namely :—

“On receipt of the intimation and declaration under sub-rule (3), the inspection agency shall inspect the consignment of rubber hoses as per the instructions issued by the Export Inspection Council from time to time with a view to seeing that the same conforms to the aforesaid standard specifications or the approved sample, as the case may be.”

(b) The following proviso shall be added at the end of sub-rule (5) :

“Provided that where the agency is not so satisfied, it shall within the said period of 7 days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with reason therefor.”

[No. 6(26)/72-EI&EP]

का. आ. 274.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय को सं. का. आ. 1609 ता. 3 मई, 1968 में भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित मानव केश के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1968 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नीलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम मानव केश के निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मानव केश के निर्यात (निरीक्षण), नियम, 1968 के नियम 5 में निम्नीलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु, जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं हुआ है, वहां वह उक्त चार दिनों की अवधि के अन्दर ऐसा प्रमाणपत्र देने से इंकार कर देगा तथा निर्यातकर्ता को इसके लिए कारणों सहित अस्वीकृति की सूचना देगा।”

[सं. 60(27)/67-नि. नि. तथा नि. सं.]

म. क. ब. भटनागर, उप-निर्देशक
(निर्यात संवर्धन)

S.O. 274.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rule to amend the Export of Human Hair (Inspection) Rules, 1968, published with the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 1609, dated the 3rd May, 1968. namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Human Hair (Inspection) Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 5 of the Export of Human Hair (Inspection) rules, 1968 the following provision shall be added, namely :

“Provided that where the agency is not so satisfied it shall within the said period of four days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter alongwith the reason therefor.”

[No. 60(27)/67-EI&EP]

(Export Promotion) M. K. B. BHATNAGAR, Dy. Director.

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1972

आदेश

का. आ. 275.—सर्वश्री टाटा इन्जी. एंड लोकोमोटिव कं. लि., बम्बई, 24 वूस स्ट्रीटफोर्ट बम्बई-1 को लाइसेंस के साथ संलग्न सूची के अनुसार संघटकों के आयात के लिए 15,16,900 रु. का एक आयात लाइसेंस सं. पी/डी/2189458/सी/एक्स एड्स/43/एच/33-34 दिनांक 1-8-72 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस को अनुलिपि सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति उनके द्वारा खां गई है/अस्थानस्थ हो गई है। लाइसेंसधारी द्वारा आगे यह बताया गया है कि लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क कार्यसंबंधी प्रति

किसी भी सीमाशुल्क कार्यालय में पंजीकृत कराए बिना और कुछ भी उपयोग किए बिना ही खो गई है/अस्थानस्थ हो गई है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेंस सं. पी डी/2189458/सी/एक्स एक्स/43/एच/33-34 दिनांक 1-6-72 की मूल सीमाशुल्क कार्य-संबंधी प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता है कि उन्हें उपयुक्त लाइसेंस की अनुमिलीप सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति जारी की जानी चाहिए। मूल सीमा शुल्क कार्यसंबंधी प्रति रद्द की जाती है। आयात लाइसेंस की अनुमिलीप सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या: ट्रैक्टर 7(4)/71-72/आर. एम-6]

जे. शंकर, उप मुख्य नियंत्रक

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

New Delhi, the 30th November, 1972

ORDER

S.O. 275.—M/s. Tata Engineering & Locomotive Co. Ltd., Bombay House, 24 Bruce Street, Fort, Bombay-I were granted import licence No. P/D/2189458/C/XX/43/H/33-34 dated 1-6-1972 for Rs. 15,16,900/- for the import of components as per list attached thereto. They have requested for issue of duplicate Customs Purposes Copy of the licence on the ground that the original Customs Purposes Copy has been lost/misplaced by them. It has further been reported by the licensee that the Customs Purposes Copy has been misplaced without having been registered with any customs and that the same has not been utilised at all.

In support of their contention the applicant have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original Customs Purposes Copy of Licence No. P/D/2189458/C/XX/43/H/33-34 dated 1-6-1972 has been lost/misplaced and directs that a duplicate Customs Purposes Copy of the said licence should be issued to them. The original Customs Purposes Copy is cancelled. A duplicate Customs Purposes Copy of the import licence is being issued separately.

[No. Tractor. 7(4)/71-72/R.M. 6]

J. SHANKAR, Dy. Chief Controller.

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1973

आदेश

का. आ. 276.—सर्वश्री खनिज तथा धातु व्यापार निगम, भारत लि. नई दिल्ली को सीमित समाजवादी गणतंत्र संघ से अपरीफ़्त निकल के आयात के लिए 9,00,000 रु. का एक आयात लाइसेंस सं. जी/टी/2395737 दिनांक 7-8-1972 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उपयुक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क कार्यसंबंधी प्रति उनके द्वारा खो गई है। लाइसेंसधारी द्वारा आगे यह प्रतिवेदन किया गया है कि मूल लाइसेंस भारत के किसी भी पत्तन पर पंजीकृत नहीं करवाया गया था।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेंस सं. जी/टी/2395737 दिनांक 7-8-72 की मूल सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति खो गई है और निदेश देता है कि आवेदक को उपयुक्त लाइसेंस की अनुमिलीप सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति जारी की जानी चाहिए। लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति रद्द द्वारा रद्द की जाती है।

लाइसेंस सं. जी/टी/2395737 की अनुमिलीप सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या: एम. एम. टी. सी./77-79/72-73/आर. एम. सेल/201]

New Delhi, the 15th January, 1973

S.O. 276.—The Minerals and Metals Trading Corporations of India Ltd., New Delhi were granted licence No. G/T/2395737 dated 7-8-1972 for the import of Virgin Nickel from U.S.S.R. to the value of Rs. 9,00,000/-. They have requested for the issue of duplicate Custom copy of the above licence on the ground that the original Custom/copy of the above licence has been lost by them. It has been further reported by the licensee that the licence has not been registered with any port in India.

In support of their contention, the applicant have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original Custom copy of the licence No. G/T/2395737 dated 7-8-1972 has been lost and direct that duplicate Custom copy of the said licence should be issued to them. The original Custom copy of the licence is hereby cancelled.

The duplicate Custom copy of the licence No. G/T/2395737 is being issued separately.

[No. MMTC/77—79/72-73/R.M. Cell/201]

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1973

आदेश

का. आ. 277.—सर्वश्री डेली गावकारी, 797, आगरा रोड, राविवर पठ नासिक का 5000 रु. (पांच हजार रु. मात्र) मूल्य के लिए एक आयात लाइसेंस सं. पी/ए/1359140/सी/एक्स एक्स/42/एच/33-34 दिनांक 29-3-72 प्रदान किया गया था। उक्त लाइसेंस की मूला विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुमिलीप जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मूला विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। यह भी उल्लेख किया गया है कि मूल मूला विनिमय नियंत्रण प्रति का उपयोग नहीं किया था और इस पर 5000 रु. (पांच हजार रु. मात्र) का उपयोग करना बाकी था।

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने तालुका मजिस्ट्रेट नासिक से एक प्रमाण पत्र के साथ एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूँ कि उक्त लाइसेंस की मूल मूला विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है। इसलिए यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उप धारा 9 (सी सी) के अंतर्गत प्रकृत अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री डेली गावकारी, 797, आगरा रोड, नासिक को जारी किए गए लाइसेंस सं. पी/ए/1359140/सी/एक्स एक्स/42/एच/33-34 दिनांक 29-2-1972 की मूल मूला विनिमय नियंत्रण प्रति एस् द्वारा रद्द की जाती है।

3. उक्त लाइसेंस की मूला विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुमिलीप लाइसेंसधारी की अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या: 303-4/जी.1/71-72/एन.पी.सी.आई.ए.]

सरदूल सिंह, उप मुख्य नियंत्रक,

New Delhi, the 18th January, 1973

ORDER

S.O. 277.—M/s. Daily Gavakari, 797, Agra Road, Ravivar Peth, Nasik were granted an import licence No. P/A/1359140/C/XX/42/H/33-34 dated 29-3-1972 for Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only). They have applied for the issue of a duplicate Exchange Control Purposes copy of the said licence on the ground that the original Exchange Control Purposes copy has been lost/misplaced. It is further stated that the original Exchange Control copy was unutilised. It was utilised for NIL and the balance available on it was Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only).

2. In support of this contention the applicant has filed an affidavit along with a certificate from Taluka Magistrate Nasik. I am accordingly satisfied that the original Exchange Control Purposes copy of the said licence has been lost. Therefore in exercise of the powers conferred under Sub-Clause 9(cc) of the Imports (Control) Order,

1955 dated 7-12-1955 as amended the said original/Exchange Control Purposes copy of licence No. P/A/1359140/C/XX/42/H/33-34 dated 29-3-1972 issued to M/s. Daily Gavakari, 797, Agra Road, Nasik is hereby cancelled.

3. A duplicate Exchange Control Purposes copy of the said licence is being issued separately to the licensee.

[No. 303-IV/G-1/71-72/NPCIA]
SARDUL SINGH, Dy. Chief Controller.

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1973

आवृत्ति

का. आ. 278.—सर्वश्री हिन्द साइकिल लि., 250, वर्ली, बम्बई-18 को साइकिलों तथा पुर्जों के निर्यात के लिए मशीन के आयात के लिए 7.21,925 रु. का एक आयात लाइसेंस सं. पी/सी/जी/2049705/टी/टी आर/26/सी/11/23 दिनांक 31-1-68 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति उनके द्वारा खो गई है। आगे यह बताया गया है कि मूल प्रति का 7,11,662 रु. मात्र का उपयोग कर लिया गया है।

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने नोटरी पब्लिक, महाराष्ट्र राज्य के सम्मुख विधिवत शपथ लेते हुए एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार, मैं संतुष्ट हूँ कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति खो गई है। इसलिए, यथा संशोधित, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उपधारा 9 (सी सी) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर लाइसेंस सं. पी/सी. जी./2049705/टी/टीआर/26/सी/एच/23 दिनांक 31-1-68 की उपर्युक्त मूल सीमाशुल्क कार्य संबंधी प्रति जो सर्वश्री हिन्द साइकिल, लि., बम्बई को जारी की गई थी, एतद् द्वारा रद्द की जाती है।

3. उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रति (सीमाशुल्क कार्य संबंधी प्रति) अलग से जारी की जा रही है।

[सं. 7(54)/66-67/सी. जी.-1]

New Delhi, the 8th January, 1973

ORDER

S.O. 278.—M/s. Hind Cycles Ltd., 250, Worli, Bombay-18 were granted import licence No. P/CG/2049705/TTR/26/C/H/23 dated 31-1-1968 for Rs. 7,21,925/- for import of machinery for the manufacture of Bicycles and parts thereof. They have applied for the issue of duplicate Customs Purposes copy of the licence on the ground that the import licence (Customs Purposes copy) has been lost/misplaced by them. It is stated that the original copy was utilised for Rs. 7,11,662/- only.

2. In support of this contention, the applicant has filed an affidavit duly sworn in before Notary Public, Maharashtra State, Bombay. I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes copy of the licence has been lost. Therefore, in exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) Order, 1955, dated 7-12-1955 as amended, the said original Customs Purposes copy of licence No. P/CG/2049705/T/TR/26/C/H/23 dated 31-1-1968 issued to M/s. Hind Cycles Ltd., Bombay is hereby cancelled.

3. duplicate of the said licence (Customs Purposes copy) is being issued separately.

[No. 7(54)/66-67/CG.I]

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1973

आवृत्ति

का. आ. 279.—सर्वश्री दि टाटा आयरन एंड स्टील कं. लि., जमशेदपुर को 940 रु. (नौ सौ चालीस रु. मात्र) का एक सीमाशुल्क निकासी परीमिट सं. पी/जे/2357291 दिनांक 14-12-1970 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उपर्युक्त सीमाशुल्क निकासी परीमिट की

अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रति खो गई है। आगे यह बताया गया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी परीमिट सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पास पंजीकृत नहीं करवाया गया था और उसका बिलकुल उपयोग नहीं किया गया था।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने नोटरी पब्लिक दिल्ली के सम्मुख विधिवत शपथ लेते हुए एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूँ कि मूल सीमाशुल्क निकासी परीमिट खो गया है। इसलिए तथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 17-12-1955 की उप धारा 9 (सी सी) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर उपर्युक्त सीमाशुल्क निकासी परीमिट सं. पी/जे/2357291 दिनांक 14-12-1970 जो सर्वश्री टाटा आयरन एंड स्टील कं. लि., जमशेदपुर को जारी किया गया था एतद् द्वारा रद्द किया जाता है।

3. लाइसेंसधारी को अब उपर्युक्त सीमाशुल्क निकासी परीमिट की अनुलिपि प्रति जिसका मूल्य बढ़ा कर 4550 रु. कर दिया गया है, अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या 36(167)/69/70/सी.जी.-4/3146]

एच. डी. गुप्ता, उप मुख्य नियंत्रक

New Delhi, the 23rd January, 1973

ORDER

S.O. 279.—M/s. The Tata Iron and Steel Co. Ltd., Jamshedpur were granted Customs Clearance Permit No. P/J/2357291 dated 14-12-1970 for Rs. 940/- (Rupees Nine hundred and Forty only). They have applied for the issue of a duplicate copy of the said C.C.P. on the ground that the original has been misplaced. It is further stated that original C.C.P. was not registered with the Customs Authorities and was not utilised at all.

2. In support of this contention, the applicant has filed an affidavit duly sworn before Notary Public, Delhi. I am accordingly satisfied that the original Customs Clearance Permit has been lost. Therefore, in exercise of the powers conferred under Sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended, the said Customs Clearance Permit No. P/J/2357291 dated 14-12-1970 issued to M/s. Tata Iron and Steel Co. Ltd., Jamshedpur is hereby cancelled.

3. A duplicate copy of the said Customs Clearance Permit with the enhanced value of Rs. 4,550/- is being issued separately to the licensee.

[No. 36(167)/69-70/CG.IV/3146]

H. D. GUPTA, Dy. Chief Controller.

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

बम्बई, 30 जून, 1972

आवृत्ति

का. आ. 280.—सर्वश्री फार्मर इन्सॉल्वेंटसाइड्स, एण्ड पीस्टसाइड्स, पटेल निवास, जोरा कम्पाउन्ड, इंदौर को अप्रैल, 1970 की रैंड बुक के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किस्म की मर्चों (1) डायलड्राइन (2) क्लोरोड्रेन तथा (3) एन. डी. आयल्स के आयात के लिए 9524 रु. तथा 4725 रु. के क्रमशः आयात लाइसेंस सं. पी/एस/1642003 दिनांक 3-9-1969 तथा पी/एस/1643197 दिनांक 25-10-1969 स्वीकृत किए गए थे :—

कि इस लाइसेंस के अंतर्गत आयातित माल का उपयोग उनके स्वयं के कारखाने में किया जाएगा और इसका कोई भी भाग किसी भी अन्य पार्टी को बेचा नहीं जाएगा अथवा उपयोग नहीं किया जाएगा अथवा किसी भी अन्य विधि से उपयोग करने के लिए स्वीकृत नहीं दी जाएगी। उपर्युक्त लाइसेंस निर्वशक उपयोग, इंदौर द्वारा जारी किए गए आवश्यकता

प्रमाण पत्र सं. 164/इन्ड/ए एम.-69/95 दिनांक 5-4-1969 के आधार पर भी जारी किए गए थे।

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना सं. 1/140/70/ए-यू/इन्फ/5061 दिनांक 6-11-1970 यह पृष्ठों हुए जारी की गई थी कि 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों की क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उसे इस आधार पर कि उन्होंने गलत जानकारी देकर आवश्यकता प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।

3. उपर्युक्त कारण बताओ सूचना के प्रत्युत्तर में सर्वश्री फार्मर इन्सेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स ने अपने पत्र दिनांक 19-11-1970 में एक विवरण दिया था और अधोस्ताक्षरी से व्यक्तिगत मुलाकात के लिए भी कहा था। इसके लिए उनके एक प्रतिनिधि को 11-1-71 को मिलने की इजाजत दी गई थी, किन्तु वे व्यक्तिगत मुलाकात के लिए नहीं पहुँचा।

4. लेकिन उन्होंने यह बताया कि उन्होंने अपने फेज प्रोग्राम में यह दिया था कि वे 56000 रु. मूल्य की मशीन का स्थापित कर रहे किन्तु यह सत्य नहीं है कि उन्होंने लाइसेंस प्राधिकारी से कंटा प्राप्त करने के लिए इसी मूल्य का उल्लेख किया था।

5. अधोस्ताक्षरी ने उपर्युक्त प्रतिक्रिया की भली भाँति जाँच कर ली है और इस परिणाम पर पहुँचा है कि उन्होंने मशीन के लिए पक्के आवेश के देने से संबंधित आवश्यकता प्रमाण पत्र को मिथ्या जानकारी दे कर प्राप्त किया था।

6. ऊपर की कीडका में जो बताया गया है उसे ध्यान में रखते हुए अधोस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस को रद्द अथवा अन्यथा रूप से अमर्यादित किया जाना चाहिए। इसलिए, अधोस्ताक्षरी आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9 (सी सी) उप धारा (ए) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आयात लाइसेंस सं. पी/एस/1642003 दिनांक 3-9-1969 मूल्य 9524 रु. तथा आयात लाइसेंस सं. पी/एस/1643197 दिनांक 25-10-69, मूल्य 4725 रु. जो सर्वश्री फार्मर इन्सेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, पटेल निवास, जांरा कम्पाउंड, इंदौर के नाम जारी किए गए थे तत्पश्चात् रद्द करता है।

[संख्या 1/140/70/ए.यू./ई.एन.एफ.]

(Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports)

Bombay, the 30th June, 1972

ORDER

S.O. 280.—Licences No. P/S/1642003 dated 3-9-1969 and P/S/1643197 dated 25-10-1969 for Rs. 9,524/- and Rs. 4,725/- respectively for import of (1) Dieldrine (2) Chlordane and (3) N. E. Oils of permissible types as per AM-1970 Red Book were issued to M/s. Farmer Insecticides and Pesticides, Patel Nivas, Jaora Compound, Indore subject to the conditions as under:—

"that the goods imported thereunder shall be utilised in their factory and no portion thereof shall be sold to any other party and or utilised or be permitted to be used in any other manner. The said licences were also issued on the basis of the Essentiality Certificate No. 164/IND/AM-69/95 dated 5-4-1969 issued by the Director of Industries, Indore".

2. Therefore, a show cause notice No. 1/140/70/AU/Enf./5061 dated 6-11-1970 was issued asking them to show cause within 15 days as to why the said licence in their favour should not be cancelled on the ground that they have obtained an Essentiality Certificate by giving misleading information in terms of Clause 9, sub-clause (a).

3. In response to the aforesaid show cause notice, M/s. Farmer Insecticides and Pesticides had by their letter dated 19-11-1970 furnished an explanation and had also asked for personal hearing with the undersigned which was allowed to their representative on 11-1-1971, but they failed to appear for personal hearing.

4. However they had stated that they had given in their phase programme that they would establish the machinery worth Rs. 56,000/- but they stated that it was not a fact that they mentioned the same amount to obtain quota from the licensing authority.

5. The undersigned has carefully examined the said representation and has come to the conclusion that they had obtained an Essentiality Certificate by giving misleading information about placement of firm orders for machinery.

6. Having regard to what has been stated in the preceding paragraph, the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned, in exercise of the powers vested in him under Clause 9 sub-clause (a) of the Imports (Control) Order, 1955 hereby cancel the licences Nos. P/S/1642003 dated 3-9-1969 for Rs. 9,524/- and P/S/1643197 dated 25-10-1969 for Rs. 4,725/- issued in favour of M/s. Farmer Insecticides and Pesticides, Patel Nivas, Jaora Compound, Indore.

[No. 1/140/70/AU/Enf.]

बम्बई, 20 सितम्बर, 1972

आवेश

का. आ. 281.—सर्वश्री रेखा आयरन इंडस्ट्रीज, अपोजिट अशोक होटल, तिलक रोड, औरंगाबाद को 1.6 मि. मी. और इससे पतली प्राइम क्वालिटी एम. एस. सी. आर. सी. ए/बी. पी. शीट्स के आयात के लिए लाइसेंस संख्याएं पी/एस/8021350/सी/एसएस एक्स/34/27-28 और पी/एस/8021351/टी/आ/बी/34/बी/27-28 इनका दिनांक 24-2-1970 है जो क्रमशः 3334 रु. और 6668 रु. मूल्य के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किए गए थे:—

(1) इस लाइसेंस के अधीन आयात किए गए माल की सभी मद्धों का उपयोग लाइसेंसधारी के उस कारखाने में होगा जिस का पता संस्तुति प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए उस अनिवार्यता प्रमाणपत्र में दिये गया है जिसके आधार पर यह लाइसेंस जारी किया गया है और जिस एकक/कार्य के लिए विषयाधीन लाइसेंस जारी किया गया है उससे भिन्न किसी भी कार्य के लिए माल के किसी भाग का उपयोग लाइसेंसधारी द्वारा नहीं किया जाएगा या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा अन्यथा प्राधिकृत किए बिना किसी दूसरी पार्टी को न बेचा जाएगा, न उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी (गैर अनुसूचित उद्योगों के लिए लागू)।

2. इस लाइसेंस के अधीन आयात किए गए माल की सभी मद्धों का उपयोग केवल लाइसेंसधारी के कारखाने में किया जाएगा। अन्य निर्माण करने वाले एकक के कारखाने में आयातित माल संसाधित किया जा सकता है परन्तु उसका कोई भाग अन्य पार्टी को नहीं बेचा जाएगा। लेकिन, दूसरे कारखाने में इस प्रकार संसाधित किया गया माल जिस अनुसूचित एकक को यह लाइसेंस जारी किया गया है उसके द्वारा नियंत्रित निर्माण प्रक्रिया में तब तक उपयोग किया जाएगा जब तक अन्यथा उपयोग करने के लिए लाइसेंस प्राधिकारी प्राधिकृत न कर दें (अनुसूचित उद्योगों के लिए लागू)।

2. तत्पश्चात् उनको यह पृष्ठों हुए 15 दिनों के भीतर कारण बताने के लिए एक कारण बताओ नोटिस सं. 1/178/71/ई पी/एन्फ/246 दिनांक 4-10-1971 जारी किया गया था कि उनको जारी किए गए लाइसेंसों का धारा 9 उपधारा (सी सी) की शर्तों के अनुसार इस

आधार पर रक्ष कर्षों न कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उनके एकक की कार्य न करने की सूचना मिली है और इस कारण उपर्युक्त लाइसेंस उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेंगे जिसके लिए वे जारी किए गए हैं।

3. पूर्वोक्त कारण बताओ नोटिस का सर्वश्री रेखा आयरन इंडस्ट्रीज, औरंगाबाद से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले पर ध्यानपूर्वक विचार कर लिया है और इस निर्णय पर पहुंचा है कि उपर्युक्त लाइसेंस उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेंगे जिसके लिए वे जारी किए गए हैं।

5. पिछले पैरा में जो कुछ कहा गया है उसका ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए या अन्यथा अप्रभावी कर देने चाहिए। इसलिए आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9 उपधारा (सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी सर्वश्री रेखा आयरन इंडस्ट्रीज औरंगाबाद को जारी किए गए लाइसेंस सं. पी/एस/8021350/सी/एसएस/34/27-28 और पी/एस/8021351 दोनों का दिनांक 24-2-1970 जिनका मूल्य क्रमशः 3334 रु. और 6666 रु. है को एतद्वारा रद्द करता है।

[सं. 1/178/71/एफ/1917]

बी. सी. बनर्जी, उप मुख्य नियंत्रक

Bombay, the 20th September, 1972

ORDER

S.O. 281.—Licence Nos. P/S/8021350/C/XX/34/27-28 and P/S/8021351/T/OR/34/B/27-28 both dated 24th February, 1970 of the value of Rs. 3,334/- and Rs. 6,666/- respectively for import or Prime Quality M.S.C.R.C.A./B.P. Sheets of 1.6 m.m. and thinner were issued to M/s. Rekha Iron Industries, Opp. Ashoka Hotel, Tilak Road, Aurangabad subject to the conditions as under:—

- (1) All items of goods imported under this licence shall be used only in the licence holder's factory at the address shown in the Essentiality Certificate issued by the recommending authority against which this licence has been issued and no portion thereof will be utilised by the licensee for a unit/purpose other than the one for which the licence in question has been issued or will be sold or be permitted to be utilised by another party unless otherwise authorised by the licensing authority (applicable to non-scheduled Industries).
- (2) All items of goods imported under this licence shall be used only in the licence holders factory. The imported material may be processed in the factory of another manufacturing unit but no portion thereof will be sold to any other party. The goods so processed in another factory will, however be utilised in the manufacturing process undertaken by the scheduled unit to whom this licence has been issued unless otherwise authorised by the Licensing Authority (applicable to scheduled Industries).

2. Thereafter a show cause notice No. 1/178/71/EP/Enf/246 dated 4th October, 1971 was issued asking them to show cause within 15 days as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that as their unit is reported to be not functioning, the above licences will not serve the purpose for which those have been issued in terms of Clause 9, sub-clause (cc).

3. In response to the aforesaid show cause notice, no reply has been received from M/s. Rekha Iron Industries, Aurangabad.

4. The undersigned has carefully considered the matter and has come to the conclusion that the above licence will not serve the purpose for which they have been issued.

5. Having regard to what has been stated in the preceding paragraph, the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned, in exercise of the powers vested in him under Clause 9 sub-clause (cc) of the Imports (Control) Order, 1955 hereby cancel the licences Nos. P/S/8021350/C/XX/34/27-28 and P/S/8021351 both dated 24th February, 1970 for Rs. 3334/- and Rs. 6,666/- respectively issued in favour of M/s. Rekha Iron Industries, Aurangabad.

[No. 1/178/71/EP/Enf./1917]

B. C. BANERJEE, Dy. Chief Controller.

बम्बई, 3 अक्टूबर, 1970

आदेश

का. आ. 282.—सर्वश्री माइक्रो इंजीनियरिंग वर्क्स, सी-23, इन्डस्ट्रियल इस्टेट राजकोट को वाल्व स्टीलबार तथा स्ट्रिप्स इत्यादि के आयात के लिए 42,262 रुपये तथा 84,552 रुपये के लिए लाइसेंस सं. पी/एस/1624552 तथा पी/एस/1624553 दोनों दिनांक 24-1-69, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किए गए थे।

“कि इस के अन्तर्गत आयातित माल का उन के स्वयं के कारखाने में प्रयोग किया जाएगा और उस का कोई भाग किसी अन्य पार्टी को नहीं बेचा जाएगा अथवा प्रयोग किया जाएगा अथवा अन्य किसी भी प्रकार से प्रयोग करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

2. तत्पश्चात् एक कारण बताओ नोटिस सं. 1/157/69/एफ/इन्फ/3240 दिनांक 9-7-70 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि धारा 9 उपधारा (ए) के अनुसार उन के नाम जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और वह इस आधार पर कि उन के द्वारा उक्त लाइसेंस नियमानुरूप से प्राप्त किए गए हैं।

3. उक्त कारण बताओ नोटिस जो सर्वश्री माइक्रो इंजीनियरिंग वर्क्स सी 23, इन्डस्ट्रियल इस्टेट, राजकोट को जारी की गई थी। उसके निर्धारित समय-सीमा के भीतर उत्तर नहीं आया है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित कारणों के लिए विषयाधीन लाइसेंस आयातित माल का दुरुपयोग करने के विचार से प्राप्त किए गए हैं।

5. पूर्वगत कीड़का में जो बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी इस से संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द किए जाने चाहिए अथवा अन्यथा रूप से अप्रभावी किए जाने चाहिए। इसलिए अधोहस्ताक्षरी, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 धारा 9 उपधारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सर्वश्री माइक्रो इंजीनियरिंग वर्क्स, सी-23 इन्डस्ट्रियल इस्टेट, राजकोट के नाम जारी किए गए लाइसेंस सं. पी/एस/1624552 तथा पी/एस/1624553 दोनों दिनांक 24-1-69 जो क्रमशः 42,262 रुपये तथा 84,552 रुपये मूल्य के थे, एतद्वारा उन्हें रद्द करता है।

[सं. 1/157/69/एफ/इन्फ/4610]

आर. डी. मंगत, उप-मुख्य नियंत्रक

Bombay, the 3rd October, 1970

ORDER

S.O. 282.—Licences No. P/S/1624552 and P/S/1624553 both dt. 24th January, 1969 of the value of Rs. 42,262/- and Rs. 84,552/- for import of Valve Steel Bars and Strips etc. were issued to M/s. Micro Engineering Works, C-23, Industrial Estate Rajkot subject to the conditions as under:—

“That the goods imported thereunder shall be utilized in their factory and no portion thereof shall be sold

to any other party or utilized or permitted to be used in any other manner.

2. Thereafter, a Show Cause Notice No. 1/157/69/AU Enf./3240 dated 9th July, 1970 was issued asking them to show cause within fifteen days as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that the said licences have been obtained by them by misrepresentation in terms of Clause 9, sub-clause (a).

3. No reply to the aforesaid Show Cause Notice issued to M/s. Micro Engineering Works C. 23, Industrial Estate, Rajkot has come within the specified time limit.

4. The undersigned has carefully examined the case and has come to the conclusion that the licences in question have been obtained with a view to misuse of the imported material, for reasons stated in the Show Cause Notice.

5. Having regard to what has been stated in the preceding paragraph, the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned, in exercise of the powers vested in her Under Clause 9 sub-clause (a) of the Imports (Control) Order, 1955 hereby cancel the licences No. P/S/1624552 and P/S/1624553 both dated 24th January, 1969 for Rs. 42262/- and Rs. 84,552/- respectively issued in favour of M/s. Micro Engineering Works, C-23, Industrial Estate, Rajkot.

[No. 1/157/69/AU/Enf./4610]

R. D. MANGAT, Dy. Chief Controller.

बम्बई, अक्टूबर, 1972

आवेश

विषय : सर्वश्री प्रेसर कुर्कस एंड एलायन्स प्रा. लि., धाना के नाम में जारी किए गए लाइसेंस संख्या 8562589, दिनांक 20-1-1972, 8562590 दिनांक 20-1-1972 तथा 8562591, दिनांक 20-1-1972 की मूला विनिमय नियंत्रण तथा सीमाशुल्क निकासी कार्यसम्बन्धी प्रतियां को रद्द करना।

का. आ. 283.—सर्वश्री प्रेसर कुर्कस एंड एलायन्स प्रा. लि., सी-21/22, वाग्ले इन्डस्ट्रियल इस्टेट, धाना, महाराष्ट्र को अप्रैल, 70—मार्च, 71 अवधि के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :—

आयात लाइसेंस संख्या तथा दिनांक	विवरण	मूल्य
(1) पी/ए/8563589/सी/एस 200 एस एस की बोर्डर्स से 9,472 रु. एस/42/बी/31-32 दिनांक 20-1-72 अधिक वाले हाईकार्बन स्टील		
(2) पी/ए/8562590/टी/मोमार/42 31-32 दिनांक 20-1-72	वहीं	9,471 रु.
(3) पी/ए/8562591-मार एम एल/42/ 31-32 दिनांक 20-1-72	वहीं	18,942 रु.

उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंसों के पूरे मूल्य यानी 9,472 रु., 9,471 रु. तथा 18,942 रु. के लिए अनुलिपि मूला विनिमय नियंत्रण तथा सीमाशुल्क निकासी कार्य सम्बन्धी प्रतियां के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूला विनिमय नियंत्रण तथा सीमाशुल्क कार्य सम्बन्धी प्रतियां खो गई हैं। आगे यह बताया गया है कि मूल लाइसेंस न तो किसी सीमाशुल्क कार्यालय में पंजीकृत करवाए गए थे और न ही पूरे मूल्य तक यानी 9,472 रु., 9,471 रु. तथा 18,942 रु. का उपयोग ही किया गया था।

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने नोटरी द्वारा विधिवत साक्ष्यकित स्टाम्प कागज पर एक शपथपत्र दाखिल किया है।

3. मैं संतुष्ट हूँ कि आयात लाइसेंस संख्या 8562589, दिनांक 20-1-1972, 8562590, दिनांक 20-1-1972 तथा 8562591, दिनांक 20-1-1972 की मूला विनिमय नियंत्रण तथा सीमाशुल्क निकासी कार्य सम्बन्धी प्रतियां खो गई हैं और निदेश देता हूँ कि

आवेदक को पूरे अप्रयुक्त मूल्य यानी 9,472 रु., 9,471 रु. तथा 18,942 रु. के लिए अनुलिपि मूला विनिमय नियंत्रण तथा सीमाशुल्क निकासी कार्य सम्बन्धी प्रतियां जारी की जानी चाहिए। पूरे अप्रयुक्त मूल्य यानी 9,472 रु., 9,471 रु. तथा 18,942 रु. के लिए लाइसेंस की मूल मूला विनिमय नियंत्रण तथा सीमाशुल्क निकासी कार्य सम्बन्धी प्रतियां रद्द की जाती हैं।

[सं. 21/5451/बी. एल./25/पी. एन. 140/पी. 39/31/32/2]

Bombay, October, 1972.

(Iron and Steel Division)

ORDER

Subject:—Cancellation of Exchange Control copies and Customs Clearance Purposes copies of Import licences No. 8562589 dt. 20-1-72, 8562590 dt. 20-1-72 & 8562591 dt. 20-1-72 issued to M/s. Pressure Cookers & Appliances Private Limited, Thana.

..S.O. 283.—M/s. Pressure Cookers & Appliances Private Limited, C-21/22, Wagle Industrial Estate, Thana, Maharashtra were issued Import Licences for April, 70/March, 71 period under P.N. 140 as under :—

I/L No. & Date.	Description	Value
(1) P/A/8562589/C/XX/42/B/31-32 dt. 20.1.72.	High Carbon steel Strips above 200 mm in width.	Rs. 9,472/-
(2) P/A/8562590/T/OR/42/B/31-32 dt. 20.1.72	-do-	Rs. 9,471/-
(3) P/A/8562591/R/ML/42/B/31-32 dt. 20.1.72.	-do-	Rs. 18,942/-

They have now applied for duplicate copies of Exchange Control copies and Customs Clearance Purposes copies of the above mentioned Import licences for the full values of Rs. 9,472, 9,471 & 18,942 respectively on the ground that the Exchange Control copies and Customs Clearance copies have been lost. It is further stated that the original licences were neither registered with any Customs House nor utilised by them to the extent of full value of Rs. 9,472, 9,471 & 18,942 respectively.

2. In support of this contention the applicant has filed an affidavit on a stamped paper duly attested by a notary.

3. I am satisfied that the Exchange Control copies and Customs Clearance Purposes copies of the Import licences Nos. 8562589 dt. 20-1-72, 8562590 dt. 20-1-72 & 8562591 dt. 20-1-72, have been lost and direct that duplicate copies of Exchange Control copies and Customs Clearance Purposes copies of Import licences for the full unutilised values of Rs. 9,472, 9,471 & 18,942 should be issued to the Applicant. The Exchange Control copies and Customs Clearance Purposes copies of above Import licences are cancelled for the full unutilised amount of Rs. 9,472, 9,471 & 18,942.

[No. 21/5451/BL/25/P. N. 140/P-39/31/32/II]

आवेश

का. आ. 284.—विषय: सर्वश्री मिलन टिम वर्क्स, बम्बई-59 के नाम जारी किए गए लाइसेंस संख्या. 8231644, दिनांक 30-3-72 की मूला विनिमय नियंत्रण प्रती को रद्द करना।

सर्वश्री मिलन टिम वर्क्स, बिल्डिंग नं. 2, शेड नं. 3, स्टीलमेड इन्डस्ट्रियल इस्टेट, मार्गेल आन्धीईस्ट, बम्बई-59 को अप्रैल, 71-

मार्च, 71 अवधि के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किया गया था :—

(सा. एल. ए.)

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 1972

आयात लाइसेंस संख्या तथा दिनांक	विवरण	मूल्य
(1) पी/एस/8231644/ आर/एमएल/42/बी/33-34 दिनांक 30-3-72.	टिनप्लेट वेस्ट/वेस्ट	रु. 12,549/-

आवेश

उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस के पूरे मूल्य यानि 12,549 रु. के लिए मूद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के अनुलिपि लाइसेंस के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मूद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है। आगे यह बताया गया है कि मूल लाइसेंस न तो किसी सीमाशुल्क कार्यालय में पंजीकृत करवाया गया था और न ही पूरे मूल्य यानी 12,549 रुपये का उपयोग ही किया गया था।

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने नोटरी द्वारा विधिवत् साक्ष्यीकृत स्टाम्प कागज पर एक शपथपत्र दाखिल किया है।

3. मैं संतुष्ट हूँ कि आयात लाइसेंस संख्या. 8231644, दिनांक 30-3-72 की मूल मूद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है और निवेश देता हूँ कि आवेदक को पूरे अप्रयुक्त मूल्य यानी 12,549 रुपये के लिए आयात लाइसेंस मूद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति जारी की जानी चाहिए। पूरे अप्रयुक्त मूल्य यानि 12,549 रुपये के लिए उपर्युक्त आयात लाइसेंस की मूद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति रद्द की जाती है।

[सं. 109/8683/एस.एस.आई./एन.एन.पी./ए.एम-72]

एन. बनर्जी, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

Subject:—Cancellation of Exchange Control copy of Import licence No. 8231644 dt. 30-3-72, issued to M/s. Milan Tin Works, Bombay-59.

S.O. 284.—M/s. Milan Tin Works, Bldg., No. 2, Shed No. 3, Steelmade Indl. Estate, Marol, Andhri-East, Bombay-59 were issued import licence for Apl./March, 72 period as under :—

I/L No. & date.	Description	Value
(1) P/S8231644/R/ML/42/ B/33-34 dt. 30-3-72.	Tinplate W/W.	Rs. 12,549/-

They have now applied for a duplicate licence of Exchange Control purposes copy of the above mentioned import licence for the full value of Rs. 12,549 on the ground that the original Exchange Control copy has been lost. It is further stated that the original licence was neither registered with any Customs House nor utilised by them to the extent of full value of Rs. 12,549.

2. In support of this contention the applicant has filed an affidavit on a stamped paper duly attested by a Magistrate.

3. I am satisfied that the Exchange Control copy of the Import licence No. 8231644 dt. 30-3-72 has been lost and direct that duplicate copy of Exchange Control copy of Import Licence for the full unutilised value of Rs. 12,549 should be issued to the applicant. The Exchange Control copy of above Import licence is cancelled for the full unutilised amount of Rs. 12,549.

[No. 109/8683/SSI/NNP/AM-72]

N. BANERJI, Dy. Chief Controller.

का. आ. 285.—सर्वश्री डिलाइट इंडस्ट्रीज, गंचा बाजार, जोधपुर (राजस्थान) को 2,500 रु. तक की पर्सिस्टेंट किस्म की ए. पी. शीट्स और 1,000 रुपये तक की सी. ए. शीट्स मर्चें के लिए 3500 रु. मूल्य का एक आयात लाइसेंस सं. पी/एस/1687591 दिनांक 30-4-1971 प्रदान किया गया था। उन्होंने शेष बिना उपयोग की गई धनराशि 750 रु. के लिए सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति 2750 रु. की धनराशि का उपयोग करने के बाद और 750 रु. बिना उपयोग किए शेष रहते हुए खो गई/अस्थानस्थ है गई है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक फर्म ने इस संबंध में एक शपथ पत्र दाखिल किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि, हैंडबुक, 1972-73 के पैरा 318(2) के अनुसार खो गई/अस्थानस्थ है गई है। मैं संतुष्ट हूँ कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई/अस्थानस्थ है गई है।

आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 के खंड 9 (सी सी) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं सीमाशुल्क निकासी प्रति सं. पी/एस/1687591/सी दिनांक 30-4-1971 को रद्द करने का आदेश देता हूँ।

अब आवेदक को आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि, हैंडबुक, 1972-73 के पैरा 318(4) की शर्तों के अनुसार इस लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि जारी की जा रही है।

[सं. एन पी/डी-26 (एन)/ए एम 71/ए यू-राज एंड एडहोक सी एल ए/3017]

(Central Licensing Area)

New Delhi, the 24th October, 1972

ORDER

S.O. 285.—M/s. Delite Industries, Gancha Bazar, Jodhpur (Raj) were granted Import Licence No. P/S/1687591 dated 30-4-1971 for Rs. 3500/- for the item A.P. Sheets Pearlascant Variety upto Rs. 2500/- and C.A. Sheets upto Rs. 1000/-. They have applied for issue of duplicate copy of customs purposes copy for the balance unutilised amount of Rs. 750/- on the ground that the original custom purposes copy has been lost/misplaced after utilizing an amount of Rs. 2750/- and with unutilized balance of Rs. 750/-.

In support of their contention the firm have furnished an affidavit to the effect that original custom copy has been lost/misplaced in terms of para 318(2) of I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure, 1972-73. I am satisfied that the original custom copy has been lost/misplaced.

In exercise of the powers conferred on me under section 9(CC) Import (Control) order 1955 dated 7-12-1955, I order the cancellation of custom purposes copy No. P/S/1687591. C dated 30-4-1971.

The applicant is now being issued a duplicate copy of the custom purposes copy of this licence in accordance with the provisions of para 318(4) of the I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure, 1972-73.

[No. NP/D-26(N)/AM71/AU-Raj&Adhoc/CLA/3017]

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर 1972

आवृत्ति

का. आ. 286.—सर्वश्री देवकी इंडस्ट्रीज, फगवाड़ा गेट, जालन्धर सिटी को अप्रैल-मार्च 1972 की रोल बुक के बा. 1 के परिशिष्ट 14(6)(ए) तथा 14(6) (बी) में विशिष्टकृत के अतिरिक्त टेपेड रोलर बेयरिंग तथा (2) परिशिष्ट 14(5) में विशिष्टकृत के अतिरिक्त सिलिन्ड्रीकल रोलर के आयात के लिए 27, 734 रु., 13,367 रु. 25,433 रु. तथा 12,717 रु. के लिए क्रमशः आयात लाइसेंस सं. पी/एस/1713595, पी/एस/1713596, पी/एस/1713597 तथा पी/एस/1713598 सभी का दिनांक 30-3-1972 स्वीकृत किए गए थे। उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंसों की अनुलिपि प्रतियां के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रतियां खो गई हैं/अस्थानस्थ हो गई हैं।

2. अपने तर्कों के समर्थन में आवेदक ने आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि, हॉडबुक, 1972-73 की कंडिका 318(2) के अंतर्गत अपेक्षित स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूँ कि मूल लाइसेंस अस्थानस्थ हो गए हैं।

3. अद्यतन यथासंशोधित, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 (सी सी) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर मैं उपर्युक्त लाइसेंसों को रद्द करने का आदेश देता हूँ।

4. आवेदक को अब अनुलिपि प्रतियां जारी करने के मामलों पर आयात व्यापार नियंत्रण, नियम तथा क्रियाविधि, हॉडबुक, 1972-73 की कंडिका 318(1) के अनुसार विचार किया जाएगा।

[संख्या: पी/डी/7/ए एम-72/ए यू-पी बी/सी एल ए/]

डी. एस. मारक्रीमा, उप-मुख्य नियंत्रक

कृत संयुक्त मुख्य-नियंत्रक

New Delhi, 31st October, 1972

CANCELLATION ORDER

S.O. 286.—M/s. Devco Industries, Phagwara Gate, Jullundur City were granted import licences No. P/S/1713595, P/S/1713596, P/S/1713597 & P/S/1713598 all dt. 30-3-72 for import of Tapered Roller Bearings other than those in Appendix 14(6)(a) & 14(6)(b) and (2) Cylindrical Roller Bearings other than those specified in Appendix 14(5) of AM-72 Red Book Vol. I for Rs. 27,734, Rs. 13,367, Rs. 25,433 & Rs. 12,717 respectively. They have applied for issue of duplicate copies of these licences on the ground that original copies have been lost/misplaced without having been utilized.

2. The applicant has filed an affidavit on stamped paper in support of their contention as required under para 318(2) of ITC Hand Book of Rules & Procedure 1972-73. I am satisfied that the original licences have been misplaced.

3. In exercise of the powers conferred on me under clause 9(cc) Import (Control) order 1955 dated 7-12-55 as amended upto date, I order the cancellation of the above referred licences.

4. The applicant's case will now be considered for issue of duplicate licences in accordance with para 318(1) of ITC Hand Book of Rules & procedure 1972-73.

[No. P/D-7/AM-72/AU. PB./CLA]

D. S. MOKKRIMA, Dy. Chief Controller,
for Jt. Chief Controller.

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 1972

आवृत्ति

का. आ. 287.—सर्वश्री बीके रबड़ इंडस्ट्रीज, पी. ओ. रंथान एंड सिल्क मिल्स, अमृतसर को (1) प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स सहित प्राकृतिक रबड़ (2) कार्बन ब्लैक 3. रबड़ एक्सप्लेन्सर्स, एंटीआक्सीडेंट्स रिकार्डर्स, रिफ्रेनफ्रीसिंग सिलिकान फिल्लर्स, मंगनीशियम कार्बोनेट लाइट 4, रबड़ प्लास्टिफाइजर, पेंटिजर्स एंड वीटिंग

एजेंट्स के आयात के लिए 11092 रु. का एक आयात लाइसेंस सं. पी/यू/2687253/सी/दिनांक 6-7-1972 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि हॉडबुक, 1972-73 की कंडिका 318 के अंतर्गत अपेक्षित एक शपथ पत्र दाखिल किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि लाइसेंस सं. पी/यू/2687253/सी दिनांक 6-7-72 मूल्य 11092 रु. की दोनों प्रतियां बिल्कुल उपयोग किए बिना ही खो गई हैं/अस्थानस्थ हो गई हैं।

2. मैं संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस की दोनों मूल सीमाशुल्क कार्य संबंधी तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां खो गई हैं/अस्थानस्थ हो गई हैं।

3. अद्यतन यथा संशोधित आयात व्यापार नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 (सी) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर लाइसेंस सं. पी/यू/2687253/सी दिनांक 6-7-1972 मूल्य 11092 रु. की सीमाशुल्क कार्यसंबंधी और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

4. आवेदक को अब आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रिया विधि, हॉडबुक, 1972-73 की कंडिका 318(4) में की गई व्यवस्था के अनुसार लाइसेंस की दोनों अनुलिपि सीमाशुल्क कार्य संबंधी प्रति तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी की जा रही है।

[सं. कैम/40/ओ. डी.-71/एस. सी.-3/सी. एल. ए/2247]

ए. एल. भल्ला, उप मुख्य नियंत्रक

कृत संयुक्त मुख्य नियंत्रक

New Delhi, the 12th October, 1972

ORDER

S.O. 287.—M/s. Beekay Rubber Industries, P.O. Rayon & Silk Mills, Amritsar were granted Import Licence No. P/U/2687253/C dated 6/7/72 for Rs. 11092 for import of (1) Natural Rubber including Natural Rubber Latex (2) Carbon Black 3. Rubber Accelerators, Antioxidants, Retarders, Reinforcing Silicon Fillers, Manganese Carbonate Light 4. Rubber Plasticizers, Peptizers & Wetting Agents. They have filed affidavit as required under para. 318 read with appendix 8 of Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1972-73 wherein they have stated that both copies of licence No. P/U/2687253/C dated 6/7/72 for all Rs. 11092 have been lost/misplaced without having been utilised at all.

2. I am satisfied that the both original Customs Purposes and Exchange Control copies of the said licence have been lost/misplaced.

3. In exercise of the powers conferred on me under subject Clause 9(c) in the Import Trade Control Order 1955 dt. 7-12-55 as amended upto date, the said licence No. P/U/2687253/C dated 6/7/72 for Rs. 11092 Customs Purposes and as well as Exchange Control copies is hereby cancelled.

4. The applicant is now being issued a duplicate of both Customs Purposes as well as Exchange Control copies of the licence in accordance with the provisions of para. 318(4) of Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure 1972-73.

[No. Chem/40/OD-71/SC-III/CLA/2247]

A. L. BHALLA, Dy. Chief Controller,
for Jt. Chief Controller.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(भारतीय मानक संस्था)

नई दिल्ली, 24 जनवरी 1973

क्र. आ. 288.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणनियमन) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी एम/एल-2877 जिसके ध्योरे नीचे दिए गए हैं, 16 प्रपत्रावर, 1972 से रद्द कर दिया गया है क्योंकि लाइसेंसधारी का नाम बदल गया है।

अनुसूची

लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक
1	2	3	4
सी एम/एल-2877 15-1-1971	एसोसियेटेड बैटरी मेकर्स, (ईस्टर्न) लि० एक्साइड फैक्टरी, स्पू-कार्ड रोड ग्राम-नगर (प० बंगाल)	8.0 ग्रामी और 1.0 ग्रामी रेटिंग वाली खनिकों की टोपी लैम्पों की बैटरियां (सीसा-ग्राम्य वाली)	IS: 2512-1963 खनिकों की टोपी लैम्पों की बैटरियां (सीसा अम्ल वाली) की विशिष्ट

[सं० सी० एम० बी०/55:2877(इ टी)]

ए० बी० राव० निदेशक (सैट्रल मार्क)

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 24th January 1973

S. O. 288.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, as amended subsequently, the Indian Standards Institution hereby notifies that Certification Marks Licence No. CM/L-2877 particulars of which are given below, has been cancelled with effect from 16 October 1972 due to change in the name of the licensee:

THE SCHEDULE

Licence no. and Date.	Name and Address of the Licensee	Article/Process covered by the licence cancelled	Relevant Indian Standard
CM/L-2877 15.1.1972	Associated Battery Makers (Eastern) Limited, Exide Factory, New Chord Road, Shamnagar, West Bengal	Miners' cap lamp batteries (lead-acid type) —0.8 amp and 1.0 amp rating Brand: 'EXIDE' Triclad	IS: 2512-1963 Specification for miners' cap lamp batteries (Lead-acid type)

[No. CMD/55 : 2877 (ET)]

A. B. RAO, Director (Central Marks).

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1972

क्र. आ. 289.—यतः औषधी और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में और संशोधन करने के लिये, इससे उपबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट प्रारूप नियम उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में यथा विनिर्दिष्ट भारत के राजपत्रों में औषधी और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23 की धारा 12 और 33 की अपेक्षानुसार, प्रकाशित किये गये थे जिनमें उन सभी व्यक्तियों से जिनका उनसे प्रभावित होना संभाव्य था पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 7 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई तारीख तक आक्षेप या सूझाव मांगे गये थे।

और यतः उक्त राजपत्र जनता को उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख को उपलब्ध करा दिया गया था।

और यतः उक्त प्रारूप के बारे में जनता से प्राप्त हुए आक्षेपों और सूझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

अतः, अब औषधी और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार औषधी तकनीकी सहायकार बोर्ड से परामर्श के पश्चात् औषधी और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित मिथम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—

(1) इन नियमों का नाम औषधी और प्रसाधन सामग्री (तृतीय संशोधन) नियम, 1972 होगा।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 58 का प्रतीस्थापन:—

उक्त नियमों के नियम 58 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतीस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

“58-औषधी, उपकरण मशीनरी आदि का अधिहृत—

(1) यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के अध्याय 4 के किसी उपबन्ध के या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उल्लंघन के लिये सिद्धांश ठहराया गया हो, तो ऐसी औषधी के स्टॉक की जिसके संबंध में उल्लंघन किया गया है, अधिहृत कर लिया जाएगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 17 के खण्ड (क), खण्ड (ख), खण्ड (ग), खण्ड (घ), खण्ड (च), या खण्ड (छ) के अधीन किसी ऐसी औषधी के, जिसके बारे में यह समझा गया हो कि उस पर मिथ्या छाप लगी है, या अधिनियम की धारा 17 ख के अधीन अप्रामाणिक औषधी के विनिर्माण के लिये या अधिनियम की धारा 18 के खण्ड (ग) के अधीन यथापेक्षित किसी विधिमन्य अनुज्ञापित के बिना किसी औषधी का विक्रय के लिये विनिर्माण करने या स्टॉक करने या विक्रय के लिये प्रदर्शित करने या वितरण करने के लिये सिद्धांश ठहराया गया हो तो ऐसे विनिर्माण, विक्रय या वितरण में प्रयोग किये गये किन्हीं उपकरणों या मशीनरी की और किन्हीं ऐसे पात्रों, पैकेजों या आविष्टकों को जिनमें ऐसी औषधी रखी गयी हो और ऐसी औषधी के वहन करने में प्रयोग किये गये पशुओं, यानों, जलयानों, या अन्य वाहनों को अधिहृत कर लिया जाएगा।”

3. नियम 67 का लोप :

उक्त नियमों का नियम 67 लुप्त कर दिया जायेगा।

4. नियम 127 का प्रतिस्थापन :

उक्त नियम के नियम 127 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

127 "श्रीवधो में प्रयुक्त किए जाने के लिए अनुज्ञात रंगों की सूची

(1) किसी भी श्रीवधि में नीचे लिखे रंगों के अलावा और किसी अन्य रंगों का प्रयोग न किया जाये।

(i) प्राकृतिक रंग

अनाटो

कैरोटोम

कलोरोफिल

कोविनिन

कुर्कुमिन

रेड आक्साइड आफ आयरन

यलो आक्साइड आफ आयरन

(2) कृत्रिम रंग

कैरामेल

(3) कोलतार रंग

रंग का सामान्य नाम	रंग सूचकांक	रासायनिक नाम
1	2	3
हरा		
क्विनाजराइन धीन एस एस	61565	1. 4 बिस ((पो-टालुइनों) एनथाक्विनोन।
एलिजाफिन साइयाजाइन धीन एफ०	61570	1, 4 बीस (ओ-सल्फो-पी-टालुइनों) एनथाक्विनोन का डाइसोडियम साल्ट।
पीला		
टार्टराजाइन	19140	3-कारबोक्सी-5-हाइड्राक्सी-1-पी-सल्फोफेनिल-4-पी-सल्फो-फेनिल-आजोपाइराजोल का डाइसोडियम साल्ट।
सनसेट एलो एफ सी एफ	15985	1-पी-सल्फोफेनिल-2-नेफथाल-6-सल्फोनिक एसिड का डाइसोडियम साल्ट।
बिजनीलाइन यलो एम०एम०	47000	2-(2-क्विनोलिन)-1, 3-इनडान-डाइमिन
लाल		
एमरन्थ	16185	1-(4-सल्फो-1-नेफथोलाजी) 2-नेफथाल 3, 6-डाइसल्फोनिक एसिड का डाइसोडियम साल्ट।
एरिथ्रोसिन	45430	9-ओ-कार्बोक्सीफेनिल-6-हाइड्राक्सी 2, 4, 5, 7-टेट्राब्राह्मोडो-3-ब्राह्मोक्सानथान का डाइसोडियम साल्ट।
इथ्रोसिन बार्ड एस या इथ्रोसिन	45380	2, 4, 5, 7 टेट्रा-ओमो-9-पी-कार्बोक्सी फेनिल-6-हाइड्राक्सी-3-ब्राह्मोक्सानथान का डाइसोडियम साल्ट।

1	2	3
टोनोरेड या सूडान III	26100	1-पी-फेनिलाजो फेनिलाजो-2-नेफथाल।
पोनसिग्राउ 4 धार	16255	1-(4-सल्फो-1-1-नेफथोलाजी)-2-नेफथाल-6: 8-डाइसल्फोनिक एसिड का डाइसोडियम साल्ट
कामोइसोन	14720	2-(4-सल्फो-1-नेफथोलाजी)-1-1-नेफथाल-4-सल्फोनिक एसिड का डाइसोडियम साल्ट।
फास्ट रेड इ	16045	2-(4-सल्फो-1-नेफथोलाजी)-2-नेफथाल 6-सल्फोनिक एसिड का डाइसोडियम साल्ट।
मीला		
इन्डिगो कार्मिन	73015	इन्डीगोटिन-5 : 5-डाइसल्फोनिक एसिड का डाइसोडियम साल्ट।
बैंगनी		
एलिजुराल पर्पल एस एस	60725	1-हाइड्राक्सी-4-पो-टालुइनों-एनथाक्विनोन।
भारंगी		
आरेन्ज जो	16230	1-फेनिलाजो-2-नेफथाल-6, 8-डाइसल्फोनिक एसिड का डाइसोडियम साल्ट।
भूरा		
रेसोसिन ब्राउन	20170	4-पी-सल्फोफेनिलाजो-2-(2, 4-एक्सोलोलाजे-1, 3, रेसोसिनाल का मोनो-सोडियम साल्ट।
काला		
नेफथाल ब्लू ब्लेक	20470	9-एमिनो-7-पी-नाइट्रो-फेनिलाजो-2-फेनिलाजो-1-नेफथाल-3, 6 डाइसल्फोनिक एसिड का डाइसोडियम साल्ट।

(4) लेक्स

ऊपर सूची-बद्ध जल-विलेया रंगों में से किसी का एल्युमीनियम या कैल्सियम साल्ट (लेक्स)।

(2) ऐसे पात्र का लेखल जिसमें किसी अनुज्ञात रंग की श्रीवधि हो, उस रंग का सामान्य नाम उपरिर्लिखित करेगा।"

5. अनुसूची का संशोधन

उक्त नियमों में अनुसूची क में —

(1) प्ररूप 20-ख में, अनुज्ञप्ति की शर्त के नीचे, शर्त 4 लुप्त कर दी जायेगी;

(2) प्ररूप 21-ख में, अनुज्ञप्ति की शर्त के नीचे शर्त 5 लुप्त कर दी जायेगी;

(3) प्ररूप 22 और 23 लुप्त कर दिये जायेंगे;

(4) प्ररूप 25 में अनुज्ञप्ति की शर्त के नीचे, शर्त 4 लुप्त कर दी जायेगी,

(5) प्ररूप 25-क में, अनुज्ञप्ति की शर्त के नीचे, शर्त 4 खूट कर दी जायेगी,

(6) प्ररूप 25 ख में, अनुज्ञप्ति की शर्त के नीचे, शर्त 5 खूट की जायेगी,

(7) प्ररूप 28 में, 'अनुज्ञप्ति की शर्त' के नीचे, शर्त 4, खूट कर दी जायेगी,

(8) प्ररूप 28-क में, 'अनुज्ञप्ति की शर्त' के नीचे, शर्त 4 खूट कर दी जायेगी,

[संख्या एक्स 11014/17/72 डी]

अनुसूची

औषधी प्रसाधन सामग्री नियम 1945 में और संशोधन करने के लिए प्रकाशित प्रावय अधिसूचना को बिशिष्टियों

अ० सं० नियमों का संक्षिप्त नाम संशोधन के लिये प्रतिस्थापित औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की संख्या	अधिसूचना संख्या और तारीख	भारत के राजपत्र की भाग सं०, तारीख और उसका पृष्ठ जिसमें अधिसूचना प्रकाशित की गई	वह तारीख जिसको राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई	ऐसे व्यक्तियों से जिनका प्रतिस्थापित संशोधन से प्रभावित होना संभाव्य था आक्षेपों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख		
1	2	3	4	5	6	7
1- औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम, 1968	नियम 58	फा० 1-39/64-डी तारीख 29-2-1968	भाग 2, खण्ड 3(ii) का० प्रा० सं० 867 तारीख 9-3-68 पृष्ठ 1370 और 1371	11-3-1968	20 मई 1968	
2- यथोक्त-	नियम 67	-यथोक्त-	भाग 2 खण्ड 3 (ii) का० प्रा० सं० 867 तारीख 9-3-68 पृष्ठ 1371	-यथोक्त-	-यथोक्त-	
3- -यथोक्त-	नियम 127	-यथोक्त-	भाग 2 खण्ड 3(ii) का० प्रा० सं० 867 तारीख 9-3-68 पृष्ठ 1372 और 1373.	-यथोक्त-	-यथोक्त-	
4- औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम 1968	अनुसूची क	फा० 1-39/64-डी तारीख 29-2-1968	भाग 2 खण्ड 3(ii) का० प्रा० सं० 867 तारीख 9-3-68 पृष्ठ 1373	11-3-1968	20 मई, 1968	

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (Department of Health)

New Delhi, the 20th December, 1972

S.O. 289—WHEREAS the draft rules, as specified in column 2 of the Schedule annexed hereto, further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 were published, as required by sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), in the Gazettes of India, as specified in the corresponding entries in column 5 of the said Schedule, inviting all persons likely to be affected thereby to make objections or suggestions by the date specified in the corresponding entry in column 7 of the Schedule aforesaid;

AND WHEREAS the said Gazette was made available to the public on the corresponding date, specified in column 6 of the said Schedule;

AND WHEREAS the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby makes the following

rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, namely:—

1. Short title and commencement:

- (1) These rules may be called the Drugs and Cosmetics (Third Amendment) Rules, 1972.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Substitution of Rule 58

For rule 58 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"58 Confiscation of drugs, implements, machinery etc.

- (1) Where any person has been convicted for contravening any of the provisions of Chapter IV of the Act or any rule made thereunder, the stock of the drug in respect of which the contravention has been made shall be liable to confiscation.
- (2) Where any person has been convicted for the manufacture, of any drug deemed to be misbranded under clause (a), clause (b), clause (c), clause (d), clause (f) or clause (g) of section 17 of the Act, or adulterated drug under section 17B of the Act, or for manufacture for sale, or stocking or exhibiting for sale or distribution of any drug without a valid licence as required under clause (c) of section 18 of the Act, any implements or

machinery used in such manufacture, sale or distribution and any receptacle, packages, or coverings in which such drug is contained and the animals, vehicles, vessels or other conveyances used in carrying such drug shall also be liable to confiscation”.

3. Omission of rule 67

Rule 67 of the said rules shall be omitted.

4. Substitution of Rule 127

For rule 127 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

“127. List of colours permitted to be used in drugs

(1) No drug shall contain a colour other than that specified below:—

(1) Natural Colours

Annatto
Carotene
Chlorophyll
Cochineal
Curcumin
Red Oxide of iron
Yellow Oxide of iron

(2) Artificial Colours

Caramel

(3) Coal Tar Colours

Common name of the colour	Colour Index Number	Chemical Name
1	2	3
GREEN		
Quinazarine Green SS	61565	1, 4-bis (p-Toluino)-anthraquinone.
Alizarin Cyanine Green F.	61570	Disodium salt of 1, 4-bis (O-sulfo-p-toluino) anthraquinone.
YELLOW		
Tartrazine	19140	Trisodium salt of 3-carboxy-5-hydroxy-1-p-sulphophenyl-4-p-sulphophenyl azopyrazole.
Sunset Yellow FCF	15985	Disodium salt of 1-p-sulphophenyl-azo-2-naphthol-6-sulfonic acid.
Quinoline yellow SS	47000	2-(2-quinolyl)-1, 3-indandione
RED		
Amaranth	16185	Trisodium salt of 1-(4-sulfo-1-naphthylazo) 2-naphthol 3, 6-disulfonic acid.
Erythrosine	45430	Disodium salt of 9-0-carboxy-phenyl-6-hydroxy 2, 4, 5, 7-tetraido-3-isoxanthone.
Eosin YS or Eosine G	45380	Disodium salt of 2, 4, 5, 7-Tetrabromo-9-p-carboxy-phenyl-6-hydroxy-3-isoxanthone.
Toney Red or Sudan III.	26100	1-p-phenylazophenylazo-2-naphthol.
Ponceau 4 R	16255	Trisodium salt of 1-(4-sulpho-1-1-naphthylazo)-2 naphthol-6; 8-disulphonic acid.

Carmoisine . 14720 Disodium salt of 2-(4-sulpho-1-naphthylazo)-1 naphthol-4-sulphonic acid.

Fast Red E . 16045 Disodium salt of 2-(4'-sulpho-1'-naphthylazo)-2-naphthol-6-sulphonic acid.

BLUE

Indigo Carmine . 73015 Disodium salt of indigotin-5: 5'-Disulphonic acid.

VIOLET

Alizarol purple SS . 60725 1-Hydroxy-4-p-toluino-anthraquinone.

ORANGE

Orange G . 16230 Disodium salt of 1-phenylazo-2-naphthol-6, 8-disulphonic acid.

BROWN

Resorcin Brown . 20170 Monosodium salt of 4-p-sulphophenylazo-2-(2, 4-xylazo)-1, 3-resorcinol.

BLACK

Napthol Blue Black . 20470 Disodium salt of 8-amino-7-P-nitrophenylazo-2-phenylazo-1-naphthol-3, 6-di-sulfonic acid.

(4) LAKES

The Aluminium or calcium salts (lakes) of any of the water-soluble colours listed above.

(2) The label on the container of a drug containing a permitted colour shall indicate the common name of the colour.”

5. Amendment of Schedule A

In the said rules, in Schedule A;

- (1) In Form 20-B, under 'Conditions of Licence', condition 4 shall be omitted;
- (2) In Form 21-B, under 'Conditions of Licence' Condition 5 shall be omitted;
- (3) Forms 22 and 23 shall be omitted;
- (4) in Form 25, under 'Conditions of Licence' Condition 4 shall be omitted;
- (5) in Form 25-A, under 'Conditions of Licence' Condition 4 shall be omitted;
- (6) in Form 25-B, under 'Conditions of Licence' Condition 5 shall be omitted;
- (7) in Form 28, under 'Conditions of Licence' Condition 4 shall be omitted;
- (8) in Form 28-A, under 'Conditions of Licence' Condition 4 shall be omitted.

THE SCHEDULE

Particulars of the draft notification published for amending further the Drugs and Cosmetics Rules, 1945.

Sl. No.	Short title of the rules	No. of the Drug and Cosmetics Rules, 1945 proposed to be amended	Notification No. and date	Part No., date & page of the Gazette of India in which notification has been published	Date on which the Gazette copies were made available to the public	The last date fixed for receipt of objections from persons likely to be affected by the proposed amendment.
1.	The Drugs and Cosmetics (Amendment) Rules, 1968.	Rule 58	F.1-39/64-D Dt. 29-2-1968	Part-II-Section 3(ii) S.O. No. 867 dt. 9-3-68 Pages 1370 to 1371	11-3-1968	20-5-1968
2.	Do.	Rule 67	Do.	Part-II-Section 3(ii) S.O. No. 867 dt. 9-3-68 Page 1371.	Do.	Do.
3.	Do.	Rule 127	Do.	Part II-Section 3(ii) S.O. No. 867 Dated 9-3-68 pages 1372 and 1373	Do.	Do.
4.	Do.	Schedule A	Do.	Part II-Section 3(ii) S.O. No. 867 dated 9-3-68 page 1373.	Do.	Do.

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1973

का. आ. 290.—आँषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार आँषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और 33 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आँषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के पश्चात्, बनाने की प्रस्थापना करती है, सभी ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनका इसके द्वारा प्रभावित होना सम्भाव्य है, उक्त धाराओं की आशुनसूत्र प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर, भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से तीन मास की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जायेगा।

ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पहले प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जायेगा :

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम : इन नियमों का नाम आँषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम, 1973 है।

2. अनुसूची का संशोधन :

आँषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में अनुसूची घ में, (1) मद 1 उसकी मद 2 के रूप में पुनः संख्यांकित की जायेगी, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित मद 2 के पहले, निम्नलिखित मद अन्तः स्थापित की जायेगी, अर्थात्—

(1) प्रसाधन सामग्री और परिसाधित प्रसाधन सामग्री के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री के लिए मानक

(1) प्रसाधन सामग्री और परिसाधित प्रसाधन सामग्री के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री, भारतीय मानक संस्था द्वारा समय समय पर अधिकृत भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुरूप होंगे।

(2) प्रसाधन सामग्री के विनिर्माण में प्रयुक्त ऐसी कच्ची सामग्री, जिनके लिए भारतीय मानक संस्था द्वारा विनिर्देश अधिकृत न किये गये हों, उन मानकों के अनुरूप होंगे, जो अधिनियम और उसके अधीन बनाए गये नियमों के अधीन विहित आँषधकेशों में अधिकृत किये गये हैं।

(11) इस प्रकार पुनः संख्यांकित मद 2 में, निम्नलिखित शीर्षक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“ऐल्कीहाली सुगंध घोलों के लिए मानक”।

[सं एक्स 11014/3/71 डी]

रमेश बहादुर, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd January, 1973

S.O. 290.—The following draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, which the Central Government proposes to make, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, in exercise of the powers conferred by sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), is published, as required by the said sections for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of three months from the date of its publication in the Gazette of India.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the date so specified will be considered by the Central Government:—

DRAFT RULES

1. Short title: These rules may be called the Drugs and Cosmetics (Amendment) Rules, 1973.

2. Amendments of Schedule S: In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, in Schedule S,

(i) item 1 shall be renumbered as item 2 thereof, and before item 2 as so renumbered, the following item shall be inserted, namely:—

“1. Standards for raw materials used in the manufacture of cosmetics and cosmetics in finished form.

(1) Raw materials used in the manufacture of cosmetics and cosmetics in finished form, shall conform to the Indian Standard specifications laid down from time to time by the Indian Standards Institution.

(2) Raw materials used in the manufacture of cosmetics for which specifications have not been laid down by the Indian Standards Institution, shall conform to the standards, wherever laid down in the pharmacopoeias prescribed under the Act and the rules thereunder”;

(ii) in item 2 as so renumbered, the following heading shall be inserted, namely:—

“Standards for Alcoholic Fragrance Solutions.”

[No. X 11014/3/71-D]
RAMESH BHADUR, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1973

का. आ. 291.—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम 1956 (1956 का 25) की धारा 4 के खण्ड (ड.) के अनुसार में भारत सरकार एतद्वारा श्री सी. एस. रामचन्द्रन, सचिव भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय को श्री के. के. दास के स्थान पर, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली का सदस्य मनोनीति करती है।

[सं. एफ. बी. 16011/1/73 एम. ई. (पी. जी.)]

New Delhi, the 10th January, 1973

S.O. 291.—In pursuance of clause (e) of section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (No. 25 of 1956), the Government of India hereby nominates Shri C. S. Ramachandran, Secretary to the Government of India in the Ministry of Health and Family Planning as a member of the All India Institute of Medical Sciences. New Delhi, vice, Shri K. K. Dass resigned.

[No. V. 16011/1/73-ME(PG)]

का. आ. 292.—स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़, अधिनियम 1966 (1966 का 51) के खण्ड 5 की धारा (घ) के अनुसार में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री सी. एस. रामचन्द्रन, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय को श्री के. के. दास के स्थान पर जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ का सदस्य मनोनीति करती है।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय की अधिसूचना सं. बी. 17013/1/72 एम. ई. (पी. जी.) की क्रम संख्या 3 तथा तत्सम्बन्धित प्रविष्टियां मिटा दी जाएंगी।

[सं. 17013/8/72-एम ई (पी. जी.)]

सी. आर. कृष्णमूर्ति, निदेशक

S.O. 292.—In pursuance of clause (d) of section 5 of the Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, Act, 1966 (No. 51 of 1966), the Central Government hereby nominates Shri C. S. Ramachandran, Secretary, Ministry of Health and Family Planning to be a member of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh vice Shri K. K. Dass, resigned.

In the Ministry of Health and Family Planning notification No. V. 17013/1/72-ME(PG), dated 2-6-1972 serial No. 3 and entries pertaining thereto shall be deleted.

[No. V. 17013/8/72-ME(PG)]

C. R. KRISHNAMURTHI, Director.

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1973

खैराती विन्यास अधिनियम, 1890 के विषय में और "लेडी हार्डिंग महिला और बालक अस्पताल, दिल्ली निधि" के विषय में।

का. आ. 293.—लेडी हार्डिंग महिला बालक अस्पताल दिल्ली निधि के आवेदा पर उसके प्रशासन बोर्ड की सहमति से और खैराती विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 4 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह आदेश देती है कि निम्नलिखित व्यापार के अनुसार विनिहित 20,000/- रु. की राशि,

1- पांच पांच हजार रुपये के 6 प्रतिशत पश्चिमी बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड बंधपत्र, 1982, सं. 821370 से 821373 तक में विनिहित 20,000/- रु. की राशि, और

2- एक एक हजार रुपये के 6 प्रतिशत पश्चिमी बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड बंधपत्र 1982 सं. 821374 से 821375 तक में विनिहित 2,000 रुपये की राशि,

भारत के खैराती विन्यासों के कोषपाल में निहित होगी जो उसके द्वारा या उसके पद-उत्तरवर्ती द्वारा (खैराती विन्यास अधिनियम, 1890 और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन) रखी जायेगी।

[संख्या: बी 21020/12 एम. ई. (पू. जी.)]

प्रताप मुखोपाध्याय, अवर सचिव

New Delhi, the 11th January, 1973

In the matter of the Charitable Endowments Act, 1890
In the matter of "The Lady Hardinge Hospital, for Women and Children, Delhi Fund"

S.O. 293.—On the application of, and with the concurrence of the Board of Administration for the Lady Hardinge Hospital for Women and Children, Delhi, Fund and in exercise of the powers conferred on it by sub-section (1) of Section 4 of the Charitable Endowments Act, 1890, (6 of 1890), the Central Government both hereby order that a sum of Rs. 22,000 invested as per details below—

(1) A sum of Rs. 20,000 invested in 6 per cent West Bengal State Electricity Board Bonds, 1982 Nos 821370 to 821373 of Rs. 5,000 each, and

(2) A sum of Rs. 2,000 invested in 6 per cent West Bengal State Electricity Board Bonds, 1982 Nos. 821374 to 821375 of Rs. 1,000 each.

shall vest in the Treasurer of Charitable Endowments for India to be held by him or his successor in office (subject to the provisions of the Charitable Endowments Act, 1890 and the rules framed thereunder from time to time by the Central Government).

[No. V. 21020/12/72-ME(UG)]

P. MUKHOPADHYAY, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1973

का. आ. 294.—नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) नियम 1960 के नियम 9 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा छुट्टी पर गये श्री यू. एस. श्रीवास्तव के स्थान पर श्री वा. बी. सुब्रह्म नियम को 4 दिसम्बर 1972 से 15 फरवरी, 1973 तक के लिये नौवहन विकास निधि समिति के सचिव नियुक्त करती है।

[संख्या 35-एम. डी. (54)/72]

ब. क. साही, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 20th January, 1973

S.O. 294.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Shipping Development Fund Committee (General) Rules, 1960, the Central Government hereby appoints Shri V. V. Subrahmanyam as Secretary of the Shipping Development Fund Committee with effect from the 4th December, 1972, to 15th February, 1973, vice Shri U. S. Shrivastav, proceeded on leave.

[No. 35-MD(54)/72]

B. K. SAHI, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1973

का. आ. 295.—लोक परिसर (अधिकृत अधिभोगियों की बंदखली) अधिनियम 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतत्पूर्व स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय (निर्माण, आवास और नगरीय विकास विभाग) की अधिसूचनाओं सं. का. आ. 1626, तारीख 3 मई, 1969 सं. 3528 तारीख 6 सितम्बर, 1969 और सं. 2775, तारीख 22 अगस्त 1970 को अधिकांत करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 1 में उल्लिखित अधिकारी को सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी होने के नाते, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट लोक परिसरों के संबंध में अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमा के भीतर उक्त अधिनियम के द्वारा या अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का पदनाम	लोक परिसरों के प्रवर्ग और क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं
1	2
सीच, भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।	भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में स्थित सभी सम्पत्तियां, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :— अशोक होटल, 50 बी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली। जनपथ होटल, जनपथ, नई दिल्ली। होटल रणजीत, महाराजा रणजीत सिंह रोड, नई दिल्ली। लोधी होटल, लिंक रोड, नई दिल्ली। अकबर होटल, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली। क़ुतुब रेस्तरां, क़ुतुब, दिल्ली और प्लॉट सं. 119, नरैना औद्योगिक सम्पदा, दिल्ली।

[फाइल सं. 21012(5)/69-नीति-4]

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 23rd January, 1973

S.O. 295.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), and in supersession of the notifications of the Government of India in the late Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Department of Works, Housing and Urban Development) No. S.O. 1626 dated the 3rd of May, 1969 No. 3528, dated the 6th September, 1969, and No. 2775, dated the 22nd August, 1970, the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being an officer equivalent to the rank of gazetted officer of Government to be Estate Officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on Estate Officers by or under the said Act, within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

THE TABLE

Designation of the officer Categories of public premises and local limits of jurisdiction.

1	2
The Secretary, India Tourism Development Corporation Limited, New Delhi.	All properties belonging to the India Tourism Development Corporation Limited and situated in the Union territory of Delhi, including the following:— Ashoka Hotel, 50-B, Chanakya-puri, New Delhi Janpath Hotel Janpath, New Delhi, Hotel Ranjit, Maharaja Ranjit Singh Road, New Delhi, Lodhi Hotel, Link Road, New Delhi, Akbar Hotel, Chanakya-puri, New Delhi, Qutab Restaurant, Qutab, Delhi, and Plot No. 119, Naraina Industrial Estate, Delhi.

[F. No. 21012(5)/69-Pol. IV]

का. आ. 296.—लोक परिसर (अप्रतिधिकृत अधिभोगियों की बंदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 20 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतत्पूर्व स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय (निर्माण, आवास और नगर विकास विभाग) (सम्पदा निदेशालय) की अधिसूचना सं. का. आ. 2361, तारीख 10 जून, 1969 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे की सारणी में, स्तम्भ 1 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, ट्राम्बे यूनिट, भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, मुम्बई।

[फाइल सं. 21012(10)/नीति-3]

S.O. 296.—In exercise of the powers conferred by section 3, read with section 20, of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the late Ministry of Health, Family Planning, Works, Housing and Urban Development, (Department of Works, Housing and Urban Development) (Directorate of Estates), No. S.O. 2361 dated the 10th June, 1969, namely :—

In the Table below the said notification, in column 1, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

Chief Administrative Officer, Trombay Unit, Bombay.

The Fertilizer Corporation of India Ltd.

[F. No. 21012(10)/69-Pol. III]

का. आ. 297.—लोक परिसर (अप्रतिधिकृत अधिभोगियों की बंदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निम्न सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित अधिकारी को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समतुल्य अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी के रूप में एतद्वारा नियुक्त करती है, और वह उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट लोक परिसरों के संबंध में अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	लोक परिसरों के प्रबन्ध और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
सहायक कार्यपालक-अधिकारी (प्रशासन), एण्टीबायोटिक्स प्लांट, ऋषिकेश	ऋषिकेश स्थित एण्टीबायोटिक्स प्लांट के प्रशासनिक नियंत्रण में और उसके अधीन के परिसर, संयंत्र भवन के क्षेत्र को अप-बीजित करते हुए।

[फाइल सं. 21012(14)/72-नीति-3]

S.O. 297.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being an officer equivalent to the rank of gazetted officer of Government to be Estate Officer for the purposes of the said Act, and that he shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on the Estate Officer, by or under the said Act, within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

THE TABLE

Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction,
(1)	(2)
Assistant Executive Officer (Administration) Antibiotics Plant, Rishikesh.	Premises belonging to and under the administrative control of Antibiotics Plant at Rishikesh excluding the area of the Plant building.

[F. No. 21012(14)/69-Pol. III]

का. आ. 298.—लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बंदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 20 के साथ पठित, धारा 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के निर्माण और आवास तथा नगर-विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1093, तारीख 20 मार्च, 1966 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, स्तम्भ 1 में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“सम्पदा अधिकारी मंगलौर बंदरगाह परियोजना, पनमबूर”।

[फा. सं. 21012(25)/72-नीति-3]

S.O. 298.—In exercise of the powers conferred by section 3, read with section 20, of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Works and Housing and Urban Development No. S.O. 1093, dated the 26th March, 1966, namely :—

In the said notification, in the Table in column 1, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

“The Estate Officer Mangalore Harbour Project, Panambur”.

[F. No. 21012(25)/72-Pol. III]

का० आ० 279.—लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बंदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, नीचे की सारणी

के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारियों की रैंक के समतुल्य अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारियों के रूप में एतद्वारा नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिश्चित लोक परिसरों की बाबत अपनी-अपनी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे, और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे।

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	लोक परिसरों के प्रबन्ध और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं।
---------------------	--

(1)	(2)
(i) प्रशासन-प्रबन्धक, मुम्बई क्षेत्र, इण्डियन एयरलाइन्स के परिसर, चाहे इण्डियन एयरलाइन्स, मुम्बई।	ऐसे परिसर इण्डियन एयरलाइन्स के कब्जे में हों या उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए हों और जो इण्डियन एयरलाइन्स के मुम्बई क्षेत्र में उसके प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।
(ii) प्रशासन-प्रबन्धक, कलकत्ता क्षेत्र, इण्डियन एयरलाइन्स, कलकत्ता	इण्डियन एयरलाइन्स के परिसरों, चाहे ऐसे परिसर इण्डियन एयरलाइन्स के कब्जे में हों या उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए हों और जो इण्डियन एयरलाइन्स के कलकत्ता क्षेत्र में उसके प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।
(iii) प्रशासन-प्रबन्धक, दिल्ली क्षेत्र, इण्डियन एयरलाइन्स, नई दिल्ली	इण्डियन एयरलाइन्स के परिसर, चाहे ऐसे परिसर इण्डियन एयरलाइन्स के कब्जे में हों या उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए हों और जो इण्डियन एयरलाइन्स के दिल्ली क्षेत्र में उसके प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।
(iv) प्रशासन-प्रबन्धक, मद्रास क्षेत्र, इण्डियन एयरलाइन्स, मद्रास।	इण्डियन एयरलाइन्स के परिसर, चाहे ऐसे परिसर इण्डियन एयरलाइन्स के कब्जे में हों या उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए हों और जो इण्डियन एयरलाइन्स के मद्रास क्षेत्र में उसके प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।
(v) मुख्य प्रशासन-अधिकारी, इण्डियन एयरलाइन्स, नई दिल्ली	इण्डियन एयरलाइन्स के परिसर, चाहे ऐसे परिसर इण्डियन एयरलाइन्स के कब्जे में हों या उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए हों और जो नई दिल्ली स्थित इण्डियन एयरलाइन्स के मुख्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।

[फा० सं० 21012(26)/72-नीति III]

S.O. 299.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below, being officers equivalent to the rank of gazetted officers of Government to be estate officers for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officers by or under the said Act, within the limits of their respective jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

THE TABLE

Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction.
(1)	(2)
(i) Administrative Manager, Bombay Region, Indian Airlines, Bombay.	Premises belonging to Indian Airlines whether such premises are in possession of or leased out by Indian Airlines and which are under the administrative control of Indian Airlines in its Bombay Region.
(ii) Administrative Manager, Calcutta Region, Indian Airlines, Calcutta.	Premises belonging to Indian Airlines whether such premises are in possession of or leased out by Indian Airlines and which are under the administrative control of Indian Airlines in its Calcutta Region.
(iii) Administrative Manager, Delhi Region, Indian Airlines, New Delhi.	Premises belonging to Indian Airlines whether such premises are in possession of or leased out by Indian Airlines and which are under the administrative control of Indian Airlines in its Delhi Region.
(iv) Administrative Manager, Madras Region, Indian Airlines Madras.	Premises belonging to Indian Airlines whether such premises are in possession of or leased out by Indian Airlines and which are under the administrative control of Indian Airlines in its Madras Region.
(v) Chief Administrative Officer, Indian Airlines, New Delhi.	Premises belonging to Indian Airlines whether such premises are in possession of or leased out by Indian Airlines and which are under the administrative control of the Headquarters of Indian Airlines at New Delhi.

[F. No. 21012(26)/72-pol. III]

का. आ. 300.—लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों को बंदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के निर्माण और आवास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2186, तारीख 7 अगस्त, 1972 में एस्वद्वारा निम्नीलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, स्तम्भ (1) में —

(1) कम सं. 9 के सामने, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नीलिखित प्रविष्टि प्रतीस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“ज्येष्ठ उप-महालेखापाल (प्रशासन)/उप-महालेखापाल (प्रशासन), महालेखापाल का कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।”

(2) कम सं. 12 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नीलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“महाप्रबंधक/प्रबंधक (प्रशासन)/उप-प्रबंधक (प्रशासन)/ सहायक प्रबंधक (प्रशासन), विहीकल कारखाना, जयपुर।”

[फा. सं. 21012(27)/72-नीति-3]

आर. बी. सक्सेना, सम्पदा उप निदेशक
और पदम अवर सचिव

S.O. 300.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Works and Housing No. S.O. 2186, dated the 7th August, 1972, namely :—

In the said notification, in the Table, in column 1,

(i) against serial No. 9, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

“Senior Deputy Accountant General (Administration)/ Deputy Accountant General (Administration), Office of the Accountant General, Rajasthan. Jaipur.”

(ii) against serial No. 12, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

“The General Manager/Manager (Administration)/ Deputy Manager (Administration)/Assistant Manager (Administration), Vehicle Factory, Jabalpur.”

[F. No. 21012(27)/72-Pol. III]

R. B. SAXENA, Dy. Director of Estates and
ex-officio Under Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1972

आदेश

का. आ. 301.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपा-बद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बंस्ट बोकारो कील-चरी, हाकधर घाटोटाई, जिला हजारीबाग के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है।

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद में न्यायनिर्णयन के लिए निर्वेशित करना वांछनीय समझती है,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एस्वद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (संख्या 2), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्वेशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स बंस्ट बोकारो लिमिटेड की बंस्ट बोकारो कीलचरी, हाकधर घाटोटाई, जिला हजारीबाग के प्रबन्धतंत्र की श्री गुरुदास राम, फिटर (रोपवे), जो मेकैनिक्ल फोरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं, के नियमित आधार पर मेकैनिक्ल फोरमैन के रूप में प्रोन्नति के दावे को नामजूर करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुसूची का हकदार है?

[संख्या फल/20012/115/72-एल.आर.-2]

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION
(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 27th December, 1972

ORDER

S.O. 301.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of West Bokaro Colliery, Post Office Ghatotand, District Hazaribagh, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of West Bokaro Colliery of Messrs West Bokaro Limited, Post Office Ghatotand, District Hazaribagh in denying the claim of Shri Gurudas Ram, Fitter (Ropeway) acting as Mechanical Foreman for promotion as Mechanical Foreman on regular basis is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?

[No. L/20012/115/72-LR II.]

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1973

सूचीकरण

का. आ. 302.—भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (2), दिनांक 4 नवम्बर, 1972 के पृष्ठ 5163 पर प्रकाशित, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय के आवेदन में, का. आ. संख्या 3597, दिनांक 27 अगस्त, 1972 में, "27 अगस्त, 1972" की तारीख के लिए "27 सितम्बर, 1972" पढ़ें।

[सं. एल-2012(45)/72-एल. आर.-2]

करनैल सिंह, अवर सीक्रेटरी

New Delhi, the 22nd January, 1973

CORRIGENDUM

S.O. 302.—In the order of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation, (Department of Labour and Employment), S.O. No. 3597, dated the 27th October, 1972, published on page 5163 of the Gazette of India Part-II, Section 3, Sub Section (ii), dated the 4th November, 1972, in line three for "27th October, 1972" read "27th September, 1972."

[No. L/2012/45/72-LR. II.]

S.O. 303.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Rawanwara, Datla West, Bhamori and Eklehra Collieries belonging to Amalgamated Coalfields Limited and Chandametta, East Dongar Chickli, Barkui and North Chandametta Collieries belonging to Pench Valley Coal Company Limited, Post Office Parasia, District Chhindwara (Madhya Pradesh), and their workmen, which was received by the Central Government on the 12th January, 1973.

[No. L/18011/2/72-LR. II.]

KARNAIL SINGH, Under Secy.

**CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-
LABOUR COURT, JABALPUR.**

Dated December 29, 1972

Present :

MR. JUSTICE S. N. KATJU ... Presiding Officer,
CASE REF. NO. CGIT/LC(R)(23) OF 1971

(Notification No. L/18011/2/71-LR. II dated 16-7-1971.)

Parties :

Employers in relation to the Management of Rawanwara, Datla West, Bhamori and Eklehra Collieries belonging to Amalgamated Coalfields Limited and Chandametta, East Dongar Chickli, Barkui and North Chandametta Collieries belonging to Pench Valley Coal Company Limited, Parasia, District Chhindwara and their workmen represented through the Bhartiya Koyala Khadan Mazdoor Sangh, P. O. Chandametta, District Chhindwara (M.P.).

Appearances :

For Employers.—S/Shri P. S. Nair, S. D. Singh and R.K. Mehta.

For workmen—Sri S. S. Shakrawar.

Industry : Coal Mine

District : Chhindwara (M.P.)

AWARD

This is a reference under Sec. 10 of the Industrial Disputes Act. The dispute referred to this Tribunal for adjudication is:—

"Whether the action of the management of Rawanwara, Datla West, Bhamori and Eklehra Collieries belonging to Amalgamated Coalfields Limited and Chandametta, East Dongar fields Limited and Chandametta, Est Donger Chickli, Barkui and North Chandametta Collieries belonging to Pench Valley Coal Company Limited, Parasia, in not paying Variable Dearness Allowance as per the recommendations of the Central Wage Board for Coal Mining Industry to certain categories of employees (mentioned in the schedule to the reference) who draw their wages at the rate of Rs. 500/- per month is justified and if not to what relief are the workmen entitled to and from what date?"

The proceedings in this reference have dragged on since long. On the last date of the hearing viz. 25th November, 1972 a telegram was received from the representative of the worker stating that he was unable to attend and he prayed for the adjournment of the case. I allowed the prayer for adjournment on the clear understanding that the hearing shall proceed pre-emptorily on 29th December, 1972. No one has appeared on behalf of the workmen today, nor any witness on behalf of the workmen has appeared before the Tribunal today. I examined Sri R. K. Mehta, the Personnel Officer of the Amalgamated Coalfields Ltd. and Pench Valley Coal Company Ltd. He said that the persons mentioned at items 1 to 9 in the schedule to reference (viz. Head Clerks, Clerks employed in Accounts General Administration and Stores etc., Colliery Engineers, Electrical Supervisors, Head Overmen, Surveyors, Labour Welfare Officers, Medical Officers and Laboratory Technician) are not workmen, nor are they members of the Union, nor any dispute with regard to them was raised by the Union after the settlement dated 30th December, 1970 (Ex. E/1). There is no evidence to contradict the aforesaid evidence of Sri R. K. Mehta. My answer to the reference, therefore, is that the employees in the categories specified in the schedule to the reference are not entitled to any relief and I make my award accordingly. I make no order as to costs.

S. N. KATJU, Presiding Officer.

New Delhi, the 22nd January, 1973

S.O. 304.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of New Ghusick Colliery of Messrs Ghusick and Muslia Collieries Limited, Post Office Kalipahari, District Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 18th January, 1973.

[No. L-19012/21/72-LRIL.]

KARNAIL SINGH, Under Secy.

**CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL
AT CALCUTTA**

Reference No. 14 of 1972

Parties :

Employers in relation to the management of New Ghusick Colliery of Messrs Ghusick and Muslia Collieries Limited,

AND

Their workmen.

Present :

Sri S. N. Bagchi ... Presiding Officer.

Appearances :

On behalf of Employers—Sri J. D. Purohit, An employee of the Company.

On behalf of Workmen—Sri Provat Goswami, Joint General Secretary, Colliery Mazdoor Union (INTUC).

State : West Bengal

Industry : Coal Mine

AWARD

By Order No. L/19012/21/72-LRIL, dated 23rd February, 1972, the Government of India, in the Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour and Employment, referred the following dispute existing between the employers in relation to the management of New Ghusick Colliery of Messrs Ghusick and Muslia Collieries Limited and their workmen, to this tribunal, for adjudication, namely:

"Whether the action of the management of New Ghusick Colliery of Messrs Ghusick and Muslia Collieries Limited, Post Office Kalipahari, District Burdwan in locking out the mine with effect from 8 A.M. of the 7th February, 1972, *vide* their notice dated the 4th February, 1972, is legal and justified? If not, to what relief are the workmen of the colliery entitled?"

2. On 27th November, 1972 an issue was raised upon the statement of case filed by the employer and the workmen purported to be represented by the union Colliery Mazdoor Union (INTUC). The issue reads as follows:

"Did the Union approach the management any time before approaching the A.L.C.(C) relating to the demand under dispute? If not, is the present dispute referred to this tribunal an industrial dispute U/S 2(k) of the I. D. Act?, and can it be entertained and adjudicated upon by the tribunal?"

The case was fixed for hearing on that preliminary issue on 17th December, 1972. On that date it was found that in the proceeding before this tribunal neither the employer nor the workmen had been lawfully represented in terms of Section 36(1)(a) of the Industrial Disputes Act read with Rule 36 Form F of the Central Rules. So, both the parties were directed to file proper letter of authority entitling the respective party to the dispute that means the employers and the workmen to be represented by their respective representative as required by Section 36(1)(a) of the Industrial

Disputes Act read with Rule 36 Form F of the Central Rules.

3. On the date of hearing *i.e.* on 3rd January, 1973 one letter of authority was filed purported to have had been signed by the workmen and accepted by the Vice-President and the Joint General Secretary of the union concerned. It is dated 30th December, 1972. On that date the employer authorised one Sri J. D. Purohit, an employee of the company to appear and to represent the employer before this tribunal. It is dated 2nd January, 1973. These are two letters of authority.

4. Be that as it may, the parties purported to file a compromise petition relating to the dispute referred to for adjudication by this tribunal. This tribunal can have jurisdiction to record a compromise in this proceeding only if the dispute referred to it for adjudication is an industrial dispute within the meaning of Section 2(k) of the Industrial Disputes Act and the law as inunciated by the decisions in the cases of *Raju's Cafe, Coimbatore and Ors., vs. Industrial Tribunal, Coimbatore and Another*, 1951 I LLJ, p. 219, *Sindhu Resettlement Corporation Ltd. and Industrial Tribunal Gujarat & Ors.*, 1968, I LLJ p. 834 and *Fedders Lloyed Corporation Private Ltd. and Lt. Governor, Delhi & Ors.*, F.L.R. 1970(2) p. 343. I have already pointed out the issue raised. The issue is the alleged lock-out of the management of Ghusick Colliery of Messrs Ghusick and Muslia Collieries Limited with effect from 8 A.M. of 7th February, 1972 *vide* management's notice dated 4th February, 1972. So, in regard to the issue referred to for adjudication a demand relating to the issue in dispute must have to be lodged first either by the body of workmen involved in the dispute or by a registered trade union authorised in that behalf by the workmen in terms of Section 36(1)(a) of the Industrial Disputes Act read with Rule 36 Form F of the Central Rules. If this demand was not raised according to law before the authority of the management and either the workmen or the registered union representing the workmen as the case may be went straight with the demand relating to the dispute referred to for adjudication, then upon the failure report in the conciliation proceedings there would not be an industrial dispute under Section 2(k) of the Industrial Disputes Act in view of Law I have just quoted. The management in paragraph 4 of its statement of case asserted that neither the workman nor the union at any point of time raised any industrial dispute within the meaning Industrial Disputes relating to the subject matter of the issue referred to adjudication in terms of the said Government order dated 23rd February, 1972. The union, representing the workmen, in its statement of case in paragraph 11 stated that immediately after the notice dated 4th February, 1972 the union representative on behalf of the workmen saw the management, protested against the management's decision to lockout the colliery with effect from 7th February, 1972 and demanded withdrawal of the lockout notice. This statement is as vague as vagueness could possibly be imagined. Who the representative of the union was that had seen the management? The word 'management' carries no sense. It is the settled law that the demand relating to the dispute must be served on the authority of the management that can either accede to or reject the demand either by the body of workmen or by an officer of a registered trade union authorised in that behalf by the body of workmen involved in the dispute in terms of Section 36(1)(a) of the Industrial Disputes Act read with Rule 36 Form F of the Central Rules. The expression 'management' thus carries no sense at all. In *Raju's Cafe's* case their Lordships had clearly laid down that there must be service of the charter of demand on the authority of the management. In that case there was a conference of employers and employees over certain matters in dispute but employees did not serve any charter of demand on the respective employers. So, it was held that conference would not do. What would do is the service of the charter of demand by the workmen on the employer. So, paragraph 11 of the statement of case filed by the union representing the workmen comes within the mischief of law laid down in *Raju's Cafe's* case on the very words used in that paragraph. By its rejoinder to the written statement filed by the union on behalf of the workmen in paragraph 11, the employer asserts that immediately after the declaration of the lockout on 7th February, 1972 there was no direct representation by the workmen or any trade union before the management. On the pleadings, as I have just quoted, the issue as to whether the dispute referred to for adjudication by this tribunal is

an industrial dispute was raised. Unless a dispute is an industrial dispute within Section 2(k) of the Industrial Disputes Act this tribunal has no jurisdiction to entertain the dispute for adjudication and to pass any award thereon adjudication upon the dispute. So, if the parties come and file a compromise in relation to a dispute which is not an industrial dispute in a proceeding before the tribunal where the dispute has been referred to for adjudication, the tribunal cannot have any jurisdiction to record compromise in the proceeding since the dispute referred to for adjudication is not an industrial dispute. That is the position in this case. The dispute referred to for adjudication as appearing from the materials on record is not an industrial dispute under Section 2(k) of the Industrial Disputes Act for the reasons I have already discussed.

5. So, I cannot entertain the dispute nor can I adjudicate upon it. Therefore, I cannot record the compromise filed by the parties and to pass an award in terms of the compromise in this proceeding. The compromise petition is, therefore, rejected, and the reference is also rejected.

This is my award.

S. N. BAGCHI, Presiding Officer.

Dated, January 8, 1973.

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1972

आदेश

का. आ. 305.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपाब्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में श्री गुरुबचन सिंह द्वारा मनजीत स्टोन कम्पनी, छावनी, कोटा की बुधपुरा सैंड स्टोन माईन के प्रबन्धन से सम्बन्धित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्विशेष करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री उपदेश नारायण माथुर होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्विशेष करती है ।

अनुसूची

क्या श्री गुरुबचन सिंह, खान स्वामी द्वारा मनजीत स्टोन कम्पनी, छावनी, कोटा की बुधपुरा सैंड स्टोन में नियोजित कर्मचारों की, लेखा वर्ष 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70 और 1970-71 के लिए अपने द्वारा उपार्जित मजदूरियों की 20 परसेन्ट की वर से बोनस के भुगतान की मांग न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार इनमें से प्रत्येक वर्ष के लिए बोनस की किस मात्रा के हकदार हैं ?

[संख्या एल-29011/67/72-एल-आर-4]

New Delhi, the 30th December, 1972

ORDER

S.O. 305.—WHEREAS the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employer in relation to the Budhpura Sand Stone Mine owned by Shri Gurubachan Singh, Care of Manjit Stone Company, Chhawani, Kota and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

AND WHEREAS the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri Updesh Narain Mathur, as Presiding Officer with headquarters at Jaipur, and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

Whether the demand of the workmen employed in Budhpura Sand Stone Mine of Shri Gurubachan Singh Mine Owner, Care of Manjit Stone Company, Chhawani, Kota for payment of bonus at the rate of 20 per cent of the wages earned by them for the accounting years 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70, and 1970-71 is justified? If not, to what quantum of bonus are the workmen entitled for each of these years?

[No. L-29011/67/72-LRIV.]

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1973

आदेश

का. आ. 306.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाब्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बुधपुरा रेत पत्थर खानों, जिनके स्वामी श्री कुनेह सिंह गेहलोत, नयापुरा, कोटा हैं, से सम्बन्धित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्विशेष करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री उपदेश नारायण माथुर होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्विशेष करती है ।

अनुसूची

"क्या कुनेह सिंह गेहलोत, खान स्वामी, नयापुरा, कोटा की बुधपुरा और रामपुरा रेत पत्थर खानों में नियोजित कर्मचारों की, लेखा वर्ष 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70 और 1970-71 के लिए मजदूरियों के 20 प्रतिशत की दर से बोनस के भुगतान की मांग न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार इनमें से प्रत्येक वर्ष के लिए बोनस की किस मात्रा के हकदार हैं?"

[सं. एल-29011(31)/72-एल. आर-4]

New Delhi, the 11th January, 1973

ORDER

S.O. 306.—WHEREAS the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Budhpura and Rajpura Sand Stone Mines owned by Shri Kuneh Singh Gehlot, Nayapura, Kota and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

AND WHEREAS the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the

Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri Updesh Narain Mathur as Presiding Officer with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the demand of the workmen employed in the Budhpura and Rajpura Sand Stone Mines of Shri Kunch Singh Gehlot, Mine Owner, Nayapura, Kota for payment of bonus @ 20 per cent of the wages for the accounting years 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70 and 1970-71 is justified? If not, to what quantum of bonus are the workmen entitled for each of these years?"

[No. L-29011(31)/72-LR-IV]

आवृत्त

का. आ. 307.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावृद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड की फलाडी कोरी, सवाई माधोपुर के प्रबन्धतंत्र से सम्बन्धित नियोजकों और कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्टित करना वांछनीय है,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री उपदेश नारायण माथुर होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्टित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स जयपुर लिमिटेड की फलाडी कोरी, सवाई माधोपुर के निम्नलिखित कर्मकार उच्चतर ग्रेड में मेकैनिनिक के पद के लिए पात्र हैं? यदि हाँ, तो वे किस अनुसूची के हकदार हैं?

1. श्री हरिशंकर, बुलडोजर अपरेटर-सर्व-मेकैनिनिक
2. श्री शीतलसिंह, बुलडोजर अपरेटर-सर्व-मेकैनिनिक
3. श्री माल सिंह, शोवल अपरेटर-सर्व-मेकैनिनिक।

[संख्या एल/29011(61)/72-एल.आर.-4]

एस. एस. सहस्रनामान, अवर सचिव

ORDER

S.O. 307.—WHEREAS the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employer in relation to the management of Phulodi Quarry of Messrs Jaipur Udyog Limited, Sawaimadhopur and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

AND WHEREAS the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri Updesh Narain Mathur as Presiding Officer with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

Whether the following workmen of Phalodi Quarry of Messrs Jaipur Udyog Limited, Sawaimadhopur, are eligible for the post of Mechanic in the higher grade? If so, to what relief are they entitled?

1. Shri Hari Shanker, Bulldozer Operator-cum-Mechanic.
2. Shri Sheetal Singh, Bulldozer Operator-cum-Mechanic.
3. Shri Mal Singh, Shovel Operator-cum-Mechanic.

[No. L-29011(61)/72-LR. IV]

New Delhi, the 22nd January, 1973

S.O. 308.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial dispute between the employers in relation to the Ruby General Insurance Company, Limited, Bombay and their workmen which was received by the Central Government on the 12th January, 1973.

[File No. 26/3/68-LR. III (LR. I)]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR CAMP AT BOMBAY

Dated, December 26, 1972.

Present :

Mr Justice S. N. Katju—Presiding Officer.

Case No. CGIT/LC(R)(19) of 1971

(Notification No. F. No. 26/3/68-LR. III dated 25-3-1968)

Parties :

Employers in relation to the Ruby General Insurance Company Limited, Bombay and their workmen represented through the General Insurance Employees Union, 35/5, Lakhun Terrace, 34, Cawasji Patel Street, Bombay-1.

Appearances :

For employers—Sri H. K. Desai, Advocate.

For workmen—Sri B. P. Sharma.

Industry : Insurance Company.

District : Bombay (M.S.)

PART-II

AWARD

This is a reference under Sec. 10 of the Industrial Disputes Act. The dispute relates in respect of the demands raised on behalf of the workmen by the General Insurance Employees Union, Bombay as set out in the schedule to the reference. There was a part settlement between the parties and Mr. Justice Mahesh Chandra, the then Presiding Officer of this Tribunal, gave an interim award dated 12-10-1971. Now there has been a full settlement in respect of the dispute between the parties and the terms of the settlement are incorporated in a deed of settlement dated 14-10-1972 which has been signed by Mr J. B. Setalvad, Regional Manager for the Ruby General Insurance Company Ltd. and by Sri K. S. B. Pillai, General Secretary of the General Insurance Employees Union for and on behalf of the workmen and by Sri M. K. Salian, Group Secretary of the General Insurance Employees Union, Western Zone Bombay. The witnesses of the deed of settlement are Sri H. K. Desai, Advocate and Sri B. K. Advani. Shri S. K. Salian is not present before us today. The signature of Sri Advani is identified by Sri B. P. Sharma who is a Group Member of the Ruby General Insurance Employees Union and is present before us today. Sri B. P. Sharma also identifies the signatures of Sri M. K. Salian.

I have persued the terms of the aforesaid settlement and they appear to be fair and reasonable. I make my award in terms of the aforesaid settlement between the parties dated 14-10-1972. The said deed of settlement shall part of the award.

26-12-1972

B. K. KATJU, Presiding Officer.

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL JABALPUR**

Ref. CGIT/2/69 (New Ref. No. CGIT/LC/R(19)71)

In the matter of Industrial Dispute between

The employers in relation:

The Ruby General Insurance Co. Ltd. Resham Bhavan,
78, Veer Nariman Road, Bombay-20.

AND

Their Workmen as represented by the General Insurance
Employees' Union (Western Zone) Bombay.

Both the Parties to the above dispute respectfully submit as under:—

1. That the above dispute is pending before the Honourable Tribunal since 1968.
2. That the erstwhile management on 22-4-71 had agreed to settle the dispute by giving the offer in writing;
3. That the parties to the dispute carried on negotiations with a view to arriving at an amicable settlement and after the promulgation of the General Insurance (Emergency Provision) Ordinance 1971, the Custodian carried on and continued the negotiations in view of the said offer as contained in the erstwhile management's offer dated 22-4-1971.
4. That as a result of negotiations an interim settlement was signed on 9th August, 1971 and an application was made by the parties to make an interim Award in terms of the settlement. This Honourable Tribunal was pleased to pass this award as Part I in respect of aforesaid terms of settlement and same was published in the Gazette of India dated 18th December, 1971.
5. That thereafter further in view of the said written offer dated 22-4-1971 negotiations were carried on by and between the parties with a view to finally settle the above dispute and parties have now reached a full and final settlement of the whole dispute on the following terms in accordance with the offer of the Management dated 22nd April, 1971 in addition to the terms already agreed in the Interim Settlement:

TERMS OF SETTLEMENT

1. It is agreed to introduce Medical Benefits as under:— It is agreed that with effect from 1st January, 1970 the Company shall reimburse full medical expense incurred by an employee on the medical treatment of himself only subject to a maximum of Rs. 100/- in a year on a production of a certificate of any Registered Practitioner. The scheme of Medical Benefits agreed upon is as under:—

1. The benefit is meant only for the employee himself.
2. The benefit can be claimed only if the treatment is had from a Registered Medical Practitioner.
3. All medical bills shall, in the first instance be paid by the employee. He will, thereafter, submit the bill/bills along with medical prescription within a week to the Company.
4. The Company may have the bills and prescription for treatment submitted by an employee scrutinised, if necessary, by a Registered Medical Practitioner Approved by the Company.
5. Medical bills upto the admissible limit incurred by the employee should be paid by the Company within one month.

6. The employee shall intimate the Company of his illness as soon as practicable and the Company may require the employee to be examined by a Doctor appointed by the Company at its own cost.

7. This benefit will not be applicable for self-inflicted injuries, cost incurred for spectacles, dentures etc. venereal disease and intemperance.

8. Any amount not expended during any calendar year will lapse.

At the time of finalisation of the terms of this Agreement the Union brought to the Notice of the Custodian the difficulties that the employees would face in regard to the production and submission of Medical Bills, Certificates etc. for the years 1970 and 1971 in most of the cases the non-availability of the same due to lapse of time. After consideration, it is agreed between the parties that the employee who is not in a position to produce documentary evidence to substantiate his claim for reimbursement of Medical Expenses incurred by him during the year 1970 and 1971, may put in applications for reimbursement of Medical Expenses under the above Scheme for the years 1970 and 1971 subject to declaration that he had in fact undergone medical treatment to entitle him to the reimbursement to the extent of Rs. 100/- for each year and that as he has not preserved the Medical Certificates vouchers bills etc., it is not possible for him to produce the same. The Company will make payment on the basis of the applications and will not insist on Medical Bills/Certificates etc. for the said years as required under the Scheme.

II. It is agreed that existing gratuity scheme shall be substituted by the following Scheme.

GRATUITY SCHEME

The Gratuity will be paid by the Company to all permanent employees on the following basis:—

- (a) On retirement after 10 years of continuous service from the date of joining:—

One month's basic salary for each completed year of continuous service, subject to a maximum of 18 months basic salary.

- (b) On death and/or permanent physical or mental disability:—

One month's basic salary for each completed year of continuous service, subject to a maximum of 18 months basic salary;

- (c) On resignation, termination or dismissal after 15 years continuous service:—

One-half month's basic salary for each completed year of continuous service, subject to a maximum of 18 months basic salary.

- (d) In the event of dismissal of an employee for gross misconduct and/or theft, fraud, misappropriation or dishonesty in connection with the Company's business or property involving financial loss to the Company in money or property the amount of gratuity, if any, payable shall be reduced by the amount of loss caused to the Company.

- (e) The basic salary for the purpose of calculating gratuity shall be the last basic salary drawn on the date of retirement, death, disability, resignation or termination of service whichever the case may be.

III. It is agreed that this along with the terms and conditions of the interim award fully and finally settles the above disputes and also satisfies the commitments made by the Company in Clause 2(d) of Interim Settlement and the letter dated 22-4-1971.

It is therefore, Prased that this Honourable Tribunal may be pleased to pass final award in terms of above settlement.

Dated this 14th day of October, 1972.

For Ruby General Insurance Company Ltd.

J. B. SETALVAD,
Regional Manager.

Witness:

H. K. DESAI, Advocate.

K. S. B. PILLAI,
General Secretary,
General Insurance Employees Union, W.Z.

for and on behalf of the workmen employed by
Ruby General Insurance Company Limited at Bombay.

M. K. SALJAN,
Group Secretary.

Witness:

B. M. ADVANI

Ruby General Insurance Employees' Group of
General Insurance Employees Union,
Western Zone, Bombay.

Verified before me today
S. N. KATJU.

B. P. SHARMA,
Group Member of Ruby Group of the Union.

H. K. DESAI,
Advocate for Ruby General Insurance Co. Ltd.

PART OF THE AWARD

Dated: 26-12-1972

S. N. KATJU, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1973

का. आ. 309.—वैयक्तिक क्षति (प्रतिकार बीमा) अधिनियम, 1963 (1963 का 37) की धारा 14 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (1), धारा 16, 17 और 18 के अनुसूचन में, केन्द्रीय सरकार, श्रम आयुक्त, गोवा, दमण और दीव को गोवा, दमण और दीव के समस्त संघ राज्यक्षेत्र में उक्त अधिनियम की धारा 14, 15, 16, 17 और 18 के अधीन शक्तियों का और कारखाना निरीक्षक, गोवा, दमण और दीव को अपनी अधिकारिता के अन्वय उक्त अधिनियम की धारा 14 और 15 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत करती है।

[सं. एस-19025/27/72-कारखाना]

लालफक जुआला, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd January, 1973

S.O. 309.—In pursuance of sub-section (i) of section 14, sub-section (1) of section 15, sections 16, 17 and 18 of the Personal Injuries (Compensation Insurance) Act, 1963 (3 of 1963), the Central Government hereby authorises the Labour Commissioner Goa, Daman and Diu to exercise the powers under sections 14, 15, 16, 17 and 18 of the said Act throughout the Union Territory of Goa, Daman and Diu and the Factory Inspector, Goa, Daman and Diu to exercise, within his jurisdiction, the powers under sections 14 and 15 of the said Act.

[No. S. 19025/27/72-Fac.]

LALFAK ZUALA, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1973

आदेश

का. आ. 310.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कलकत्ता पत्तन डिग्घी नौका मालिक संघ कलकत्ता के प्रबंधन से संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्वीक्षित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गीठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्वीक्षित करती है।

अनुसूची

क्या श्री बी. सी. नाग, नौका मालिक की तीन सितम्बर, 1972 से श्री शेख अमीरुल-इस्लाम, मानजी की सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुपात का हक्कार है?

[संख्या. एल-32011/26/72-पी. एण्ड डी.]

बी. शंकरालिंगम, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd January, 1973

ORDER

S.O. 310.—WHEREAS the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of the Calcutta, Port the Dinghy Boat Owners Association, Calcutta and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule here-to annexed;

AND WHEREAS the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of Shri B. C. Nag, Boat Owner in terminating the services of Shri Sk. Amirul Islam, Manjee with effect from the 3rd September, 1972, is justified? If not, to what relief is the workman entitled?

[No. L-32011/26/72-P&D.]

New Delhi, the 23rd January, 1973

S.O. 311.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Ivan Milutinovic Pim, Vasco-da-Gama (Goa) and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th January, 1973.

[No. L-36012/3/72-P&D.]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

BEFORE THE GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL
BOMBAY.

Reference No. CGIT-4 of 1972

Parties:Employers in relation to the management of Messrs.
Ivan Milutinovic Pim, Vasco-da-Gama (Goa).

AND

Their Workmen

Present :

Shri A. T. Zambre—Presiding Officer.

Appearances:For the employers—Shri D. B. Johnney, Secretary, Ivan
Milutinovic Pim.For the workmen—Shri Mohan Nair, General Secretary,
Goa Dock Labour Union, (INTUC).**State:**—Goa.**Industry:**—Major Ports and Docks.
Bombay dated 12th December, 1972.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) have by three order No. 36012/3/72-P&D dated 14-7-1972 referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Messrs. Ivan Milutinovic Pim, Vasco da Gama, Goa and their workmen in respect of the matters specified in the following schedule:—

SCHEDULE

“Whether the action of Messrs. Ivan Milutinovic PIM Capital Dredging Contractors, Mormugao Harbour (Goa) in terminating the services of the workman Shri R. Kuttan Pillai, Helper with effect from 26th April, 1972 is justified? If not, to what relief is the Workman entitled?”

2. The employers are a limited company incorporated in Yugoslavia having their head office at Belgrade. They are dredging contractors and have undertaken the work of dredging the Goa harbour. The company has got its principal office for India also. Shri Kuttan Pillai the workman involved in this reference was working with them as a dumper helper. He is a member of the Goa Dock Labour Union. It appears that the workman was irregular in attending to duty and used to absent himself and hence the management by their order dated 26-4-1972 terminated his services for irregular attendance and absenting from duty frequently without justification. The Goa Dock Labour Union made a representation to the management that when the workman had to report for work after leave he was bedridden with chicken pox and when he reported for duty he was assigned the job of jack hammer driller whereas his original duty was dumper helper and because of the physical inability of the workman he had approached the management to put him in the mechanical section or in the pipeline or dumper section but they did not accede to his request. The management contended that his past record was not satisfactory but offered him some duties in the quarry but he refused. Thereafter the matter was taken to the Labour Commissioner in conciliation but as the conciliation ended in failure Government referred this dispute to adjudication.

After receipt of the order of reference the Tribunal issued notices to both the parties. But they did not file any written statement as they had started negotiations and when the reference was again fixed for hearing at Goa they filed terms of settlement. By the settlement the management has agreed to pay a lump sum of Rs. 525/- to the workman Shri Kuttan Pillai in full and final settlement of all the claims for the services rendered by him to the company from 22nd November 1969 to 15th January 1972. The workman also agreed to tender a letter of resignation to the management from the date of the termination of his services. The terms of settlement are signed by both the parties including the workman.

By the terms of settlement the termination has been changed to resignation. The workman has also been paid the lump sum of Rs. 525/-. In my opinion the terms of settlement are reasonable and I pass an award in terms of the memorandum of settlement annexure B. The application of the parties praying for an award in terms of the settlement and the memorandum of settlement (Annexures A and B respectively) shall form part of this award.
No order as to costs.

A. T. ZAMBRE, Presiding Officer.

ANNEXURE 'A'

BEFORE THE HON. JUSTICE A. T. ZAMBRE, PRESID-
ING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL BOMBAY,

Reference No. CGIT-4 of 1972

BETWEEN

The Management of M/s. Ivan Milutinovic PIM, Vasco-
da Gama, Goa.

AND

Their Workman represented by the General Secretary
Goa Dock Labour Union, Vasco-da-Gama, Goa.

May it please your honour.

We are enclosing herewith a copy of a memorandum of settlement signed between the Management of M/s. Ivan Milutinovic PIM and their workman (Shri Kuttan Pillai) represented by Goa Dock Labour Union, Vasco-da-Gama in connection with the dispute which is referred to your Honourable Tribunal vide Government of India Order No. L-36012/3/72 F & D dated 14th July, 1972.

Your honour was pleased to direct both the parties to file their written statements vide letter No. 4/72/1147/72 dated 3rd August 1972. Your honour may be pleased to note that when we approached the Management with a request for an amicable settlement, the Management without prejudice to their contention, agreed to settle the dispute amicably and thus the settlement was arrived at between us. The workman concerned, Shri Kuttan Pillai is also a party to this settlement.

We therefore, pray your Honour to be kind enough to pass a consent award in the light of the above settlement for which act of kindness we shall ever pray.

Dated this 16th day of September, 1972.

For M/s. Ivan Milutinovic PIM

MR. D. RADOJEVIC, Project Manager.

For Goa Dock Labour Union,
MOHAN NAIR, General Secy.

ANNEXURE 'B'

MEMORANDUM OF SETTLEMENT SIGNED UNDER
SECTION 2(P) OF THE INDUSTRIAL DISPUTE ACT
1947 BETWEEN THE MANAGEMENT OF M/S. IVAN
MILUTINOVIC PIM AND THEIR WORKMAN SHRI
KUTTAN PILLAI, HELPER. REPRESENTED BY GOA
DOCK LABOUR UNION.

PRESENT

Representing the Workman

1. Shri Kuttan Pillai, Helper.
2. Shri Mohan Nair, General Secretary, Goa Dock Labour Union.
3. Shri M. T. Antony, Managing Committee Member, Goa Dock Labour Union

Representing the Management

1. Mr. D. Radojevic, Project Manager.
2. Mr. J. Costa, Secretary.

SHORT RECITAL OF THE CASE

The Management of M/s. Ivan Milutinovic Pim, hereinafter called as the Management terminated the service of Shri Kuttan Pillai, *vide* their letter No. 299/PER dated 26th April, 1972 for irregular attendance and absents from duties frequently without proper justifications. The Management contended that the past record of the workman is far from satisfactory and Shri Kuttan Pillai is of the regular habit of absents himself from work. However, the Management stated that Shri Kuttan Pillai was allowed to resume duties in Quarry as a Helper. He refused to work and preferred to work only as a Helper on the Truck except in the Pipeline section where he was originally employed.

The Goa Dock Labour Union, hereinafter called the Union negotiated with the Management for an amicable settlement. The Union represented to the Management when the workman had reported for work after leave and during the leave period, he was bed-ridden with Chicken-Pox. When he reported for duty, he was assigned the job of Jack Hammer Driller, whereas his original duty was Dumper Helper. Because of the physical inability of the workman, the Management was approached by the workman to put him in mechanical section, or in the Pipeline or on the Dumper, but the Management did not concede to this request. Union contended that this was a clear case of victimisation. The matter could not be settled between the parties, hence, the Union approached the Assistant Labour Commissioner on 28th April, 1972, for his intervention, and the dispute was taken up by the Assistant Labour Commissioner (Central). Vasco-da-Gama for conciliation and finally, the conciliation proceedings ended in failure on 27-5-1972.

The Government of India *vide* their order dated 14th July, 1972, referred the dispute for adjudication for the Central Government Industrial Tribunal (Bombay).

The honourable Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal (Bombay), issued notice to the parties *vide* letter No. 4/72/1147/72 dated 3rd August, 1972, for filing written statements required under Rule 10B of the Industrial Dispute (Central) 1957. After the reference of this dispute for adjudication, the Union and the Management again negotiated for an amicable settlement in order to maintain good industrial relation and finally, it is agreed between the parties to close the dispute on the following terms and conditions:—

TERMS OF SETTLEMENT

1. The Management agrees to pay a lump sum of Rs. 525/- to Shri Kuttan Pillai on or before Monday the 18th September, 1972 towards full and final settlement of all the claims of Shri Kuttan Pillai for the services rendered by him with the Company from 22nd November, 1969 to 15th January, 1972.
2. The Union and workman agree to tender letter of resignation to the Management from the date on which Shri Kuttan Pillai's services were terminated.
3. The Management and the Union agree to file a joint application before the Central Government Industrial Tribunal (Bombay) and pray for a consent award in the light of this settlement.

Representing the Management Representing the workman

1. MR. D. RADOJEVIC 1. SHRI KUTTAN PILLAI,
2. MR. J. COSTA 2. SHRI MOHAN NAIR,
SHRI M. T. ANTHONY 3. SHRI M. T. ANTONY,
Managing Committee Member,
Vasco-da-Gama, Goa.

Witnesses

1. Sd/-
3. Sd/-

Vasco-da-Gama, Goa.
16th September, 1972

New Delhi, the 23rd January, 1973

S.O. 312.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award (Part I) of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs. Elesbao Pereira and Sons, Vasco-da-Gama (Goa) and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th January, 1973.

[No. L-36011/3/71-P & D]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, BOMBAY

Reference No. CGIT-8 of 1971

Parties :

Employers in relation to the management of Elesbao Pereira and Sons, Vasco-da-Gama, Goa.

AND

their workmen

Present :

Shri A. T. Zambre—Presiding Officer.

Appearances :

For the employers—Shri Ramesh Desai, Labour Adviser,
For the workmen—Shri G. D. Bhadkamkar, General Secretary, Mormugao Stevedores Staff Association.

State : Union Territory of Goa.

Industry : Major Ports and Docks.

Bombay dated 23rd December, 1972.

AWARD PART I

The Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour and Employment, by their Order No. L-36011/3/71-P & D dated 19th October 1971 have referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Elesbao Pereira and Sons, Stevedores, Vasco-da-Gama and their workmen in respect of the issues specified in the following schedule:—

SCHEDULE

1. Whether the action of the management of Messrs. Elesbao Pereira and Sons, Stevedores, Vasco-da-Gama in implementing the recommendations of the Central Wage Board for the Port and Dock workers in respect of their stevedoring staff with effect from September, 1970 instead of 1st January, 1969 as accepted by the Government of India *Vide* Resolution No. WB-21(7)/69, dated the 28th March, 1970, is justified? If not, to what relief are the concerned workmen entitled?"
2. Whether Shri S. Almedin, Chief Foreman, under the aforesaid Stevedores is entitled to a scale of pay higher than that prescribed for the Foreman in the Wage Board recommendations for Port and Dock Workers? If so, what should be the scale of pay for the said Chief Foreman and from which date should it be effective. If not, whether he is entitled to any other benefit and if so, from which date?"

This Award Part I relates to a part of issue No. 1 and the facts relating to this reference may be stated in brief as follows:—

2. Messrs. Elesbao Pereira & Sons are registered employers and are carrying on stevedoring business in the Mormugao Harbour. They have a number of workmen in their employment such as supervisory staff, winchmen, gang workers etc. The Government of India in their Resolution No. WB-21(7)/69 dated 28th March 1970 had accepted the majority and unanimous recommendations of the Central Wage Board for Port and Dock Workers and the recommendations were to come into operation with effect from 1-1-1969.

3. The Mormugao Stevedores' Staff Association representing the workmen of the management who are its members have by their statement of claim *inter alia* contended that after the acceptance of the recommendations of the Central Wage Board by the Government the union had called upon the management to implement the said recommendations in respect of the stevedoring staff but the management did not agree to implement them and after a long time the said management implemented the recommendations partly and have not implemented the recommendations fully. It has been contended that the recommendations have not been implemented with retrospective effect from 1-1-1969 but they have been implemented with effect from 1-9-1970. It has been further contended that the management had implemented the Wage Board recommendations as accepted by the Government only in respect of registered dock workers namely gang workers and winchmen (reserve pool or monthly) and has ignored the recommendations in respect of the other employees such as stevedoring staff which included the chief foreman, foreman, assistant foreman, supervisors, tally clerks, shovel keepers. Some of the employees of the supervisory staff were not fitted properly and it was contended that the shovel keepers were totally denied the benefits of the Wage Board recommendations. There were other contentions which are not material for the purposes of this Part I award.

4. The employers have by their written statement denied the allegations and *inter alia* contended that the Wage Board had not made any recommendations for shovel keepers and as such they were rightly not given the benefit of the Wage Board recommendations. It was further contended that the shovel keepers were totally denied the benefits of the Wage Board recommendations.

5. After the statements and rejoinder the dispute was fixed for hearing on a number of occasions when the parties stated that they were making efforts to negotiate a settlement. Finally when the matter was fixed for hearing at Bombay on 20th December 1972 the parties negotiated and arrived at a settlement in respect of a part of demand No. 1 which related to the category of shovel keepers and by the settlement the company has agreed to prescribe the basic scale of Rs. 110-2/50-120-3-135-EB-3-147 with retrospective effect from 1-1-1969 for the category of shovel keepers. In addition to the above scale the shovel keepers are entitled to receive D.A. A.D.A. C.C.A. and H.R.A. on the basis payable to registered dock workers with effect from 1-1-1969 and the arrears have been agreed to be paid to the shovel keepers in two equal instalments the first to be paid on or before 10th March, 1973 and the balance amount on or before 30th April 1973. By these terms it is clear that the shovel keepers have been given all the benefits under the recommendations of the Central Wage Board and the settlement is reasonable.

6. Parties have filed the terms of settlement which are at exhibit I. I accept the settlement and pass an award part I in terms of the settlement exhibit I which shall form part of this award Part I.

No order as to cost.

A. T. ZAMBRE, Presiding Officer.

Exhibit—I

BEFORE SHRI A. T. ZAMBRE, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

Reference No. CGIT-8 of 1971.

PARTIES:—

Employers in relation to the management of Elesbao Pereira and Sons, Vasco-da-Gama, Goa

AND

their workmen.

May it Please Your Honour,

The parties to the above reference jointly submit as under:

(a) The parties have arrived at the following settlement in relation to part of demand No. 1 in so far as it relates to the category of shovel keepers:

(i) The company agrees to prescribe the basic scale of Rs. 110-2/50-120-3-135-EB-3-147 with retros-

39 G of India/72—21.

pective effect from 1st January 1969 for the category of shovel keepers.

(ii) In addition to the above scale the shovel keepers would receive D.A. A.D.A. C.C.A. and H.R.A. (allowances) on the basis payable to registered dock workers with effect from 1st January 1969.

(iii) The arrears arising out of the above clauses would be payable to shovel keepers in two equal instalments, the first instalment would be paid on or before 10th March, 1973 and the balance amount on or before 30th April 1973.

The parties therefore pray that Part Award in terms of the above settlement may please be passed for which act of kindness the parties shall ever remain bound.

Dated at Bombay on 20th December 1972.

For the workmen.

For Elesbao Pereira & Sons.

G. D. BHADKAMKAR

ELESBAO PEREIRA

नई दिल्ली, 23 जनवरी 1973

आवेश

का. आ. 313.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावृद्ध अनुसूची में निर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स बिन्नी लिमिटेड, मद्रास के प्रबन्धकों सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिससे पीठासीन अधिकारी श्री के. सीताराम राय होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट करती है ।

अनुसूची

“क्या मैसर्स बिन्नी एंड कम्पनी लिमिटेड के अधीन उनके समुद्र-तट विभाग में नियोजित निम्नलिखित प्रवर्गों के कर्मचारी, महा-पत्तनों पर पत्तन और डाक कर्मचारों के लिए केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड द्वारा यथा सिफारिश की गई मजदूरी और अन्य भत्तों के हकदार हैं? यदि नहीं, तो ये कर्मकार किस अनुसूची के हकदार हैं?”

1. सुपरवाइजर
2. लिपिक
3. टैली-लिपिक
4. सेरंग
5. ठिठल
6. चौकीदार

[सं 74/23/70-पी एण्ड डी]

पी. शंकरालिंगम, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd January, 1973

ORDER

S.O. 313.—WHEREAS the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Binny Limited, Madras and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

AND, WHEREAS, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri K. Seetharama Rao shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the following categories of employees employed under Messrs Binny and Company Limited in their Beach Department are entitled to the wages and other allowances, as recommended by the Central Wage Board for Port & Dock Workers at Major Ports? If not, to what relief are these workmen entitled?"

1. Supervisors.
2. Clerks.
3. Tally Clerks.
4. Serangs.
5. Findals.
6. Watchmen.

[No. 74/23/70-P & D]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1973

का. आ. 314.—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की उपधारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अभूक खान श्रम कल्याण निधि संगठन के निम्नलिखित चिकित्सक अधिकारियों को, अर्हित चिकित्सा व्यवसायी होने के कारण राजस्थान राज्य की सभी खानों के लिए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ एतद्वारा प्रमाणकता सर्टन नियुक्त करती है :—

- (1) चिकित्सा अधीक्षक, सेंट्रल अस्पताल, गंगापूर, जिला भिलवारा, राजस्थान.
- (2) चिकित्सा अधिकारी, चलता-फिरता चिकित्सा यूनिट, अभूक खान श्रम कल्याण निधि, भिलवाड़ा, राजस्थान ।

[सं. एस. 29013/10/72-उम-1]

New Delhi, the 24th January, 1973

S.O. 314.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby appoints the following medical officers of the Mica Mines Labour Welfare Fund

Organisation, being qualified medical practitioners, to be certifying surgeons for the purposes of the said Act for all the mines in the State of Rajasthan:—

- (1) Medical Superintendent, Central Hospital, Ganganpur, District Bhilwara, Rajasthan.
- (2) Medical Officer, Mobile Medical Unit, Mica Mines Labour Welfare Fund, Bhilwara, Rajasthan.

[No. S. 29013/10/72-M. I]

का. आ. 315.—खान अधिनियम 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 531 दिनांक 2 मार्च 1961 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित प्रविष्टि का लोप कर दिया जाएगा, अर्थात्:—

"(9) श्री जी. एस. मरवाहा" ।

[संख्या ए-35017/2/72-एम-1]

आर. कुंजीथापदम, अवर सचिव

S.O. 315.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. S.O. 531 dated the 2nd March, 1961, namely:—

In the said notification, the following entry shall be omitted, namely:—

"(9) Shri G. S. Marwaha."

[No. A-35017/2/72-MI]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1973

का. आ. 316.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत हौसी प्लेट एण्ड वंसल्स लिमिटेड, विशाखा-पत्तनम्, आन्ध्र प्रदेश, को उक्त अधिनियम के सभी उपबंधों से जनवरी, 1973 के 22वें दिन से एक वर्ष की अवधि के लिए छूट देती है ।

[सं. एस.-38014(2)/72-एच. आर्.]

दत्तजीत सिंह, अवर सचिव

New Delhi, 23rd January, 1973

S.O. 316.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts the Bharat Heavy Plate and Vessels Limited, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, from all the provisions of the said Act for a period of one year with effect from the 22nd day of January, 1973.

[S. 38014(2)/72-HI]

DALJIT SINGH, Under Secy.

संचार विभाग
(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1973

सा. का. नि. 317.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खण्ड 3 के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने

खड़गपुर टेलीफोन केंद्र में दिनांक 16-3-73 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं. 5-13/73 पी. एच. बी. (4)]

ए. एस. वोहरा,

सहायक महानिदेशक (पी. एच. बी.)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(P. & T. Board)

New Delhi, the 27th January, 1973

S.O. 317.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16-3-1973 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in KHARAGPUR Telephone Exchange, West Bengal Circle.

[No. 5-13/73-PHB(4)]

A. S. VOHRA,

Asstt. Director General (PHB).

